



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 318] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 5, 2017/अग्रहायण 14, 1939
No. 318] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 5, 2017/AGRAHAYANA 14, 1939

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 5 दिसम्बर, 2017

सं. 43/2015-2020

फा.सं. 01/94/180/333/एएम-15/पीसी-4. विदेश व्यापार नीति, 2015-2020 के पैराग्राफ 1.03 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्वारा प्रक्रिया पुस्तक के संशोधित संस्करण, जैसाकि इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक में निहित है, को अधिसूचित करते हैं। यह 05 दिसम्बर, 2017 से प्रभावी होगा।

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव: विदेश व्यापार नीति, 2015-2020 की प्रक्रिया पुस्तक के संशोधित संस्करण को एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है।

आलोक वर्धन चतुर्वेदी, महानिदेशक, विदेश व्यापार

अध्याय - 1

परिचय एवं व्यापार सरलीकरण

1.01 प्रक्रिया की अधिसूचना

विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) के पैरा 1.03 के प्रावधानों के अनुसरण में, महानिदेशक, विदेश व्यापार (डीजीएफटी) एतद्वारा विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम के प्रावधान, इसके अधीन बनाए गए नियम/आदेश तथा विदेश व्यापार नीति के प्रावधानों को लागू करने के लिए निर्यातक या आयातक अथवा लाइसेंसिंग/ क्षेत्रीय प्राधिकारी अथवा किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रिया को अधिसूचित करते हैं। उक्त प्रक्रिया निम्नलिखित संकलनों में समाविष्ट है:-

(क) प्रक्रिया पुस्तक

(ख) परिशिष्ट और आयात निर्यात प्रपत्र तथा

(ग) मानक निविष्टि उत्पादन मानदंड (सिओन)

समय-समय पर यथा संशोधित ये संकलन अपनी अधिसूचना की तिथि से लागू होंगे तथा 31 मार्च, 2020 तक लागू रहेंगे।

1.02 उद्देश्य

इसका उद्देश्य सरल, पारदर्शी और ईडीआई संगत प्रक्रियाओं के द्वारा विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम के प्रावधानों, इसके अधीन बनाए गए नियमों और जारी किए गए आदेशों और विदेश व्यापार नीति (2015-20) के प्रावधानों को कार्यान्वित करना है जो प्रयोक्ता अनुकूल हो तथा जिनका विदेश व्यापार के प्रभावी प्रबंधन हेतु अनुपालन किया जा सकता है।

1.03 परिभाषा

इस पुस्तक के प्रयोजन के लिए विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियम और आदेश तथा विदेश व्यापार नीति (2015-20) की परिभाषाएं तथा शब्दावली लागू होंगे।

1.04 विदेश व्यापार का ई-शासन

(क) विदेश व्यापार महानिदेशालय आवेदनों की आनलाइन फाइलिंग, सामुदायिक भागीदारों के साथ संदेश का आदान-प्रदान, डिजिटल हस्ताक्षर और आवेदन शुल्क का इलेक्ट्रॉनिक भुगतान जैसे साधनों का उपयोग करके पारदर्शी एवं कुशल ईडीआई प्लेटफार्म पर अपनी अधिकांश सेवाएं प्रदान करता है। विदेश व्यापार महानिदेशालय में ईडीआई के उपयोग से तेजी से प्रोसेसिंग, ईमेल के द्वारा शीघ्र सम्प्रेषण तथा आवेदन प्रोसेसिंग की स्थिति की आनलाइन उपलब्धता आसान हुई है। इसका उद्देश्य एसएमएस के जरिए उच्च स्तर पर सूचना का आदान-प्रदान सुनिश्चित करना है।

(ख) ऑनलाइन डीजीएफटी पोर्टल सहित अधिनियमों, नियमों, उसकी नीति और प्रक्रियाओं सहित निर्यात आयात संबंधी जानकारी <http://dgft.gov.in> से ली जा सकती है।

(ग) विदेश व्यापार महानिदेशालय के सभी क्षेत्रीय प्राधिकरण 24x7 वातावरण में एक्जिम समुदाय को आनलाइन सम्पर्क प्रदान करने के लिए ईडीआई समर्थित है और डीजीएफटी के केन्द्रीय सर्वर से जुड़े हुए हैं।

(घ) विदेश व्यापार महानिदेशालय सतत आधार पर ईडीआई के क्षेत्र और व्यापकता का विस्तार करता रहता है। इसका प्रयास सामुदायिक भागीदारों का उच्च स्तर पर एकीकरण करने का है।

1.05 प्रक्रिया

निर्यातक डीजीएफटी की वेबसाइट <http://dgft.gov.in> पर ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करेगा। तत्पश्चात आवेदन को विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुसार प्रक्रियाबद्ध किया जाएगा। आवेदनों की प्रोसेसिंग ऑनलाइन की जाएगी। विदेश व्यापार महानिदेशालय ऑनलाइन तरीके से या ईमेल का उपयोग करके त्रुटि संबंधी पत्र भेजेगा। विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा मैन्युअल तरीके से कोई पत्र जारी नहीं किया जाएगा।

1.06 डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग

(क) विदेश व्यापार महानिदेशालय श्रेणी-II डिजिटल हस्ताक्षर के साथ उसमें अन्तःस्थापित आईईसी संख्या सहित ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की अनुमति देता है। डीजीएफटी से अनुमोदित डिजिटल हस्ताक्षर जारी करने वाले प्राधिकारियों की सूची निम्नलिखित है:

- (i) (ढ) कोड सोल्यूशन्स सीए
- (ii) ई-मुद्रा
- (iii) सेफस्क्रीप्ट (सिफी कम्यूनिकेशन लि0)

(ख) आवेदन जमा करने के अतिरिक्त अन्य प्रयोजनों जैसे ई-बीआरसी डाटा की पूछताछ या अपलोड करने/संसाधित करने के प्रयोजन के लिए भारतीय प्रमाणन नियंत्रक प्राधिकरण की किसी अनुमोदित संस्था द्वारा जारी श्रेणी-II या उसके ऊपर का डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र स्वीकार किया जाता है।

1.07 ईडीआई और गैर-ईडीआई पत्तनों से निर्यात के लिए अलग आवेदन

ईडीआई पत्तनों और गैर-ईडीआई पत्तनों से निर्यात के लिए विदेश व्यापार महानिदेशालय में अलग-अलग आवेदन प्रस्तुत किए जाएंगे।

1.08 गैर-ईडीआई पत्तनों से निर्यात के लिए आवेदन

निर्यातक विदेश व्यापार महानिदेशालय की वेबसाइट <http://dgft.gov.in> पर अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। उसके बाद आवेदक आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन की हार्ड प्रति के संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा। समुचित संविधा के पश्चात

प्रक्रिया पुस्तक में यथा प्रस्तावित दस्तावेजों की हार्ड प्रतियों के आधार पर प्राधिकार पत्र/स्क्रिप जारी किया जाएगा।

1.09 ईडीआई पत्तनों से निर्यात हेतु आवेदन

ईडीआई पत्तनों से निर्यात से संबंधित आवेदन संगत प्रावधानों के अनुसार ऑनलाइन प्रस्तुत किए जाएंगे। निम्नलिखित दस्तावेजों की वास्तविक या हार्ड प्रतियों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी:

- (i) विदेश व्यापार महानिदेशालय को आवेदन
- (ii) ईडीआई पोतलदान बिल
- (iii) इलेक्ट्रॉनिक बैंक वसूली प्रमाणपत्र (ईबीआरसी)
- (iv) आर सी एम सी

1.10 ईडीआई पोतलदानों के लिए किसी मैनुअल फीडिंग की आवश्यकता नहीं

ईडीआई पोतलदान बिलों के लिए ऑनलाइन साफ्टवेयर में आवेदकों के लिए पोतलदान बिलों के ब्यौरे की मैनुअल फीडिंग की अनुमति नहीं होगी और तदनुसार ईडीआई पोतलदान बिल के ब्यौरे को प्रति सत्यापित करने की आवश्यकता के बिना क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा लाभ प्रदान किया जाएगा।

1.11 दस्तावेजों की हार्ड कापी को समाप्त करना

निर्यातक की प्रोफाइल में पहले से ऑनलाइन प्रस्तुत दस्तावेजों की हार्ड कापी की मांग नहीं की जाएगी।

1.12 क्षेत्रीय प्राधिकरण में गैर-ईडीआई पोतलदान बिलों को प्रक्रियाबद्ध करना

गैर-ईडीआई पोतलदान बिलों या सीमाशुल्क से संदेश आदान-प्रदान के माध्यम से प्राप्त नहीं हुए पोतलदान बिलों के मामले में संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी लाभ प्रदान करने से पहले मूल पोतलदान बिलों से निर्यातक द्वारा दिए गए ब्यौरे को सत्यापित करेगा।

1.13 आवेदन जमा करने के लिए अनुदेश

आवेदन ऑनलाइन प्रस्तुत करने के लिए प्रत्येक चरण के विस्तृत ब्यौरे विदेश व्यापार महानिदेशालय की वेबसाइट में संगत मद फाइल और प्रक्रिया पुस्तक के योजना विशिष्ट एएनएफ में उपलब्ध हैं।

1.14 तीसरी पार्टी निर्यातों के संबंध में लाभों का दावा करने हेतु ईडीआई प्रणाली

तीसरी पार्टी निर्यातों के संबंध में, ईडीआई सिस्टम में लाभों का दावा करने के लिए, प्रथम पार्टी द्वारा प्रक्रिया की शुरुआत की जाएगी जो रिपोर्टरी के पास पोतलदान बिलों और बीआरसी को संबद्ध करेगा। यदि प्रथम पार्टी किसी एक विशेष पोतलदान बिल मद/मदों के लिए लाभों का दावा न करने का विकल्प चुनती है, तो यह तीसरी पार्टी को ऐसे पोतलदान बिल/बिलों के लिए लाभों का दावा करने के लिए प्राधिकृत कर सकती है। प्रथम पार्टी द्वारा ऐसे प्राधिकार-पत्र के बाद, तीसरी पार्टी अपने आवेदन पत्र में ऐसे पोतलदान बिल मद/मदों का उपयोग कर पाएगी।

1.15 ई-बीआरसी में मुद्रा परिवर्तन

(क) मुद्राएं, जहां पर सीबीईसी द्वारा विनिमय दर अधिसूचित की जाती है:

अनुमत निर्यात आदेश (एलईओ) की तिथि को सीबीईसी द्वारा प्रकाशित मासिक विनिमय दरों का प्रयोग करते हुए प्राप्त की गई विदेशी मुद्रा (ईबीआरसी में बैंक द्वारा यथा उल्लिखित) भारतीय रुपयों में बदला जाता है।

(ख) मुद्राएं, जहां पर सीबीईसी द्वारा विनिमय दर अधिसूचित नहीं की जाती है:

ऐसे मामलों में, भारतीय रुपयों में प्राप्त कुल मात्रा (ईबीआरसी में बैंक द्वारा यथा उल्लिखित) सीबीईसी द्वारा प्रकाशित प्राप्ति की तिथि पर प्रचलित अमेरिकी डालर/भारतीय रुपए की विनिमय दर का प्रयोग करते हुए अमेरिकी डालर में परिवर्तित की जाएगी।

1.16 दावों को प्रक्रियाबद्ध करने के लिए दिशा-निर्देश जहाँ निर्यातक को बीमा एजेंसियों के माध्यम से (बैंकों के माध्यम से नहीं) निर्यात लाभ का भुगतान मिलता है

(क) बीमा एजेंसी के माध्यम से निर्यात लाभ प्राप्त करने वाला आवेदक संबंधित बीमा कम्पनी द्वारा जारी भुगतान के प्रमाण के साथ संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी से सम्पर्क करेगा। क्षेत्रीय प्राधिकारी भुगतान की प्रामाणिकता के बारे में संतुष्ट होने के बाद अपर महानिदेशक (ईडीआई) का अनुमोदन प्राप्त करेगा और उसके बाद मामले को प्रक्रियाबद्ध करने के लिए विदेश व्यापार महानिदेशालय की ईडीआई प्रणाली में मूल्य (ईबीआरसी मूल्य के स्थान पर) को अपलोड करेगा।

(ख) यदि बीमा एजेंसी द्वारा जारी भुगतान के प्रमाण में विदेशी मुद्रा और भारतीय रुपये दोनों में दावा मूल्य का उल्लेख है तो

क्षेत्रीय प्राधिकारी प्रक्रियाबद्धता के लिए विदेशी मुद्रा मूल्य का उपयोग करेगा। यदि दावा मूल्य का केवल समतुल्य भारतीय रुपये में उल्लेख किया जाता है तो क्षेत्रीय प्राधिकारी बीमा दावा के निपटान की तारीख को लागू विनिमय दर (सीबीईसी द्वारा प्रकाशित) का उपयोग करके इस भारतीय रुपये के मूल्य को समतुल्य अमेरिकी डॉलर में परिवर्तित करेगा।

1.17 ईडीआई हेल्प डेस्क और ऑनलाइन शिकायत पंजीकरण तथा मानीटरिंग प्रणाली

ईडीआई हेल्प डेस्क विदेश व्यापार महानिदेशालय के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने में निर्यातकों की सहायता करने तथा ईडीआई से जुड़े अन्य मुद्दों का समाधान करने के लिए उपलब्ध है। सहायता के लिए <http://dgft.gov.in> पर ईमेल भेजा जा सकता है या टॉल फ्री नं० 1800111550 का उपयोग किया जा सकता है। हेल्प डेस्क की सुविधा विदेश व्यापार महानिदेशालय के चारों मंडलीय कार्यालयों जैसे सीएलए (नई दिल्ली), मुम्बई, चेन्नई और कोलकाता में भी उपलब्ध है। ऑनलाइन शिकायत पंजीकरण और मानीटरिंग प्रणाली में उपयोगकर्ता के लिए शिकायत दर्ज करने तथा स्थिति/ उत्तर ऑनलाइन (ब्यौरे <http://dgft.gov.in> पर) प्राप्त करने की सुविधा है।

1.18 ई-मेल

आयात/निर्यात से जुड़े प्रश्नों के लिए ईमेल के उपयोग को बढ़ावा दिया जाता है। सम्पर्क ईमेल की आईडी <http://dgft.gov.in/exim/2000/dgftContactUs.html> पर उपलब्ध है।

1.19 ई-व्यापार परियोजना

ई-व्यापार परियोजना उपयोगकर्ताओं के लिए उनके विदेश व्यापार से जुड़े विनियामक या अन्य अनुपालनों को ऑनलाइन पूरा करने के लिए सुविधा प्रदान करती है। वाणिज्य विभाग इस परियोजना को चलाता है।

इस परियोजना के प्रमुख हितधारक सीमाशुल्क कार्यालय, विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी), समुद्री पत्तन, वायुपत्तन, भारतीय कंटेनर निगम (कान्कॉर), इंग्लैन्ड कंटेनर डिपो (आईसीडी)/कंटेनर फ्रेट स्टेशन (सीएफएस) बैंक, आयातक/ निर्यातक, एजेंट, एयरलाइन्स/शिपिंग लाइन्स हैं।

इस परियोजना में व्यापार अनुरोधों को तेजी से प्रक्रिया में लाने के लिए आन्तरिक प्रक्रियाओं के स्वचालन पर बल दिया गया है। सरकारी एजेंसियों के साथ आयातकों/निर्यातकों के न्यूनतम व्यक्तिगत सम्पर्क के द्वारा प्रणाली में पारदर्शिता लायी जाती है।

परियोजना में निम्नलिखित प्रमुख सेवाओं का प्रावधान है:

- (i) सीमाशुल्क कार्यालयों और समुद्रीपत्तनों, वायुपत्तनों और आईसीडी/सीएफएस के अभिरक्षकों जैसे सामुदायिक भागीदारों द्वारा सेवाओं/ मंजूरीयों की ई-सुपुर्दगी। ये सेवाएं निर्यातकों, आयातकों, एजेंटों आदि को दी गई हैं।
- (ii) निर्यातक, आयातक, एजेंट आदि द्वारा सीमाशुल्क कार्यालय तथा समुद्रीपत्तनों, वायुपत्तनों और आईसीडी/सीएफएस के अभिरक्षकों को निर्यात/आयात के दस्तावेजों को ई-फाइल करना।
- (iii) सामुदायिक भागीदारों अर्थात् सीमाशुल्क कार्यालय तथा समुद्री-पत्तनों, वायुपत्तनों, आईसीडी/सीएफएस के बीच दस्तावेजों का इलेक्ट्रॉनिक आदान-प्रदान।
- (iv) सीमाशुल्क के लिए, डीजीएफटी के आवेदन और अन्य शुल्क तथा समुद्रीपत्तनों, वायुपत्तनों, आईसीडी/सीएफएस के अभिरक्षकों के शुल्क (लदाई-उतराई/माल भाड़ा आदि) के लिए निर्यातक, आयातक, एजेंटों द्वारा ई-भुगतान।

अध्याय - 2

निर्यात और आयात से संबंधित सामान्य प्रावधान

2.00 नीति

विदेश व्यापार नीति के अध्याय-2 में निर्यात और आयात के बारे में सामान्य प्रावधानों से संबंधित नीति दी गई है।

2.01 कवरेज

इस अध्याय में पूर्ण दस्तावेजीकरण सहित विभिन्न आवेदनों की प्रक्रिया शामिल है। आयात/निर्यात के लिए प्राधिकार पत्र/लाइसेंस/अनुमति/प्रमाणपत्र के लिए आवेदनों तथा विदेश व्यापार नीति के तहत लाभ के लिए आवेदनों की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है।

2.02 आयात/निर्यात के देश

जब तक अन्यथा विशेष रूप से प्रावधान न किया गया हो, किसी भी देश से/को अन्तराष्ट्रीय व्यापार (अर्थात् भारत में आयात और/अथवा भारत से निर्यात) हो सकता है। विदेश व्यापार नीति/ आईटीसी (एचएस) में देश विशिष्ट निषेध/सीमाओं, यदि कोई है, का उल्लेख किया गया है।

आवेदन:

2.03 आवेदन प्रस्तुत करना

(क) विदेश व्यापार नीति में स्कीमों के तहत लाभ का दावा करने या स्पष्टीकरण लेने और अन्य प्रयोजनों के लिए "प्रतिबंधित" माल के आयात/निर्यात हेतु प्राधिकार पत्र के लिए आवेदन क्षेत्रीय प्राधिकारी (आरए) को भेजे जा सकते हैं।

(ख) आवेदक दस्तावेज प्रस्तुत करते समय यह सुनिश्चित कर सकता है कि दस्तावेज अंग्रेजी या हिन्दी में हो। क्षेत्रीय भाषाओं के दस्तावेजों को अंग्रेजी या हिन्दी में अनुवाद कराया जा सकता है और अनुदित प्रतिलिपि को स्वप्रमाणित किया जा सकता है तथा मूल प्रति के साथ प्रस्तुत किया जा सकता है।

2.04 क्षेत्रीय प्राधिकारियों (आरए) का प्रादेशिक-क्षेत्राधिकार

क्षेत्रीय प्राधिकारियों का प्रादेशिक क्षेत्राधिकार परिशिष्ट एवं आयात निर्यात प्रपत्र के **परिशिष्ट 1क** में दिया गया है। आवेदक का पता क्षेत्रीय प्राधिकारी का क्षेत्राधिकार निर्धारित करता है। जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया गया हो, प्रत्येक आवेदन पत्र संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा।

2.05 अपूर्ण आवेदन पत्र

(क) अधूरे अथवा अप्राधिकृत आवेदन पत्र को अस्वीकृति का विशिष्ट कारण बताते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा रद्द कर दिया जाएगा। ऐसे अपूर्ण आवेदन पर कमियाँ दूर करने के बाद पुनः विचार किया जा सकता है।

(ख) यदि आवेदक द्वारा कमियों को 90 दिनों के भीतर दूर नहीं किया जाता है तो आवेदन को वापस लिया गया माना जाएगा।

2.06 आवेदन-शुल्क

शुल्क की मात्रा, भुगतान का तरीका, शुल्क-वापसी की प्रक्रिया और शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त व्यक्तियों की श्रेणियाँ **परिशिष्ट-2ट** में दी गई हैं।

आयातक निर्यातक कोड (आईईसी):

2.07 आयातक-निर्यातक कोड संख्या छूट प्राप्त श्रेणियाँ

(क) आयातक निर्यातक कोड आयात और/अथवा निर्यात के लिए अनिवार्य है। तथापि, आयातकों या निर्यातकों की निम्नलिखित श्रेणियों को आयातक-निर्यातक कोड संख्या प्राप्त करने से छूट है:-

क्र.सं.	आयात निर्यात कोड प्राप्त करने से छूट प्राप्त श्रेणियाँ
(i)	विदेश व्यापार (कुछ मामलों में नियमों के अनुप्रयोग से छूट) आदेश, 1993 की धारा 3(1) (उप धारा (ड.) और (ठ) को छोड़कर) में शामिल आयातक तथा धारा 3(2) (उप धारा (झ) और (ट) को छोड़कर) में शामिल निर्यातक।
(ii)	केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार के मंत्रालय/विभाग।
(iii)	जो व्यक्ति अपने निजी प्रयोग के लिए माल का आयात या निर्यात करते हैं जो व्यापार अथवा विनिर्माण या कृषि से संबंधित नहीं है।
(iv)	जो व्यक्ति नेपाल, भूटान, म्यांमार (भारत-म्यांमार के सीमावर्ती क्षेत्रों के माध्यम से), और चीन (गुंजी, नामग्या शिपकिला और नाथुला पत्तनों के माध्यम से) से/को माल का आयात/निर्यात करता है, बशर्ते कि नेपाल, भूटान और म्यांमार (भारत-म्यांमार के सीमावर्ती क्षेत्रों के माध्यम से) से/को आयात/निर्यात की एकल खेप का लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य भारतीय मुद्रा में 25,000/- रूपए से अधिक न हो, और चीन के मामले में (क) गुंजी और नामग्या शिपकिला के माध्यम से माल के आयात/निर्यात हेतु एकल खेप का लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य भारतीय मुद्रा में 1,00,000/-रूपए से अधिक न हो, तथा (ख) नाथुला के माध्यम से माल के आयात/निर्यात की एकल खेप का लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य 2,00,000/-रूपए से अधिक न हो।

इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त श्रेणी 2 द्वारा निर्यात के मामलों को छोड़कर आई टी सी (एच एस) की अनुसूची-2, परिशिष्ट-3 में यथा सूचीबद्ध विशेष रसायनों, जीवों, सामग्रियों, उपकरणों और प्रौद्योगिकियों (एस सी ओ एम ई टी) के निर्यात के लिए आयातक-निर्यातक कोड (आई ई सी) प्राप्त करने की छूट लागू नहीं होगी।

(ख) आयात/निर्यात प्रयोजन हेतु गैर वाणिज्यिक सार्वजनिक उपक्रमों और निर्यातक/आयातक की श्रेणियों द्वारा उनके समक्ष दर्शाए गए निम्नलिखित स्थाई आई ई सी संख्या का उपयोग करेंगे:-

क्र.सं.	स्थायी आयात निर्यात कोड	आयातक/निर्यातक की श्रेणियाँ
1.	एएमडीसीजी0111ई	केन्द्रीय सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग और उनके पूर्ण/आंशिक स्वामित्व वाली एजेंसियाँ।
2.	एडीएसजीए0129ई	राज्य सरकार के सभी विभाग और उनके पूर्ण/आंशिक स्वामित्व वाली एजेंसियाँ।
3.	डीसीयूएनओ0137ई	डिप्लोमेटिक कार्मिक, भारत में काउंसिलर अधिकारी, संयुक्त राष्ट्र संगठन और इसकी विशिष्ट एजेंसियों के अधिकारी।
4.	आईएबीबीआर0145ई	बैगेज नियमों के अधीन लाभों का दावा करने वाले विदेश जाने/लौटने वाले भारतीय
5.	आईआईएचआई0153ई	व्यक्ति/संस्थान/अस्पताल जो व्यापार या विनिर्माण अथवा कृषि से जुड़ा न हो और अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयात या निर्यात करता हो।
6.	आईआईईजीएन0161ई	वह व्यक्ति जो नेपाल को/से माल का निर्यात/ आयात करता हो।
7.	आईआईईजीएम0170ई	वह व्यक्ति जो म्यांमार को/से भारत-म्यांमार सीमा के माध्यम से माल का निर्यात/आयात करता हो।
8.	आईएफएफआईई0188ई	फोर्ड फाउंडेशन।
9.	एटीआईएफ1096ई	आयातक जो ए टी ए कार्नेट के प्रावधानों के अधीन मेलों/प्रदर्शनियों या इसी प्रकार के आयोजनों में प्रदर्शन या उपयोग करने के लिए माल का आयात करता हो। यह आईईसी संख्या प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 2.63 के अनुसार प्रदर्शनियों/ मेलों हेतु आयात के लिए भी आयातक प्रयोग कर सकता है।
10.	आईडीएनबीजी1100ई	निदेशक, राष्ट्रीय ब्लड ग्रुप।
11.	आईसीआईआरएन1126ई	व्यक्ति/धर्मार्थ संस्था/पंजीकृत गैर सरकारी संगठन जो माल का आयात करते हैं और जिन्हें प्राकृतिक आपदा से प्रभावित पीड़ितों द्वारा वास्तविक उपयोग के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अधीन सीमाशुल्क से छूट दी गई है।
12.	आईआईईजीसी1134ई	उपरोक्त पैरा 2.07 (iv) में यथा उल्लिखित एकल खेप की मूल्य सीमा के अधीन गुंजी, नामग्या, शिपकिला और नाथुला पत्तनों के माध्यम से चीन से/को समय-समय पर यथा अधिसूचित अनुमत माल का आयात/निर्यात करनेवाले व्यक्ति।
13.	एनसीआईईई1169ई	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत इकाइयों द्वारा गैर वाणिज्यिक आयात व निर्यात

2.08 आयातक-निर्यातक कोड के लिए आवेदन पत्र

(क) ई-आयातक निर्यातक कोड (ईआईईसी) के लिए निर्यातकों/आयातकों को आयात निर्यात प्रपत्र 2क में डिजिटल हस्ताक्षर के साथ आवेदन करना होगा जिसके साथ अपेक्षित दस्तावेज संलग्न करने होंगे और लागू शुल्क का भुगतान करना होगा। आईईसी हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा डीआईपीपी के ई-बिज पोर्टल के माध्यम से भी उपलब्ध है।

(ख) डीजीएफटी की वेबसाइट पर "आनलाइन आईईसी आवेदन" पर लागू करके तथा अपेक्षित दस्तावेजों के साथ आवेदन प्रपत्र को पुनः भरकर आवेदन पत्र की कमी को दूर किया जा सकता है।

2.09 आयातक-निर्यातक कोड फार्मेट

आयात निर्यातक कोड दिए गए फार्मेट (एएनएफ 2(क) (ii)) में जारी होगा। ऐसी आयातक निर्यातक कोड संख्या की एक प्रति संबंधित बैंक (आयात-निर्यात प्रपत्र 2क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार) को भेजी जाएगी। ऐसा पृष्ठांकन सामान्यतः ईमेल के द्वारा किया जाना चाहिए।

2.10 आयातक-निर्यातक कोड संख्या की वैधता

किसी आवेदक को आबंटित आयातक निर्यातक कोड संख्या की स्थायी वैधता होगी जब तक कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा रद्द नहीं की गई हो। आईईसी में आवेदक के सभी शाखा/प्रभाग/यूनिट/फैक्टरी शामिल होंगे।

2.11 ईओयू/एसईजेड के लिए आईईसी की वैधता

किसी फर्म के डीटीए यूनिट या ईओयू या एसईजेड/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी यूनिट के रूप में दर्जा पर ध्यान दिए बिना आयातक निर्यातक कोड वैध रहेगा तथा बंध-पत्र मुक्त और डीटीए में परिवर्तित किसी फर्म/यूनिट के मामले में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया निम्नानुसार है:

(क) कोई यूनिट जो बंध-पत्र मुक्त किए जाने के बाद ईओयू है या एसईजेड/ईएचटीपी/ एसटीपी/बीटीपी में है, अपने क्षेत्राधिकारी विकास आयुक्त, एसईजेड से प्राप्त आईईसी वापस नहीं करेगी।

(ख) क्षेत्राधिकारी विकास आयुक्त, एसईजेड बंधपत्र मुक्त करने के बाद मूल आईईसी फाईल को विदेश व्यापार महानिदेशालय के संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को भेजेगा।

(ग) क्षेत्रीय प्राधिकारी ऐसी फाईल का संरक्षक हो जाता है और आईईसी में आवश्यक संशोधन करने के लिए बंधपत्र मुक्त यूनिट को अनुमति देगा।

(घ) विदेश व्यापार नीति के अनुसार बंधपत्र मुक्त यूनिट क्षेत्रीय प्राधिकारी से लाभ के लिए पात्र होगी।

2.12 एक पैन-एक आईईसी

एक "पैन" नम्बर के मद्दे सिर्फ एक ही आईईसी जारी किया जाएगा। एक पैन के लिए जारी अनेक आईईसी 31.03.2015 से स्वतः ही निष्क्रिय हो जाएंगी।

2.13 आयातक-निर्यातक कोड संख्या को लौटाना

यदि कोई आयातक-निर्यातक कोड संख्या धारक आबंटित आयातक-निर्यातक कोड संख्या का उपयोग नहीं करना चाहता है, तो वह जारी करने वाले प्राधिकारी को उक्त कोड संख्या को लौटा सकता है। प्राप्त होने पर, जारी करने वाला प्राधिकारी तत्काल आईईसी रद्द कर देगा और सीमाशुल्क कार्यालय और विदेश व्यापार महानिदेशालय को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सूचित करेगा।

2.14 आयातक-निर्यातक कोड में संशोधन

(क) ई-आईईसी/आईईसी में संशोधन केवल ऑनलाइन किया जा सकता है। अपने आईईसी में संशोधन कराने वाले आवेदकों को dgft.nic.in पर लॉग-ऑन करना होगा और विक्क लिंक्स के अंतर्गत आयातक निर्यातक कोड (आईईसी) पर क्लिक करना होगा तथा अपने ई-आईईसी और वास्तविक रूप के आईईसी में संशोधन हेतु संबंधित क्षेत्राधिकार के क्षेत्रीय प्राधिकारी, जहां से आईईसी मूल रूप से जारी किया गया था, को अपेक्षित शुल्क का भुगतान करके तथा अपेक्षित दस्तावेज जमा करके "अपने आईईसी में संशोधन करें" का चयन करना होगा। क्षेत्रीय प्राधिकारियों और उनके क्षेत्राधिकार की सूची परिशिष्ट-1क में दी गई है।

(ख) नाम, पता, गठन, मालिकाना फर्म में स्वामित्व फर्म के स्वरूप में परिवर्तन जैसे मालिकाना से साझेदारी आदि जैसे ब्यौरे में परिवर्तन हेतु संशोधन के लिए आवेदन किया जा सकता है।

(ग) क्षेत्रीय प्राधिकारी आईईसी में संशोधन से संबंधित आवेदनों जिनमें पैन बदलना हो, के संबंध में यह सुनिश्चित करेगा कि पिछले आवेदक/पिछली आवेदक फर्म की देयताएं उस नए आवेदक/नई आवेदक फर्म को हस्तांतरित कर दी गई हैं जिसका पैन संशोधित आईईसी में प्रदर्शित होगा। क्षेत्रीय प्राधिकारियों को संशोधित आईईसी इसमें समाविष्ट परिवर्तित पैन सहित सभी संबंधित प्राधिकारियों को अवगत कराना चाहिए।

(घ) क्षेत्रीय प्राधिकारी पावर ऑफ अटॉर्नी/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा किए गए डिजिटल हस्ताक्षर वाले आवेदनों पर भी संज्ञान लेगा।

2.14(क) आईईसी में शाखा कार्यालय/प्रधान कार्यालय/पंजीकृत कार्यालय के पते में संशोधन/परिवर्तन जिसमें क्षेत्राधिकार वाले क्षेत्रीय प्राधिकारी में परिवर्तन भी शामिल है।

जब कोई आईईसी धारक अपने आईईसी में शाखा कार्यालय/प्रधान कार्यालय/पंजीकृत कार्यालय के पते में संशोधन/परिवर्तन चाहता है, तो उसे संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी जिसके क्षेत्राधिकार में आवेदक आता है, को इस संबंध में अनुरोध करेगा।

इस अनुरोध के आधार पर, क्षेत्रीय प्राधिकारी (जो अब तक आईईसी फाइल का अभिरक्षक है) ऐसे अनुरोधों को प्रोसेस करेगा और आईईसी के सही पाए जाने पर उसमें संशोधन करेगा और उस क्षेत्रीय प्राधिकारी, जिसके क्षेत्राधिकार में आवेदक स्थानांतरण चाहता है, को भी सूचित करेगा। नया क्षेत्रीय प्राधिकारी उक्त व्यक्ति को नए पते पर आवश्यक कार्य करने तथा एफटीपी के अनुसार पात्र लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन करने की भी अनुमति देगा।

2.15 आयातक/निर्यातक की प्रोफाइल

(क) आयातक निर्यात प्रपत्र-1 में आयातक/निर्यातक की प्रोफाइल है। आयातक-निर्यातक कोड धारक इसमें परिवर्तन होने पर तत्काल या किसी भी तरह कम से कम वर्ष में एक बार इसका अद्यतनीकरण करने के लिए जिम्मेवार होगा।

(ख) उन दस्तावेजों को इस विदेश व्यापार नीति की विभिन्न स्कीमों के तहत प्राधिकार पत्रों/स्क्रिपों के लिए आयातक/निर्यातक द्वारा प्रत्येक बार आवेदन करने पर प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है जिन्हें आयातक-निर्यातक प्रोफाइल में अपलोड किया जाता है। तथापि, यदि कोई व्यक्ति किसी प्राधिकारी से विनिर्माता निर्यातक के रूप में अपनी हैसियत का दावा कर कोई लाभ प्राप्त करना चाहता है, तो उसे इस संबंध में अपना विश्वास उस प्राधिकारी को स्वतंत्र रूप से साबित करना होगा।

प्राधिकार पत्र जारी करना:

2.16 प्राधिकार पत्र/लाइसेंस/प्रमाणपत्र/अनुमति पत्र/सीसीपी की वैधता अवधि

जारी होने की तिथि से आयात/निर्यात प्राधिकार पत्र की वैधता इस प्रकार होगी जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो:-

क्र.सं.	प्राधिकार पत्र का प्रकार	वैधता अवधि
(i)	प्रतिबंधित (गैर-स्कोमेट) माल के लिए निर्यात प्राधिकार पत्र	12 माह
(ii)	स्कोमेट मर्च के लिए निर्यात प्राधिकार पत्र	24 माह
(iii)	प्रतिबंधित मर्च और सीसीपी के लिए आयात प्राधिकार पत्र	18 माह
(iv)	ईपीसीजी प्राधिकार पत्र	18 माह
(v)	मान्य निर्यात हेतु अग्रिम प्राधिकार पत्र (एए)	परियोजना कार्यान्वयन की संविदा अवधि के साथ समाप्त अथवा 12 महीने, जो भी अधिक हो।
(vi)	विदेश व्यापार नीति के अध्याय 4 के अनुसार रत्न एवं आभूषणों के लिए प्राधिकार पत्र (उपर्युक्त (v) को छोड़कर), शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार पत्र और प्रतिपूर्ति प्राधिकार पत्र।	जारी होने की तारीख से न्यूनतम 12 महीने।

तथापि एकजिम सुविधा समिति (ईएफसी) (गैर-स्कोमेट वस्तुओं हेतु) और अंतर मंत्रालयी कार्य दल (आईएमडब्ल्यूजी) अनुबंध संबंधी दायित्व/डिलीवरी शेड्यूल को पूरा करने के लिए या संबंधित तकनीकी/प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग/या अन्य किसी एजेंसी की विशिष्ट सिफारिश पर अल्पावधि/दीर्घावधि के लिए निर्यात प्राधिकार पत्र जारी करने का अनुमोदन दे सकते हैं।

(ख) विदेश व्यापार महानिदेशालय दीर्घकालिक/अल्पकालिक वैधता अवधि हेतु विशिष्ट प्राधिकार पत्र/प्राधिकार पत्रों की श्रेणी जारी करने का निर्णय ले सकता है। इन मामलों में किसी विस्तार/पुनर्वैधीकरण की अनुमति डीजीएफटी ही दे सकता है।

2.17 आयात/निर्यात की गणना की तारीख

(क) आयात की गणना की तारीख प्रक्रिया पुस्तक के पैराग्राफ 9.11 में यथाउल्लिखित आपूर्तिकर्ता देश से माल के पोतलदान/प्राण की तारीख से निर्धारित की जाती है न कि भारतीय पत्तन पर माल पहुंचने की तारीख से।

(ख) प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 9.12 में यथा उल्लिखित भारत से माल के पोतलदान/प्रेषण की तारीख के संदर्भ में निर्यात की

गणना की तारीख का निर्णय किया जाता है। तथापि, विदेश व्यापार नीति के तहत लाभ के लिए अनुमत निर्यात आदेश (एलईओ) की तारीख निर्यात की गणना की तारीख होगी।

2.18 आयात/निर्यात के लिए प्राधिकार पत्र/लाइसेंस की वैधता

(क) प्राधिकार पत्र आयात की तारीख को वैध होने चाहिए।

(ख) इसी प्रकार, प्राधिकार पत्र की निर्यात दायित्व अवधि निर्यात की तारीख को वैध होनी चाहिए।

2.19 स्क्रिप की वैधता

अध्याय-3 और 5 के तहत स्क्रिप्स उस तारीख को वैध होने चाहिए जिस तारीख को शुल्क का वास्तविक डेबिट किया गया हो।

2.20 गैर-स्कोमेट और स्कोमेट मदों के लिए आयात/निर्यात लाइसेंस प्रमाण पत्र/प्राधिकार पत्र/अनुमति का पुनः वैधीकरण

(क) संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी गुणावगुण के आधार पर आयात प्राधिकार पत्र की वैधता अवधि समाप्त होने पर इसका 6 महीनों के लिए पुनःवैधीकरण कर सकता है।

(ख) स्कोमेट मदों सहित अन्य मदों के निर्यात प्राधिकार पत्रों का पुनर्वैधीकरण संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा एक बार के लिए छः माह और अधिकतम 12 माह तक की अवधि के लिए योग्यता आधार पर प्रक्रिया पुस्तक पैरा 2.16 (ख) में दिए गए मामलों को छोड़कर किया जा सकता है।

(ग) तथापि, मुक्त रूप से हस्तांतरणीय प्राधिकार पत्र/शुल्क क्रेडिट स्क्रिप्स और स्टॉक तथा बिक्री (स्कोमेट मदों को छोड़कर) प्राधिकार पत्र के पुनर्वैधीकरण की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि इनकी वैधता सीमाशुल्क प्राधिकारी/क्षेत्रीय प्राधिकारी/सरकारी प्राधिकारी के पास होते हुए ही समाप्त न हो गयी हो।

(घ) प्राधिकार पत्र/ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप का पुनर्वैधीकरण भी विलम्ब की अवधि (अवधि जिसके लिए प्राधिकार पत्र/स्क्रिप धारक उसका उपयोग करने में असमर्थ रहा) या छः महीने, जो भी कम हो, के लिए कोई शुल्क लिए बिना निम्नलिखित कारणों से अनुमत होगा:

(i) यदि प्राधिकार पत्र/स्क्रिप या उसमें किसी संशोधन को निर्गम/संशोधन की तारीख से 15 कार्य दिवसों के भीतर सीमा शुल्क सर्वरों पर प्रेषित नहीं किया गया हो;

(ii) यदि सीमाशुल्क सर्वर द्वारा त्रुटि कोड के साथ प्राधिकार पत्र/स्क्रिप अस्वीकार किया गया हो;

(iii) यदि बांड/ईओडीसी की छूट जारी करने हेतु अनुरोध पर प्रक्रिया पुस्तक, 2015-2020 के पैरा 9.10 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर विचार नहीं किया गया हो जहां पूर्ण दस्तावेज प्राधिकार पत्र वैधता के भीतर प्रस्तुत किया गया है।

ऐसे मामलों में पुनर्वैधीकरण विलम्ब की अवधि के लिए पृष्ठांकन की तारीख अथवा छः माह के लिए, जो भी कम हो, से अनुमत होगा। उदाहरण के लिए, प्राधिकार पत्र दिनांक 01.04.2017 को 12 माह की प्रारंभिक वैधता के साथ जारी किया गया है। इसे सीमाशुल्क के सर्वर में डीजीएफटी के सर्वर द्वारा 01.04.2017 को प्रेषित किया गया परन्तु सीमाशुल्क के सर्वर द्वारा इसे 31/10/2017 को स्वीकार किया गया। इस प्रकार, प्राधिकार पत्र धारक को 7 माह (अभी भी 5 माह की वैधता शेष है) का नुकसान हुआ। ऐसे मामले में क्षेत्रीय प्राधिकारी पृष्ठांकन की तारीख से 6 माह (5 माह की वैधता को शामिल कर लिया गया है) की अवधि के लिए पुनर्वैधीकरण की अनुमति देगा।

आवेदक अपने दावे के समर्थन में डीजीएफटी के सर्वर के साथ-साथ सीमाशुल्क के सर्वर के स्क्रीन शॉट के साथ प्राधिकार-पत्र/स्क्रिप के पृष्ठांकन के लिए आवेदन प्रस्तुत करेगा। क्षेत्रीय प्राधिकारी पुनर्वैधीकरण की अनुमति देने से पहले इसका सत्यापन करेगा।

तथापि, आवेदन सीमाशुल्क के सर्वर में प्राधिकार पत्र/स्क्रिप की अंतिम स्वीकृति की तारीख से एक माह के भीतर संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को अवश्य प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

उपर्युक्त निहित किसी बात के बावजूद पुनर्वैधीकरण के ये प्रावधान वहां लागू नहीं होंगे जहां प्राधिकार पत्र/स्क्रिप धारक के पास इसके उपयोग के लिए स्पष्ट रूप से छह माह उपलब्ध था।

2.21 पुनः वैधीकरण का प्राधिकारी

पैरा 2.20 के तहत ऐसे पुनः वैधीकरण की अनुमति संबंधित कार्यालय प्रमुख के विशेष आदेशों के तहत दी जाएगी तथा ऐसे पुनः वैधीकरण परिरक्षा अवधि तक सीमित होगी।

2.22 पुनः वैधीकरण के लिए आवेदन

प्राधिकार पत्र के पुनः वैधीकरण के लिए आवेदन संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जा सकता है। क्षेत्रीय प्राधिकारी विदेश व्यापार नीति/प्रक्रिया पुस्तक के अनुसार ऐसे आवेदन पर विचार करेगा। जहां विदेश व्यापार महानिदेशक संबंधित प्राधिकारी हैं, वहाँ मूल आवेदन पत्र संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारियों को प्रस्तुत करना होगा और उसकी एक स्वसत्यापित प्रति महानिदेशक, विदेश व्यापार को प्रस्तुत करनी होगी।

डुप्लीकेट प्रतियां जारी करने की प्रक्रिया:

2.23 निर्यात/आयात प्राधिकार पत्र की डुप्लीकेट प्रतियाँ

जब कोई प्राधिकार पत्र/अनुमति पत्र/सीसीपी/लाइसेंस/प्रमाण पत्र खो जाता है, या गुम हो जाता है तो **परिशिष्ट-2ड** में दिए गए फार्म में, स्व-घोषणा पत्र की प्रति के साथ उस क्षेत्रीय प्राधिकारी को उसकी डुप्लीकेट प्रतिलिपि जारी करने के लिए आवेदन किया जा सकता है जहां मूल लाइसेंस जारी किया गया था।

2.24 मुक्त रूप से हस्तांतरणीय प्राधिकार पत्र की डुप्लीकेट प्रति के लिए आवश्यक दस्तावेज

मुक्त रूप से हस्तांतरणीय प्राधिकार पत्र की डुप्लीकेट प्रति निम्नलिखित दस्तावेजों सहित आवेदन के मद्दे जारी की जाएगी:

- (i) बचाए गए शुल्क अथवा शुल्क क्रेडिट (अप्रयुक्त बकाया का) के 10 प्रतिशत के समतुल्य फीस के साथ एक आवेदन पत्र।
- (ii) नुकसान को दर्शाने वाली प्राथमिक सूचना रिपोर्ट (एफ आई आर) की एक प्रति।
- (iii) ऐसे डुप्लीकेट जारी करने के कारण राजस्व की होने वाली क्षति की पूर्ति करने की स्व-घोषणा।

2.25 अपवाद

जब प्राधिकार पत्र सरकारी एजेन्सी द्वारा गुम हो जाता है और इस आशय का प्रमाण प्रस्तुत किया जाता है तो उपर्युक्त पैरा 2.24 के (i) से (iii) तक के दस्तावेज नहीं माँगे जाएंगे। ऐसे मामलों में, पुनः वैधीकरण पृष्ठांकन की तारीख से छः महीनों की अवधि के लिए होगा।

2.26 डुप्लीकेट जारी करने के लिए प्रणाली

संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी, अप्रयुक्त अधिशेष के लिए डुप्लीकेट जारी करने से पूर्व पंजीकरण के पत्तन पर सीमाशुल्क प्राधिकारी से ऐसे प्राधिकार पत्र के उपयोग से संबंधी रिपोर्ट प्राप्त करेगा।

2.27 डुप्लीकेट प्राधिकार पत्र की वैधता

डुप्लीकेट प्राधिकार पत्र की वैधता मूल अवधि के साथ समाप्त होगी। यदि वैधता समाप्त हो गई हो तो किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

2.28 प्रावधान की अनुप्रयोज्यता

पैरा 2.26 तथा 2.27 के प्रावधान, पैरा 2.23 तथा 2.24 दोनों में शामिल मामलों में लागू होंगे।

बैंक गारंटी/एल्यूटी:

2.29 अग्रिम प्राधिकार पत्र/ई पी सी जी प्राधिकार पत्र के लिए बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता का निष्पादन

(क) सीमा शुल्क कार्यालय द्वारा माल की निकासी से पूर्व, प्राधिकार पत्र धारक को सीमा शुल्क प्राधिकारियों के साथ एक बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता निष्पादित करनी होगी। ऐसे मामलों में, लाइसेंस/प्राधिकार पत्र पर क्षेत्रीय प्राधिकारी निम्नलिखित शर्तें पृष्ठांकित करेगा:

"यथा लागू बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता को संबंधित सीमा शुल्क प्राधिकारियों के साथ निष्पादित करना होगा।"

(ख) स्वदेशी स्रोतों से माल की प्राप्ति के मामले में, प्राधिकार पत्र धारक समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क परिपत्र संख्या 58/2004 दिनांक 31-10-04 के अनुसार, क्षेत्रीय प्राधिकारी को बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता प्रस्तुत करेगा। यदि, फर्म ने सीमाशुल्क प्राधिकारियों को लाइसेंस/प्रमाणपत्र/प्राधिकार पत्र/अनुमति पत्र (स्वदेशी स्रोतों से प्राप्त मर्दों सहित) के कुल मूल्य के लिए पहले ही बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता निष्पादित कर दी है और क्षेत्रीय प्राधिकारी को उसका प्रमाण प्रस्तुत कर दिया है तो क्षेत्रीय प्राधिकारी को बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता निष्पादित करने की आवश्यकता नहीं होगी। संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी प्राधिकार पत्र पर पृष्ठांकित करेगा कि सीमाशुल्क प्राधिकारी संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाणपत्र या ईओडीसी की प्राप्ति के बाद ही बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता को जारी/विमुक्त करेगा। क्षेत्रीय प्राधिकारी उसकी एक प्रति अग्रेषण पत्र के साथ पंजीकरण के पत्तन पर सीमाशुल्क प्राधिकारी के पास उसकी सूचना एवं रिकार्ड के लिए भेजेगा।

2.30 कारपोरेट गारंटी

इस संबंध में, संबद्ध सीमा शुल्क परिपत्र के प्रावधानों के अनुसार स्तर धारक अथवा पीएसयू बैंक गारंटी/एल्यूटी के बदले में कारपोरेट गारंटी भी प्रस्तुत कर सकते हैं।

2.31 अग्रिम भुगतान

यदि भुगतान पहले प्राप्त हो जाता है और निर्यात/मान्य निर्यात बाद में किया जाता है तो प्राधिकार पत्र के लिए आवेदन आगामी माह के लिए विशिष्ट अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा जिस माह के दौरान निर्यात/मान्य निर्यात किया गया हो, जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न किया गया हो।

2.32 पट्टा वित्तीयन के तहत आयात

ई ओ यू/एस ई जैड, स्कीम के अन्तर्गत पट्टा वित्तीयन के तहत आयात उपलब्ध होगा। मान्य निर्यात की पात्र श्रेणियों के पूंजीगत माल के घरेलू आपूर्तिकर्ता, ऐसे मामलों में भी जहां आपूर्ति, पट्टा वित्तीयन के तहत की गई है, विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 7.03 में यथाउल्लिखित मान्य निर्यात लाभों के हकदार होंगे।

दस्तावेजों के खो जाने के मामले में:

2.33 पोतलदान बिलों की ई पी प्रति खो जाने पर स्क्रिप जारी करना

यदि पोतलदान बिल की ई पी प्रति खो जाती है तो अध्याय 3 और अध्याय 5 के तहत स्क्रिप्स दावे के बारे में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने की शर्त पर विचार किया जाएगा:-

- i) मूल दस्तावेज के बदले सीमा शुल्क प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए संगत दस्तावेज की डुप्लीकेट/प्रमाणित प्रति;
- ii) सम्बद्ध हकदारी के 2 प्रतिशत के बराबर आवेदन शुल्क। तथापि, सरकारी अभिकरणों द्वारा ये दस्तावेज गुम करने पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा और इस आशय का दस्तावेजी सबूत प्रस्तुत किया गया है;
- iii) निर्यातक द्वारा दस्तावेज खो जाने के बारे में स्व-घोषणा पत्र और यह वचनबद्धता कि यदि बाद में यह मिल जाता है तो इसे तत्काल संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को वापिस कर दिया जाएगा।
- iv) निर्यातक द्वारा इस आशय का स्व-घोषणा पत्र कि गुम हो गए पोतलदान बिलों के मद्दे जारी ड्यूटी क्रेडिट के कारण यदि कोई वित्तीय हानि होती है तो वह सरकार को क्षतिपूर्ति करेगा। निकासी की अनुमति देने से पहले, सीमा-शुल्क प्राधिकारी, यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे पोतलदान बिल के मद्दे लाभ/ड्यूटी क्रेडिट का उपयोग नहीं किया गया है।

2.34 पोतलदान बिल की गुम हुई प्रति के लिए दावा

पोतलदान बिल गुम होने के मद्दे दावा पोतलदान बिल की डुप्लीकेट प्रति जारी होने की तारीख से छह महीनों की अवधि के भीतर पेश करना होगा। इस अवधि के बाद प्राप्त आवेदन को अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

2.35 दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत करना

जहां मूल दस्तावेज भिन्न क्षेत्रीय प्राधिकारी/नामित एजेंसियों या उसी क्षेत्रीय प्राधिकारी के भिन्न प्रभाग को सौंपे गए हैं, आवेदक मूल प्रति के एवज में विधिवत रूप से स्वप्रमाणित दस्तावेजों की प्रतियां प्रस्तुत कर सकता है।

गोदाम की सुविधा:

2.36 गोदामों की सुविधा

(क) विदेश व्यापार नीति के पैरा 2.36 के अनुसार मदों का आयात करने के लिए सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अध्याय-9 के अनुसार घरेलू प्रशुल्क क्षेत्रों में सार्वजनिक/निजी सीमाशुल्क बाण्डेड गोदाम स्थापित किये जा सकते हैं। माल की प्राप्ति पर, ऐसे गोदाम इस माल को यथा लागू सीमाशुल्क का भुगतान किए बिना एक वर्ष की अवधि के लिए रख सकेंगे। घरेलू उपभोग के लिए सक्षम सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा जारी ऐसे माल की निकासी के आदेश के बाद, सीमाशुल्क का भुगतान करने पर घरेलू उपभोग के लिए आगम-पत्र और प्राधिकार पत्र की प्रस्तुति, जहाँ कहीं आवश्यक हो, के माल की निकासी की जा सकती है। शुल्क मुक्त श्रेणियों/शुल्क रियायत श्रेणियों के मद्दे निपटान के मामलों में, शुल्क में छूट/रियायत, की अनुमति दी जा सकती है।

(ख) सीमाशुल्क का भुगतान किए बिना माल का पुनः निर्यात किया जा सकता है बशर्ते कि ऐसे माल के मामले में शिपिंग बिल या निर्यात बिल प्रस्तुत किया गया हो; और ऐसे माल का निर्यात करने के लिए सक्षम सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा आदेश दिया गया हो।

प्रमाण पत्र:

2.37 मुक्त बिक्री और वाणिज्य प्रमाणपत्र

(क) (i) क्षेत्रीय प्राधिकारी, आवेदन करने पर, अस्पताल, नर्सिंग होम और क्लीनिक आदि में प्रयोग होने वाले चिकित्सीय और

शल्य उपकरणों के लिए, औषध और प्रसाधन अधिनियम, 1940 के तहत न आने वाली निर्यात की मदों के लिए और जो निर्यात के लिए प्रतिबंधित नहीं है उनके लिए मुक्त बिक्री और वाणिज्य प्रमाणपत्र भी जारी कर सकता है। ऐसे प्रमाणपत्र की वैधता जारी होने की तारीख से दो वर्ष तक होगी जबकि अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो।

(ii) मुक्त बिक्री और वाणिज्य प्रमाणपत्र के लिए आवेदन परिशिष्ट और आयात निर्यात प्रपत्र के एएनएफ-2ज में दिए गए प्रपत्र में अनुलग्नक क सहित संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी के पास जमा किया जा सकता है। क्षेत्रीय प्राधिकारी एएनएफ-2ज के अनुलग्नक ख के अनुसार मुक्त बिक्री और वाणिज्य प्रमाणपत्र जारी करेगा।

(ख) (i) क्षेत्रीय प्राधिकारी आवेदन करने पर अन्य किसी भी मद का निर्यात जो प्रतिबंधित या निषिद्ध नहीं है उनके लिए मुक्त बिक्री और वाणिज्य प्रमाण-पत्र भी जारी कर सकता है। ऐसे प्रमाण पत्र की वैधता जारी होने की तारीख से दो वर्ष तक होगी जबकि अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो।

(ii) इन मदों के लिए मुक्त बिक्री और वाणिज्य प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन परिशिष्ट और आयात निर्यात प्रपत्र के एएनएफ-2ज में दिए गए प्रपत्र में अनुलग्नक 'क' सहित संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी के पास जमा किया जा सकता है। क्षेत्रीय प्राधिकारी एएनएफ-2ज के अनुलग्नक 'ख' के अनुसार मुक्त बिक्री और व्यापार प्रमाण पत्र जारी करेगा।

2.38 वास्तविक प्रयोक्ता प्रमाण पत्र

भारत में किसी मुक्त आयात की जाने वाली मदों के आयात के मामले में, यदि विदेशी सरकार मद के वास्तविक प्रयोक्ता के प्रमाणन पर बल देती है तो, उनके देश से उसका निर्यात करने से पहले परिशिष्ट और आयात निर्यात प्रपत्र के परिशिष्ट-2थ के अनुसार ऐसा प्रमाणपत्र जारी कर सकता है। यह प्रमाण पत्र एएनएफ-2ज में, निर्धारित दस्तावेजों सहित, किए गए आवेदन के आधार पर जारी किया जायेगा।

2.39 भारत-अमेरिका समझौता ज्ञापन के अन्तर्गत आयात

(क) संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) से विशिष्ट पूंजीगत माल, कच्चे माल, संघटकों आदि का आयात संयुक्त राज्य अमेरिका निर्यात नियन्त्रण विनियमों के अधीन किया जाएगा। ऐसी मदों के संयुक्त राज्य अमेरिका के आपूर्तिकर्ताओं को, भारत में जारी आयात प्रमाणपत्र के आधार पर आयात प्राधिकार पत्र प्राप्त करना होगा। आयात प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी (आई.सी.आई.ए.) निम्नलिखित हैं:

(i) कम्प्यूटर तथा कम्प्यूटर पर आधारित सिस्टम के आयात हेतु इलैक्ट्रॉनिक विभाग; (डीओई)

(ii) कम्प्यूटर तथा कम्प्यूटर आधारित सिस्टम को छोड़कर औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, (डी आई पी पी) प्रौद्योगिकी सहायता खण्ड (टी एस डब्ल्यू), के अधीन पंजीकृत संगठित क्षेत्र की यूनिटों के लिए।

(iii) रक्षा से संबंधित मदों के लिए रक्षा मंत्रालय (एमओडी)।

(iv) लघु उद्योग तथा इकाइयाँ जो उपर्युक्त में शामिल नहीं तथा उपर्युक्त में से किसी के लिए विदेश व्यापार महानिदेशालय।

(v) उपर्युक्त किसी की भी ओर से भारतीय दूतावास, वाशिंगटन डी सी।

(ख) आयात प्रमाणपत्र के लिए 'आयात-निर्यात प्रपत्र' -2ट(i) में आवेदन करना होगा। परिशिष्ट-2त (i)क में आयात प्रमाण-पत्र आई.सी.आई.ए. द्वारा सीधे ही आयातक को दिया जाएगा तथा इसकी प्रतिलिपि (i) विदेश मंत्रालय (एमईए) (ए एम एस अनुभाग), नई दिल्ली (ii) इलैक्ट्रॉनिक विभाग, (डीओई) नई दिल्ली, और (iii) विदेश व्यापार महानिदेशालय, नई दिल्ली को भेजी जाएगी।

(ग) तथापि, आयात प्रमाणपत्र को आई टी सी (एच एस) में यथा प्रतिबंधित उल्लिखित मदों के लिए आयात प्राधिकार पत्र को के स्थान पर नहीं माना जाएगा और ऐसी मदों के लिए जब अपेक्षित हो आयात प्राधिकार पत्र प्राप्त करना होगा।

(घ) संयुक्त राज्य अमेरिका के एकपक्षीय निर्यात नियंत्रण मदों [परिशिष्ट 2त (ii) क] में यथा सूचीबद्ध अपराध नियंत्रण (सीसी) मद और परिशिष्ट 2त (ii) ख) में यथा सूचीबद्ध क्षेत्रीय सुरक्षा (आरएस) मद] के संबंध में भारत का आयात और निर्यात निम्नलिखित विनियमनों से अभिशासित होगा:

संयुक्त राज्य अमेरिका से आयात के लिए परिशिष्ट 2त (ii) क) और परिशिष्ट 2त (ii) ख) दोनों में सूचीबद्ध मदें विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा अनुमत होंगी बशर्ते आयातक आयात निर्यात प्रपत्र 2ट(i) में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करें:

(i) संयुक्त राज्य अमेरिका के पत्तन को दर्शाते हुए लदान-पत्र का दस्तावेजी प्रमाण,

(ii) विधिक वचनबद्धता कि माल का निर्यात/हस्तांतरण नहीं किया जाएगा और

(iii) वास्तविक प्रयोक्ता शर्त के साथ आयात किया गया है।

(ड.) यदि आयातक संयुक्त राज्य अमेरिका से आयातित मर्चों या उससे हिस्से का बाद में निर्यात करना चाहता है तो ऐसे निर्यात के लिए आयात निर्यात प्रपत्र 2ट (ii) के अनुसार विदेश व्यापार महानिदेशालय से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता होगी तथा निर्यात प्रमाण-पत्र परिशिष्टि-2त (i ख) प्रपत्र में जारी किया जाएगा।

(च) इन मर्चों का आयात/निर्यात भारत के केवल ईडीआई समर्थित पत्तनों से अनुमत होगा।

आयात:

2.40 उपभोक्ता अथवा अन्य माल का उपहार के रूप में आयात

(क) विदेश व्यापार नीति के पैरा 2.25 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार, आई टी सी (एच एस) में आयात के लिए प्रतिबंधित स्तर में उल्लिखित मर्चों का उपहार के रूप में आयात के लिए सीमाशुल्क निकासी परमिट की मंजूरी हेतु आवेदन पत्र विदेश व्यापार महानिदेशक को निर्धारित दस्तावेजों के साथ आयात निर्यात प्रपत्र 2ड में दिए प्रपत्र में प्रस्तुत करना होगा।

(ख) जहां उपहार का प्राप्तकर्ता लागू कानून के अधीन पंजीकृत धर्मार्थ, धार्मिक अथवा एक शैक्षिक संस्थान हैं और आयात किए जाने वाले उपहार को सीमाशुल्क के भुगतान से छूट दी गई है, ऐसा आयात सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा सीमाशुल्क निकासी अनुज्ञा पत्र के बिना अनुमत होगा।

2.41 चैक बुक/टिकट फार्म आदि का आयात

विदेशी बैंकों, बीमा कम्पनियों तथा ट्रेवल एजेंसियों की भारतीय शाखाओं द्वारा चैक बुक, बैंक ड्राफ्ट फार्म तथा ट्रेवेलर चैक फार्मों का सीमाशुल्क निकासी परमिट के बिना आयात किया जा सकता है। इसी प्रकार, भारत में कार्यरत एअरलाइन्स/शिपिंग कम्पनियाँ, जिनमें इन एअरलाइन्स/शिपिंग कम्पनियों द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति भी शामिल हैं, सीमाशुल्क निकासी परमिट के बिना पैसेंजर्स टिकट फार्मों का आयात कर सकती है।

2.42 वायुयान के रीकंडीशनड/ पुराने कल पुर्जों का आयात

नागर विमानन महानिदेशक, भारत सरकार (डीजीसीए) की सिफारिशों पर वायुयान के रीकंडीशनड/ पुराने कलपुर्जों के लिए आयात प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

2.43 प्रतिस्थापन माल का आयात

सामान और उसके पुर्जे आयात करने पर खराब या अन्यथा उपयोग के लिए उपयुक्त न हो अथवा जो आयात करने के बाद नैट हो गये हों, उनका प्राधिकार पत्र के बिना निर्यात किया जा सकता है तथा प्रतिस्थापन वाले सामान की विदेशी सप्लायरों द्वारा बिना प्रभार की आपूर्ति की जा सकती है या समुद्री बीमा के प्रति आयात अथवा बीमा कम्पनी द्वारा निपटाये गए समुद्री सह निर्माण बीमा दावों का निपटान के विरुद्ध आयात किया जा सकता है। ऐसे सामान का सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा आयात प्राधिकार पत्र के बिना निकासी करने की अनुमति होगी बशर्ते कि:

(क) सीमाशुल्क द्वारा पिछले आयातित सामान की निकासी की तारीख से 24 माह के भीतर प्रतिस्थापन माल का पोतलदान किया जाता है अथवा मशीन या उसके कलपुर्जों के मामलों में, जहाँ 24 माह से अधिक समय लग गया है, गारंटी अवधि के भीतर ऐसा किया जाता है; और

(ख) आयातक द्वारा किए गए बीमा और/अथवा भाड़े के भुगतान के अधीन विदेशी आपूर्तिकर्ता द्वारा सामान की प्रतिपूर्ति पर बीमा और भाड़े के भुगतान को छोड़कर कोई प्राँण शुल्क अनुमत नहीं होगा और प्रेषण शुल्क देते समय इस प्रयोजन का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा।

2.44 प्रतिस्थापन माल के आयात की अन्य शर्तें

(क) ऐसे मामलों में जहाँ माल पोत में कम चढ़ाया, कम उतारा गया पाया जाए या आवाजाही में गुम पाया जाए, प्रतिस्थापन माल का आयात, सीमाशुल्क प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र के आधार पर बिना किसी आयात प्राधिकार पत्र के अनुमत होगा।

(ख) यह प्रक्रिया उस मामले में भी लागू होगी जहाँ विदेशी आपूर्तिकर्ता द्वारा पोत में सामान के कम लदान को प्रमाणित किया जाता है और वह सामान मुफ्त बदलने के लिए तैयार है।

(ग) जो मामले उपर्युक्त प्रावधानों में शामिल नहीं होते हैं उनके संबंध में वस्तुओं के प्रतिस्थापन के लिए प्राधिकार पत्र की मंजूरी हेतु विदेश व्यापार महानिदेशक द्वारा गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाएगा, जिसके लिए आवेदन पत्र प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 2.50 के अनुसार प्रस्तुत करने होंगे।

2.45 विदेशी कार्यालय उपकरणों का आयात

भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन से स्थापित समुद्रपारीय कार्यालयों को बंद करने पर, प्रयुक्त कार्यालय उपकरणों और अन्य मदों का आयात प्राधिकार पत्र के बिना किया जा सकता है।

2.46 लाइसेंसधारी/प्राधिकृत हथियार व्यापारियों द्वारा हथियारों का आयात

(क) लाइसेंसधारी हथियार व्यापारियों द्वारा प्राधिकार पत्र के मद्दे निम्नलिखित प्रकार के हथियारों का आयात अनुमत है बशर्ते कि यह यथाविनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करता हो :

(i) शाटगन कार्टरिज 28, बोर के;

(ii) रिवाल्वर कार्टरिज .450, .455 और .45 बोर के;

(iii) पिस्टल कार्टरिज .25, .30 माउजर, .450 और .45 बोर के;

(iv) राइफल कार्टरिज 6.5 एम एम, .22 सेवेज, .22 हार्नेट, 300 शेखुड, 32/40, .256, .275, .280, 7 एम/ एम माउजर, 7 एम/एम मैनस्कूनर, 9 एम/एम माउजर, 9 एम/एम मैनस्कूनर, 8x57, 8x57 एस, 9.3 एम/एम, 9.5 एम/एम, .375 मैगनम, .405, .30.06, .270, .30/30 विंच, .318, .33 विंच .275 मैग, .350 मैग, 400/350, .369 पुरडे, .450/400, .470, .32 विन .458 विन, .380 रूक, .220 स्वीफ्ट और .44 विन बोर्स के।

(ख) आयात प्राधिकार पत्र विगत 3 लाइसेंसिंग वर्षों के दौरान गोला बारूद के वार्षिक औसत बिक्री कारोबार (देशी अथवा आयातित) के मूल्य के 5 प्रतिशत मूल्य तक दिया जाएगा बशर्ते कि यह न्यूनतम 2000/- रुपये से कम न हो।

(ग) उपर्युक्त पैरा में दी गई मदों के लिए प्राधिकार पत्र हेतु आवेदन उसमें विहित निर्धारित दस्तावेजों के साथ आयात-निर्यात फार्म-2ड में क्षेत्रीय प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जा सकता है।

2.47 विशिष्ट क्षेत्र के लिए शुल्क मुक्त आयातः

(क) भेषज और जैव-प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए अनुसंधान और विकास उपकरण

(i) पिछले लाइसेंसिंग वर्ष के दौरान निर्यात के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 25 प्रतिशत तक वस्तुओं (समय-समय पर यथा संशोधित सीमा-शुल्क अधिसूचना सं0 21/2012 दिनांक-17.03.2012 की सूची 28 में यथा निर्दिष्ट) के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी जाएगी।

(ii) पात्र यूनिट परिशिष्ट-8क में दिए अनुसार चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा विधिवत् प्रति-हस्ताक्षरित आवेदन-पत्र संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

(iii) अनुसंधान और विकास उपकरण के शुल्क मुक्त आयात के मामले में उन यूनिटों को स्वतंत्र सनदी अभियंता द्वारा जारी अधिष्ठापन प्रमाण-पत्र देने की अनुमति होगी जो क्षेत्राधिकार प्राप्त सीमा शुल्क प्राधिकारियों के पास पंजीकृत नहीं हैं।

(ख) खाद्य-रसायन क्षेत्र:-

(i) कृषि रसायन क्षेत्र यूनिट जिनका पिछले लाइसेंसिंग वर्ष के दौरान निर्यात कारोबार 20 करोड़ रुपये या अधिक है को पिछले लाइसेंसिंग वर्ष के दौरान किए गए निर्यात के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 1 प्रतिशत तक, सीमाशुल्क अधिसूचना संख्या 21/2012 दिनांक 17-03-2012 की सूची 28क में यथा निर्दिष्ट माल के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति होगी।

(ii) पात्र यूनिट परिशिष्ट-8ख में दिए गए चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा विधिवत् प्रतिहस्ताक्षरित आवेदन- पत्र संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगी।

(iii) जो यूनिटें क्षेत्राधिकार प्राप्त सीमा शुल्क प्राधिकारियों के पास पंजीकृत नहीं हैं उन्हें अनुसंधान एवं विकास उपकरण के शुल्क मुक्त आयात के संबंध में स्वतंत्र सनदी अभियंता द्वारा जारी अधिष्ठापन प्रमाण पत्र देने की अनुमति होगी।

2.48 एक सरकार से दूसरी सरकार के समझौतों के अन्तर्गत आयात

एक सरकार से दूसरी सरकार के समझौतों के अन्तर्गत माल का आयात, सीमाशुल्क प्राधिकारियों को उनकी संतुष्टि के अनुसार आवश्यक साक्ष्य प्रस्तुत करने पर प्राधिकार पत्र या सीमाशुल्क निकासी परमिट के बिना अनुमत किया जा सकता है।

2.49 आयातित माल का हस्तांतरण**(क) ऐसे मामले जहाँ पूर्व अनुमति प्राप्त करना अपेक्षित है:-**

ऐसे आयातित माल, जो वास्तविक प्रयोक्ता शर्तों के अधीन हैं और वास्तविक उपयोक्ता की आवश्यकता से अधिक है, का हस्तांतरण केवल संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से किया जा सकता है। सहायक दस्तावेजों के साथ निम्नलिखित सूचना, हस्तांतरण के लिए मंजूरी के अनुरोध सहित, सम्बंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को प्रस्तुत करनी होगी :-

- (i) आयातित सामग्री के हस्तांतरण के कारण;
- (ii) जिसको हस्तांतरित किया जाना है उस व्यक्ति का नाम, पता, आयातक-निर्यातक कोड संख्या तथा औद्योगिक प्राधिकार पत्र पंजीकरण, यदि कोई हो;
- (iii) आयातित माल का विवरण, मात्रा और मूल्य तथा जिसका हस्तांतरण करने की अनुमति मांगी गई है;
- (iv) किए गए आयात से संबंधित आयात प्राधिकार पत्र और आगमपत्र की प्रतियां;
- (v) क्रेता और विक्रेता के बीच हस्तांतरण की शर्तें जिस पर सहमति बनी है।

(ख) ऐसे मामले जहाँ पूर्व अनुमति प्राप्त करना अपेक्षित नहीं है:-

- (i) मुक्त रूप से आयातित माल के आयातक द्वारा बिक्री अथवा अन्यथा के मामले में।
- (ii) वास्तविक प्रयोक्ता शर्त सहित आयातित माल हेतु, बशर्ते ऐसा माल हस्तांतरण की वास्तविक प्रयोक्ता शर्त के बिना मुक्त रूप से आयातित हो।
- (iii) आयात की तिथि से दो वर्ष की अवधि के पश्चात वास्तविक प्रयोक्ता शर्त वाले माल हेतु।
- (iv) आयातित आग्नेयशस्त्रों के हस्तांतरण हेतु, (क) आयात 10 वर्ष बाद अथवा (ख) आयातक के 60 की आयु प्राप्त कर लेने पर, बशर्ते कि अंतरिती अस्त्र-शस्त्र अधिनियम और उसके अधीन बन नियमों में दी गई शर्तें पूरी करता हो।
- (v) प्रसिद्ध निशानेबाजों (जिन्हें आईटीसी (एचएस) 2017 के अध्याय 93 की नीति शर्त 3 में यथा परिभाषित) के लिए आयातित हथियार (आग्नेयशस्त्रों) के

हस्तांतरण जो किसी उभरते निशानेबाज के खेल के क्षेत्र में निशानेबाजी करने के उद्देश्य हेतु या राष्ट्रीय रायफल एसोसिएशन आफ इण्डिया (एनआरएआई) अथवा खेल विभाग, युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय द्वारा आयात के दो वर्ष पश्चात प्रमाणित किया जाना चाहिए। तदुपरांत हस्तांतरिती पहली बिक्री की तिथि से एक वर्ष के पश्चात निशानेबाजी को जारी रखने के एकमात्र उद्देश्य हेतु एनआरएआई अथवा खेल विभाग द्वारा प्रमाणित किए जाने पर किसी खरीददार को हस्तांतरित/पुनः बेच सकता है। ऐसा हस्तांतरण/बिक्री शस्त्र अधिनियम, 1959 तथा राज्य/स्थानीय पुलिस द्वारा लागू अन्य नियमों/विनियमों के प्रावधानों के अधीन होगा। एनआर-एआई/खेल विभाग अपेक्षित रिकार्ड का रखरखाव करेंगे।

प्रतिबंधित मदों का आयात:**2.50 'प्रतिबंधित' मदों का आयात**

आईटीसी (एचएस) में "प्रतिबंधित" के रूप में उल्लिखित मदों के आयात या निर्यात के लिए प्राधिकार पत्र की मंजूरी हेतु आवेदन पत्र, एएनएफ-2ड में निर्धारित दस्तावेजों सहित डीजीएफटी मुख्यालय को एक प्रति भेजते हुए क्षेत्रीय प्राधिकरण को भेजा जा सकता है। वास्तविक आवेदन को कौागार रसीद/डिमांड ड्राफ्ट के साथ संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जाना चाहिए तथा इसकी स्वःअभिप्रमाणित दूसरी प्रति संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकरण को प्रस्तुत आवेदन के प्रमाण सहित डीजीएफटी को भेजी जानी चाहिए।

2.51 निर्यात आयात सुविधा समिति

- (क) प्रतिबंधित मद प्राधिकार पत्र विदेश व्यापार महानिदेशक या उनकी ओर से इस संबंध में प्राधिकृत कोई अन्य क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा दिया जा सकता है। विदेश व्यापार महानिदेशालय/क्षेत्रीय प्राधिकारी, प्राधिकार पत्र देते समय सुविधा समिति की सहायता और सलाह ले सकते हैं। तकनीकी प्राधिकारियों से भी लिखित में सलाह लेकर सहायता ली जा सकती है। सुविधा समिति में संबंधित तकनीकी प्राधिकरणों और विभागों/मंत्रालयों के प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे।

- (ख) यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा निदेश दिया जाता है तो प्रतिबंधित मद के लिए आयात प्राधिकार पत्र, आवेदक द्वारा लिखित रूप से बताये गये विकल्प के अनुसार किसी पत्तन या हवाई अड्डे अथवा आई.सी.डी अथवा एल.सी.एस. के माध्यम से आयात हेतु जारी किये जाएंगे। प्राधिकार पत्र धारक आयात प्राधिकार पत्र को प्राधिकार पत्र में निर्दिष्ट पत्तन पर पंजीकृत करवायेगा और इसके बाद उक्त प्राधिकार पत्र के मद्दे सभी आयात केवल इसी पत्तन के माध्यम से किये जाएंगे जब तक कि प्राधिकार पत्र धारक किसी अन्य विनिर्दिष्ट पत्तन से आयात करने के बारे में संबंधित सीमा शुल्क प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त नहीं कर लेता।
- (ग) निर्यात आयात सुविधा समिति (ईएफसी) सामान्यतः महीने में एक बार बैठक करेगी। जहां मामले को ईएफसी में तकनीकी प्राधिकारियों और संबंधित विभागों/मंत्रालयों से टिप्पणियों के अभाव में आस्थगित कर दिया गया है और तत्पश्चात एजेंसी (एजेंसियों) से बिना किसी भिन्न दृष्टिकोण के अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त हो गया है/हो गए हैं, अध्यक्ष, ईएफसी के अनुमोदन से प्राधिकार-पत्र जारी किया जाएगा और ईएफसी की अनुवर्ती बैठक में कार्योत्तर आधार पर अनुमोदन हेतु मामले को रखा जाएगा।

2.52 होटलों, रेस्तराओं, ट्रेवल एजेंटों, टूर- आपरेटरों और अन्य विनिर्दिष्ट श्रेणियों द्वारा अपेक्षित प्रतिबंधित मदों का आयात

महानिदेशक, पर्यटन, भारत सरकार की सिफारिशों के आधार पर होटलों, रेस्तराओं, ट्रेवल एजेंटों और टूर आपरेटरों द्वारा अपेक्षित आईटीसी(एचएस) में आयात के लिए प्रतिबंधित के रूप में उल्लिखित मदें प्राधिकार पत्र के मद्दे अनुमत होंगी।

(क) महानिदेशक, पर्यटन, भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पर्यटन होटलों सहित होटल, पिछले लाइसेंसिंग वर्ष के दौरान होटल और पर्यटन उद्योग से संबंधित आवश्यक माल के आयात के लिए, विदेशी पर्यटकों से उनके द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा के 25 प्रतिशत मूल्य तक के आयात प्राधिकार पत्र के पात्र होंगे।

(ख) भारत सरकार के पर्यटन महानिदेशक द्वारा मान्यता प्राप्त ट्रेवल एजेंटों, टूर संचालकों, रेस्तराओं तथा पर्यटन परिवहन संचालकों और साहसिक/वन्य जीव जैसे पर्यटन के लिए अन्य यूनिट और कन्वेन्शन यूनिट को गत लाइसेंसिंग वर्ष के दौरान उनके द्वारा अर्जित की गई विदेशी मुद्रा के 10 प्रतिशत मूल्य का आयात प्राधिकार पत्र प्राप्त करने के पात्र होंगे और ऐसे प्राधिकार पत्र ट्रेवल तथा पर्यटन उद्योग को उनकी व्यावसायिक प्रयोग के लिए अपेक्षित कार्यालय एवं अन्य उपकरणों सहित अनिवार्य वस्तुओं, जिनका आयात प्रतिबंधित है उनका आयात करने के लिए दिए जाएंगे।

(ग) पैरा 2.52 (क) तथा 2.52 (ख) के अन्तर्गत किसी भी लाइसेंसिंग वर्ष की आयात हकदारी के लिए पूरी अथवा उसके एक भाग को आगे ले जाया जा सकता है तथा दो आगामी लाइसेंसिंग वर्षों की आयात हकदारी में जोड़ा जा सकता है।

(घ) ऐसी आयातित वस्तुएं विदेश व्यापार महानिदेशालय की अनुमति से 2 वर्षों के बाद हस्तांतरित की जा सकती हैं। आयातित माल के पुनर्निर्यात के मामले में हस्तांतरण के लिए अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। तथापि पुनर्निर्यात, आईटीसी (एचएस) की अनुसूची-II में यथा अपेक्षित सभी शर्तों अथवा लाइसेंस की आवश्यकताओं अथवा अनुमति के अधीन किया जाएगा।

(ङ.) पैराग्राफ 2.52 (क) और 2.52 (ख) के अधीन प्राधिकार पत्र की मंजूरी के लिए आवेदन आयात निर्यात प्रपत्र 2ड में महानिदेशक विदेश व्यापार को निदेशक, पर्यटन विभाग, भारत सरकार के जरिए देना होगा जो इस आवेदनपत्र को अपनी सिफारिश के साथ संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को अग्रणी करेंगे।

2.53 सरकार की यूनिटों द्वारा अनुसंधान एवं विकास के लिए प्रतिबंधित मदों का आयात

अनुसंधान एवं विकास प्रयोजन के लिए जीवित जानवरों को छोड़कर सभी प्रतिबंधित मदों और एस टी ई के माध्यम से अनुमत मदों का आयात सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अनुसंधान और विकास यूनिटों द्वारा प्राधिकार पत्र के बिना किया जा सकता है।

2.54 धात्विक छीजन और स्क्रेप का आयात

किसी प्रकार के धात्विक छीजन, स्क्रेप का आयात इस शर्त के अधीन होगा कि उसमें खतरनाक, जहरीला छीजन, रेडियोएक्टिव दूषित छीजन/स्क्रेप जिसमें रेडियोएक्टिव सामान, किसी प्रकार के हथियार, गोला बारूद, माइन्स, गोलीयों के खोल जिंदा या चला हुआ बारूद या किसी भी प्रकार की अन्य विस्फोटक सामग्री हो चाहे वह प्रयोग की गई हो या नहीं, नहीं होगी।

(क) निम्नलिखित प्रकार के धात्विक छीजन और स्क्रेप का आयात कुछ शर्तों के अधीन होगा, जिनका विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है:

क्र.सं.	एगजिम कोड	मद ब्यौरा
1	72041000	कास्ट आयरन का छीजन और स्क्रेप
2.	72042190	अन्य

3.	72042920	हाई स्पीड स्टील का
4.	72042990	अन्य
5.	72043000	टिन वाले लोहे या स्टील का छीजन और स्क्रेप
6.	72044100	टर्निंग, शेविंग, चिप्स, मिलिंग वेस्ट, सॉ डस्ट, फिलिंग्स, ट्रिमिंग्स और स्टैपिंग्स, चाहे गठ्ठर में हो या नहीं
7.	72044900	अन्य
8.	72045000	दोबारा पिघलने वाले स्क्रेप इनगोट्स
9.	74040012	कॉपर स्क्रेप
10.	74040022	ब्रास स्क्रेप
11.	75030010	निकल स्क्रेप
12.	76020010	ऐल्युमिनियम स्क्रेप
13.	79020010	जिंक स्क्रेप
14.	80020010	टिन स्क्रेप
15.	81042010	मैगनीशियम स्क्रेप

(ख) 'मुक्त रूप' से आयातित (खंडित रूप में) धात्विक छीजन और स्क्रेप का आयात निम्नलिखित शर्तों के अधीन भारत के सभी पत्तनों से अनुमत किया जाएगा:-

(i) माल की निकासी के समय आयातक को सीमा शुल्क प्राधिकारी को परिशिष्ट-2छ में दिए गये किसी भी जाँच और प्रमाणन अभिकरणों से प्राप्त परिशिष्ट-2ज में दिये गये प्रपत्र के अनुसार इस आशय का पोटलदान पूर्व जाँच प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि इस खेप में किसी भी प्रकार के रेडिएशन स्तर के लिए जाँच कर ली गई है और स्क्रेप में प्राकृतिक रूप से आधिक्य में रेडिएशन स्तर (गामा और न्यूट्रान) शामिल नहीं है। यह प्रमाण पत्र स्क्रेप पर अधिकतम रेडिएशन स्तर के साथ बैकग्राउंड रेडिएशन स्तर के मान को दर्शाएगा; और

(ii) आयातक निर्यातक के साथ हुए करार की प्रति प्रस्तुत करेगा जिसमें यह दर्शाया गया हो कि इस खेप में किसी भी रूप में कोई रेडियो एक्टिव दूषित सामग्री नहीं है।

(ग) होदाईडेह, यमन और बंदार अबास, ईरान से आयात केवल खंडित रूप में होगा।

(घ) पैरा 2.54 (क) में उल्लिखित अखंडित, संकुचित और टूटे रूप में धात्विक छीजन और स्क्रेप का आयात निम्नलिखित शर्तों के अधीन किया जाएगा:-

(i) माल की निकासी के समय आयातक को सीमा शुल्क प्राधिकारी को परिशिष्ट-2छ में दिए गये किसी भी जाँच और प्रमाणन अभिकरणों से प्राप्त परिशिष्ट-2ज में दिये गये प्रपत्र के अनुसार इस आशय का पोटलदान पूर्व जाँच प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि इस खेप में किसी भी प्रकार के हथियार, बारूद, माइन्स, शैल्स, कार्ट्रिजेज या किसी भी रूप में विस्फोटक सामग्री चाहे प्रयुक्त हुई हो या नहीं, विद्यमान नहीं है और रेडिएशन स्तर के लिए इस खेप की जाँच कर ली गई है और इसमें प्राकृतिक बैकग्राउण्ड के आधिक्य में रेडिएशन स्तर (गामा और न्यूट्रान) शामिल नहीं है। प्रमाण पत्र में स्क्रेप पर अधिकतम रेडिएशन स्तर के साथ बैकग्राउंड रेडिएशन स्तर के मान को दर्शाया जाएगा।

(ii) आयातित मद (मदें) ऐसे वर्गीकरण के लिए अन्तराष्ट्रीय रूप से स्वीकृत मानदंड के अनुसार धात्विक अपशिष्ट/स्क्रेप/ पुराने दोषपूर्ण है।

(iii) आयातक और निर्यातक के बीच समझौते की प्रति जिसमें यह उल्लेख किया गया हो कि इस खेप में किसी भी प्रकार के हथियार, बारूद, माइन्स, शैल्स, कार्ट्रिजेज, रेडियो एक्टिव कंटेमिनेटेड अथवा अन्य रूप में विस्फोटक सामग्री, चाहे प्रयुक्त हुई हो अथवा नहीं नहीं है।।

(iv) स्क्रेप का आयात केवल निम्नलिखित नामित पत्तनों द्वारा किया जा सकेगा और ईओयू तथा एसईजैड के मामले में भी कोई छूट नहीं दी जाएगी:

1. चेन्नई 2. कोचीन 3. इन्नोर 4. जे.एन.पी.टी. 5. काण्डला 6. मोर्मूगाव 7. मुम्बई 8. न्यू मंगलोर 9. पारादीप 10. तूतीकोरिन 11. विशाखापट्टनम 12. पिपावा 13. मुन्द्रा 14. कोलकाता
- (v) निम्नलिखित शर्तों के अधीन अखंडित धात्विक अपशिष्ट और स्कैप के आयात के लिए केवल प्रविष्टि समुद्री पत्तनों को नामित और अधिसूचित किया जाएगा:
- (i) अखंडित धात्विक स्कैप के आयात के लिए नामित किसी भी समुद्री पत्तन को पर्याप्त सुरक्षा युक्त रेडिएशन पोर्टल मॉनीटर और कंटेनर स्कैनर अधिस्थपित करना होगा। उपर्युक्त पूरा कर लेने वाले समुद्री पत्तन को निरीक्षण और प्रमाणन के लिए क्षेत्राधिकार प्राप्त सीमा शुल्क कार्यालय में सम्पर्क करना होगा। सीमा शुल्क कार्यालय आईआरबी से प्रमाणन प्राप्त कर लेने के बाद आवश्यक मंजूरी प्रदान करेगा। सीमा शुल्क कार्यालय से मंजूरी मिलने के बाद विदेश व्यापार महानिदेशालय ऐसे पत्तन को अखंडित स्कैप के आयात के लिए नामोदिदष्ट पत्तन के रूप में अधिसूचित करेगा।
- (ii) मौजूदा नामोदिदष्ट समुद्री पत्तन नामतः चेन्नई, कोचीन, इन्नोर, जेएनपीटी, कांडला, मोर्मूगांव, मुम्बई, न्यू मंगलोर, पारादीप, तूतीकोरिन, विशाखापट्टनम, पिपावा, मुन्द्रा और कोलकाता को 31 मार्च, 2018 तक अखंडित स्कैप के आयात के लिए अनुमति होगी और तब तक उन्हें रेडिएशन पोर्टल मानीटर और कंटेनर स्कैनर अधिष्ठापित और प्रचालित करना होगा। ऐसे समुद्री पत्तनों जो समय-सीमा का पालन नहीं करते हैं, की 01.04.2018 से अखंडित धात्विक स्कैप के आयात के प्रयोजन हेतु मान्यता रद्द कर दी जाएगी।
- (iii) इसके अलावा, कोई भी आईसीडी अखंडित धात्विक स्कैप की मंजूरी कर सकता है बशर्ते यह उपरोक्त नामोदिदष्ट किसी भी समुद्री पत्तनों या समय-समय पर अधिसूचित/नामोदिदष्ट किए जाने वाले किसी नए पत्तन से गुजरता हो जहां रेडिएशन पोर्टल मानीटर और कंटेनर स्कैनर प्रचालन में है तथा सीमाशुल्क कार्यालय द्वारा निर्धारित प्रोटोकाल के अनुसार खेप जोखिम आधारित स्कैनिंग/मानीटरिंग के अधीन है।
- (iv) उपर्युक्त के बावजूद आयात खेप उद्गम देश से निरीक्षण-पूर्व प्रमाणपत्र के अधीन होंगी। तथापि, अखंडित धातु स्कैप के आयात से जुड़े जोखिम के मूल्यांकन के आधार पर अखंडित धातु स्कैप के आयात की मंजूरी अभिशासित करने वाले उपर्युक्त तंत्र के क्रियान्वयन के साथ पोतलदान-पूर्व निरीक्षण प्रमाणन (पीएसआईसी) की आवश्यकता की समीक्षा की जाएगी।

2.55 पोतलदान पूर्व निरीक्षण एजेंसी (पीएसआईए) को मान्यता देना और पोतलदान-पूर्व निरीक्षण प्रमाण पत्र (पीएसआईसी) जारी करना।

- (क) पीएसआईए के लिए मान्यता हेतु आवेदन आयात निर्यात प्रपत्र 2ठ में निर्धारित प्रपत्र में करना होगा। अनुलग्नकों और दस्तावेजों सहित आयात निर्यात प्रपत्र 2ठ में आवेदन की स्कैन की हुई प्रतिलिपि डाक द्वारा भेजने के अलावा विदेश व्यापार महानिदेशालय को ईमेल (psia-dgft@nic.in पर) द्वारा भेजी जाएगी।
- (ख) भारत में स्थित आवेदकों के लिए आवेदन शुल्क 7500/- रु0 होगा और विदेश में स्थित आवेदकों के लिए आवेदन शुल्क 200 अमेरिकी डालर होगा। विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा समय-समय पर शुल्क में संशोधन किया जा सकता है।
- (ग) अन्तर-मंत्रालयी समिति द्वारा आवेदन-पत्रों पर विचार किया जाएगा।
- (घ) मान्यताप्राप्त पीएसआईए को तीन वर्षों की अवधि के लिए परिशिष्ट-2छ के तहत अधिसूचित किया जाएगा। 3 वर्ष पूरा होने पर पीएसआईए को आगे मान्यता प्राप्त करने के लिए नया आवेदन करना होगा।
- (ङ.) पीएसआईए परिशिष्ट-2ज में दिए गए प्रपत्र में पोत-लदान पूर्व निरीक्षण प्रमाणपत्र (पीएसआईसी) जारी करेगी। पीएसआईसी में पीएसआईए का विशिष्ट रूप से अंकित हॉलोग्राम भी होगा।
- (च) पीएसआईए उन देशों में भी अपने निरीक्षकों की तैनाती करके निरीक्षण कर सकती है जहां इसका पूर्णकालिक सुव्यवस्थित शाखा कार्यालय नहीं है किन्तु जो इसके प्रचालन के क्षेत्र में आता है। तथापि, अन्य देशों में ऐसे निरीक्षणों के लिए पीएसआईए को ईमेल (psia-travel-dgft@gov.in पर) भेजकर तथा निरीक्षक द्वारा किए गए दौर/निरीक्षण का ब्यौरा पीएसआईसी में प्रस्तुत करके विदेश व्यापार महानिदेशालय को पूर्व में सूचित करना होगा।
- (छ) आवेदक आयात निर्यात प्रपत्र-2ठ की कम सं.9 के अंतर्गत यथा अपेक्षित बैंक गारंटी के बिना प्रारंभ में अपने आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। उनके आवेदन-पत्र केवल बैंक गारंटी प्रस्तुत नहीं करने के आधार पर अस्वीकार नहीं किए जाएंगे। तथापि, आवेदकों को विदेश व्यापार नीति/प्रक्रिया पुस्तक, 2015-20 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा उन्हें पीएसआईए के रूप में अधिसूचित किए जाने से पूर्व बैंक गारंटी या कोई समतुल्य वित्तीय दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

2.56 पीएसआईए और आयातक की जिम्मेवारी और देयता

- (क) पीएसआईए में गलत घोषणा या पीएसआईए के रूप में मान्यता के लिए आवेदन-पत्र में गलत घोषणा के मामले में पीएसआईए पर मान्यता के निलंबन/निरस्तीकरण के अलावा यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
- (ख) आयातक और निर्यातक संयुक्त रूप से तथा अलग-अलग यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेवार होंगे कि आयात की गई सामग्री पीएसआईसी में की गई घोषणा के अनुसार है। किसी गलत घोषणा के मामले में उनपर यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
- (ग) पीएसआईए को पीएसआईसी की स्कैन की हुई प्रतिलिपि (पीडीएफ फॉर्मेट में) को डीजीएफटी की वेबसाइट पर अपलोड करना होगा और ईमेल (psia-dgft@gov.in पर) करना होगा। यह प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र **परिशिष्ट-2ज** में जारी किया जाएगा।
- (घ) पीएसआईए को निम्नलिखित कार्यकलापों/ब्यौरों को विधिवत रूप से कैप्चर करते हुए किए गए निरीक्षण का फोटोग्राफ लेना होगा या वीडियो बनाना होगा:
- निरीक्षण का समय, तारीख के साथ पीएसआईए निरीक्षक (अनिवार्य) और निर्यातक/आयातक का प्रतिनिधि, यदि उपलब्ध है (वैकल्पिक) के साथ निरीक्षण स्थल की फोटोग्राफ या वीडियो क्लिपिंग (कम से कम 1 फोटोग्राफ या क्लिपिंग);
 - निरीक्षण के लिए प्रयुक्त जांच उपकरण (उपकरणों) के फोटोग्राफ या वीडियो क्लिपिंग;
 - कंटेनर की संख्या दर्शाते हुए कंटेनरों को भरने की प्रक्रिया के फोटोग्राफ या वीडियो क्लिपिंग (कम से कम प्रति कंटेनर 1 फोटोग्राफ या वीडियो क्लिपिंग);
 - सील करने की प्रक्रिया के फोटोग्राफ या वीडियो क्लिपिंग (प्रति कंटेनर कम से 1 फोटोग्राफ या वीडियो क्लिपिंग)।
- (ङ.) पीएसआईए द्वारा फोटोग्राफ और/या वीडियो क्लिपिंग [उपर्युक्त 2.56 (ख) के अनुसार] तथा पीएसआईसी डिजिटल हस्ताक्षर के द्वारा डीजीएफटी की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा या पीएसआईए के पंजीकृत ई-मेल के द्वारा psicdgft@gov.in पर भेजा जाएगा। जब तक डीजीएफटी की वेबसाइट लिंक को प्रचालित किया जाता है तब तक पीएसआईसी और फोटोग्राफ/वीडियो विदेश व्यापार महानिदेशालय को (psiadgft@gov.in पर) ईमेल किया जाएगा।

2.57 अन्य प्रकार के धात्विक छीजन और स्क्रेप का आयात

अन्य प्रकार की धात्विक छीजन और स्क्रेप का आयात आईटीसी (एचएस) की शर्तों के प्रावधानों के अनुसार अनुमत किया जाएगा।

2.58 पुराने और दोषपूर्ण माल का आयात

पुराने और दोषपूर्ण, चीथड़े, पैट बोतलें/छीजन और समुद्री जहाजों के लिए आयात नीति आईटीसी (एचएस) में उल्लिखित है।

2.59 निरीक्षण एवं प्रमाणन अभिकरणों की सेवाएँ

सीमाशुल्क विभाग अथवा अन्य केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार के प्राधिकरण पूंजीगत वस्तुओं की बाकी मियाद और मूल्य/खरीदने की कीमत को प्रमाणित करने के लिए परिशिष्टो एवं आयात निर्यात प्रपत्र के **परिशिष्ट 2झ** में निरीक्षण तथा प्रमाणन अभिकरणों की सेवा प्राप्त कर सकते हैं।

प्रशुल्क दर कोटा स्कीम:

2.60 प्रशुल्क दर कोटा स्कीम के अन्तर्गत आयात की प्रक्रिया

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 21/2002-सीमाशुल्क, दिनांक 1 मार्च, 2002 तथा अधिसूचना सं. 33/2010 सीमाशुल्क, दिनांक 12.3.2010 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। इनके अनुसार चार मदों अर्थात् (1) स्किम्ड और संपूर्ण दुग्ध चूर्ण, बच्चों के लिए दुग्ध से बने खाद्य पदार्थ आदि (0402.10 अथवा 0402.21) और व्हाइट बटर, बटर ऑयल, एनहाइड्रस मिल्क फैट (0405) (2) मक्का (कार्न); अन्य (1005.90) (3) कच्चा सूरजमुखी बीज अथवा कुसुम्भ तेल अथवा उनके भाग (1512.11) और (4) रिफाईंड रेप, कोल्जा अथवा सरसो का तेल, अन्य (1514.19 अथवा 1514.99) के आयात की एक वित्तीय वर्ष में, सीमाशुल्क की ऐसी रियायती दर तथा मात्रा तक, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है, अनुमति है:-

विवरण	एचएस सं०	विश्व व्यापार संगठन के अनुसार कोटा दर का आना/ जाना (प्रतिशत)	भारतीय प्रशुल्क के अनुसार कोटा दर के आने/जाने का (प्रतिशत)	अधिसूचना	टीआरक्यू (मि.टन में)
मलाई रहित दूध पाउडर/ हो दूध पाउडर	040210	15/60	15/60	12/12-सीमाशुल्क क्र.सं.7	10,000
	040221	15/60	15/60	12/12- सीमाशुल्क क्र.सं.7	
मक्का (दाना) बीज गुणवत्ता के अलावा	100590	15/60	0/50	12/12- सीमाशुल्क क्र.सं.37/38	5,00,000
कच्चा सूर्यमुखी बीज तेल तथा सेफफ्लावर सीड तेल	151211	50/300	50/75	12/12-सीमाशुल्क क्र.सं. 60/61	1,50,000
	रेप, कोल्जा अथवा सरसो का तेल	151419	45/75	45/10	
	151499	45/75	45/10	12/12-सीमाशुल्क क्र.सं.64/66	1,50,000
मक्खन और अन्य वसा	040510	उपलब्ध नहीं	0/30	12/12-सीमाशुल्क क्र.सं.9	15,000
	04059010		0/30	12/12-सीमाशुल्क क्र.सं.9	
	04059020		0/30	12/12-सीमाशुल्क क्र.सं.9	
मक्खन और अन्य वसा	040520	उपलब्ध नहीं	0/40	12/12-सीमाशुल्क क्र.सं.9	15,000
	04059090		0/40	12/12-सीमाशुल्क क्र.सं.9	

2.61 कोटे के आवंटन के लिए पात्र कंपनियाँ

(क) दुग्ध चूर्ण (प्रशुल्क कोड संख्या 0402.10 अथवा 0402.21): तथा व्हाइट बटर, बटर ऑयल, एनहाइड्रस मिल्क फ़ैट (0405): राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड (एनडीडीबी), राज्य व्यापार निगम (एसटीसी), राष्ट्रीय सहकारी दुग्ध संघ (एनसीडीएफ), भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नेफेड), खनिज और धातु व्यापार निगम (एमएमटीसी), भारतीय परियोजना और उपकरण निगम लिमिटेड (पीईसी) और मसाला व्यापार निगम लिमिटेड (एसटीसीएल) ।

(ख) मक्का (कार्न) (प्रशुल्क कोड संख्या 1005.90): भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नेफेड), राज्य व्यापार निगम (एसटीसी), खनिज और धातु व्यापार निगम (एमएमटीसी), भारतीय परियोजना और उपकरण निगम लिमिटेड (पीईसी), मसाला व्यापार निगम लिमिटेड (एसटीसीएल) और राज्य सहकारी विपणन संघ।

(ग) कच्चे सूर्यमुखी के बीज अथवा कुसुम्भ तेल अथवा उनके भाग (प्रशुल्क कोड संख्या 1512.11) और रिफाइन्ड रेप, कोल्जा, कैनोला या सरसों का तेल, अन्य (प्रशुल्क कोड संख्या 1514.19 या 1514.99): राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड (एनडीडीबी),

राज्य व्यापार निगम (एसटीसी), भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नेफेड), मसाला व्यापार निगम लिमिटेड (एसटीसीएल) और केन्द्रीय भण्डारण निगम (सीडब्ल्यूसी), राज्य सहकारी विपणन संघ और राज्य सहकारी नागरिक आपूर्ति निगम।

2.62 कोटा प्राप्त करने हेतु लागू शर्तें

सभी पात्र कंपनियाँ नीचे दी गई शर्तों के अधीन कोटा प्राप्त करने की पात्र हैं।

- (i) सभी पात्र कंपनियाँ, जो उपर्युक्त कोर्ट को प्राप्त करने के इच्छुक हैं विदेश व्यापार महानिदेशालय के कार्यालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011 में, एएनएफ 2ड में निर्यात आयात सुविधा समिति को आवेदन कर सकते हैं। पूरे भरे हुए आवेदन पत्र निर्धारित दस्तावेजों सहित कोटा वर्ष के प्रत्येक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के 1 मार्च, तक कार्यालय में पहुँच जाने चाहिए।
- (ii) आयात वित्तीय वर्ष के 31 मार्च से पूर्व पूरा हो जाना चाहिए अर्थात् इस तारीख से पूर्व सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा खेप की निकासी कर दी जानी चाहिए।
- (iii) चूँकि, मक्के (कार्न) का आयात एस टी ई के तहत है, कोटे के आवंटि अर्थात् इस मद के लिए पैरा 2.61 (ख) में नामित एजेंसियाँ को भी, विदेश व्यापार नीति, 2015-2020 के पैरा 2.20 के अनुसार सीमाशुल्क अधिसूचना संख्या 21/2002 दिनांक 1/3/2002 की क्रम संख्या 21 (ख) में दर्शाई आवंटित मात्रा के लिए आयात प्राधिकार पत्र प्रदान किया जाएगा।
- (iv) परिशिष्टों और आयात निर्यात प्रपत्रों के परिशिष्ट 2ट में शामिल प्रक्रिया के अनुसार इन आवेदनों के लिए आवेदन शुल्क का भुगतान किया जाएगा।
- (v) विदेश व्यापार महानिदेशालय की निर्यात सुविधा समिति (ईएफसी) मूल्यांकन करेगी और कोटा वर्ष के प्रत्येक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक आवेदकों के मध्य कोटा आवंटित करेगी।

प्रदर्शनियाँ एवं नमूने:

2.63 राष्ट्रीय और अन्तर-राष्ट्रीय प्रदर्शनियों या मेलों और प्रदर्शनियों के लिए अपेक्षित प्रदर्शित वस्तुएँ

(क) प्रदर्शनी-वस्तुओं जो मुक्त रूप से आयातित/निर्यातित की जाती है का आयात/निर्यात जिसमें प्रदर्शनियों, मेलों अथवा इस प्रकार के शो और डिस्पले में पुनः निर्यात/पुनः आयात आधार पर छह महीनों के लिए विदेशी/भारतीय प्रदर्शकों के लिए अस्थायी तौर पर दिखाने के लिए अपेक्षित निर्माण तथा सज्जा सामग्रियाँ शामिल हैं उन्हें सीमाशुल्क विभाग अथवा एटीए कार्नेट को एक अनुबंध पत्र/प्रतिभूति प्रस्तुत करके बिना प्राधिकार पत्र के अनुमत किया जाएगा।

(ख) पुनः निर्यात/पुनः आयात के लिए छः माह से आगे अवधि बढ़ाने पर विचार सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा गुण-दोष के आधार पर किया जाएगा। प्रदर्शित वस्तुओं से संबंधित पेंट, प्रिंट सामग्री, पैम्पलेट, साहित्य आदि जैसे उपभोग्यों के पुनः निर्यात/पुनःआयात की आवश्यकता नहीं है।

2.64 नुमाइशी मदों की बिक्री

(क) प्रतिबंधित मदें: अन्तरराष्ट्रीय प्रदर्शनी/मेलों के लिए आयातित आई टी सी (एच एस) में उल्लिखित प्रतिबंधित मदों के प्रदर्शों की बिक्री, प्रभावी सीमाशुल्क का भुगतान करने पर प्राधिकार पत्र के बिना, बाण्ड अवधि के भीतर पुनः निर्यात की अनुमति होगी, बशर्ते कि प्रत्येक प्रदर्श के लिए ऐसे प्रदर्शों की निर्धारित सीमा 5 लाख रु (सीआईएफ) हो।

(ख) मुक्त रूप से आयात की जाने वाली मदें:- तथापि, जिन प्रदर्शित मदों का मुक्त आयात किया जाता है उनकी, लागू सीमा शुल्क के भुगतान पर पुनः निर्यात की अनुमत बाण्ड अवधि के भीतर बिक्री की जाएगी।

(ग) यदि आयातक के नियंत्रण से बाहर परिस्थितियों के कारण प्रदर्शनी के लिए लाई गई वस्तुओं का बांड अवधि के अंदर पुनः निर्यात या बिक्री नहीं की जाती है तो सीमाशुल्क प्राधिकारी गुण-दोष आधार पर बंध पत्र अवधि में वृद्धि कर सकते हैं।

2.65 नमूनों का आयात

(क) सब्जियों के बीज, मधुमक्खी और नई औषधियों को छोड़कर, आई टी सी (एच एस) में प्रतिबंधित मदों के वास्तविक, तकनीकी और व्यापार नमूनों के आयात के लिए किसी प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। चाय उद्योग से सम्बद्ध किसी भी व्यक्ति को प्राधिकार पत्र के बिना एक खेप में 2000 स्मए (लागत बीमा भाड़ा मूल्य) तक चाय के नमूनों के आयात की अनुमति होगी।

(ख) सभी निर्यातकों के लिए 300,000 स्मए तक नमूनों के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति सीमा-शुल्क अधिसूचना के नियम एवं शर्तों के अनुसार दी जाएगी।

2.66 नमूनों/नुमाइशी वस्तुओं का निर्यात

(क) मुक्त रूप से निर्यात की जाने वाली मर्दों के वास्तविक व्यापार और तकनीकी नमूनों का निर्यात बिना किसी सीमा के अनुमत होगा।

(ख) ऐसे नमूनों या नुमाइशी वस्तुएँ, जो निर्यात के लिए प्रतिबंधित हों, के निर्यात के लिए आवेदन पत्र एएनएफ 2थ के अनुसार विदेश व्यापार महानिदेशक को प्रस्तुत किए जाएँ।

निर्यात:

2.67 निर्यात नीति

निर्यात से संबंधित नीति, विदेश व्यापार नीति के अध्याय-2 में दी गई है। इसके अलावा, आईटीसी (एच एस) के परिशिष्ट 1 अनुसूची-2 में उन मर्दों को विनिर्दिष्ट किया गया है जिनका किसी प्राधिकार पत्र के बिना निर्यात किया जा सकता है, जो कि इस संबंध में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन होगा।

2.68 उपहार/पुर्जे/प्रतिस्थापन माल

विदेश व्यापार नीति में उपहार के निर्यात के लिए निर्धारित सीमा/अवधि से अधिक में उपहारों, देशी/आयातित वारण्टी स्पेयर्स और प्रतिस्थापन माल, उपहार के निर्यात के लिए आवेदन पत्र विदेश व्यापार महानिदेशक को एएनएफ 2थ में प्रस्तुत किया जा सकता है।

2.69 सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम (एमएसएमआई) क्षेत्र के लिए आरक्षित मर्दों का निर्यात

लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित मर्दों के संबंध में लघु उद्योग एककों से भिन्न अन्य एककों को नई क्षमताओं का सृजन करने या इनमें विस्तार करने की अनुमति है बशर्ते कि उन्होंने यथा विनिर्दिष्ट निर्यात दायित्व सहित उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त कर लिया हो। ऐसे लाइसेंसधारी को इस संबंध में विधिक वचनबद्धता क्षेत्रीय प्राधिकारी तथा विदेश व्यापार महानिदेशालय को प्रस्तुत करनी होगी। निर्यात दायित्व को विदेश व्यापार महानिदेशालय/संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा मानीटर किया जाएगा।

2.70 डाक द्वारा निर्यात

डाक द्वारा निर्यात के मामले में समुद्र/वायु मार्ग द्वारा निर्यात के लिए निर्धारित दस्तावेजों के स्थान पर निर्यातक को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे:

(क) परिशिष्ट 2प में ई-बीआरसी के अनुसार निर्यात और वसूली का बैंक प्रमाणपत्र।

(ख) संबद्ध डाक रसीद।

(ग) सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा विधिवत सत्यापित बीजक।

2.71 निर्यात दस्तावेजों का सीधे लेन-देन

उन मामलों में जहाँ निर्यातक भारतीय रिज़र्व बैंक की अनुमति से दस्तावेज का सीधे (प्राधिकृत डीलर के माध्यम से नहीं) लेन-देन करता है, तो उसे निर्यात संवर्धन स्कीमों के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे :-

(क) दस्तावेजों के सीधे लेन-देन की अनुमति हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक से अनुमति (स्तर धारकों हेतु आवश्यक नहीं है) ;

(ख) बीआरसी के बदले में आयकर विभाग के फार्म-10ज के अनुसार विदेश से स्वदेश में धन प्रेषण प्रमाणपत्र (एफआईआरसी) की प्रति तथा

(ग) शिपिंग बिलों/बीजक के ब्यौरे देने का विवरण जिसके मद्दे एफआईआरसी जारी किया गया था।

स्कोमेट:

2.72 निर्यात प्राधिकार पत्र/प्रमाणपत्र/गैर स्कोमेट मर्दों हेतु अनुमति पत्र की मंजूरी के लिए आवेदन-पत्र

(क) निर्यात और आयात मर्दों के आई टी सी (एच एस) वर्गीकरण की अनुसूची-2 में उल्लिखित प्रतिबंधित मर्दों [विशेष रसायनों, आर्गेनिज्म, सामग्रियों, उपस्कर और प्रौद्योगिकियों (स्कोमेट) को छोड़कर] के संबंध में निर्यात प्राधिकार पत्र की मंजूरी के लिए आवेदन पत्र, आयात-निर्यात फार्म 2ढ में उसमें उल्लिखित दस्तावेजों के साथ विदेश व्यापार महानिदेशक को दिया जाए। निर्यात सुविधा समिति, निर्यात प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए गुणावगुण के आधार पर आवेदन पत्रों पर विचार करेगी।

(ख) यदि निर्यातक को डीजीएफटी द्वारा लिखित में सूचित किया गया है अथवा वह यह जानता है अथवा उसका यह

विश्वास है कि स्कोमेट में शामिल नहीं किए गए किसी मद के प्रयोग में संभावित जोखिम है अथवा इसे जनसंहार हेतु हथियार अथवा इनकी मिसाइल प्रणाली अथवा सैन्य वास्तविक प्रयोग आतंकवादी और देशद्रोहियों सहित में परिवर्तित किया जा सकता है, तो ऐसी मद का निर्यात निषिद्ध अथवा पैरा 2.73 में उल्लिखित स्कोमेट मदों हेतु दी गई प्रक्रिया के अनुसार लाइसेंस प्राप्त करने के अधीन अनुमत किया जा सकता है।

टिप्पणी: “सैन्य उपयोग” का अर्थ स्कोमेट की श्रेणी 5ड या 6 में सूचीबद्ध वस्तुएं शामिल हैं या इन श्रेणियों में सूचीबद्ध सैन्य उपयोग, विकास या उत्पादन के लिए वस्तुएं हैं।

2.73 स्कोमेट प्राधिकार-पत्र हेतु आवेदन।

- (क) निर्यात और आयात मदों के आईटीसी (एचएस) वर्गीकरणों की अनुसूची 2 के परिशिष्ट 3 में उल्लिखित प्रतिबंधित मदों [विशेष रसायन, आर्गेनिज्म, पदार्थ, उपकरण एवं प्रौद्योगिकी (स्कोमेट)] के संबंध में निर्यात प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए आवेदन पत्र विदेश व्यापार महानिदेशालय (मुख्यालय) को **आयात-निर्यात प्रपत्र 2ण** में उसमें निर्धारित दस्तावेजों के साथ किया जा सकता है।
- (ख) तथापि, ऐसे आवेदन डीजीएफटी की वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से आईकन ई-काम के अंतर्गत आनलाईन भरे जाने हैं। आनलाईन आवेदन हेतु यूनिफार्म रिसोर्स लोकेटर(यूआरएल) <http://dgft.gov.in/CallModule.asp?scho=SCOMET> है। आनलाईन आवेदन प्रस्तुत करते समय अन्तिम प्रयोक्ता प्रमाण पत्र (ईयूसी) सहित अपेक्षित दस्तावेज पीडीएफ फाइलों के रूप में अपलोड किए जाने चाहिए। आपूर्ति की सभी इकाईयों अर्थात् विदेशी खरीददार, अन्तिम प्रयोक्ता मध्यवर्ती/खेपकर्ता (यदि वे विदेशी खरीददार तथा अन्तिम प्रयोक्ता से भिन्न हो) से **परिशिष्ट 2घ** में वास्तविक अन्तिम प्रयोक्ता प्रमाणपत्र (पत्रों) को छोड़कर हाथ से भरकर आवेदन करना आवश्यक नहीं है, जिसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत करने के अतिरिक्त डीजीएफटी (मुख्यालय) के स्कोमेट अनुभाग को हार्ड कापी में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- (ग) **अभिलेखों का रखरखाव:**

प्रत्येक स्कोमेट प्राधिकार-पत्र धारक को यथा लागू निर्यात अथवा आयात की तिथि से 5 वर्षों की अवधि हेतु निम्नलिखित अभिलेखों का दस्ती या इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखरखाव करना होगा:

- (क) स्कोमेट प्राधिकार पत्र हेतु आवेदन करते समय सभी दस्तावेज प्रस्तुत करना।
- (ख) क्रेता/खेप प्राप्तकर्ता/वास्तविक प्रयोक्ता अथवा डीजीएफटी अथवा संबंधित सरकार अभिकरण से किया गया पत्राचार
- (ग) संबंधित संविदाएं,
- (घ) संबंधित लेखा पुस्तिकाएं
- (ङ.) संबंधित वित्तीय अभिलेख
- (च) स्कोमेट सूची की किसी मद हेतु प्राधिकार पत्र हेतु आवेदन अथवा पण्य वर्गीकरण अनुरोध के संबंध में किसी सरकारी अभिकरण से किया गया कोई पत्राचार
- (छ) पोत लदान बिल, प्रविष्टि बिल तथा लदान बिल सहित पोत लदान दस्तावेज

2.74 अंतर्मंत्रालीय कार्य समूह

विदेश व्यापार महानिदेशालय (मुख्यालय) में स्थित अन्तर मंत्रालयीय कार्य समूह (आईएमडब्ल्यूजी) नीचे दिए गए दिशा निर्देशों के आधार पर निर्यात और आयात मदों के आई टी सी (एच एस) वर्गीकरण की अनुसूची-2 के परिशिष्ट-3 में यथा विनिर्दिष्ट स्कोमेट मदों के निर्यात के आवेदनों पर विचार करेगा:

- I. स्कोमेट सूची पर निर्यात मदों या प्रौद्योगिकी के लिए प्राधिकार पत्र हेतु आवेदनों पर निम्नलिखित सामान्य मानदंडों के आधार पर विचार किया जाता है:

(क) अन्तिम प्रयोक्ता के व्यक्तिगत ब्यौरे, मद या प्रौद्योगिकी के अन्तिम प्रयोक्ता की घौणाओं की विश्वसनीयता, आपूर्तिकर्ता से अन्तिम प्रयोक्ता को मद की सुपुर्दगी और मद या प्रौद्योगिकी क्षमता जिसमें इसके निर्यात का समय शामिल है जो अन्तिम प्रयोग के लिए योगदान देता है कि यह भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा या विदेश नीति के लक्ष्यों और उद्देश्यों, वैश्विक निशस्त्रीकरण के लक्ष्यों व उद्देश्यों या भारत के वे दायित्व जो अन्तराष्ट्रीय संधियों/समझौता के तहत जिनकी यह देश के पक्षकार हैं, के अनुसम नहीं है;

- (ख) मूल्यांकित खतरे कि निर्यातित मदें आतंकवादी, आतंकवादी समूहों और देशद्रोहियों के हाथों में जा सकती हैं;

- (ग) प्राप्तकर्ता राज्य द्वारा किए गए निर्यात नियंत्रण उपाय;
- (घ) हथियारों और उनकी सुपुर्दगी से संबंधित प्राप्त कर्ता राज्य के कार्यक्रमों की क्षमताएँ और उद्देश्य;
- (ङ.) मद (मदों) के अन्तिम प्रयोग (प्रयोगों) का मूल्यांकन;
- (च) विचारणीय मामले के तहत संगत द्विपक्षीय अथवा बहुपक्षीय समझौते के प्रावधानों की व्यवहारियता जिसमें भारत एक पक्ष हो या समर्थक जिसमें परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह, मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था, ऑस्ट्रेलिया समूह और वाइसनार व्यवस्था (और इसकी संवेदनशील सूची या अति संवेदनशील सूची) के समय-समय पर अपडेट किए गए दिशा-निर्देश और नियंत्रण सूचियाँ सम्मिलित हैं परन्तु सीमित नहीं हैं।

II. आवेदन पत्र परिशिष्ट 2घ के अनुसार एक अंतिम प्रयोक्ता प्रमाण पत्र के साथ होना चाहिए, जिसमें यह प्रमाणित हो कि:-

- (क) मद का प्रयोग सिर्फ बताए गए उद्देश्य के लिए किया जाएगा और ऐसे प्रयोग को भारत सरकार की मंजूरी के बिना बदला नहीं जाएगा, न ही मदों को संशोधित अथवा दुहराया जाएगा;
- (ख) भारत सरकार की मंजूरी के बिना न तो मदों को या न ही उनकी प्रतिकृति अथवा व्युत्पन्न को पुनर्हस्तांतरित किया जाएगा;
- (ग) अन्तिम प्रयोक्ता, वैसे प्रमाणन उपलब्ध कराएगा जैसा कि भारत सरकार द्वारा आवश्यक होगा।

III. अंतिम प्रयोक्ता प्रमाण-पत्र आयात की जाने वाली मद का नाम, आयातक का नाम, संबंधित वस्तुओं का विशिष्ट अंतिम प्रयोग और खरीद आदेश/संविदा के विवरण को दर्शाएगा।

IV. भारत सरकार प्राप्तकर्ता के राज्य से अंतिम प्रयोग और गैर पुनः स्थानांतरण सहित अतिरिक्त औपचारिक आश्वासन जो उपयुक्त माने जाते हो, को भी प्राप्त कर सकती हैं।

V. (क) आई टी सी (एच एस) की अनुसूची 2 के परिशिष्ट-3 में वस्तु पहचान नोट की श्रेणी-0 और नोट-2 में दी गई मदों के लिए लाइसेंसिंग प्राधिकारी परमाणु उर्जा विभाग है। परमाणु उर्जा विभाग द्वारा परमाणु उर्जा अधिनियम, 1962 के तहत लागू दिशानिर्देश अधिसूचित हैं। श्रेणी-0 की कुछ मदों के लिए, प्राप्तकर्ता राज्य से औपचारिक आश्वासनों में किसी नाभिकीय विस्फोट उपकरण में न प्रयोग किया जाना भी शामिल है। श्रेणी-0 की कुछ मदों के निर्यात के लिए प्राधिकार पत्र प्रदान नहीं किया जाएगा, जब तक की हस्तांतरण अतिरिक्त स्म से उचित संरक्षण के तहत और उचित अंतर्राष्ट्रीय परमाणु उर्जा एजेंसी (आई ए ई ए) रक्षोपाय अथवा हस्तांतरणीय मदों के किसी भी अन्य पारस्परिक सहमति नियंत्रणों के तहत नहीं होगी।

(ख) आईटीसी (एचएस) की अनुसूची 2 के परिशिष्ट 3 में श्रेणी 6 में दी गई मदों के लिए लाइसेंसिंग प्राधिकरण रक्षा उत्पादन विभाग है। श्रेणी 6 में उल्लिखित मदों का निर्यात रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग द्वारा जारी मौजूदा मानक संचालन प्रक्रिया द्वारा संचालित किया जाता है। आईटीसी (एचएस) की अनुसूची 2 के परिशिष्ट 3 में 'पण्य पहचान टिप्पण' की टिप्पणी 3 में शामिल मदों का निर्यात निषिद्ध है।

VI. मदों अथवा तकनीक के निर्यात के लिए प्राधिकार पत्रों में अतिरिक्त अन्तिम प्रयोग शर्तें निर्धारित की जाएँ, जो दिशा परिवर्तन की संभावना रखती हों अथवा उसके विकास अथवा विनिर्माण में प्रयोग हों अथवा व्यापक विध्वंस के हथियारों की सुपुर्दगी में सक्षम प्रक्रिया के स्म में प्रयोग हो।

VII. सिर्फ प्रदर्शन अथवा प्रदर्शनी के उद्देश्य के लिए स्कोमेट सूची (श्रेणी 0,1 और 2 के तहत सूची को छोड़कर) की मदों के निर्यात के लिए प्राधिकार पत्रों हेतु किसी अन्तिम प्रयोग अथवा अन्तिम प्रयोक्ता प्रमाणन की आवश्यकता नहीं है। तथापि, प्रदर्शन अथवा प्रदर्शनी हेतु किसी वर्ग में 'प्रौद्योगिकी' के लिए कोई निर्यात प्राधिकार पत्र जारी नहीं किया जाएगा। आईएमडब्ल्यूजी जहां भी आवश्यक समझेगा, तकनीकी एजेंसियों से टिप्पणियां मांगेगा।

VIII. ईरान को निर्यात हेतु स्कोमेट सूची की श्रेणी 0,3 (3घ के अतिरिक्त), 4,5 और 7 की मदों हेतु प्राधिकार पत्र संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संकल्प 2231 (2015) के अनुलग्नक ख में उल्लिखित संबंध प्रावधानों के अधीन होगा। लाइसेंसिंग प्राधिकरण अर्थात डीजीएफटी अथवा परमाणु उर्जा विभाग, जैसा मामला हो, आईएमडब्ल्यूजी प्रक्रिया अर्थात लागू आंतरिक प्रक्रिया के पूरा होने पर विदेश मंत्रालय के निरस्त्रीकरण तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मामले (डी एवं आईएसए) प्रभाग, जैसा आवश्यक हो, से स्वीकृति प्राप्त करेगा।

IX. अंतर-मंत्रालयी कार्य दल की सामान्यतः प्रत्येक माह में एक बार बैठक होगी। ऐसे मामले में जो आईएमडब्ल्यूजी में आस्थगित किया जाता है और तदोपरांत सभी संबंधित अभिकरणों से अनापत्ति प्रमाण पत्र/पत्रों के बिना किसी असहमति के प्राप्त होने पर प्राधिकार पत्र को अध्यक्ष, आईएमडब्ल्यूजी की स्वीकृति से जारी किया जाएगा तथा मामले को आईएमडब्ल्यूजी के समक्ष इसकी अगली बैठक में कार्यान्तर आधार पर अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाएगा। ऐसे मामला/मामले जिन पर आईएमडब्ल्यूजी में

निर्णय नहीं लिया जा सका हो उन्हें प्राधिकार पत्र जारी करने हेतु समुचित निर्णय लेने के लिए महानिदेशक, विदेश व्यापार के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

2.75 व्यापक विध्वंस हथियार अधिनियम (डब्ल्यूएमडी एक्ट) की अनुप्रयोज्यता:

जो मदें स्कोमेट सूची में शामिल नहीं हैं उनका निर्यात भी व्यापक विध्वंस के हथियारों और उनकी सुपुर्दगी प्रणाली (गैर कानूनी गतिविधियों की निषिद्धता) अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अधीन नियंत्रित होगा।

टिप्पणी:1- प्राधिकार-पत्र की किसी शर्त के उल्लंघन में निर्यात अथवा निर्यात के प्रयास दीवानी और/अथवा फौजदारी अभियोजन को आमंत्रित करेगा।

टिप्पणी:2- विदेश में प्रदर्शन अथवा प्रदर्शनी के लिए स्कोमेट सूची की मदों के निर्यात के लिए प्राधिकार पत्र छः माह तक की अवधि में पुनः आयात शर्त के अधीन है। निर्यातक विदेश में प्रदर्शित ऐसी मदों के लिए निर्यात प्राधिकार-पत्र के लिए आवेदन करने के हकदार होंगे। विदेश में प्रदर्शनी के दौरान प्रदर्शनीकर्ता ने मद को बिक्री के लिए रखा हो, तो ऐसी बिक्री बिना वैध प्राधिकार-पत्र के नहीं होगी।

टिप्पणी:3- स्कोमेट सूची की श्रेणी-2 में निर्यात की मदें, समय-समय पर जारी अन्य लागू दिशा निर्देशों द्वारा भी नियंत्रित होंगी।

टिप्पणी:4- निर्यातक यह अनुरोध कर सकते हैं कि केवल ऐसी शर्तें ही लगाई जाएँ जो स्कोमेट सूची की मदों के निर्यात पर सरकार - से - सरकार समझौते के अधीन हैं।

टिप्पणी:5- प्रौद्योगिकी (निर्यात और आयात मदों आई टी सी (एच एस) वर्गीकरण की अनुसूची 2 के परिशिष्ट -3 की शब्दावली में प्रविष्टि प्रौद्योगिकी” को भी देखें): स्कोमेट सूची की मद के निर्यात का अनुमोदन, मद की स्थापना, संचालन, रख-रखाव और मरम्मत के लिए आवश्यक न्यूनतम प्रौद्योगिकी के लिए उसी अन्तिम प्रयोक्ता को निर्यात के लिए प्राधिकृत करता है।

2.76 डीटीए से एसईजैड में स्कोमेट मदों की आपूर्ति

डीटीए से एसईजैड के स्कोमेट मदों की आपूर्ति के लिए किसी निर्यात प्राधिकार-पत्र की आवश्यकता नहीं है। तथापि, डीटीए से एसईजैड में सभी स्कोमेट मदों को सभी आपूर्तियां संबंधित एसईजैड विकास आयुक्त को आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्तियों के होने के एक सप्ताह के अंदर निर्धारित प्रपत्र [निर्यात और आयात मदों के आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण की अनुसूची 2 के परिशिष्ट-3 का अनुलग्नक 1] में सूचित की जानी चाहिए। डीटीए से एसईजैड में ऐसी आपूर्तियों की एक वार्षिक रिपोर्ट विकास आयुक्त (डीसी), एसईजैड निर्धारित प्रपत्र [निर्यात और आयात मदों के आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण की अनुसूची 2 के परिशिष्ट-3 का अनुलग्नक 2] में स्कोमेट सैल, विदेश व्यापार महानिदेशालय (मुख्यालय), वाणिज्य विभाग, उद्योग भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110011 को भेजी जाएगी। एसईजैड के विकास आयुक्त द्वारा एक रिपोर्ट पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान की गई आपूर्तियों के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष की 15 मई तक दायर की जानी चाहिए। तथापि, निर्यात प्राधिकार-पत्र अपेक्षित होगा यदि स्कोमेट मदों को एसईजैड से देश के बाहर अर्थात् अन्य देश (एसईजैड नियमावली, 2006 के नियम 26 का संदर्भ लें) वास्तविक रूप से निर्यात किया जाना है।

2.77 स्कोमेट निर्यात नियंत्रण प्रणाली के संबंध में आउटरीच कार्यक्रम

विदेश व्यापार महानिदेशालय प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों व व्यापार एसोसिएशनों के सहयोग से व्यापार से संबंधित आयातक/निर्यातक के मध्य विशेष रूप से स्कोमेट मदों के संबंध में प्रभावी जागरूकता के लिए इन्डस्ट्री आउटरीच कार्यक्रम का नियमित आधार पर आयोजन करेंगे।

2.78 साइट का दौरा, साइट पर जाँच और रिकार्ड/दस्तावेजों को देखने हेतु किसी व्यवस्था अथवा समझौते में शामिल होने के लिए आवेदनों को प्रस्तुत करने/मूल्यांकन करने के लिए प्रक्रिया/दिशा निर्देश।

निर्यात और आयात मदों के आईटीसी(एचएस) वर्गीकरण की अनुसूची-2 के परिशिष्ट-3 में यथाउल्लिखित किसी ऐसी व्यवस्था या समझौते, जिसमें किसी विदेशी सरकार अथवा विदेशी तृतीय पक्ष द्वारा, स्वयं या किसी भारतीय पक्ष के माध्यम से, साइट का दौरा, साइट पर जाँच और रिकार्ड/दस्तावेजों को देखने की व्यवस्था है, में शामिल होने के लिए आवेदन आयात निर्यात प्रपत्र 2त में, उसमें निर्धारित दस्तावेजों सहित विदेश व्यापार महानिदेशालय (मुख्यालय) नई दिल्ली, को प्रस्तुत किये जायेंगे। विदेश व्यापार महानिदेशालय में अन्तरमंत्रालयीय कार्य समूह (आईएमडब्ल्यूजी) निम्नलिखित दिशा-निर्देशों/सामान्य मानदण्डों के आधार पर इन आवेदनों पर विचार करेगा:-

I. साइट का दौरा, साइट पर जाँच और रिकार्ड/दस्तावेजों को देखने हेतु किसी व्यवस्था अथवा समझौते में शामिल होने के लिए आवेदनों का मूल्यांकन करते समय अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाएगा:-

(क) व्यवस्था/समझौता जिसके तहत साइट का दौरा, साइट पर जाँच या रिकार्ड/दस्तावेजों को देखा जाना प्रस्तावित है, का

प्रयोजन।

(ख) संबंधित पक्षों का परिचय पत्र और ब्यौरे।

(ग) अंतिम प्रयोक्ता का परिचय-पत्र, मदों अथवा प्रौद्योगिकी के अंतिम प्रयोग की घोषणा की विश्वसनीयता, आपूर्तिकर्ता से अंतिम प्रयोक्ता को मद के स्थानान्तरण की श्रृंखला की सत्यता, और मद अथवा प्रौद्योगिकी की उन अंतिम प्रयोगों में योगदान की क्षमता पर, इसके निर्यात के समय सहित, जो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा अथवा विदेश नीति के लक्ष्यों और उद्देश्यों, वैश्विक निशस्त्रीकरण के उद्देश्यों अथवा उन संधियों के अन्तर्गत जिसमें एक पक्ष सरकार है, इसके दायित्वों के अनुस्र नहीं है।

(घ) व्यवस्था/समझौते के परिणामस्वरूप दोहरे प्रयोग वाली मदों और प्रौद्योगिकी के आतंकवादियों, आतंकवादी गुटों और गैर-सरकारी व्यक्तियों के हाथों में पड़ने का संभावित जोखिम।

(ड.) यदि साइट का दौरा साइट पर जाँच अथवा रिकार्ड/दस्तावेज़ को देखना किसी विदेशी सरकार अथवा इसके किसी प्रतिनिधि (प्रतिनिधियों) द्वारा किया जाना है तो निम्नलिखित बातों को ध्यान रखा में जाएगा : -

(i) विदेशी सरकार द्वारा किए गए निर्यात नियंत्रण उपाय;

(ii) हथियार और उनकी सुपुर्दगी के संबंध में विदेशी सरकार के कार्यक्रमों की क्षमताएं और उद्देश्य।

(च) संबंधित द्विपक्षीय और बहुपक्षीय समझौतों, जिसमें एक पक्ष भारत है, की व्यवहार्यता।

(छ) साइट का दौरा, साइट पर जाँच अथवा रिकार्ड/दस्तावेज़ देखने से भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा और दूसरे किसी देश से संबंधों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव, यदि कोई हो, का मूल्यांकन।

(ज) विदेशी पक्षों के, आतंकवादी संगठनों और उनके अपने देश अथवा किसी दूसरे देश के गैर-सरकारी व्यक्तियों से संभावित संबंधों का मूल्यांकन।

II. साइट का दौरा, साइट पर जाँच या रिकार्ड/दस्तावेज़ों को देखने हेतु व्यवस्था या समझौते के लिए निम्नलिखित शर्तों के मद्दे अनुमति दी जाएगी:-

(क) साइट का दौरा, साइट पर जाँच या रिकार्ड/दस्तावेज़ों को देखने की अनुमति उन उद्देश्य, उन साइट्स और उन क्रिया कलापों तक सीमित रहेगी जिनके लिए उसे अनुमति प्रदान की गई है/जो प्राधिकार-पत्र में उल्लिखित है।

(ख) साइट का दौरा, साइट पर जाँच या रिकार्ड/दस्तावेज़ों को देखने की अनुमति केवल उन व्यक्तियों को होगी जिसका उल्लेख प्राधिकार-पत्र में किया गया है।

(ग) साइट का दौरा, साइट पर जाँच या रिकार्ड/दस्तावेज़ों को देखना प्राधिकार-पत्र में उल्लिखित अवधि के दौरान पूरा करना होगा।

(घ) निर्यातक/आयातक साइट के दौरे, साइट पर जाँच या रिकार्ड/दस्तावेज़ों को देखने का एवं उन व्यक्तियों का जो इसके दौरान आये, रिकार्ड रखेगा, और भारत सरकार द्वारा माँगे जाने पर यह विवरण प्रस्तुत करेगा।

(ड.) दौरे के दौरान किन्हीं वस्तुओं, सेवाओं और प्रौद्योगिकियों, और ड्रॉइंग्स, विनिर्देशन शीटों आदि सहित किसी दस्तावेज़ का आदान प्रदान नहीं किया जाएगा।

(च) भारत सरकार द्वारा माँगे जाने पर निर्यातक/आयातक को कोई भी अन्य आश्वासन देना पड़ेगा।

(छ) अनुमति में निर्धारित की गई कोई अन्य शर्त।

III. व्यापक विध्वंस के हथियार अधिनियम, 2005 के प्रावधान भी ऐसी व्यवस्था या समझौते पर लागू होंगे जिसके तहत साइट का दौरा, साइट पर जाँच या रिकार्ड/दस्तावेज़ों को देखना शामिल है।

IV. लाइसेंस की किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर कानून के अनुसार सिविल/आपराधिक अभियोग चलाया जाएगा।

2.79 पुनः आदेश जारी करने हेतु प्राधिकार-पत्र का निर्गम

स्कोमेट मदों के निर्यात हेतु पुनः आदेश जारी करने के लिए प्राधिकार हेतु आवेदनों पर चेयरमैन आईएमडब्ल्यूजी द्वारा स्वीकृति दी जाएगी और पूर्वव्यापी आधार पर स्वीकृति के लिए आगामी बैठक में आईएमडब्ल्यूजी के समक्ष मामले को लाया जाएगा। स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के पूरा होने पर ही जाएगी:

(i) (क) तकनीकी ब्यौरे के साथ उत्पाद (ख) निर्यातक (ग) विदेशी क्रेता (घ) प्रौद्योगिकी अथवा मध्यवर्ती, यदि कोई हो (ड.) अन्तिम प्रयोक्ता (च) अन्तिम प्रयोग (छ) गंतव्य देश, समान होंगे।

- (ii) पुनः निर्यात प्राधिकार पत्र के निमित्त अनुमत मात्रा संगत उत्पाद, अन्तिम प्रयोक्ता द्वारा यथाप्रमाणित, के संबंध में अन्तिम प्रयोक्ता की वार्षिक विनिर्माण क्षमता के अधीन मूल प्राधिकार पत्र की मात्रा के दोगुने से अधिक नहीं होगी।
- (iii) मूल स्कोमेट प्राधिकार पत्र के आईएमडब्ल्यूजी के द्वारा अनुमोदन की तारीख से दो वर्ष के भीतर प्रस्तुत किए गए आवेदन ही पुनः प्राधिकार पत्र के लिए पात्र होंगे।
- (iv) मूल प्राधिकार पत्र के निमित्त दो पुनः प्राधिकार पत्र की सीमा होगी।
- (v) (i) से (iv) के अनुसार पुनः आदेश मार्ग के तहत विचारार्थ आवेदन के साथ पात्रता शर्तों पर अधिकृत हस्ताक्षरी द्वारा एक घोषणा प्रस्तुत करनी होगी।

2.79क स्कोमेट मदों के भंडारण और बिक्री हेतु निर्यात प्राधिकार पत्र जारी करना।

'स्टॉकिस्ट' का संदर्भ विदेशी इकाई से है जिसे भारतीय प्रमुख/पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक इकाई द्वारा स्कोमेट मदों का मूलतः निर्यात किया जाता है। स्टॉकिस्ट इकाई को भारतीय निर्यातक की सहायक/प्रधान कम्पनी होना चाहिए। भंडारण एवं बिक्री प्रयोजन हेतु स्कोमेट मदों के निर्यात हेतु प्राधिकार पत्र जारी करने के आवेदनों का मूल्यांकन/विचार निम्नलिखित निर्धारित शर्तों के अधीन आईएमडब्ल्यूजी द्वारा किया जाएगा।

- (क) **स्टॉकिस्ट को 'भंडारण एवं बिक्री' के प्रयोजन हेतु स्कोमेट मदों के निर्यात के लिए प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए आवेदन:**
 - (i) भारत में निर्यात केवल प्रधान कम्पनी/पूर्णतः स्वामित्व की सहायक कम्पनी से विदेश में इसकी सहायक कम्पनियों/प्रधान कम्पनी को उनके वास्तविक प्रयोग सह वास्तविक प्रयोक्ता प्रमाण पत्र (ईयूसी) आधार पर भंडारण एवं बिक्री प्रयोजनों (परिशिष्ट-2छ(iii) के अनुसार) हेतु अनुमत होगा जब इसे सुरक्षा और अन्य महत्वपूर्ण मामलों की दृष्टि से उपयुक्त समझा जाए। उन देशों की विस्तृत सूची, जिनमें स्टॉकिस्ट द्वारा निर्यात किया जाएगा को भंडारण और बिक्री प्रयोजनों हेतु ईयूसी में दर्शाए जाने की आवश्यकता है। निर्यातक और स्टॉकिस्ट के बीच के संबंध के बारे में दस्तावेजी प्रमाण आवेदन के समय प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
 - (ii) भंडारण एवं बिक्री प्राधिकार पत्र धारक को भारत से किए गए निर्यात स्टॉकिस्ट की वस्तु सूची, प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में 31 दिसम्बर तक अंतिम वास्तविक प्रयोक्ता को किए गए हस्तांतरण का विवरण अगले वर्ष की 31 जनवरी तक प्रस्तुत करना होगा। समेकित विवरण को भंडारण एवं बिक्री प्राधिकार पत्र के समाप्त होने से तीन माह की अवधि में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
 - (iii) प्राधिकार पत्र के तहत स्टॉकिस्ट इकाई से निर्यात की गई वस्तुओं को अंतिम वास्तविक प्रयोक्ता को प्राधिकार पत्र की वैध अवधि के अंदर हस्तांतरित किया जाना चाहिए। प्राधिकार पत्र का प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 2.80 में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार पुनर्विधीकरण किया जा सकता है।
 - (iv) 'भंडारण और बिक्री' उद्देश्य हेतु स्कोमेट मदों के निर्यात के लिए प्राधिकार पत्र हेतु किसी भी आवेदन पर स्कोमेट सूची के श्रेणी 0.1ग और 6 में आने वाले मदों के लिए विचार नहीं किया जाएगा।
 - (v) 'भंडारण और बिक्री' उद्देश्य हेतु निर्यात प्राधिकार पत्र किसी भी श्रेणी में 'प्रौद्योगिकी' के लिए जारी नहीं किया जाएगा।
- (ख) **वास्तविक प्रयोक्ता (प्रयोक्ताओं) को स्टॉकिस्ट से पुनः निर्यात/पुनः हस्तांतरण के लिए अनुमति हेतु आवेदन**
 - (i) वास्तविक प्रयोक्ता को स्टॉकिस्ट इकाई से मदों के पुनः निर्यात/पुनः हस्तांतरण हेतु आवेदन निम्नलिखित दस्तावेजों (इसके बाद आवश्यक दस्तावेजों के रूप में संदर्भित किया गया) के साथ एएनएफ-2ण (क) के अनुसार डीजीएफटी (मुख्यालय) को प्रस्तुत किया जाएगा:
 - (क) परिशिष्ट-2छ (i)/2छ (ii), जैसा लागू हो के अनुसार आपूर्ति श्रृंखला में प्रत्येक लिंक से अन्तिम प्रयोक्ता/अन्तिम प्रयोग प्रमाणपत्र
 - (ख) क्रय आदेश (आदेशों)/बीजक (बीजकों)
 - (ग) स्थानांतरित होने वाले उत्पाद का तकनीकी विनिर्देश (केवल तभी जब स्टॉकिस्ट द्वारा उत्पाद में कोई मूल्य वर्धन होगा)
 - (ii) स्टॉकिस्ट द्वारा उसी देश के भीतर पुनः हस्तांतरण:
 - (क) उसी देश में, वास्तविक प्रयोक्ता सहित इकाई (इकाईयों) को स्टॉकिस्ट इकाई (जिनके लिए मद मूलतः भारतीय मूलधन/पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी द्वारा निर्यात किए गए) द्वारा इन मदों को आगे किसी भी हस्तांतरण

के लिए, स्टॉकिस्ट इकाई आपूर्ति श्रृंखला में प्रत्येक लिंक से अपेक्षित दस्तावेजों को प्राप्त करेगा और ऐसे हस्तांतरण के लिए पूर्व अनुमति मांगने हेतु डीजीएफटी (मुख्यालय) को प्रस्तुत करने के उद्देश्य हेतु भारतीय आवेदक/लाइसेंसधारी को उसे अग्रेषित करेगा। आईएमडब्ल्यूजी, तथापि उसी देश के भीतर ऐसे बिक्री/हस्तांतरण के लिए जोखिम मूल्यांकन के आधार पर पूर्व अनुमति की इस शर्त में छूट दे सकता है।

(ख) स्टॉकिस्ट इकाई द्वारा उसी देश में बिक्री/हस्तांतरण के मामले में, जहां आईएमडब्ल्यूजी पूर्व अनुमति की शर्त में छूट देने पर सहमत है, वहां आवश्यक दस्तावेजों को भारतीय आवेदक/लाइसेंसधारी द्वारा ऐसे हस्तांतरण के 3 महीने के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा। ऐसे मामले में, आपूर्ति श्रृंखला में कोई भी लिंक देश के बाहर की इकाई नहीं होनी चाहिए और मद देश के भीतर रहने चाहिए।

(ग) देश एक स्वतंत्र सार्वभौम इकाई को निरूपित करेगा जो राजनीतिक भूगोल में एक विशिष्ट इकाई है। अतः आर्थिक संघ अथवा सीमाशुल्क संघ के भीतर हस्तांतरण 'उसी देश को हस्तांतरण' के रूप में पात्र नहीं होगा।

(iii) स्टॉकिस्ट द्वारा देश के बाहर पुनः निर्यात:

टपने देश के बाहर के इकाई (इकाईयोंको) को स्टॉकिस्ट द्वारा पुनः निर्यात के लिए आवेदन को स्टॉकिस्ट इकाई द्वारा ऐसे हस्तांतरण के लिए पूर्व अनुमति मांगने हेतु डीजीएफटी (मुख्यालय) को प्रस्तुत करने के उद्देश्य के लिए आपूर्ति श्रृंखला में सभी लिंक्स से आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदक/लाइसेंसधारी को अग्रेषित किया जाएगा।

(iv) पुनरावर्ती आदेश के लिए वास्तविक प्रयोक्ता को स्टॉकिस्ट इकाई से स्कोमेट मदों के पुनः निर्यात/पुनः हस्तांतरण के लिए आवेदनों पर आईएमडब्ल्यूजी द्वारा स्वचालित आधार पर विचार किया जाएगा, जो शर्तों के अधीन है कि, उत्पाद तकनीकी विनिर्देशन: विदेशी क्रेता: प्रेषिती या मध्यस्थ, यदि कोई है के साथ हो, वास्तविक प्रयोक्ता, वास्तविक प्रयोग और गंतव्य का देश, पहले की अनुमति के समान होगा।

2.79ख भण्डारण और बिक्री के अधीन स्कोमेट मदों के पुरजों हेतु निर्यात प्राधिकार पत्र को जारी करना।

आवेदक के अनुरोध पर, स्कोमेट के तहत पुरजों के लिए निर्यात अनुमति पर मुख्य मद/उपकरण हेतु आवेदन के साथ आईएमडब्ल्यूजी द्वारा विचार किया जा सकता है। तदनुसार, पुरजों के निर्यात हेतु अनुमति मांगने वाले आवेदक न्यायोपित और उसके तर्कसंगत मूल्यांकन के बाद मुख्य उपकरण हेतु आवेदन में पुरजों की आवश्यकता को दर्शात और उसके लिए औचित्य प्रदान करे।

2.80 स्कोमेट प्राधिकार पत्र का पुनः वैधीकरण

स्कोमेट मदों के लिए निर्यात लाइसेंस का पुनः वैधीकरण प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 2.20 (ख) के अनुसार क्षेत्रीय प्राधिकार द्वारा किया जा सकता है।

2.81 स्कोमेट श्रेणी 6 की मदों का निर्यात

पैराग्राफ 2.73 से 2.80 में शामिल होने के बावजूद, स्कोमेट श्रेणी 6 के मदों के निर्यात की अनुमति रक्षा उत्पादन विभाग द्वारा जारी किए गए प्राधिकार पत्र के मदों दी जाएगी। प्राधिकार पत्र की मंजूरी रक्षा उत्पादन विभाग द्वारा इस उद्देश्य हेतु जारी किए गए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) द्वारा शासित होंगे।

2.82 टिप्पणियों/अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु घटनाक्रम

आईएमडब्ल्यूजी के सदस्य डीजीएफटी (मुख्यालय) द्वारा आवेदनों के अग्रगण्य की तारीख से 30 दिन के भीतर डीजीएफटी को अपनी लिखित टिप्पणियों/विचार/अनापत्ति प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। यदि नियत अवधि के भीतर कोई टिप्पणी/विचार/अनापत्ति प्राप्त नहीं होती है तो इन मामलों को निर्णय लेने हेतु आईएमडब्ल्यूजी के समक्ष, जैसा उचित प्रतीत हो, रखा जाएगा।

राज्य व्यापार उद्यमों (एसटीई) के माध्यम से निर्यात:

2.83 एसटीई के तहत मदों का निर्यात

एसटीई व्यवस्था के तहत आईटीसी (एचएस), 2012 में उल्लिखित मदों के निर्यात हेतु एएनएफ-2ड के तहत एफटीपी के पैरा 2.20 के अनुसार डीजीएफटी को आवेदन किया जा सकता है।

निर्यातकों के लिए प्रावधान/कारोबार और व्यापार करने हेतु अन्य प्रावधान:

2.84 स्तरधारकों के लिए निःशुल्क निर्यात

स्तर धारक निर्यात संवर्धन के लिए निःशुल्क आधार पर मुक्त रूप से निर्यात योग्य मदों का निर्यात करने के पात्र होंगे जोकि पिछले तीन लाइसेंसिंग वर्षों के दौरान औसत वार्षिक निर्यात प्राप्ति के 10 लाख रु या 2 प्रतिशत की वार्षिक सीमा, जो भी कम हो, के अधीन होगा। फार्मा निर्यात हेतु, वार्षिक सीमा पिछले तीन लाइसेंसिंग वर्षों के दौरान औसत वार्षिक निर्यात प्राप्ति 2 प्रतिशत होगी। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों जैसे कि यूएन और डब्ल्यूएचओ-पीएचओ के स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए सरकारी सहायता और वैक्सीन की

आपूर्ति और जीवनदायी दवाओं के मामले में पिछले तीन लाइसेंसिंग वर्षों के दौरान औसत वार्षिक निर्यात प्राप्ति 8 प्रतिशत तक होगी। ऐसी निःशुल्क लागत वाली आपूर्तियां शुल्क वापसी अथवा किसी भी निर्यात संवर्धन स्कीम के तहत कोई अन्य निर्यात प्रोत्साहन के लिए हकदार नहीं होगी।

2.85 बीमा कवर के जरिए भुगतान पर लाभ की स्वीकार्यता

(i) इसीजीसी कवर के जरिए किए गए भुगतान पर विदेश व्यापार नीति के तहत लाभ हेतु विचार किया जाएगा।

(ii) साधारण/निजी बीमा कम्पनियों के जरिए भुगतान:

भारत में साधारण बीमा और निजी अनुमोदित बीमा कम्पनियों द्वारा पारगमन हानि हेतु बीमा कवर की राशि को विभिन्न निर्यात संवर्धन स्कीमों के तहत निर्यात हेतु प्राप्त भुगतान के रूप में माना जाएगा।

(क) बीमा एजेंसी के जरिए निर्यात आय प्राप्त करने वाले आवेदक को संबंधित बीमा एजेंसी द्वारा जारी किए गए भुगतान के साक्ष्य के साथ संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी से सम्पर्क करना होगा। क्षेत्रीय प्राधिकारी दावे के प्रामाणिक आवेदक से संतुष्ट होने के पश्चात् अपर महानिदेशक, विदेश व्यापार (ईडीआई) का अनुमोदन प्राप्त करेगा और मामले की प्रक्रिया हेतु डीजीएफटी की ईडीआई प्रणाली में मूल्य (ईबीआरसी के बजाए) अपलोड करेगा।

(ख) यदि बीमा एजेंसी द्वारा जारी भुगतान के साक्ष्य में दावा मूल्य का उल्लेख विदेशी मुद्रा और भारतीय रुपया दोनों में हो, तो क्षेत्रीय प्राधिकारी प्रक्रिया हेतु विदेशी मुद्रा मूल्य का प्रयोग करेगा। यदि दावा मूल्य का उल्लेख केवल समतुल्य भारतीय रुपए में ही हो तो क्षेत्रीय प्राधिकारी इस भारतीय रुपये के मूल्य को बीमा दावे के निपटान की तारीख को लागू विदेशी मुद्रा (सीबीईसी द्वारा प्रकाशित), का उपयोग करके समतुल्य अमरीकी डॉलर में बदल देगा।

2.86 अपरिवर्तनीय साख पत्र

उन मामलों में जहाँ आवेदक अपरिवर्तनीय साखपत्र (या विनिमय बिल जो बिना शर्त बैंक द्वारा भुनाया/सह-स्वीकृत/ बैंक द्वारा गारंटी दी गयी हो) के मद्दे शुल्क क्रेडिट स्क्रिप्ट/ई ओ के निपादन हेतु आवेदन करता है तथा निर्यात और प्राप्ति से संबंधित बैंक प्रमाणपत्र में निर्यातक बैंक द्वारा पुष्ट और प्रमाणित किया जाता है तो निर्यात आय का भुगतान प्राप्त कर लिया गया माना जाएगा। स्तर-धारकों के लिए अपरिवर्तनीय साख-पत्र पर्याप्त रहेगा।

2.87 निर्यात आय वसूली को आर बी आई द्वारा बट्टे खाते में डालना

विदेश व्यापार नीति के तहत निर्यात आय की प्राप्ति पर जोर नहीं दिया जाएगा, यदि गुण-दोष के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक अथवा अन्य अधिकृत बैंक (इस प्रयोजन हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिकृत) प्राप्ति की आवश्यकता को बट्टे खाते में डाल देता है और निर्यातक भारत के संबंधित विदेशी मिशन से क्रेता से निर्यात प्राप्तियों की गैर-वसूली के बारे में प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर देता है। तथापि, यह स्वयं द्वारा बट्टे खाते में डाले गए मामलों पर लागू नहीं होगा।

2.88 एक स्कीम से दूसरी स्कीम में शिपिंग बिल की ईपी प्रति में परिवर्तन

यदि सीमाशुल्क प्राधिकारी, लिखित रूप में कारणों को दर्ज करने के बाद, किसी स्कीम-पोतलदान बिल की ई.पी. प्रति के परिवर्तन की अनुमति देते हैं जिस पर उस स्कीम का लाभ नहीं लिया गया है, निर्यातक उस स्कीम के तहत लाभ पाने का हकदार होगा जिसमें पोतलदान को बाद में परिवर्तित किया गया है।

2.89 निर्यात आय की ऑफसेटिंग

किसी भी निर्यात संवर्धन स्कीम के अन्तर्गत प्राधिकार पत्र धारक किसी देय या इक्विटी निवेश के मद्दे अपनी निर्यात आय को ऑफसेट प्राप्तियों के रूप में प्रयोग कर सकता है बशर्ते कि भारतीय रिजर्व बैंक का विशेष अनुमोदन लिया गया हो। ऐसे मामलों में, ऑफसेटिंग निर्यात आय की प्राप्ति के बराबर होगी तथा निर्यातक को निम्नलिखित अतिरिक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे:-

(क) बैंक प्राप्ति प्रमाणपत्र की एवज में **परिशिष्ट-2ठ**

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक की विशेष अनुमति।

गुणवत्ता प्रमाणन संबंधी प्रावधान:

2.90 गुणवत्ता प्रमाणन

यह निरन्तर कोशिश रही है कि निर्यात उत्पाद का विनिर्माण करने वाले एककों/निर्यात उत्पाद में गुणवत्ता मानदण्डों को बढ़ावा दिया जाए।

गुणवत्ता प्रमाणन प्रदान करने हेतु अधिकृत एजेंसियाँ:

(क) गुणवत्ता प्रमाणन देने के लिए जिन्हें प्राधिकृत किया गया है, ऐसे अभिकरणों की सूची **परिशिष्ट-2** में दी गई है।

(ख) आईएसओ 9000 (श्रृंखला) और आई एस ओ 14000 (श्रृंखला) के लिए भारतीय गुणवत्ता परिषद् के तहत नेशनल एक्रिटेशन बोर्ड फार सर्टिफिकेशन बाडीज (एनएबीसीबी) से मान्यता प्राप्त अधिकरणों को इस नीति के तहत प्राधिकृत माना जायेगा। ऐसे मान्यता प्राप्त अभिकरणों की सूची www.qcin.org वेबसाइट पर उपलब्ध है और **परिशिष्ट-2** में दी गई है।

(ग) एजेंसियों को आईएसओ (9000) श्रृंखला और आईएसओ 14000 श्रृंखला के लिए निम्नलिखित के अतिरिक्त वर्गीकरण पर मान्यता दी गई है:

(i) गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (क्यूएमएस)-

<http://www.qcin.org/nabcb/accreditation/reg.bod qms.php>

गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के लिए

(ii) पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली (ईएमएस)-

<http://www.qcin.org/nabcb/accreditation/reg.bod ems.php>

पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली के लिए।

इन एजेंसियों को एएनएफ के **परिशिष्ट-2** में सूचीबद्ध किया गया है।

(घ) **परिशिष्ट-2** में अपना नाम लिखवाने के इच्छुक अभिकरण **परिशिष्ट-2** के अनुलग्नक-I के अनुसार डीजीएफटी को अपना आवेदन कर सकते हैं।

2.90क औषध सूत्रीकरण के निर्यात के लिए खोज-बीन प्रणाली

औषध सूत्रीकरण के निर्यात के लिए खोज-बीन प्रणाली के कार्यान्वयन की प्रक्रिया निम्नलिखित है:

(i) औषध सूत्रीकरण के विनिर्माता अथवा निर्यातक अपने उत्पादों की खोज-बीन को सुकर बनाने हेतु विभिन्न पैकेजिंग स्तरों पर **जीएस1 वैश्विक स्तर** के अनुसार बारकोड का मुद्रण करेंगे। इसका ब्यौरा इस प्रकार है:

(क) **प्रारंभिक स्तर:**

14 अंकीय वैश्विक व्यापार मद संख्या (जी.टी.आई.एन) के प्रारूप में अद्वितीय और **सार्वभौम वैश्विक उत्पाद पहचान** कोड का कूटलेखन करते हुए द्विआयामी (2डी) बार कोड का बैच सं०, समाप्ति की तारीख और प्राथमिक पैक की अद्वितीय क्रम संख्या सहित समावेश। प्रारंभिक स्तर पर बार कोड लेबल लगाए जाने पर अगली अधिसूचना तक छूट प्राप्त है, तथापि, अगली अधिसूचना तक **वैकल्पिक आधार पर** ऊपर उल्लिखित ब्यौरे को पढ़ने योग्य रूप में मुद्रण किया जाना अपेक्षित है।

(ख) **द्वितीयक स्तर:**

एक अथवा द्वि-आयामी (1डी अथवा 2 डी) बारकोड को सम्मिलित करना जिसमें द्वितीयक पैक की बैच संख्या, अंतिम तिथि तथा एक विशिष्ट क्रम संख्या के साथ 14 अंकों की वैश्विक व्यापार मद संख्या (जीटीआईएन) के प्रारूप में विशिष्ट और सार्वभौमिक वैश्विक उत्पाद पहचान कोड उल्लिखित किया गया हो। तथापि, मोनो कार्टनों के मामले में विनिर्माता अथवा निर्यातक अगली अधिसूचना तक वैकल्पिक आधार पर एक प्रारंभिक पैक वाले मोनो कार्टन पर बारकोड मुद्रित करेंगे।

(ग) **तृतीयक स्तर:**

एक आयामी (1डी) बारकोड को सम्मिलित करना जिसमें तृतीयक पैक की बैच संख्या, अंतिम तिथि तथा एक विशिष्ट श्रेणी संख्या अर्थात् क्रमिक पोतलदान कंटेनर कोड (एसएससीसी) के साथ 14 अंकों की वैश्विक व्यापार मद संख्या (जीटीआईएन) के प्रारूप में विशिष्ट एवं सार्वभौमिक वैश्विक उत्पाद पहचान कोड उल्लिखित किया गया हो।

(ii) एसएसआई तथा गैर एमएसआई विनिर्माताओं हेतु **पैरेंट-चाइल्ड संबंध:**

विनिर्माता अथवा निर्यातक त्रि-स्तरीय पैकेजिंग अर्थात् प्रारंभिक द्वितीयक तथा तृतीयक पैकेजिंग तथा इनकी आपूर्ति संख्या में संचालन हेतु आंकड़ों की देख-रेख पैरेंट-चाइल्ड संबंध के रूप में करेंगे।

(iii) **पैरेंट चाइल्ड संबंध के डाटा का रख-रखाब:**

ऊपर पैरा (ii) में उल्लिखित आँकड़ों को बिक्री या वितरण हेतु संरूपण जारी किए जाने से पहले विनिर्माता अथवा निर्यातक

अथवा उसकी पदनामित एजेंसी द्वारा भारत सरकार के केन्द्रीय पोर्टल (<http://dava.gov.in>) पर अपलोड किया जाएगा।

- (iv) शुद्धता, पूर्णता और केन्द्रीय पोर्टल पर डाटा समय पर अपलोड करने की जिम्मेवारी विनिर्माता अथवा निर्यातक की होगी।
- (v) उपर्युक्त नियम (i) से (iv) निर्यात प्रयोजनों के लिए विनिर्मित उन औषध संरूपणों के लिए लागू नहीं होंगे, जिनमें आयातक देश की सरकार ने विशिष्ट आवश्यकता का अधिदेश दिया है तथा निर्यातक डीसीजीआई और उसके नामिती की विधिवत अनुमति से अपने प्रपत्र में बारकोड प्रिन्ट कराने के विकल्प का लाभ लेना चाहता है। तथापि, तृतीयक स्तर की पैकेजिंग में आयात देश की आवश्यकता, यदि कोई हो, के अलावा उपर्युक्त (i) (ग) के अनुसार बार कोड की अतिरिक्त प्रिन्टिंग होगी।
- (vi) गैर-लघु उद्योग इकाइयों द्वारा दिनांक 31.03.2016 तक विनिर्मित उत्पाद और लघु उद्योग इकाइयों द्वारा दिनांक 31.03.2017 तक विनिर्मित उत्पादों को केन्द्रीय पोर्टल पर डाटा अपलोड करने की आवश्यकता से छूट होगी।
- (vii) गैर लघु उद्योग इकाइयों द्वारा दिनांक 01.04.2016 को या उसके बाद विनिर्मित सभी औषधों तथा दिनांक 01.04.2017 को या उसके बाद की विनिर्माण तारीख वाले लघु उद्योग इकाइयों के सभी औषध का तभी निर्यात किया जा सकता है, जब तृतीयक और द्वितीयक दोनों पैकेजिंग में यथा लागू बारकोड हो तथा विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा यथा निर्धारित संगत आंकड़ा केन्द्रीय पोर्टल पर अपलोड किया जाए।

स्पष्टीकरण :

(क) इस नियम के प्रयोजन हेतु,

- (i) औषध संरूपण का अर्थ ऐसे संरूपण से है जो औषध एवं सौन्दर्य सामग्री अधिनियम के प्रावधानों तथा उसके तहत निर्मित नियमावली के तहत औषध नियंत्रण प्राधिकारी से प्राप्त लाइसेंस के अंतर्गत विनिर्मित हो और आयातकर्ता देश के खाद्य एवं औषध प्रशासन के पास "औषध" के रूप में पंजीकृत हो।
- (ii) प्रारंभिक पैकेजिंग का अर्थ ऐसे पैकेज से है जो सक्रिय घटक के साथ प्रत्यक्ष वास्तविक सम्पर्क में है।
- (iii) द्वितीय पैकेजिंग का अर्थ एक अथवा एक से अधिक प्रारंभिक पैक्स युक्त कार्टन और एक प्रारंभिक पैक युक्त मोनो कार्टन समाविष्ट है।
- (iv) तृतीय पैकेजिंग का अर्थ एक अथवा एक से अधिक द्वितीय पैकेजिंग युक्त शिपर है।
- (ख) विशेष रियायत (रियायतें) यदि कोई है, को प्रदान करने के संबंध में सभी प्रासंगिक दिशा-निर्देश, डेटा आवश्यकता/रखरखाव की प्रक्रिया केन्द्रीय पोर्टल पर अपलोड है और इस अधिसूचना के तहत जारी स्पष्टीकरण आदि केन्द्रीय पोर्टल अर्थात् <http://dava.gov.in> पर उपलब्ध हो जाएगी।
- (ग) औषध विनिर्माताओं/निर्यातकों की यह जिम्मेवारी होगी कि जैसी स्थिति हो वह सीमाशुल्क प्राधिकारी को संतुष्ट करें कि निर्यात खेप अधिसूचना की शर्तों की पूर्ति कर रहा है।

निर्यात संवर्धन परिाद् (ईपीसी)/पण्य बोर्ड:

2.91 पंजीकरण प्राधिकरण

(क) इस संबंध में पंजीकरण प्राधिकरण डीजीएफटी द्वारा अधिसूचित एक निकाय है जिसका उद्देश्य आयातकों/निर्यातकों को आरसीएमसी जारी करके अपने सदस्य के रूप में पंजीकृत करना है।

(ख) अधिसूचित पंजीकरण प्राधिकरणों की सूची **परिशिष्ट-2न** पर है।

(ग) वर्तमान में आरसीएमसी हेतु पंजीकरण प्राधिकरणों के रूप में कार्य कर रहे ईपीसी पंजीकरण प्राधिकरणों के रूप में कार्य करते रहेंगे और अपने सदस्यों को 31 मार्च 2016 तक आर.सी.एम.सी जारी करते रहेंगे। अपने उत्पाद समूह के लिए पंजीकरण प्राधिकरण के रूप में कार्य करते रहने की इच्छा रखने वाले ईपीसी को उन शर्तों का अनुपालन करना और 31 मार्च 2016 से पहले पूरा करना होगा जैसा कि नीचे दिए गए पैरा 2.92 में विनिर्दिष्ट किया गया है।

2.92 पंजीकरण प्राधिकरणों के रूप में ईपीसी के लिए मानदण्ड

ईपीसी को वस्तुतः लोकतान्त्रिक और सहभागी स्वरूप का बनाने तथा बेहतर अभिशासन और पारदर्शिता लाभ के उद्देश्य से पंजीकरण प्राधिकरण के रूप में कार्य करने हेतु मानदण्ड निर्धारित किया जा रहा है जो इस प्रकार है:-

(क) **ई-वोटिंग:** उपाध्यक्ष और कार्यकारी समिति के सदस्यों के पदों के निर्वाचन हेतु इलेक्ट्रॉनिक मतदान अनिवार्य होगा जिससे कि व्यापक भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।

(ख) **निर्वाचित प्रमुखों का कार्यकाल:** एक निर्वाचित प्रमुख का कार्यकाल दो वर्ष के लिए होगा। ईपीसी के अध्यक्ष का निर्वाचन

उपाध्यक्ष के माध्यम से होगा तथापि कोई सदस्य जो अध्यक्ष तथा/अथवा उपाध्यक्ष के पद पर रहा हो, अधिक से अधिक चार वर्ष के अन्तराल के पश्चात् उसी परिषद में उपाध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण कर सकता है।

(ग) **केन्द्र सरकार के निर्देश:** पंजीकरण प्राधिकरण के रूप में कार्य कर रहे ईपीसी अन्तराष्ट्रीय व्यापार के संवर्धन और विकास संबंधी केन्द्र सरकार के सभी निदेशों का पालन करेंगे।

2.93 पंजीकरण - सह - सदस्यता प्रमाणपत्र (आरसीएमसी)

(क) निर्यातक, **एएनएफ-2ग** में दिए गए प्रपत्र में आवेदन करके स्वयं को पंजीकृत करवा सकता है और ई पी सी का सदस्य बन सकता है। सदस्यता मिल जाने पर आवेदक को **परिशिष्ट-2द** में दिए गए प्रपत्र में संबंधित ई पी सी का पंजीकरण-सह-सदस्यता प्रमाणपत्र दिया जाएगा। यदि कोई निर्यातक विनिर्माता निर्यातक के रूप में पंजीकरण करवाना चाहता है तो उसे इस आशय का सबूत देना होगा।

(ख) भावी/सम्भावित निर्यातक भी आवेदन करके स्वयं को पंजीकृत करवा सकते हैं और ईपीसी के सहयोगी सदस्य बन सकते हैं।

2.94 पंजीकरण सह सदस्यता प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करना

(क) पंजीकरण सह सदस्यता प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करते समय निर्यातक को आवेदन में अपने मुख्य व्यापार की घोषणा करनी होगी। निर्यातक को उस परिषद से पंजीकरण सह सदस्यता प्राप्त करना होगा जो उसके मुख्य व्यापार के उत्पाद से संबंधित हो।

(ख) यदि निर्यात उत्पाद ऐसा है कि वह किसी निर्यात संवर्धन परिषद/पण्य बोर्ड आदि में शामिल नहीं है तो इसके संबंध में पंजीकरण सह सदस्यता फियो से प्राप्त की जाएगी। आगे यदि बहु-उत्पाद निर्यातक जो किसी भी निर्यात संवर्धन परिषद में पंजीकृत नहीं हैं, जहाँ मुख्य व्यापार समझने योग्य नहीं है, वहाँ निर्यातक के पास फेडरेशन ऑफ इण्डियन एक्सपोर्टर्स आर्गेनाइजेशन (फियो) से पंजीकरण सह-सदस्यता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने का विकल्प रहेगा।

(ग) जिन बहु उत्पाद निर्यातकों के मुख्यालय/पंजीकृत कार्यालय उत्तर पूर्व राज्यों में स्थित हो वे आरसीएमसी सैलक व वन्य उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद (एपीडा, स्पाइस बोर्ड और टी बोर्ड के द्वारा देखे जाने वाले उत्पादों के अतिरिक्त) से प्राप्त करेंगे।

(घ) जम्मू-कश्मीर राज्य से हथकरघा एवं हस्तशिल्प के निर्यातकों के लिए पंजीकरण-सह- सदस्यता प्रमाण पत्र जारी करने हेतु निदेशक, हथकरघा, जम्मू-कश्मीर सरकार को प्राधिकृत किया गया है।

2.95 आर सी एम सी की वैधता अवधि

आर सी एम सी लाइसेंसिंग वर्ष, जिसमें यह जारी किया गया है, के 1 अप्रैल से वैध होगा और लाइसेंसिंग वर्ष, के 31 मार्च के अन्त तक पाँच वर्ष के लिए वैध होगा, जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न किया गया हो।

2.96 आरसीएमसी धारक के व्यापारिक संविधान में परिवर्तन के संबंध में सूचना देना

(क) निर्यातक का स्वामित्व, संविधान, नाम या पते में परिवर्तन होने पर आर सी एम सी धारक को ऐसा परिवर्तन होने की तारीख से एक महीने की अवधि के भीतर पंजीकरण प्राधिकारी को इस परिवर्तन के बारे में बताना जरूरी होगा। तथापि, पंजीकरण प्राधिकारी गुण-दोष के आधार पर विलम्ब को नज़रअंदाज़ कर सकता है।

(ख) निर्यातक विभिन्न वस्तुओं के निर्यात की तिमाही विवरणी/ ब्यौरे संबंधित पंजीकरण प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा। तथापि, स्तर धारक फियो द्वारा निर्दिष्ट प्रपत्र में फियो को तिमाही विवरणी भी भेजेंगे।

2.97 पंजीकरण रद्द करना

पंजीकरण प्राधिकारी पंजीकरण की शर्तों का उल्लंघन करने पर निर्दिष्ट अवधि के लिए आर सी एम सी धारक का पंजीकरण रद्द कर सकता है। इस प्रकार पंजीकरण रद्द करने से पहले, आर सी एम सी धारक को पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा और प्रस्तावित पंजीकरण रद्द करने के विरुद्ध अभ्यावेदन करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त अवसर दिया जाएगा। पंजीकरण रद्द किए जाने पर संबंधित ई पी सी इसके बारे में सभी क्षेत्रीय प्राधिकारियों को सूचित करेगा।

2.98 पंजीकरण रद्द करने के विरुद्ध अपील

यदि किसी व्यक्ति को आरसीएमसी जारी किए जाने के संबंध में पंजीकरण प्राधिकारी के निर्णय से कोई दिक्कत है तो वह विदेश व्यापार महानिदेशालय या इनकी ओर से पदनामित किसी अधिकारी को उक्त निर्णय लिए जाने के विरुद्ध 45 दिन के भीतर अपील कर सकता है और अपील प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

2.99 विदेश व्यापार महानिदेशालय के निर्देश

विदेश व्यापार महानिदेशालय निर्यातक को पंजीकृत करने या उसका पंजीकरण रद्द करने के बारे में पंजीकरण प्राधिकारी को निर्देश दे सकता है अथवा विदेश व्यापार (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के उपबंधों, इसके तहत बनाये गए नियमों और आदेशों, विदेश व्यापार नीति या इस प्रक्रिया पुस्तक को कार्यान्वित करने के लिए अन्य कोई निर्देश जारी कर सकता है।

अन्य सामान्य प्रावधान:

2.100 आयातकों/निर्यातकों के लिए पहचान पत्र

(क) विदेश व्यापार महानिदेशालय मुख्यालय और क्षेत्रीय प्राधिकारियों से प्राधिकार पत्र तथा अन्य दस्तावेजों को प्राप्त करने की सुविधा के लिए आयातकों और निर्यातकों को प्रोपराइटर/साझेदारों/निदेशकों और प्राधिकृत कर्मचारियों (तीन से अधिक नहीं) को एएनएफ-2ख में पहचान पत्र (परिशिष्ट 2ब में 3 वर्षों के लिए वैध) जारी किए जा सकते हैं।

(ख) इसके अलावा, आवेदक फर्म द्वारा संबंधित कर्मचारियों को अपने लैटर हैड पर पहचान पत्र भी जारी कर सकती हैं। ये पहचान पत्र संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होंगे। तथापि, आवेदक द्वारा पहचान पत्र के लिए आवेदन एएनएफ-2ख में प्रस्तुत करना होगा और अन्य मानदण्डों को पूरा करना होगा।

(ग) लिमिटेड कंपनियों के मामले में, क्षेत्रीय प्राधिकारी प्रति कम्पनी तीन से अधिक पहचान पत्र जारी करने का अनुमोदन दे सकता है। पहचान पत्र गुम होने के मामले में, एक स्व-घोषणा के आधार पर डुप्लीकेट कार्ड जारी किया जा सकता है। क्षेत्रीय प्राधिकारी लिखित रूप में कारण दर्ज करने के बाद बहुप्रयोजन पहचान पत्र जारी कर सकता है।

2.101 अधिकृत अधिकारियों के साथ साक्षात्कार

अधिकारी अपने विवेकानुसार आयातक/निर्यातक के प्राधिकृत प्रतिनिधि को भी साक्षात्कार के लिए बुला सकते हैं। साक्षात्कार/स्पष्टीकरण ई.मेल के माध्यम से भी माँगे जा सकते हैं।

2.102 अधिकृत हस्ताक्षरी

निर्यातक/आयातक की ओर से क्षेत्रीय प्राधिकरण सहित विदेश व्यापार महानिदेशालय को किए जाने वाले पत्र व्यवहार में फर्म/कम्पनी द्वारा ऐसे पत्र व्यवहार करने हेतु विधिवत रूप से अधिकृत व्यक्ति का नाम, हस्ताक्षर, ईमेल आईडी अवश्य होना चाहिए।

अधिमान्य व्यापारिक समझौते:

2.103 मुक्त व्यापारिक समझौते (एफटीए)/अधिमान्य व्यापारिक समझौते (पीटीए)

(क) भारत हमेशा पारदर्शी, साम्य, समोवशी, पूर्वानुमेय, गैर-अधिमान्य और नियमों पर आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रणाली का पक्षधर रहा है। इस संबंध में भारत के व्यापारिक समझौतों को अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में भारतीय अर्थव्यवस्था के नपे-तुले और सुदृढ़ प्रदर्शन के रूप में देखा जा सकता है। अक्टूबर-2014 की स्थिति के अनुसार भारत ने 10 मुक्त व्यापारिक समझौतों और 6 सीमित अधिमान्य व्यापारिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत की लगभग 18 अन्य मुक्त व्यापारिक समझौतों पर बातचीत चल रही है।

(ख) भारत द्वारा हस्ताक्षर किए गए एफटीए की सूची इस प्रकार है:

- (i) भारत-श्रीलंका एफटीए
- (ii) दक्षिण एशिया मुक्त व्यापारिक समझौते पर समझौता (साफ्टा)
- (iii) अनधिकृत व्यापार पर नियंत्रण के उद्देश्य को भारत और नेपाल सरकार के बीच सहयोग का संशोधित समझौता।
- (iv) व्यापार, वाणिज्य और पारगमन पर भारत-भूटान समझौता
- (v) भारत-थाइलैंड एफटीए-अर्ली हार्वेस्ट स्कीम (ईएसएच)
- (vi) भारत-सिंगापुर व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता (सीईसीए)
- (vii) भारत-आसियान सीईसीए (माल, सेवा एवं निवेश)
- (viii) भारत-दक्षिण कोरिया व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता (सीईपीए)
- (ix) भारत-जापान सीईपीए
- (x) भारत-मलेशिया सीईसीए

(ग) भारत द्वारा हस्ताक्षर किए गए अधिमान्य व्यापारिक समझौता (पीटीए) की सूची:

- (i) एशिया प्रशांत व्यापारिक समझौता (एपीटीए)
- (ii) व्यापारिक प्राथमिकताओं की वैश्विक प्रणाली (जीएसटीपी)
- (iii) भारत-अफगानिस्तान पीटीए
- (iv) भारत-मर्कोसुर पीटीए
- (v) भारत-चिली पीटीए
- (vi) सार्क अधिमान्य व्यापारिक समझौता (साप्टा)

(घ) भागीदार देशों के साथ उक्त समझौते और उनके लागू होने की तारीख की सूची **परिशिष्ट-2क** में दी गई है।

2.104 एकपक्षीय टैरिफ प्राथमिकताएँ

इन स्कीमों के तहत विकसित और विकासशील दोनों देश अल्प विकसित देशों सहित विकासशील देशों से निर्यात को एक पक्षीय टैरिफ प्राथमिकताएँ देते हैं। इनमें से कुछ स्कीमें इस प्रकार हैं:

(क) तरजीहों की सामान्यकृत प्रणाली (जीएसपी):

(क) जीएसपी एक गैर अनुबंधीय व्यवस्था है जिसके द्वारा औद्योगिक (विकसित) देश एकतरफा तौर पर और गैर-आदान प्रदान के आधार पर विकसित देशों को प्रशुल्क छूट दे सकती हैं। निम्नलिखित देश अपनी जी एस पी स्कीम के तहत प्रशुल्क तरजीहें उपलब्ध कराते हैं: (i) संयुक्त राज्य अमेरिका (ii) न्यूजीलैंड (iii) बेलारूस (iv) यूरोपीय संघ (v) जापान (vi) रूस (vii) कनाडा (viii) नार्वे (ix) आस्ट्रेलिया (केवल एलडीसी को) (x) स्विटजरलैंड

(ख) लाभ दिलाने की शर्तों और प्रक्रियाओं सहित इन देशों की जीएसपी स्कीमों में सैक्टरों/उत्पादों और टैरिफ लाइनों के ब्यौरे हैं जिसके तहत ये लाभ उपलब्ध हैं। ये स्कीमें समय-समय पर नवीकृत और संशोधित की जाती हैं। सामान्यतः जीएसपी प्रदान करने वाले देशों के सीमाशुल्क कार्यालय लाभान्वित देशों के निर्यातकों द्वारा विधिवत रूप से भरे हुए फार्म 'क' (उद्गम के जीएसपी नियमों हेतु निर्धारित) में अपेक्षित सूचना मांगते हैं जो प्राधिकृत एजेंसियों द्वारा प्रमाणित हो। उद्गम का जीएसपी उद्गम प्रमाणपत्र जारी करने वाली एजेंसियों की सूची **परिशिष्ट-2ग** में दी गयी है।

(ग) यूरोपीय संघ (ईयू) ने 1.1.2017 के बाद से जीपीएस के तहत मूल के नियमों को प्रमाणित करने के लिए स्वयं-प्रमाणन योजना लागू की है। 1.1.2017 से पंजीकृत निर्यातक प्रणाली (आरईएक्स) के तहत लागू की गई है, आरईएक्स संख्या वाले निर्यातकों को जीएसपी योजना के तहत ईयू को निर्यात किए जाने वाले अपने सामान के मूल पर स्वयं प्रमाणित बयान करने में सक्षम हो जाएगा। आरईएक्स पर पंजीकरण बिना किसी शुल्क या चार्ज के है और यह प्रणाली **परिशिष्ट-2ग** में सूचीबद्ध सक्षम प्राधिकरणों द्वारा मूल के प्रमाण पत्र (पपत्र-क) के जारी करने की वर्तमान प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है। इस योजना का विवरण अनुबंध-1 से **परिशिष्ट-2ग** पर है।

(ख) अत्यंत अल्प विकसित देशों के लिए शुल्क मुक्त प्रशुल्क तरजीह (डीएफटीपी) स्कीम:

(क) अत्यंत अल्प विकसित देशों (एलडीसी) के लिए शुल्क मुक्त, कोटा मुक्त (डीएफक्यूएफ) पहुंच के लिए अधिदेश 2005 के हॉगकांग अधिकार प्राप्त घोषणा के पैरा-47 से प्राप्त हुआ है। भारत एलडीसी के लिए अपनी शुल्क मुक्त प्रशुल्क तरजीह (डीएफटीपी) स्कीम के माध्यम से यह सुविधा प्रदान करने वाला पहला विकासशील देश बन गया है और यह स्कीम पांच वर्षों से प्रशुल्क कटौतियों के साथ अगस्त 2008 में आरंभ हुई। इस स्कीम में प्रशुल्क लाइनों के संबंध में अधिमानी बाजार पहुंच की व्यवस्था है जिसमें सभी एलडीसी के वैश्विक निर्यात का 92.5 प्रतिशत हिस्सा है।

(ख) तत्पश्चात् 2014 में इस स्कीम को कवरेज के साथ-साथ इसको सरलीकरण के संदर्भ में बदलाव किया गया। यह कदम अनेक एलडीसी द्वारा उनके निर्यात सहित और उत्पत्ति प्रक्रियाओं की नियमावली के सरलीकरण के क्षेत्रों पर अतिरिक्त उत्पाद कवरेज हेतु अनुरोध के प्रत्युत्तर में उठाया गया है। नई विस्तारित डीएफटीपी स्कीम के तहत भारत कुल निशुल्क लाईनों के 96.4 प्रतिशत भाग पर शुल्क मुक्त पहुंच प्रदान कर रहा है जिससे अपवर्जन और सकारात्मक सूचियों के लगभग 3.6 प्रतिशत लाईनों तक ही रोका जा रहा है। इस संबंध में विस्तृत ब्यौरे के लिए वाणिज्य विभाग की वेबसाइट:

<http://commerce.gov.in/trade/international ttp DFTP.pdf> और सीमाशुल्क विभाग की अधिसूचना सं0.8/2014,

दिनांक 1 अप्रैल 2014 का संदर्भ लिया जा सकता है।

2.105 उद्गम प्रमाणपत्र (सीओओ)

- (क) उद्गम प्रमाण पत्र (सीओओ) किसी देश से आयातित माल के उद्गम का प्रमाण स्थापित करने का साधन है।
- (ख) उद्गम प्रमाण पत्र की दो श्रेणियाँ हैं अर्थात्
- तरजीही और
 - गैर-तरजीही।

2.106 उद्गम की नियमावली (तरजीही)

(क) उद्गम की नियमावली ऐसी नियमावली है जिसके द्वारा किसी माल के उद्गम का निर्धारण कारोबारी भागीदार को निर्यात के प्रयोजन हेतु किया जाता है। एफटीए, पीटीए अथवा एकपक्षीय प्रशुल्क रियायत के तहत प्रशुल्क रियायत किसी आयातकर्ता देश द्वारा तभी प्रदान की जाती है जब उद्गम की इस निर्धारित नियमावली का पालन किया जाता है। उद्गम नियमावली से कारोबार संबंधी आंकड़ों के आकलन तथा कारोबार संबंधी उपचारात्मक उपायों के निर्धारण और अधिरोपण में भी आसानी होती है।

(ख) उद्गम नियमावली के निर्धारण में इस्तेमाल होने वाल प्रमुख मानदण्ड इस प्रकार हैं:

- पूर्णतः प्राप्त
- प्रशुल्क वर्गीकरण में परिवर्तन
- मूल्य वर्धन
- गैर न्यूनतम प्रचालन

(ग) भारत के एफटीए, पीटीए और जीएसपी के निर्यात हेतु उद्गम प्रमाणपत्र जारी करने के लिए विनिर्दिष्ट एजेंसियाँ अधिकृत हैं। ये एजेंसियाँ उद्गम नियमावली, किसी समझौते के अन्तर्गत आने वाली मदों की सूची, प्रशुल्क प्राथमिकता की सीमा, पात्रता का सत्यापन और प्रमाणन सहित उद्गम प्रमाणपत्र संबंधी सेवाएँ भी प्रदान करेंगी। विभिन्न एफटीए/पीटीए के तहत इन अधिकृत एजेंसियों की सूची **परिशिष्ट-2ख** में दी गई है।

(घ) निर्यात निरीक्षण परिषद (ईआईसी) ऐसी एजेंसी है जो रिक्त प्रमाणपत्र के मुद्रण हेतु अधिकृत है। ईआईसी की वेबसाइट (www.eicindia.gov.in) में उद्गम प्रमाणपत्र जारी करने हेतु प्रक्रिया संबंधी ब्यौरे (शुल्क सहित) उपलब्ध हैं।

2.107 एफटीए/सीईसीए के अधीन टीआरक्यू

सरकार समय-समय पर विभिन्न एफटीए/सीईसीए प्रशुल्क दर कोटा (टीआरक्यू) के तहत आयात हेतु अपनी वचनबद्धताएँ पूरा करती है: तदनुसार डीजीएफटी समय-समय पर टीआरक्यू के प्रशासन हेतु प्रक्रिया अधिसूचित करता है।

मौजूदा प्रशुल्क कोटा इस प्रकार है:

विवरण	एचएस सं.	डब्ल्यूटीओ के अनुसार कोटा दर से कम/अधिक	भारतीय प्रशुल्क के अनुसार कोटा दर से कम/अधिक	अधिसूचना	टीआरक्यू
श्रीलंका से वनस्पति, बेकरी शॉर्टनिंग और मार्जरीन	1516, 1517 या 1518 (15161000, 15171010, 15179030 और 15180040 से भिन्न जो आयात हेतु निर्दिष्ट है।)	-	-	सं0.2/2007-सीमाशुल्क दिनांक 5 जनवरी 2007	*2,50,000 मी.टन
श्रीलंका से काली मिर्च	0904	-	-	सं0.2/2007-सीमाशुल्क दिनांक 5 जनवरी 2007	*2500 मी.टन

श्रीलंका से सूखा नारियल	08011100	-	-	सं0.2/2007-सीमाशुल्क दिनांक 5 जनवरी 2007	*500 मी.टन
श्रीलंका से आयात की जाने वाली पोशाक और इनकी अनुगुंजी वस्तुएँ	61,62	-	5 प्रतिशत/10 प्रतिशत	26/2000-सीमाशुल्क सूची 3	8 मिलियन पीस
श्रीलंका से आयतित चाय और इससे तैयार वस्तुएं	2101	-	5 प्रतिशत/30 प्रतिशत	26/2000-सीमाशुल्क सूची 4	15 मिलियन किग्रा0
नेपाल से वनस्पति वसा (वनस्पति)				22/2007-सीमाशुल्क 5 जून 2007	एक लाख मी.टन
नेपाल से अक्रिलिक यार्न				22/2007-सीमाशुल्क 5 जून 2007	10,000 मी.टन
नेपाल से तांबा उत्पाद	अध्याय 74 आईटीसी (एचएस) और 8544			22/2007-सीमाशुल्क 5 जून 2007	10,000 मी.टन
नेपाल से जिंक आक्साईड				22/2007-सीमाशुल्क 5 जून 2007	2500 मी.टन
* आयात की अनुमति परिशिष्ट 2क के अनुलग्नक-I में यथानिर्धारित व्यवस्थाओं/प्रक्रिया के अधीन दी जाएगी।					

2.108 उद्गम (गैर तरजीही) के नियम

(क) उद्गम (गैर-तरजीही) के नियमों का मानदंड निम्नानुसार है:-

(I) माल को विदेश व्यापार नीति के पैरा 9.31 में 'विनिर्माण' की परिभाषा के अनुसार निर्यातक कंपनी द्वारा विनिर्मित होना चाहिए; और

(II) यदि आयतित निविष्टियाँ (शुल्क प्रदत्त अथवा शुल्क मुक्त) का उपयोग निर्यात उत्पाद के उत्पादन के लिए हुआ हो तो निर्यात उत्पाद को तभी भारत में उद्गम होने वाला माना जाएगा (गैर अधिमान्य) जब आयतित निविष्टियाँ निम्नलिखित प्रक्रियाओं/परिचालनों से होकर गुजरती हो:

(i) सामान्य प्रचालन जिसमें धूल हटाना, फटकना अथवा जाँच करना, छांटना, वर्गीकृत करना, मिलाना (वस्तुओं का सेट बनाना सहित), धुलाई करना, रंगना, काटना शामिल हैं;

(ii) पैकिंग में बदलाव करना और अलग-अलग करना और माल को जोड़ना;

(iii) सामान्य कटिंग, स्लाइसिंग और पुनः पैकिंग अथवा बोतल, फ्लास्क, बैग, बक्सों में भरना, कार्ड अथवा बोर्ड पर फिक्स करना और अन्य सभी सामान्य पैकिंग कार्य;

(iv) परिवहन और भण्डार (जैसे सुखाना, फ्रिज में रखना, लवण-जल में रखना, हवादार बनाना, फैलाना, ठण्डा करना, लवण, सल्फर डाईआक्साईड अथवा अन्य जलीय घोलों में रखना, टूटे हुए भागों को हटाना और इसी तरह के कार्य) के दौरान उत्पादों को अच्छी स्थिति में संरक्षण सुनिश्चित करने हेतु कार्य;

- (v) उत्पादों अथवा उनकी पैकिजिंग पर चिन्ह, लेबल, अथवा अन्य विशेष संकेत लगाना;
- (vi) उत्पादों का सामान्य मिलान करना;
- (vii) पूर्ण उत्पाद बनाने हेतु उत्पादों के पूर्जों को सामान्य रूप से जोड़ना;
- (viii) पुर्जों को अलग-अलग करना;
- (ix) पशु वध जिसका अभिप्राय पशुओं की हत्या है; तथा
- (x) जल व अन्य पदार्थ के साथ मात्र विलयन करना जिससे उत्पादों की विशेषताएं भौतिक रूप से परिवर्तित नहीं होती हैं।

(ख) सरकार ने भी गैर-तरजीही उद्गम का प्रमाणपत्र (सीओओ) जारी करने के लिए कुछ एजेंसियों को नामित किया है। उद्गम के प्रमाणपत्र सामान के उद्गम के साक्ष्य हैं और ये तरजीही प्रशुल्क का कोई अधिकार नहीं देते। इन अधिसूचित एजेंसियों की सूची **परिशिष्ट-2ड.** में दी गई है। इसके अलावा, तरजीही उद्गम प्रमाणपत्र जारी करने हेतु प्राधिकृत एजेंसियाँ गैर-तरजीही उद्गम प्रमाणपत्र भी जारी करने हेतु प्राधिकृत हैं।

(ग) सभी निर्यातकों जिन्हें उद्गम प्रमाणपत्र (गैर-तरजीही) प्रस्तुत करना है, को निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ **परिशिष्ट-2ड.** में उल्लिखित एजेंसियों में से किसी को आवेदन करना होगा:-

- (i) निर्यात उत्पाद में प्रयुक्त मात्रा/निविष्टियों के उद्गम/उपभोग्यों के ब्यौरे।
- (ii) बीजक की दो प्रतियाँ।
- (iii) संबंधित बीजक के लिए पैकिंग सूची दो प्रतियों में।
- (iv) संबंधित अभिकरण द्वारा यथा निर्धारित प्रति प्रमाण पत्र शुल्क 100/- ₹ से अधिक न हो।

(घ) उद्गम प्रमाण पत्र (गैर तरजीही) मंजूर करने से पूर्व एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि उपर्युक्त (क) में परिभाषित मानदंड के अनुसार वस्तुएँ भारतीय मूल की हैं। प्रमाणपत्र **परिशिष्ट-2ड. के अनुलग्नक II** में दिये गये प्रपत्र के अनुसार जारी किया जायेगा। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रमाणपत्र में कोई शुद्धि/पुनः टंकन नहीं किया गया है। **परिशिष्ट-2ड.** में सूचीबद्ध होने की इच्छुक एजेंसी **परिशिष्ट-2ड. के अनुलग्नक-I** के अनुसार डीजीएफटी को अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकती है।

(ड.) **गैर-अधिमानी-स्व-प्रमाणन:** विनिर्माता निर्यातक जो स्तर धारक भी हों **परिशिष्ट-2ड. के अनुलग्नक III** के अनुसार अपने माल को भारत से उद्गम होने को स्व-प्रमाणित करने के पात्र होंगे बशर्ते उनका माल निविष्टि परिवर्तन मानदण्ड को पूरा करता हो।

2.109 स्व-प्रमाणन हेतु अनुमोदित निर्यातक स्कीम (आईएस)

स्कीम का ब्यौरा एएनएफ के परिशिष्ट 2च में दिया गया है।

नीति व्याख्या और रियायत:

2.110: पीआईसी को आवेदन

विदेश व्यापार नीति के पैरा 2.57(ख) के तहत नीति व्याख्या समिति (मुख्यालय में) के एएनएफ-2च में दिए गए किसी भी नीति प्रावधान की व्याख्या के लिए आवेदन किया जाएगा।

2.111: पीआरसी को आवेदन

(क) विदेश व्यापार नीति के पैरा 2.58 के तहत नीति रियायत समिति (पीआरसी) के लिए आवेदन, निर्धारित शुल्क और दस्तावेजों के साथ एएनएफ-2ड. के अनुसार किया जाएगा, इसकी प्रति टिप्पणी के लिए संबंधित आरए को भी दी जाएगी। इसी प्रकार एफटीपी के पैरा 2.59 के तहत किसी भी अधीनस्थ प्राधिकरण द्वारा दिए गए किसी भी समिति के निर्णय या निर्णय/आदेश की समीक्षा के लिए आवेदन, एएनएफ-2ड. में विदेश व्यापार महानिदेशालय में जमा करना आवश्यक है।

(ख) विदेश व्यापार महानिदेशक, सभी अपर महानिदेशकों, सभी संयुक्त महानिदेशकों, सदस्य के रूप में मुख्यालय में नीति प्रभाग के प्रभारी के साथ पीआरसी के अध्यक्ष होंगे और जब आवश्यक हो, समिति विशिष्ट विशेषज्ञता/अनुभव के साथ सह-चयन सदस्य कर सकती है।

अध्याय-3

भारत से निर्यात की स्कीम

3.01 भारत से व्यापारिक वस्तुओं का निर्यात संबंधी स्कीम (एमईआईएस)

- (क) भारत से व्यापारिक वस्तुओं का निर्यात संबंधी स्कीम (एमईआईएस) के लिए नीति विदेश व्यापार नीति के अध्याय 3 में दी गई है।
- (ख) निर्यात (ई-कामर्स का प्रयोग करते हुए, कूरियर अथवा विदेशी पोस्ट ऑफिस के माध्यम से माल के निर्यात के अलावा) पर एमईआईएस के तहत प्रतिफल का दावा करने के लिए एक आवेदन-पत्र विदेश व्यापार महानिदेशालय की वेबसाइट <http://dgft.gov.in> पर संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को एएनएफ 3क में डिजिटल हस्ताक्षर का प्रयोग कर ऑनलाइन प्रस्तुत करना होगा। संबंधित पोतलदान बिलों और ईबीआरसी को ऑन लाइन आवेदन-पत्र के साथ लिंक करना होगा।
- (ग) यदि आवेदन ईडीआई पत्तनों के माध्यम से किए गए निर्यात के लिए प्रस्तुत किया जाता है, तब क्षेत्रीय प्राधिकारी नीचे पैरा 3.01 (ज) के प्रावधानों के तहत दस्तावेजों को छोड़कर किसी अन्य दस्तावेज की वास्तविक रूप से माँग नहीं करेगा, अतः आरए को निम्नलिखित दस्तावेजों की हार्ड कॉपी प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी: जैसे, डीजीएफटी को आवेदन-पत्रों की हार्ड प्रति, ईडीआई पोतलदान बिल, इलेक्ट्रॉनिक बैंक प्राप्ति प्रमाण-पत्र (ई-बीआरसी) और आरसीएमसी। आवेदक को एचबीपी के पैरा 3.03 के तहत निर्धारित तरीके से उतराई का प्रमाण सौंपना होगा।
- (घ) यदि गैर ईडीआई पत्तनों के माध्यम से किए गए निर्यात के लिए आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया जाता है तब आवेदक को गैर-ईडीआई पोतलदान बिलों की निर्यात संवर्धन प्रति सौंपनी होगी। आवेदक को एचबीपी के पैरा 3.03 के तहत निर्धारित तरीके से उतराई का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। आवेदक जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, स्क्रिप का दावा करने के लिए निर्धारित दस्तावेजों में से किसी की भी स्कैन की हुई प्रति अपलोड करेंगे। तथापि, आवेदक को इस मामले में भी डीजीएफटी को आवेदनों, इलेक्ट्रॉनिक बैंक प्राप्ति प्रमाण-पत्र (ई-बीआरसी) और आरसीएमसी की हार्ड प्रति सौंपने की आवश्यकता नहीं होगी।
- (ङ.) आवेदक गैर-ईडीआई पोतलदान बिलों के मामले में निर्यात के प्रत्येक पत्तन के लिए अलग आवेदन-पत्र प्रस्तुत करेगा। ईडीआई पोतलदान बिलों के मामले में आवेदक केवल एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत करेगा जिसमें विभिन्न ईडीआई पत्तनों के पोतलदान बिल होंगे। तदनुसार भिन्न-भिन्न ईडीआई पत्तनों से पोतलदान के लिए अलग-अलग आवेदन-पत्रों की आवश्यकता नहीं होगी।
- (च) आरए में गैर-ईडीआई पोतलदान बिलों को प्रक्रियाबद्ध करना: यदि गैर ईडीआई पोतलदान बिल अथवा पोतलदान बिल सीमाशुल्क विभाग से संदेश विनिमय के माध्यम से प्राप्त नहीं होते हैं, तो संबंधित आरए स्क्रिप प्रदान करने से पहले निर्यातक द्वारा दिए गए विवरणों से मूल पोतलदान बिलों की जांच करेगा।
- (छ) ईडीआई पोतलदानों के लिए किसी हस्तलिखित प्रविष्टि की अनुमति नहीं है: ईडीआई पोतलदानबिलों के लिए, ऑनलाइन प्रणाली में पोतलदान बिलों के विवरण की कोई हस्तलिखित प्रविष्टि अनुमत नहीं की जाएगी। आरए द्वारा ईडीआई पोतलदान बिलों के विवरण की दोबारा जांच के बिना प्रतिफल प्रदान किए जाएंगे।
- (ज) आरए इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त की गई फाइलों को प्रक्रियाबद्ध करेगा और इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों की उपयुक्त समीक्षा के बाद स्क्रिप जारी की जाएगी। जाँच के पश्चात् यदि अधिकारी को किसी आवेदन में गलत वर्गीकरण/मिथ्या घोषणा का पर्याप्त संदेह हो, तो ऐसे मामलों में अधिकारी अपने वरिष्ठ अधिकारी/कार्यालय प्रमुख के अनुमोदन के पश्चात् जाँच के लिए मूल दस्तावेजों की माँग कर सकता है। ऐसे दस्तावेजों की प्राप्ति के पश्चात् अधिकारी को दावे पर 7 कार्य दिवसों के भीतर अवश्य निर्णय ले लेना चाहिए। ऐसे मामलों जिनमें दावा अस्वीकृत कर दिया जाता है, तो सकारण आदेश जारी किया जाएगा।
- (झ) दस्तावेज जिन्हें मूल रूप में सौंपे जाने की आवश्यकता नहीं है, आवेदक द्वारा स्क्रिप के जारी होने की तिथि से तीन वर्षों की अवधि के लिए लिए रख लिए जाएंगे अथवा जैसाकि विदेश व्यापार नीति के पैरा 3.19(ख) के तहत निर्धारित किया गया है।
- (ञ) लाइसेंसिंग प्राधिकारी ऐसे दस्तावेजों को मूल रूप में तीन वर्षों के अंदर किसी भी समय मंगवा सकता है। यदि आवेदक लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा मांगे गए मूल दस्तावेजों को प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो आवेदक स्क्रिप जारी होने की तिथि से प्रदान किए गए प्रतिफलों को सीमा-शुल्क अधिनियम 1961 की धारा 28कक के तहत निर्धारित दर पर ब्याज के साथ वापस करेगा।
- (ट) एमईआईएस के तहत प्रतिफलों का दावा करने के लिए उत्पाद की पात्रता, संबंधित आईटीसी (एचएस) कोड और बाजार (परिशिष्ट 3ख में दिए अनुसार) एचबीपी के पैरा 9.12 के अनुसार अनुमत निर्यात तिथि से निर्धारित किए जाएंगे।

3.02 ई-कामर्स का प्रयोग कर कूरियर अथवा विदेशी डाक घरों के माध्यम से माल का निर्यात करने के लिए आवेदन

- (क) निर्यातक द्वारा एएनएफ 3घ में डिजिटल हस्ताक्षर का प्रयोग करते हुए आवेदन-पत्र ऑनलाइन दायर किया जाएगा। आवेदक एचबीपी के पैरा 3.03 के तहत निर्धारित तरीके से उतराई का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे।
- (ख) आवेदक निर्यात के प्रत्येक पत्तन के लिए अलग आवेदन-पत्र प्रस्तुत करेगा।
- (ग) आरए स्क्रिप्ट प्रदान करने से पहले प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की वास्तविक रूप से स्वयं जांच करेगा।

3.03 उतराई का प्रमाण:

- (क) जहाँ भी एमईआईएस के तहत प्रतिफल जिन देशों में उपलब्ध है, प्रतिफल का दावा करने के लिए उतराई का प्रमाण-पत्र सौंपने की आवश्यकता नहीं होगी।

- (ख) उतराई के प्रमाण के रूप में दस्तावेजों को अपलोड/प्रस्तुत किया जाना:-

व्यापार करने में सुविधा प्रदान के उपाय के रूप में, अधिसूचित बाजार में निर्यात खेप की उतराई के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित तरीके से डिजिटली रूप से अपलोड किया जा सकता है:-

- (i) कोई निर्यातक अपने डिजिटल हस्ताक्षर के तहत पैरा 3.03 (ग) (i) में यथा उल्लिखित दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रति अपलोड कर सकता है।

- (ii) स्तरधारक जो कि तीन स्टार, चार स्टार अथवा पांच स्टार निर्यात सदन की श्रेणी में आते हैं, पैरा 3.03 (ग) (iv) में यथा उल्लिखित दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियों को अपलोड कर सकते हैं।

- (iii) अन्य सभी मामलों में, वास्तविक प्रति मूल रूप में निर्यातकों की सभी श्रेणियों द्वारा प्रस्तुत की जाएगी।

- (ग) आवेदक को अधिसूचित बाजार में निर्यात खेप पहुँचने के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित में से कोई भी दस्तावेज, जैसा भी मामला हो, प्रस्तुत अथवा अपलोड करना होगा:-

- (i) विनिर्दिष्ट बाजार में आयातक द्वारा प्रस्तुत प्रविष्टि के आयात बिल की स्वयं प्रमाणित प्रति, या
- (ii) पत्तन प्राधिकारियों द्वारा जारी सुपुर्दगी आदेश, या
- (iii) मालवाहक द्वारा जारी आगमन सूचना, या
- (iv) निर्यात कार्गो का गन्तव्य फोकस बाजार में आगमन प्रमाणित करते हुए, मालवाहक (शिपिंग लाइन/एअर लाइन आदि या भारत में उसके मान्यता प्राप्त एजेंट) द्वारा उनकी प्रमाणित ट्रैकिंग रिपोर्ट, या
- (v) जमीनी अधिसूचित बाजार हेतु, पत्तन से जमीनी अधिसूचित मार्केट में वस्तुओं के परिवहन की रेल/लॉरी रसीदें, या
- (vi) कोई अन्य दस्तावेज जो संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को सन्तुष्ट करे कि माल अधिसूचित बाजार में रख दिया गया है/पहुँच गया है।

- (घ) उपर्युक्त (iv) और (vi) के मामले में, माल वाहक के मान्यता प्राप्त एजेंट को यह प्रमाणित करना होगा कि वह ट्रैकिंग रिपोर्ट/दस्तावेज जारी होने की तारीख को संबंधित वस्तुओं के वाहक का मान्यता प्राप्त एजेंट है।

- (ड.) इसके अलावा, उपर्युक्त (vi) के तहत कोई अन्य दस्तावेज जारी होने के मामले में मान्यता प्राप्त एजेंट को यह बताना होगा कि उसने इस बात की पुष्टि कर ली है कि माल वाहक के बैंकअप डाटा बेस में उपलब्ध जानकारी के आधार पर संबद्ध अधिसूचित बाजार में वस्तुएँ पहुँचने का प्रमाण दिया गया है और उसने इसकी जाँच कर ली है तथा तदनुसार दस्तावेज जारी किया है।

- (च) ई-कामर्स का प्रयोग कर किए गए निर्यातों के मामले में, निर्यातक एक्सप्रेस आपरेटर लैंडिंग प्रमाण-पत्र/ऑनलाइन वेब ट्रैकिंग प्रिंट आउट प्रस्तुत कर सकता है जिसमें यह दर्शाया गया हो कि एयरवे बिल सं. एएनएफ-3घ के अनुलग्नक (ख) के अनुसार है।

3.04 भारत से सेवा निर्यात की स्कीम (एसईआईएस)

- (क) भारत से सेवा निर्यात की स्कीम (एसईआईएस) के लिए नीति एफटीपी के अध्याय-3 में दी गई है।

- (ख) प्रदान की गई पात्र सेवाओं के लिए ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट प्रदान करने के लिए आवेदन-पत्र एएनएफ 3ख में डिजिटल हस्ताक्षर का प्रयोग करके वार्षिक आधार पर एक वित्तीय वर्ष के लिए ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाएगा।

(ग) आरए उपयुक्त जांच के बाद आनलाइन प्राप्त आवेदन-पत्रों को प्रक्रियाबद्ध करेगा।

एमईआईएस और एसईआईएस के लिए लागू समान प्रक्रियात्मक विशेषताएं, जब तक विशेष रूप से प्रदान न किया गया हो।

3.05 अन्तरवर्ती प्रबंध:-

(क) मौजूदा विदेश व्यापार नीति की अधिसूचना की तिथि तक निर्यात किए गए माल अथवा प्रदान की गई सेवाएं, जो कि पहले की विदेश व्यापार नीति (नीतियों) के अध्याय 3 के तहत स्क्रिप जारी करने के लिए पात्र थीं और ऐसे माल के निर्यात अथवा प्रदान की गई सेवाओं के निम्न मौजूदा विदेश व्यापार नीति की अधिसूचना की तिथि को या बाद में स्क्रिप के लिए आवेदन किया गया है तो आवेदन क्षेत्राधिकारी आरए को एचबीपी 2009-2014 में यथा निर्धारित दस्तावेजों के साथ करना होगा।

(ख) हटा दिया गया है।

(ग) आवेदक एफपीएस/एमएलएफपीएस/एफएमएस/वीकेजीयूआई/एसएफआईएस/एसएचआई

एस/आईआईएस तथा कृषि ढांचागत प्रोत्साहन स्कीम स्क्रिप के संबंध में तदनुरूपी प्रक्रिया पुस्तक में निर्धारित आवेदन पत्र में और निर्धारित तरीके से आवेदन करना जारी रखेंगे।

3.06 क्षेत्राधिकार से संबंधित आर ए/संबंधित आर ए

(क) आवेदक को एमईआईएस और एसईआईएस के तहत आवेदन-पत्र/आवेदन-पत्रों को सौंपने के लिए आईसी पर पृष्ठंकित कारपोरेट कार्यालय/पंजीकृत कार्यालय/मुख्यालय/शाखा कार्यालय के पते के आधार पर क्षेत्राधिकार से संबंधित आरए को चुनने का विकल्प होगा। इस विकल्प का चुनाव वित्तीय वर्ष की शुरुआत में करना होगा। एक बार यदि एक विकल्प का प्रयोग कर लिया जाता है तो उस वर्ष से संबंधित दावों के लिए कोई परिवर्तन अनुमत नहीं किया जाएगा। इसे समझने के लिए, यदि एक आवेदक ने 2015-16 के दौरान किए गए निर्यात के लिए प्रतिफल का दावा करने के लिए आरए चेन्ई का चुनाव किया है तो 2015-16 के लिए किए गए निर्यात के लिए सभी दावे, आवेदन-पत्र की तिथि को ध्यान में रखे बगैर, केवल आरए चेन्ई को ही किए जाएंगे।

(ख) एमईआईएस का क्षेत्राधिकार

1	2	3
क्र० सं०	इकाई	क्षेत्राधिकार के संबंधित आरए
(i)	ऐसे आयातक निर्यातक कोड (आईसी) धारक जिनकी डीटीए/ ईएचटीपी/ बीटीपी/एसटीपी में अथवा इनमें से एक से अधिक में इकाइयाँ हों।	डीजीएफटी का क्षेत्राधिकार से संबंधित आरए जैसाकि परिशिष्ट 1क में दिया गया है।
(ii)	ऐसे आईसी धारक जिनकी एसईजेड/ईओयू में अथवा दोनों में इकाइयाँ हों।	विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) के संबंधित विकास आयुक्त जैसाकि परिशिष्ट 1क में दिया गया है।
(iii)	ऐसे आईसी धारक जिनकी ऊपर (i) और (ii) दोनों में इकाइयाँ हों।	श्रेणी (i) और (ii) में अविस्थित इकाइयाँ कॉलम-3 में दिए गए संबंधित क्षेत्राधिकारों पर लागू होगी।

(ग) एसईआईएस (वार्षिक आधार पर एकल आवेदन) हेतु क्षेत्राधिकार

1	2	3
क्र० सं०	इकाई	क्षेत्राधिकार के संबंधित आरए
(i)	ऐसे आयातक निर्यातक कोड (आईसी) धारक जिनकी केवल डीटीए में केवल इकाइयाँ हो।	डीजीएफटी का क्षेत्राधिकार से संबंधित आरए जैसाकि परिशिष्ट 1क में दिया गया है।
(ii)	ऐसे आईसी धारक जिनकी केवल एसईजेड में इकाइयाँ हो।	विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) के संबंधित विकास आयुक्त जैसाकि परिशिष्ट 1क में दिया गया है।
(iii)	ऐसे आईसी धारक जिनकी कई एसईजेड में इकाइयाँ हों	सभी इकाइयों के लिए उस एसईजेड के विकास आयुक्त को एकल आवेदन जहाँ

		उन्होंने अधिकतम विदेशी मुद्रा अर्जित की है।
(iv)	ऐसे आईसीसी धारक जिनकी डीटीए और एसईजेड दोनों में इकाइयाँ हों।	सभी अलग-अलग इकाइयों के लिए डीजीएफटी के क्षेत्राधिकार से संबंधित आरए को एकल आवेदन जैसाकि परिशिष्ट 1क में दिया गया है।

3.07 इस प्रक्रिया-पुस्तक के अध्याय-2 और 9 में निहित प्रावधानों की प्रयोजनीयता

इस प्रक्रिया-पुस्तक के अध्याय-2 और 9 में निहित प्रावधान एमईआईएस और एसईआईएस पर लागू होंगे।

3.08 स्क्रिप का पंजीकरण का पत्तन:-

(क) एमईआईएस के तहत पंजीकरण का पत्तन निम्नानुसार होगा:-

- (i) एमईआईएस के तहत शुल्क क्रेडिट स्क्रिप (अलग-अलग समेत) पंजीकरण के एकल पत्तन के साथ जारी किया जाएगा जो ईडीआई पत्तनों जहां से निर्यात किया जाता है, में से कोई एक पत्तन होगा गैर-ईडीआई पत्तनों से पोतलदान के मामले में, एमईआईएस के तहत ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप (अलग-अलग समेत) पंजीकरण के एकल पत्तन से जारी किया जाएगा जो निर्यात का पत्तन होगा।
- (ii) ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप को निर्यात के पत्तन पर पंजीकरण करवाया जाना अपेक्षित होगा। इसे ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप के प्रयोग को अनुमत करने से पहले किया जाना है। एक बार ईडीआई पत्तन पर पंजीकृत होने के बाद, आयात के लिए किसी ईडीआई पत्तन और टेलीग्राफिक विमुक्ति सलाह (टीआरए) प्रक्रिया के तहत मैनुअल पत्तन पर स्क्रिप को स्वतः ही प्रयोग किया जाएगा।
- (iii) यदि पंजीकरण का पत्तन एक मैनुअल पत्तन है, तो किसी अन्य पत्तन पर आयात के लिए टीआरए की आवश्यकता होगी।
- (iv) एसईजेड के गैर-ईडीआई पत्तन होने के कारण स्क्रिप का पंजीकरण एसईजेड के पत्तन पर किया जाएगा तथा यदि स्क्रिप धारक दूसरे पत्तन से आयात के लिए स्क्रिप का उपयोग करना चाहता है तो संबंधित विकास आयुक्त टेलीग्राफिक रिलीज एडवाइस (टीआरए) जारी करेगा।

(ख) यदि भारत से सेवा निर्यात की स्कीम के तहत स्क्रिप का आवेदन किया गया है, आवेदक किसी पंजीकरण के पत्तन के रूप में किसी भी का चुनाव कर सकता है और इसका आवेदन-पत्र के उपयुक्त कॉलम में उल्लेख कर सकता है। आरए ऐसे पंजीकरण के पत्तन के साथ स्क्रिप को जारी करेगा। ऐसी ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप को ड्यूटी क्रेडिट के ऐसे पंजीकरण के पत्तन पर पंजीकृत करवाया जाना आवश्यक होगा। एक बार ईडीआई पत्तन पर पंजीकृत करवाने के बाद, स्क्रिप को स्वतः ही आयात के लिए किसी ईडीआई पत्तन पर और टेलीग्राफिक विमुक्ति सलाह (टीआरए) प्रक्रिया के तहत किसी मैनुअल पत्तन पर प्रयोग किया जा सकता है। यदि पंजीकरण का पत्तन एक मैनुअल पत्तन है, तो किसी अन्य पत्तन पर आयातों के लिए टीआरए की आवश्यकता होगी।

3.09 विभाजित स्क्रिपों हेतु सुविधा

(क) आवेदन के समय, अनुरोध पर, न्यूनतम 5 लाख रुपये और उसके गुणकों की शर्त के अधीन विभाजित शुल्क क्रेडिट स्क्रिप प्रमाणपत्र भी जारी किया जा सकता है।

(ख) एक बार ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप जारी होने के बाद विभाजन का अनुरोध उसी पंजीकरण के पत्तन पर अनुमत होगा जैसा कि मूल स्क्रिप में दिया गया है। उपर्युक्त प्रक्रिया ईडीआई समर्थित पत्तनों के संबंध में ही लागू होगी।

(ग) गैर ईडीआई पत्तनों के माध्यम से निर्यात के मामले में स्क्रिप जारी होने के बाद विभाजन की सुविधा अनुमत नहीं होगी।

3.10 सनदी लेखाकार/कंपनी सचिव/लागत लेखाकार द्वारा दस्तावेजों को अपलोड करने की सुविधा

(क) प्रतिफल स्कीमों के लिए कागजरहित प्रक्रिया की तरफ अग्रसर होने के लिए सनदी लेखाकार/कंपनी सचिव/लागत लेखाकार द्वारा हस्ताक्षर किए गए दस्तावेजों को डिजिटल रूप से अपलोड करने के लिए एक इलैक्ट्रॉनिक प्रक्रिया विकसित की जा रही है। ऐसे दस्तावेज जैसे एएनएफ-3ख, एएनएफ-3ग और एएनएफ-3घ के साथ संलग्न अनुलग्नक, जिन्हें फिलहाल इन हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा हस्ताक्षर किया जाता है, को इस प्रक्रिया द्वारा सुगम बनाया जा सकता है।

(ख) जब तक इन अनुलग्नकों को डिजिटल रूप में अपलोड करना अनिवार्य है एएनएफ-3ख, एएनएफ-3ग, एएनएफ-3घ के

साथ संलग्न ऐसे अनुलग्नक आरए को वास्तविक रूप से प्रस्तुत किए जाते रहेंगे।

(ग) निर्यातक ऐसी सुविधा प्रारम्भ किए जाने के बाद उनके ऑनलाइन आवेदनों के साथ डिजिटल रूप से अपलोड किए गए अनुलग्नकों को लिंक करेंगे।

3.11 प्राइवेट/पब्लिक बाण्डेड गोदामों से आयात

विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 2.36 और राजस्व विभाग की अधिसूचना के नियमों एवं शर्तों की पूर्ति के अधीन प्राइवेट/पब्लिक बाण्डेड गोदामों से आयात के लिए हकदारी का उपयोग किया जा सकता है।

3.12 खराब/अनुपयुक्त माल का पुनः निर्यात

आयात किया गया माल जिसे खराब अथवा प्रयोग के लिए अनुपयुक्त पाया जाता है, उसका राजस्व विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार पुनः निर्यात किया जा सकता है। जहाँ आयात के लिए ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप का उपयोग किया गया है, उन मामलों में सीमा शुल्क विभाग उपयोग की गई स्क्रिप, पुनः निर्यातित माल के आयात की तिथि और ऐसे माल का आयात करते हुए डेबिट की गई राशि का ब्यौरा देने वाला एक प्रमाण-पत्र जारी करेगा। इस प्रमाण-पत्र के आधार पर, आवेदन करने पर, संबंधित आरए द्वारा डेबिट की गई धनराशि की 98 प्रतिशत की सीमा तक पंजीकरण के उसी पत्तन और खराब/अनुपयुक्त माल के आयात की तारीख को शेष उपलब्ध अवधि की समतुल्य अवधि हेतु वैध एक नई स्क्रिप जारी की जाएगी।

3.13 वैधता अवधि एवं पुनर्वैधीकरण

अध्याय 3 के तहत दिनांक 01.01.2016 को या इसके पश्चात् जारी शुल्क क्रेडिट स्क्रिप जारी करने की तिथि से 24 महीनों की अवधि के लिए वैध होगी और उस तिथि तक वैध होनी चाहिए जिस पर शुल्क का वास्तविक डेबिट किया गया है। शुल्क क्रेडिट स्क्रिप के पुनर्वैधीकरण की अनुमति नहीं होगी जब तक कि यह प्रक्रिया पुस्तक के पैराग्राफ 2.20(ग) के अधीन शामिल न हो।

3.14 ई-कॉमर्स का प्रयोग करने वाले करियर अथवा विदेशी डाकघरों के माध्यम से माल के निर्यात सहित एमईआईएस के तहत प्रतिफलों का दावा करने के लिए ईडीआई और गैर-ईडीआई पोतलदान बिलों पर आशय की घोषणा की प्रक्रिया

(क) (i) ईडीआई पोतलदान बिल: प्रत्येक मद के सामने पोतलदान बिलों के "प्रतिफल" कालम "वाई" (हां के लिए) अंकित करना/चिह्न लगाना जो कि अनिवार्य है, इस स्कीम के तहत प्रतिफल का दावा करने के आशय की घोषणा करना पर्याप्त होगा। यदि निर्यातक विदेश व्यापार नीति के अध्याय-3 के तहत प्रतिफल के लाभ का दावा नहीं करना चाहता है, तो निर्यातक "एन" (नहीं के लिए) का निशान लगाएगा। विदेश व्यापार नीति के अध्याय-4 (शुल्क वापसी सहित), अध्याय-5 या अध्याय-6 की किसी भी स्कीमों के तहत निर्यात पोतलदानों के लिए भी ऐसे अंकित करने/चिह्नित करने की आवश्यकता होगी।

(ii) गैर-ईडीआई पोतलदान बिल: गैर-ईडीआई पोतलदान बिलों के मामले में निर्यात पोतलदान के लिए एमईआईएस के तहत प्रतिफल का दावा करने के लिए पात्र होने के लिए पोतलदान बिलों पर निम्नलिखित घोषणा करने की आवश्यकता होगी: "हम भारत से व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात की स्कीम (एमईआईएस) के तहत प्रतिफलों का दावा करना चाहते हैं"। ऐसी घोषणा विदेश व्यापार नीति के अध्याय-4 (शुल्क वापसी सहित), अध्याय-5 या अध्याय-6 की किसी भी स्कीम के तहत निर्यात पोतलदानों के लिए भी आवश्यक होगी।

(ख) जब भी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी नए उत्पाद/माल को अथवा नए बाजारों को शामिल करने का निर्णय लिया जाता है, तो ऐसे प्रतिफलों का लाभ उठाने के लिए:-

(i) ऐसे बाजारों में, ऐसे उत्पादों/माल के निर्यात के लिए इस आशय की घोषणा करने के लिए अधिसूचना/सार्वजनिक सूचना की तारीख से एक महीने की छूट अवधि की अनुमति होगी।

(ii) एक माह की छूट अवधि के बाद, सभी निर्यात (ऐसे उत्पादों/माल के अथवा ऐसे बाजारों को) के पोतलदान बिलों की सभी श्रेणियों पर आशय की घोषणा शामिल करनी होगी।

(iii) उत्पादों/बाजारों की अधिसूचना/सार्वजनिक सूचना की तिथि से पहले किए गए निर्यातों के लिए, ऐसी घोषणा की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि ऐसे निर्यात पहले ही किए जा चुके हैं।

3.15 ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्स प्राप्त करने हेतु आवेदन करने की अंतिम तारीख

(क) एमईआईएस के तहत ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप प्राप्त करने के लिए आवेदन इस अवधि के अंदर प्रस्तुत किए जाएंगे:

(i) अनुमत निर्यात (एलईओ) तिथि से बारह माह तक अथवा

(ii) इस तिथि से तीन माह तक:

(1) सीमा शुल्क विभाग द्वारा डीजीएफटी सर्वर पर ईडीआई पोतलदान बिलों को अपलोड करना

(2) गैर-ईडीआई पोतलदान बिलों के लिए पोतलदान बिलों की प्रिंटिंग/विमुक्ति। ऐसे पोतलदान जिनके लिए दावा प्रस्तुत किया जा रहा है, जो भी बाद में हो।

(ख) एसईआईएस के लिए, आवेदन-पत्र प्रस्तुत किए जाने की अंतिम तिथि दावा अवधि के संबंधित वित्तीय वर्ष के अंत से 12 माह तक होगी।

3.16 एमईआईएस के तहत ईडीआई पत्तनों और गैर-ईडीआई पत्तनों से पोतलदान के लिए आवेदन-पत्र

(क) ईडीआई पत्तनों और गैर ईडीआई पत्तनों से पोतलदानों को एक आवेदन-पत्र में क्लब नहीं किया जा सकता।

(ख) ईडीआई समर्थित पत्तनों के लिए पंजीकरण का पत्तन कोई भी पत्तन होगा, जहां से निर्यात किया जाता है।

(ग) गैर-ईडीआई पत्तन के माध्यम से निर्यात के मामले में, पंजीकरण का पत्तन निर्यात के लिए संबंधित गैर-ईडीआई पत्तन रहेगा। तदनुसार, प्रत्येक गैर-ईडीआई पत्तन के लिए अलग आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।

(घ) कई आवेदन-पत्र प्रस्तुत किए जा सकते हैं और पूरक कटौती लागू नहीं होगी। तथापि, एक आवेदन-पत्र अधिकतम 50 पोतलदान बिलों के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है।

3.17 जोखिम प्रबंधन प्रणाली

जोखिम प्रबंधन प्रणाली से संबंधित नीति विदेश व्यापार नीति के पैरा 3.19 में दी गई है। जोखिम प्रबंधन प्रणाली निम्नानुसार कार्य करेगी:-

(क) डीजीएफटी मुख्यालय में कम्प्यूटर प्रणाली, यादृच्छिक आधार पर और समय-समय पर डीजीएफटी द्वारा जारी दिशानिर्देशों के आधार पर प्रत्येक आरए के लिए 10 प्रतिशत मामलों का चयन करेगी जहाँ पर पूर्व माह में प्रत्येक माह की 10 तारीख तक स्क्रिप्ट/स्तरधारक प्रमाणपत्र जारी कर दिए गए हैं।

(ख) चुने गए ऐसे मामलों की सूची एनआईसी द्वारा संबंधित आरए को माह की 15 तारीख तक भेजी जाएगी।

(ग) तत्पश्चात संबंधित आरए, माह की 30 तारीख तक विस्तृत परीक्षण के लिए मूल/वास्तविक, दस्तावेजों की मांग करेगा।

(घ) आवेदक मांगे गए दस्तावेजों को अगले 15 दिनों में सौंपने के लिए बाध्य होगा।

(ङ.) संबंधित आरए उसके बाद ऐसे दस्तावेजों की जांच अगले 15 दिनों में करेगा। यदि कोई कमी पायी जाती है तो आवेदक आरए द्वारा संप्रौण की तिथि से अगले एक माह में उसमें त्रुटि सुधार करेगा। प्रतिफलों का अधिक लाभ उठाने के मामले में, आवेदक विदेश व्यापार नीति के पैरा 3.19 में यथा निर्धारित ब्याज के साथ आधिक्य दावे की वापसी करेगा।

(च) यदि आवेदक उपरोक्त यथा निर्धारित तरीके से अपेक्षित दस्तावेजों को सौंपने/कमियों को ठीक करने/आधिक्य दावे की वापसी करने में असफल रहता है अथवा जोखिम प्रबंधन प्रणाली संबंधी किसी पत्राचार का, पत्राचार की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर कोई प्रत्युत्तर नहीं देता है, तो आरए एफटीडीआर अधिनियम और नियमों के अनुसार कार्रवाई शुरू करेगा।

3.18 स्तर प्रमाण पत्र

विदेश व्यापार नीति के अध्याय-3 में स्तर धारक के लिए नीति दी गई है।

3.19 स्तर प्रमाण-पत्र प्रदान करने के लिए आवेदन-पत्र

(क) एफटीपी 2009-14 के तहत एक आईईसी धारक को जारी स्तर प्रमाण-पत्र 30 सितम्बर 2015 तक अथवा विदेश व्यापार नीति, 2015-20, जो भी पहले हो, के तहत ऐसे आईईसी धारक को स्तर प्रमाण-पत्र जारी किए जाने तक, वैध रहेगी।

(ख) आवेदकों को इस नीति के तहत एएनएफ-3ग में स्तर की पहचान करने के लिए एक आवेदन आनलाइन प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा। संबंधित निर्धारित दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रति आवेदक द्वारा, जब तक कि अन्यथा निर्धारित न हो, अपलोड की जाएगी।

(ग) स्तर प्रमाणपत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन नीचे दी गई तालिका में यथा दर्शाए अनुसार कंपनी और मुख्यालय के मामले

में पंजीकृत कार्यालय द्वारा क्षेत्राधिकार प्राप्त क्षेत्रीय प्राधिकारी/विकास आयुक्त (डी सी) को डिजिटल हस्ताक्षर का प्रयोग करते हुए प्रस्तुत किया जा गया:

क्र.सं.	श्रेणी	स्तर प्रमाण-पत्र को जारी करने/रिन्यू करने के लिए प्राधिकारी
1.	एसईजैड/ईओयू यूनिट के साथ-साथ डीटीए यूनिट में निर्यात वाले आईईसी धारक। ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी	क्षेत्राधिकार के अनुसार संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी जैसाकि परिशिष्ट 1क में दर्शाया गया है।
2.	केवल एसईजैड/ईओयू यूनिट वाले आईईसी धारक	क्षेत्राधिकार के अनुसार संबंधित विकास आयुक्त जैसाकि परिशिष्ट 1क में दर्शाया गया है।
3.	केवल डीटीए यूनिट वाले आईईसी धारक	क्षेत्राधिकार के अनुसार संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी जैसाकि परिशिष्ट 1क में दर्शाया गया है।

3.20 स्तर प्रमाण-पत्र की वैधता:

- (क) इस विदेश व्यापार नीति के तहत जारी स्तर प्रमाण-पत्र उस तिथि से, पांच वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगा, जिस तिथि से पहचान के लिए आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया था,
- (ख) 31.3.2020 के बाद वैध स्तर प्रमाण-पत्र लागू रहेंगे, यदि बाद की विदेश व्यापार नीति के प्रावधान उसे स्तर प्रदान करना जारी रखते हों।

3.21 खातों का रख-रखाव

स्तर धारक अपने निर्यात और आयात के खाते का उसी प्रकार सही और उचित लेखा रखेगा जिसके आधार पर उसे यह मान्यता दी गई है। रिकार्ड स्तर प्रमाण-पत्र प्रदान किए जाने की तिथि से दो वर्षों की अवधि के लिए रखे जाएंगे। ये खाते संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी या विदेश व्यापार महानिदेशक द्वारा नामित किसी अन्य प्राधिकारी को निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे।

3.22 प्रमाण पत्र की अस्वीकृति/ निलम्बन/ निरस्तीकरण

संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा स्तर प्रमाण पत्र अस्वीकृत/निलम्बित/रद्द किया जा सकता है यदि स्तर धारक या अन्य कोई प्राधिकृत प्रतिनिधि निम्नलिखित कार्य करता है:-

- (क) लगाए गए निर्यात दायित्व को पूरा करने में असफल रहता है;
- (ख) प्राधिकार पत्र में रद्दोबदल करता है;
- (ग) किसी प्राधिकार पत्र को प्राप्त करने के लिए गलत विवरण देता है या भ्रष्ट या छल कपट करने में एक पक्ष बनता है;
- (घ) विदेश व्यापार नीति के अधीन विदेश व्यापार (विकास व विनियमन) अधिनियम अथवा उसके अधीन बने नियमों या आदेशों सीमा-शुल्क अधिनियम 1962, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम 1944, फेमा अधिनियम 1999 और कोफेपोसा अधिनियम 1974 का उल्लंघन करता है;
- (ङ.) इस निदेशालय द्वारा अपेक्षित सूचना प्रस्तुत करने में असफल रहता है;

इस पैराग्राफ के अधीन कोई कार्रवाई करने से पहले स्तर धारक को समुचित अवसर दिया जाएगा।

3.23 अपील

आवेदक, जो स्तर प्रमाण पत्र के निलम्बन या रद्द के निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं, वह 45 दिनों के भीतर महानिदेशक, विदेश व्यापार को अपील कर सकता है। उस संबंध में विदेश व्यापार महानिदेशक का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

अध्याय - 4

शुल्क छूट/माफी स्कीम

4.01 नीति

शुल्क छूट/माफी स्कीम से संबंधित नीति विदेश व्यापार नीति के अध्याय-4 में विनिर्दिष्ट की गई है।

4.02 सामान्य प्रावधान

(i) आईईसी धारक द्वारा अग्रिम प्राधिकार पत्र/परिधान सामग्री और वस्त्र की सहायक सामग्री के निर्यात हेतु विशेष अग्रिम प्राधिकार पत्र/वार्षिक आवश्यकता हेतु अग्रिम प्राधिकार पत्र/ शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार पत्र (डी एफ आई ए) की मंजूरी के लिए आवेदन परिशिष्ट-1क के अनुसार संबंधित क्षेत्राधिकार प्राप्त क्षेत्रीय प्राधिकारी को आनलाइन (डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित) प्रस्तुत किया जा सकता है। आवेदक आईईसी धारक का पंजीकृत कार्यालय अथवा मुख्यालय अथवा शाखा कार्यालय अथवा विनिर्माण यूनिट हो सकता है।

(ii) आवेदक आनलाइन आवेदन प्रस्तुत करते समय आयात निर्यात प्रपत्र 4क में यथा निर्धारित दस्तावेजों, यदि कोई हो, को अपलोड करेगा। क्षेत्रीय प्राधिकारी को वास्तविक प्रतिलिपि प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है।

(iii) यदि कोई आवेदक तदर्थ मानदंड/मानदंड मानकीकरण के निर्धारण के लिए परिशिष्ट 4ड. में दिए अनुसार इलेक्ट्रानिक रूप में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाता है तो केवल उन्हीं दस्तावेजों को डीजीएफटी मुख्यालय में संबंधित मानदंड समिति को वास्तविक रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है।

4.03 आवेदक का ब्यौरा

जहां आवेदक कोई शाखा कार्यालय या विनिर्माण यूनिट है, आवेदक के इलेक्ट्रानिक आरसीएमसी और आईईसी में शाखा कार्यालय या विनिर्माण यूनिट का नाम होना चाहिए।

4.04 अग्रिम प्राधिकार पत्र

आवेदक एएनएफ 4क में आनलाइन आवेदन प्रस्तुत करेगा। प्रक्रिया पुस्तक के पैराग्राफ 4.07 के अनुसार तदर्थ मानदंड या स्वघोषणा आधार पर समान प्रपत्र प्रयोग किया जाएगा जहां मानक निविष्टि उत्पादन मानदंड (सिओन) अधिसूचित किए गए हैं।

4.05 निर्यात के लिए अन्यथा निषिद्ध मदों के लिए अग्रिम प्राधिकार पत्र

(i) आईटीसी (एचएस) अनुसूची-2 के अध्याय-7 और अध्याय-15 के तहत शामिल मदों जो निर्यात हेतु निषिद्ध हैं, को अग्रिम प्राधिकार पत्र स्कीम के अंतर्गत निर्यात हेतु अनुमत किया जा सकता है। प्रक्रिया पुस्तक के पैराग्राफ 4.06 के अनुसार अधिसूचित सिओन/मानदंड समिति द्वारा मानदंडों के पूर्व-निर्धारण के अंतर्गत आयात-पूर्व शर्त के अधीन निर्यात की अनुमति होगी। केवल ईडीआई पत्तनों के माध्यम से आयात और निर्यात की अनुमति होगी।

(ii) ऐसी मदों के लिए जारी अग्रिम प्राधिकार पत्रों की निर्यात दायित्व अवधि (ईओपी) आयात खेप की मंजूरी की तारीख से 90 दिनों की होगी तथा निर्यात दायित्व की अवधि में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी। ऐसा आयात वास्तविक प्रयोक्ता शर्त के अधीन होगा तथा जॉब कार्य सहित किसी प्रयोजन के लिए आयातित कच्चे माल का अंतरण नहीं किया जाएगा। निर्यात दायित्व पूरा नहीं किए जाने/निर्धारित मूल्य संवर्धन प्राप्त नहीं किए जाने के मामले में, लागू शुल्क और ब्याज के अलावा आयातित माल के सीआईएफ मूल्य के पांच गुना के बराबर दंड जो निर्यात दायित्व में कमी के अनुरूप हों, लगाया जाएगा। प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 4.49 के प्रावधान इस मामले में लागू नहीं होंगे।

4.06 मानदंड निर्धारण

(i) उन मामलों में जहां मानदंड अधिसूचित नहीं किए गए हैं, अथवा जहां आवेदक अग्रिम प्राधिकार पत्र हेतु आवेदन करने से पहले तदर्थ मानदंड निर्धारित कराने का इच्छुक हो सिओन/तदर्थ मानदंड निर्धारण के लिए एएनएफ 4ख में आवेदन निर्धारित दस्तावेज समेत डीजीएफटी मुख्यालय में संबंधित मानदंड समिति (एनसी) को आनलाइन अपलोड किया जाएगा। प्रत्येक मानदंड समिति द्वारा देखरेख किए जा रहे उत्पाद समूह के साथ मानदंड समितियों और मानदंड निर्धारण से संबंधित पत्राचार हेतु संबंधित ईमेल पता का ब्यौरा निम्नानुसार है:

डीजीएफटी मुख्यालय में मानदंड समिति (एनसी)	निम्नलिखित आईटीसी एचएस अध्याय के तहत निर्यात उत्पादों के मानदंडों का निर्धारण/परिशोधन/संशोधन	संबंधित मानदंड समिति के साथ सम्पर्क हेतु ईमेल पता
एनसी-1	81 से 84, 86 से 93	nc1.dgft@nic.in
एनसी-2	72 से 76, 78 से 80, 85	nc2.dgft@nic.in
एनसी-3	29, 30	nc3.dgft@nic.in
एनसी-4	27, 28, 31 से 38, 44 से 49, 68 से 71	nc4.dgft@nic.in
एनसी-5	41 से 43, 50 से 67	nc5.dgft@nic.in
एनसी-6	1 से 26, 94 से 98	nc6.dgft@nic.in
एनसी-7	39, 40	nc7.dgft@nic.in

(ii) आवेदक सम्पर्क के लिए वैध ईमेल पता दर्शाएगा तथा यह सुनिश्चित करेगा कि यह ईमेल पता सक्रिय है।

(iii) मानदंड समितियों के निर्णय डीजीएफटी की वेबसाइट (<http://dgft.gov.in>) पर आवधिक रूप से उपलब्ध रहेंगे तथा आवेदक स्वयं को प्राप्त प्राधिकार पत्र के संबंध में मानदंड निर्धारण की स्थिति को स्वयं को अद्यतन करेगा।

(iv) निर्यातक/ईपीसी निर्यात उत्पाद के लिए सिओन/तदर्थ मानदंड के निर्धारण के लिए संबंधित मानदंड समिति को आंकड़ा उपलब्ध कराएंगे। मानदंड समिति सम्पूर्ण आंकड़ा के प्राप्त होने के बाद सिओन या तदर्थ मानदंडों को निर्धारित करने का प्रयास करेगी। इस पैरा के अधीन निर्धारित तदर्थ मानदंड निर्यातक द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर केवल एक प्राधिकार पत्र के लिए वैध होगा जिसके लिए यह आवेदन किया गया है और दुबारा प्राधिकार पत्र जारी नहीं किया जाएगा। तथापि, मानदंड समिति ऐसे मानदंड के तहत आगे प्राधिकार पत्र देने के लिए इन तदर्थ मानदंडों के निर्धारण की तारीख से अधिकतम 2 वर्षों की बढ़ायी गई वैधता अवधि को विनिर्दिष्ट कर सकती है।

(v) मानदंड समितियां सिओन की अधिसूचना के लिए सिफारशी प्राधिकरण के रूप में भी कार्य करेंगी तथा विदेश व्यापार महानिदेशालय समय-समय पर ऐसे मानदंड अधिसूचित कर सकता है।

(vi) उद्योग जगत/विनिर्माताओं/ईपीसी के लिए पिछले तीन वर्षों का उत्पादन एवं खपत आंकड़ा प्रदान करना अनिवार्य है जिसकी सिओन के निर्धारण के लिए विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा मांग की जाए। अन्यथा, आवेदकों को स्व-घाँषा आधार पर दुबारा अग्रिम प्राधिकार-पत्र लेने के लिए अग्रिम प्राधिकार पत्र स्कीम का लाभ लेने की अनुमति नहीं होगी। मानदंड समिति राजस्व विभाग (सीबीईसी) से भी आंकड़े की मांग कर सकती है।

(vii) मानदंडों के निर्धारण हेतु वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिक संस्थानों से विशेषज्ञों को मानदंड समिति के सदस्यों के रूप में आमंत्रित किया जा सकता है।

4.07 स्वघोषित प्राधिकार पत्र जहां सिओन नहीं है

(i) क्षेत्रीय प्राधिकारी आवेदक के स्वघोषणा के आधार पर अग्रिम प्राधिकार पत्र भी जारी कर सकता है जहां सिओन निर्धारित नहीं है। इस प्रकार दावा किया गया अपशिष्ट मानदंड समिति द्वारा निर्धारित अपशिष्ट मानदंड के अध्यक्षीन होगा। आवेदक मानदंड समिति के निर्णय का अनुपालन करने का वचन देगा। इससे संबंधित प्रावधान विदेश व्यापार नीति के पैरा 4.03 और 4.11 में दिए गए हैं।

(ii) संशोधन/अस्वीकृति के मामले में आवेदक मानदंड समिति के निर्णय को डीजीएफटी की वेबसाइट पर डालने की तारीख से तीस दिनों के भीतर राजस्व विभाग द्वारा यथा अधिसूचित शुल्क और ब्याज का भुगतान करेगा।

(iii) विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 4.11 में सूचीबद्ध मदों के लिए क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा इस पैराग्राफ के तहत कोई प्राधिकार पत्र जारी नहीं किया जाएगा।

4.08 निविष्टि के रूप में एसेटिक एनहाइड्राइड, एफेड्रिन और स्यूडो इफेड्रिन से संबंधित मामले

(i) जहाँ आयात के लिए निविष्टि के रूप में एसेटिक एनहाइड्राइड, इफेड्रिन और स्यूडो इफेड्रिन की आवश्यकता है, ऐसे मामलों में आवेदन संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारियों को प्रस्तुत किए जाएंगे। आवेदन आनलाइन प्रस्तुत करने के बाद आवेदक द्वारा ऐसे आवेदनों की प्रिन्टेड प्रतियाँ (क) भारत के औषध नियंत्रक, निर्माण भवन, नई दिल्ली, (ख) स्वापक आयुक्त, केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो, ग्वालियर और (ग) स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के संबंधित जोनल निदेशक को भी पृष्ठांकित की जाएगी। आवेदक को यह घोषणा करनी होगी कि आवेदक निर्धारित रिकार्डों/दस्तावेजों का रखरखाव करेगा और समय-समय पर विधि द्वारा यथा निर्धारित समय के भीतर संगत प्राधिकारियों को निर्धारित रिकार्ड/विवरणियाँ भी प्रस्तुत करेगा।

(ii) क्षेत्रीय प्राधिकारी ऐसे अग्रिम प्राधिकार पत्र की प्रति उपर्युक्त तीनों एजेंसियों को पृष्ठांकित करेगा। क्षेत्रीय प्राधिकारी यह शर्त भी पृष्ठांकित करेगा कि आयात करने से पूर्व, भारत के भेषज नियंत्रक एवं स्वापक आयुक्त से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाएगा।

4.09 स्वच्छता आयात परमिट की आवश्यकता वाले मामले

(i) जहाँ, स्वच्छ, शीतित और प्रशीतित माँस, मुर्गियों के उत्तक अथवा अंग, सूअर, भेड़, बकरी; अण्डे और अण्डे का चूर्ण; दुग्ध व दुग्ध उत्पाद; गाय, भेड़ और कैप्राइन के भ्रूण, अण्डाणु अथवा शुक्राणु; तथा पशु से उत्पन्न पालतू पशुओं के खाद्य उत्पादों सहित किसी भी प्रकार के माँस और माँस उत्पादों का एक निविष्टि के रूप में आयात करने हेतु अग्रिम प्राधिकार पत्र के तहत माँग की गई है, क्षेत्रीय प्राधिकारी, अग्रिम प्राधिकार पत्र जारी करते समय, यह शर्त पृष्ठांकित करेगा कि इन निविष्टियों में से किसी के भी आयात से पूर्व, पशुपालन, दुग्ध उत्पादन और मत्स्य पालन विभाग (डी ए एच डी एफ) से स्वच्छता आयात परमिट प्राप्त करना होगा।

(ii) क्षेत्रीय प्राधिकारी प्राधिकार पत्र की एक प्रति डी ए एच डी एफ, कृषि भवन, नई दिल्ली को भी पृष्ठांकित करेगा।

4.10 एक से अधिक यूनिटों वाले आवेदकों हेतु अग्रिम प्राधिकार पत्र

(i) विनिर्माण प्रयोजन हेतु कंपनी की एक यूनिट से दूसरी यूनिट को अग्रिम प्राधिकार पत्र के तहत आयातित या प्राप्त किसी शुल्क मुक्त माल का हस्तांतरण क्षेत्राधिकार प्राप्त सीमा शुल्क प्राधिकारी को पूर्व सूचना के साथ किया जाएगा। ऐसी हस्तांतरित निविष्टि पर कोई सेनवेट लाभ का दावा नहीं किया जाएगा।

(ii) हटा दिया गया है।

(iii) हटा दिया गया है।

(iv) हटा दिया गया है।

(v) आयातित शुल्क मुक्त निविष्टियों को पत्तन/स्वदेशी आपूर्तिकर्ता के परिसर से प्राधिकार पत्र/ सह-प्राधिकार-पत्र धारक के फैक्टरी या परिसर अथवा सहायक विनिर्माता की फैक्टरी में ले जाया जाएगा (जिनका नाम प्राधिकार पत्र में पृष्ठांकित या क्षेत्राधिकार प्राप्त सीमा शुल्क प्राधिकारी द्वारा अनुमत है) तथापि, अग्रिम प्राधिकार पत्र के तहत आयातित अथवा खरीदे गए ऐसे शुल्क मुक्त माल को आयात के पत्तन पर सीमाशुल्क प्राधिकारी को बंधपत्र और अन्य दस्तावेज/घौणा प्रस्तुत करने तथा राजस्व विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार अन्य प्रावधानों के अधीन पत्तन से परियोजना प्राधिकारी की परियोजना स्थल तक सीधे ले जाया जा सकता है।

4.11 निःशुल्क और भुगतान किए गए माल हेतु अग्रिम प्राधिकार पत्र

विदेश व्यापार नीति के पैरा 4.19 के अनुसार प्राधिकार पत्र में अग्रिम प्राधिकार पत्र की विनियम नियंत्रण प्रति पर क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा विशिष्ट पृष्ठांकन किया जाएगा जिसमें निःशुल्क आपूर्तित माल के प्रति शुल्क वापसी की अनुमति नहीं दी जाएगी। अपशिष्ट को छोड़कर सभी आयातित निवेशों को निर्यात उत्पाद के विनिर्माण में प्रयुक्त किया जाएगा।

4.12 हकदारी

प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 4.07 के तहत जारी किए जाने वाले एक या एक से अधिक प्राधिकार पत्रों का अधिकतम सीआईएफ मूल्य निम्नानुसार होगा:

- (i) स्तर धारकों के लिए-पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य और/या पिछले वर्ष के निर्यात और/या आपूर्ति के एफ ओ आर मूल्य का 300 प्रतिशत।
- (ii) स्तर धारकों के अलावा-पिछले वर्ष के निर्यात और/या आपूर्ति के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य और/या एफ ओ आर मूल्य का 300 प्रतिशत या 10 करोड़ रु इसमें से जो भी अधिक हो।

- (iii) मानदंड समिति द्वारा मानदंड निर्धारित कर दिए जाने के बाद उपर्युक्त उप-पैराग्राफ (i) और (ii) में उल्लिखित मूल्य सीमाएं प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 4.07 के तहत जारी अग्रिम प्राधिकार पत्रों पर लागू नहीं होंगी। मानदंड समिति द्वारा मानदण्ड के निर्धारण के बाद ऐसे प्राधिकार पत्रों का मूल्य बढ़ाया जा सकता है यदि अग्रिम प्राधिकार पत्र सीआईएफ मूल्य को उपर्युक्त उप-पैरा (i) और (ii) के अधिकतम मूल्य तक सीमित कर जारी किया गया हो।
- (iv) ऐसे मामलों में "तदर्थ मानदंड निर्धारित" श्रेणी के तहत संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा प्राधिकार पत्र जारी किए जाएंगे तथा आवेदन की प्रतियाँ मानदंडों के निर्धारण/पुष्टि हेतु मानदंड समिति को भेजने की जरूरत नहीं होगी। मानदण्डों की पुष्टि के पहले जहाँ आवेदन पहले ही अग्रेषित कर दिया गया है, पक्षकार के इस तरह के मामलों में क्षेत्रीय प्राधिकारी उसके बाद मानदण्ड समिति द्वारा पुष्टि मानदण्ड के अनुसार मामले को अंतिम रूप देगी।
- (v) ऐसे मामलों में प्राधिकार पत्र धारक मानदंड समिति द्वारा बाद में अनुमोदन की आवश्यकता के बिना मानदंड समिति द्वारा अनुमोदित मानदंडों के अनुसार प्राधिकार पत्रों हेतु पात्र होगा। ऐसे मामलों में आवेदक "तदर्थ मानदंड निर्धारित" श्रेणी के तहत संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करेगा।
- (vi) जहाँ मानदंड समिति ने पैरा 4.07 के तहत प्राप्त प्राधिकार पत्र के संबंध में उसी निर्यात और आयात उत्पाद हेतु मानदंडों की पहले ही पुष्टि कर दी है, ऐसे मानदंड पुष्टि की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए वैध होंगे। ये आवेदक ही ऐसे तदर्थ मानदंडों पर आधारित दुबारा प्राधिकार पत्र का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तथापि, दूसरे निर्यातक को ऐसे तदर्थ मानदंड के आधार पर क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा प्राधिकार पत्र नहीं दिया जा सकता है।
- (vii) जहाँ आवेदक ने "जवाबदेही शर्त के साथ निवल दर निवल आधार" पर संघटकों के लिए आवेदन किया है और ऐसे मामले सभी निर्यात उत्पादों के लिए सामान्य टिप्पणी के पैराग्राफ-6 के अन्तर्गत आते हैं तो इन्हें मानदंड निर्धारण के लिए मानदंड समिति के पास भेजने की आवश्यकता नहीं है। तथापि, निर्यातक निर्यात/आपूर्ति दस्तावेजों जैसे पोतलदान बिल, निर्यात बिल, जीएसटी नियमावली के तहत निर्धारित निर्यात/आपूर्तियों हेतु कर बीजक में "जवाबदेही शर्त के साथ निवल दर निवल आधार" पर आयातित ऐसी निविष्टियों के ब्यौरे स्पष्ट रूप से दर्शाएंगे जिसमें यह साक्ष्य हो कि इन आयातित निविष्टियों का निर्यात किया गया है।

4.13 हकदारी से अधिक प्राधिकार पत्र

आवेदक सीमाशुल्क से छूट प्राप्त करने हेतु सीमाशुल्क प्राधिकारी को 100 प्रतिशत बैंक गारण्टी प्रस्तुत करके पैरा 4.12 में उल्लिखित हकदारी से अधिक प्राधिकार पत्र हेतु हकदार होगा। क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा प्राधिकार पत्र पर इस आशय का विशिष्ट पृष्ठान्कन किया जाएगा। यह प्रावधान स्तरधारकों के लिए भी लागू होगा।

4.14 मानदंड/तदर्थ मानदंड निर्धारण के लिए आवेदन और आनलाइन अन्तर-मंत्रालयी परामर्श

- (i) आवेदक द्वारा आनलाइन प्रस्तुत आवेदन को डीजीएफटी मुख्यालय में संबंधित मानदंड समिति द्वारा तीन दिनों के भीतर संबंधित तकनीकी/प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग/वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिक संस्थाओं या किसी अन्य एजेंसी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजा जाएगा।
- (ii) संबंधित तकनीकी/प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग/वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिक संस्थाओं या कोई अन्य एजेंसी, जैसा भी मामला हो, 45 दिनों के भीतर अपने विचार/टिप्पणी/सिफारिश इलेक्ट्रॉनिक रूप से/आनलाइन भेज सकते हैं। यदि 90 दिनों के भीतर कोई टिप्पणी नहीं प्राप्त होती है तो मानदंड समिति रिकार्ड में उपलब्ध तथ्य के आधार पर अपना मत बना सकती है।

4.15 वचनबद्धता

आवेदक यह वचन देगा कि वह मानदंड समिति द्वारा निर्धारित मानदण्डों का पालन करेगा तथा तदनुसार बिना किसी संदेह के निम्नलिखित कार्रवाई करेगा:

- (i) मानदंड समिति द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार राजस्व विभाग द्वारा यथा अधिसूचित ब्याज के साथ बचाए गए सीमा शुल्क का भुगतान करेगा। तथापि, यदि मानदंड समिति एक, अधिक या सभी निविष्टियों के लिए कम मानदंड की अनुमति देती है तो प्राधिकार पत्र धारक के पास अतिरिक्त अप्रयुक्त निविष्टि के अनुपात में अतिरिक्त निर्यात दायित्व का विकल्प होगा।
- (ii) यदि मानदंड समिति द्वारा आवेदन अस्वीकृत किया जाता है, तो प्राधिकार पत्र धारक राजस्व विभाग द्वारा यथा अधिसूचित लागू निविष्टियों पर बचाए गए सीमा शुल्क का, ब्याज सहित भुगतान करेगा। स्वदेशी रूप से खरीदी गई निविष्टियों के मामले में भुगतान की जाने वाली राशि, घरेलू आपूर्तिकर्ता द्वारा सीमा शुल्क/कर/उपकर पर ली गई छूट/रिफंड पर आधारित होगी।
- (iii) यदि निविष्टियां मुक्त रूप से आयात की जाने वाली नहीं हैं तो आवेदक प्रक्रिया-पुस्तक के पैरा 4.49 (क)(ii) के अनुसार धनराशि जमा करेगा। यह राशि उपर्युक्त उप-पैरा (i) की राशि के अलावा है।

4.16 मानदंड समिति द्वारा मानदंडों के निर्धारण हेतु समय-सीमा

(i) हटा दिया गया है।

(ii) जिन मामलों में मानदंड समिति या मानदंड समिति में प्रतिनिधित्व वाले तकनीकी प्राधिकारी को अपेक्षित दस्तावेज/सूचना न देने के कारण तदर्थ/मानक निविष्टि उत्पादन मानदण्डों के निर्धारण के आवेदन को रद्द कर दिया जाता है, वहाँ प्राधिकार पत्र धारक को राजस्व विभाग द्वारा यथा अधिसूचित ब्याज सहित सीमाशुल्क तथा पैरा 4.49 (क)(ii) के अनुसार राशि का भुगतान करना होगा। यदि उक्त उत्पाद के लिए मानक निविष्टि उत्पाद मानदण्ड अधिसूचित है, तो मानक निविष्टि उत्पाद मानदण्ड अपशिष्ट मानदण्ड और निर्यात दायित्व निश्चित करने के प्रयोजन हेतु लागू कर दिए जाएंगे।

(iii) पैराग्राफ 4.12 के अनुसार अग्रिम प्राधिकार पत्र देने हेतु आवेदक की हकदारी अग्रिम प्राधिकार पत्र के तहत आवेदक द्वारा आवेदित निविष्टि की मात्रा कम होने तथा मानदंड समिति द्वारा मानदंडों के निर्धारण से पूर्व पूरे किए गए निर्यात दायित्व के मामलों में, पैराग्राफ 4.12 में यथा उल्लिखित प्राधिकार पत्र की हकदारी विगत प्राधिकार पत्रों के संबंध में निर्यात दायित्व की पूर्ति दर्शाने वाले दस्तावेजी प्रमाण (शिपिंग बिल/निर्यात बिल की प्रतियाँ/जीएसटी नियमावली के तहत निर्धारित आपूर्ति हेतु कर बीजक) प्रस्तुत करने पर पुनः उनके खाते में डाली जाएगी। तथापि, ऐसे मामलों में मानदंडों के निर्धारित होने तक बांड मुक्त करने/बांड निष्क्रिय करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

4.17 अभ्यावेदन के लिए समय-सीमा

आवेदक मानदंड के निर्धारण के संबंध में मानदंड समिति के निर्णय के विरुद्ध डीजीएफटी की वेबसाइट पर निर्णय डालने की तारीख से 90 दिनों की अवधि के भीतर अभ्यावेदन प्रस्तुत करेंगे। 90 दिनों के बाद के अभ्यावेदन पर 5000/- रु के संघटन शुल्क का भुगतान करेगा।

4.18 भेषज उत्पादों के लिए प्रावधान

क्षेत्रीय प्राधिकारी गैर-उल्लंघन (एनआई) प्रक्रिया के द्वारा विनिर्मित भेषज उत्पादों के लिए अग्रिम प्राधिकार पत्र जारी कर सकता है। उक्त उत्पाद के लिए मानक निविष्टि उत्पादन मानदंड (सिऑन) अथवा तदर्थ मानदंड (प्रक्रिया पुस्तक के पैराग्राफ 4.07 के अनुसार स्वघोषित आधार पर) के उपलब्ध होने या नहीं होने पर भी विनिर्माता निर्यातक इस प्रावधान का लाभ उठा सकता है। "विनियमित बाजारों की संबंधित एजेंसी द्वारा यथा अनुमोदित, गैर-उल्लंघन प्रक्रिया के तहत अनुमत निविष्टि संयोजन" निर्यातक विशिष्ट और देश विशिष्ट होगा और केवल तभी उपलब्ध होगा जब निर्यात उसी देश के लिए हो।

4.19 आवेदन और प्रक्रिया

(i) पैरा 4.18 के तहत अग्रिम प्राधिकार पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन आयात और निर्यात प्रपत्र 4ड. में उसमें अपलोड किए गए दस्तावेजों सहित संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को आनलाइन प्रस्तुत किया जाएगा।

(ii) उत्पाद के विनिर्माण के लिए गैर-उल्लंघन प्रक्रिया के तहत अनुमत निविष्टि संयोजन को प्रत्येक निविष्टि के ब्यौरे और आवेदक के संक्षिप्त रूप नए औषध आवेदन (एएनडीए)/औषध मास्टर फाइल (डीएमएफ) में दी गई इसकी मात्रा के समुचित सत्यापन के बाद चार्टर्ड इंजीनियर (रसायन) द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। चार्टर्ड इंजीनियर (रसायन) प्रक्रिया पुस्तक में निर्धारित परिशिष्ट 4ठ के अनुसार ब्यौरे को प्रमाणित करेगा। क्षेत्रीय प्राधिकारी आवेदन में दिए गए ब्यौरे के अनुसार तथा आवेदन के साथ प्रस्तुत चार्टर्ड इंजीनियर के प्रमाण पत्र के अनुसार निविष्टियों की आवश्यकता की पुनः जाँच करेगा और प्राधिकार पत्र जारी करेगा। क्षेत्रीय प्राधिकारी ऐसे आवेदन को मानदंड समिति को अग्रेषित नहीं करेगा और क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार अनुमत निविष्टि और निर्यात उत्पाद को गैर-उल्लंघन प्रक्रिया के तहत अनुमत निविष्टि संयोजनों के रूप में माना जाएगा।

4.20 प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 4.18 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की विमुक्ति

उप पैराग्राफ (च) को छोड़कर प्रक्रिया पुस्तक, 2015-20 के पैराग्राफ 4.49 में उल्लिखित प्रावधान लागू रहेंगे। क्षेत्रीय प्राधिकारी गैर-उल्लंघन प्रक्रिया के द्वारा विनिर्मित भेषज उत्पाद (उत्पादों) के लिए जारी प्रत्येक अग्रिम प्राधिकार पत्र के मद्दे विमुक्ति अथवा बॉड में छूट की अनुमति देने से पहले क्षेत्राधिकार प्राप्त सीमा शुल्क प्राधिकारी द्वारा विधिवत् रूप से सत्यापित और प्रमाणित परिशिष्ट-4झ के ब्यौरे से प्राधिकार पत्र में दी गई/अनुमत निविष्टियों के ब्यौरे की तुलना करेगा। सत्यापन प्रक्रिया के फलस्वरूप यदि यह पाया जाता है कि प्राधिकारी पत्र धारक ने आयात की गई मात्रा की तुलना में कम मात्रा की खपत की है तो प्राधिकार पत्र धारक अप्रयुक्त आयातित माल पर राजस्व विभाग द्वारा यथा अधिसूचित ब्याज सहित सीमा-शुल्क भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होगा अथवा निर्यात दायित्व अवधि के भीतर अतिरिक्त निर्यात करेगा। तथापि, सीमा शुल्क घटक के लिए प्राधिकार पत्र धारक के पास विदेश व्यापार नीति के अध्याय 3 के अंतर्गत जारी मान्य ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्स प्रस्तुत करने का भी विकल्प होगा।

4.21 प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 4.18 के तहत जारी प्राधिकार पत्रों हेतु उचित लेखे का रखरखाव

प्रत्येक प्राधिकार पत्र धारक परिशिष्ट 4अ में यथा निर्धारित प्रत्येक प्राधिकार पत्र के मद्दे शुल्क मुक्त आयातित/स्वदेशी रूप से खरीद की गई निविष्टियों की खपत और उपयोग का सही और उपयुक्त लेखे का रखरखाव करेगा। क्षेत्राधिकार प्राप्त सीमा शुल्क प्राधिकारी द्वारा विधिवत् रूप से सत्यापित और प्रमाणित, परिशिष्ट 4अ प्रपत्र में यह रिकार्ड विमुक्ति/बाँड में छूट प्राप्त करने के लिए आवेदन संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा। क्षेत्रीय प्राधिकारी प्रत्येक प्राधिकार पत्र के मद्दे विमुक्ति अथवा बाँड में छूट की अनुमति देने से पहले परिशिष्ट -4अ के ब्यौरे से प्राधिकार पत्र में अनुमत निविष्टियों के ब्यौरे की तुलना करेगा। ऐसे रिकार्डों को विमुक्ति की तारीख से न्यूनतम तीन वर्षों की अवधि के लिए रखा जाएगा।

4.22 तदर्थ मानदण्डों का मानकीकरण

(क) मानदण्डों के मानकीकरण के लिए, एएनएफ 4ख में सम्पूर्ण आंकड़ों सहित आनलाइन आवेदन किया जाएगा। ऐसे आवेदन डीजीएफटी मुख्यालय में संबंधित मानदंड समिति को किए जा सकते हैं।

(ख) मानदंड समिति द्वारा मानक निविष्टि उत्पादन मानदण्डों के तहत वास्तविक प्रयोक्ता शर्त के साथ ईंधन के आयात की अनुमति भी दी जा सकती है, बशर्ते कि निम्नलिखित शर्तें पूरी होती हों:-

- (i) ईंधन के आयात की सुविधा केवल कैप्टिव पावर प्लांट वाले विनिर्माताओं को दी जायेगी।
- (ii) उन मामलों में जहाँ ईंधन को विशिष्ट तौर पर मानक निविष्टि उत्पादन मानदण्डों के तहत अनुमति है, उसे अग्रिम प्राधिकार पत्र के तहत अनुमति दी जाएगी। तथापि, यदि मानक निविष्टि उत्पादन मानदण्ड के तहत ईंधन की अनुमति नहीं है, तो मानक निविष्टि उत्पादन मानदण्डों के तहत आने वाले उत्पादों के लिए सामान्य ईंधन नीति के अनुसार ईंधन की अनुमति दी जाएगी या उपर्युक्त पैरा 4.07 के तहत अनुमति दी जाएगी।
- (iii) नये क्षेत्रों के लिए ईंधन हकदारी के निर्धारण के लिए तथा प्रक्रिया पुस्तक में ईंधन हेतु सामान्य टिप्पणी के अनुसार मौजूदा हकदारी के संशोधन के लिए आवेदन आयात निर्यात प्रपत्र 4ख में अपेक्षित डाटा सहित मानदंड समिति को आनलाइन प्रस्तुत किया जाएगा।
- (iv) यदि कोई आवेदक किसी निर्धारित दस्तावेज को अपलोड नहीं कर सकता है, तो इन दस्तावेजों को वास्तविक रूप में संबंधित प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जा सकता है।

4.23 मानक निविष्टि उत्पादन मानदण्ड का संशोधन

डीजीएफटी मुख्यालय में संबंधित मानदंड समिति को आयात निर्यात प्रपत्र 4ख में मौजूदा मानक निविष्टि उत्पादन मानदण्डों में संशोधन के लिए आनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

4.24 निर्यात मद और निविष्टि का संशोधन

(i) सिओन अथवा तदर्थ मानदण्ड के अन्तर्गत निर्यात मद अथवा निविष्टि या निविष्टि की मात्रा के संशोधन हेतु निर्यातक आयात निर्यात प्रपत्र 4ख में आनलाइन आवेदन किया जाएगा।

(ii) आवेदक को संशोधन हेतु औचित्य बताना होगा तथा क्षेत्रीय कार्यालय के कार्यालय प्रमुख के विशेष अनुमोदन के साथ इसपर विचार करेगा। निविष्टि में किसी मुख्य परिवर्तन अथवा तदर्थ मानदण्ड अथवा सिओन के तहत अनुमत अधिक छीजन के लिए आवेदन के मामले में इसे पुटि के लिए मानदंड समिति को भेजा जाएगा।

4.25 मानदण्ड समिति द्वारा सिओन का संशोधन

मानदंड समिति ऐसे सिओन की पहचान करेगी, जिनमें उसके विचार से पुनरीक्षण की आवश्यकता है। निर्यातकों को ऐसे पुनरीक्षण के लिए दिए गए आयात निर्यात फार्म 4ख में संशोधित डाटा देना होगा। उद्योग/निर्यातक (निर्यातकों) के लिए यह अनिवार्य है कि सिओन के पुनरीक्षण के लिए, विदेश व्यापार महानिदेशालय/ईपीसी को उत्पादन और खपत के आँकड़े आदि उपलब्ध करवाएँ। अन्यथा, आवेदक को अग्रिम प्राधिकार पत्र स्कीम का लाभ प्राप्त करने की अनुमति नहीं होगी।

4.26 अग्रिम प्राधिकार पत्र का विवरण

अग्रिम प्राधिकार पत्र में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित को विनिर्दिष्ट किया जायेगा:-

- (क) विनिर्देशनों, जहां लागू हो, सहित आयात और निर्यात/आपूर्ति की जानेवाली मदों का नाम और विवरण;
- (ख) आयात की जानेवाली प्रत्येक मद की मात्रा अथवा जहां कहीं मात्रा नहीं बताई जा सकती, मद का मूल्य बताया जाएगा। जहां कहीं भी मानक निविष्टि उत्पादन मानदंड में प्रत्येक निविष्टि की मात्रा और मूल्य सीमाकारी कारक है तो वह लागू होगा;

- (ग) आयातों का कुल लागत बीमा भाड़ा मूल्य; और
 (घ) निर्यात/आपूर्तियों का पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य/रेल पर्यन्त निःशुल्क मूल्य और मात्रा।

4.27 प्राधिकार पत्र की प्रत्याशा में अथवा प्राधिकार पत्र जारी किए जाने पश्चात निर्यात/आपूर्ति

(क) अग्रिम प्राधिकार पत्र के लिए ई डी आई द्वारा तैयार फाइल संख्या जारी करने की तारीख से किए गए निर्यात/आपूर्तियों को निर्यात दायित्व की पूर्ति के लिए स्वीकार किया जाएगा। जारी प्राधिकार पत्र के साथ निर्यातों/आपूर्तियों से संबंध स्थापित करने के लिए फाइल संख्या अथवा प्राधिकार पत्र संख्या के साथ पोतलदान/आपूर्ति दस्तावेज पृष्ठांकित करना होगा। निर्यात/आपूर्ति दस्तावेज (दस्तावेजों) में छूट प्राप्त सामग्री/खपत की गई निविष्टियों का ब्यौरा भी होना चाहिए।

(ख) यदि आवेदन अनुमोदित हो, तो क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा आवेदन प्राप्त होने की तारीख को प्रभावी निविष्टि/उत्पादन मानदंडों के आधार पर प्राधिकार पत्र जारी किया जायेगा। यदि बीच की अवधि (अर्थात् आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की तिथि और प्राधिकार-पत्र जारी करने की तिथि) में मानदंडों में परिवर्तन हो जाता है, तो प्राधिकार-पत्र, मानदंडों में संशोधन अधिसूचित किए जाने तक पहले से किए गए अन्तिम निर्यातों/आपूर्तियों के अनुपात में जारी किया जाएगा। निर्यात के शौ हिस्से के लिए, प्राधिकार पत्र के जारी होने की तारीख को प्रभावी नीति/प्रक्रिया लागू होगी। शे ।

(ग) स्कोमेट मर्चें का निर्यात प्राधिकार पत्र के प्रति अनुमत नहीं होगा जब तक कि आवेदक द्वारा अपेक्षित स्कोमेट प्राधिकार-पत्र प्राप्त न कर लिया जाए ।

(घ) प्राधिकार पत्र की प्रत्याशा में किए गए निर्यात/आपूर्तियां आयात-पूर्व शर्त के साथ निविष्टियों के लिए पात्र नहीं होंगी।

4.28 निर्यातक जोखिम

अग्रिम प्राधिकार पत्र मिलने की प्रत्याशा में किए गए निर्यात/आपूर्तियाँ पूर्णतः निर्यातक की जिम्मेदारी और जोखिम पर होंगी।

4.29 आवेदन के निरस्त होने के मामले में वापसी की स्वीकार्यता

यदि अग्रिम प्राधिकार पत्र हेतु आवेदन को क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा अस्वीकृत अथवा संशोधित किया जाता है तो सीमाशुल्क प्राधिकारी राजस्व विभाग के नियमों के अनुसार अग्रिम प्राधिकार पत्र के अंतर्गत प्रस्तुत पोतलदान बिलों के लिए शुल्क वापसी की अनुमति प्रदान कर सकता है।

4.30 अन्तरवर्ती आपूर्तियों हेतु अग्रिम प्राधिकार पत्र अथवा डी एफ आई ए

(क) अन्तरवर्ती आपूर्ति के लिए अग्रिम लाइसेंस अथवा डीएफआईए की मंजूरी के लिए आवेदन, अग्रिम प्राधिकार-पत्र अथवा डीएफआईए धारक अन्तिम निर्यातक (वास्तविक/मान्य) के साथ पारस्परिक करार के आधार पर दिया जा सकता है। ऐसे अनुरोध पर संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा विचार किया जाएगा।

(ख) अन्तरवर्ती आपूर्ति के लिए अग्रिम प्राधिकार पत्र अथवा डीएफआईए अन्तरवर्ती विनिर्माता द्वारा आपूर्ति की गई मर्चों के सीधे आयात के लिए अंतिम निर्यातक के प्राधिकार पत्र/निर्यातक को अवैध घोषित करने के बाद जारी किया जाएगा। ऐसे मामले में, अंतिम प्राधिकार पत्र धारक को अवैधीकरण पत्र की एक प्रति दी जाएगी तथा उसकी एक प्रति मध्यवर्ती आपूर्तिकर्ता के साथ-साथ मध्यवर्ती आपूर्तिकर्ता के क्षेत्रीय प्राधिकारी को भी भेजी जाएगी। ऐसे मामले में, प्राधिकार पत्र धारक के पास अग्रिम प्राधिकार पत्र/ (अथवा अंतिम निर्यातक) अथवा डीएफआईए को अन्तरवर्ती उत्पाद की आपूर्ति करने अथवा सीधे निर्यात (वास्तविक/मान्य) करने का विकल्प होगा। अंतिम निर्यातक (डी एफ आई ए अथवा अग्रिम प्राधिकार पत्र धारक) द्वारा निर्यात के पत्तन को सीधे उत्पाद (उत्पादों) की आपूर्ति भी अन्तरवर्ती आपूर्तिकर्ता कर सकता है। ऐसे मामलों में शिपिंग बिल पर पृष्ठांकित अन्तरवर्ती आपूर्तिकर्ता के नाम के साथ अंतिम निर्यातक का नाम होगा।

(ग) अन्तरवर्ती आपूर्तिकर्ता के लिए अग्रिम प्राधिकार की सुविधा उन मामलों में भी उपलब्ध होगी जहाँ अन्तरवर्ती आपूर्तिकर्ता ने अग्रिम प्राधिकार पत्र/डीएफआईए वाले निर्यातक द्वारा निर्यात दायित्व पूरा करने पर सामग्री की आपूर्ति कर दी है या करना चाहता है जहाँ से अवैधीकरण पत्र जारी किया गया था।

(घ) अवैधीकरण पत्र में निम्नलिखित विनिर्दिष्ट किया जाएगा:

- (i) आपूर्तिकर्ता का नाम, पता और जीएसटीआईएन;
- (ii) अग्रिम प्राधिकार पत्र धारक/डीएफआईए धारक की प्राप्तकर्ता यूनिट का जीएसटीआईएन और पता जहाँ निविष्टियों को प्रसंस्कृत किया जाएगा;
- (iii) नाम, विनिर्देशन सहित विवरण, जहाँ लागू हो, और मर्चों की मात्रा; और

(iv) खरीद की जाने वाली प्रत्येक मद का मूल्य।

4.31 अग्रिम निर्मुक्ति आदेश (एआरओ)

स्वदेशी स्रोतों/एसटीई से निविष्टियों की खरीद करने के लिए एआरओ प्राप्त करने के लिए संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को एएनएफ 4क में आवेदन आनलाइन प्रस्तुत किया जाएगा।

4.32 एआरओ जारी करने हेतु दिया जाने वाला विवरण

(क) एआरओ के लिए आवेदन में निम्नलिखित विनिर्दिष्ट होगा:

(i) आपूर्तिकर्ता का नाम, पता और जीएसटीआईएन;

(ii) अग्रिम प्राधिकार पत्र धारक/डीएफआईए धारक की प्राप्तकर्ता यूनिट का जीएसटीआईएन और पता जहां निविष्टियों को प्रसंस्कृत किया जाएगा;

(iii) नाम, विनिर्देशन सहित विवरण, जहां लागू हो, और मदों की मात्रा; और

(iv) खरीद की जाने वाली प्रत्येक मद का मूल्य।

(ख) एआरओ अग्रिम प्राधिकार पत्र/डीएफआईए के साथ या उसके बाद जारी किया जा सकता है और इसकी वैधता अग्रिम प्राधिकार पत्र/डीएफआईए की वैधता के साथ सह-समाप्य होगी।

(ग) हटा दिया गया है।

4.33 हटा दिया गया है।

4.34 हटा दिया गया है।

4.35 सह-विनिर्माता/जाबकर्ता/सह लाइसेंस धारक की सुविधा

(क) आयातित माल प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 4.10 की शर्त के अधीन अग्रिम प्राधिकार पत्र धारक या जाबकर्ता/सहविनिर्माता के किसी भी एकक में प्रयुक्त हो सकता है बशर्ते कि उसका पृष्ठांकन क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा प्राधिकार पत्र में किया गया है। यदि आवेदक किसी विनिर्माता अथवा जाबकर्ता का नाम प्राधिकार पत्र में जोड़ना चाहता है, वह आवेदन कर सकता है। जहाँ अग्रिम प्राधिकार पत्र स्कीम का लाभ प्राप्त करने के लिए निर्यात से पहले आयात एक शर्त है और प्राधिकार-पत्र धारक किसी अन्य विनिर्माता अथवा जाबकर्ता के जरिए सामग्री संसाधित करवाना चाहता है वहाँ ऐसा पृष्ठांकन अनिवार्य होगा।

(ख) क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा किए गए ऐसे पृष्ठांकन पर, प्राधिकार पत्र धारक और सह-प्राधिकार पत्र धारक संयुक्त रूप से और अलग-अलग निर्यात दायित्व पूरा करने के लिए उत्तरदायी होंगे। सह-प्राधिकार पत्र धारक में से कोई एक माल का आयात अपने नाम अथवा संयुक्त नाम से कर सकता है। उनके संयुक्त नाम में बैंक गारंटी/विधिक बचनबद्धता भी प्रस्तुत की जाएगी।

(ग) यदि प्राधिकार पत्र धारक जीएसटी अधिनियम के तहत पंजीकृत है, तो क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा प्राधिकार पत्र के पृष्ठांकन के बदले जीएसटी नियमावली के अनुसार क्षेत्राधिकार प्राप्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कार्यालय द्वारा पृष्ठांकित जाबकर्ता के नामों को प्राप्त करने का विकल्प होगा। यदि प्राधिकार पत्र धारक विनिर्माता निर्यातक जीएसटी अधिनियम के तहत पंजीकृत नहीं है/पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है, वहां संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी से प्राधिकार पत्र में सहायक विनिर्माता के नाम के पृष्ठांकन के पश्चात जाब वर्क की अनुमति होगी। तथापि, प्राधिकार पत्र धारक आयातित मदों और निर्यात दायित्व को पूरा करने के लिए पूर्णतया जिम्मेदार होगा।

4.36 बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता की स्वीकृति

(क) प्राधिकार पत्र जारी करते समय संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी आवेदक द्वारा संबंधित आयात निर्यात प्रपत्र में दी गई वचनबद्धता की स्वीकृति को अग्रिम प्राधिकार पत्र के पीछे पृष्ठांकित करेगा। प्राधिकार पत्र धारक प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 2.28 की शर्तों के अनुसार बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता, जैसा भी मामला हो, का निष्पादन करेगा।

(ख) यदि बैंक गारंटी/विधिक वचन बद्धता विमुक्त कर दी गयी है, तो अग्रिम प्राधिकार पत्र धारक, जीएसटी अधिनियमों के प्रावधानों के तहत निर्धारित जाब कार्य विनियमन के अनुसार वास्तविक प्रयोक्ता शर्त के अधीन किसी विनिर्माता से शुल्क मुक्त निविष्टियों का प्रसंस्करण करा सकता है और इस संबंध में सीमा शुल्क प्राधिकारी को सूचित करेगा। तथापि, हस्तान्तरणीय डी एफ आई ए धारक के मामले में ऐसे प्रतिबन्ध लागू नहीं होंगे।

4.37 पंजीकरण का पत्तन

(क) अग्रिम प्राधिकार पत्र नीचे विनिर्दिष्ट किसी भी समुद्र पत्तन या वायुपत्तन अथवा आई सी डी अथवा एल सी एस के माध्यम

से आयात और निर्यात के प्रयोजन के लिए जारी किया जाएगा। प्राधिकार पत्र धारक प्राधिकार में विनिर्दिष्ट पत्तन पर प्राधिकार पत्र को पंजीकृत करेगा और उसके बाद उस प्राधिकार पत्र के प्रति सभी आयात तब तक केवल उसी पत्तन से करेगा जब तक कि वह उस पत्तन के सीमाशुल्क प्राधिकारी से किसी दूसरे विशिष्ट पत्तन के माध्यम से आयात करने की अनुमति नहीं ले लेता। तथापि, निर्यात किसी भी एक विनिर्दिष्ट पत्तन के माध्यम से किया जा सकता है।

समुद्री पत्तन:

बेदी (रोजी-जामनगर सहित), चेन्नई, दाहेज, धरमतार, इन्नौर, (तमिलनाडु), हव्दिया, हजिरा (सूरत), जामनगर, काकीनाडा, कांडला, कट्टुपल्ली समुद्री पत्तन (तमिलनाडु), कोच्चि, कोलकाता, कृणापत्तनम, मंगलौर, मारमागोवा, मुल्द्वारका, मुम्बई, मुन्ध्रा, नागापट्टिनम, न्हावाशेवा, ओरवा, पारादीप, पीपावाव, पोरबंदर, सिक्का, सूरत (मगदल्ला), तुतीकोरीन, वदिनार, विशाखापत्तनम।

वायु पत्तन:

अहमदाबाद, बंगलौर, भुवनेश्वर, कालीकट हवाईअड्डा (केरल), चेन्नई, कोयम्बटूर एयर कार्गो परिसर, डबोलिम (गोवा), दिल्ली, हैदराबाद, इंदौर, जयपुर, कोच्चि, कोलकाता, लखनऊ (अमौसी), मुम्बई, नागपुर, राजासांसी (अमृतसर), श्रीनगर, त्रिवेन्द्रम, वाराणसी, विशाखापट्टनम।

आईसीडी:

आगरा, अहमदाबाद, अनापार्थी, अरक्कोनाम (तमिलनाडू), बंगलौर, बाबरपुर, भदोही, भटिण्डा, भीलवाड़ा, भिवाड़ी, भूसावल, चेटीपलयम (तमिलनाडू), छेहराटा (अमृतसर), कोयम्बटूर, दादरी, दिल्ली, दीघी (पुणे), दप्पर, डेरा बस्सी, धन्नाद राऊ (इंदौर जिला), दौलताबाद, (वंजारवाड़ी और मालीवाड़ा), दुर्गापुर (निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क), फरीदाबाद, गढ़ी हरसारु, गुंटूर, गुवाहाटी (अमीनगाँव), हैदराबाद, इरुगुर गाँव (तमिलनाडू) जयपुर, जालंधर, जमशेदपुर, जोधपुर, कलिंगानगर और तुम्ब गाँव (तालुका उम्बरगाँव, जिला वलसाड), कानपुर, करूर, खेड़ा (पिथमपुर, धार जिला), कोटा, कुंडली, लोनी (जिला गाजियाबाद), लुधियाना, मदुरै, मल्लनपुर, मांडीदीप (जिला रायसेन), मेरीपलम, गुंटूर जिला (आन्ध्र प्रदेश), मिराज, मोरादाबाद, नागपुर, नासिक, पिम्परी (पुणे) पीतमपुर (इंदौर), पातली (गुडगांव), पांडिचेरी, रायपुर, रेवाड़ी, रूद्रपुर (नैनीताल), सेलम, सिंगनालुर, सूरजपुर, सूरत, तालेगांव (जिला पुणे), थूडियालूर (तमिलनाडू), तिरुपुर, तोडियारपेट (टीएनपीएम) तुतीकोरीन, उदयपुर, वडोदरा, वाराणसी, वीरापंडी (तमिलनाडू), वालूज (औरंगाबाद), होसुर (तमिलनाडू) और नाट्टकम (कोट्टयम तालुका और जिला)

एलसीएस:

अगरतला, अमृतसर रेल कार्गो, अटारी, चेंगराबंदा, दावकी, घोजाडांगा, हिली, जोगबनी, महादीपुर, नौतनवा (सोनौली) नेपाल गंज रोड, पेट्रापोल, रानाघाट, रक्सौल, सिंघावा, सूतरखंडी

एसईजैड:

केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अधिसूचित कोई भी एस ई जैड आयात एवं निर्यात के लिए निर्दिष्ट पत्तन हो सकता है।

(ख) सीमाशुल्क आयुक्त, किसी अन्य समुद्री पत्तन/वायु पत्तन/आईसीडी या एससीएस से आयात की अनुमति दे सकता है।

(ग) पंजीकरण पत्तन के अलावा किसी वायु पत्तन/समुद्री पत्तन/आई सी डी/एलसीएस से आयात के लिए, पंजीकरण के पत्तन पर सीमाशुल्क प्राधिकारी द्वारा आयात पत्तन के सीमाशुल्क प्राधिकारी को टेलीग्राफिक रिलीज सलाह (टी आर ए) जारी किया जाएगा। तथापि टी आर ए की यह आवश्यकता अपेक्षित नहीं होगी यदि पंजीकरण का पत्तन और आयात का (के) पत्तन ई डी आई समर्थित है और प्राधिकार पत्र धारक ने अपना प्राधिकार पत्र पंजीकृत करवाया है।

4.38 प्राधिकार पत्रों को मिलाने (क्लबिंग) की सुविधा

(i) 31 मार्च, 2009 को या इससे पहले जारी किए गए प्राधिकार पत्रों को कोई क्लबिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ii) क्लबिंग हेतु अनुरोध एएनएफ-4ग में उस संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी, जिसने प्राधिकार पत्र जारी किया है, को करना होगा।

(iii) अग्रिम प्राधिकार पत्रों की क्लबिंग की सुविधा ऐसे प्राधिकार पत्रों के मोचन/नियमितीकरण हेतु ही उपलब्ध होगी तथा आगे किसी आयात अथवा निर्यात की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(iv) क्लबिंग की सुविधा विदेश व्यापार नीति 2009-14 और 2015-20 की अवधि के दौरान जारी वार्षिक आवश्यकताओं हेतु अग्रिम प्राधिकार पत्रों के लिए उपलब्ध होगी, जहां कहीं भी निर्यात एवं आयात मानक निविष्ट उत्पाद मानदंड (सिओन) के अनुसार निर्यात और आयात हुआ हो।

(v) क्लबिंग के लिए केवल प्राधिकार पत्रों की अनुमति होगी जिनके तहत सदृश शुल्क छूट का लाभ की लिया गया है। ऐसे प्राधिकार पत्र अलग-अलग वित्तीय वर्ष के हो सकते हैं।

(vi) यदि किसी प्राधिकार पत्र की निर्यात दायित्व अवधि के बाहर निर्यात किया जाता है तो संघटन शुल्क का भुगतान करने पर प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 4.42 के अनुसार ऐसे प्राधिकार पत्र की क्लबिंग के पहले निर्यात दायित्व में विस्तार की अनुमति दी जाएगी।

(vii) केवल ऐसे प्राधिकार पत्रों को क्लब किया जाएगा जहां सबसे पहले जारी किए गए प्राधिकार पत्र की प्रारंभिक/विस्तारित निर्यात दायित्व अवधि के भीतर सभी प्राधिकार पत्रों के तहत निर्यात किया गया है।

(viii) क्लबिंग की केवल तभी अनुमति होगी जब प्रथम प्राधिकार पत्र में उल्लिखित निर्यात दायित्व की पूर्ति में कोई कमी है तथा अत्यधिक निर्यात अनुवर्ती प्राधिकार-पत्रों के तहत किए जाते हैं। तथापि, इस शर्त पर जोर नहीं दिया जाना चाहिए जब प्राधिकार पत्रों की वैधता अवधि (आयात के लिए) साथ-साथ चलती है तथा उत्तरवर्ती प्राधिकार पत्र के तहत किया गया आयात प्रथम प्राधिकार पत्र की वैधता (आयात के लिए) के भीतर आता है एवं प्रथम प्राधिकार पत्र की वैधता अवधि के भीतर किया गया ऐसा आयात यथानुपात आधार पर समान आधार पर या प्रथम प्राधिकार पत्र में किए गए आयात की सीमा से अत्यधिक है। प्रथम प्राधिकार की वैधता समाप्त होने के बाद जारी अनुवर्ती प्राधिकार पत्रों को क्लब किए जाने की अनुमति नहीं होगी।

(ix) अलग-अलग निर्यात दायित्व अवधि के साथ जारी प्राधिकार पत्रों की क्लबिंग की भी अनुमति होगी।

(x) सबसे पहले जारी प्राधिकार पत्र की प्रारंभिक या विस्तारित निर्यात दायित्व अवधि की समाप्ति के बाद किए गए निर्यात के लेखांकन पर ऐसे प्राधिकार पत्रों की क्लबिंग के बाद निर्यात दायित्व की पूर्ति हेतु विचार नहीं किया जाएगा।

(xi) निविष्टियों जो सभी प्राधिकार पत्रों के लिए सामान्य है, को ही क्लब किया जाएगा और सिऑन/मानदंड समिति द्वारा निर्धारित तदर्थ मानदंडों के अनुसार शुल्क मुक्त निविष्टियों का हिसाब किया जाएगा। दूसरे शब्दों में, सभी प्राधिकार पत्रों में शामिल सभी निविष्टियों का समान होना आवश्यक नहीं है।

(xii) क्लबिंग करने पर निर्यात उत्पाद के लिए विदेश व्यापार नीति और प्रक्रियाओं में यथा निर्धारित न्यूनतम मूल्य वर्धन को बनाए रखना होगा। क्लबिंग करने पर यदि मूल्य या मात्रा में कमी पायी जाती है तो उसे प्रक्रिया पुस्तक 2015-20 के पैरा 4.49 के प्रावधानों के तहत विनियमित किया जाएगा।

(xiii) क्लबिंग के बाद प्राधिकार पत्रों को सभी प्रयोजनों के लिए एक प्राधिकार पत्र के रूप में मान्य माना जाएगा। प्राधिकार पत्रों को क्लब करने के बाद परिकलित कुल सीआईएफ और कुल एफओबी के आधार पर मूल्य संवर्धन की गणना की जाएगी।

(xiv) उन प्राधिकार पत्रों के संबंध में किसी क्लबिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी जहां क्षेत्रीय प्राधिकारी को किसी गलत तथ्य/धोखा की जानकारी मिलती है। इसके अलावा, उन प्राधिकार पत्रों को क्लब करने की अनुमति नहीं होगी जहां क्षेत्रीय प्राधिकारी/सीमा शुल्क प्राधिकारी द्वारा ईओडीसी/मोचन पत्र पहले ही जारी कर दिया गया है या न्यायनिर्णय आदेश पहले ही जारी कर दिया गया है।

(xv) परिशिष्ट-30क (एफटीपी 2009-14 के तहत जारी)/परिशिष्ट 4अ (एफटीपी 2015-20 के तहत जारी) के अंतर्गत शामिल प्राधिकार पत्रों तथा 18 महीने से कम ईओपी के साथ जारी प्राधिकार पत्रों को क्लब करने के लिए अतिरिक्त प्रावधान:

(क) क्लब किए जाने हेतु प्रस्तावित किसी भी प्राधिकार पत्रों में क्लब किए गए प्राधिकार पत्रों की निर्यात दायित्व अवधि की गणना सबसे पहले किए गए आयात की तारीख से की जाएगी।

(ख) ऐसे प्राधिकार पत्रों की क्लबिंग की अनुमति दी जाएगी बशर्ते सभी निर्यात क्लब किए जाने हेतु प्रस्तावित किसी भी प्राधिकार पत्रों में सबसे पहले किए गए आयात की तारीख से गणना की गई प्रारंभिक/विस्तारित निर्यात दायित्व अवधि के भीतर पूरे किए जाते हैं।

4.39 अग्रिम प्राधिकार पत्र के मूल्य में वृद्धि/कमी

(क) अग्रिम प्राधिकार के संबंध में, संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी (अपनी वित्तीय शक्तियों के अनुसार) निम्न हेतु आवेदनों पर विचार कर सकता है :-

(i) अग्रिम प्राधिकार पत्र के लागत बीमा भाड़ा मूल्य में वृद्धि/कमी करने के लिए;

(ii) लागत बीमा भाड़ा मूल्य में वृद्धि/कमी, निविष्टियों की मात्रा, पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य और अग्रिम प्राधिकार पत्र के निर्यात की मात्रा। तथापि, ऐसी वृद्धि के बाद मूल्य संवर्धन विदेश व्यापार नीति और इसके तहत निर्धारित प्रक्रिया पुस्तक में (निर्यात उत्पाद हेतु) निर्धारित न्यूनतम मूल्य संवर्धन से कम नहीं आता तथा निविष्टि उत्पादन मानदण्डों और विदेश व्यापार नीति में कोई परिवर्तन नहीं आया हो जिसके अनुसार अग्रिम प्राधिकार-पत्र जारी किया गया था।

(ख) तथापि, विदेश व्यापार नीति 2004-09 के अधीन 27.8.2009 से पहले जारी किए गए अग्रिम प्राधिकार पत्र (पत्रों) के मामले में, प्राधिकार पत्र के मूल्य में किसी बढ़ोत्तरी के लिए निम्नलिखित शर्तें लागू होंगी :-

(i) जहाँ 27.8.09 को या उसके बाद से निर्यात किए गए हैं, सीआईएफ/एफओबी मूल्यों में बढ़ोत्तरी, निर्यात के उस हिस्से के लिए न्यूनतम 15 प्रतिशत मूल्य संवर्धन अथवा मौजूदा प्रक्रिया पुस्तक के परिशिष्ट 4घ में निर्धारित मूल्य संवर्धन जो भी कम हो, के अधीन होगी।

(ii) जहाँ कहीं 27.8.09 से पहले निर्यात किए गए हैं, सीआईएफ/एफओबी मूल्य में बढ़ोत्तरी, 15 प्रतिशत न्यूनतम मूल्य संवर्धन अथवा मौजूदा प्रक्रिया पुस्तक के परिशिष्ट 4घ में निर्धारित मूल्य संवर्धन अथवा मूल अग्रिम प्राधिकार पत्र के आवेदन में घोषित मूल्य संवर्धन, जो भी कम हो, के अधीन होगी।

(ग) मूल्य और मात्रा में यथानुपातिक वृद्धि हेतु आवेदन निर्यात से पूर्व या बाद में किया जा सकता है। उन मामलों में जहाँ उक्त उत्पाद के निर्यात से पूर्व मानक निविष्टि उत्पादन मानदंडों में परिवर्तन किया गया हो, संशोधित मानक निविष्टि उत्पादन मानदंडों पर हकदारी की गणना करने के बाद यथानुपातिक वृद्धि प्रदान की जाएगी।

(घ) प्राधिकार पत्र के सीआईएफ अथवा एफओबी के मूल्य में वृद्धि/प्राधिकार पत्र के मूल्य में कमी/ईओपी को बढ़ाने/प्राधिकार पत्र के पुनः वैधीकरण के लिए, क्षेत्रीय प्राधिकारी को आयात निर्यात प्रपत्र 4घ में आवेदन किया जाएगा।

4.40 वृद्धि के लिए आवेदन शुल्क

वृद्धि के लिए लगने वाला आवेदन शुल्क मूल और अन्तिम प्राधिकार पत्र के लागत बीमा भाड़ा मूल्य के अन्तर पर लगेगा। तथापि, कोई भी आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा, यदि प्राधिकार पत्र के मूल्य को कम किया जा रहा हो अथवा आवेदक ने अग्रिम प्राधिकार पत्र/डीएफआईए के लिए पहले ही अग्रिम प्राधिकार पत्र/डीएफआईए हेतु अधिकतम शुल्क 100,000 रुपये जमा किए हैं।

4.41 प्राधिकार पत्र का पुनःवैधीकरण

(क) अग्रिम प्राधिकार पत्र के आयात के लिए वैधता अवधि प्राधिकार पत्र के जारी किए जाने की तारीख से 12 माह के लिए होगी।

(ख) एफटीपी के अध्याय-7 के तहत आपूर्तियों के लिए अग्रिम प्राधिकार पत्र की वैधता परियोजना के निष्पादन की संविदा अवधि की सह-मियादी होगी अथवा प्राधिकार पत्र जारी किए जाने की तारीख से 12 माह, जो भी बाद में हो, के लिए होगी।

(ग) क्षेत्रीय प्राधिकारी मूल प्राधिकार पत्र धारक के अनुरोध पर विचार कर सकते हैं और मूल प्राधिकार की समाप्ति की तारीख से छः महीने की अवधि के लिए एक पुनर्वैधीकरण कर सकते हैं। प्राधिकार पत्र के पुनर्वैधीकरण के लिए आवेदन, आयात-निर्यात प्रपत्र 4घ में देना होगा।

(घ) 27.8.2009 (विदेश व्यापार नीति 2004-09) से पहले जारी किए गए अग्रिम प्राधिकार-पत्र के पुनः वैधीकरण के मामले में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि मूल्य वर्धन 15% (और विदेश व्यापार नीति के पैरा 4.09 में उल्लिखित विवरणों के अनुसार) अथवा अग्रिम प्राधिकार-पत्र में यथानिर्धारित पर, जो भी अधिक हो, बनाए रखा जाए। तथापि, परिशिष्ट-4घ के अनुसार मूल्य संवर्धन वाले उत्पादों के लिए अग्रिम प्राधिकार-पत्रों हेतु मूल्य संवर्धन परिशिष्ट 4घ में उल्लिखित मूल्य संवर्धन अथवा अग्रिम प्राधिकार-पत्र में यथा उल्लिखित, जो भी अधिक हो, के अनुसार होगा।

4.42 निर्यात दायित्व (ईओ) अवधि और इसका विस्तार

(क) अग्रिम प्राधिकार पत्र के तहत निर्यात दायित्व पूरा करने की अवधि प्राधिकार पत्र जारी करने की तारीख से 18 माह के लिए होगी जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो। अग्रिम प्राधिकार पत्र के तहत निर्यात दायित्व पूरा करने की अवधि प्राधिकार पत्र जारी करने की तारीख से आरंभ होगी, जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो।

(ख) एफटीपी के अध्याय-7 के तहत भारत में परियोजनाओं को अथवा विदेश की परियोजनाओं को आपूर्तियों के मामले में निर्यात दायित्व अवधि परियोजना के पूरा होने की संविदा अवधि की सह मियादी होगी, अथवा 18 माह की होगी, जो भी अधिक हो।

(ग) रक्षा, सैन्य भंडार, एयरोस्पेस और परमाणु ऊर्जा की श्रेणी में आने वाली मदों की निर्यात दायित्व अवधि प्राधिकार पत्र जारी किए जाने की तारीख से 24 माह के लिए अथवा निर्यात आदेश की संविदा अवधि की सह-मियादी होगी, जो भी अधिक हो।

(घ) परिशिष्ट-4अ के तहत जारी प्राधिकार पत्रों के लिए निर्यात दायित्व अवधि में विस्तार की निर्धारित निर्यात दायित्व अवधि के अधिकतम आधे से अधिक अवधि के लिए अनुमति दी जाएगी। ऐसे मामले में यदि किया गया निर्यात प्रारंभिक निर्यात दायित्व अवधि के भीतर 50% से अधिक है तो पूरा नहीं किए गए पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 0.5% प्रति माह की दर से और जहां प्रारंभिक निर्यात दायित्व अवधि के भीतर 50% से कम निर्यात किया गया है, 1% प्रति माह की दर से संयोजन शुल्क लगाया जाएगा।

(ड.) क्षेत्रीय प्राधिकारी अग्रिम प्राधिकार पत्र धारक द्वारा निर्यात दायित्व अवधि को समाप्ति की तारीख से छः माह तक के लिए निर्यात दायित्व अवधि के एक विस्तार हेतु किए गए अनुरोध पर विचार कर सकता है, जो निर्यात दायित्व में हुई कमी के 0.5 प्रतिशत के संयोजन शुल्क के भुगतान के अधीन होगा। प्राधिकार पत्र धारक को एक स्वघोषणा क्षेत्रीय प्राधिकारी को प्रस्तुत करनी होगी जिसमें यह बताना होगा कि अप्रयुक्त आयातित/स्वदेशी निविष्टियाँ आवेदक के पास उपलब्ध हैं।

(च) पहले विस्तार के पश्चात् छः माह के अतिरिक्त विस्तार, जैसा कि ऊपर (ख) में दिया गया है, पर क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा विचार किया जा सकता है बशर्ते कि प्राधिकार पत्र धारक ने मात्रा तथा मूल्य की दृष्टि से न्यूनतम 50 प्रतिशत का निर्यात दायित्व समानुपाती आधार पर पूरा कर लिया है। यह निर्यात दायित्व के अधूरे एफओबी मूल्य पर 0.5 प्रतिशत प्रति माह की दर से संयोजन शुल्क के भुगतान के अधीन होगा। क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा और किसी विस्तार की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह प्रावधान एफटीपी 2009-2014 के दौरान जारी अग्रिम प्राधिकार पत्रों पर भी लागू होगा। तथापि, 6 माह प्रत्येक के केवल दो विस्तार जैसा कि ऊपर उल्लिखित है, की अनुमति संयोजन शुल्क के भुगतान के अधीन दी जा सकती है तथा किसी भी परिस्थिति में क्षेत्रीय प्राधिकारी निर्यात दायित्व अवधि की समाप्ति की तारीख से 12 माह के पश्चात् कोई विस्तार नहीं प्रदान करेगा। दूसरे निर्यात दायित्व विस्तार हेतु आवेदन फाइल करते समय प्राधिकार पत्र धारक द्वारा क्षेत्रीय प्राधिकारी को एक स्वघोषणा प्रस्तुत करनी होगी जिसमें यह बताना होगा कि अप्रयुक्त आयातित/स्वदेशी निविष्टियाँ आवेदक के पास उपलब्ध हैं।

(छ) हटा दिया गया है।

(ड.) जब कभी किसी उत्पाद के निर्यात पर रोक/प्रतिबंध लगाया जाता है, रोक लगाने से पूर्व पहले से जारी अग्रिम प्राधिकार पत्र के संबंध में निर्यात दायित्व अवधि रोक की अवधि के समकक्ष अवधि के लिए बिना किसी समझौता शुल्क के स्वतः बढ़ जाएगा।

4.43 निर्यात खेप हेतु अनंतिम स्वीकृति

सीमाशुल्क कार्यालय निर्यात खेप की अस्थायी निकासी की अनुमति दे सकता है जब प्राधिकार पत्र धारक संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को निर्यात दायित्व बढ़ाने के लिए आवेदन किये जाने का दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करें।

4.43क अग्रिम प्राधिकार पत्र स्कीम के तहत आयातित माल का पुनः निर्यात

राजस्व विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार अग्रिम प्राधिकार पत्र स्कीम के तहत आयातित माल के दोषपूर्ण तथा उपयोग हेतु अनुपयुक्त पाए जाने पर, पुनः निर्यात किया जा सकता है। प्राधिकार पत्र धारक को ऐसे दोषपूर्ण माल के पुनः निर्यात से पहले उस क्षेत्रीय प्राधिकारी को सूचित करना होगा, जिसने प्राधिकार पत्र जारी किया है।

4.44 निर्यात दायित्व की मानीटरिंग

(क) क्षेत्रीय प्राधिकारी, जिसके साथ अग्रिम प्राधिकार पत्र धारक द्वारा विधिक वचनबद्धता निष्पादित की गई है, निर्यात दायित्व की मानीटरिंग करने के लिए वह एक मास्टर रजिस्टर में दायित्व अवधि प्रारंभ होने और समाप्त होने की तारीख और अन्य विवरणों का उचित रिकार्ड रखेगा। इसके अलावा इस सूचना को कम्प्यूटर प्रणाली में डालकर पुस्तक के रूप में रखरखाव किया जा सकता है।

(ख) निर्यात दायित्व की अवधि समाप्त होने की तारीख से दो महीने के भीतर प्राधिकार पत्र धारक, प्राधिकार पत्र के मदे पोतलदान बिलों का ब्यौरा जोड़कर आनलाइन आवेदन प्रस्तुत करेगा।

(ग) ईओडीसी आवेदन की ऑनलाइन फाइलिंग के मामले में तिमाही आधार पर मान्य निर्यात/जीएसटी नियमावली के तहत निर्धारित आपूर्तियों के लिए कर बीजक के मामले में निर्यातक डीजीएफटी की आनलाइन प्रणाली में संबंधित फाइल सं./प्राधिकार पत्र सं. तथा संबंधित पोतलदान बिल सं./निर्यात बिल/बीजकों को लिंक करके सभी किए गए निर्यातों को आनलाइन लिंक करेंगे।

(घ) एफटीपी के अध्याय-7 के अंतर्गत गैर ईडीआई पोतलदान बिलों तथा आपूर्तियों के मामले में निर्यातक डीजीएफटी की वेबसाइट पर निर्यात दायित्व की अवधि के समाप्त होने की तिथि से दो महीनों के भीतर सभी संबंधित विवरण को मैनुअल रूप से जारी करेगा। पोतलदान बिलों की प्रतियों को निर्यात दायित्व को पूरा करने की अंतिम तिथि से दो मास की अवधि के भीतर सत्यापन हेतु संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा। यदि कोई आवेदक किसी निर्धारित दस्तावेज को अपलोड नहीं कर सकता है, तो इन दस्तावेजों को वास्तविक रूप में संबंधित प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जा सकता है।

(ड.) ई-बीआरसी को निर्यात दायित्व को पूरा करने/प्राप्ति की अंतिम तिथि अथवा आरबीआई द्वारा विदेशी मुद्रा को भुनाने की निर्धारित अवधि के अनुसार इन पोतलदान बिलों से लिंक किया जाएगा। उक्त अवधि के समाप्त होने तक ई-बीआरसी को प्रस्तुत न करने पर क्षेत्रीय प्राधिकरण कोई कार्रवाई नहीं करेगा बशर्ते निर्यातक द्वारा निर्यात दायित्व को पूरा करने की पुष्टि करने हेतु अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हों।

(च) यदि निर्यात दायित्व को पूरा करने अथवा संबंधित सूचना/दस्तावेज प्रस्तुत करने में प्राधिकार पत्र धारक असफल रहता है, तो क्षेत्रीय प्राधिकारी आगे प्राधिकार पत्र देने की मनाही, प्राधिकार पत्र की शर्त तथा वचनबद्धता को लागू करने संबंधी कार्यवाही कर

सकता है जिसमें दोषी निर्यातक को आगे प्राधिकार पत्र जारी करने से इन्कार करना शामिल है।

4.45 वार्षिक आवश्यकता के लिए अग्रिम प्राधिकार पत्र

(क) ऐसे प्राधिकार पत्रों के लिए पात्र निर्यातक संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को 'आयात निर्यात फार्म 4' में आवेदन करेंगे। ऊपर दिए गए अग्रिम प्राधिकार पत्र पर लागू सभी प्रावधान निम्नलिखित को छोड़कर लागू होंगे:

- (i) छूट प्राप्त सामग्री का इस्तेमाल करने वाले निर्यात उत्पाद समूह के अन्तर्गत आने वाले किसी उत्पाद का निर्यात करने की प्राधिकार पत्र धारक को छूट प्राप्त होगी।
- (ii) पात्रता हकदारी के भीतर, निर्यातक किसी एक लाइसेंसिंग वर्ष में एक या अधिक प्राधिकारों के लिए आवेदन कर सकता है बशर्ते पंजीकरण के एक पत्तन के मद्दे, उसी उत्पाद समूह के लिए पाँच से अधिक प्राधिकार पत्र जारी नहीं किए गए हों। प्राधिकार पत्र की एक बारगी वृद्धि/कटौती उपलब्ध होगी।
- (iii) एक लाइसेंसिंग वर्ष में एक अथवा अधिक प्राधिकार पत्रों के प्रति निर्यात दायित्व पूरा होने पर निर्यातक की हकदारी, उस लाइसेंसिंग वर्ष के लिए प्राधिकार पत्र के मद्दे निर्यात दायित्व पूरा होने के बराबर राशि तक पुनः जीवित मान ली जाएगी।
- (iv) ऐसे निर्यात उत्पाद जिनका सिओन नहीं है उनके लिए वार्षिक आवश्यकता हेतु अग्रिम प्राधिकार पत्र उपलब्ध नहीं होगा। इसके अलावा जहां सिओन निर्धारित है परंतु निविष्टि 4ज में सूचीबद्ध है तो अग्रिम प्राधिकार पत्र के तहत कोई निर्यात नहीं किया जाएगा।

(ख) प्राधिकार पत्र के मद्दे आयात खेप की निकासी के समय निर्यातक निम्नलिखित निविष्टियों के संबंध में तकनीकी विशेषताओं, गुणवत्ता और विनिर्देशनों का उल्लेख करेगा जिसे सीमाशुल्क प्राधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित आगम बिल/बीजक में पृष्ठांकित किया जाएगा।

"एलाय स्टील, स्टेनलेस स्टील, कापर एलाय, सिंथेटिक रबर, बीयरिंग्स सॉल्वेंट्स परफ्यूम्स/सुगंधित तेल/ एरोमेटिक्स रसायन, सरफेक्टेंट्स, सम्बद्ध फैब्रिक्स और संगमरमर।"

4.45क निर्यात एवं आयात का आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण के अध्याय-61 और 62 के तहत शामिल परिधान सामग्री और वस्त्र की सहायक सामग्री के निर्यात हेतु विशेष अग्रिम प्राधिकार पत्र

- (i) निर्यात एवं आयात का आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण के अध्याय-61 और 62 के तहत शामिल परिधान सामग्री और वस्त्र की सहायक सामग्री के निर्यात हेतु विशेष अग्रिम प्राधिकार पत्र संबंधी नीति विदेश व्यापार नीति के पैरा 4.04क में निर्धारित की गई है।
- (ii) प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 4.05, 4.06, 4.10, 4.11, 4.12 (v) और (vi), 4.21, 4.24, 4.25, 4.26, 4.29, 4.35, 4.36, 4.37, 4.39, 4.40, 4.41, 4.42, 4.43, 4.43क, 4.44, 4.46, 4.47(ख), 4.49, 4.50, 4.51, 4.52 के प्रावधान इस स्कीम पर लागू होंगे जब तक कि वे इस स्कीम के असंगत न हो जाएँ।

4.46 निर्यात दायित्व की पूर्ति

प्राधिकार पत्र धारक, संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकरण को एएनएफ 4च में आनलाइन आवेदन प्रस्तुत करेगा तथा निर्यात दायित्व को पूरा करने के लिए निर्धारित दस्तावेज अपलोड करेगा।

4.47 विमुक्ति/गैर बंध प्रमाण पत्र

(क) **बाँण्ड से छूट:** यदि प्राधिकार पत्र धारक आयातित निविष्टियों/स्वदेशी रूप से अधिप्राप्त कच्चे माल का प्रयोग करके पहले निर्यात करता है (आयात करने से पहले) तो ऐसे मामले में प्राधिकार-पत्र धारक किए गए निर्यात तथा इसे प्राप्त भुगतान का साक्ष्य प्रस्तुत करके बाण्ड शर्त से छूट की मांग कर सकता है। यदि किया गया निर्यात प्राधिकार पत्र में निर्धारित निर्यात दायित्व से कम है तो यथानुपात आधार पर बाण्ड शर्त से छूट के अनुरोध पर भी विचार किया जा सकता है।

(i) ऐसे अनुरोध के लिए आवेदक को पोतलदान बिलों और ई-बीआरसी को संलग्न करके आनलाइन आवेदन करना होगा। एएनएफ 4च में निर्धारित अन्य दस्तावेजों की स्केन्ड प्रति भी अपलोड करनी होगी। यदि मान्य निर्यात या गैर-ईडीआई पत्तनों से निर्यात के मामले में ई-बीआरसी को छोड़कर वास्तविक रूप में आनलाइन आवेदन का संदर्भ देते हुए निर्यात/आपूर्ति के प्रमाण हेतु दस्तावेजों को संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी के पटल पर प्रस्तुत किया जाएगा।

(ii) हटा दिया गया है।

(iii) यदि निर्यात दायित्व पूरा कर लिया गया है, क्षेत्रीय प्राधिकारी एक बांड से छूट प्रमाण-पत्र (बी डब्ल्यूसी) जारी करेगा और बांड से शर्त में छूट को अनुमत करते हुए, प्राधिकार पत्र के पंजीकरण के पत्तन पर, पोतलदान बिल (बिलों की संख्या), तिथि

(तिथियों), पोतलदान बिल (बिलों) के अनुसार भारतीय रूप्यों में एफओबी मूल्य और विचारार्थ पोतलदान के संबंध में निर्यात उत्पाद के विवरण संबंधी विवरणों को संलग्न करते हुए सीमा-शुल्क प्राधिकारियों को एक प्रति संलग्न करेगा। बांड की ऐसी छूट सीमा-शुल्क अधिकारियों को सीमा-शुल्क विभाग की अधिसूचना के अनुसरण में नहीं रोकेगी।

(iv) ऐसे निर्यात के लिए बांड की छूट देते हुए क्षेत्रीय प्राधिकारी निर्यातित उत्पाद के उत्पादन में उपभोग की गई निविष्टियों की पुनः पूर्ति के लिए पृष्ठांकन की तारीख से छः माह की अवधि के लिए प्राधिकार पत्र को मान्यता दे सकता है, बशर्ते कि आवेदक ने एएनएफ 4घ में विशेष अनुरोध कर रखा हो तथा पुनः मान्यकरण हेतु अपेक्षित शुल्क का भुगतान कर रखा हो। आगे यह इस शर्त के अधीन होगा कि आवेदक ने प्रक्रिया पुस्तक 2015-20 के पैरा 4.41(क) के अनुसार पहले पुनः मान्यकरण प्राप्त नहीं किया था। इस पैरा के तहत अनुमत पुनः मान्यकरण सहित प्राधिकार पत्र की वैधता की अधिकतम अवधि प्राधिकार पत्र जारी करने की तारीख से 24 माह से अधिक नहीं होगी।

(v) क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा बांड से छूट प्रमाण-पत्र की एक प्रति पंजीकरण के पत्तन पर डाक द्वारा सीमा शुल्क विभाग को पृष्ठांकित की जाएगी जब तक कि डीजीएफटी और सीबीईसी के बीच संदेश आदान-प्रदान के तहत ईडीआई तरीके के माध्यम से यह प्रणाली शुरू न हो जाए।

(ख) निर्यात दायित्व विमुक्ति प्रमाण-पत्र (ईओडीसी):-

(i) प्राधिकार-पत्र धारक निर्यात एवं आयात के पूरा होने पर एएनएफ-4च में एक आनलाईन आवेदन-पत्र प्रस्तुत करेगा जैसा कि उपरोक्त (क) (i) में दिया गया है। ऐसे मामलों में, यदि निर्यात दायित्व की पूर्ति कर ली गई है, क्षेत्रीय प्राधिकारी, प्राधिकार-पत्र धारक को एक ईओडीसी/मोचन प्रमाण-पत्र जारी कर सकता है और सीमा शुल्क प्राधिकारियों को प्राधिकार के पंजीकरण के पत्तन पर निर्यात दायित्व की पूर्ति का प्रमाण देते हुए जैसा कि उपरोक्त पैरा (क) में दर्शाया गया है, निर्यात दायित्व की पूर्ति के प्रमाण के उन विवरणों को दर्शाते हुए एक प्रति अग्रणी कर सकता है।

(ii) क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा ईओडीसी की एक प्रति पंजीकरण के पत्तन पर डाक द्वारा सीमा शुल्क विभाग को पृष्ठांकित की जाएगी जब तक कि डीजीएफटी और सीबीईसी के बीच संदेश आदान-प्रदान के तहत ईडीआई तरीके के माध्यम से यह प्रणाली शुरू न हो जाए।

(ग) साधारणतया, बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता से छूट सीमा शुल्क प्राधिकारियों को आकस्मिक रोक लगाने अथवा सीमा शुल्क अधिनियम के अनुसार तदनुसार किसी गलत बयानी, गलत घोषणा और पता लगाई गई चूक के विरुद्ध कार्रवाई करने से नहीं रोकेगी।

(घ) ऐसे प्रमाण-पत्र की प्रमाणिकता डीजीएफटी की वेबसाइट (dgft.gov.in) अथवा डीजीएफटी के जोनल कार्यालयों की वेबसाइटों की सहायता से जांची जाएगी। डीजीएफटी के जोनल कार्यालय उनके द्वारा और उनके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले सभी क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा जारी ऐसे ईओडीसी प्रमाण पत्रों का विवरण अपनी अधिकारिक वेबसाइट पर प्रत्येक माह डालेंगे।

(ड.) क्षेत्रीय प्राधिकारी विधिवत रूप से भरे हुए परिशिष्ट-4ज और 4झ को न सौपने के मामले में जैसा कि नीचे दिए गए पैराग्राफ 4.51 में निर्धारित किया गया है अथवा तदनुसार परिशिष्ट-4ज और 4झ में घोषित और प्रस्तुत किए गए विवरणों में किसी गलतबयानी, गलत घोषणा अथवा पता लगाई गई चूक के लिए प्राधिकार-पत्र धारक के विरुद्ध कार्रवाई करेगा। इस संबंध में क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा मोचन प्रमाणपत्र में पृष्ठांकन किया जाएगा।

4.48 26.8.2009 तक जारी किए गए प्राधिकार पत्रों के लिए परिवर्ती व्यवस्था

(क) 26.8.2009 तक जारी वार्षिक जरूरतों हेतु अग्रिम लाइसेंसों सहित अग्रिम लाइसेंस समय-समय पर यथा संशोधित प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-1 (आर ई 2001) के अध्याय-7, 31.3.2002 को यथा अधिसूचित प्रक्रिया पुस्तक खण्ड 1(2002-2007) के अध्याय 4 तथा 31.8.2004 को यथा अधिसूचित प्रक्रिया पुस्तक, खण्ड-1 (2004-2009) के अध्याय-4 और 27.08.2009 को यथा अधिसूचित प्रक्रिया पुस्तक, खण्ड-1 (2009-14) के अध्याय-4 में निहित प्रावधानों द्वारा शासित होंगे। सम्बंधित प्रावधान निर्यात दायित्व अवधि को जोड़ने और उसके विस्तार पर लागू नहीं होंगे, जो उपर्युक्त पैरा क्रमशः 4.38 और 4.42 (ड.) के प्रावधानों और डी जी एफ टी द्वारा यथा अधिसूचित किसी अन्य प्रावधान द्वारा शासित होंगे।

(ख) जिन मामलों में अप्रयुक्त माल पर सीमाशुल्क देय है, वह उस पर राजस्व विभाग द्वारा यथा अधिसूचित ब्याज सहित देय होगा।

4.49 वास्तविक चूक का विनियमन

निर्यात दायित्व को पूरा करने में यदि वास्तविक चूक हो जाती है तो उस मामले में क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा नीचे उल्लिखित तरीकों से विनियमन किया जा सकता है :-

(क) यदि निर्यात दायित्व मूल्य के अनुसार पूरा किया गया है, लेकिन मात्रा के अनुसार उसमें कमी है तो प्राधिकार पत्र धारक विनियमन के लिए निम्नलिखित को भुगतान करेगा:-

(i) सीमा शुल्क प्राधिकारी को राजस्व विभाग द्वारा यथा अधिसूचित ब्याज के साथ आयातित माल/स्वदेशी रूप से प्राप्त माल के अप्रयुक्त मूल्य पर सीमा शुल्क देगा। निर्यातकों के पास विदेश व्यापार नीति के तहत जारी वैध ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्स के माध्यम से सीमा-शुल्क अदा करने का विकल्प रहेगा। तथापि, ब्याज/जुर्माना नकद रूप से दिया जाना अपेक्षित होगा।

(ii) यदि आयात की मद प्रतिबंधित है, अप्रयुक्त आयातित सामग्री के सीआईएफ मूल्य के 3 प्रतिशत की राशि के बराबर राशि को “शीर्ष लेखा: 1453, विदेश व्यापार और निर्यात संवर्धन तथा उपशीर्ष 102” में डाला जाएगा। तथापि इस उप पैरा के प्रावधान लागू नहीं होंगे यदि आयात/घरेलू खरीद की तारीख को अप्रयुक्त माल मुक्त रूप से आयात योग्य हों।

(ख) यदि निर्यात दायित्व मात्रा के अनुसार पूरा कर लिया है लेकिन मूल्य के अनुसार इस में कमी आ गई है तो प्राधिकार पत्र धारक पर न्यूनतम निर्धारित मूल्य संवर्धन प्राप्त करने पर जुर्माना नहीं लगाया जायेगा। तथापि, मूल्य संवर्धन यदि निर्धारित न्यूनतम मूल्य संवर्धन से नीचे आ जाता है तो प्राधिकार पत्र धारक खजाना रसीद के माध्यम से सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया की प्राधिकृत शाखा में अथवा ईएफटी प्रणाली अथवा क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य में कमी के 1 प्रतिशत राशि के बराबर भारतीय रुपये में जमा करेगा।

(ग) मूल्यवार कमी की गणना, निर्यात की वास्तविक मात्रा के सन्दर्भ में और आयातों की यथानुपात मात्रा के सन्दर्भ में तथा लागत बीमा भाड़ा मूल्य के संदर्भ में अर्जित पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य पर की जाएगी। उदाहरण के लिए, यदि निर्यात निष्पादन मात्रावार केवल 50% है लेकिन आयात अनुमत पूर्ण लागत बीमा भाड़ा मूल्य के लिए है तो मूल्यवर्धन की गणना यथानुपात अर्थात् आयात के लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य के 50% के संदर्भ के आधार पर की जाएगी। तदनुसार, उसका यह तात्पर्य होगा कि जहाँ प्राधिकार पत्र धारक निर्यात निष्पादन करने में असमर्थ हो, वहाँ मूल्यवार कमी पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा।

(घ) यदि निर्यात दायित्व की प्रतिपूर्ति मात्रात्मक और मूल्यात्मक दोनों ही शर्तों के अनुसार पूरा नहीं होता है तो प्राधिकार पत्र धारक ऊपर उल्लिखित (क) (ख) और (ग) के अनुसार विनियमन के लिए भुगतान करेगा।

(ङ.) यदि निर्यातक, निर्यात दायित्व को पूर्ण रूप से पूरा करने में असमर्थ है और उसने प्राधिकार पत्र के अधीन कोई आयात नहीं किया है तो प्राधिकार पत्र धारक के पास पोतलदान बिलों को शुल्क वापसी पोतलदान बिलों में परिवर्तित करने के लिए सीमाशुल्क प्राधिकारी से अनुमति लेने के बाद शुल्क वापसी हेतु आवेदन करने और लाइसेंस रद्द करवाने का विकल्प होगा।

(च) क्षेत्रीय प्राधिकारी सनदी लेखाकार द्वारा प्रमाणित और सत्यापित परिशिष्ट 4ज के सम्बद्ध अंशों को पिछले लाइसेंसिंग वर्ष के शुरु में प्राधिकार (प्राधिकारों) के अधीन आयातित वास्तविक मात्रा और प्राधिकार (प्राधिकारों) में अनुमत मानदण्डों से तुलना करेगा। इस सत्यापन प्रक्रिया में यदि यह पाया जाता है कि प्राधिकार पत्र धारक ने आयातित से कम मात्रा की खपत की है, तो प्राधिकार पत्र धारक आयातित माल के अप्रयुक्त मूल्य पर यथा अधिसूचित ब्याज सहित सीमा-शुल्क का भुगतान करना होगा या निर्यात दायित्व की अवधि के भीतर अतिरिक्त निर्यात करना होगा।

(छ) उन मामलों में वास्तविक चूक का नियमितीकरण जहां आयात-पूर्व शर्त के साथ गैर-पंजीकृत स्रोतों से औषधियों के आयात के लिए प्राधिकार पत्र जारी किया गया था। आयात-पूर्व शर्त के साथ जारी गैर-पंजीकृत स्रोतों से औषधियों का आयात निम्नलिखित तरीके से नियमित किया जाएगा:

(i) प्राधिकार पत्र धारक मानदंडों के अनुसार पूर्ण आयतित मात्रा की खपत को दर्शानेवाले दस्तावेजों को प्रस्तुत करेगा। यदि निर्यात दायित्व पूरा करने में कमी है और अप्रयुक्त आयातित मात्रा प्राधिकार पत्र धारक के पास है तो प्राधिकार पत्र धारक प्रक्रिया पुस्तक 2015-20 के पैरा 4.43 क के अनुसार अप्रयुक्त आयातित मात्रा को उनकी उपस्थिति में विध्वंस करने का प्रमाण देते हुए क्षेत्राधिकारी केन्द्रीय उत्पाद/सीमाशुल्क प्राधिकारी से प्रमाण पत्र या उस मात्रा का पुनः उसी आपूर्तिकर्ता को निर्यात करने का प्रमाण प्रस्तुत करेगा।

(ii) औषधियों की अप्रयुक्त मात्रा का उपयोग करके निर्यात दायित्व अवधि के समाप्त होने के बाद मुक्त पोतलदान बिलों/समान प्राधिकार पत्र के अधीन किए गए निर्यात को भी विध्वंस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के एवज में स्वीकार किया जाएगा बशर्ते निर्यात किए गए औषध के सही-सही विवरण और तकनीकी विशिष्टता अग्रिम प्राधिकार पत्र में वर्णित निर्यात मद के समान हों। तथापि, प्राधिकार पत्र धारक अग्रिम प्राधिकार पत्र के तहत आयातित अप्रयुक्त मात्रा पर सीमा शुल्क का भुगतान करेगा। निर्यात दायित्व अवधि से बाहर किए गए निर्यात के लिए ही विध्वंस प्रमाण पत्र से छूट पर विचार किया जाएगा, देय शुल्क और ब्याज की देयता से छूट पर विचार नहीं किया जाएगा।

4.50 निर्यात दायित्व में वास्तविक चूक के मामले में सीमाशुल्क और ब्याज की अदायगी

(क) बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता को विनियमित या लागू करने के संबंध में प्राधिकार पत्र धारक से राजस्व विभाग द्वारा यथा अधिसूचित वसूल किया जाने वाला ब्याज सहित सीमाशुल्क, प्राधिकार पत्र धारक क्षेत्रीय/सीमा शुल्क प्राधिकारी द्वारा की गई

माँग के 30 दिनों के भीतर निर्धारित टी.आर.चालान में संबंधित सीमाशुल्क राजस्व के "मुख्य शीर्ष 0037- सीमाशुल्क" और उपशीर्ष 001- आयात शुल्क" में जमा करेगा और क्षेत्रीय/सीमा शुल्क प्राधिकारी के पास तत्काल इस आशय का दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। निर्यातक राजस्व विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार स्वयं/अपनी गणना के आधार पर सीमा-शुल्क और ब्याज की स्वतः अदायगी कर सकता है।

(ख) भुगतान का तरीका: भुगतान के निम्नलिखित तरीके उपलब्ध हैं-

(i) सीमा शुल्क प्राधिकारियों को टीआर चालान के माध्यम से नकद अदायगी।

(ii) संबंधित प्रतिफल/शुल्क छूट स्क्रिप के तहत अनुमत माल के संबंध में विदेश व्यापार नीति 2009-2014 के अध्याय-3 (एसएचआईएस, एसएफआईएस और एआईआई एस स्क्रिप्स को छोड़कर) अथवा इस विदेश व्यापार नीति के अध्याय 3 अथवा निर्यात-पश्च ईपीसीजी शुल्क छूट स्कीम स्क्रिप के तहत जारी वैध शुल्क क्रेडिट स्क्रिप्स के माध्यम से सीमा शुल्क की अदायगी।

(ग) निर्यातक टीआर चालान 006 पर अथवा ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप (स्क्रिप्स) के पीछे जिसके तहत सीमा शुल्क की अदायगी स्वीकार की गई है/ डेबिट की गई है, सीमा शुल्क प्राधिकारियों से एक पृष्ठांकन प्राप्त करेगा और उसे शुल्क गणना शीट के साथ आरए के पास अपने मामले के नियमितीकरण के समय प्रस्तुत करेगा।

(घ) क्षेत्रीय प्राधिकारी मामले का मोचन करने से पहले अधिक आयात की मात्रा की जांच करेगा। आरए प्राधिकार-पत्र धारक द्वारा गणना की गई देयता और क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा की गई गणना में अंतर के कारण को सूचित करने के बाद लाइसेंस धारकों को सीमाशुल्क की बकाया राशि अदा करने का निदेश दे सकता है। ऐसे मामले में, शुल्क और ब्याज की शौ राशि, यदि कोई है, प्राधिकार-पत्र धारक द्वारा मामले का नियमितीकरण करने के लिए 30 दिनों के अंदर अदा की जाएगी।

(ड.) सीमा शुल्क प्राधिकारी को ब्याज विलम्बित शुल्क राशि की अदायगी की तिथि पर लागू दर पर टीआर चालान 006 के माध्यम से नकद रूप में अदा किया जाएगा।

(च) प्राधिकार-पत्र धारक से उक्त दस्तावेजी प्रमाण प्राप्त होने पर, क्षेत्रीय प्राधिकारी मामले का मोचन करेगा, ईओडीसी/मोचन पत्र पर भुगतान किए गए शुल्क के ब्यौरे को पृष्ठांकित करेगा और पंजीकरण के पत्तन पर अथवा प्राधिकार-पत्र धारक की फैंक्ट्री पर क्षेत्राधिकार वाले सीमा शुल्क के आयुक्त, जैसा भी मामला हो, सीमा शुल्क प्राधिकारी को की गई वसूली/जमा के विवरण के बारे में सूचित करेगा।

(छ) तथापि, नियमितीकरण के लिए शुल्क की अदायगी, ब्याज और अन्य बकाया, सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के तहत सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा की जा सकने वाली कार्यवाई से परे होंगे।

4.51 खातों का समुचित रख-रखाव

प्रत्येक अग्रिम प्राधिकार पत्र धारक परिशिष्ट 4ज या 4झ में यथा निर्धारित प्रत्येक प्राधिकार पत्र के अधीन शुल्क मुक्त आयातित/घरेलू स्रोत से प्राप्त वस्तुओं के इस्तेमाल और खपत का सही और उचित हिसाब रखेगा। प्रत्येक लाइसेंसिंग वर्ष के शुरु में उन सभी प्राधिकार पत्रों के लिए जो पिछले लाइसेंसिंग वर्षों में विमुक्त किए गये हैं, इन रिकार्ड्स को सम्बंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी को भेजना होगा। तथापि, 13-5-2005 को या इसके बाद जारी प्राधिकारों हेतु इन रिकार्ड्स को उक्त प्रपत्र में प्रस्तुत करना होगा। इन रिकार्ड्स को विमुक्ति की तिथि से कम से कम 3 वर्ष के लिए सुरक्षित रखा जाना चाहिए।

4.52 पोतलदान बिलों और/अथवा बैंक वसूली प्रमाण-पत्र/ई-बीआरसी की निर्यात संवर्धन प्रति खो जाने के मामले पर विचार करना

(क) जिन मामलों में पोतलदान बिल/मूल बी.आर.सी. की मूल ई.पी.प्रति खो गई हो तो अग्रिम प्राधिकार पत्र/डी.एफ.आई.ए. स्कीम अथवा डी.एफ.आई.ए. के तहत हस्तान्तरणीयता के पृष्ठांकन के, ई.ओ.डी.सी., बैंक गारंटी न देने/विधिक वचनबद्धता की शर्त संबंधी अनुरोध पर विचार किया जा सकता है बशर्ते मूल दस्तावेजों के स्थान पर निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएँ:

(i) मूल के स्थान पर पोतलदान बिल की डुप्लीकेट/सीमाशुल्क प्रमाणित/स्व सत्यापित प्रति; मूल के स्थान पर बीआरसी की डुप्लीकेट/बैंक प्रमाणित प्रति;

(ii) बचाये गये शुल्क के 1 प्रतिशत के बराबर आवेदन शुल्क। तथापि, सरकारी एजेंसियों द्वारा ऐसा दस्तावेज खो दिये जाने पर कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा बशर्ते इसका दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत किया गया है।

(iii) निर्यातक द्वारा दस्तावेज खोने के बारे में स्वः घोषणा और यदि बाद में ये दस्तावेज मिल जाते हैं तो इसे संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को तत्काल वापिस करने के संबंध में एक शपथ-पत्र।

(iv) निर्यातक को इस आशय का एक क्षतिपूर्ति बाण्ड प्रस्तुत करना होगा कि वह पोतलदान बिलों/बी.आर.सी. खो जाने के अधीन उपयोग में लाये गये/अनुमत शुल्क मुक्त आयात हकदारी का उपयोग करने पर सरकार को होने वाली वित्तीय हानि की क्षतिपूर्ति करेगा।

(ख) सीमाशुल्क प्राधिकारी, बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता को निष्कृत करने अथवा "बैंक गारंटी ना देने/विधिक वचनबद्धता शर्त" के पृष्ठांकन के पश्चात निकासी करने अथवा हस्तान्तरणीयता का पृष्ठांकन करने से पहले ऐसे पोतलदान बिलों की सत्यता की जाँच करेगा और सुनिश्चित करेगा कि ऐसे जहाजरानी बिल के अधीन कोई दोहरा लाभ तो नहीं उठाया गया है। यह विशिष्ट शर्त संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा ईओडीसी पर पृष्ठांकित की जाएगी।

शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार पत्र (डीएफआईए) स्कीम

4.53 नीति

शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार (डीएफआईए) स्कीम से सम्बन्धित नीति विदेश व्यापार नीति के अध्याय 4 में दी गई है।

4.54 आवेदन-पत्र

(क) 'आयात निर्यात फार्म 4छ' में आवेदन, आवेदन पत्र में निर्धारित दस्तावेजों के साथ संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा।

(ख) इस प्रक्रिया-पुस्तक के पैराग्राफ 4.26, 4.27, 4.28, 4.48, 4.49(ड.) और 4.49(च) तथा 4.52 के प्रावधान डीएफआईए स्कीम के लिए भी लागू होंगे।

(ग) निर्यात के पूरा होने और धनराशि की प्राप्ति के पश्चात् हस्तान्तरणीय शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार पत्र जारी करने हेतु अनुरोध संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को निर्यात की तारीख से बारह माह की अवधि के भीतर अथवा निर्यात संबंधी धनराशि के प्राप्त होने की तारीख से छः माह (अथवा आरबीआई द्वारा प्राप्ति हेतु अनुमत अतिरिक्त समय) के भीतर, जो भी बाद में हो, किया जा सकता है।

(घ) प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 9.02 के अनुसार आवेदक फाइल सं. के सृजन की तारीख से 24 माह के बाद भी आवेदन कर सकता है।

4.55 खण्डित डीएफआईए हेतु सुविधा

हस्तान्तरणीयता माँगने के अनुरोध पर प्रत्येक 10 लाख रु के न्यूनतम लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य और उसके गुणकों के अधीन डीएफआईए के अलग-अलग प्राधिकार भी जारी किए जा सकते हैं। प्रत्येक अलग-अलग प्राधिकार हेतु 1000/- रु का शुल्क अदा किया जाएगा। अलग-अलग डी एफ आई ए की अनुमति उसी पंजीकरण के पत्तन से होगी जोकि मूल डी एफ आई ए पर अंकित है।

4.56 डीएफआईए स्कीम के तहत आयातित माल का पुनः निर्यात

(i) हस्तान्तरणीय डीएफआईए के अधीन आयातित माल, जिसे खराब या उपयोग के लिए अनुपयुक्त पाया जाता है, उसे राजस्व विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार पुनः निर्यात किया जा सकता है। ऐसे मामलों में यदि ऐसे माल का आयात के बाद उपयोग नहीं किया गया है तो सम्बन्धित सीमाशुल्क आयुक्त द्वारा डीएफआईए के अधीन डेबिट किए गए लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य के 95 प्रतिशत तक एक प्रमाणपत्र तैयार किया जाएगा जिसमें धनराशि और निर्यातित माल का विवरण और मूल डीएफआईए का ब्यौरा शामिल हो।

(ii) प्रमाणपत्र के आधार पर संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा एक नया डीएफआईए जारी किया जाएगा। इस प्रकार जारी किया गया नया डीएफआईए में पंजीकरण का समान पत्तन होगा और वह ऐसे खराब/अनुपयुक्त सामान के आयात की तारीख को उपलब्ध शेष अवधि के समतुल्य अवधि के लिए वैध होगा।

4.57 आयात और इसके उपयोग के उचित खातों का रख रखाव

मूल डीएफआईए धारक परिशिष्ट 4ज में यथा निर्धारित प्रत्येक प्राधिकार पत्र के अधीन शुल्क मुक्त आयातित/घरेलू स्रोतों से प्राप्त माल के उपयोग और खपत का सही और उचित लेखा जोखा रखेगा। इन रिकार्डों को बाण्ड से छूट/विमुक्ति/निर्यात दायित्व के निपादन/हस्तान्तरणीयता के लिए अनुरोध सहित सम्बन्धित क्षेत्रीय प्राधिकारी को भेजना होगा। इन रिकार्डों को विमुक्ति की तिथि से कम से कम 3 वर्ष की अवधि तक सुरक्षित रखना होगा।

रत्न और आभूषण क्षेत्र**4.58 सामान्य प्रावधान**

रत्न पुनःपूर्ति प्राधिकार पत्र और स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम के आभूषणों की स्कीम से संबंधित नीति विदेश व्यापार नीति में दी गई है। नामित एजेंसी प्रमाण पत्र सहित रत्न एवं आभूषण के लिए निर्यात संवर्धन स्कीम के संबंध में आवेदन परिशिष्ट-4क के अनुसार संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी के पास किया जाएगा।

4.59 पुनःपूर्ति प्राधिकार पत्र हेतु आवेदन

- (क) पुनःपूर्ति प्राधिकार पत्र के लिए आनलाइन आवेदन परिशिष्ट-4ज के अनुसार किया जाएगा तथा संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी के पास परिशिष्ट 4क के अनुसार उसमें निर्धारित दस्तावेजों को अपलोड किया जाएगा।
- (ख) आवेदन उस माह से छ माह के भीतर प्रस्तुत करना चाहिए जिस माह के दौरान निर्यात आय प्राप्त की गई है। माह के दौरान निर्यात से प्राप्त आय के लिए पूरे महीने के लिए समेकित आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
- (ग) यदि पोतलदान बिलों की ईपी प्रति और सीमा शुल्क कार्यालय से अधिप्रमाणित बीजक नामित एजेंसियों को सौंप दिए जाते हैं, तो निर्यातक उसकी एक स्व प्रमाणित प्रति और नामित एजेंसी से यह प्रमाणित करते हुए एक प्रमाण पत्र सौंपेगा जिसमें जड़े हुए आभूषणों के मामले में जुड़ाव का कैरेट/मूल्य प्रमाणित किया गया हो।
- (घ) जिस मामले में भुगतान अग्रिम स्म से प्राप्त हो गया है और निर्यात बाद में किया जाता है तो पुनःपूर्ति प्राधिकार पत्र के लिए आवेदन, जिस महीने के दौरान निर्यात किया गया है उससे छः महीने के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा।
- (ङ.) यह स्पष्ट किया जाता है कि अग्रिम भुगतान मामले में, जिस माह निर्यात किया गया है और निर्यात करने के बाद जिस माह निर्यात आय आंशिक स्म से या पूर्णस्म से प्राप्त की जाती है उस माह को पुनःपूर्ति प्राधिकार पत्र हेतु आवेदन पत्र दाखिल करने के प्रयोजन के लिए छः माह की अवधि में नहीं गिना जाएगा।

4.60 छीजन मानदण्ड

स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम के आभूषणों तथा उससे बनी वस्तुओं के लिए अधिकतम छीजन या विनिर्माण हानि नीचे दी गई है:

क्रम सं.	निर्यात की मर्दे	निर्यात मर्द में सोने/चाँदी/प्लेटिनम के संदर्भ में छीजन का प्रतिशत	
		सोना/प्लेटिनम	चाँदी
क)	सोना और काले मनकों/बनावटी नगीना, घनाकार जिरकोनिया, हीरे, कीमती और अर्द्ध-कीमती नगीनों सहित मंगलसूत्र जैसे सहज आभूषण, वस्तुएं और आभूषण	2.5 %	3.2 %
ख)	जड़ित जेवर और उनकी वस्तुएं	5.0 %	5.0 %
ग)	स्वदेशी रूप से विनिर्मित (गैर-मैकेनाईज्ड प्रक्रिया द्वारा) माउटिंग्स एवं फाइनडिंग्स	2.5 %	3.2 %
घ)	एक पूर्ण रूप से मैकेनाईज्ड और गैर जड़ित प्रक्रिया द्वारा विनिर्मित कोई आभूषण/वस्तुएं	0.9 %	0.9 %
ङ.)	जड़ित आभूषण में प्रयुक्त माउटिंग्स, चाहे आयातित अथवा स्वदेशी रूप से प्राप्त/विनिर्मित हों	1.8 %	1.8 %
च)	सोने/चाँदी/प्लेटिनम के पदक और सिक्के (वैध मुद्रा प्रकार के सिक्कों को छोड़कर)	0.2 %	0.2 %
छ)	मैकेनाईज्ड प्रक्रिया द्वारा विनिर्मित फाइनडिंग्स और माउनटिंग्स	0.9 %	0.9 %

4.61 मूल्य संवर्धन

आभूषण निर्यात स्कीम के तहत मूल्य संवर्धन का परिकलन विदेश व्यापार नीति के पैरा 4.38 के अनुसार किया जाएगा। न्यूनतम मूल्य संवर्धन निम्नानुसार होगा:

क्रम सं.	निर्यात की मदें	न्यूनतम मूल्यवर्धन
क)	सामान्य स्वर्ण/प्लेटिनम/चाँदी के आभूषण, संबंधित वस्तुएं और आभूषण जैसे मंगलसूत्र जिसमें जड़ित स्वरूप के आभूषण को छोड़कर सोने और काले मनके/बनावटी नगीने हों	3.5 %
ख)	जड़ित सोने/प्लेटिनम/चाँदी के सभी प्रकार के आभूषण और तत्संबंधी वस्तुएं	6.0% (रंगीन रत्न नगीनों के साथ जड़ित के लिए) और 7.0% (हीरों के साथ जड़ित के लिए)
ग)	एक पूर्ण रूप से मैकेनाईज्ड प्रक्रिया से विनिर्मित कोई आभूषण/वस्तुएं	2.0 %
घ)	सोने/चाँदी/प्लेटिनम के पदक और सिक्के (वैध मुद्रा प्रकार के सिक्कों को छोड़कर)	1.5 %
ड.)	मैकेनाईज्ड प्रक्रिया द्वारा विनिर्मित सोने/चाँदी/प्लेटिनम के फाइनडिंग्स/माउन्टिंग्स	2.5 %

4.62 हकदारी

इन धातुओं से बनायी गई वस्तुओं के निर्यात के प्रति स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम की मात्रा की हकदारी में अनुमत छीजन/विनिर्माण क्षति सहित निर्यात की मद में स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम की मात्रा होगी। जड़ित आभूषण के मामले में कीमती धातु की मात्रा का आकलन जुड़ाव के भार को घटाकर किया जाएगा।

4.63 पारगमन में रत्न और आभूषण खो जाना

देश के बाहर निर्यातित रत्न और आभूषण मदों की खेप, जो निर्यात के बाद रास्ते में खो गए हैं तथा ऐसे निर्यातों के लिए जहाँ विदेशी मुद्रा प्राप्त हो चुकी हो अथवा बीमा दावा कर लिया गया हो, वे भी पुनःपूर्ति प्राधिकार पत्र के पात्र होंगे।

4.64 रत्न और आभूषण पुनः पूर्ति प्राधिकार पत्र

(क) रत्न पुनःपूर्ति प्राधिकार पत्र, रत्न एवं आभूषण उत्पादों के निर्यात में प्रयुक्त बहुमूल्य पत्थरों, अर्ध-बहुमूल्य तथा सिन्थेटिक पत्थरों और मोतियों के आयात के लिए वैध होगा। इसके साथ-साथ यह प्राधिकार पत्र समग्र लागत बीमा भाड़ा मूल्य के भीतर प्राधिकार पत्र के मूल्य के 5% तक आभूषणों के खाली बक्सों के आयात के लिए भी वैध होगा। जड़ित स्वर्ण/चाँदी/ प्लेटिनम आभूषणों/वस्तुओं के निर्यात के प्रति जारी रत्न पुनःपूर्ति प्राधिकार पत्र, समग्र लागत बीमा भाड़ा मूल्य के भीतर प्राधिकार पत्र के लागत बीमा भाड़ा मूल्य के 10 प्रतिशत तक के पन्ना के अतिरिक्त कट और पालिश किए गए बहुमूल्य/अर्ध बहुमूल्य पत्थरों के आयात के लिए भी वैध होगा।

(ख) रत्न पुनःपूर्ति प्राधिकार पत्र परिशिष्ट-4च में निर्धारित पुनःपूर्ति दर के अनुसार जारी किया जाएगा तथा जड़े हुए आभूषण के मामले में शेष एफओबी मूल्य संबंधी पुनःपूर्ति का मानदंड परिशिष्ट-4छ के अनुसार होगा।

4.65 अभिकरण कमीशन

स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम आभूषणस्कीम का लाभ लेने वाले निर्यातक को आरबीआई द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अधीन अभिकरण कमीशन देने की अनुमति है। मूल्य संवर्धन का परिकलन अभिकरण कमीशन को घटा कर किया जाएगा।

4.66 पोतलदान बिल और बीजक पर पृष्ठांकन

आभूषणों के निर्यात के समय, सीमाशुल्क प्राधिकारियों को प्रस्तुत किए गए पोतलदान बिल और बीजक में मद का विवरण, इसकी शुद्धता, स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम अंश का भार, इस पर दावा किए गए छीजन, स्वर्ण/चाँदी/ प्लेटिनम अंश का कुल भार तथा दावा किए गए छीजन तथा स्वर्ण/चाँदी के लिए 0.995/0.999 शुद्धता और प्लेटिनम के लिए 0.9999 शुद्धता में इसकी समकक्ष मात्रा तथा इसका मूल्य, निर्यात का एफ ओ बी मूल्य, प्राप्त मूल्य परिवर्धन के ब्यौरे होने चाहिए। निर्यात के लिए इन प्रत्येक धातुओं से

निर्मित सभी या कुछ मर्दों के संबंध में इस्तेमाल किए गए स्वर्ण/ चाँदी/प्लेटिनम की शुद्धता यदि वही है तो निर्यातक को स्वर्ण/ चाँदी/ प्लेटिनम का कुल भार और ऐसी ही मर्दों, जिनकी शुद्धता वही है, के अन्य ब्यौरे भी देने होंगे। जड़ित मर्दों के मामलों में, पोतलदान बिल में विनिर्माण में इस्तेमाल किए गए बहुमूल्य/अर्ध बहुमूल्य पत्थरों/हीरों/मोतियों का भार और मूल्य तथा स्वर्ण/चाँदी के मिश्रण में इस्तेमाल की गई किसी अन्य बहुमूल्य धातु का भार/मूल्य के ब्यौरे भी होने चाहिए।

4.67 निर्यात की शर्तें

सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा निर्यात की अनुमति दी जाएगी बशर्ते कि पोतलदान बिल और बीजक में पृष्ठांकन ठीक से किया गया हो तथा प्राप्त किया गया मूल्य संवर्धन विदेश व्यापार नीति में निर्धारित मूल्य संवर्धन से कम न हो।

4.68 निर्यात का प्रमाण

(क) निर्यातक को जहां कहीं अपेक्षित हो, निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करके

स्वर्ण/ चाँदी/प्लेटिनम आभूषणों और इसकी वस्तुओं के निर्यात का प्रमाण देना होगा :-

(i) पोतलदान बिल की ई पी प्रति,

(ii) जीएसटी नियमावली के तहत यथा निर्धारित निर्यात/आपूर्तियों के लिए सीमाशुल्क प्राधिकारी द्वारा सत्यापित कर बीजक,

(iii) परिशिष्ट 2प में दिए गए प्रपत्र में वसूली का बैंक प्रमाण पत्र/ई-बीआरसी

(ख) विदेशी क्रेता द्वारा आभूषणों के व्यक्तिगत सामान के मामले में निर्यात हकदारियों का दावा करने के लिए निर्यात के सबूत के तौर पर निर्यातक/विक्रेता को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे:-

(i) भारतीय विक्रेता द्वारा प्रस्तुत किए गए पोतलदान बिल की प्रति

(ii) विदेशी क्रेता के आगमन के समय सीमाशुल्क कार्यालय को उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए मुद्रा घौणा प्रपत्र की एक प्रति ; और

(iii) बैंक से विदेशी मुद्रा नकदी प्रमाणपत्र।

(ग) इसके अलावा, स्वीकृति के प्रति दस्तावेज (डी ए)/सुपुर्दगी पर नकद (सीओडी) आधार पर व्यक्तिगत सामान की भी अनुमति है। निर्यात हकदारी का दावा करने हेतु निर्यातक को निर्यात के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित कागजात प्रस्तुत करने होंगे:

(i) भारतीय विक्रेता द्वारा प्रस्तुत किए गए पोतलदान बिल की प्रति; और

(ii) निर्यात और विदेशी मुद्रा प्राप्ति का बैंक प्रमाणपत्र/ई-बीआरसी

(घ) इस संबंध में सीमाशुल्क विभाग द्वारा जारी निर्देशों का आवश्यक परिवर्तनों सहित अनुपालन किया जाना चाहिए।

4.69 शुद्धता/परिशुद्धता का परिवर्तन

परिशुद्धता के स्तर में समतुल्य मात्रा के अनुसार स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम की मात्रा के परिवर्तन के लिए निम्नलिखित फार्मूला अपनाया जाएगा :-

(i) जहां स्वर्ण वस्तुओं का कैरेट में निर्यात किया गया है, वहाँ स्वर्ण की मात्रा को निर्यातित स्वर्ण के कैरेट की संख्या से गुणा, 24 से भाग किया जाएगा और इसके बाद पुनः 0.995/ 0.999/0.900 से भाग किया जाएगा ताकि क्रमशः 0.995/ 0.999/0.900 की परिशुद्धता के स्तर में स्वर्ण की समकक्ष मात्रा तक पहुँचा जा सके, और

(ii) जहां कहीं निर्यात की वस्तु की शुद्धता, परिशुद्धता के स्तर में व्यक्त की गई है, वहां स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम की मात्रा को निर्यातित स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम की परिशुद्धता द्वारा गुणा किया जाएगा और इसके पश्चात 0.995/0.999/0.900 से भाग किया जाएगा ताकि स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम की क्रमशः 0.995/ 0.999/0.900 परिशुद्धता की बराबर मात्रा तक पहुँचा जा सके।

4.70 नामित अभिकरणों द्वारा स्वर्ण/चाँदी/ प्लेटिनम जारी करना।

नामित अभिकरणों/भारतीय रिजर्व बैंक के प्राधिकृत बैंकों द्वारा आभूषणों के निर्यातक को स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम केवल 10 ग्राम या स्वर्ण के संबंध में दस तोला छड़ों के गुणकों में जारी किया जाएगा। तथापि, निर्यातकों को चाँदी केवल 1 किग्रा गुणकों में जारी की जाएगी। स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम का कोई भी शै, निर्यातक को उसकी भावी हकदारी सहित उपलब्ध रहेगा। नामित अभिकरणों द्वारा स्वर्ण/चाँदी 0.995 परिशुद्धता में और प्लेटिनम 0.900 या इससे अधिक परिशुद्धता में जारी की जाएगी।

4.71 भुगतान की शर्तें

स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम आभूषणों और इसकी वस्तुओं का निर्यात अपरिवर्तनीय साख-पत्र के अधीन, सुपुर्दगी पर नकद भुगतान के आधार पर, स्वीकृति के प्रति दस्तावेज (डीए) आधार पर या विदेशी मुद्रा में अग्रिम भुगतान अथवा निर्यातित आभूषण/वस्तुओं में स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम अंश की प्रतिपूर्ति के आधार पर होगा।

4.72 निर्यात का पत्तन

स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम आभूषणों और इसकी वस्तुओं संबंधी स्कीमों के अधीन निर्यात की अनुमति मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, जयपुर, बंगलौर, कोच्चि, कोयम्बटूर, अहमदाबाद, डेबोलिन एअरपोर्ट, गोवा, हैदराबाद और सूरत (सूरत हीरा बोर्स) स्थित सीमाशुल्क सदनों के जरिए वायु भाड़े और विदेशी डाकघर द्वारा दी जाएगी। प्रति खेप 20 लाख रुपए मूल्य के पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य तक मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, कोच्चि, कोयम्बटूर, दिल्ली, जयपुर, बंगलौर, अहमदाबाद और हैदराबाद स्थित सीमा-शुल्क सदनों के माध्यम से कूरियर द्वारा भी निर्यात अनुमत होगा।

4.73 डाक द्वारा निर्यात

डाक द्वारा रत्न और आभूषण पार्सल के निर्यात की नीति विदेश व्यापार नीति के पैरा 4.48 दी गयी है। निर्यात के समय, निर्यातक को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे :-

- (i) विदेशी डाकघर में प्रस्तुत किया गया जीएसटी नियमावली के तहत यथा निर्धारित निर्यात/आपूर्तियों के लिए पोतलदान बिल या कर बीजक,
- (ii) नामित अभिकरणों से प्रमाण पत्र जिसमें वह मूल्य दर्शाया गया हो जिस पर स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम बुक किया गया था या तुरन्त बिक्री आधार पर या ऋण के आधार पर दिया गया था।
- (iii) जीएसटी नियमावली के तहत यथा निर्धारित निर्यात/आपूर्तियों के लिए कर बीजक की तीन प्रतियाँ।

4.74 प्रमाणन/ग्रेडिंग और पुनःआयात हेतु कटिंग और पॉलिश किए गए हीरों का निर्यात

0.25 और इससे अधिक कैरेट के हीरों के प्रमाणन/ग्रेडिंग के लिए निम्नलिखित अधिकृत प्रयोगशालाएं हैं:

- (1) इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट (आईजी)-हाँगकाँग।
- (2) अमेरिकन जेम सोसाइटी लैबोरेट्रीज (एजीएस लैबोरेट्रीज), 8917 वेस्ट सहारा एवेन्यू, लास वेगास, नीवाडा 89117;
- (3) सेंट्रल जेम लैबोरेटरी मियागी बिल्डिंग, 5-15-14 यूनो टेटोकू, टोक्यो, जापान;
- (4) डायमण्ड ट्रेडिंग कम्पनी, मेडनहेड, यूके;
- (5) यूरोपीयन जेमोलॉजिकल लैबोरेटरी (ईजीएल), यूएसए;
- (6) जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका (जीआईए), यूएसए;
- (7) होज रोड वुअर डायमण्ड, एंटवर्प, (एचआरडी);
- (8) इंटरनेशनल डायमण्ड लैबोरेट्रीज डीएमसीसी, दुबई;
- (9) द रॉबर्ट मुआवैड कैम्पस, इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट (आईजीआई) यूएसए;
- (10) वर्ल्ड डायमण्ड सेंटर ऑफ डायमण्ड्स हाई काउंसिल, एंटवर्प, बेल्जियम;
- (11) जीआईए हाँगकाँग लैबोरेटरी लि0, हाँगकाँग;
- (12) जेमोलॉजिकल रिसर्च (थाईलैंड) क0लि, बैंकॉक;
- (13) जीआईए एजुकेशन एंड लैबोरेटरी (प्रा0) लि0, जोहानेसबर्ग;
- (14) जीआईए एजुकेशन एंड लैबोरेटरी, गोबोरोन (बोत्सवाना);
- (15) फोरवरमार्क एनवी, एंटवर्प, बेल्जियम;
- (16) इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट (आईजी)-एंटवर्प, बेल्जियम;

4.75 प्रमाणन/ग्रेडिंग और पुनःनिर्यात के लिए हीरों का आयात

(क) विदेश व्यापार नीति के पैरा 4.42 में इस सुविधा का उल्लेख किया गया है। हीरों के आयात के समय प्रविष्टि बिल में हीरों का माप/विशिष्टियों सहित विस्तृत विवरण होगा। ग्रेडिंग/ प्रमाणन के बाद पुनःनिर्यात के समय, जहाँ तक हीरों के माप और अन्य विशिष्टियों/ब्यौरों का संबंध है, प्रविष्टि बिल का ब्यौरा पोत लदान बिल में पृष्ठांकित होना चाहिए, ताकि आयातित हीरों और पुनः निर्यात किए जाने वाले हीरों के मध्य एक स्पष्ट सहसंबंध स्थापित किया जा सके। इसके अतिरिक्त, पोत लदान के समय पोत लदान बिल सहित जी आई ए (अथवा किसी अन्य अनुमोदित एजेन्सी) के साथ एक अलग स्वप्रमाणित प्रमाणपत्र संलग्न करना होगा ताकि आयात को दस्तावेजों तथा जी आई ए (अथवा किसी अन्य अनुमोदित एजेन्सी) प्रमाणपत्र के अनुसार निर्यातों के बराबर किया जा सके।

(ख) ऐसे सभी मामलों में, जी आई ए (अथवा इस संबंध में अनुमोदित कोई अन्य एजेन्सी) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाई गई प्रक्रिया के अनुसार जी आर छूट प्राप्त करेगी।

(ग) आयातित हीरों का पुनःनिर्यात, आयात (आयातों) की तारीख से 3 माह की अधिकतम समयावधि के भीतर पूरा करना होगा। आयात के समय एजेन्सी इस बारे में सीमाशुल्क कार्यालय को वचनबद्धता प्रस्तुत करेगी। जीआईए (अथवा इस संबंध में अनुमोदित कोई अन्य एजेन्सी) आगामी तिमाही अवधि के अन्त में, माह की 25 तारीख तक, आयात के पत्तन पर, सीमाशुल्क प्राधिकारी को एक तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, ताकि निर्धारित समयावधि के भीतर निर्यात सुनिश्चित किया जा सके।

4.76 0.25 और इससे अधिक कैरेट के हीरों के प्रमाणन/ग्रेडिंग के लिए प्रयोगशालाओं का सूचीकरण/प्राधिकार-पत्र

प्रयोगशालाओं के सूचीकरण हेतु आवेदन निर्धारित मानकों को पूरा करने के लिए आवेदन की जांच करने हेतु रत्न और आभूषण संवर्धन परिषद् (जीजेईपीसी) के पास प्रस्तुत किए जाने चाहिए। जीजेईपीसी प्रामाणिक आवेदकों के सत्यापन के पश्चात् अपनी स्पष्ट सिफारिश के डीजीएफटी के सैद्धान्तिक रूप से अनुमोदन के लिए आवेदन अग्रेषित करेगा। डीजीएफटी द्वारा सैद्धान्तिक रूप से अनुमोदन के पश्चात् जीजेईपीसी प्रयोगशाला के लिए अपेक्षित उपकरणों, तकनीकी मानव शक्ति और अन्य अवसंरचना की उपलब्धता के सत्यापन हेतु सुविधा का निरीक्षण करेगा जिससे कि यह 0.25 और इससे अधिक कैरेट के हीरों के प्रमाणन/ग्रेडिंग के लिए अधिकृत प्रयोगशाला के रूप में कार्य कर सके। जीजेईपीसी की निरीक्षण रिपोर्ट और सिफारिशों के आधार पर संबंधित प्रयोगशाला को एफटीपी के पैरा 4.42, अथवा 4.43, जैसा भी मामला हो, में शामिल करने हेतु विचार किया जाएगा।

4.77 विदेशी क्रेता द्वारा आपूर्तियों के मद्दे निर्यात

(क) विदेशी क्रेता द्वारा की गई आपूर्ति के प्रत्येक आयात खेप की निकासी से पहले, नामित अभिकरण/स्तर धारक, जिसके पास नामित एजेंसी प्रमाणपत्र हो/ **पात्र निर्यातक**, इस आशय का एक बॉण्ड सीमाशुल्क प्राधिकारी के पास निष्पादित करेगा कि वह करार में निर्धारित अवधि के भीतर ग्राह्य अपशिष्ट को छोड़कर स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम, माउंटिंग और फाईंडिंग आदि के सम्पूर्ण आयात के बराबर स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम के आभूषणों या वस्तुओं का निर्यात करेगा।

(ख) स्तर धारक/निर्यातक को सोना/चाँदी/प्लेटिनम, मिश्रधातु, सोना/चाँदी/प्लेटिनम की फाईंडिंग्स और माउंटिंग्स और सादा अर्द्ध निर्मित सोना/चाँदी/प्लेटिनम आभूषणों की प्रत्यक्ष आपूर्ति के मामले में, स्तरधारक/निर्यातक आयातित सोना/चाँदी/प्लेटिनम, मिश्रधातु, सोना/चाँदी/प्लेटिनम की फाईंडिंग्स और माउंटिंग्स और सादा अर्द्ध निर्मित सोना/चाँदी/प्लेटिनम आभूषणों आदि पर लगने वाले मूल सीमा शुल्क के नियम और विनियमनों के अनुसार बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता, सीमा शुल्क विभाग के पास जमा करानी होगी। सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम की धारा 3(7) और 3(9) के तहत लगने वाले एकीकृत माल और सेवा कर और मुआवजा उपकर आयात पर अलग से देय होगा।

(ग) सीमा शुल्क विभाग के पास निष्पादित बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता एक वर्ष की अवधि के लिए वैध होगी। स्तर-धारक/निर्यातक को प्रत्यक्ष आपूर्ति के संबंध में, निर्यात 90 दिनों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। निर्यात दायित्व को पूरा न करने/निर्धारित मूल्य संवर्धन प्राप्त न करने की स्थिति में सीमा शुल्क प्राधिकारी, राजस्व विभाग द्वारा यथा अधिसूचित, सीमा शुल्क और ब्याज की वसूली कर सकता है जिसमें बैंक गारंटी/ विधिक वचनबद्धता को लागू करना भी सम्मिलित है। इसके अलावा, आयातक सीमा शुल्क अधिनियम के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई का भी भागी हो सकता है।

4.78 निर्यात प्रक्रिया/सीमाशुल्क का भुगतान

(क) नामित अभिकरण/स्तर धारक जिसके पास नामित एजेंसी प्रमाण पत्र हो/निर्यातक को उस मात्रा पर लगने वाला सीमाशुल्क देना होगा जिसके बारे में यह साबित हो गया है कि निर्यात नहीं किया गया है।

(ख) सीमाशुल्क प्राधिकारी के जरिए नामित अभिकरण/स्तर धारक जिसके पास नामित एजेंसी प्रमाण पत्र हो/ निर्यातक द्वारा माल की निकासी की जाएगी। उन मामलों में भी जहाँ सहायक कम्पनियों द्वारा निर्यात आदेश प्राप्त किया गया है, नामित अभिकरण द्वारा सीमाशुल्क विभाग के जरिए ही माल निकासी करायी जाएगी, न कि सहायक द्वारा। ऐसे मामलों में, सहायक

कम्पनी, नामित अभिकरण को प्रविष्टि का बिल और पोतलदान बिल प्रस्तुत करने के लिए अपने एजेंट के रूप में प्राधिकृत करेगी।

(ग) निर्यात के समय, सीमाशुल्क प्राधिकारी को प्रस्तुत किए गए पोतलदान बिल में निम्नलिखित ब्यौरे भी होने चाहिए :-

(i) सहायक/स्तर धारक जिसके पास नामित एजेंसी प्रमाण पत्र हो/निर्यातक का नाम और पता;

(ii) नामित एजेन्सी/स्तर धारक, जिसके पास नामित एजेंसी प्रमाण पत्र हो, द्वारा स्वीकृति पत्र कि सम्बद्ध सहायक कम्पनी द्वारा प्राप्त आदेश के मद्दे निर्यात किया गया है, नामित एजेन्सी के पास इसके पंजीकरण की तिथि। स्तर धारक, जिसके पास नामित एजेंसी प्रमाण पत्र हो/ निर्यातक द्वारा निर्यातों के मामले में, इस संबंध में स्व घोषणापत्र दिया जाएगा;

(iii) सीमाशुल्क सदन का नाम जिसके माध्यम से सोना/चाँदी/प्लेटिनम/सादा अर्द्ध-निर्मित सोना/ चाँदी/प्लेटिनम आभूषण का आयात किया गया है और प्रविष्टि बिल संख्या एवं तारीख तथा आयात की तारीख।

(घ) प्रत्येक पोतलदान बिल निर्यात हेतु केवल उस सीमा शुल्क सदन के माध्यम से वैध होगा जहाँ संबंधित नामित अभिकरण/स्तरधारक, जिसके पास नामित एजेंसी प्रमाण पत्र हो/निर्यातक का कार्यालय स्थित है। यदि निर्यात नामित अभिकरण के जरिए किया गया है तो यह पोत लदान हेतु 7 दिन की अवधि के लिए वैध होगा जिसमें वह तारीख भी शामिल है जिस दिन नामित अभिकरण द्वारा पृष्ठांकन किया गया था । यदि निर्यात इस समयावधि में नहीं किया जाता है, तो निर्यातक एक नया पोत लदान बिल दाखिल करेगा।

(ङ.) निर्यात के समय निर्यातक निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा:-

(i) सीमाशुल्क सदन जिसके माध्यम से स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम/ सादा अर्द्ध-निर्मित सोना/चाँदी/ प्लेटिनम आभूषण का तदनुस्र आयात हुआ है, को छोड़कर सीमाशुल्क सदन जहाँ निर्यात किया गया है, के पोतलदान बिल की दो अतिरिक्त प्रतियों सहित। अन्य मामलों में, पोतलदान बिल की एक अतिरिक्त प्रति;

(ii) माल और सेवा कर नियमों के तहत यथा निर्धारित निर्यात/आपूर्तियों के लिए कर बीजक की तीन प्रतियाँ;

(iii) विदेशी खरीदारों द्वारा भेजी गई मदों की मात्रा और मूल्य को इंगित करने वाला नामित एजेन्सी का प्रमाण पत्र।

(च) सीमाशुल्क प्राधिकरण पोतलदान बिल और सम्बद्ध बीजक की विधिवत सत्यापित दो प्रतियाँ वापिस लौटाएगा । एक प्रति उस व्यक्ति को भेजी जाएगी जिसने दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं और दूसरी प्रति सीमाशुल्क प्राधिकरण द्वारा नामित एजेन्सी/स्तर धारक/ निर्यातक के कार्यालय को भेजी जाएगी ।

(छ) नामित अभिकरण के जरिए निर्यात के मामले में निर्यातक, निर्यात की तिथि से 15 दिन के भीतर उस नामित एजेन्सी को जिसने निर्यात किया है, को निर्यात का प्रमाण प्रस्तुत करेगा जो दस्तावेजों की जाँच करने के पश्चात निर्यातक को स्वर्ण/ चाँदी/प्लेटिनम इत्यादि की अनुमत मात्रा जारी करेगा ।

(ज) उन मदों की अन्तरराष्ट्रीय कीमत में उन पर लगने वाले सीमाशुल्क को जोड़कर उसके बराबर राशि की बैंक गारंटी/विधिक बचनबद्धता प्रस्तुत करके निर्यातक अग्रिम रूप से विदेशी क्रेता द्वारा आपूर्तित स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम इत्यादि को प्राप्त कर सकते हैं । सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम की धारा 3(7) और 3(9) के तहत लगने वाला एकीकृत माल और सेवा कर और मुआवजा उपकर आयात पर अलग से देय होगा। बैंक गारन्टी/विधिक वचनबद्धता की राशि तभी वापिस की जाएगी जब निर्यातक नामित एजेन्सी को निर्यात का सबूत प्रस्तुत करेगा तथा निर्यात उत्पाद में मदों की अग्रिम आपूर्ति के उपयोग को ध्यान में रखा जाएगा।

(झ) सीमाशुल्क कार्यालय के पास निष्पादित बाँड/बैंक गारन्टी/विधिक बचन बद्धता को छुड़ाने के लिए नामित अभिकरण/स्तर धारक, जिसके पास नामित एजेंसी प्रमाण पत्र हो/निर्यातक, विदेशी खरीदार द्वारा आपूर्तित मदों की मात्रा और मूल्य, तदनुस्र आगम बिल संख्या और तिथि, तदनुस्र किए गए निर्यात संबंधी प्रत्येक शिपिंग बिल की संख्या के ब्यौरे प्रस्तुत करेगा।

4.79 खातों का रखरखाव

नामित अभिकरण/स्तर धारक, जिसके पास नामित एजेंसी प्रमाण पत्र हो, प्रत्येक निर्यात आदेश के निष्पादन के लिए आयातित सोना, चाँदी, प्लैटिनम, माउटिंग्स, फाइंडिंग्स, सादा अर्द्ध निर्मित सोना/चाँदी/प्लेटिनम आभूषण इत्यादि, किए गए निर्यात और ऐसे निर्यात के लिए जारी सोना/चाँदी/प्लैटिनम, माउटिंग्स, फाइंडिंग्स इत्यादि का प्रेषण वार पूर्ण लेखा-जोखा रखेगा। इस लेखा जोखा का रख-रखाव निर्यात की तिथि से कम से कम तीन वर्ष की अवधि के लिए रखा जाएगा।

4.80 प्रदर्शनियों के जरिए निर्यात/निर्यात संवर्धन दौरे/ब्राण्डेड आभूषण के निर्यात

(क) नामित अभिकरण सीमाशुल्क प्राधिकारी के पत्र की मूल प्रति या इसकी प्रमाणित प्रतिलिपि जिसमें प्रदर्शनी लगाने/ब्राण्डेड आभूषण के निर्यात के लिए सरकारी अनुमोदन हो, प्रस्तुत करेगा । अन्य कोई व्यक्ति सहायक सीमाशुल्क आयुक्त को पत्र की मूल

प्रति या इसकी प्रमाणित प्रतिलिपि जिसमें प्रदर्शनी लगाने/निर्यात संवर्धन दौरे/ब्रान्डेड आभूषण के निर्यात के लिए विनिर्दिष्ट जी जे ई पी सी के अनुमोदन हो, प्रस्तुत करेगा।

(ख) पुनः आयात के मामले में, ऐसी मदों के पहुँचने पर निकासी से पहले निर्यात दस्तावेजों के साथ जाँच की जाएगी।

(ग) निर्यात के निम्नलिखित तरीकों के लिए इस योजना के अन्तर्गत निर्यात निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:-

(i) विदेशी प्रदर्शनी में आयोजित/भाग लेने के लिए रत्नों और आभूषणों का निर्यात।

(क) विदेशों में न बेची गई मदों का प्रदर्शनी के बन्द होने के 60 दिनों के भीतर पुनः आयात किया जाएगा। तथापि यदि निर्यातक पहली प्रदर्शनी के बन्द होने के 45 दिनों के भीतर एक से अधिक प्रदर्शनी में भाग ले रहा है तो दूसरी प्रदर्शनी के बन्द होने की तारीख से 60 दिन गिने जाएंगे। यदि प्रदर्शनी संयुक्त राज्य अमेरिका में होगी, तो ऊपर उल्लिखित समयावधि 60 दिनों के स्थान पर 90 दिन की होगी। विदेश की प्रदर्शनी में आयोजन/भाग लेने के लिए रत्न और आभूषण के व्यक्तिगत सामान के मामले में, ऐसे रत्न और आभूषण का मूल्य 5 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक नहीं होगा। ऐसी प्रदर्शनियों में बेची गई मदों पर सोना/चाँदी/प्लेटिनम अंश पुनःपूर्ति के रूप में आयात किए जा सकते हैं।

(ख) निर्यातक को प्रदर्शनी में विदेश में बेचे गए माल के पुनःपूर्ति अंश के प्रयोजन के लिए सोना/चाँदी/प्लेटिनम प्रदर्शनी के बन्द होने की तारीख से 120 दिनों के भीतर नामित एजेंसी से पुनःपूर्ति ले सकता है।

(घ) विदेशों के निर्यात संवर्धन दौरे/छायाचित्र प्रदर्शनियों/फैशन प्रदर्शनी हेतु वायु भाड़े/पोस्ट पार्सल मार्ग के जरिए रत्न और आभूषणों को व्यक्तिगत रूप से ले जाना या निर्यात

एक मिलियन अमरीकी डालर तक सोना/चाँदी/प्लेटिनम आभूषण, कटे और पॉलिशड हीरे, कीमती, अर्द्ध-कीमती पत्थर, मोती और नमूनों को व्यक्तिगत रूप से ले जाना/वायु भाड़े/पोस्ट पार्सल मार्ग के जरिए निर्यात के रूप में वस्तुएँ निर्यात संवर्धन दौरे/फोटो प्रदर्शनी/फैशन प्रदर्शनी और अस्थायी डिस्पले/विदेश में बिक्री के लिए भी रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद् के अनुमोदन के साथ अनुमति है बशर्ते कि प्रमोटर सामान्य बैंकिंग चैनल के जरिए प्रस्थान की तारीख से 45 दिनों के भीतर आभूषण/सामान या बिक्री से प्राप्त आय को वापिस लाएगा। निर्यात संवर्धन दौरे के लिए व्यक्तिगत सामान के मामले में, निर्यातक, देश को छोड़ते समय सीमाशुल्क प्राधिकारी को ऐसे नमूनों को व्यक्तिगत सामान के रूप में घोषित करेगा और सीमाशुल्क के आभूषण मूल्यांकन कर्ता द्वारा जारी निर्यात प्रमाणपत्र पर आवश्यक पृष्ठांकन प्राप्त करेगा। ऐसे मामलों में, निर्यातक निर्यात संवर्धन दौरे के बाद 120 दिनों के भीतर या 45 दिनों की निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद, जो भी पहले हो, सोना/चाँदी/प्लेटिनम विदेश में बेची गई मदों के प्रति पुनःपूर्ति अंश के प्रयोजन के लिए नामित एजेंसी के साथ बुक करेगा।

(ड) **ब्रान्डेड आभूषण का निर्यात**

(i) ब्रान्डेड आभूषण का निर्यात भी विदेशों में स्थापित अनुमत दुकानों या उनके वितरकों/एजेन्टों के शोरूम में डिस्प्ले/बिक्री के लिए रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद् के अनुमोदन से अनुमत है। 365 दिनों के भीतर विदेश में न बेची गई मदें पुनः आयात की जाएंगी। विदेशों में बेची गई मदों के प्रति पुनःपूर्ति अंश के उद्देश्य हेतु स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम को 365 दिनों की निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद निर्यातक 120 दिनों के भीतर नामित एजेंसी को बुक करेगा।

(ii) ऐसी पुनःपूर्ति के दावे के लिए निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएंगे:

(i) सीमाशुल्क कार्यालय द्वारा सत्यापित बीजक;

(ii) सरकार/जीजेईपीसी द्वारा जारी अनुमोदन पत्र की प्रति।

(iii) परिशिष्ट-4ण में दिए गए नामित अभिकरण/जी जे ई पी सी से प्रमाणपत्र।

नामित अभिकरणों द्वारा आयोजित प्रदर्शनियों के मामले में, नामित अभिकरणों द्वारा प्रदर्शनी समाप्त होने की तारीख से 60 दिन के भीतर पुनःपूर्ति के रूप में स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम का आयात किया जाएगा।

(च) नामित अभिकरण किए गए निर्यात, विदेश में बेची गई वस्तुओं, वस्तुओं के पुनः आयात और विदेश में खरीदी गई और भारत में आयातित धातुओं का पूरा लेखा-जोखा रखेगा। ऐसा लेखा जोखा प्रदर्शनी समाप्त होने की तारीख से कम से कम 3 वर्ष की अवधि के लिए रखा जाएगा।

4.81 नामित अभिकरणों द्वारा आपूर्ति के तहत निर्यात

निर्यातक निम्नलिखित आधार पर स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम को प्राप्त कर सकता है :-

- (i) निर्यात पूरा करने के पश्चात पुनःपूर्ति के आधार पर,
- (ii) अग्रिम स्म से तत्काल खरीद आधार पर,
- (iii) ऋण आधार पर।

4.82 पुनःपूर्ति आधार

(क) निर्यातक बहुमूल्य धातु स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम की बुकिंग के लिए नामित अभिकरण/स्तर धारक, जिसके पास नामित एजेंसी प्रमाणपत्र हो, को आवेदन कर सकता है। नामित अभिकरण के पास बुक बहुमूल्य धातु की मात्रा निर्यात उत्पाद में बहुमूल्य धातु के अंश और स्वीकार्य अपशिष्ट के बराबर होनी चाहिए।

(ख) आवेदक बुकिंग के समय बहुमूल्य धातु के अनुमानित मूल्य का कम से कम 20% बयाना राशि जमा करेगा जिसे वास्तविक बिक्री के समय समायोजित कर लिया जाएगा।

(ग) बैंक द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रमाण पत्र के आधार पर निर्यातक, आभूषण अनुमान आधार पर निर्यात करेंगे। निर्यातक क्रेता के क्रेडिट शर्तों के अन्दर मूल्य निर्धारित करेगा तथा उसकी आय नियत समय अथवा 180 दिन, जो भी पहले हो, प्राप्त करे। निर्यातक जो प्रतिपूर्ति स्कीम के अन्तर्गत अनुमान आधार पर निर्यात कर रहे हैं, वो उसी दर पर तथा उसी मात्रा के बराबर नामित एजेंसी से सोना बुक कर सकते हैं जो उन्होंने क्रेता के साथ बुक किया है। नामित अभिकरण निर्यातक की ओर से निर्धारित दर पर बहुमूल्य धातु खरीदेंगे और इसके पश्चात निर्यातक क्रम संख्या वाला एक खरीद प्रमाण पत्र जारी करेंगे जिसमें स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम की मात्रा तथा लागत बीमा भाड़ा मूल्य डालर में निर्दिष्ट होगा, साथ ही रुपये में भी मूल्य दर्शाया जाएगा। मूल्य वह वास्तविक मूल्य होगा जिस पर नामित अभिकरणों द्वारा स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम खरीदा गया है और इसमें नामित अभिकरणों द्वारा मूल्य परिवर्धन के प्रयोजन के लिए स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम के मूल्य पर लगाया गया अनुमत सेवा प्रभार शामिल होगा। नामित एजेंसियों द्वारा निर्यातक हेतु क्रय प्रमाणपत्र की प्रतियों सहित निर्यातक के आवेदन की दूसरी और तीसरी प्रतियाँ संबंधित सीमाशुल्क सदन को तथा लेन देन करने वाली बैंक को भेजी जाएंगी जो सोने के क्रय की पुष्टि करेगी। निर्यातक जो अनुमानित दर पर निर्यात कर रहे हैं वे पुनःपूर्ति तभी लेंगे जब आय प्राप्त हो जाएगी।

(घ) बुकिंग की तारीख से 120 दिन की अवधि के भीतर निर्यात किया जाएगा और बुकिंग की तारीख से 150 दिन की अवधि के भीतर या निर्यात की तारीख से 30 दिन के भीतर, जो भी बाद में हो, बहुमूल्य धातु को निकाला जाएगा।

4.83 अग्रिम स्म से पूर्णतया खरीद आधार पर

(क) निर्यातक पूर्णतया खरीद आधार पर अग्रिम तौर पर बहुमूल्य धातु की आवश्यक मात्रा प्राप्त कर सकता है बशर्ते कि नामित अभिकरण द्वारा निर्धारित राशि हेतु नामित अभिकरणों को बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता प्रस्तुत की गई हो। निर्धारित अवधि के भीतर निर्यात करने में असफल रहने पर नामित अभिकरण बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता, जैसा भी मामला हो, को लागू करेंगे।

(ख) बहुमूल्य धातु की पूर्णरूप से खरीद की तारीख से 90 दिन की अधिकतम अवधि के भीतर निर्यात किया जाएगा।

4.84 ऋण आधार पर

(क) निर्यातक ऋण आधार पर बहुमूल्य धातु की आवश्यक मात्रा प्राप्त कर सकता है बशर्ते नामित अभिकरण द्वारा निर्धारित राशि हेतु नामित अभिकरणों को सीमा शुल्क हेतु बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता प्रस्तुत की गई हो। सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम की धारा 3(7) और 3(9) के तहत लगाए जाने योग्य एकीकृत माल और सेवा कर तथा मुआवजा उपकर आयात पर अलग देय होगा। निर्धारित अवधि के भीतर निर्यात करने में असफल रहने पर नामित अभिकरण बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता को लागू करेंगे।

(ख) निर्यातक को ऋण के आधार पर लिए गए स्वर्ण पर यथानिर्दिष्ट दर से राजस्व विभाग द्वारा यथा अधिसूचित ब्याज देना होगा।

(ग) ऋण आधार पर प्राप्त सोने के रिलीज होने के 90 दिन के अधिकतम अवधि के अन्दर निर्यात पूर्ण करना है। निर्यात दायित्व की पूर्ति हेतु अवधि बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(घ) (i) निर्यातक को नामित अभिकरणों/रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (जीजेईपीसी) द्वारा जारी किए गए अनुमानित दर प्रमाणपत्र के आधार पर आभूषण निर्यात की स्वीकृति दी जाएगी। यह दर मौजूदा स्वर्ण/अमेरिकी डालर दर तथा अमेरिकी/भारतीय स्मया दर अनुमानित दर प्रमाण पत्र के आधार पर होगी। नामित एजेंसियों/जीजेईपीसी द्वारा जारी प्रमाण पत्र पोतलदान की तारीख से 7 कार्य दिवसों से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।

(ii) खरीदार और नामित अभिकरणों के साथ निर्धारित की गई दर पर मूल्य संवर्धन को प्राप्त करना होगा।

(iii) निर्यात की तिथि से 180 दिनों के अन्दर निर्यातकों को मूल्य निर्धारण करने और स्वर्ण ऋण की वापसी की छूट

होगी। इस मूल्य के बारे में नामजद अभिकरणों को सूचित किया जाएगा जो दस्तावेजों पर कार्रवाई करने वाले बैंकों को दर की अन्तिम पुष्टि दर्शाने वाला एक प्रमाण पत्र जारी करेगा ताकि इस दर पर निर्यात आय को सुनिश्चित किया जाएगा।

(ड.) नामित एजेन्सी निर्यातक के ईईएफसी खाते से बहुमूल्य धातु के आयात की लागत का डालर में भुगतान स्वीकार कर सकती है।

4.85 अग्रिम प्राधिकार पत्र के तहत निर्यात

(क) मूल्य संवर्धन मानदंड, निर्यात दायित्व अवधि और चूक के विनियमन को छोड़कर इस प्रक्रिया पुस्तक के अध्याय 4 के अधीन अग्रिम प्राधिकार पत्र के लिए लागू प्रक्रिया इस स्कीम हेतु भी लागू होगी। इस प्रक्रिया पुस्तक के पैराग्राफ 4.61 के अनुसार रत्न और आभूषण मर्दों का मूल्य संवर्धन होगा।

(ख) निर्यात दायित्व को प्राधिकार पत्र के तहत प्रत्येक खेप के आयात की तारीख से 120 दिन के भीतर पूरा करना होगा। तथापि, निर्यात दायित्व अवधि स्वर्ण, प्लेटिनम और चांदी के बने हुए फाइनिंग, माउंटिंग के आयात और आभूषणों के निर्यात होने की तारीख से 180 दिन के भीतर होगी। इसके पश्चात निर्यात दायित्व अवधि में वृद्धि की अनुमति नहीं होगी। अग्रिम प्राधिकार पत्र निर्यात पूरा होने के पश्चात पुनःपूर्ति के रूप में स्वर्ण का आयात कर सकता है।

(ग) अग्रिम प्राधिकार पत्र धारक सीधे आयात के बदले नामित अभिकरणों से स्वर्ण/चांदी/प्लेटिनम को प्राप्त कर सकता है। ऐसे मामले में, नामित अभिकरणों द्वारा स्वर्ण/चांदी/प्लेटिनम की आपूर्ति की तिथि से 90 दिनों के भीतर निर्यात दायित्व पूरा किया जाना आवश्यक होगा और नामित अभिकरण प्राधिकार पत्र की विनियमन नियंत्रण प्रति और सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति दोनों सीधे आयात के लिए अवैध कर देगा।

4.86 वास्तविक चूक का विनियमन

निर्यातक द्वारा निर्यात दायित्व को पूरा करने में वास्तविक चूक के मामलों में, उन बहुमूल्य धातुओं को जिन्हें उसने नामित अभिकरणों से प्राप्त किया है, को नियमित करेगा बशर्ते निर्यातक ने राजस्व विभाग द्वारा यथा अधिसूचित ब्याज सहित सीमाशुल्क का भुगतान किया हो। प्राधिकार धारक के पास विदेश व्यापार नीति के तहत जारी वैध शुल्क क्रेडिट स्क्रिप्ट प्रस्तुत करने का विकल्प होगा। ब्याज/दंडराशि का भुगतान नकद में करना होगा। अग्रिम प्राधिकार पत्र के मामले में, उपरोक्त पैराग्राफ 4.49 में दिए गए उपबन्ध लागू होंगे। यह किसी भी ऐसी कार्रवाई के पूर्वाग्रह के बिना होगा जो विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम तथा इसके अधीन जारी, समय-समय पर यथा संशोधित आदेश या नियमों के तहत निर्यातक के विरुद्ध की जा सकती है।

4.87 उपभोक्त्यों आदि के आयात हेतु प्रतिपूर्ति प्राधिकार पत्र

उपभोक्त्यों इत्यादि के आयात के लिए आवेदन पत्र, जैसाकि एफटीपी के पैरा 4.36 में दिया गया है, संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को आयात निर्यात प्रपत्र 4ज में ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

4.88 रत्नों और आभूषणों के निर्यात पार्सलों को व्यक्तिगत तौर पर ले जाना

(क) सभी ई ओ यू/एस ई जैड यूनिटों और दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, कोच्चि, कोयम्बटूर, बंगलौर, हैदराबाद, जयपुर के हवाई अड्डों के माध्यम से डी टी ए में स्थित सभी फर्मों से भी विदेश जाने वाले यात्रियों द्वारा रत्नों और आभूषणों के पार्सलों को व्यक्तिगत रूप से ले जाने की अनुमति है। निर्यात के व्यक्तिगत तौर पर ले जाने की प्रक्रिया सीमाशुल्क द्वारा निर्धारित होगी। तथापि, निर्यात आय को सामान्य बैंकिंग चैनल के जरिये प्राप्त किया जाएगा।

(ख) विदेश जाने वाले यात्री द्वारा निर्यात के व्यक्तिगत तौर पर ले जाने के मामले में पुनःपूर्ति दावे के लिए दस्तावेज वही होंगे जो ऊपर पैरा 4.82(ग) में दिये गये हैं। प्राधिकृत कुरियर कम्पनियाँ भी उपरोक्तानुसार काम कर सकती हैं।

4.89 रत्नों और आभूषणों के आयात पार्सलों को व्यक्तिगत तौर पर ले जाना

सभी ई ओ यू/एस ई जैड यूनिटों और दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई, बंगलौर, हैदराबाद और जयपुर के हवाई अड्डों के माध्यम से डी टी ए में स्थित सभी फर्मों से भी भारतीय आयातक/विदेशी नागरिक द्वारा रत्नों और आभूषणों के आयात पार्सल को व्यक्तिगत रूप से ले जाने की अनुमति है। इसकी प्रक्रिया हवाई भाड़े द्वारा माल के आयात के समान होगी लेकिन जाँच और रिलीज करने के लिए पार्सलों को आयातक/विदेशी नागरिक द्वारा सीमाशुल्क प्राधिकारी को सौंपा जाएगा। इस स्कीम के अन्तर्गत आयातों की निकासी सामान्य सीमाशुल्क निकासी पद्धति के अनुसार होगी।

4.90 नमूनों का शुल्क मुक्त आयात

रत्न और आभूषण मर्दों के विगत तीन वर्ष के निर्यात कारोबार के औसत के 0.25 प्रतिशत अथवा 3 लाख रुपए तक के रत्न और आभूषण के नमूनों का शुल्क मुक्त आयात, जो भी कम हो, सीमाशुल्क अधिसूचना की शर्तों के अनुसार एक वित्तीय वर्ष में अनुमत

होगा ।

4.91 अस्वीकृत आभूषणों का पुनः आयात

सादे/जड़ित बहुमूल्य पत्थर आभूषणों के निर्यातक को, पिछले लाइसंसिंग वर्ष (पिछले वर्ष के निर्यात की सनदी लेखाकार के प्रमाणित प्रति के आधार पर) में सीमाशुल्क नियमों और विनियमनों के अनुसार प्रयोग किए गए निवेशों पर प्राप्त किसी शुल्क छूट/वापसी/पुनःपूर्ति लाभ की वापसी के साथ, किए गए निर्यातों के पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य के 2 प्रतिशत तक, अस्वीकृत और खरीदार द्वारा लौटाए गए आभूषणके शुल्क मुक्त पुनः आयात की अनुमति होगी ।

4.92 हीरा और आभूषण डालर लेखा

हीरा और आभूषण डालर लेखा हेतु नीति का विदेश व्यापार नीति के पैरा 4.50 में उल्लेख किया गया है । इसके संचालन की प्रक्रिया का विस्तृत ब्यौरा अलग से अधिसूचित किया जाएगा।

4.93 खेप आधार पर हीरे, रत्न और आभूषण का निर्यात तथा आयात

(क) खेप आधार पर हीरे, रत्न और आभूषण के निर्यात के लिए नीति विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 4.53 में दी गई है।

(ख) इस संबंध में ब्यौरेवार प्रक्रिया संगत सीमा शुल्क नियमों और विनियमनों के द्वारा अभिशासित होगी। खेप आधार पर निर्यातित मर्दों (पूरे अथवा आंशिक मात्रा में) का पुनः आयात इस शर्त के अधीन होगा कि निर्यातक संगत सीमाशुल्क अधिसूचना के निर्धारित प्रावधानों का पालन करेगा ताकि यह स्थापित हो कि निर्यात किया गया माल वही है।

4.94 नामित एजेंसियों द्वारा कीमती धातु के आयात हेतु दिशानिर्देश/मॉनिटरिंग

नामित एजेंसियों द्वारा कीमती धातु के आयात संबंधी दिशा-निर्देश और मॉनिटरिंग इस प्रकार है:

(क) हटा दिया गया है।

(ख) बहुमूल्य धातु के आयात तथा इसके वितरण और/अथवा नामित अभिकरणों के द्वारा स्वप्रयोग की मॉनीटरिंग के लिए निम्नलिखित दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखा जाएगा (इस प्रयोजन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नामित निर्दिष्ट बैंकों से भिन्न):

(i) प्रत्येक नामित अभिकरणों द्वारा प्रक्रिया पुस्तक के परिशिष्ट 4ड में दिये गए प्रारूप के अनुसार घरेलू उपभोग के प्रयोजन हेतु और मूल्यवर्धित उत्पाद के निर्यात के लिए मूल्यवान धातु के आयात (मात्रा और मूल्य दोनों) और उसके वितरण के रिकार्ड की देखरेख करना अपेक्षित है। नामित अभिकरणों को आरबीआई और डीजीएफटी के द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों/नियमों/प्रक्रियाओं/निर्देशों का भी पालन करना होगा। वैयक्तिक सुनवाई के अवसर का में लाभ उठाने के बाद यथा संशोधित, विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम 1992, के तहत कार्रवाई के अलावा करने में असफल होने पर नामित अभिकरण प्रमाणपत्र रद्द किया जा सकता है।

(ii) रत्न एवं आभूषणनिर्यात संवर्धन परिसद द्वारा निगरानी:

नामित अभिकरणों एमएमटीसी लि., हस्तशिल्प और हथकरघा निर्यात निगम लि., राज्य व्यापार निगम लि, पीईसी लिमिटेड, एसटीसीएल लिमिटेड, एमएसटीसी लिमिटेड., डायमन्ड इंडिया लिमिटेड के संबंध में निगरानी रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिसद (जीएण्डजेईपीसी) के द्वारा होगी। नामित अभिकरण रत्न और आभूषण संवर्धन परिषद (जीजेईपीसी), मुम्बई को प्रत्येक छमाही के 15 दिन के भीतर, प्रक्रिया पुस्तक के परिशिष्ट 4ड में दिए गए प्रारूप के अनुसार अर्ध वार्षिक रिटर्न फाईल करेगा। इसके बदले में, जीएण्डजेईपीसी अर्ध वार्षिक रिटर्न और नामित अभिकरण द्वारा प्रस्तुत किए गए ऑकड़ों का संकलन करेगा और नामित अभिकरण के निष्पादन की जाँच-पड़ताल करेगा। तत्पश्चात, जीजेईपीसी प्रत्येक छमाही के एक महीने के भीतर नामित अभिकरण के निष्पादन पर टिप्पणी के साथ उसके संकलित किए गए अर्ध वार्षिक रिटर्न डीजीएफटी (मुख्यालय) को अग्रेषित करेगा। प्रत्येक पूर्ण छमाही के 15 दिनों के भीतर अर्ध वार्षिक रिटर्न जमा न करने पर अथवा फाइलिंग में विलंब के मामले में, जीजेईपीसी चूककर्ता नामित अभिकरण से टिप्पणियाँ माँग सकता है। जीजेईपीसी चूककर्ता नामित अभिकरण के विरुद्ध उचित कार्रवाई करने के लिए डीजीएफटी मुख्यालय को चूककर्ता नामित अभिकरण के विवरण को भी भेज सकती है।

(iii) डीजीएफटी के क्षेत्रीय प्राधिकारियों द्वारा निगरानी:

क्षेत्रीय प्राधिकारी जिसने नामित अभिकरण प्रमाणपत्र जारी किया है संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को ऐसे अभिकरणों द्वारा फाइल किए जाने वाले अर्ध वार्षिक रिटर्न्स के आधार पर ऐसे प्रमाणपत्र धारकों के निष्पादन की निगरानी करेगा। नामित अभिकरण प्रक्रिया पुस्तक के परिशिष्ट 4ड में दिए गए प्रारूप के अनुसार क्षेत्रीय प्राधिकारी को अक्टूबर (अप्रैल से सितम्बर की अवधि के लिए)/अप्रैल (अक्टूबर से मार्च की अवधि के लिए) महीने में अर्ध वार्षिक रिटर्न फाईल करेगा। क्षेत्रीय प्राधिकारी इन रिटर्नों का समेकन और सत्यापन करेगा। क्षेत्रीय प्राधिकारी डीजीएफटी को जिन अभिकरणों द्वारा रिटर्न फाइल नहीं किए गए और

नामित अभिकरण प्रमाणपत्र के निलंबन/रद्द करने के लिए 30 दिन के भीतर उचित कार्रवाई करने हेतु सूचित करेगा।

(ग) डीजीएफटी मुख्यालय नामित अभिकरण के निपादन की भी जब भी आवश्यक हो समीक्षा कर सकता है।

अध्याय - 5

निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल (ई.पी.सी.जी.)स्कीम

5.01 नीति

विदेश व्यापार नीति के अध्याय 5 में ईपीसीजी स्कीम से संबंधित नीति दी गई है।

5.02 आवेदन प्रपत्र

किसी पात्र निर्यातक के पंजीकृत कार्यालय या मुख्यालय या शाखा कार्यालय या विनिर्माण एकक द्वारा प्राधिकार पत्र की मंजूरी के लिए आवेदन, आयात-निर्यात प्रपत्र 5क में निर्धारित दस्तावेजों के साथ संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को प्रस्तुत करने होंगे।

5.03 अंतरसंबंध प्रमाणीकरण

- (क) संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी परिशिष्ट 5क में आवेदक द्वारा प्रस्तुत स्वतंत्र सनदी अभियन्ता (सीईसी) से अन्तरसंबंध प्रमाण पत्र के आधार पर ईपीसीजी प्राधिकार-पत्र जारी करेगा। पूंजीगत माल के अधिष्ठापन के समय उपयुक्त अपशिष्ट, यदि कोई हो, भी नेक्सस प्रमाण-पत्र में चार्टर्ड इंजीनियर द्वारा प्रमाणित होगा और इसको जारी करने के समय ईपीसीजी प्राधिकार पत्र की शर्त पत्र में इसका उल्लेख किया जाएगा। ऐसा प्रमाणपत्र जारी करने के लिए चार्टर्ड इंजीनियर केवल अपनी क्षमता के क्षेत्र में कार्य करेगा।
- (ख) इसके पश्चात क्षेत्रीय प्राधिकारी ईपीसीजी प्राधिकार पत्र की एक प्रति संबंधित क्षेत्राधिकार प्राप्त केन्द्रीय सीमाशुल्क प्राधिकारी को भेजेगा। प्राधिकार पत्र को जारी करने के समय अनुमत अपशिष्ट को लागू शुल्क के भुगतान पर स्क्रेप/अपशिष्ट के रूप में बेचने की अनुमति होगी।
- (ग) परिवर्धन करने/हटाने सहित आयात मद (मदों) की सूची में संशोधन हेतु आवेदन यदि कोई है, को संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जा सकता है बशर्ते कि आयात के लिए प्राधिकार पत्र वैध है। आवेदक को स्वतंत्र सनदी अभियन्ता से नए अंतरसंबंध प्रमाणपत्र के साथ ऐसे संशोधन (संशोधनों) के अनुरोध हेतु औचित्य देना होगा।
- (घ) परिवर्धन (परिवर्धनों)/हटाने सहित निर्यात मद (मदों) की सूची में संशोधन हेतु आवेदन, यदि कोई है, को संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जा सकता है बशर्ते कि प्राधिकार पत्र की निर्यात दायित्व अवधि वैध है और पूंजीगत माल का निर्यात उत्पाद के साथ अंतरसंबंध है। आवेदक को स्वतंत्र सनदी अभियन्ता से नए अंतरसंबंध प्रमाणपत्र के साथ ऐसे संशोधन (संशोधनों) के अनुरोध हेतु औचित्य देना होगा।

5.04 पूंजीगत माल के अधिष्ठापन का प्रमाणपत्र

- (क) प्राधिकार पत्र धारक आयात पूरा करने के 6 महीने के भीतर क्षेत्राधिकार प्राप्त सीमा शुल्क प्राधिकारी या स्वतंत्र सनदी अभियन्ता से एक प्रमाण-पत्र प्राधिकार पत्र धारक के विकल्प पर प्रस्तुत करेगा जिसमें इस बात की पुष्टि हो कि पूंजीगत माल को प्राधिकार पत्र धारक या उसके सहायक विनिर्माता (विनिर्माताओं) की फैक्टरी/परिसर में अधिष्ठापित कर दिया गया है। क्षेत्रीय प्राधिकारी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए 5000/-रु. की संरचना शुल्क के साथ उक्त अवधि को एक बार और 12 महीने की अधिकतम अवधि के लिए बढ़ाने की अनुमति दे सकता है। जहां प्राधिकार पत्र धारक स्वतंत्र सनदी अभियन्ता के प्रमाण-पत्र का चयन करता है, वहां वह क्षेत्राधिकार प्राप्त सीमा शुल्क प्राधिकारी को प्रमाण पत्र की एक प्रति सूचना/अभिलेख के लिए भेजेगा। प्राधिकार पत्र धारक को आईईसी और आरसीएमसी में उल्लिखित अन्य इकाई को इस अवधि के दौरान पूंजीगत माल का नए अधिष्ठापन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की शर्त पर स्थानान्तरण करने के लिए अनुमति दी जाएगी।
- (ख) कलपुर्जों के आयात के मामले में, प्राधिकार पत्र धारक द्वारा अधिष्ठापन प्रमाण-पत्र आयात की तिथि से तीन वर्षों के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा।

5.05 पंजीकरण पत्तन

आयातों के लिए प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 4.37 के अनुसार एक मात्र पंजीकरण पत्तन के साथ ईपीसीजी प्राधिकार पत्र जारी किया जाएगा। तथापि, प्रक्रिया पुस्तक के पैराग्राफ 4.37 में विनिर्दिष्ट किसी पत्तन से निर्यात किया जा सकता है।

5.06 पुर्जों, औजारों, रिफ्रैक्ट्रीज और उत्प्रेरकों का आयात

(क) विदेश व्यापार नीति के पैरा 5.01 के उप-पैरा (क), (iii) और (iv) के तहत शामिल पूंजीगत माल की खरीद के लिए आवेदनों में सनदी अभियंता अथवा क्षेत्राधिकार प्राप्त सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित, आवेदक की फैक्टरी/परिसर जिसके लिए ऐसे पूंजीगत माल की आवश्यकता है, में अधिष्ठापित संयंत्र/मशीनरी की सूची संलग्न होनी चाहिए।"

(ख) पुर्जों के आयात के मामलों में, ईपीसीजी प्राधिकार पत्र पुर्जों की सूची को विनिर्दिष्ट नहीं करेगा बल्कि निम्नलिखित को दर्शाएगा:

(i) संयंत्र/मशीनरी का नाम जिसके लिए पुर्जों की आवश्यकता है।

(ii) प्राधिकार पत्र के तहत अनुमत बचाए गए शुल्क का मूल्य।

(iii) निर्यात किए जाने वाले उत्पाद का विवरण और निर्यात दायित्व का मूल्य।

(ग) प्राधिकार पत्र धारक स्कीम के तहत आयातित विदेश व्यापार नीति के पैरा 5.01 के उप-पैरा (क), (iii) और (iv) के अन्तर्गत शामिल पूंजीगत माल का स्टॉक और खपत रजिस्टर रखेगा तथा निर्यात दायित्व के अन्तिम मोचन के समय प्राधिकार पत्र धारक इस रजिस्टर के आधार पर संस्थापित पूंजीगत माल में उनके उपयोग की पुष्टि करते हुए स्वतंत्र सनदी अभियंता का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा।

5.07 ईओयू/पुनर्स्थापित एसईजेड यूनिटों का ई.पी.सी.जी. स्कीम के तहत डीटीए यूनिट में परिवर्तन

(क) ई.ओ.यू./पुनर्स्थापित एस.ई.जेड एकक, डीटीए यूनिट में परिवर्तन करते समय ई.पी.सी.जी. प्राधिकार पत्र के लिए निर्धारित दस्तावेजों सहित आवेदन कर सकता है। संबंधित विकास आयुक्त से 'अनापत्ति प्रमाण-पत्र' प्रस्तुत करना होगा।

(ख) यूनिट जो ईओयू/एसईजेड स्कीम से ईपीसीजी स्कीम में परिवर्तित होती है, की निर्यात दायित्व अवधि वही होगी जो विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) के पैरा 5.01 के अनुसार सीधे ईपीसीजी प्राधिकार पत्र धारक के लिए उपलब्ध है।

(ग) यदि कोई एकल ईओयू/एसईजेड यूनिट ईपीसीजी स्कीम के लिए ईओयू से अलग होना चाहती है तो औसत निर्यात दायित्व के अनुक्षण की कोई आवश्यकता नहीं होगी और यूनिट को पूंजीगत माल जिसके लिए प्राधिकार पत्र प्राप्त किया गया है, के ह्रासित मूल्य के आनुपातिक बचाए गए शुल्क की राशि के 6 गुने के समतुल्य केवल विशिष्ट निर्यात दायित्व को बरकरार रखना होगा।

(घ) यदि किसी फर्म/कम्पनी की एक यूनिट ईपीसीजी स्कीम के लिए ईओयू से अलग होना चाहती है जबकि अन्य यूनिट (यूनिटें) डीटीए यूनिटें हैं तो फर्म/कम्पनी (अलग होने वाली यूनिट को छोड़कर) को जारी प्राधिकार पत्रों के लिए औसत निर्यात दायित्व अपरिवर्तित रहेगा तथा यूनिट के अलग होने के बाद औसत निर्यात दायित्व फर्म/कम्पनी जो फर्म/कम्पनी की सभी यूनिटों के लिए साथ-साथ चलता है, के कुल निर्यात से अलग हुई यूनिट द्वारा किए गए निर्यात को हटाकर निर्धारित किया जाएगा। ऐसे मामले में, पूंजीगत माल के ह्रासित मूल्य पर आनुपातिक शुल्क बचत राशि के 6 गुने का समतुल्य विशिष्ट निर्यात दायित्व ईपीसीजी स्कीम में जाने वाली यूनिट पर लगाया जाएगा।

5.08 स्वदेशी रूप से विनिर्मित पूंजीगत माल की प्राप्ति

(क) स्वदेशी रूप से विनिर्मित पूंजीगत माल को प्राप्त करने के इच्छुक ई पी सी जी प्राधिकार पत्र धारक, सीधे आयात/अग्रिम निर्गम आदेश (एआरओ) जारी करने के लिए ईपीसीजी प्राधिकार पत्र को अमान्य कराने के लिए क्षेत्रीय प्राधिकारी को अनुरोध करेगा ताकि प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 7.02 (ग) के साथ पठित विदेश व्यापार नीति के पैरा 7.03 तहत मान्य निर्यात लाभों को प्राप्त किया जा सके।

(ख) यह अनुरोध आवेदन पत्र के साथ अथवा ई.पी.सी.जी. प्राधिकार पत्र की वैधता अवधि के दौरान किया जा सकता है।

(ग) आवेदक पूंजीगत माल के विनिर्माता (विनिर्माताओं) का नाम और पता देगा।

(घ) संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी अवैधीकरण पत्र/एआरओ चार प्रतियों में जारी करेगा।

5.09 निविष्टियों के आयात हेतु अग्रिम प्राधिकार पत्र जारी करना

ई.पी.सी.जी. प्राधिकार पत्र धारक को पूंजीगत माल की आपूर्ति करने के इच्छुक स्वदेशी विनिर्माता, ई.पी.सी.जी. प्राधिकार पत्र धारक को आपूर्ति के लिए पूंजीगत माल के विनिर्माण के लिए अपेक्षित संघटकों सहित निविष्टियों के आयात के लिए अग्रिम प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए क्षेत्रीय प्राधिकारी को आवेदन कर सकते हैं।

5.10 निर्यात दायित्व को पूरा करने की शर्तें

विदेश व्यापार नीति के पैराग्राफ 5.04 में उल्लिखित शर्तों के अतिरिक्त निर्यात दायित्व पूरा करने के लिए निम्नलिखित शर्तें भी लागू होगी:

- (क) सहायक विनिर्माता और निर्यातक का नाम निर्यात दस्तावेजों पर दर्शाया जाएगा।
- (ख) ईपीसीजी प्राधिकार पत्र धारक या तो सीधा निर्यात अथवा तीसरी पार्टी (पार्टियों) के माध्यम से निर्यात कर सकता है।
- (ग) यदि प्राधिकार पत्र धारक एक तृतीय पक्ष के माध्यम से निर्यात करना चाहते हैं तो उनको निर्यात दस्तावेज जैसे पोत लदान बिल/निर्यात बिल इत्यादि में ईपीसीजी प्राधिकार पत्र संख्या के साथ प्राधिकार पत्र धारक और सहायक विनिर्माता, दोनों के नाम, यदि कोई है, दर्शाने होंगे। बीआरसी, जीआर घोषणा, निर्यात आदेश तथा बीजक पत्र तृतीय पक्ष निर्यातक के नाम होने चाहिए। तृतीय पक्ष के माध्यम से निर्यात किया गया माल ईपीसीजी प्राधिकार पत्र धारक अथवा सहायक विनिर्माता द्वारा विनिर्मित किया जाना चाहिए जहां प्राधिकार-पत्र के अंतर्गत आयातित **पंजीगत माल को संस्थापित किया गया है। केवल ऐसे निर्यात से तीसरे पक्ष निर्यातक के खाते से सामान्य बैंकिंग चैनल के माध्यम से वसूला गया लाभ प्राधिकार पत्र धारक के खाते में गई राशि निर्यात दायित्व की पूर्ति की गणना की जाएगी।**
- (घ) ईपीसीजी प्राधिकार पत्र धारक तृतीय पक्ष (पक्षों) के माध्यम से निर्यात दायित्व (ईओ) के निर्वहन हेतु निम्नलिखित अतिरिक्त दस्तावेज प्रस्तुत करेगा:
 - (i) संबंधित ईपीसीजी प्राधिकार-पत्र के मद्दे निर्यात दायित्व को पूरा करने के लिए प्राधिकार-पत्र धारक/सहायक विनिर्माता द्वारा विनिर्मित माल के निर्यात को प्रारंभ करने के लिए प्राधिकार पत्र धारक तथा अंतिम निर्यातक के बीच हुए समझौते की प्रति।
 - (ii) प्राधिकार पत्र धारक के कारखाने के परिसर से अंतिम निर्यातक/निर्यात के पत्तन को माल प्रेषित किए जाने का प्रमाण अर्थात् (क) पोतलदान बिल संख्या, तिथि तथा ईपीसीजी प्राधिकार पत्र संख्या सहित निर्यात के सत्यापन के साथ सीमाशुल्क विभाग द्वारा विधिवत प्रमाणीकरण सहित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा जारी एआरई—I प्रमाणपत्र/जीएसटी नियम के तहत निर्धारित निर्यात के लिए कर बीजक (ख) यदि इकाई केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/जीएसटी के साथ पंजीकृत नहीं है तो बीजक पत्र जिसमें प्रेषण के समय संबंधित ईपीसीजी प्राधिकार-पत्र की संख्या और तिथि का विधिवत उल्लेख किया गया हो।
 - (iii) प्राधिकार-पत्र धारक के परिसर से तृतीय पक्ष/निर्यात पत्तन को भेजे गए माल की लॉरी रसीद/संभार-तंत्र साक्ष्य।
 - (iv) स्टॉप पेपर पर तृतीय पक्ष द्वारा शपथ-पत्र दिया जाए जिसमें घोषित किया जाए कि निर्यात-कथन में दिए गए विवरण के अनुसार लाइसेंस धारक की ओर से निर्यात दायित्व को पूरा करने हेतु निर्यात किए जाने वाले उत्पादों का विनिर्माण लाइसेंस-धारक द्वारा किया गया था।
 - (v) तृतीय पक्ष को आपूर्ति करने पर ऐसे निर्यात के कारण सामान्य बैंकिंग चैनल के माध्यम से तृतीय पक्ष निर्यातक के खाते से प्राधिकार पत्र धारक के खाते में आय की प्राप्ति होने हेतु वित्तीय साक्ष्य।
 - (vi) तीसरे पक्ष से दावा-परित्याग प्रमाणपत्र कि वे, उनके द्वारा प्राप्त किसी ईपीसीजी प्राधिकार-पत्र के निर्यात दायित्व पूरा होने के प्रति प्राप्त आय का प्रयोग नहीं करेंगे।

5.11 निर्यात से आय की प्राप्ति

अध्याय-7 के तहत मान्य निर्यात के अलावा निर्यात आय, मुक्त स्म से परिवर्तनीय मुद्रा में वसूल की जाएगी। वसूली की मुद्रा चाहे जो भी हो, एसईजेड यूनिटों को निर्यात/विकासकर्ता/सह-विकासकर्ता को किया गया निर्यात को निर्यात दायित्व पूरा किया गया समझा जाएगा। एसईजेड इकाइयों को की गई आपूर्ति से प्राप्त आय को एसईजेड इकाई की विदेशी मुद्रा खाते से प्राप्त किया जाएगा।

5.12 औसत निर्यात दायित्व की गणना

औसत निर्यात दायित्व की गणना करते समय वैध निर्यात दायित्व समयावधि (मूल अथवा बढ़ाया गया) के अंदर ईपीसीजी प्राधिकार पत्रों के लिए विशिष्ट निर्यात दायित्व को पूरा करने के लिए गणना किए गए/गणना किए जा रहे पूर्ववर्ती तीन वर्षों में किए गए निर्यात को ध्यान में नहीं रखा जाएगा।

5.13 औसत निर्यात दायित्व को बनाए रखने से छूट

(क) निम्नलिखित वस्तुओं के निर्यात के मामले में ईपीसीजी प्राधिकार पत्र धारक को औसत निर्यात दायित्व के स्तर को बनाए रखने की आवश्यकता नहीं होगी:

- (i) हस्तशिल्प,
- (ii) हथकरघा,
- (iii) कुटीर व अत्यन्त छोटे उद्योग,
- (iv) कृषि,
- (v) जल कृषि (मत्स्य क्षेत्र सहित), मत्स्योद्योग,
- (vi) पशु-पालन,
- (vii) पुष्पोत्पादन व बागवानी,
- (viii) मुर्गी पालन,
- (ix) अंगूरोत्पादन,
- (x) रेशमोत्पाद,
- (xi) कालीन,
- (xii) कँयर और
- (xiii) जूट

(ख) तथापि, औसत निर्यात दायित्व के स्तर को बनाए रखने से यह छूट मछली पकड़ने के ट्रॉलर्स, नौका, पोत, और अन्य ऐसी ही मदों के आयात के लिए अनुमत नहीं होगी।

(ग) उपर्युक्त उप-पैरा (क) में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों द्वारा ईपीसीजी स्कीम के तहत औजारों को छोड़कर आयातित माल को, आयात की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए, ऐसे मामलों में भी जहाँ निर्यात दायित्व पूरा कर दिया गया है, हस्तांतरित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

5.14 निर्यात दायित्व को ब्लाकवार पूरा करना

(क) ईपीसीजी स्कीम के तहत प्राधिकार पत्र धारक औसत निर्यात दायित्व बनाए रखते समय निर्धारित ब्लाक अवधि में निम्नलिखित अनुपात में विशिष्ट निर्यात दायित्वों को एक विशेष अवधि में पूरा करेगा:

प्राधिकार पत्र जारी करने की तारीख से अवधि	पूरा किया जाने वाला न्यूनतम निर्यात दायित्व
1 से 4 वर्ष का ब्लॉक	50 प्रतिशत
5 और 6 वर्ष का ब्लॉक	बाकी निर्यात दायित्व

(ख) प्राधिकार पत्र धारक निर्यात दायित्व के साथ-साथ औसत निर्यात के पूरा होने पर ब्लॉक पूरा होने के तीन महीने के भीतर डिजिटल हस्ताक्षर का प्रयोग करके सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग द्वारा क्षेत्रीय प्राधिकारी को सूचित करेगा।

(ग) जहाँ उन मामलों जिसमें ब्लाक से संबंधित निर्यात दायित्व अपूर्ण भाग के अनुपात में बचाई गई शुल्क की राशि पर 2 प्रतिशत संघटन शुल्क के भुगतान के अधीन क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा प्रथम ब्लाक के लिए निर्धारित ईओ का विस्तार किया गया है, को छोड़कर प्रथम ब्लाक के ईओ को उपर्युक्त अनुपात के अनुसार पूरा नहीं किया गया है, प्राधिकार-पत्र धारक ब्लाक के समाप्त होने के तीन महीने के भीतर प्रथम ब्लाक के कुल अपूर्ण ईओ पर बचाई गई शुल्क की राशि के अनुपात के सीमाशुल्क (राजस्व विभाग द्वारा यथा अधिसूचित लागू ब्याज सहित) का भुगतान करेगा।

(घ) (i) 1 अप्रैल, 2002 से 31 अगस्त, 2004 तक जारी किए गए प्राधिकार पत्र समय-समय पर यथा संशोधित प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) (संशोधित संस्करण-02) के पैरा 5.8 के उपबन्धों द्वारा अधिशासित होंगे।

(ii) 1 सितम्बर, 2004 से 17 अप्रैल, 2013 तक जारी प्राधिकार पत्र 17.04.2013 तक यथा संशोधित प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) (संशोधित संस्करण-12) के पैरा 5.8 के उपबन्धों द्वारा अधिशासित होंगे।

(iii) 18.04.2013 से विदेश व्यापार नीति 2015-20 की अधिसूचना जारी होने तक जारी किए गए प्राधिकार पत्र सार्वजनिक सूचना सं.1 दिनांक 18.04.2013 के जरिए यथा संशोधित प्रक्रिया पुस्तक खंड 1 के पैरा 5.8 के उपबंधों द्वारा अधिशासित किए जाएंगे।

(iv) 1 अप्रैल, 2015 से 4 दिसम्बर, 2017 तक जारी किए गए प्राधिकार पत्र सार्वजनिक सूचना सं. 1 दिनांक 01.04.2015 द्वारा यथा संशोधित प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 5.14 के प्रावधानों द्वारा अभिशासित होगा।

5.15 निर्यात दायित्व की निगरानी

प्राधिकार पत्र धारक, निर्यात दायित्व को पूरा करने संबंधी रिपोर्ट संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल तक डिजिटल हस्ताक्षरों का उपयोग करके सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग/इसकी हार्ड कॉपी द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

5.16 10 प्रतिशत शुल्क बचत राशि तक स्वतः कमी/ वृद्धि और निर्यात दायित्व में यथानुपात कमी/वृद्धि

यदि जारी किया गया प्राधिकार पत्र का मालों के आयात के लिए वास्तव में उपयोग किया गया हो:-

(क) प्राधिकार पत्र पर दर्शायी गई बचायी गई शुल्क राशि का आधिक्य जो 10 प्रतिशत से अधिक न हो, प्राधिकार-पत्र उस अनुपात द्वारा बढ़ाया हुआ माना जाएगा। सीमाशुल्क प्राधिकारी संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी के पृष्ठांकन के बिना, प्राधिकार पत्र के ऐसे माल की निकासी की अनुमति स्वतः ही दे देगा। प्राधिकार-पत्र धारक संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को बचाई गई शुल्क राशि में आयात के एक महीने के भीतर, किए गए अतिरिक्त आयात को शामिल करने के लिए अतिरिक्त फीस देगा। निर्यात दायित्व स्वयं आनुपातिक रूप से बढ़ जाएगा।

(ख) प्राधिकार-पत्र पर दर्शायी गई बचायी गई शुल्क राशि 10 प्रतिशत से अधिक होने की स्थिति में, संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी अपनी प्रत्यायोजित शक्तियों के अनुसार, ईपीसीजी प्राधिकार पत्र की बचत शुल्क राशि में वृद्धि को अनुमत कर सकता है। प्राधिकार पत्र धारक सीमाशुल्क प्राधिकारी को अतिरिक्त बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता प्रस्तुत करेगा।

(ग) यदि प्राधिकार-पत्र पर दर्शायी गई बचायी गई राशि शुल्क राशि से कम हो तो, उसका निर्यात दायित्व प्राधिकार पत्र के वास्तविक प्रयोग के सन्दर्भ में यथानुपात आधार पर कम हो जाएगा।

5.17 निर्यात दायित्व अवधि में विस्तार

(क) विदेश व्यापार नीति 2015-20 आर ई 2017 की अधिसूचना से पूर्व जारी ईपीसीजी प्राधिकार-पत्र की निर्यात दायित्व अवधि में विस्तार प्राधिकार-पत्र जारी होने की तारीख को लागू प्रक्रिया-पुस्तक के संगत प्रावधानों द्वारा अभिशासित होगा।

(ख) विदेश व्यापार नीति 2015-20 की अधिसूचना से पूर्व जारी ईपीसीजी प्राधिकार-पत्र की निर्यात दायित्व अवधि में विस्तार प्राधिकार-पत्र जारी होने की तारीख को लागू प्रक्रिया-पुस्तक के संगत प्रावधानों द्वारा अभिशासित होगा।

(ग) शून्य शुल्क ईपीसीजी प्राधिकार पत्र के मामले में संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक एक-एक वर्ष के लिए निर्यात दायित्व अवधि में प्रत्येक दो वर्ष की बढ़ोतरी हेतु अपूर्ण निर्यात दायित्व पर बचाई गई समानुपातिक शुल्क राशि के कमशः 5 प्रतिशत और 10 प्रतिशत के बराबर संयोजक शुल्क का भुगतान किए जाने पर अथवा प्रत्येक पहले/दूसरे वर्ष की बढ़ोतरी हेतु प्राधिकार पत्र के तहत लागू कुल निर्यात दायित्व में कमशः 10 प्रतिशत और 20 प्रतिशत तक निर्यात दायित्व की बढ़ोतरी करने पर, जैसा भी मामला हो, निर्यातक की इच्छा के अनुसार विचार किया जा सकता है। न्यूनतम संयोजन शुल्क 10,000 रु. होगा।

(घ) निर्यात दायित्व की अवधि को बढ़ाने का अनुरोध क्षेत्रीय प्राधिकारी को मूल निर्यात दायित्व अवधि के समाप्त हो जाने की तिथि से 90 दिनों के अन्दर किया जाएगा। तथापि, क्षेत्रीय प्राधिकारी 5000 रु. के अतिरिक्त संघटन शुल्क के साथ 180 दिनों तक प्राप्त किए गए विस्तार हेतु अनुरोध पर विचार कर सकते हैं।

5.18 बीआईएफआर/पुनर्वास के अंतर्गत इकाईयों हेतु प्रावधान

(क) हटा दिया गया है।

(ख) हटा दिया गया है।

5.19 औसत निर्यात दायित्व में राहत

(क) उन क्षेत्रों के निर्यातकों को राहत प्रदान करने के लिए जहाँ उस क्षेत्र/उत्पाद समूह का कुल निर्यात पिछले वर्ष की तुलना में 5% से अधिक कम हुआ है, पिछले वर्ष की तुलना में संबद्ध वर्ष में उस विशेष क्षेत्र/उत्पाद समूह के निर्यातों के समानुपात में वर्ष के लिए औसत निर्यात दायित्व को कम किया जा सकता है। तथापि, यदि निर्यात में वर्षों तक लगातार कमी जारी रहती है, तो औसत निर्यात दायित्व में पात्रता की गणना और कमी की गणना का आधार वर्ष उस वर्ष को माना जाएगा, जिसके बाद निर्यात में

लगातार कमी आई है ।

(ख) क्षेत्रों/उत्पाद समूहों जिनके लिए इस छूट की अनुमति दी जानी है, पिछले वित्तीय वर्ष समाप्त होने के सात महीनों के अंदर विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा सभी क्षेत्रीय प्राधिकारियों को सूचित किया जाएगा और तदनुसार, क्षेत्रीय प्राधिकारी उस क्षेत्र/उत्पाद समूह के निर्यातकों के लिए वार्षिक औसत निर्यात दायित्व का पुनः निर्धारण करेंगे ।

5.20 निर्यात उत्पाद पर रोक के मामले में स्वतः निर्यात दायित्व विस्तार

जब कभी किसी उत्पाद के निर्यात पर रोक/प्रतिबंध लगाया जाता है, ऐसे निर्यात उत्पादों पर रोक लगाने से पूर्व पहले से जारी ईपीसीजी प्राधिकार पत्र के सम्बंध में निर्यात दायित्व अवधि, बिना किसी संघटन शुल्क के ऐसी रोक की अवधि की समतुल्य अवधि के लिए स्वतः बढ़ जाएगी। प्राधिकार-पत्र धारक को रोक की अवधि के लिए औसत निर्यात दायित्व बनाए रखने की आवश्यकता नहीं होगी।

5.21 हटा दिया गया है ।

5.22 विमुक्ति

(क) निर्यात दायित्व की पूर्ति के प्रमाण के रूप में, प्राधिकार पत्र धारक आयात-निर्यात फार्म 5ख में निर्धारित किए गए दस्तावेजों सहित विमुक्ति आवेदन प्रस्तुत करेगा ।

(ख) संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी, सन्तुष्ट होने पर, ई.पी.सी.जी प्राधिकार पत्र धारक को निर्यात दायित्व के निष्पादन का प्रमाणपत्र जारी करेगा और उसकी एक प्रति, सीमाशुल्क प्राधिकारियों को भेजेगा जिनके साथ बैंक गारन्टी/विधिक वचनबद्धता निषादित की गई है। प्राधिकार-पत्र धारक द्वारा निर्यात दायित्व पूर्ति के प्रमाण के लिए सौंपे गए दस्तावेजों का ब्यौरा देने वाला एक विवरण प्रमाण-पत्र के साथ संलग्न किया जाएगा।

(ग) क्षेत्रीय प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे आवेदन साधारणतया 30 दिनों के भीतर निपटाए जाएँ। यदि कोई कमी है तो उसे एक बार में बताया जायेगा । उसके बाद सभी पत्राचार, सिर्फ उन कमियों के बारे में होंगे । यदि आवश्यक हुआ तो नया पत्राचार 15 दिनों के भीतर किया जाए । एक बार दस्तावेज पूरे हो जाने पर सभी दस्तावेजों/ सूचनाओं के प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर निर्यात दायित्व पूरा करना होगा।

(घ) संपूर्ण दस्तावेजों की प्राप्ति के बाद जो आवेदन 60 दिन की अवधि के बाद भी बकाया हैं उनकी सूचना कारणों सहित डी.जी.एफ.टी. के ईपीसीजी प्रभाग को दी जाएगी।

5.23 वास्तविक चूक को नियमित करना और ईपीसीजी स्कीम से बाहर निकलना

(क) यदि ई.पी.सी.जी प्राधिकार पत्र धारक निर्धारित निर्यात दायित्व को पूरा करने में असफल रहता है तो वह, सीमाशुल्क प्राधिकारी द्वारा निर्धारित सीमाशुल्क तथा ब्याज का भुगतान करेगा। ई पी सी जी प्राधिकार पत्र धारक के पास अपनी मर्जी से बाहर होने का विकल्प रहेगा। प्राधिकार पत्र धारक के पास सीमाशुल्क संघटक के भुगतान के लिए विदेश व्यापार नीति के अध्याय 3 या अध्याय 5 के तहत जारी वैध शुल्क क्रेडिट स्क्रिप्स प्रस्तुत करने का विकल्प होगा।

(ख) प्राधिकार-पत्र धारक प्रक्रिया-पुस्तक के पैरा 4.50 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार स्व-गणना के आधार पर स्वतः ही शुल्क और ब्याज अदा कर सकते हैं।

5.24 अभिलेखों का रख-रखाव

प्रत्येक ई.पी.सी.जी प्राधिकार पत्र धारक विमुक्ति की तारीख से 2 वर्षों की अवधि के लिए, निर्यात दायित्व की पूर्ति के लिए की गई आपूर्ति और प्रदान की गई सेवाओं/निर्यात का सही और उचित लेखा रखेगा ।

5.25 ईपीसीजी स्कीम के तहत आयातित पूंजीगत माल का पुनः निर्यात/मरम्मत/पुनः स्थापन

(क) ई.पी.सी.जी स्कीम के तहत आयातित पूंजीगत माल जिसे खराब अथवा प्रयोग के काबिल नहीं पाया गया उसे आयात पर शुल्क के भुगतान की तारीख से 3 वर्षों के भीतर ऐसे माल के सीमा-शुल्क विभाग द्वारा निष्पत्ति की तिथि से विदेशी आपूर्तिकर्ता को पुनः निर्यात कर सकते हैं जिसकी अनुमति क्षेत्रीय प्राधिकारी/ सीमाशुल्क प्राधिकारी से लेनी होगी। परिणामस्वरूप निर्यात दायित्व पुनः निर्धारित किया जाएगा।

(ख) आयातित और खराब पाए गए अथवा अन्यथा प्रयोग हेतु उपयुक्त नहीं पाये गए पूंजीगत माल का निर्यात आरए/सीमा शुल्क प्राधिकारी की अनुमति से ऐसे माल की सीमा शुल्क विभाग द्वारा दी गई निकासी तिथि से दो वर्षों के भीतर किया जा सकता है तथा ई.पी.सी.जी. स्कीम के तहत इसके बदले में पूंजीगत माल का आयात किया जा सकता है । ऐसे मामलों में, निर्यात की अनुमति देते समय, सीमाशुल्क विभाग प्राप्त किए गए शुल्क लाभ को क्रेडिट करेगा जिस ऐसे प्रतिस्थापित पूंजीगत माल का आयात

करने के समय पुनः घटा दिया जाएगा।

(ग) ईपीसीजी स्कीम के तहत आयातित पूंजीगत माल आरए/सीमाशुल्क प्राधिकारी की अनुमति से, ऐसे वस्तुओं का सीमाशुल्क विभाग द्वारा दी गई निकासी की तिथि से तीन वर्षों के भीतर विदेशों में मरम्मत के लिए पुनः निर्यात किया जा सकता है। मरम्मत तथा बीमा और भाड़ा पर खर्च किए गए व्यय संबंधी शुल्क संघटक पर दोनों ओर से निर्यात दायित्व के पुनः निर्धारण के लिए विचार किया जाएगा।

5.26 दण्डात्मक कार्रवाई

निर्यात दायित्व या प्राधिकार पत्र की किसी अन्य शर्त को पूरा करने में असफल रहने पर, प्राधिकार पत्र धारक के विरुद्ध विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992, यथासंशोधित तथा उसके तहत बनाए गए आदेशों और नियमों एवं विदेश व्यापार नीति/प्रक्रिया-पुस्तक तथा सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 समय-समय पर यथा संशोधित और प्रचलित किसी अन्य कानून के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्रवाई की जा सकती है।

5.27 ईपीसीजी प्राधिकार पत्रों की क्लबिंग

(क) एक ही प्राधिकार पत्र धारक को दो अथवा इससे अधिक ईपीसीजी प्राधिकार पत्रों की क्लबिंग की अनुमति दी जाएगी।

(ख) क्लबिंग के लिए एक आवेदन-पत्र संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को एएनएफ 5ग में प्रस्तुत किया जा सकता है। यदि प्राधिकार-पत्रों पर पृष्ठांकित निर्यात उत्पाद वही/समान है और यदि प्राधिकार-पत्र उसी क्षेत्रीय प्राधिकरण द्वारा जारी किए जाते हैं तो केवल क्लबिंग की अनुमति दी जाएगी।

(ग) कुल निर्यात दायित्व क्लब किए गए प्राधिकार-पत्रों के बचाए गए शुल्क की कुल राशि को ध्यान में रखते हुए पुनः निर्धारित किया जाएगा।

(घ) क्लबिंग करने पर, सभी प्रयोजनों के लिए प्राधिकार पत्र एकल ईपीसीजी प्राधिकार पत्र माना जाएगा। क्लब किए प्राधिकार पत्रों के लिए निर्यात दायित्व अवधि प्रथम प्राधिकार-पत्र जारी होने की तारीख से मानी जाएगी।

(ङ.) इस प्रकार क्लब किए गए प्रत्येक प्राधिकार पत्र के लिए औसत निर्यात दायित्व क्लबिंग के लिए अलग-अलग प्राधिकार पत्र पर लगाए गए औसत निर्यात दायित्वों का अधिकतम होगा।

(च) क्लबिंग विस्तारित अवधि यदि कोई हो, सहित वैध निर्यात दायित्व अवधि के दौरान अनुमत होगी। तथापि, सभी प्रकार के प्राधिकार पत्रों के मामले में क्लबिंग जहां निर्यात दायित्व अवधि समाप्त हो गई है नियमितीकरण उद्देश्य के लिए अनुमत होगा बशर्ते कि वे उसी नीति गत अवधि में जारी किए गए हों।

(छ) ईपीसीजी प्राधिकार पत्रों की क्लबिंग के मामले में, जहां निर्यात दायित्व वैकल्पिक उत्पादों/सेवाओं के निर्यात द्वारा पूरा किया जा सकता है, निर्यात दायित्व पूर्ति/नियमितीकरण के लिए वैकल्पिक उत्पादों/सेवाओं का अनुपात क्लब किए गए प्राधिकार पत्रों में अनुमत वैकल्पिक उत्पादों/सेवाओं का न्यूनतम प्रतिशत तक सीमित होगा।

(ज) 1.4.2007 से पूर्व जारी किए गए ईपीसीजी प्राधिकार पत्र प्रक्रिया पुस्तक खण्ड 1 (आर ई-2006) के अध्याय 5 में निहित प्रावधानों द्वारा अभिशासित होंगे। 1.4.2007 और 17.04.2013 के बीच जारी किए गए ईपीसीजी प्राधिकार पत्र प्रक्रिया पुस्तक खण्ड 1 (आर ई-2012 यथा संशोधित) के अध्याय 5 में निहित शर्तों द्वारा अभिशासित होंगे। दिनांक 18.4.2013 से प्रक्रिया पुस्तक 2015-20 की अधिसूचना तक के दौरान जारी किए गए ईपीसीजी प्राधिकार पत्र दिनांक- 18.4.2013 की सार्वजनिक सूचना सं0 1 के प्रावधानों द्वारा अभिशासित होंगे। प्रक्रिया पुस्तक 2015-20 की अधिसूचना से प्रक्रिया पुस्तक 2015-20 (आर ई 2017) की अधिसूचना के बीच जारी किए गए ईपीसीजी प्राधिकार पत्र प्रक्रिया पुस्तक 2015-20 में शामिल प्रावधानों द्वारा अभिशासित होंगे।

5.28 निर्यात पश्च ईपीसीजी शुल्क क्रेडिट स्क्रिप्ट (स्क्रिप्स)

(क) निर्यातक संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी के समक्ष एएनएफ-5क में एक आवेदन-पत्र दायर करते हुए इस योजना के लिए विकल्प चुनते हुए इस विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं।

(ख) पूंजीगत माल का आयात करते समय निर्यातक द्वारा सभी लागू शुल्क नकद राशि में चुकाए जाएंगे।

(ग) निम्नलिखित को विनिर्दिष्ट करते हुए क्षेत्रीय प्राधिकारी प्राधिकार-पत्र जारी करेगा:-

(i) प्राधिकार-पत्र के मुख्य पृष्ठ पर 'आयात के लिए नहीं' दर्शाना।

(ii) औसत निर्यात दायित्व, यदि कोई है।

(iii) लागू विशिष्ट निर्यात दायित्व के 85% की दर पर विशिष्ट निर्यात दायित्व की गणना मानो आयातों के लिए शुल्क छूट का लाभ उठाना हो; और

(iv) निर्यात दायित्व अवधि जो प्राधिकार-पत्र जारी करने की तिथि से लागू होगी।

(घ) निर्यातक विशिष्ट निर्यात दायित्व अवधि के अंदर पूरा किए गए निर्यात दायित्व के अनुपात में ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप (स्क्रिप्स) को जारी करने के लिए आयात-निर्यात प्रपत्र 5ख में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। केवल ऐसे पहले आवेदन के लिए पूंजीगत माल, पूंजीगत माल का अन्तर संबंध और स्थापन प्रमाणपत्र (प्रमाण पत्रों) पर वास्तविक शुल्क अदायगी के प्रमाण को निर्यात दायित्व की पूर्ति के प्रमाण एवं औसत निर्यात दायित्व के रखरखाव के प्रमाण के साथ सौंपा जाएगा। तदनन्तर, केवल अतिरिक्त रूप से पूरा किए गए विशिष्ट निर्यात दायित्व (औसत निर्यात दायित्व के रखरखाव के प्रमाण के साथ) के पूरा किए जाने का प्रमाण विशिष्ट निर्धारित किए निर्यात दायित्व (उपरोक्त ग (iii) जैसा) के संदर्भ में सौंपा जा सकता है जब तक कि पहले सौंपे गए दस्तावेजों/प्रमाणों में कोई अन्य परिवर्तन नहीं है।

(ङ.) क्षेत्रीय प्राधिकारी पूरा किए गए निर्यात दायित्व के अनुपात के बराबर मुक्त रूप से हस्तांतरणीय शुल्क क्रेडिट स्क्रिप (स्क्रिप्स) जारी करेगा।

(च) मुक्त रूप से हस्तांतरणीय ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप (स्क्रिप्स) की गणना मूल सीमाशुल्क पर भुगतान की गई राशि पर आधारित होगी।

(छ) हटा दिया गया है।

(ज) मौजूदा ईपीसीजी स्कीम के सभी प्रावधान लागू रहेंगे जब तक कि वे इस स्कीम से असंगत न हों।

(झ) विदेश व्यापार नीति के पैरा 5.12 के तहत आयातित पूंजीगत माल का ऐसे पूंजीगत माल के मद्दे ऑफसेटिंग निर्यात दायित्व के लिए अंतिम निर्यात की तिथि तक निपटान नहीं किया जायेगा।

(ञ) प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 5.25 के प्रावधान के अनुसार खराब अथवा प्रयोग के काबिल नहीं पाये गये पूंजीगत माल के पुनःनिर्यात के मामलों में यदि निर्यातक ऐसे पुनः निर्यात पर शुल्क वापसी का दावा करता है तो विदेश व्यापार नीति के पैरा 5.12 के तहत शुल्क में कोई छूट प्राप्त नहीं होगी

5.29 हरित प्रौद्योगिकी उत्पाद

विदेश व्यापार नीति के पैरा 5.10 के तहत शामिल किए गए निर्यात उत्पाद जिसमें हरित प्रौद्योगिकी उत्पाद के लिए 75 प्रतिशत तक घटाया हुआ निर्यात दायित्व का प्रावधान किया गया है:

(i) वि-केन्द्रीकृत सौर ऊर्जा और ग्रिड से जुड़े हुए उत्पाद के लिए उपस्कर,

(ii) बायो-मास गैसीफायर,

(iii) बायोमास/अपशिष्ट बायलर

(iv) वैपर एबजोरप्शन चिलर्स,

(v) वेस्ट हीट बायलर,

(vi) वेस्ट हीट रिकवरी यूनिटें,

(vii) अनफायर्ड हीट रिकवरी स्टीम जनरेटर्स,

(viii) विंड टरबाइन,

(ix) सोलर कलेक्टर और उसके हिस्से,

(x) वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स,

(xi) विंड मिल, विंड मिल टरबाइन/इंजिन,

(xii) अन्य जनरेटिंग सैट्स - विंड पावर्ड,

(xiii) इलेक्ट्रिकली आपरेटिड व्हीकल्स-मोटर कारें,

(xiv) इलेक्ट्रिकली आपरेटिड व्हीकल्स-लारिज एंड ट्रक्स,

(xv) इलेक्ट्रिकली आपरेटिड व्हीकल्स- मोटर साइकिल्स/मोपेड्स, और

(xvi) सोलर सैल्स।

अध्याय - 6

निर्यात अभिमुख यूनिट (ईओयू), इलैक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क (ईएचटीपी), साफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क (एसटीपी) स्कीम और बायो टेक्नोलॉजी पार्क (बीटीपी)

6.00 स्कीम

निर्यात अभिमुख यूनिट (ईओयू), इलैक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क (ईएचटीपी) सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क (एसटीपी) व जैव प्रौद्योगिकी पार्क (बीटीपी) स्कीम से संबंधित नीति विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) के अध्याय 6 में दी गयी है।

6.01 आवेदन/अनुमोदन/अनुमोदन का नवीकरण

(क) ईओयू स्थापित करने हेतु परिशिष्ट एवं आयात निर्यात प्रपत्र के आयात-निर्यात प्रपत्र 6क के अनुसार आवेदन की तीन प्रतियां विकास आयुक्त को प्रस्तुत करनी होंगी।

(ख)

(i) ईओयू स्कीम के तहत यूनिटों की स्थापना हेतु प्रस्तावों के आवेदन, परिशिष्ट एवं आयात निर्यात प्रपत्रों के **परिशिष्ट-6क** में उल्लिखित मापदण्डों तथा परिशिष्ट एवं आयात निर्यात प्रपत्रों के **परिशिष्ट 6ख** में दी गई अनुमोदन संबंधित क्षेत्र विशिष्ट शर्तों के अनुसार 15 दिनों के भीतर यूनिट अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदित अथवा रद्द किया जाएगा। अन्य मामलों में, अनुमोदन बोर्ड द्वारा स्वीकृति देने के बाद विकास आयुक्त द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाएगा।

(ii) अनुमोदन होने पर एक अनुमति पत्र (एलओपी)/आशय पत्र (एलओआई) को विकास आयुक्त/ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी इकाई के नामित अधिकार द्वारा जारी किया जाएगा। एलओपी/एलओआई की प्रारंभिक वैधता 2 वर्ष की होगी ताकि इकाई संयंत्र का निर्माण कार्य और मशीनरी संस्थापित कर सके तथा इस समय तक इकाई को उत्पादन प्रारंभ कर देना चाहिए। यदि इकाई प्रारंभिक 2 वर्षों की वैधता-अवधि में उत्पादन प्रारंभ करने में असमर्थ है तो विकास आयुक्त द्वारा लिखित में वैध कारणों का उल्लेख करते हुए एक वर्ष का अतिरिक्त समय दिया जा सकता है। तदोपरान्त इकाई अनुमोदन समिति द्वारा एक वर्ष का अतिरिक्त समय दिया जा सकता है बशर्ते इकाई को स्थापित करने से संबंधित निर्माण सहित दो तिहाई कार्यकलाप पूरे किए गए हों तथा इस संबंध में इकाई द्वारा सनदी अभियंता का प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाए। इसके आगे अतिरिक्त समय यदि आवश्यक हो, अनुमोदन बोर्ड द्वारा प्रदान किया जाएगा। एक बार इकाई द्वारा उत्पादन शुरू करने पर इसके कार्यकलापों हेतु जारी किया गया अनुमति पत्र (एलओपी)/एलओआई (आशय पत्र) 5 वर्षों की अवधि के लिए मान्य होगा। इस अवधि को विकास आयुक्त द्वारा एक बार में 5 वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है।

(ग) औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता वाले ई ओ यू स्थापित करने के प्रस्तावों को अनुमोदन बोर्ड (परिशिष्ट एवं आयात निर्यात प्रपत्रों के **परिशिष्ट 6ग** के अनुसार) और औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग द्वारा गुण-दोष के आधार पर 45 दिनों के भीतर विकास आयुक्त द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाएगा।

(घ) साफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क/इलैक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क काम्प्लेक्सों को केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, सार्वजनिक अथवा निजी क्षेत्र के उपक्रमों अथवा उनके किसी संयोजन द्वारा स्थापित किया जा सकता है जो संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग- डीईआईटीवाई) की अन्तर मंत्रालयी स्थायी समिति (आईएमएससी) द्वारा विधिवत अनुमोदित होगा। ईएचटीपी/एसटीपी यूनिट स्थापित करने हेतु आवेदन इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में होगा तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा नामित अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा।

(ङ.) बीटीपी यूनिट केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, सार्वजनिक अथवा निजी क्षेत्र के उपक्रमों अथवा इनके किसी भी संयोजन द्वारा स्थापित किया जा सकता है। बीटीपी स्थापित करने हेतु आवेदन जैव प्रौद्योगिकी विभाग को प्रस्तुत करना होगा और ऐसे आवेदन जो जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों को पूरे करते हों उन्हें अनुमोदित किया जाएगा और डीजीएफटी को अधिसूचना हेतु संस्तुत किया जाएगा। बीटीपी यूनिट को स्थापित करने हेतु आवेदन जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा नामित अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा।

(च) तैयार माल, उप-उत्पाद और डीटीए में अपशिष्ट की बिक्री तथा ऐसे अन्य मामले जो आवश्यक हों, के संबंध में एलओपी/एल ओ आई में विनिर्माण मर्दे/सेवा गतिविधियों, वार्षिक क्षमता, डालरों में प्रथम पांच वर्षों के लिए अपेक्षित वार्षिक निर्यात, निवल विदेशी मुद्रा अर्जन (एनएफई) सीमाओं यदि कोई हो, का उल्लेख होगा और ऐसी शर्तें भी होंगी जो अपेक्षित हों।

(छ) संबंधित प्राधिकारी द्वारा ईओयू/ ईएचटीपी/ एसटीपी/ बीटीपी यूनिटों को जारी एलओपी/एलओआई सभी उद्देश्यों हेतु प्राधिकार पत्र माने जाएंगे। ईओयू हेतु एलओपी का मानक प्रपत्र परिशिष्ट एवं आयात निर्यात प्रपत्र के **परिशिष्ट 6घ** में दिया गया है।

(ज) ई ओ यू के पास अलग एल ओ पी हेतु अलग निर्धारित परिसर होंगे। इसी प्रकार, ईओयू लीज्ड परिसरों पर अनुमोदित की जा सकती है बशर्ते कि लीज सरकारी विभाग/उपक्रम/ एजेंसी से प्राप्त की गयी हो। तथापि, यदि लीज निजी पक्षों से प्राप्त की गयी हो, तो इसकी वैधता एल्यूटी की तारीख से 5 वर्षों की अवधि होगी तथा विकास आयुक्त लीज की वास्तविकता के बारे में स्वयं को संतुष्ट करेगा।

(झ) विदेश व्यापार नीति के पैरा 6.05 में उल्लिखित अनुमोदन अवधि के पूरा होने पर, स्कीम में बने रहने अथवा उससे बाहर चले जाने का विकल्प यूनिट के पास होगा। जहाँ यूनिटें जारी रहने का विकल्प चुनती है, तो विकास आयुक्त अनुमोदन अवधि को बढ़ा देगा। यदि अनुमोदन अवधि समाप्त होने के छह महीनों की अवधि के भीतर यूनिट से कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है तो विकास आयुक्त ई ओ यू स्कीम के अन्तर्गत अनुमोदन को स्वयं रद्द करने की कार्रवाई करेगा और इस संबंध में आगे कार्रवाई करेगा। जहाँ इकाईयों उपर्युक्त निर्धारित 6 माह की अवधि के समाप्त होने के पश्चात् कार्य जारी रखने का विकल्प चुनती है तो विकास आयुक्त बी और ए के अनुमोदन से अवधि को बढ़ा देगा।

6.02 विधिक वचनबद्धता(एल्यूटी)

(क) अनुमोदित ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी यूनिट परिशिष्ट एवं आयात निर्यात प्रपत्र के परिशिष्ट 6ड. में उल्लिखित प्रपत्र के अनुसार संबंधित विकास आयुक्त/नामित अधिकारी को विधिक वचनबद्धता प्रस्तुत करेगी।

(ख) सभी ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी यूनिटों का स्थायी ई-मेल पता होना चाहिए। स्थायी ई-मेल पता तथा उपरोक्त ई-मेल आई डी पर डिजिटल हस्ताक्षर न होने की स्थिति में नई यूनिटों हेतु कोई विधिक वचनबद्धता निष्पादित नहीं की जाएगी। ईओयू का स्थायी ई-मेल पता तथा डिजिटल हस्ताक्षर न होने की स्थिति में आगे आयात और डीटीए बिक्री की विकास आयुक्त द्वारा अनुमति नहीं दी जाएगी।

6.03 माल और सेवाओं का निर्यात

(क) सॉफ्टवेयर यूनिटें, पेशेवर सेवाओं के निर्यात समेत डाटासंचार लिंकों का इस्तेमाल करते हुए अथवा वास्तविक निर्यात के रूप में (जो कूरियर सेवा के माध्यम से भी हो सकता है) निर्यात कर सकती हैं।

(ख) ईओयू को नामित एजेंसी द्वारा जारी नोशनल रेट सर्टीफिकेट के आधार पर आभूषणों का निर्यात करने की अनुमति होगी। यह रेट नोशनल रेट सर्टीफिकेट में प्रचलित स्वर्ण/अमेरिकी डालर दर और अमेरिकी डालर/भारतीय रुपया दर पर आधारित होगा। नामित एजेंसी द्वारा जारी सर्टीफिकेट पोत लदान की तारीख के 7 कार्य दिवसों से पहले का नहीं होना चाहिए।

(ग) निर्यातक को निर्यात करने की तारीख से 180 दिन के भीतर स्वर्ण का मूल्य निर्धारित करने और स्वर्ण ऋण चुकाने की छूट होगी। नामित एजेंसियों को मूल्य की सूचनाएं दी जाएगी जो प्रमाणपत्र जारी करेंगी, जिसमें निर्यात आय की प्राप्ति इस दर पर सुनिश्चित करने हेतु दस्तावेज तैयार करने वाले बैंक की दर की अन्तिम पुष्टि दर्शाई गई हो।

(घ) रत्न और आभूषण तथा आभूषण ईओयू आयातित माल का पुनः निर्यात और घरेलू तौर पर खरीदे माल का निर्यात कर सकती हैं जिसमें आंशिक संसाधन/विनिर्माण से पैदा हुई वस्तुएँ शामिल हैं। इसके अलावा, उपयुक्त शुल्क का भुगतान करके यथा लागू वैध रत्न एवं आभूषण प्रतिपूर्ति के मद्दे डीटीए में आयातित अथवा स्वदेशी तौर पर खरीदे माल के मूल्य के 5% तक अनुपयुक्त/टूटे, कटे और पालिश किए गए हीरों, कीमती और अर्ध-कीमती रत्नों की आपूर्ति भी अनुमत होगी।

6.04 माल का आयात/घरेलू खरीद

घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र से निम्नलिखित पूँजीगत माल के आयात/ खरीद की अनुमति होगी:—

(क) कच्चा माल, संघटक, उपभोज्य, अन्तर्वर्ती, कल-पुर्जे और पैकिंग सामग्री;

(ख) पूँजीगत माल, चाहे नया हो या पुराना हो, जिसमें अन्य बातों के साथ निम्नलिखित और उनके कल-पुर्जे हों:

1. डी जी सैट्स, कैपटिव पावर प्लांट्स, ट्रांसफार्मर्स तथा उपरोक्त सभी के लिए सहायक उपकरण।
2. प्रदूषण नियंत्रण उपकरण।
3. गुणवत्ता गारंटी उपकरण।
4. सामग्री प्रबंधन उपकरण जैसे फोर्क लिफ्ट्स तथा ओवरहैड क्रेन्स, मोबाइल क्रेन्स, कालर क्रेन्स, हाएस्ट्स और स्टैकर्स
5. अबाधित बिजली आपूर्ति प्रणाली (यूपीएस) संचयन के लिए विशेष बैक्स, संचयन प्रणाली, मोडयूलर फर्नीचर, कम्प्यूटर फर्नीचर, एंटी स्टैटिक कारपेट, टेलीकन्फ्रेंस उपकरण, सर्वो कन्ट्रोल प्रणाली, एयर-कंडीशनर्स, एयरकंडीशनिंग सिस्टम, विद्युत उपकरण के लिए पैनल और स्पेशल डाटा ट्रांसमीशन केबल।

6. सुरक्षा प्रणालियाँ।

7. टूल्स, जिग्स, फिक्सचर्स, गेजेज, मोल्ड्स, डाइज, उपकरण तथा अनुांगिक मर्दे।

(ग) यूनिट के भीतर उपयोग हेतु पूँजीगत माल बनाने के लिए कच्चा माल।

(घ) अन्य जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं-

1. मौजूदा उत्पाद (उत्पादों) हेतु प्रोटोटाइप तथा तकनीकी नमूने तथा उत्पाद विविधीकरण, विकास अथवा मूल्यांकन।
2. ड्राइंग्स, ब्लू प्रिन्ट्स, चार्ट्स, माइक्रो फिल्म और तकनीकी डाटा।
3. पीएबीएक्स, फैक्स मशीनें, प्रोजेक्शन प्रणाली, कम्प्यूटर्स, लैपटॉप, सर्वर सहित कार्यालय उपकरण।

(ङ) उक्त मर्दों के लिए कल-पुर्जे तथा उपभोज्य।

(च) अनुमोदन बोर्ड के अनुमोदन से अन्य कोई मद जो ऊपर उल्लिखित न हो ।

6.05 आभूषणकी मरम्मत/पुनर्निर्माण

ईओयू, मरम्मत/पुनर्निर्माण के बाद निर्यात हेतु सादा/जड़ित स्वर्ण/ प्लेटिनम अथवा चाँदी आभूषणों का आयात कर सकती है।

6.06 आयात की शर्तें

ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी द्वारा माल का आयात निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:-

(क) माल का ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बी टी पी परिसरों में आयात किया जाएगा। तथापि, ईओयू में कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों और ग्रेनाइट क्षेत्र के एकक क्षेत्राधिकार में आने वाले सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों को पहले ही सूचित करके फार्मों/फील्डों/खदानों में पूँजीगत वस्तुओं और निविष्टियों की आपूर्ति/हस्तांतरण कर सकते हैं बशर्ते माल का स्वामित्व ईओयू एकक का हो। ग्रेनाइट सैक्टर को खदान स्थल को पूँजीगत माल के मूल्य के 5 प्रतिशत तक हिस्से पूर्जों को ले जाने की भी अनुमति होगी।

(ख) निर्यात अभिमुख एककों और ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी की एककों के लिए सीमा शुल्क/केन्द्रीय उत्पाद शुल्क संबंधी नियमों के अधीन यथा निर्धारित प्रक्रिया अपनाई जायेगी तथा सीमा शुल्क/केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों के साथ समुचित बांड निष्पादित किया जाएगा।

(ग) (i) पूँजीगत माल सहित वस्तुओं के उपयोग की अवधि एलओपी की वैधता की सहमियादी होगी।

(ii) तथापि, आयातित चाय का इस्तेमाल आयात की तारीख से छः महीने की अवधि के भीतर करना होगा। इसी प्रकार, मर्दों (आई.टी.सी. (एचएस) के अध्याय-9 के अन्तर्गत शामिल) के आयात के मर्दे निर्यात दायित्व और नारियल तेल की प्रतिपूर्ति सीमा शुल्क प्राधिकारी द्वारा आयात की प्रथम खेप की निकासी दिए जाने की तारीख से 90 दिन के भीतर करना होगा।

(iii) इसके अतिरिक्त, वीए प्रयोजन जैसे क्रशिंग/ग्राइंडिंग/स्टेरेलाइजेशन अथवा मिर्च, छोटी इलायची और लाल मिर्चों के तेल (और सिर्फ साफ करने, ग्रेडिंग और रिपैकेजिंग आदि के लिए नहीं) और ओलियोरेजिन के विनिर्माण के लिए मसालों के आयात के मामले में, निर्यात दायित्व पहली खेप के आयात की तारीख से 120 दिन के भीतर पूरा किया जाएगा। मसालों के आयात के मामले में (काली मिर्च, इलायची, लाल मिर्च को छोड़कर) मसाला तेलों और ओलियोरेसिन के विनिर्माण हेतु निर्यात दायित्व 12 महीनों के भीतर पूरा करना होगा।

(घ) अनुमति पत्र/आशय पत्र जारी किये जाने से पूर्व आयातित/जहाज से भेजी गई/पहुँच चुकी वस्तुएँ ईओयू/ ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी स्कीम के तहत शुल्क मुक्त निकासी हेतु पात्र होंगी बशर्ते सीमा-शुल्क का भुगतान न किया गया हो और वस्तुओं की सीमाशुल्क प्राधिकारी से निकासी न कराई गई हो।

(ङ.) ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी यूनिट द्वारा निविष्टियों की खपत मानक निविष्टि उत्पादन मानदण्ड (सियॉन) पर आधारित होगी बशर्ते कि:

(i) जहाँ सियॉन को अधिसूचित नहीं किया गया है, अवशिष्ट, स्क्रेप और रैमनेन्ट्स निवेश की मात्रा के 2 प्रतिशत तक होगी:

(ii) जहाँ सियॉन में दी गई मर्दों को छोड़ कर अतिरिक्त मर्दे निवेशों के रूप में अपेक्षित है अथवा जहाँ अपशिष्ट, स्क्रेप और रैमनेन्ट्स निवेश की मात्रा से 2 प्रतिशत अधिक है, ऐसे निवेशों के प्रयोग की अनुमति की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर और स्व घोषित मानदण्ड के आधार पर क्षेत्रीय निर्यात आयुक्त द्वारा होगी और विदेश व्यापार

महानिदेशालय में मानदण्ड समिति द्वारा अंतिम रूप से निर्धारित मानदण्डों के अनुसार यूनिट द्वारा स्व घोषित/तदर्थ मानदण्डों पर वचनबद्धता दी जाएगी।

(iii) यथोपरोक्त सियॉन के निर्धारण में कठिनाई के मामले में, अनुमोदन बोर्ड विदेश व्यापार महानिदेशालय में मानदण्ड समिति के साथ विचार विमर्श करके मामला दर मामला निर्णय करेगा।

6.07 अनुमोदित परिसरों के बाहर फ़ैक्स मशीनें/ लैपटॉप/कम्प्यूटर को ले जाना

(क) ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी यूनिट इकाई के परिसर के बाहर, अपनी पसंद के स्थान पर एक फ़ैक्स मशीन लगा सकते हैं बशर्ते कि इसके कार्य स्थल के बारे में सीमा शुल्क/ केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों को सूचित किया जाएगा।

(ख) ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी यूनिट शुल्क तथा/अथवा कर मुक्त लैपटॉप/कम्प्यूटर और वीडियो प्रोजेक्शन सिस्टम को अस्थायी रूप से इकाई परिसर के बाहर ले जा सकते हैं ताकि इन पर प्राधिकृत कर्मचारी कार्य कर सकें।

(ग) ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी यूनिटें अपने पंजीकृत/प्रशासनिक कार्यालय में राजस्व विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार शुल्क तथा/अथवा कर मुक्त आयातित/प्राप्त निजी कम्प्यूटर, जो दो से ज्यादा न हों, लगा सकते हैं।

(घ) सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं के लिए सॉफ्टवेयर यूनिटों द्वारा प्राधिकृत सूचना व्यक्ति संचार लिंकों के माध्यम से ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी यूनिट में स्थापित सुविधा का लाभ ले सकते हैं।

6.08 यूनिट से बाहर के स्थान पर कार्य करने की सुविधा

(i) आईटी से संबंधित ईओयू अथवा (ii) एसटीपी अथवा (iii) ईएचटीपी अथवा (iv) बीटीपी की यूनिटों के व्यक्ति (व्यक्तियों)/ कर्मचारी (कर्मचारियों) निम्नलिखित शर्तों के अधीन उक्त यूनिट से बाहर के स्थान पर कार्य कर सकते हैं:

(i) यूनिट द्वारा ऐसे प्राधिकार-पत्र की अवधि को दर्शाते हुए प्राधिकार-पत्र होना चाहिए।

(ii) कार्य और निरीक्षण करने का उत्तरदायित्व, यदि कोई है चाहे वह यूनिट का हो, जो किसी दुरुपयोग के लिए उत्तरदायी होगा।

(iii) परिणामी उत्पादों/सेवाओं का निर्यात केवल यूनिट के परिसर से किया जाएगा।

6.09 पूँजीगत माल की लीजिंग

लीजिंग कम्पनियों के माध्यम से वित्तपोषित अथवा मुफ्त प्राप्त और/अथवा ऋण/लीज आधार पर आयातित पूँजीगत माल के मूल्य को भी विदेश व्यापार नीति में यथा परिभाषित निवल विदेशी मुद्रा के परिकलन के उद्देश्य हेतु ध्यान में रखा जाएगा।

6.10 निवल विदेशी मुद्रा (एन एफ ई) अर्जन

(क) ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी यूनिटें निवल विदेशी मुद्रा अर्जक होंगी। निवल विदेशी मुद्रा की संगणना विदेश व्यापार नीति के पैरा 6.04 के अनुसार खण्ड अवधि में संचयी आधार पर निम्नलिखित फार्मूला के अनुसार की जाएगी। केवल अनुज्ञापत्र/ आशयपत्र में विनिर्दिष्ट निर्यात हेतु विनिर्माण की मदें निवल विदेशी मुद्रा की संगणना हेतु ध्यान में रखी जाएंगी।

सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा अर्जन (एन एफ ई) =

'ए' - बी > 0

जहाँ

'एनएफई' निवल विदेशी मुद्रा है;

'ए' ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी यूनिट के निर्यात का पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य है;

'बी' सभी आयातित निविष्टियों का लागत बीमा भाड़ा मूल्य, सभी आयातित पूँजीगत माल का लागत बीमा भाड़ा मूल्य और प्रथम पाँच वर्षों के दौरान कमीशन, रायल्टी, शुल्क, लाभांश, विदेशी उधार पर ब्याज/खुले समुद्र में बिक्री के माध्यम से विदेशी मुद्रा में किए गए सभी भुगतान का मूल्य या किसी अन्य प्रभार का समग्र योग है। इसमें खुले समुद्र पर भारतीय रूपये में किया गया भुगतान भी शामिल होगा।

"निविष्टि" का तात्पर्य कच्चे माल, अन्तर्वर्ती, संघटक, उपभोज्य, कलपुर्ज और पैकिंग सामग्री से है।

(ख) यदि कोई माल अन्य ईओयू/ईएचटीपी/ एसटीपी/ बीटीपी/ एसईजैड यूनिट या भारत में आयोजित अन्तराष्ट्रीय प्रदर्शनियों या बाँडेड गोदामों से या बहुमूल्य धातुएं नामित एजेंसियों से प्राप्त है तो ऐसी वस्तुओं का मूल्य 'बी' के अधीन शामिल किया जाएगा।

(ग) यदि किसी लीजिंग कम्पनी से किसी पूँजीगत माल का शुल्क तथा/अथवा कर मुक्त आयात किया जाता है/अथवा लीज किया जाता है, मुफ्त और/अथवा ऋण आधार पर या हस्तांतरण आधार पर प्राप्त किया जाता है तो पूँजीगत माल के लागत बीमा भाड़ा मूल्य को जब तब ये उसके पास रहता है, 'बी' के अधीन यथानुपात शामिल किया जाएगा।

(घ) निवल विदेशी मुद्रा की वार्षिक संगणना के लिए, आयातित पूँजीगत माल का मूल्य और विदेशी तकनीकी जानकारी शुल्क का एकमुश्त भुगतान निम्नानुसार प्राधिकृत किया जाएगा:

प्रथम - दसवां वर्ष = 10 प्रतिशत।

बशर्ते कि उपर्युक्त परिशोधन दरें तभी लागू होंगी जब यूनिट द्वारा यह वचनबद्धता दी जाये कि वह पहले दस वर्ष में डीटीए से बाहर नहीं जाएगी। मौजूदा यूनिटों हेतु, बाहर जाने से पूर्व, अनुपातिक सीमाशुल्क और उत्पाद शुल्क देना होगा जहाँ पहले से दावित मूल्य हास की तुलना में निवल विदेशी मुद्रा कम है।

6.11 खातों का रखरखाव

(क) ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी यूनिट अपने खातों को ठीक ढंग से रखेगी और परिशिष्टों और एएनएफ के अनुलग्नक और परिशिष्ट 6ड. में यथानिर्धारित नियमों के अनुसार विकास आयुक्त/प्रौद्योगिकी विभाग/जैव प्रौद्योगिकी विभाग के नामित अधिकारी तथा सीमाशुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों को डिजिटल हस्ताक्षरित तिमाही और वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

(ख) यूनिट, डीटीए में निर्यात, बिक्री/आपूर्ति या अन्य एसईजैड/ ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/ बीटीपी यूनिटों को हस्तांतरित और अपने स्टॉक के शेष माल के माध्यम से सुसंगत मालों के प्रत्येक श्रेणी के शुल्क तथा/अथवा कर मुक्त आयात/प्राप्त माल की कुल मात्रा का हिसाब लगा सकेगी। तथापि, किसी भी समय यूनिटों को अपने निर्यातों के साथ प्रत्येक आयात खेप को सम्बद्ध करने, अन्य एसईजैड/ईओयू/ ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी यूनिटों को हस्तान्तरण करने, डीटीए में बिक्री करने और शेष वस्तुओं को स्टॉक में रखना अपेक्षित है। माल एकरूप है या नहीं उसके बारे में निर्णय यूनिट अनुमोदन समिति द्वारा लिया जाएगा।

6.12 निवल विदेशी मुद्रा की निगरानी

परिशिष्टों और एएनएफ के परिशिष्ट 6च में उल्लिखित दिशा निर्देशों के अनुसार यूनिट अनुमोदन समिति द्वारा ईओयू के निष्पादन की निगरानी की जाएगी। ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी यूनिटों के निष्पादन की निगरानी सूचना प्रौद्योगिकी विभाग/जैव प्रौद्योगिकी विभाग, केन्द्रीय उत्पाद/ सीमाशुल्क प्राधिकारी के साथ संयुक्त रूप से करेगा।

6.13 स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम के स्क्रेप/डस्ट/ स्वीपिंग का मानक छड़ों में परिवर्तन

स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम के स्क्रेप/डस्ट/स्वीपिंग ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी यूनिट से गर्वमेंट ऑफ इण्डिया मिण्ट/प्राइवेट मिण्ट को भेजी जा सकती है और सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार इन्हें मानक छड़ों के रूप में लौटाया जा सकता है अथवा सीमाशुल्क प्राधिकरण द्वारा यथा अधिसूचित स्वर्ण/ चाँदी/ प्लेटिनम अंश के आधार पर लागू निविष्टियों पर छूट के रूप में प्राप्त सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम 1975 की प्रथम अनुसूची के अंतर्गत लगाए जाने वाले सीमा शुल्क के रिवर्सल सहित जीएसटी और प्रतिपूर्ति उपकर के भुगतान पर डीटीए में बेचने की अनुमति दी जा सकती है।

6.14 डीटीए आपूर्तियाँ

विदेश व्यापार नीति के पैरा 6.08 में डी टी ए बिक्री के प्रावधान के बावजूद डी टी ए बिक्री उस समय लागू आयात को प्रभावित करने वाले किसी प्रतिबंध अथवा विनियमन के किसी माल के अनुप्रयोग को प्रभावित नहीं करेगा जब ऐसी वस्तुओं का आयात किया गया है। आयातक को कानूनों अथवा नियमों के तहत किन्ही आवश्यकताओं के मद्दे प्रतिबद्धता अथवा अनुपालन से किसी प्रकार की छूट अथवा रियायत भी प्राप्त नहीं होगी।

6.15 अन्य ईओयू/ईएच टीपी/ एसटीपी/एसईजैड/बीटी पी यूनिटों को आपूर्तियाँ

अन्य ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/एसईजैड/बीटीपी/एसईजैड यूनिटों को आपूर्तियाँ निवल विदेशी मुद्रा के लिए गिनी जाएगी बशर्ते कि ऐसा माल इन यूनिटों द्वारा प्राप्ति के लिए अनुमत हो।

6.16 एक एकक से दूसरे एकक को विद्युत का हस्तांतरण

एक ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी यूनिट से दूसरे ईओयू/ ईएचटीपी/एसटीपी/एसईजैड यूनिट को कैपटिव पावर प्लान्टों (डीजी सैट) से विद्युत का हस्तांतरण परिशिष्टों और एएनएफ के परिशिष्ट 6ख में क्षेत्र विशिष्ट शर्त में विनिर्दिष्ट अनुसार अनुमत होगी।

6.17 डीटीए से बहुमूल्य /अर्ध बहुमूल्य/ सिंथेटिक पत्थरों की आपूर्ति

डीटीए से ईओयू को बहुमूल्य और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों, सिंथेटिक पत्थरों और संसाधित मोतियों के आपूर्तिकर्ता प्रक्रिया पुस्तक में उल्लिखित मदों और दरों पर प्रतिपूर्ति प्राधिकार पत्र पाने के पात्र होंगे। प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के सम्बद्ध अध्याय में यथा निहित प्रतिपूर्ति प्राधिकार पत्र की मंजूरी के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया लागू होगी। तथापि, आवेदन संबंधित विकास आयुक्त को प्रस्तुत किया जाए। विदेश व्यापार नीति 2015-20 के अध्याय-7 के तहत ईओयू को की गई ऐसी आपूर्तियों को किसी मान्य निर्यात लाभ के लिए पात्र नहीं माना जाएगा।

6.18 हकदारियों की मंजूरी के लिए आवेदन पत्र

सभी हकदारियों की मंजूरी के लिए आवेदन संबंधित विकास आयुक्त को प्रस्तुत किया जाए।

6.19 अन्य निर्यातकों के जरिए निर्यात

कोई निर्यात अभिमुख यूनिट/इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क/सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क/ बीटीपी की यूनिट अपने विनिर्मित माल/इसके द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर का निर्यात किसी निर्यातक या किसी अन्य निर्यात अभिमुख यूनिट/ इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क/सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क/बीटीपी/एसईजेड यूनिट के जरिये निम्नलिखित शर्तों के अधीन किया जा सकता है:-

- (क) माल संबंधित ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी यूनिट में तैयार किया जाएगा।
- (ख) निवल विदेशी मुद्रा का स्तर अथवा यथानिर्धारित आयातों और निर्यातों से संबंधित अन्य शर्तें संबंधित ईओयू/ ईएचटीपी/ एसटीपी/बीटीपी यूनिट द्वारा पालन की जाएगी।
- (ग) इस प्रकार प्राप्त निर्यात आदेश ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी स्कीमों के मानदण्डों के अन्तर्गत ही निर्यात किए जाएंगे और माल यूनिट से सीधे ही पोत लदान के पत्तन पर भेज दिया जाएगा।
- घ) ऐसे निर्यात के संबंध में ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी यूनिटों द्वारा एन एफ ई को पूरा करने के लिए अन्य ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी/एस ई जेड यूनिट या अन्य निर्यातक को ई ओ यू द्वारा जिस मूल्य पर आपूर्ति की गई है, के आधार पर गणना की जाएगी।
- ड.) सभी निर्यात हकदारियाँ जिसमें स्तरधारक की मान्यता भी शामिल है, निर्यातक के खाते में जोड़े जाएंगे जिसके नाम से विदेशी मुद्रा की प्राप्ति हुई है। तथापि, ऐसा निर्यात ई ओ यू/ ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी स्कीम के अन्तर्गत दायित्व को पूरा करने के लिए गिना जाएगा।

6.20 अन्य हकदारियाँ

(क) निर्यात सदन और व्यापार सदन स्तर प्रदान करने के लिए ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी यूनिट डी टी ए में मूल कंपनी अथवा विलोमतः के निर्यात के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के साथ निर्यात के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य को मिला दिया जाएगा।

(ख) भारत सरकार द्वारा यथा अधिसूचित क्षेत्रीय मानदण्ड सेवा गतिविधियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर लागू होंगे।

(ग) प्रशिक्षण प्रयोजन (जिसमें वाणिज्यिक प्रशिक्षण शामिल है) के लिए एसटीपी इकाईयां/ईएचटीपी इकाईयां/सॉफ्टवेयर ईओयू भी सभी शुल्क तथा/अथवा कर मुक्त उपस्कर/वस्तुओं का उपयोग कर सकती हैं बशर्ते कि इस प्रयोजन के लिए परिसर से बाहर कोई शुल्क तथा/अथवा कर मुक्त उपस्कर/वस्तुएं संस्थापित न हों।

(घ) लौह अयस्क का निर्यात भारत सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के अधीन होगा। आई टी सी (एचएस) के अनुसार निर्यात की अन्य शर्तें जैसे न्यूनतम निर्यात मूल्य/ उपभोक्ता पैक आदि में निर्यात की अपेक्षा डीटीए से खरीदे गए कच्चे माल और ईओयू द्वारा प्रसंस्करण/ विनिर्माण के बिना निर्यात के मामले में लागू होगी। वस्त्र मदों का निर्यात द्विपक्षीय समझौते के अन्तर्गत आएगा। काँठ आधारित एककों को इमारती लकड़ी/अन्य काँठ के उपयोग के संबंध में 1996 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 171 टी.एन. गोडावर्मन थिस्मुलपाद बनाम भारत सरकार और अन्य 1995 की रिट सिविल) संख्या 202 में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 12.12.1996 के आदेश में दिए गए निदेशों का अनुपालन करना होगा।

6.21 उप ठेका

(क) अन्य ईओयू या एसईजेड यूनिटों अथवा डीटीए में यूनिटों के माध्यम से ईओयू रत्न और आभूषणयूनिटों द्वारा उप-ठेका निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिया जाएगा :-

- (i) उप ठेके पर दिया गया तैयार या अर्ध तैयार माल, जिसमें जड़ित आभूषण भी शामिल हैं, को 90 दिनों के भीतर यूनिट में वापस लाना होगा।

- (ii) किसी कटे और पालिश किए हीरों, बहुमूल्य और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों (बहुमूल्य, अर्द्धबहुमूल्य और सिंथेटिक पत्थर, जिनपर शून्य शुल्क हो, को छोड़कर) उप-ठेके पर देने की अनुमति नहीं होगी।
- (iii) डीटीए/ईओयू/एसईजैड यूनिटों से सादे स्वर्ण/चाँदी/ प्लेटिनम की बराबर मात्रा के बदले प्राप्त उक्त आभूषणमें शामिल स्वर्ण/चाँदी/ प्लेटिनम के आभूषण, जैसा भी मामला हो।
- (iv) ईओयू प्रक्रिया पुस्तक के पैरा-4.60 के अनुसार उप ठेके हेतु अदला-बदली के मद्दे यथा लागू छीजन के लिए पात्र होगा।
- (v) विदेश व्यापार नीति के अध्याय 7 के तहत डीटीए यूनिट जो स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम के बदले में जॉब कार्य या आभूषणआपूर्ति का कार्य करती है, वह मान्य निर्यात लाभों की पात्र नहीं होगी।
- (ख) डीटीए यूनिट से जॉब वर्क करवाने की सुविधा उपलब्ध होगी बशर्ते जॉबवर्क पूरा होने पर वस्तुओं को यूनिट के परिसर में वापस लाया जाए।
- (ग) जॉब वर्कर के परिसर से तैयार माल के निर्यात की अनुमति होगी बशर्ते कि ऐसे परिसर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/जीएसटी प्राधिकारियों के साथ पंजीकृत हों। जहाँ जॉब वर्कर एसईजैड/ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी यूनिट है, वहाँ निर्यात या तो जॉब वर्कर के परिसर अथवा यूनिट के परिसरों से किया जा सकता है। जॉब वर्कर के परिसर से ऐसे उत्पादों के तृतीय पार्टी के माध्यम से निर्यात करने की अनुमति नहीं होगी जैसा कि विदेश व्यापार नीति में उल्लेख किया गया है।
- (घ) ईओयू को उप ठेकेदारों के परिसर से मोल्ड्स, जिग्स, टूल्स, फिक्चर्स, टेकल्स, उपकरण, हैंगर्स और पैटर्न और ड्राइंग को हटाने की अनुमति होगी बशर्ते कि इन्हें निर्धारित अवधि के भीतर जॉब कार्य पूरा होने पर यूनिट के परिसर में वापस लाया जाए। इस माल के साथ कच्चा माल भेजा अथवा नहीं भी भेजा जा सकता है।
- (ड.) विदेश में उत्पादन प्रक्रिया के उपठेके के मामले में माल का उपठेकेदार के परिसर से निर्यात किया जा सकता है बशर्ते कि माल की निकासी के समय, ईओयू/ईएचटीपी/बीटीपी/एसटीपी यूनिट (i) विदेश में उप-ठेकेदार के परिसर से निकासी किए जाने वाले तैयार माल की सौदा लागत; (ii) विदेश में उप-ठेकेदार को भुगतान किए गए जॉब वर्क प्रभारों; और (iii) अन्तर्वर्ती माल के मूल्य की घोषणा करेगी; इसके साथ दस्तावेज अर्थात (क) तैयार माल का बिक्री मूल्य कांट्रेक्ट/अथवा बीजक (ख) जॉब वर्क कांट्रेक्ट और (ग) अन्तर्वर्ती माल का मूल्य आंकने का आधार भी प्रस्तुत करना होगा। ईओयू/ईएचटीपी/बीटीपी/एसटीपी यूनिट घोषित विदेशी मुद्रा की पूरी वापसी भी सुनिश्चित करेगी जो उपठेकेदार के विदेशी परिसर से तैयार माल के सौदा लागत मूल्य के रूप में होगी।

6.22 ठेका कृषि

कृषि/बागवानी/जलकृषि उत्पादों के उत्पादन/संसाधन में संलग्न ई ओ यू सीमाशुल्क प्राधिकारियों से वार्षिक अनुमति के आधार पर निम्नलिखित शर्तों के मद्दे डीटीए फार्म से उपकरण और साजो सामान निकाल सकती है (परिशिष्ट 6अ के अनुलग्नक और एएनएफ में विनिर्दिष्ट):-

- (क) ठेके फार्मों से ईओयू द्वारा निविष्टियों की आपूर्ति विदेश व्यापार महानिदेशालय/अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदित निविष्टि-उत्पादन मानदंडों के मद्दे होगी।
- (ख) ईओयू और डीटीए किसान (किसानों) के बीच ठेका कृषि समझौता होगा।
- (ग) ईकाई, कृषि/बागवानी/जलकृषि उत्पादों के निर्यात में कम से कम दो वर्षों के लिए संलग्न रहनी चाहिए, अन्यथा उस यूनिट को सीमाशुल्क/केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के उप/सहायक आयुक्त के पास बाहर ले जाने वाले पूंजीगत माल/निविष्टियों के लिए छोड़े गए शुल्क तथा/अथवा कर के बराबर बैंक गारंटी प्रस्तुत करनी होगी, जब तक यूनिट दो वर्ष पूरे न कर लें।

6.23 प्रदर्शनियों के माध्यम से निर्यात/निर्यात संवर्धन दौरे

ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी यूनिटें विकास आयुक्त की अनुमति से विदेशों में प्रदर्शनियाँ आयोजित करने/प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन माल का निर्यात कर सकती है:-

- (क) यूनिट, सीमाशुल्क प्राधिकारियों को मूल पत्र या इसकी प्रमाणित प्रति जिसमें विकास आयुक्त का अनुमोदन हो, प्रस्तुत करेगा। रत्न और आभूषण मर्दों के लिए, उत्पाद की एक स्व प्रमाणित फोटोप्रति भी प्रस्तुत करनी होगी।
- (ख) पुनः आयात के मामले में, आगमन पर ऐसी मर्दों को, निकासी से पूर्व निर्यात दस्तावेजों के साथ प्रमाणित किया जाएगा।
- (ग) जिन मर्दें विदेश में बिक्री न की गई हों, प्रदर्शनी समाप्त होने के 60 दिनों के भीतर उनका पुनः आयात किया जाएगा। तथापि, यदि निर्यातक प्रथम प्रदर्शनी के बंद होने के 45 दिनों के भीतर एक से अधिक प्रदर्शनी में, भाग लेना चाहता है तो 60 दिनों की गणना प्रथम प्रदर्शनी के बंद होने की तारीख से की जाएगी। यू.एस.ए. में प्रदर्शनी के मामले में, समयावधि उल्लिखित

60 दिनों की बजाय 90 दिन होगी ।

(घ) वस्तुओं को व्यक्तिगत असबाब के रूप में ले जाने/विदेशों में प्रदर्शिनियों में भाग लेने के लिए ऐसे रत्नों और आभूषणों का मूल्य 5 मिलियन अमेरिकी डालर से अधिक नहीं होना चाहिए।

6.24 निर्यात संवर्धन दौरो के लिए रत्न एवं आभूषणों को व्यक्तिगत असबाब के रूप में ले जाना ।

ईओयू द्वारा निर्यात संवर्धन दौरो और विदेशों में अस्थायीप्रदर्शन/ बिक्री के लिए 1 मिलियन अमेरिकी डालर तक के स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम के आभूषणों, कटे और पॉलिश किए हुए हीरों, बहुमूल्य, अर्ध बहुमूल्य रत्नों, मनकों और नमूनों के रूप में सामग्री के व्यक्तिगत असबाब की निम्नलिखित शर्तों पर विकास आयुक्त के अनुमोदन से अनुमति होगी :-

(क) ईओयू सामान्य बैंकिंग चैनल के माध्यम से भेजने की तारीख से 45 दिनों के भीतर माल अथवा प्रत्यावर्तित बिक्री आय को वापस लाएगा ।

(ख) यूनिट देश छोड़ते समय ऐसे नमूनों के व्यक्तिगत असबाब की सीमाशुल्क को घोषणा करेगा और आवश्यक अनुमति प्राप्त करेगा ।

6.25 विदेशों में शोस्म/ शुल्क मुक्त दुकानों के माध्यम से निर्यात

विदेश में स्थापित अनुमत दुकानों या वितरकों/एजेंटों के शोस्म में प्रदर्शनी/बिक्री के लिए भी माल के निर्यात की अनुमति है । मर्दे जो 180 दिनों के भीतर विदेशों में नहीं बिकती उसका 45 दिनों में पुनः आयात किया जाएगा ।

6.26 अन्तराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर स्थित शोस्म /फुटकर दुकानों से बिक्री

ईओयू सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार माल की बिक्री के लिए अन्तराष्ट्रीय वायु-पत्तनों में शोस्म/फुटकर दुकान स्थापित कर सकते हैं। जो मद 60 दिनों के भीतर विदेशों में नहीं बिकती है उसे निर्यात किया जायेगा या संबंधित ईओयू को लौटा दिया जाएगा ।

6.27 आयात/ निर्यात पार्सलों को व्यक्तिगत असबाब, जिनमें विदेश जाने वाले यात्रियों का असबाब भी शामिल है, के रूप में ले जाना

(क) विदेश जाने वाले यात्रियों द्वारा आभूषणों के व्यक्तिगत असबाब के लिए ईओयू यूनिट द्वारा निर्यात के प्रमाण के तौर पर निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएँगे :-

(i) ईओयू द्वारा दाखिल की गई पोत लदान बिल की प्रति ।

(ii) विदेशी खरीददार द्वारा आगमन के समय सीमाशुल्क को प्रस्तुत मुद्रा घोषणा फार्म की एक प्रति।

(iii) बैंक से विदेशी मुद्रा वसूली प्राप्ति/नकदीकरण प्रमाणपत्र ।

(ख) इसके अलावा, विदेश जाने वाले यात्री के व्यक्तिगत असबाब पर स्वीकृति के प्रति दस्तावेज (डीए)/सुपुर्दगी पर भुगतान(सीओडी) आधार पर अनुमति होगी। ईओयू को निर्यात के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे :-

(i) पोतलदान बिल की प्रति;

(ii) निर्यात और प्राप्ति का बैंक प्रमाण पत्र ।

(ग) आयात पार्सलों के व्यक्तिगत रूप से ले जाने के लिए वहीं प्रक्रिया अपनायी जाएगी जो वायुभाड़ा द्वारा माल को आयात के लिए होती है इसमें वह पार्सल शामिल नहीं हैं जिसे ईओयू/विदेशी नागरिक द्वारा जाँच और निकासी के लिए सीमाशुल्क के पास लाया जाता है। इस संबंध में सीमा-शुल्क प्राधिकारियों द्वारा अनुदेशों का आवश्यक परिवर्तनों के साथ अनुसरण किया जाएगा ।

(घ) विदेश जाने वाले यात्रियों द्वारा पार्स को व्यक्तिगत समान के तौर पर ले जाने की अनुमति होगी यदि ग्राहक के स्थान पर निर्यातित माल की मरम्मत हेतु उनकी आवश्यकता हो । निर्यातों के प्रमाण के तौर पर निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे :

(i) निर्यातों हेतु सीमाशुल्क कार्यालय से अनुज्ञा पत्र ।

(ii) मूल्य सहित बीजक (भुगतान करने पर अथवा निःशुल्क) ।

6.28 आयातित/स्वदेशी माल का प्रतिस्थापन/मरम्मत

(क) यूनिट पूँजीगत माल की मरम्मत के लिए सीमा शुल्क प्राधिकारी की अनुमति से इसे विदेश भेज सकता है । इस प्रयोजन के

लिए किसी भी विदेशी मुद्रा में भुगतान करने की भी अनुमति होगी। तथापि, देश के भीतर मरम्मत के लिए पूंजीगत माल भेजने के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।

(ख) ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी यूनिटें अपने रिकार्ड के अनुसार और सीमा शुल्क प्राधिकारी की अनुमति से निम्नलिखित कार्य करेंगी :

- (i) मरम्मत/प्रतिस्थापन, जाँच या केलिब्रेशन तथा वापसी के लिए माल का डीटीए/विदेश में हस्तांतरण।
- (ii) माल की वापसी के लिए सीमाशुल्क प्राधिकारी को उपयुक्त बचनबद्धता देते हुए ऐसे मामलों में शुल्क तथा/अथवा कर का भुगतान किये बिना प्रतिवर्ष 5 लाख रु तक के माल का किसी मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला/ संस्थान को गुणवत्ता जाँच/अनुसंधान एवं विकास प्रयोजन के लिए हस्तांतरण किया जा सकता है। तथापि, यदि जाँच के दौरान माल का उपयोग कर लिया गया है/नष्ट हो जाता है तो इस आशय का एक प्रमाण पत्र प्रयोगशाला /संस्थान से सीमा शुल्क प्राधिकारी को प्रस्तुत करना होगा।

6.29 नमूने

- (क) ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी यूनिटें अपने रिकार्ड के आधार पर तथा सीमा शुल्क प्राधिकारियों को पूर्व सूचना देकर यदि लागू हो उत्पाद शुल्क का भुगतान तथा/अथवा यदि निविष्टियों पर लाभ प्राप्त करते हैं, सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम 1975 की प्रथम अनुसूची के अंतर्गत लगाए जाने वाले सीमा शुल्क के रिवर्सल सहित जीएसटी और प्रतिपूर्ति उपकर का भुगतान करने पर प्रदर्शन/बाजार संवर्धन हेतु डीटीए में नमूनों की आपूर्ति/विक्रय कर सकती हैं।
- (ख) एक निर्धारित अवधि के भीतर नमूनों की वापसी के लिए सीमा शुल्क प्राधिकारियों को एक उपयुक्त वचनबद्धता देकर शुल्क तथा/अथवा कर का भुगतान करने अथवा भुगतान किए बगैर नमूनों को हटाया जा सकता है।
- (ग) एक ईओयू कूरियर एजेंसियों/डाकघर के माध्यम से निर्यात के सभी अनुमत तरीकों से, किसी सीमा के बिना, मुफ्त नमूनों का निर्यात कर सकता है जिनमें वैक्स मोल्ड, सिल्वर मोल्ड और रबर मोल्ड के नमूने शामिल हैं। विनिर्माता के पास स्थायित्व और अवरोधन नमूने की सांविधिक आवश्यकता हेतु, ईओयू/ईएचटीपी/बीटीपी/एसटीपी यूनिट विदेश व्यापार नीति के पैरा 6.01(घ)(ii) के अनुसार शुल्क/कर का भुगतान करने अथवा इसके भुगतान के बिना पुनः आयात कर सकती हैं, जो इसके द्वारा निर्यात किए गए हैं, जिसकी सूचना सीमाशुल्क प्राधिकारियों को देनी होगी, तथा ऐसे नमूनों के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य की निवल विदेशी मुद्रा प्रयोजन हेतु गणना नहीं की जाएगी, यदि कोई हो।
- (घ) अपने पास रखे रिकार्डों के आधार पर और सीमाशुल्क प्राधिकारियों को पूर्व सूचना देकर कोई ई.ओ.यू. अन्य ई.ओ.यू. को 30 दिनों के भीतर वापसी आधार पर प्रदर्शन हेतु नमूने भेज सकता है।

6.30 कम्प्यूटर एवं कम्प्यूटर परिफेरल्स का दान

संबंधित प्राधिकारियों द्वारा ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी यूनिट को यह अनुमति दी गयी है कि वह आयातित/स्वदेश से खरीदे गये/(खरीदे या उधार लिए गये) कम्प्यूटर और कम्प्यूटर परिफेरल्स जिनमें प्रिन्टर्स, प्लॉटर, स्कैनर, मानिटर, की-बोर्ड और स्टोरेज यूनिट शामिल हैं, उनको आयात/खरीद और यूनिट द्वारा उपयोग की गई दो वर्ष के बाद जीएसटी कानून के तहत लागू कर के अलावा किए शुल्क का भुगतान किए बिना किसी मान्यता प्राप्त गैर वाणिज्यिक शिक्षण संस्थाओं, पंजीकृत खैराती अस्पतालों, सार्वजनिक पुस्तकालयों, सरकारी निधि प्राप्त अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठानों, केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों के सामुदायिक सूचना केन्द्र, केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या केन्द्र शासित क्षेत्र के प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र अथवा स्थानीय निकाय अथवा केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या केन्द्र शासित प्रदेश के संगठनों को इस संबंध में जारी सीमा/उत्पाद शुल्क अधिसूचना के अनुसार दान स्वस्थ दे सकता है।

6.31 पृथक पहचान

यदि औद्योगिक उद्यम घरेलू यूनिट के साथ साथ ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी यूनिट दोनों स्तरों में कार्य कर रहा है तो उसकी दो पृथक पहचान होगी और पृथक-पृथक बैंक खाते होंगे। तथापि इसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि उसकी कोई पृथक कानूनी पहचान हो लेकिन ईओयू/ ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी द्वारा प्रभावी आयात और निर्यात अथवा आपूर्तियों को प्रतीकान की अन्य यूनिटों द्वारा किये गये कार्य से पृथक करना संभव हो।

6.32 ईओयू के लिए यूनिट अनुमोदन समिति

(क) एकक अनुमोदन समिति की संरचना निम्नानुसार होगी :-

विकास आयुक्त	:	अध्यक्ष
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क	:	सदस्य

के क्षेत्राधिकारिक आयुक्त अथवा नामिती

संयुक्त महानिदेशक, विदेश व्यापार : सदस्य
अथवा नामिती

क्षेत्र के संयुक्त/उप विकास आयुक्त : सदस्य

विशेष अतिथि के रूप में किसी विभाग/एजेंसी के कोई

अन्य नामित व्यक्ति

(ख) ईओयू की एकक अनुमोदन समिति की शक्तियाँ और कार्य इस प्रकार होंगे:-

- (i) सेवा क्षेत्र में यूनिट स्थापित करने के प्रस्तावों के अलावा ईओयू स्थापित करने हेतु आवेदनों पर विचार करना। (आर एण्ड डी साफ्टवेयर और आई.टी. समर्थित सेवाएं या बीओए द्वारा सौंपी गई किसी अन्य सेवा के अलावा) औद्योगिक (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन जिन विनिर्माण मर्दों के लिए औद्योगिक लाइसेंस आवश्यक है उन आवेदनों पर अनुमोदन बोर्ड द्वारा विचार किया जाएगा।
- (ii) एसईजैड से ईओयू में यूनिट के परिवर्तन पर विचार करना और अनुमति देना।
- (iii) यूनिटों के कार्य निष्पादन की मानिट्रिंग करना।
- (iv) यूनिट को दी गयी अनुमति, निकासी, लाइसेंस का पर्यवेक्षण और मानिट्रिंग तथा विधि के अनुसार समुचित कार्रवाई करना;
- (v) यूनिट को दी गयी अनुमति निकासी, लाइसेंस के अधीन उसके कार्य निष्पादन की मानिट्रिंग करने के लिए अपेक्षित सूचना मांगना।
- (vi) केन्द्रीय सरकार या उसकी एजेंसियों द्वारा सौंपे गए किसी अन्य कार्य को करना।
- (vii) राज्य सरकारों या उसकी एजेंसियों द्वारा सौंपे गए किसी अन्य कार्य को करना।
- (viii) ईओयू की स्थापना और प्रचालन के लिए सभी अनुमोदन और निकासी देना।

6.33 ईएचटीपी/एसटीपी/ बीटीपी यूनिटों का अनुमोदन

ईएचटीपी/एसटीपी स्कीम के तहत यूनिटों के मामले में, संचार प्रौद्योगिक विभाग/निदेशक (एसटीपीआई) द्वारा नामित अधिकारी द्वारा आवश्यक अनुमोदन/अनुमति प्रदान की जाएगी। एसटीपी/ईएचटीपी के मामले में राजपत्र में दिनांक 30-1-2006 की अधिसूचना सं. एस.ओ. 106 (ई) में उल्लिखित के अनुसार नामित अधिकारी को विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 खण्ड-13 जो खण्ड-11 के साथ पठनीय है, के अधीन प्रदान की गई निर्णय की शक्तियों का प्रयोग करेगा। इसी प्रकार बीटीपी के तहत यूनिटों के मामले में, जैव-प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा नामित अधिकारी द्वारा आवश्यक अनुमोदन/अनुमति प्रदान की जाएगी। तथापि, परिशिष्टों और एएनएफ के परिशिष्ट 6क में दिए अनुसार, नए यूनिटों को स्वतः अनुमोदन देने के लिए मनोनीत अधिकारी निर्धारित मानदण्डों को अपनाएँगे।

6.34 ई ओ यू का प्रशासन/विकास आयुक्त/नामित अधिकारी की शक्तियाँ

यूनिटों के संबंध में विकास आयुक्त/नामित अधिकारी की निम्नलिखित शक्तियाँ होगी। विकास आयुक्त का अधिकार क्षेत्र परिशिष्टों और एएनएफ के परिशिष्ट 6ज में दिया गया है।

- (1) रुण/बन्द डीटीए यूनिट को ई ओ यू में बदलना;
- (2) ईओयू को एसटीपी/ईएचटीपी/बीपीटीपी तथा विलोमतः निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार बदलना;
- (3) विदेशी मुद्रा की दर के घटने बढ़ने के कारण भारतीय रुपये में पूँजीगत माल के मूल्य में वृद्धि करने की अनुमति देना;
- (4) केवल बिना लाइसेंस वाले उद्योगों के मामले में बिना सीमा के क्षमता वृद्धि अनुमत करना;
- (5) एलओपी में उल्लिखित समान वस्तुओं के लिए ब्रॉड बैंडिंग की अनुमति देना अथवा विनिर्माण की मौजूदा पद्धति को बैकवर्ड या फारवर्ड लिंकेज प्रदान करना;
- (6) कार्यान्वयन समिति या कम्पनी के नाम परिवर्तन को अधिकृत करना तथा एक कम्पनी से दूसरे में परिवर्तन करना बशर्ते कि नई कार्यान्वयन समिति/कम्पनी, मौजूदा यूनिट की सम्पत्ति और जिम्मेवारी लेने का वचन दे;

- (7) एल ओ पी में उल्लिखित स्थापना-स्थल से दूसरे स्थापना-स्थल में परिवर्तन अनुमत करना और या अतिरिक्त स्थान सम्मिलित करना बशर्ते कि अनुमोदन की अन्य शर्तों तथा समझौतों में किसी परिवर्तन पर ध्यान नहीं दिया जाता है और नया स्थापना-स्थल विकास आयुक्त/नामित अधिकारी के क्षेत्राधिकार के भीतर है;
- (8) एलओपी की वैधता अवधि को विदेश व्यापार नीति के पैरा 6.05(क) के अनुसार एल ओ पी की शुष्काती वैधता अवधि से आगे बढ़ाना (अनुमोदन की शुष्काती अवधि पर जहाँ कहीं भी प्रतिबंध हैं वैसे मामलों के अलावा, जैसे तेल परिशोधन परियोजना की स्थापना करना);
- (9) जहाँ कहीं उचित हो, एलओपी को रद्द करना;
- (10) दो या अधिक यूनिटों का एक यूनिट में विलय करना बशर्ते कि यूनिटें उसी विकास आयुक्त/नामित अधिकारी के क्षेत्राधिकार में आती हों, यह इस शर्त पर किया जायेगा कि यूनिटों का कार्यकलाप ब्रॉड बैंडिंग के प्रावधानों के तहत आते हैं;
- (11) राजपत्र अधिसूचना संख्या सां० आ० 194 (ड.) दिनांक 6.3.2000 में यथा उल्लिखित निर्यात अभिमुख यूनिटों के संबंध में विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, की धारा 11 के साथ पठित धारा 13 के अन्तर्गत न्याय निर्णय की शक्तियों का प्रयोग करना;
- (12) भारतीय रिजर्व बैंक ए.डी. (एमए श्रृंखला) परिपत्र एवी (डीआईआर श्रृंखला परिपत्र संख्या 9 दिनांक 25.10.2001) के अनुसार निर्यात अभिमुख यूनिटों द्वारा साफ्टेक्स फार्म पर घोषित निर्यातों का मूल्यांकन करना;
- (13) गृह मंत्रालय के पत्र संख्या 25022/7/99-एफ 1 दिनांक 20.9.1999 के अनुसार निर्यात अभिमुख यूनिटों द्वारा निम्न स्तर के विदेशी तकनीशियनों को काम में लगाने के लिए रोजगार वीजा प्रदान करने के लिए योग्यता प्रमाण पत्र जारी करना;
- (14) पंजीकरण -सह-सदस्यता प्रमाण पत्र
निर्यातोंमुख इकाई/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी यूनिटों के लिए पंजीकरण प्राधिकारी के रूप में काम करना। मसालों के मामले को छोड़कर, विदेश व्यापार नीति के पैरा 2.44 में दिए गए प्रावधान के अनुसार इनके मामलों में अलग से पंजीकरण-सह-सदस्यता प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं होगी। मसालों के मामले में, इकाइयों को मसाला बोर्ड के पास स्वयं को पंजीकृत करवाना भी अनिवार्य होगा।
- (15) आयातक निर्यातक कोड संख्या फर्म को यदि पहले आयातक निर्यातक कोड संख्या आवंटित नहीं की गयी है तो निर्यात अभिमुख यूनिटों को उसे आवंटित करना।
- (16) ग्रीन कार्ड विधिक वचन बद्धता के निष्पादन के बाद स्वतः ग्रीन कार्ड जारी करना ।
- (17) निर्यातोन्मुखी यूनिटों के संबंध में स्तर प्रमाण पत्र की स्वीकृति देना/नवीनीकरण करना बशर्ते कि घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र में इसकी मूल कम्पनी के निर्यात के पोतपर्यन्त निःशुल्क मूल्य का मिलाना शामिल न हो।
- (18) इसके क्षेत्राधिकार के तहत ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी स्कीम का प्रचार करना ।

6.35 बीओए के अनुमोदन से स्थापना-स्थल में परिवर्तन/ अतिरिक्त स्थापना-स्थल शामिल करना।

बीओए द्वारा एल ओ पी में उल्लिखित स्थान से ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी के स्थापना-स्थल में परिवर्तन तथा मूल डीसी/नामित अधिकारी के क्षेत्रीय अधिकार के बाहर अतिरिक्त/स्थापना-स्थल शामिल किया जा सकता है बशर्ते कि अनुमोदन बोर्ड की शर्तें पूरी हों।

6.36 डीटीए में पूँजीगत माल की निकासी

डीटीए में पुराने माल सहित पूँजीगत माल की निकासी की अनुमति विदेश व्यापार नीति के पैरा 6.15(ख) के अनुसार दी जाएगी और ऐसी निकासी की तारीख को लागू आयात नीति के अनुसार दी जाएगी।

6.37 मूल्य ह्रास मानदंड

कम्प्यूटर एवं कम्प्यूटर पेरिफेरल्स के मामले में 5 वॉर् में 100 प्रतिशत तक मूल्य ह्रास है तथा अन्य मदों के मामले में यह 10 वर्ष होगा ।

(क) कम्प्यूटर और कम्प्यूटर पेरिफेरल्स परिफेरल्स के लिए मूल्यह्रास मानदण्डः

कम्प्यूटर तथा कम्प्यूटर पेरिफेरल्स परिफेरल्स के लिए मूल्य ह्रास निम्नवत होगा:-

प्रथम वर्ष में प्रत्येक तिमाही के लिए 10 प्रतिशत

द्वितीय वर्ष में प्रत्येक तिमाही के लिए 8 प्रतिशत
 तृतीय वर्ष में प्रत्येक तिमाही के लिए 5 प्रतिशत
 चौथे और पाँचवें वर्ष में प्रत्येक तिमाही हेतु 1 प्रतिशत

(ख) अन्य पूँजीगत माल के लिए मूल्यहास मानदण्डः

उपरोक्त के अलावा, पूँजीगत माल के लिए हास की दर निम्नवत होगी:-

प्रथम वर्ष में प्रत्येक तिमाही के लिए 4 प्रतिशत
 द्वितीय व तृतीय वर्ष में प्रत्येक तिमाही के लिए 3 प्रतिशत
 चौथे और पाँचवें वर्ष में प्रत्येक तिमाही के लिए 2.5 प्रतिशत
 उसके बाद प्रत्येक तिमाही के लिए 2 प्रतिशत

6.38 परिवर्तन

(क) मौजूदा घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र की यूनिटें ई ओ यू/ई एच टी पी/ एस टी पी/बीटीपी यूनिट में परिवर्तन के लिए आवेदन कर सकती हैं लेकिन पूर्वस्थापित संयंत्र, मशीनरी और उपकरण के लिए स्कीम के तहत शुल्क और करों में कोई छूट उपलब्ध नहीं होगी। इस प्रयोजन के लिए, घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र का एकक संबंधित विकास आयुक्त/नामित अधिकारी को उसी तरह आवेदन कर सकता है जैसा कि नई यूनिट के लिए लागू होगा। यदि ई पी सी जी स्कीम/अग्रिम प्राधिकार पत्र स्कीम के तहत निर्यात वचनबद्धता बकाया है तो यह यूनिट प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के परिशिष्टों और एएनएफ के परिशिष्ट 6ड में उल्लिखित प्रक्रिया का अनुसरण करेगी।

(ख) मौजूदा ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी यूनिटें ईओयू में परिवर्तन/ विलय होने विलोमतः के लिए आवेदन कर सकती हैं। ऐसे मामलों में यूनिटें सम्बद्ध स्कीम के तहत लागू शुल्कों और करों की छूट की अनुमति प्राप्त करना जारी रखेंगी। ईओयू के रूप में परिवर्तन को इच्छुक ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी यूनिटें संबंधित विकास आयुक्त को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग/जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा नामित अधिकारी के माध्यम से जैसा कि नई यूनिट के लिए लागू है, उसी तरह आवेदन कर सकती हैं। वैसे ही ईएचटीपी/एसटीपी

/बीटीपी में परिवर्तन की इच्छुक ईओयू संबंधित विकास आयुक्त के माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी विभाग/जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा नामित अधिकारी को आवेदन कर सकती है।

(ग) विकास आयुक्त के अनुमोदन से निर्यातोन्मुखी यूनिट को विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थानान्तरित किया जा सकता है बशर्ते कि निर्यातोन्मुखी यूनिट, निर्यातोन्मुखी यूनिट स्कीम के तहत यथानुपात दायित्व प्राप्त कर चुकी हो।

6.39 रुण यूनिटों का पुनरुत्थान

उचित प्राधिकारी द्वारा यूनिट को रुण घोषित किये जाने की शर्त पर यूनिट के पुनरुत्थान के प्रस्ताव या अधिग्रहण करने के प्रस्ताव पर अनुमोदन बोर्ड द्वारा विचार किया जा सकता है। रुण यूनिट के पुनरुत्थान के संबंध में दिशा निर्देश परिशिष्टों और एएनएफ के परिशिष्ट 6ठ में दिये गये हैं।

6.40 शीघ्र निपटान संबंधी प्रक्रिया

(क) पात्रता:

विदेश व्यापार नीति के तहत स्तरधारक प्रमाणपत्र रखने वाले ईओयू शीघ्र निपटान प्रक्रिया हेतु पात्र होंगे।

(ख) आयात कार्गो की जाँच:

स्तरधारक यूनिटों को आयात के पत्तन पर आयात कार्गो की जाँच से छूट दी जाएगी। तथापि, सीमाशुल्क आयुक्त/केन्द्रीय उत्पाद शुल्क क्षेत्राधिकारी आयुक्त यूनिट के स्थापना-स्थल पर यादृच्छिक आधार पर खेपों की जाँच कर सकता है।

(ग) माल की घरेलू खरीद व आयात:

हटा दिया गया है।

(घ) फैक्स मशीन/ कम्प्यूटरों की स्थापना:

क्षेत्राधिकार प्राप्त सहायक/उप सीमा शुल्क अथवा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त को पूर्व सूचना के तहत बान्डेड परिसरों के बाहर अपने प्रशासनिक/पंजीकृत कार्यालय में एक फैक्स मशीन और 2 कम्प्यूटरों को स्थापित करने हेतु निर्यातोन्मुखी यूनिट पात्र होगी।

(ड.) डी जी सैटों को प्राप्त करना:

यूनिट की वास्तविक आवश्यकता से साथ क्षमता के अनुकूल डी जी सेट प्राप्त करने की अनुमति विकास आयुक्त और क्षेत्राधिकार प्राप्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारी को सूचित करते हुए दी जायेगी।

(च) पूंजीगत माल को अस्थायी रूप से हटाना:

पात्र निर्यातोन्मुखी यूनिटों क्षेत्राधिकार प्राप्त सहायक/उप सीमा शुल्क अथवा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त को पूर्व सूचना के तहत मरम्मत हेतु अपने पूंजीगत माल अथवा उनके हिस्सों को हटा सकती है।

(छ) नमूनों को वैयक्तिक रूप से लाना ले जाना:

स्तर धारक निर्यातोन्मुखी यूनिटों द्वारा रत्न और आभूषणों के नमूनों को वैयक्तिक तौर पर लाने ले जाने की अनुमति पैरा 6.24 में निर्धारित सीमा के मद्दे होगी। इसके लिए विकास आयुक्त/सीमा शुल्क/केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारी से पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।

(ज) जिन कार्याकलापों के लिए अनुमति आवश्यक नहीं है:

स्तरधारक के निम्नलिखित कार्यकलापों के संबंध में विकास आयुक्त अथवा क्षेत्राधिकार प्राप्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क/सीमा शुल्क प्राधिकारी की अनुमति आवश्यक नहीं होगी।

तैयार उत्पादों की विदेश व्यापार नीति के पैरा 6.08(क) के अनुसार डीटीए में बिक्री;

प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 6.24 की शर्तों की पूर्ति के मद्दे प्रदर्शनियों में भाग लेना, निर्यात संवर्धक दौरों के लिए रत्नों और आभूषणों को व्यक्तिगत रूप से ले जाना। तथापि, इसकी पूर्व सूचना देना आवश्यक होगा।

6.41 आवेदनों का समयबद्ध निपटान

विकास आयुक्त आवेदनों को शीघ्रता से निपटारेंगे। आवेदनों को निपटाने के लिए सामान्यतः निम्नलिखित समय सीमा को अपनाया जाता है बशर्ते कि आवेदन हर तरह से पूरे हो और उनके साथ निर्धारित दस्तावेज़ संलग्न हों।

क्र०सं०	आवेदन की श्रेणी	निपटान के लिए समय सीमा
1.	अनुमति पत्र/आशय पत्र जारी करना	15 दिन
2.	अनुमति पत्र/आशय पत्र का परिवर्तन	15 दिन
3.	विधिक वचनबद्धता की स्वीकृति	3 दिन
4.	विधिक वचनबद्धता का नवीकरण	3 दिन
5.	ब्राड बैंडिंग/दिशान्तरण की अनुमति	3 दिन
6.	स्थापना स्थल में परिवर्तन की अनुमति	7 दिन
7.	अग्रिम घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र में बिक्री की अनुमति	2 दिन
8.	यूनिटों के विलयन की अनुमति	7 दिन
9.	उत्पादन क्षमता की वृद्धि की अनुमति	3 दिन
10.	अनुमति पत्र को रद्द करना	3 दिन
11.	डिबान्डिंग/एक्जिट की अनुमति	7 दिन
12.	घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र बिक्री की अनुमति	2 दिन
13.	निम्नस्तरीय टेक्नीशियन के लिए रोजगार वीजा हेतु पात्रता प्रमाण पत्र	2 दिन
14.	ग्रीन कार्ड जारी करना	2 दिन
15.	ग्रीन कार्ड का नवीकरण	उसी दिन

16.	पूँजीगत वस्तुओं को लीज पर देने की अनुमति	1 दिन
17.	स्क्रैप/वेस्ट के निपटान की अनुमति	2 दिन
18.	नाम में परिवर्तन की अनुमति	2 दिन
19.	अन्तर यूनिट स्थानान्तरण	2 दिन
20.	वेस्टेज संबंधी माप दण्ड, तदर्थ	2 दिन
21.	पुनः आयात करने की अनुमति	उसी दिन
22.	पुनः निर्यात करने की अनुमति	उसी दिन
23.	माल के प्रतिस्थापन/मरम्मत की अनुमति	उसी दिन
24.	आई.ई.कोड का आवंटन	1 दिन
25.	साफ्टवेक्स फार्म का प्राधिकार	1 दिन
26.	सी.एस.टी दावों की प्रति पूर्ति	7 दिन
27.	जी.एस.पी प्रमाण पत्र जारी करना	उसी दिन
28.	एस.टी.पी.आई, ई.पी.सी.जी में ई.ओ.यू के परिवर्तन की अनुमति	5 दिन
29.	ई.ओ.यू की अन्तिम निकासी की अनुमति	5 दिन
30.	ई.ओ.यू में विस्तार की अनुमति	2 दिन
31.	पूँजीगत माल के मूल्य में वृद्धि करने की अनुमति	2 दिन
32.	प्रदर्शनी/दौरो के माध्यम से निर्यात हेतु अनुमति	2 दिन
33.	शुल्क वापसी/अंतिम उत्पाद शुल्क (टीईडी) की प्रतिपूर्ति	7 दिन

अध्याय 7

मान्य निर्यात

7.01 नीति

मान्य निर्यात संबंधी नीति, विदेश व्यापार नीति के अध्याय-7 में दी गई है।

7.01 लाभ का दावा करने हेतु प्रक्रिया

(क) माल के आपूर्तिकर्ता/प्राप्तकर्ता को मान्य निर्यात लाभ का दावा करने हेतु एएनएफ-7क में उसमें निर्धारित दस्तावेजों के साथ एक आवेदन संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी के पास जमा करना होगा।

(ख) ईओयू को माल की आपूर्ति के मामले में दावा संबंधित विकास आयुक्त के पास प्रस्तुत किया जाना चाहिए। डीटीयू यूनिट संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी से लाभ का दावा करेगी।

7.02 लाभ का दावा करने हेतु मानदंड

(क) (i) अग्रिम प्राधिकार पत्र/डीएफआईए धारक को प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 4.13 के अनुसार निर्गमित निरस्तीकरण पत्र के प्रति मध्यवर्ती माल की आपूर्ति के संबंध में विदेश व्यापार नीति 2015-2020 के अध्याय 4 के तहत यथा प्रदत्त शुल्क मुक्त निविष्टियों के आयात हेतु अग्रिम प्राधिकार प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रक्रिया पुस्तक के अध्याय 4 में दी गई प्रक्रियाओं के अनुसार करना होगा। निरस्तीकरण पत्र के प्रति आपूर्ति हेतु टीईडी वापसी विदेश व्यापार नीति 2015-20 के पैरा 7.03 (ग) के अनुसार की जाएगी बशर्ते कि कोई छूट प्राप्त न हो।

(ii) अग्रिम प्राधिकार पत्र/डीएनआईए को एआरओ के प्रति माल की आपूर्ति के संबंध में प्रक्रिया पुस्तक के अध्याय 4 में दी गई

प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। एआरओ के प्रति आपूर्तियों के लिए टीईडी वापसी की अनुमति विदेश व्यापार नीति 2015-20 के पैरा 7.03 (ग) के अनुसार दी जाएगी बशर्ते कि कोई छूट प्राप्त न हो। शुल्क वापसी की अनुमति ऐसी आपूर्तियों में इस्तेमाल की गई निविष्टियों जिनमें मूल सीमा शुल्क का भुगतान किया गया हो, पर प्रदान की जाएगी।

(ख) ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी को माल की आपूर्ति के संबंध में अग्रिम प्राधिकार पत्र/डीएफआईए प्रक्रिया पुस्तक के अध्याय 4 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार प्राप्त किए जा सकते हैं। मियादी उत्पाद शुल्क के भुगतान से छूट के लिए यथा संशोधित परिपत्र सं० 10/2009 सीमाशुल्क दिनांक 25-05-2009 के साथ पठित उत्पाद शुल्क परिपत्र सं० 851/9/2007 सीएक्स दिनांक 03.05.2007 के अनुसार सीटी 3 के प्रति माल हटाने की प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। ईओयू/ ईएचटीपी/ एसटीपी/ बीटीपी को माल की आपूर्ति हेतु टीईडी वापसी विदेश व्यापार नीति 2015-20 के पैरा 7.03 (ग) के अनुसार की जाएगी बशर्ते कि कोई छूट प्राप्त न हो। इस आपूर्ति के निमित्त शुल्क मुक्त निविष्टियों जिनका उपयोग परिणामी उत्पादों के लिए किया जाता है, के आयात के लिए अग्रिम प्राधिकार पत्र प्राप्त नहीं होने की स्थिति में, विदेश व्यापार नीति 2015-20 के अध्याय 4 में यथा प्रदत्त, निविष्टियों पर भुगतान किए गए मूल सीमा शुल्क के लिए शुल्क वापसी दावा संबंधित डीसी को किया जाएगा। डीटीए यूनिट द्वारा लाभ का दावा संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी से किया जाएगा।

(ग) ईपीसीजी प्राधिकार पत्र धारक को निरस्तीकरण पत्र के निमित्त माल की आपूर्ति के संबंध में अग्रिम प्राधिकार पत्र/ डीएफआईए हेतु आवेदन प्रक्रिया पुस्तक के अध्याय 4 में दी गई प्रक्रियाओं के अनुसार करना होगा। यदि शुल्क मुक्त निविष्टियों के लिए अग्रिम प्राधिकार पत्र/डीएफआईए प्राप्त नहीं किया जाता है तो परिणामी उत्पाद में उपयोग की गई निविष्टियों पर भुगतान किए गए मूल सीमाशुल्क के संबंध में शुल्क वापसी की जाएगी।

(घ) विदेश व्यापार नीति के पैरा 7.02(ड.), (च), (छ:) और (ज) में यथा सूचीबद्ध अन्य श्रेणियों को माल की आपूर्ति के संबंध में शुल्क मुक्त निविष्टियों के आयात हेतु जैसाकि विदेश व्यापार नीति 2015-20 के अध्याय 4 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है, अग्रिम प्राधिकार पत्र/डीएफआईए परिशिष्ट-7ग के अनुसार परियोजना प्राधिकार पत्र के निमित्त प्राप्त किया जा सकता है। तथापि यदि शुल्क मुक्त निविष्टियों के लिए ऐसी आपूर्तियों के निमित्त अग्रिम प्राधिकार पत्र/डीएफआईए जैसाकि एफटीपी 2015-20 के अध्याय 4 में प्रावधान किया गया है, प्राप्त नहीं किया जाता है तो मूल सीमा शुल्क के संबंध में शुल्क वापसी हेतु दावा एएनएफ-7क के अनुसार किया जा सकता है। विदेश व्यापार नीति 2015-20 के पैरा 7.08 (iii) (क) में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की अनुसूची IV के तहत शामिल आपूर्ति की पात्र मदों के संबंध में उल्लिखित परियोजनाओं हेतु टीईडी वापसी की जाएगी बशर्ते कि कोई छूट प्राप्त न हो।

7.03 टीईडी/शुल्क वापसी दावा करने हेतु पात्रता मानदंड

(क) आवेदन या तो आपूर्तिकर्ता अथवा माल प्राप्तकर्ता, जिसके पास आईसीसी संख्या है, द्वारा किया जा सकता है।

(ख) आवेदन पंजीकृत कार्यालय/मुख्य कार्यालय/शाखा कार्यालय अथवा विनिर्माण इकाई द्वारा किया जा सकता है।

(ग) आपूर्तिकर्ता द्वारा टीईडी वापसी हेतु दावा किए जाने की स्थिति में एएनएफ-7क के अनुलग्नक-I के अनुसार उसे माल प्राप्तकर्ता से सेनवैट क्रेडिट प्राप्त नहीं करने का प्रमाण पत्र लेना होगा और उसे प्रस्तुत करना होगा। यदि माल प्राप्तकर्ता आवेदक है, तो आवेदक को ही यह प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।

(घ) हटा दिया गया है।

(ड.) प्राप्तकर्ता यूनिट द्वारा टीईडी/शुल्क वापसी हेतु दावा किए जाने की स्थिति में आपूर्तिकर्ता से दावा परित्याग प्रमाणपत्र, जैसा कि एएनएफ-7क के अनुबन्ध-III में निर्धारित किया गया है, प्राप्त करना होगा और आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा। यदि माल का आपूर्तिकर्ता आवेदक है, तो माल के प्राप्तकर्ता से दावा परित्याग प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।

(च) की गई आपूर्ति की मात्रा के अनुसार पूरा भुगतान प्राप्त होने के बाद ही दावा किया जा सकता है।

(छ) ई-बीआरसी के अनुसार सामान्य बैंकिंग चैनल के जरिए प्राप्त भुगतान के निमित्त दावा किया जा सकता है। अन्य शब्दों में आपूर्ति से संबंधित दस्तावेजों के संबंध में केवल बैंक के माध्यम से ही बातचीत की जानी है। विदेश व्यापार नीति 2015-20 के पैरा 7.02(ड.) से तक के अन्तर्गत की जाने वाली आपूर्ति के संबंध में परिशिष्ट-घ में परियोजना प्राधिकारी द्वारा जारी भुगतान प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जाना है।

(ज) उप-संविदाकार भी दावा कर सकता है बशर्ते इस माल की आपूर्ति से पहले परियोजना प्राधिकार प्रमाण-पत्र/संविदा में इसका नाम पृष्ठंकित हो।

7.04 ईंधन पर टीईडी वापसी का दावा करने हेतु प्रक्रिया।

विदेश व्यापार नीति 2015-20 के पैरा 7.02(ख) के तहत घरेलू तेल सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के डिपो से हाई स्पीड डीजल की आपूर्ति के लिए एएनएफ-7क के अनुबन्ध-IV में दिए गए प्रारूप में संबंधित घरेलू तेल सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम द्वारा जारी शुल्क

भुगतान प्रमाणपत्र के आधार पर मियादी उत्पाद शुल्क की वापसी की जाएगी। शुल्क वापसी ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी यूनिट द्वारा अपने उत्पादन संबंधी कार्यकलापों, संबंधित डीसी/बॉड प्राधिकरियों द्वारा यथा प्रमाणित, के लिए अधिप्राप्त हाई स्पीड डीजल की मात्रा हेतु की जाएगी।

7.05 आवेदन की आवृत्ति और टीईडी/शुल्क वापसी हेतु समयावधि

(क) विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2015-20 के पैरा 7.02(क) से (घ) के अन्तर्गत आपूर्तियों के संबंध में टीईडी वापसी/शुल्क वापसी (जो भी लागू हो) हेतु आवेदन ऐसी आपूर्तियों के निमित्त 100 प्रतिशत भुगतान की प्राप्ति की तारीख से 12 माह के भीतर किया जा सकता है। ऐसे मामलों जिनमें भुगतान अग्रिम में प्राप्त कर लिया जाता है और तत्पश्चात् आपूर्ति की जाती है, तो ऐसे मामलों में आवेदन इन आपूर्तियों की अंतिम तारीख से 12 माह के भीतर किया जा सकता है। अग्रे यथा विनिर्दिष्ट सीमा के भीतर पृथक प्राधिकार पत्र के मद्दे 'अमान्यकरण पत्र/एआरओ वार' दावा किया जा सकता है।

(ख) एफटीपी 2015-20 के पैरा 7.02(ड.) से (ज) के अन्तर्गत आपूर्तियों के संबंध में दावा या तो की गई आपूर्तियों अथवा प्राप्त भुगतान के साक्ष्य के आधार पर किया जा सकता है। परियोजना प्राधिकारी द्वारा आपूर्तियों की प्राप्ति की तारीख से अथवा आवेदन के विकल्प के अनुसार आपूर्तिकर्ता द्वारा भुगतान की प्राप्ति की तारीख से 12 माह की अवधि के भीतर या तो किसी विशेष परियोजना अथवा सभी परियोजनाओं के निमित्त दावा किया जा सकता है। आंशिक भुगतान प्राप्त करने के मामलों में भी दावे किए जा सकते हैं। मान्य निर्यात लाभ 100 प्रतिशत आपूर्तियों के पश्चात् प्राप्त किया जा सकता है। तथापि यह लाभ प्राप्त भुगतान की मात्रा तक ही सीमित होगा।

7.06 ब्रांड दर का निर्धारण

ब्रांड दर निर्धारण के लिए एएनएफ-7क और परिशिष्ट-7ड. में निर्धारित दस्तावेजों के साथ एएनएफ-7क में संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी या विकास आयुक्त जैसा भी मामला हो, को आवेदन किया जा सकता है। ब्रांड दर के निर्धारण हेतु आवेदन निम्नलिखित के लिए किया जा सकता है:

(क) हटा दिया गया है।

(ख) जहाँ भुगतान किए गए मूल सीमा शुल्क का दावा एफटीपी 2015-20 के पैरा 7.06 के अनुसार शुल्क वापसी की ब्रांड दर के रूप में किया जाए।

7.07 समय बाधित/पूरक दावा

निर्धारित समयावधि के पश्चात् दावा किए जाने की स्थिति में प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 9.02 के तहत विलम्ब कटौती का प्रावधान और प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 9.03 के तहत पूरक दावे का प्रावधान लागू होगा।

7.08 टीईडी के भुगतान से छूट

मियादी उत्पाद शुल्क जहाँ लागू हो, के भुगतान से छूट का दावा करने हेतु केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

7.09 अन्य नियमों की प्रयोज्यता

मान्य निर्यात स्कीम पर प्रक्रिया पुस्तक में निर्धारित प्रक्रिया के अधीन सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर वापसी नियमावली, 1995 अथवा सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क वापसी नियमावली, 2017, जो भी मामला हो, यथोचित परिवर्तन करके लागू होगी।

7.10 ब्याज भुगतान

(क) क्षेत्रीय प्राधिकारी अनुमोदन पत्र जारी करने की तारीख से 30 दिन के भीतर भुगतान करेगा। अग्रे दी गई अवधि के भीतर भुगतान नहीं किए जाने पर एफटीपी के पैरा 7.09 के अनुसार मूलधन के साथ आरए ब्याज घटक शामिल करेगा। ब्याज का दावा करने हेतु कोई पृथक आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। मूलधन और ब्याज के लिए बैंक को एकल अधिकार पत्र जारी किया जाएगा।

(ख) यदि क्षेत्रीय प्राधिकारी/विकास आयुक्त द्वारा ब्याज नहीं जोड़ा जाता है तो एएनएफ-7ख के अनुसार मूलधन प्राप्ति की तारीख से 30 दिन के भीतर पृथक आवेदन किया जा सकता है। इसके पश्चात् ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा। क्षेत्रीय अधिकारी लेखाकन प्रयोजन के लिए मूलधन व ब्याज के संवितरण हेतु पृथक खाता रखेगा।

(ग) क्षेत्रीय अधिकारी परिशिष्ट-7च में दिए गए प्रारूप में मान्य निर्यात के दावों के संवितरण हेतु मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। जब भी ब्याज का भुगतान किया जाता है तो क्षेत्रीय प्राधिकारी ब्याज के भुगतान का कारण बताएगा। रिपोर्ट ई-मेल आईडी

ddgdbk@nic.in पर भेजी जाएगी।

7.11 आन्तरिक लेखापरीक्षा तंत्र

अपर महानिदेशक, विदेश व्यापार के मण्डलीय कार्यालय एफटीपी के पैरा 7.10 के अनुसार अपने कार्यालयों में लेखापरीक्षा दल का गठन करेंगे और लेखा परीक्षा पञ्च कार्य पूरा करेंगे।

अध्याय - 8

गुणवत्ता संबंधी शिकायतें और व्यापार संबंधी विवाद

8.01 गुणवत्ता संबंधी शिकायतें और व्यापार संबंधी विवादों से संबंधित समिति (सीक्यू-सीटीडी)

गुणवत्ता संबंधी शिकायतों और व्यापार संबंधी विवादों से प्रभावकारी रूप से निपटने के लिए, विदेश व्यापार महानिदेशालय के 22 कार्यालयों में गुणवत्ता संबंधी शिकायतों और व्यापार संबंधी विवादों (सीक्यूसीटीडी) पर एक समिति का गठन किया गया है। कार्यालयों का नाम जहां पर सीक्यूसीटीडी का गठन किया गया है और सीक्यूसीटीडी का क्षेत्राधिकार नीचे तालिका में दिया गया है:

क्रम सं.	सीक्यूसीटीडी की अवस्थिति	अध्यक्ष का पदनाम	सीक्यूसीटीडी का क्षेत्राधिकार
उत्तरी क्षेत्र			
i	मण्डलीय अपर महा. वि.व्या., सीएलए, नई दिल्ली	अपर महा. वि.व्या.	मण्डलीय महा.वि.व्या.; आरए, मुरादाबाद और आरए, देहरादून
ii	संयुक्त महा.वि.व्या., चण्डीगढ़	संयुक्त महा. वि.व्या.	आरए, चण्डीगढ़; आरए, जम्मू और आरए, श्रीनगर
iii	संयुक्त महा.वि.व्या., पानीपत	संयुक्त महा. वि.व्या.	आरए, पानीपत
iv	संयुक्त महा.वि.व्या., जयपुर	संयुक्त महा. वि.व्या.	आरए, जयपुर
v	संयुक्त महा.वि.व्या., कानपुर	संयुक्त महा. वि.व्या.	आरए, कानपुर
vi	संयुक्त महा.वि.व्या., लुधियाना	संयुक्त महा. वि.व्या.	आरए, लुधियाना और आरए, अमृतसर
vii	संयुक्त महा.वि.व्या., वाराणसी	संयुक्त महा. वि.व्या.	आरए, वाराणसी
पश्चिमी क्षेत्र			
viii	मण्डलीय अपर महा. वि.व्या., मुम्बई	अपर महा. वि.व्या.	मण्डलीय महा.वि.व्या., मुम्बई; आरए, नागपुर और आरए, पणजी
ix	संयुक्त महा.वि.व्या., पुणे	संयुक्त महा. वि.व्या.	आरए, पुणे
x	संयुक्त महा.वि.व्या., बड़ोदरा	संयुक्त महा. वि.व्या.	आरए, बड़ोदरा और आरए, गांधीधाम, कच्छ
xi	संयुक्त महा.वि.व्या., अहमदाबाद	संयुक्त महा. वि.व्या.	आरए, अहमदाबाद

xii	संयुक्त महा.वि.व्या., सूरत	संयुक्त महा. वि.व्या.	आरए, सूरत
xiii	संयुक्त महा.वि.व्या., भोपाल	संयुक्त महा. वि.व्या.	आरए, भोपाल और इंदौर एक्सटें. कार्यालय
पूर्वी क्षेत्र			
xiv	मण्डलीय अपर महा. वि.व्या., कोलकाता	अपर महा. वि.व्या.	मण्डलीय महा.वि.व्या., कोलकाता; आरए, पटना; आरए, गुवाहाटी; आरए, शिलांग और आरए, रायपुर, छत्तीसगढ़
xv	संयुक्त महा.वि.व्या., कटक	संयुक्त महा. वि.व्या.	आरए, कटक
दक्षिणी क्षेत्र			
xvi	मण्डलीय अपर महा. वि.व्या., चेन्नई	अपर महा.वि.व्या.	मण्डलीय महा.वि.व्या., चेन्नई और आरए, पुडुचेरी
xvii	संयुक्त महा.वि.व्या., बंगलौर	संयुक्त महा.वि.व्या.	आरए, बंगलौर
xviii	संयुक्त महा.वि.व्या., हैदराबाद	संयुक्त महा.वि.व्या.	आरए, हैदराबाद
xix	संयुक्त महा.वि.व्या., मदुरै	संयुक्त महा.वि.व्या.	आरए, मदुरै
xx	संयुक्त महा.वि.व्या., कोयम्बटूर	संयुक्त महा.वि.व्या.	आरए, कोयम्बटूर
xxi	संयुक्त महा.वि.व्या., विशाखापत्तनम	संयुक्त महा.वि.व्या.	आरए, विशाखापत्तनम
xxii	संयुक्त महा.वि.व्या., कोचीन	उप महा.वि.व्या.	आरए, कोचीन और आरए, तिरुवनन्तपुरम

8.02 सीक्यूसीटीडी की संरचना

सीक्यूसीटीडी में निम्नलिखित सदस्य होते हैं:

1. अपर महानिदेशक, विदेश व्यापार/संयुक्त महानिदेशक, विदेश व्यापार/(एच.ओ.ओ.): अध्यक्ष
2. भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के प्रतिनिधि: सदस्य
3. कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के प्रतिनिधि: सदस्य
4. संबंधित बैंक के शाखा प्रबंधक के प्रतिनिधि: सदस्य
5. भारतीय निर्यातक संगठन परिसंघ/और अथवा निर्यात संवर्धन परिषद के प्रतिनिधि: सदस्य
6. निर्यात निरीक्षण एजेंसी के प्रतिनिधि: सदस्य
7. राज्य सरकार के उद्योग निदेशक के नामित व्यक्ति: सदस्य
8. एमएसएमई के विकास आयुक्त के नामित व्यक्ति: सदस्य
9. अध्यक्ष द्वारा यथा नामित अधिकारी: सदस्य सचिव
10. अध्यक्ष द्वारा सहयोगित अन्य कोई एजेंसी: सदस्य

8.03 शिकायत दर्ज करने के लिए प्रपत्र

गुणवत्ता संबंधी शिकायतों और/अथवा अन्य विवादों की जांच के लिए आवेदन-पत्र परिशिष्ट और आयात-निर्यात प्रपत्रों के एएनएफ 8 में दिए गए प्रपत्र में उपर्युक्त पैरा 8.01 में दर्शाए गए अनुसार संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जा सकता है। शिकायत के साथ संबंधी दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित छाया प्रतियां विधिवत रूप से संलग्न होनी चाहिए। शिकायतकर्ता अपनी शिकायत डीजीएफटी की वेबसाइट <www.dgft.gov.in> पर भी दर्ज कर सकते हैं।

8.04 गुणवत्ता संबंधी शिकायत और व्यापार संबंधी विवाद के निपटान के लिए प्रक्रिया

(क) सीक्यूसीटीडी, विदेश के आयातक से भारतीय निर्यातक के विरुद्ध शिकायत प्राप्त होने पर, उस फर्म से टिप्पणियां मांगेगा जिसके विरुद्ध शिकायत दर्ज की गई है, दोनों पक्षों को सुनवाई का पर्याप्त मौका दिए जाने के बाद, सीक्यूसीटीडी मामले को सुलझाने के लिए निर्णय ले सकता है और सीक्यूसीटीडी/आरए यथोचित कार्रवाई कर सकता है।

(ख) क्षेत्रीय प्राधिकारी विदेशी निर्यातक के विरुद्ध भारतीय आयातक से प्राप्त शिकायत की एक प्रति वाणिज्य विभाग (डीओसी) के संबंधित विदेश व्यापार (एफटी) प्रभाग को भेजेगा। वाणिज्य विभाग का विदेश व्यापार प्रभाग भारत में संबंधित दूतावास/उच्चायोग/कंसूलेट जनरल और विदेश में संबंधित भारतीय दूतावास/उच्चायोग के समक्ष शिकायत के प्रभावकारी समाधान के लिए शिकायत के मामले को उठाएगा।

8.05 नोडल अधिकारी की भूमिका

(क) विदेश व्यापार महानिदेशालय में नोडल अधिकारी, विदेशों के आयातकों से शिकायतें प्राप्त होने पर, इसे जांच और उचित कार्रवाई के लिए क्षेत्राधिकार प्राप्त क्षेत्रीय प्राधिकारी के पास अग्रेषित करेंगे।

(ख) नोडल अधिकारी विदेशी निर्यातक के विरुद्ध भारतीय आयातक से प्राप्त शिकायत की एक प्रति वाणिज्य विभाग (डीओसी) के संबंधित विदेश व्यापार (एफटी) प्रभाग को भेजेगा। वाणिज्य विभाग का विदेश व्यापार प्रभाग भारत में दूतावास/उच्चायोग/कंसूलेट जनरल और विदेश में संबंधित भारतीय दूतावास/उच्चायोग के समक्ष शिकायत के प्रभावकारी समाधान के लिए शिकायत के मामले को उठाएगा।

(ग) विदेश व्यापार महानिदेशालय के क्षेत्रीय प्राधिकारी, उसे प्राप्त /संदर्भित मामलों के संबंध में की गई कार्रवाई के विवरण के साथ समेकित तिमाही रिपोर्ट नोडल अधिकारी भेजेंगे।

अध्याय - 9**विविध मामले****9.01 आयात प्राधिकार पत्र/ लाइसेंस/प्रमाणपत्र/अनुज्ञा का मूल्य-वर्ग**

(क) प्राधिकार पत्र के लागत बीमा भाड़ा मूल्य/निर्यात दायित्व के पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य को रूप्यों और मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा दोनों में, उस विनिमय दर (दरों) पर जो प्राधिकार पत्र जारी करने की तिथि को विद्यमान हो, दर्शाया जाएगा।

(ख) प्राधिकार पत्र के मद्दे विदेशी मुद्रा के विप्रेषित धन और निर्यात दायित्व के निर्वहन को मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में विनियमन किया जाएगा।

(ग) यदि भेजी गई विदेशी मुद्रा मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में दर्शाए गए प्राधिकार पत्र के लागत बीमा भाड़े के मूल्य में निहित है तो स्पष्ट के मूल्य में कोई वृद्धि जरूरी नहीं होगी।

(घ) तथापि, अग्रिम प्राधिकार पत्र (पत्रों), जोकि एसीयू देशों को निर्यात के लिए जारी किया जाता है, निर्यात दायित्व का एसीयू डालरों में भुनाया तथा भुगतान किया जाएगा।

(ड.) अन्तर्वर्ती आपूर्ति और मान्य निर्यात के लिए अग्रिम प्राधिकार पत्र में निर्यात दायित्व, जहाँ आपूर्तियाँ देश के भीतर की जानी हैं, का भारतीय रुपये में भुनाया और भुगतान किया जाएगा।

9.02 विलम्ब के लिए कटौती

जहाँ कहीं विदेश व्यापार नीति के तहत किसी राजकोषीय/वित्तीय लाभों हेतु समस्त रूप से पूर्ण कोई आवेदन ऐसे आवेदन को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त होता है तो ऐसे आवेदन पर विलम्ब कटौती लगाकर निम्नानुसार विचार किया जा सकता है:

i	अन्तिम तारीख के बाद किन्तु अन्तिम तारीख से छः महीने के भीतर प्राप्त आवेदन	2%
ii	आवेदन प्रस्तुत करने की निर्धारित तारीख से छः महीने के पश्चात प्राप्त आवेदन किन्तु निर्धारित तारीख से एक वर्ष के भीतर	5%
iii	आवेदन प्रस्तुत करने की निर्धारित तारीख से 12 महीने के पश्चात प्राप्त आवेदन किन्तु निर्धारित तारीख से 2 वर्ष के भीतर	10%

9.03 पूरक दावे

जहाँ कहीं निर्धारित समयावधि के भीतर, पूरक दावे के लिए आवेदन पत्र प्राप्त होता है, तो हकदारी पर 2% की दर से कटौती करके ऐसे आवेदन पर विचार किया जा सकता है।

9.04 सूचना प्रस्तुत करना

प्रत्येक आयातक/निर्यातक को महानिदेशक, विदेश व्यापार या उसके द्वारा विधिवत रूप से प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा माँगी गई सूचना निर्धारित समय के भीतर देनी होगी। निर्धारित समय के भीतर अपेक्षित सूचना उपलब्ध कराने में असफल रहने पर विदेश व्यापार नीति में यथा निर्धारित या विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) नियमावली, 1993 के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

9.05 नीति/प्रक्रिया का स्पष्टीकरण

विदेश व्यापार नीति या प्रक्रिया पुस्तक, आई टी सी (एच एस) के तहत मदों के आयात या निर्यात के किसी भी प्रावधान के संबंध में कोई भी स्पष्टीकरण महानिदेशक, विदेश व्यापार से एएनएफ-2च प्रपत्र में माँगा जा सकता है। ई-मेल के माध्यम से भी स्पष्टीकरण माँगा जा सकता है।

9.06 खपत रजिस्टर

आयातक, प्राधिकार पत्र के अधीन आयातित मदों के बारे में एक रजिस्टर, जैसा परिशिष्ट 4छ में है (3 वर्ष की अवधि के लिए) रखेगा और वास्तविक प्रयोक्ता शर्त के साथ आयातित मदों और उनकी खपत के लिए अलग से रजिस्टर रखेगा। विशेष स्कीमों के सम्बंध में ऐसे रजिस्टर विशिष्ट अवधि के लिए रखे जाएंगे।

9.07 निर्यात सुविधा

निर्यातकों की समस्याओं का समन्वित रूप से समाधान करने के लिए, विदेश व्यापार महानिदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालय, निर्यात सुविधा केन्द्रों और नोडल अभिकरणों के रूप में कार्य करेंगे।

9.08 स्थायी शिकायत समिति

विदेश व्यापार नीति और प्रक्रिया संबंधी व्यापार और उद्योग की वास्तविक शिकायतों के शीघ्र समाधान के लिए शिकायत समितियों का गठन किया गया है, जिनके अध्यक्ष (1) मुख्यालय में महानिदेशक, विदेश व्यापार और (2) क्षेत्रीय कार्यालयों के मुख्यालयों के क्षेत्रीय प्राधिकरण के प्रमुख होंगे। शिकायत समिति में भारतीय निर्यात संगठन संघ (एफ आई ई ओ), निर्यात संवर्धन परिषद/पण्य बोर्ड, विकास प्राधिकरण और सरकारी विभाग/तकनीकी प्राधिकारी सदस्य के रूप में शामिल होंगे।

9.09 काउंटर सहायता

(क) यद्यपि डीजीएफटी का प्रयास सभी आवेदनों की ऑनलाइन फाइलिंग/प्रस्तुत करने का है परन्तु जब तक ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध नहीं होती है, आवेदनों को काउंटर पर स्वीकार किया जाना जारी रहेगा।

(ख) आवेदनों के शीघ्र निपटान के लिए, विदेश व्यापार महानिदेशालय के सभी कार्यालयों में 'काउंटर सहायता' प्रकौष्ठ खोले गए हैं। प्रत्येक कार्यालय में विदेश व्यापार विकास अधिकारी काउंटर का प्रभारी होगा। काउंटर पर आवेदन प्रस्तुत करने पर, आवेदक को सलाह दी जाएगी कि उसका आवेदन पूर्ण है या इसमें कोई कमी है जिसे आवेदक को पूरा करना है।

(ग) छोटी प्रकृति के संशोधन/पूछताछ के लिए भी काउंटर सहायता का उपयोग किया जा सकेगा। ऐसे मामलों में, आवेदन, उपयुक्त रसीद के मद्दे क्षेत्रीय कार्यालयों में काउंटर पर स्वीकार किए जाएँगे। प्राधिकार पत्र/लाइसेंस/सूची/पूछताछ जैसा भी मामला हो, को काउंटर पर ही जहाँ तक संभव हो, उसी दिन संशोधित करके/आवश्यक जवाब दे कर वापिस कर दिया जाएगा।

9.10 आवेदनों का समयबद्ध निपटान

क्षेत्रीय प्राधिकारी आवेदनों को शीघ्रता से निपटाएंगे। आवेदनों को निपटाने के लिए सामान्यतः निम्नलिखित समय सारणी को अपनाया जाएगा बशर्ते कि आवेदन हर तरह से पूर्ण हो और उसके साथ निर्धारित दस्तावेज संलग्न हों :

क्रमांक	आवेदन की श्रेणी	निपटान हेतु समय सीमा (कार्य दिवसों में)
i)	आयातक निर्यातक कोड संख्या	2
ii)	अग्रिम प्राधिकार पत्र जहां निविष्टि-उत्पादन मानदण्ड को अधिसूचित किया गया है या प्रक्रिया पुस्तक के पैराग्राफ 4.07 के अधीन है, वार्षिक आवश्यकता हेतु अग्रिम प्राधिकार पत्र और डी एफ आई ए	3
iii)	निविष्टि-उत्पादन मानदंडों का निर्धारण	120
iv)	ईपीसीजी प्राधिकार पत्रों का निर्गम	3
v)	रत्न और आभूषणस्कीम के तहत सभी प्राधिकार पत्र	3
vi)	प्राधिकार पत्र की पुनर्वैधता तथा क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा निर्यात दायित्व अवधि में वृद्धि	3
vii)	बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता की स्वीकृति	3
viii)	प्राधिकार पत्र/डीएफआईए का मोचन/ निर्यात दायित्व निपटान प्रमाण-पत्र	15
ix)	निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल का मोचन और	30
x)	स्तर प्रमाण पत्र जारी करना/नवीकरण करना	3
xi)	किसी भी श्रेणी के प्राधिकार पत्र का संशोधन	3
xii)	विविध	10
xiii)	मान्य निर्यात के अधीन डी बी के/टी ई डी की वापसी	30
xiv)	शुल्क वापसी के लिए ब्राण्ड दर का निर्धारण	30
xv)	अध्याय 3 की स्कीम	3

उपर्युक्त सभी मामलों में, दिनों की संख्या की गणना सम्पूर्ण आवेदन पत्र जमा करने की तिथि से की जायेगी। आवेदनों के निपटान में अनुचित देशी के मामलों को क्षेत्रीय कार्यालयों के अध्यक्ष की जानकारी में लिखित रूप से लाया जायेगा और शीघ्रता से इसकी जांच की जायेगी और उत्तर दिया जायेगा।

9.11 आयात के संबंध में पोतलदान/प्रेषण की तारीख

आयात के लिए पोतलदान/प्रेषण की तारीख का हिसाब इस प्रकार लगाया जायेगा:-

क्रम सं.	परिवहन का माध्यम	पोतलदान/प्रेषण की तारीख
(i)	समुद्र मार्ग द्वारा	लदान-पत्र पर अंकित तारीख
(ii)	वायु मार्ग द्वारा	सम्बद्ध एयरवे बिल की तारीख बशर्ते कि इससे उस तारीख का पता चलता हो जब माल ने अपने देश जहाँ से आयात किया गया के अंतिम हवाई अड्डे को छोड़ा हो।
(iii)	स्थल-रुद्ध देशों से	प्रेषण आधार के माध्यम से भारत में खेप भेजने वाले को रेल, सड़क या अन्य मान्यता प्राप्त परिवहन के साधन द्वारा प्रेषण की तारीख।
(iv)	डाक पार्सल द्वारा	पैकेटों या प्रेषण नोट पर प्रेषण कार्यालय की स्टैम्प की तारीख
(v)	पंजीकृत कुरियर सेवा द्वारा	कुरियर रसीद/वे बिल पर अंकित तारीख
(vi)	बहु आयामी परिवहन	लदान-पत्र के संयुक्त परिवहन में पहले वाहन से सामान सौंपने की तारीख

9.12 निर्यात के संबंध में पोतलदान/ प्रेषण की तारीख

(क) निर्यात के लिए पोतलदान/प्रेषण की तारीख का हिसाब इस प्रकार लगाया जायेगा:-

	परिवहन का माध्यम	शिपमेंट/प्रेषण की तारीख
(i)	समुद्री मार्ग द्वारा	(क) बल्क कार्गो के लिए, लदान-पत्र की तारीख या मेट रसीद की तारीख, जो भी बाद की हो। (ख) कंटेनर-युक्त कार्गो के लिए, "जहाज पर लदान बिल" या "लदान के जहाज-लदान-बिल के लिए प्राप्त की" तारीख जहाँ एल/सी में ऐसे लदान-पत्र की व्यवस्था है। अन्तर्देशीय कंटेनर डिपो (आई सी डी) से कंटेनरों द्वारा निर्यात के लिए, सीमाशुल्क निकासी के पश्चात आई सी डी में निर्यात माल के लदान के समय शिपिंग एजेंटों द्वारा जारी किए गए लदान-पत्र की तारीख। (ग) लैश बार्जेज के लिए, लदान-पत्र की तारीख जिसमें जहाज पर निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के लदान का प्रमाण हो।
(ii)	वायु मार्ग द्वारा	उपयुक्त सीमा-शुल्क अधिकारी द्वारा पोतलदान बिल पर उल्लिखित तारीख, जिसमें लदान या वायु कार्गो काम्प्लैक्स, जो अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डे नहीं है, को माल सौंपने का या उड़ान संख्या और तारीख का प्रमाण हो।
(iii)	डाक पार्सल द्वारा	डाक रसीद पर अंकित तारीख।
(iv)	रेल द्वारा	आर आर (रेलवे रसीद) की तारीख।
(v)	पंजीकृत कुरियर सेवा द्वारा	कुरियर रसीद/माल-सूची पर अंकित तारीख।
(vi)	सड़क मार्ग द्वारा	भूमि सीमा-शुल्क प्राधिकारी द्वारा यथा प्रमाणित भारतीय सीमा से माल बाहर जाने की तारीख।

(ख) तथापि, जहाँ कहीं प्रक्रिया/नीति सम्बंधी उपबंधों को निर्यातकों के अहित में संशोधित किया गया है, तो इस सार्वजनिक सूचना/अधिसूचना की तारीख तक जाँच के लिए सीमा शुल्क प्राधिकारी को पहले से ही सौंपी गई खेपों और बाद में निर्यातों पर लागू नहीं होंगे।

(ग) इसी प्रकार, ऐसे मामलों में जहाँ निर्यात दायित्व अवधि की समाप्ति से पहले माल सीमाशुल्क प्राधिकारियों को सौंप दिया जाता है, किन्तु वास्तविक निर्यात, निर्यात दायित्व की अवधि की समाप्ति के बाद किए जाते हैं, तो ऐसे निर्यातों पर निर्यात दायित्व अवधि के भीतर विचार किया जाएगा और निर्यात दायित्व की पूर्ति मानी जाएगी।

(घ) तथापि, विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत लाभों हेतु अनुमत निर्यात आदेश (एलईओ) की तिथि निर्यात की गणना की तिथि होगी।

9.13 पुनरीक्षा का सामान्य अधिकार

महानिदेशक, विदेश व्यापार स्वयं या अन्यथा, ईपीसी/एफआईईओ के किसी अधिकारी, जिसमें उसके द्वारा नामित व्यक्ति, नियुक्त या प्राधिकारियों का समूह/समिति शामिल है, के पास लम्बित पड़े किसी मामले या उसके अधीनस्थ अधिकारी द्वारा तय किए गए मामले के रिकार्ड मंगा सकता है और ऐसे आदेश पारित कर सकता है जिसे वह उपयुक्त समझे।

शब्दावली (संक्षिप्त अक्षर)

संक्षिप्त अक्षर	पूर्णक्षर
एए	अग्रिम प्राधिकार पत्र
एएनएफ	परिशिष्ट और आयात निर्यात प्रपत्र
एसीयू	एशियाई निकासी संघ
ईजेड	कृषि निर्यात क्षेत्र
एएनएफ	आयात निर्यात प्रपत्र
एआरई-1	निर्यात (हवाई/समुद्री/डाक/स्थल द्वारा) के लिए उत्पाद शुल्क लगाये जाने योग्य वस्तुओं को हटाए जाने के लिए आवेदन-पत्र
एआरई-3	फैक्टरी से अथवा एक गोदाम से अन्य गोदाम में से उत्पाद शुल्क लगाए जाने योग्य वस्तुओं का हटाए जाने के लिए आवेदन-पत्र
एसीपी	मान्यता प्राप्त ग्राहक कार्यक्रम
ईओ	प्राधिकृत इकानामिक ऑपरेटर
ईएस	अनुमोदित निर्यातक स्कीम
एपीडा	कृषि और संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण
एआरओ	अग्रिम निकासी आदेश
आसियान	दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन
एसआईडी	निर्यात के मूलभूत विकास हेतु राज्यों को सहायता
एयू	वास्तविक प्रयोगकर्ता
बीसीडी	मूल सीमाशुल्क
बीजी	बैंक गारंटी
बीआईएफआर	औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड
बीओए	अनुमोदन बोर्ड
बीओटी	व्यापार बोर्ड
बीआरसी	बैंक वसूली प्रमाण-पत्र

बीटीपी	जैव प्रौद्योगिकी पार्क
बीआईएस	भारतीय मानक ब्यूरो
सीबीईसी	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड
सीसीपी	सीमा शुल्क निकासी परमिट
सीईए	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारी
सीईसी	चार्टर्ड इंजीनियर प्रमाण पत्र
सीईडी	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
सेनवैट	केन्द्रीय मूल्य वर्धक कर
सीईटीएफ	सामान्य बहिस्त्राव उपचार सुविधा
सीएफसी	सामान्य सुविधा केन्द्र
सीजीएसटी	केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर
सीजी	पूँजीगत माल
सीआईएफ	लागत, बीमा और भाड़ा
सीआईएन	कम्पनी पहचान संख्या
सीआईएस	स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रमंडल
सीकेडी	सम्पूर्णता खराब हुए
सीओडी	सुपुर्दगी पर भुगतान
सीओओ	मूल का प्रमाणपत्र
सीक्यूसीटीडी	गुणवत्ता की शिकायतों और व्यापार विवादों पर समिति
सीआरईएस	मसालों के निर्यातक के रूप में पंजीकरण का प्रमाणपत्र
सीएसटी	केन्द्रीय बिक्री कर
सीआरईएस	मसालों के निर्यातक के रूप में पंजीकरण का प्रमाणपत्र
सीईपीए	व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते
सीबीईसी	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड
सीएसपी	सामान्य सेवा प्रदाता
सीईसीए	व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता
सीवीडी	काउंटरवेलिंग शुल्क
डीए	स्वीकृति पर दस्तावेज
डीबीके	शुल्क वापसी
डीसी	विकास आयुक्त
डीडीए	डायमंड डॉलर खाता
डीईए	आर्थिक मामलों में विभाग
डीईएल	अस्वीकृत इकाई सूची
डीईएस	शुल्क में छूट स्कीम
डीएफआईए	शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार पत्र
डीजीसीआईएण्डएस	महानिदेशक, वाणज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी

डीआईएन	निदेशक पहचान संख्या
डीपीआईएन	निर्दिष्ट साझेदार पहचान संख्या
डीजीएफटी	विदेश व्यापार महानिदेशालय
डीआईपीपी	औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग
डीओबीटी	जैव प्रौद्योगिकी विभाग
डीओसी	वाणिज्य विभाग
डीईआईटी वाय	इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
डीओआर	राजस्व विभाग
डीओटी	दूरसंचार विभाग
डीआरएस	शुल्क में छूट स्कीम
डीटीए	घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र
ईबीआरसी	इलेक्ट्रॉनिक बैंक वसूली प्रमाणपत्र
ईआईईसी	इलेक्ट्रॉनिक आयातक-निर्यातक कोड
ईसीए	इलेक्ट्रॉनिक-सह-अधिनिर्णय
ईडीआई	इलेक्ट्रॉनिक आंकड़ों का परस्पर अंतरण
ईसीजीसी	निर्यात क्रेडिट गारंटी निगम
ईईएफसी	विनिमय अर्जक विदेशी मुद्रा
ईएफसी	एक्जिम सुविधा समिति
ईएफटी	इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण
ईजीएम	निर्यात संबंधी सामान्य घोषणा पत्र
ईएचटीपी	इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क
ईआईसी	निर्यात निरीक्षण परिषद्
ईओ	निर्यात दायित्व
ईओडीसी	निर्यात दायित्व निर्वहन प्रमाणपत्र
ईओपी	निर्यात दायित्व अवधि
ईओयू	निर्यातोन्मुख एकक
ईपीसी	निर्यात संवर्धन परिषद
ईपीसीजी	निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल
ईपीओ	इंजीनियरी प्रक्रिया आऊटसोर्सिंग
एक्जिम	निर्यात आयात
एफडीआई	विदेशी प्रत्यक्ष निवेश
एफई	विदेशी मुद्रा
एफईएमए	विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम
एफआईईओ	भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ
एफआईआरसी	फोरेन एक्सचेंज इन्वर्ड रेमिटेन्स सर्टिफिकेट
एफओबी	फ्री ऑन बोर्ड

एफओआर	सड़क और रेल पर माल ढुलाई
एफटी (डी एंड आर) एक्ट	विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992(1992 का 22)
एफटीडीओ	विदेश व्यापार विकास अधिकारी
एफटीपी	विदेश व्यापार नीति
एफटी(आर) नियमावली	विदेश व्यापार (विनियमन) नियम
एफटीडब्ल्यूजैड	मुक्त व्यापार और भंडारण क्षेत्र
एफटीए	मुक्त व्यापार समझौते
जीएण्डजेईपीसी	रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद
जीओआई	भारत सरकार
जीएटीएस	सेवाओं में व्यापार पर सामान्य समझौता
जीआर	प्राप्ति की गारंटी
जीएसटी	वस्तु एवं सेवा कर
एचएसीसीपी	खतरा, विश्लेषण और महत्वपूर्ण नियंत्रण प्रक्रिया
एचबीपी	प्रक्रिया पुस्तक
एचएचईसी	हस्तशिल्प और हथकरघा निर्यात निगम
आईसीबी	अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली
आईसीडी	अंतर्देशीय कंटेनर डिपो
आईसीएम	भारतीय वाणिज्यिक मिशन
आईईसी	आयातक निर्यातक कोड
आईजीएसटी	एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर
आईएसओ	अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन
आईईए	अंतरराष्ट्रीय परमाणु उर्जा एजेंसी
आईएनएफसीआईआरसी	अंतरराष्ट्रीय परमाणु उर्जा एजेंसी की जानकारी परिपत्र
आईईएम	औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन
आईएमएससी	आंतर मंत्रालयी स्थायी समिति
आईएल	औद्योगिक लाइसेंसिंग
आईएसओ	अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन
आईटीसी (एचएस)	निर्यात और आयात मदों के लिए भारतीय व्यापार वर्गीकरण (सुसंगत प्रणाली)
केवीआईसी	खादी और ग्रामोद्योग आयोग
एलसी	क्रेडिट का पत्र
एलसीएस	भूमि सीमा शुल्क स्टेशन
एलएलपीआईएन	सीमित देयता साझेदारी संख्या
एलपीजी	तरलीकृत पेट्रोलियम गैस
एलओसी	लाइन ऑफ क्रेडिट
एलओआई	आशय पत्र

एलओपी	परमिट पत्र
एलयूटी	विधिक वचनबद्धता
एमएआई	बाजार पहुँच पहल
एमडीए	बाजार विकास सहायता
एमईए	विदेश मंत्रालय
एमईआईएस	भारतीय स्कीम से व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात
एमआरए	परस्पर मान्यता समझौते
एमओडी	रक्षा मंत्रालय
एमओएफ	वित्त मंत्रालय
एमएसएमई	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
एमएसएमईडी	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास
एमएसटीसी	धातु स्क्रेप व्यापार निगम
एनबीएफसी	गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनी
एनसी	मानदण्ड समिति
एनएफई	निवल विदेशी मुद्रा
एनआई	गैर उल्लंघनकारी
एनसीबी	राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली
एनओसी	अनापत्ति प्रमाण-पत्र
पीडीएस	सार्वजनिक वितरण प्रणाली
पीईसी	भारतीय परियोजना एवं उपस्कर निगम लिमिटेड
पीआईसी	नीतिगत व्याख्या समिति
पीआरसी	नीतिगत छूट समिति
पीएएन	स्थायी खाता संख्या
पीएच	व्यक्तिगत सुनवाई
पीटीए	तरजीही व्यापार समझौता
पीएसयू	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम
आरएण्डडी	अनुसंधान एवं विकास
आरए	क्षेत्रीय प्राधिकारी
आरबीआई	भारतीय रिजर्व बैंक
आरसीएमसी	पंजीकरण सह सदस्यता प्रमाण पत्र
आरईपी	प्रतिपूर्ति
आरपीए	स्वयं अदायगी क्षेत्र
एस/बी	पोत लदान बिल
एसएडी	विशेष अतिरिक्त शुल्क
स्कोमेट	विशेष रसायन आर्गेनिज्म, मैटीरियल्स, उपस्कर एवं प्रौद्योगिकी
एसईआईसीएमएम	सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंस्टीट्यूट्स कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल

एसईजैड	विशेष आर्थिक क्षेत्र
एसईआईएस	भारत स्कीम से सेवा निर्यात
एसजीएसटी	राज्य वस्तु एवं सेवा कर
एसआईए	औद्योगिक सहायता सचिवालय
एसआईआईसी	राज्य औद्योगिक अवसंरचना निगम
एसआईओएन	मानक निविष्टि उत्पादन मानदंड
एसकेडी	अर्द्ध खराब
एसएलईपीसी	राज्य स्तरीय निर्यात संवर्धन समिति
एसटीसी	राज्य ट्रेडिंग निगम
एसटीसीएल	मसाला ट्रेडिंग निगम लिमिटेड
एसटीई	राज्य व्यापार उद्यम
एसटीएच	स्टार व्यापार सदन
एसटीपीआई	सॉफ्टवेयर टेक्नोलोजी पार्क ऑफ इंडिया
एसटीआर	राज्य व्यापार क्षेत्र
एसयूवी	स्पोर्ट्स यूटीलिटी व्हीकलस
टीईडी	अंतिम उत्पाद शुल्क
टीईई	निर्यात उत्कृष्टता के शहर
टीएच	व्यापार सदन
टीपीओ	व्यापार संवर्धन संगठन
टीआरए	टेलीग्राफिक रिलीज एडवाइस
टीआरक्यू	प्रशुल्क दर कोटा
टीयूएफएस	प्रौद्योगिकी उन्नयन फंड स्कीम
यूएसी	यूनिट अनुमोदन समिति
यूएन	संयुक्त राष्ट्र
वीए	मूल्यवर्धन
डब्ल्यूसीओ	विश्व सीमाशुल्क संगठन
डब्ल्यूएचओजीएमपी	विश्व स्वास्थ्य संगठन माल विनिर्माता क्रियाकलाप

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)****PUBLIC NOTICE**

New Delhi, the 5th December, 2017

No. 43/2015-2020

F. No. 01/94/180/333/AM 15/PC-4.—In exercise of powers conferred under Paragraph 1.03 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, the Director General of Foreign Trade hereby notifies the revised edition of Handbook of Procedures, as contained in Annexure to this Public Notice. This shall come into force with effect from 5th December, 2017.

Effect of this Public Notice: The revised edition of the Handbook of Procedures of Foreign Trade Policy, 2015-2020 is hereby notified.

ALOK VARDHAN CHATURVEDI, Director General of Foreign Trade

CHAPTER 1**INTRODUCTION AND TRADE FACILITATION****1.01 Notification of Procedure**

In pursuance of the provisions of paragraph 1.03 of Foreign Trade Policy (FTP), the Director General of Foreign Trade (DGFT) hereby notifies the procedure to be followed by an exporter or importer or by the licensing/Regional Authority or by any other authority for purpose of implementing the provisions of Foreign Trade (Development & Regulation) Act, the Rules/orders made thereunder and the provisions of Foreign Trade Policy. The said procedure is contained in following compilations:

- (a) Hand Book of Procedures
- (b) Appendices & Aayat Niryat Forms and
- (c) Standard Input Output Norms (SION)

These compilations, as amended from time to time, shall come into force from the date of their notification and shall remain in force until 31st March, 2020.

1.02 Objective

The objective is to implement provisions of FT (D&R) Act, Rules and Orders made thereunder and provisions of FTP (2015-20) by laying down simple, transparent and EDI compatible procedures which are user friendly and are easy to comply with and administer for efficient management of foreign trade.

1.03 Definition

For the purpose of this Handbook, definitions and glossary contained in FT (D&R) Act, Rules and orders made thereunder and in the FTP (2015-20) shall apply.

1.04 e-governance of Foreign Trade

- (a) DGFT delivers most of its services on a transparent and efficient EDI platform using tools like Online filing of Applications, Message Exchange with Community Partners, Digital Signatures and Electronic payment of application fee. Use of EDI at DGFT has enabled faster processing, speedier communication by e-mail and on-line availability of application processing status. The endeavour is to achieve higher level of information sharing through SMS.
- (b) Export Import related information including Acts, Rules, Policy & Procedures thereof including online DGFT portal can be accessed at <http://dgft.gov.in/>.
- (c) All the DGFT Regional Authorities are EDI enabled and connected with the DGFT Central Server to provide online connectivity to EXIM community in a 24x7 environment.
- (d) DGFT keeps expanding the scope and domain of EDI on a continuous basis. The endeavour is to achieve higher level of integration with community partners.

1.05 Procedure

An exporter shall file his application online on DGFT website at <http://dgft.gov.in/>. Application will then be processed in accordance with prevalent rules and regulations. The processing of applications will be made online. DGFT shall issue deficiency letters, if any, in online mode or through use of e-mail. No communication shall be issued by DGFT in manual mode.

1.06 Use of Digital Signature

- (a) DGFT allows online filing of applications with Class-II digital signature with IEC number embedded in it. A list of DGFT approved digital signature issuing authorities is given as under:
 - (i) (n) Code Solutions CA
 - (ii) e-Mudhra
 - (iii) Safescrypt (Siffy Communication Limited)
- (b) For purposes other than submission of the application, such as an enquiry or uploading/processing of eBRC data, class II or above digital signature certificate issued by any approved entity of Controller of Certifying Authority of India is accepted.

1.07 Separate applications for exports from EDI and on EDI ports

Separate applications shall be filed to DGFT for exports from EDI ports and Non EDI ports.

1.08 Application for exports from Non EDI ports

An exporter would be able to file his application on DGFT website at <http://dgft.gov.in/>. Applicant will then submit to concerned RA the hard copy of application along with requisite documents. Authorisation/Scrip shall be issued on the basis of hard copies of documents as prescribed in HBP after due scrutiny.

1.09 Application for exports from EDI ports

Applications relating to exports from EDI ports will be filed online as per relevant provisions. Physical or Hard copy of the following documents shall not be required to be submitted:

- (i) Applications to DGFT
- (ii) EDI shipping bills
- (iii) Electronic Bank Realisation Certificate (eBRC)
- (iv) RCMC

1.10 No manual feeding allowed for EDI shipments

For EDI shipping Bills, no manual feeding of Shipping bill details will be allowed to the applicants in the online software and benefits will accordingly be granted by RAs without the need for cross verifying EDI Shipping Bill details.

1.11 Dispensing with hard copy of documents

Hard copy of documents already submitted online in exporter's profile shall not be called for.

1.12 Processing of Non EDI Shipping bills at RA

In case of the Non EDI shipping bills or the shipping bills not received through the Message Exchange from Customs, concerned RA shall verify the details entered by the exporter from the original shipping bills before grant of benefits.

1.13 Instructions for filing of applications

Detailed step by step instructions for online filing of an application are available at the relevant HELP files at DGFT website and at scheme specific ANF of the HBP

1.14 EDI Procedure for claiming benefits in respect of Third Party exports

For claiming benefits under EDI system in respect of Third Party exports the process will be initiated by the First party who will link shipping bills and BRCs to repository. If the First Party chooses not to claim benefit for a particular shipping bill item/s, it may authorize Third Party to claim benefit for such shipping bill item/s. After such authorization by First party, Third Party will be able to utilize the shipping bill item/s in its application".

1.15 Conversion of Currencies in e-BRCs

- (a) **Currencies, where Exchange rates are notified by CBEC:** The foreign exchange realized (as mentioned by bank in the e BRC) is converted to Indian Rupee (INR) using the monthly exchange rates published by CBEC as on Let Export Order (LEO).

- (b) **Currencies, where Exchange rates are not notified by CBEC:** In such cases, total realized value in INR (as mentioned by bank in the e BRC), will be converted into US\$ by using the US\$ /INR exchange rate prevailing on the date of realization as published by CBEC.

1.16 Guidelines for Processing of claims where an exporter gets payment through Insurance Agencies (and not through banks) towards realization of export proceeds

- (a) An applicant realizing export proceeds through Insurance Agency will approach the concerned RA with the proof of payment issued by the concerned Insurance Agency. RA, after satisfying itself of the bona fide of the payment, will obtain approval of Additional DGFT (EDI) and then will upload the value (in lieu of e BRC value) in EDI system of DGFT for processing of the case.
- (b) If the proof of payment issued by the Insurance Agency mentions claim value both in foreign exchange and INR, RA will use the foreign exchange value for processing. If the claim value is mentioned only in equivalent INR, RA will convert this INR value in equivalent US\$ using the exchange rate (published by CBEC) applicable on the date of settlement of insurance claim.

1.17 EDI Help Desk & Online Complaint registration and monitoring system

An EDI Help Desk is available to assist the exporters in filing online applications on the DGFT portal and resolving other EDI related issues. For assistance an email may be sent at dgftedi@nic.in or Toll Free number 1800111550 can be used. Help Desk facility is also operational at the 4 Zonal Offices of DGFT, namely, CLA (New Delhi), Mumbai, Chennai & Kolkata. An Online Complaint registration and monitoring system allows users to register complaint and receive status/reply online (details at <http://dgft.gov.in>).

1.18 E-Mail

Use of Email for queries relating to import/export is encouraged. Contact email ids are available at <http://dgft.gov.in/exim/2000/dgftContactUS.html>.

1.19 e Trade Project

The e TRADE project facilitates users to carry out all their foreign trade related compliances, regulatory or otherwise, online. Department of Commerce pilots this project.

The major stake holders of the project are Customs, Directorate General of Foreign Trade (DGFT), Seaports, Airports, Container Corporation of India (CONCOR), Inland container Depots(ICDs)/ Container Freight Stations (CFSs), Banks, importers/exporters, agents, airlines/shipping lines.

The project emphasizes automation of internal processes for quicker processing of trade requests. Transparency is induced in the system by reduced personal interface of importers/exporters with Government agencies.

The project provides for following key services:

- (i) e-delivery of services / clearances by community partners like Customs and Custodians at Sea ports, Airports and ICD/CFSs. These services are extended to exporter, importer, agents etc.
- (ii) E-filing of export / import documents by exporter, importer, agents etc to Customs and Custodians at Sea Ports, Airports and ICD / CFSs.
- (iii) Electronic exchange of documents between community partners i.e. Customs and Custodians at Sea Ports, Airports, ICD/CFSs.
- (iv) e-Payment by exporter, importer, agents for Custom duties; DGFT's application and other fee and Charges (handling/freight, etc) of Custodians at Sea Ports, Airports, ICD/CFSs.

CHAPTER 2

GENERAL PROVISIONS REGARDING EXPORTS AND IMPORTS

2.00 Policy

Policy relating to general provisions regarding exports and imports is given in Chapter-2 of FTP.

2.01 Coverage

This chapter covers procedure for various applications including their complete documentation. Procedure for applications for authorisations/ license/ permissions/ certificates for import/export and applications for benefits under FTP are spelt out.

2.02 Countries of Imports / Exports

Unless otherwise specifically provided, international trade (i.e. import into India and /or export from India) can take place from/to any country. Country specific prohibitions/limitations, if any, are specified in the FTP/ITC (HS).

Applications:

2.03 Filing of Application

- (a) Applications seeking authorisation for import/export of “restricted” goods, for claiming benefits under the schemes in FTP or for seeking clarifications and for other purposes may be made to the Regional Authority (RA).
- (b) Applicants may ensure while submitting documents that documents are either in English or Hindi. Documents in regional languages may be got translated into English or Hindi and the translated copy may be self-certified and submitted along with the Original copy.

2.04 Territorial Jurisdiction of RA

Territorial jurisdiction of RAs is given in **Appendix 1A** of Appendices and Aayat Niryat Forms. The address of applicant determines the jurisdiction of RA. Each application, unless otherwise specified, shall be submitted to jurisdictional RA .

2.05 Incomplete Application

- (a) An incomplete or unauthorised application is liable to be rejected by the competent authority with specific reason for rejection. Such incomplete application may be re-opened on rectifying the deficiencies.
- (b) If the deficiencies are not rectified by the applicant within a period of 90 days, the application will be deemed to have been withdrawn.

2.06 Application Fee

The scale of fee, mode of payment, procedure for refund of fee and categories of persons exempted from payment of fee are provided for in **Appendix-2K**.

Importer Exporter Code (IEC):

2.07 IEC Number Exempted Categories

- (a) IEC is compulsory for import and /or exports. However, the following categories of importers or exporters are exempted from obtaining IEC.

Sl. No.	Categories Exempted from obtaining IEC
(i)	Importers covered by clause 3(1) [except sub- clauses (e) and (l)] and exporters covered by clause 3(2) [except sub-clauses (i) and (k)] of Foreign Trade (Exemption from application of Rules in certain cases) Order, 1993.
(ii)	Ministries /Departments of Central or State Government
(iii)	Persons importing or exporting goods for personal use not connected with trade or manufacture or agriculture.
(iv)	Persons importing/exporting goods from/to Nepal; Bhutan; Myanmar (through Indo-Myanmar border areas); and China (through Gunji, Namgaya Shipkila and Nathula ports), provided that the CIF value of single consignment of import/export of goods from/to Nepal; Bhutan and Myanmar (through Indo-Myanmar border areas) does not exceed Indian Rs. 25,000/-; and in the case of China, (a) for import/export of goods through Gunji and Namgaya Shipkila, CIF value of single consignment does not exceed Indian Rs.1,00,000/-;and (b) for import/export of goods through Nathula, CIF value of single consignment does not exceed Rs.2,00,000/-.

Further, exemption from obtaining IEC shall not be applicable for export of Special Chemicals, Organisms, Materials, Equipments and Technologies (SCOMET) as listed in Appendix - 3, Schedule 2 of ITC (HS) except in case of exports by category (ii) above.

- (b) Following permanent IEC numbers shall be used by non – commercial PSUs and categories or importers / exporters mentioned against them for import / export purposes :

Sr. No.	Permanent IEC	Categories of Importer / Exporter
1	AMDCG0111E	All Ministries / Departments of Central Government and agencies wholly or partially owned by them.
2	ADSGA0129E	All Departments of any State Government and agencies wholly or partially owned by them.
3	DCUNO0137E	Diplomatic personnel, Counsellor officers in India and officials of UNO and its specialised agencies.
4	IABBR0145E	Indians returning from / going abroad and claiming benefit under Baggage Rules.
5	IIHIE0153E	Persons /Institutions /Hospitals importing or exporting goods for personal use, not connected with trade or manufacture or agriculture.
6	IIEGN0161E	Persons importing/exporting goods from /to Nepal
7	IIEGM0170E	Persons importing / exporting goods from / to Myanmar through Indo-Myanmar border areas
8	IFFIE0188E	Ford Foundation.
9	ATAEF1096E	Importers importing goods for display or use in fairs/ exhibitions or similar events under provisions of ATA carnet. This IEC number can also be used by importers importing for exhibitions/fairs as per Paragraph 2.63 of Handbook of Procedures
10	IDNBG1100E	Director, National Blood Group
11	ICIRN1126E	Individuals /Charitable Institution /Registered NGOs importing goods, which have been exempted from Customs duty under Notification issued by Ministry of Finance for bonafide use by victims affected by natural calamity.
12	IIEGC1134E	Persons importing/exporting permissible goods as notified from time to time, from /to China through Gunji, Namgaya Shipkila and Nathula ports, subject to value ceilings of single consignment as given in Paragraph 2.07 (iv) above.
13	NCIEE1169E	Non-commercial imports and exports by entities who have been authorised by Reserve Bank of India.

2.08 Application for IEC

- (a) Exporters / Importers shall file an online application in ANF 2A format for grant of e-IEC with digital signatures along with requisite documents and paying the applicable fee. The facility of filing online application for IEC is also available through e-biz portal of DIPP.
- (b) Deficiency in the application form has to be removed by re-logging onto the “Online IEC application” on DGFT website and resubmitting the form along with the requisite documents.

2.09 IEC Format

An IEC will be issued in prescribed format (ANF 2(A) (II)). A copy of such IEC shall be endorsed to concerned banker (as per details given in ANF 2A). Such endorsement should ordinarily be done using emails.

2.10 Validity of IEC

An IEC allotted to an applicant shall have permanent validity unless cancelled by the competent authority. The IEC will cover all branches / divisions / units / factories of the applicant.

2.11 Validity of IEC for EOUs / SEZs

An IEC will remain valid irrespective of a firm's status as a DTA unit or an EOU or a SEZ/ EHTP/STP/BTP unit and the procedure to be followed in case a firm/unit is de-bonded and converted to DTA is as under:

- (a) An unit which is an EOU or in SEZ/EHTP/STP/BTP after de-bonding will not surrender the IEC obtained from its jurisdictional DC, SEZ.
- (b) The jurisdictional DC, SEZ will send the original IEC file to concerned RA of DGFT after de-bonding.
- (c) RA becomes the custodian of such file and will allow de-bonded unit to make necessary modification in IEC.
- (d) The de-bonded unit to be eligible for benefits from the RA as per FTP.

2.12 One PAN-One IEC

Only one IEC shall be issued against a single PAN. Multiple IECs against a single PAN stands deactivated suo-motu after 31.03.2015.

2.13 Surrender of IEC

If an IEC holder does not wish to operate allotted IEC, he may surrender the same to the issuing authority. On receipt, the issuing authority shall immediately cancel the IEC and electronically transmit it to DGFT and Customs authorities.

2.14 Modification of IEC

- (a) Modifications in e-IEC's/ IEC's can be done online only. Applicants seeking modification in their IEC's may log on to dgft.nic.in and click on Importer Exporter Code (IEC) under Quick Links and select “Modify your IEC” to amend their e-IEC's and IEC's in physical format by paying requisite fees and submitting requisite documents to the concerned jurisdictional RA, from where IEC was originally issued. List of RAs, along with their jurisdiction is given in Appendix 1A.
- (b) An application for modification may be made for change in details like name, address, constitution, ownership in Proprietorship firms, change in nature of the firm e.g. from proprietorship to partnership etc.
- (c) RAs shall consider applications seeking modification in IEC, involving change in PAN, by ensuring that liabilities of the previous applicant/applicant firm are transferred to the new applicant/applicant firm whose PAN will be reflecting in the modified IEC. RAs must also share the modified IEC, with the changed PAN incorporated in it, with all concerned authorities.
- (d) RAs shall also take cognizance of the applications digitally signed by power of attorney holders/authorised signatories.

2.14 (A) Modifications / Change in Branch Office / Head Office / Registered Office Address in IEC involving a shift in jurisdictional RA.

When an IEC holder seeks modification/ change of Branch Office/ Head Office/ Registered Office address in its IEC and which involves a shift in its jurisdictional RA, a request to that effect will have to be made to RA concerned under whose jurisdiction the applicant exists.

On the basis of this request, the RA (Custodian of the IEC File till now) will process such requests and amend IEC, if found appropriate, under intimation to the RA under whose jurisdiction the applicant wants transfer. The new RA shall allow the person in its new address to carry out necessary functions and also apply for eligible benefits as per FTP.

2.15 Profile of Importer / Exporter

- (a) ANF-1 contains the profile of the importer/exporter. IEC Holder shall be responsible for updating the same as and when a change takes place immediately or in any case at least once in a year.
- (b) Documents which are uploaded in the Importer-Exporter Profile are not required to be filed each time the importer/exporter applies for authorisations/scripts under different schemes of this FTP. However, persons seeking any benefit from any authority, by claiming status as manufacturer exporter, have to prove its credence for the same independently to that authority.

Issue of Authorisation:

2.16 Validity period of Authorisation/ Licence / Certificate / Authorisation / Permissions / CCPs

- (a) Validity period of Import / Export Authorisations from the date of issue shall be as follows, unless specified otherwise:

Sr. No.	Type of Authorisation	Validity Period
(i)	Export Authorisation for restricted (Non SCOMET) goods	12 months
(ii)	Export Authorisation for SCOMET items	24 months
(iii)	Import Authorisations for restricted items and CCP	18 months
(iv)	EPCG Authorisation	18 months
(v)	Advance Authorisations (AA) for Deemed Export	Coterminous with contracted duration of project execution or 12 months, whichever is more.
(vi)	AA {except (v) above}, DFIA, Replenishment Authorisation for Gems & Jewellery as per Chapter 4 of FTP.	12 months from issue date.

However, EXIM Facilitation Committee (EFC) (for non-SCOMET items) and Inter Ministerial Working Group (IMWG) (for SCOMET items) may approve the grant of Export Authorisation for a shorter / longer duration in specific cases to meet contractual obligations/delivery schedule or on specific recommendation of the concerned Technical / Administrative Ministry / Department / or any other agency.

- (b) DGFT may decide to issue specific authorisation/ class of authorisations for a longer/shorter validity period. Any extension /revalidation in such cases to be allowed only by DGFT.

2.17 Date of reckoning of Import / Export

- (a) Date of reckoning of import is decided with reference to date of shipment / dispatch of goods from supplying country as given in **Paragraph 9.11** of Handbook of Procedures and not the date of arrival of goods at an Indian port.
- (b) Date of reckoning of export is decided with reference to date of shipment / dispatch of goods from India as given in **Paragraph 9.12** of Handbook of Procedures. However, for benefit under FTP, Let Export Order (LEO) date shall be the date of reckoning of export.

2.18 Validity of Authorisation/ Licence for import/export

- (a) Authorisations must be valid on the date of import.

- (b) Similarly, export obligation period of an Authorization must be valid on the date of export.

2.19 Validity of Scrips

Scrips under Chapter 3 and 5 must be valid on the date on which actual debit of duty is made.

2.20 Revalidation of Import / Export Licence Certificate/ Authorisation / Permissions for Non-SCOMET and SCOMET items

- (a) RA concerned may revalidate import authorisation on merits for six months from date of expiry of validity.
- (b) Export Authorisation including for SCOMET items may be revalidated, on merits for a period of six months at a time and maximum upto 12 months by the RA concerned, except for cases in para 2.16(b) of HBP.
- (c) However, revalidation of freely transferable authorisation / duty credit scrips and stock and sale (excluding SCOMET items) authorisation shall not be permitted unless validity has expired while in custody of Customs Authority / RA / Government Authority.
- (d) Revalidation of Authorisation/Duty Credit Scrip shall also be allowed without charging any fee for the period of delay (the period for which authorisation/scrip holder was unable to utilise the same) or six months, whichever is less, due to the following reasons:
 - (i) If Authorisation/Scrip or any amendment thereof could not be transmitted to Customs Server within fifteen working days from the date of issue/amendment;
 - (ii) If Authorisation/Scrip rejected by Customs server with error Code;
 - (iii) If request for issue of waiver of Bond/EODC was not considered within the period specified under Para 9.10 of HBP, 2015-2020 where complete application was submitted within the validity of the Authorisation.

In such cases, revalidation shall be allowed from the date of endorsement for the period of delay or six months, whichever is less. For example: Authorisation is issued having initial validity of 12 months on 01.04.2017. It was transmitted to Customs server on 01.04.2017 by DGFT server but it is accepted by Customs server on 31.10.2017. So the Authorisation holder loses 7 months (still 5 months validity is left). In such a case, RA shall allow revalidation for a period of 6 months (validity of 5 months is subsumed) from the date of endorsement.

The applicant shall submit request for endorsement of Authorisation/Scrip along with screen shot of DGFT server as well as Customs Server in support of his claim. RA shall verify the same before revalidation is allowed.

However, request must be made to RA concerned within a month from the date of final acceptance of Authorisation/Scrip in the Customs Server.

Notwithstanding anything contained above, these provisions of revalidation shall not apply wherever, the authorisation/scrip holder had clear 6 months period in hand for utilisation.

2.21 Authority to Revalidate

Such revalidation under **Paragraph 2.20** above would be permitted under specific orders of Head of concerned Office and such revalidation would be maximum up to the extent of custody period.

2.22 Application for Revalidation

An application for revalidation of authorisation, may be made to RA concerned. RA would consider such application as per FTP/ HBP. Where DGFT is concerned authority, original application shall be submitted to RA concerned and self-attested copy of same shall be submitted to DGFT.

Procedure for issuing Duplicate copies:

2.23 Duplicate copies of Export / Import Authorisation

Where an Authorisation/ Permissions/ CCPs / Licence / Certificate / is lost or misplaced, an application for issue of a duplicate may be made along with Self declaration, as given in **Appendix 2M**, to concerned RA where the original license was issued.

2.24 Documents required for duplicate copy of freely transferable Authorisation

Duplicate copy of freely transferable Authorisation may be issued against an application accompanied with following documents:

- (i) An application with fee equivalent to 10% of duty saved or duty credit (of unutilized balance).
- (ii) A copy of FIR reporting loss.
- (iii) Self- declaration to indemnify revenue loss, which may be caused on account of issue of such duplicate.

2.25 Exception

When an Authorisation is lost by a Government agency and a proof to this effect is submitted, documents at serial nos. (i) to (iii) of **Paragraph 2.24** above shall not be required. In such cases, revalidation shall be for six months from date of endorsement.

2.26 Mechanism for issuing duplicates

RA concerned shall obtain a report regarding utilization of such Authorisation from Custom authority at port of registration before issuing duplicate, for balance unutilized.

2.27 Validity of duplicate Authorisation

Validity of duplicate Authorisation shall be co-terminus with original period. No request shall be entertained if validity has expired.

2.28 Applicability of the provision

Provision of **Paragraph 2.26 and 2.27** shall be applicable for cases covered under both **Paragraph 2.23 and 2.24**

Bank Guarantee /LUT:**2.29 Execution of BG/Legal undertaking for Advance Authorisation/ EPCG Authorisation**

- (a) Before clearance of goods through Customs, Authorisation holder shall execute a BG/LUT with Customs Authorities. In such cases, RA shall endorse the following condition on the licence/ Authorisation: "BG / LUT as applicable, to be executed with concerned Customs Authorities.
- (b) In case of indigenous sourcing, Authorisation holder shall furnish BG/ LUT to RA as per Customs Circular No.58/2004 dated 31.10.04, as amended from time to time. In case, the firm has already executed BG/LUT for the full value of the licence/ certificate/ authorisation/ permission (covering the items indigenously procured) to the Customs and furnishes proof of the same to Regional Authority (RA), no BG/LUT shall be required to be executed with the RA. The RA concerned shall endorse on the authorisation that the Customs Authority shall release/redeem BG/LUT only after receipt of NOC or EODC from the RA concerned. RA shall endorse a copy of the same along with a forwarding letter to the Customs Authority at the Port of registration for their information and record.

2.30 Corporate Guarantee

A status holder or a PSU may also submit Corporate Guarantee in lieu of Bank Guarantee/LUT in terms of the provisions of relevant Customs Circular in this regard.

2.31 Advance Payment

In case, payment is received in advance and export / deemed export takes place subsequently, application for an Authorisation shall be filed within specific period following the month during which exports/ deemed export is made, unless otherwise specified.

2.32 Import under Lease Financing

Import under lease financing shall be available under EOU/ SEZ scheme. Domestic supply of capital goods to eligible categories of deemed exports shall be eligible for benefits of deemed export as in paragraph 7.03 of FTP, even in cases where supplies are under lease financing.

In case of loss of Documents:**2.33 Issuance of scrips against lost EP copy of the Shipping Bills**

Where EP copy of Shipping Bill is lost, claim for Scrips under Chapter 3 and Chapter 5 can be considered subject to submission of following documents:

- (i) A duplicate /certified copy of relevant document issued by Customs Authority in lieu of original;
- (ii) An application fee equivalent to 2% of relevant entitlement. However, no fee shall be charged when such document is lost by Government agencies and a documentary proof to this effect is submitted
- (iii) Self-declaration by exporter about loss of document and an undertaking to surrender it immediately to concerned RA, if found subsequently
- (iv) Self-declaration by exporter to effect that he would indemnify Government for financial loss if any on account of duty credit issued against lost Shipping Bills. Customs Authority, before allowing clearance, shall ensure that benefit / duty credit against such shipping bill has not been availed.

2.34 Claims against lost copy of shipping bill

Claim against lost Shipping Bill shall be preferred within a period of six months from date of release of duplicate copy of Shipping Bill. Any application received thereafter shall be rejected.

2.35 Submission of Certified Copies of Documents

Wherever original documents have been submitted to a different RA / nominated agencies or to a different division of same RA, applicant can furnish photocopy of documents duly certified by him in lieu of original.

Warehousing Facility:**2.36 Warehousing Facility**

- (a) Public / Private Customs Bonded Warehouses may be set up in DTA as per Chapter-IX of Customs Act, 1962, to import items in terms of **Paragraph 2.36** of FTP. On receipt of goods, such warehouses shall keep these goods for one year without payment of applicable customs duties. Goods can be cleared against Bill of Entry for home consumption, on payment of custom duty and on submission of Authorisation wherever required, after an order for clearance of such goods for home consumption is issued by competent customs authorities. In case of clearance against duty free categories /concessional duty categories, exemption / concession from duty shall be allowed.
- (b) Goods can be re-exported without payment of customs duty provided shipping bill or a bill of export is presented in respect of such goods; and order for export of such goods has been made by competent customs authorities.

Certificates:**2.37 Free Sale and Commerce Certificate**

- (a)
 - (i) RAs may issue, on application, Free Sale and Commerce certificate for export of items not covered under Drugs & Cosmetics Act, 1940, which have usage in hospitals, nursing homes and clinics, for medical and surgical purposes and are not prohibited for export. Validity of such certificate shall be two years from date of issue unless otherwise specified.
 - (ii) An application for grant of Free Sale and Commerce Certificate may be made to RA concerned as per format in **ANF 2 H** of Appendices and Aayat Niryat Forms with Annexure A therein. RA shall issue Free Sale and Commerce Certificate as per Annexure B of ANF2H.
- (b)
 - (i) RAs may also issue, on application, Free Sale and Commerce Certificate for export of any other item which is not restricted or prohibited for export. Validity of such certificate shall be two year from date of issue unless otherwise specified.
 - (ii) An application for grant of Free Sale and Commerce Certificate for these items may be made to RA concerned as per format in **ANF 2H** of Appendices and Aayat Niryat Forms along with Annexure A therein. RA shall issue Free Sale and Commerce Certificate as per Annexure B of **ANF 2H**.

2.38 End User Certificate

In case of import of any freely importable item in India, if a foreign Government insists on certification of end user of the item, before permitting export of the same from their country, RA may issue such certificates as per **Appendix 2Q** of Appendices and Aayat Niryat Forms. The certificate shall be issued based on application made under **ANF 2 J** along with documents prescribed therein.

2.39 Imports under Indo-US Memorandum of Understanding

- (a) Import of specified capital goods, raw materials and components, from United States of America (USA) is subject to US Export Control Regulations. US suppliers of such items are required to obtain an export authorisation based on import certificate issued in India. The following are designated Import Certificate Issuing Authorities (ICIA):
 - (i) Department of Electronics (DoE), for computer and computer based systems
 - (ii) Department of Industrial Policy and Promotion (DIPP), Technical Support Wing (TSW), for organised sector units registered under it, except for computers and computer based systems;
 - (iii) Ministry of Defence (MoD), for defence related items;

- (iv) DGFT for small scale industries and entities not covered above as well as on behalf of any of the above;
- (v) Embassy of India, Washington, DC, on behalf of any of the above.
- (b) Application for an import certificate shall be made in **ANF 2K(i)**. Import certificate in **Appendix-2P(Ia)** may be issued by ICIA directly to importer with a copy to (i) Ministry of External Affairs (MEA) (AMS Section), New Delhi, (ii) DoE, New Delhi; and (iii) DGFT.
- (c) However, this import certificate will not be regarded as a substitute for an import authorisation in respect of items mentioned as restricted in ITC (HS) and an import authorisation will have to be obtained for such items.
- (d) India's import and export with regard to USA's unilateral export control items [**Crime Control (CC)** Items as listed in **Appendix 2P(iia)** and **Regional Security (RS)** items as listed in **Appendix 2P(iib)**] will be governed by the following regulations:
 Items listed at both **Appendix 2P (iia)** and **Appendix 2P(iib)** will be allowed by DGFT for import from USA provided the importer submits the following documents in **ANF 2K(i)** :
 - (i) documentary proof of Bill of Lading indicating Port of USA,
 - (ii) legal undertaking that goods shall not be exported/ alienated; and
 - (iii) Import is with Actual User condition.
- (e) In case the importer wants to subsequently export the imported items from USA., or any part thereof, such export will require an authorisation from DGFT as per ANF 2K(ii) and Export certificate will be issued in the format **Appendix-2P(ib)**.
- (f) Import /export of such items shall be allowed only through EDI enabled ports of India.

Imports:

2.40 Import of Consumer or Other goods as Gifts

- (a) In terms of provisions contained in **Paragraph 2.25** of FTP, an application for grant of CCP for import as gifts of items appearing as restricted for imports in ITC (HS) shall be made to the DGFT as in **ANF 2M** along with documents prescribed therein.
- (b) Where recipient of a gift is a charitable, religious or an educational institution registered under any law in force, and gift sought to be imported has been exempted from payment of customs duty, such import shall be allowed by customs authorities without a CCP.

2.41 Import of Cheque Books /Ticket Forms etc.

Indian branches of foreign banks, insurance companies and travel agencies may import chequebooks, bank draft forms and travellers cheque forms without a CCP. Similarly, airlines / shipping companies operating in India, including persons authorised by such airlines / shipping companies, may import passenger ticket forms without a CCP.

2.42 Import of Reconditioned/ Second Hand Aircraft Spares

Import Authorisation for reconditioned / second hand aircraft spares is not needed on recommendation of Director General of Civil Aviation, Government of India (DGCA).

2.43 Import of Replacement Goods

Goods or parts thereof on being imported and found defective or otherwise unfit for use or which have been damaged after import, may be exported without an Authorisation, and goods in replacement thereof may be supplied free of charge by foreign suppliers or imported against a marine insurance or marine-cum-erection insurance claim settled by an insurance company. Such goods shall be allowed clearance by the customs authorities without an import Authorisation provided that:

- (a) Shipment of replacement goods is made within 24 months from date of clearance of previously imported goods through Customs or within guarantee period in case of machines or parts thereof where such period is more than 24 months; and
- (b) No remittance shall be allowed except for payment of insurance and freight charges where replacement of goods by foreign suppliers is subject to payment of insurance and / or freight by importer and documentary evidence to this effect is produced while making remittance.

2.44 Other Conditions for Import of Replacement Goods

- (a) In case of short-shipment, short-landing or loss in transit, import of replacement goods will be permitted based on certificate issued by customs authorities without an import Authorisation.
- (b) This procedure shall also apply to cases in which short shipment of goods is certified by foreign supplier, who has agreed to replace free of cost.

- (c) Cases not covered by above provisions will be considered on merits by DGFT for grant of Authorisation for replacement of goods for which an application may be made as per paragraph 2.50 of HBP.

2.45 Import of Overseas Office Equipment

On winding up of overseas offices, set up with approval of RBI, used office equipments and other items may be imported without Authorisation.

2.46 Import of Ammunition by Licensed /Authorised Arms Dealers

- (a) Import of following types of ammunition are allowed against an Authorisation by licensed arms dealers subject to conditions as may be specified:
- (i) Shotgun Cartridges 28 bore;
 - (ii) Revolver Cartridges of .450, .455 and .45 bores;
 - (iii) Pistol Cartridges of .25, .30 Mauser, .450 and .45 bores;
 - (iv) Rifle Cartridges of 6.5 mm, .22 savage, .22 Hornet, 300 Sherwood, 32/40, .256, .275, .280, 7m/m Mauser, 7 m/m Man Schoener, 9m/m Mauser, 9 m/m Man Schoener, 8x57, 8x57S, 9.3 m/m, 9.5 m/m, .375 Magnum, .405, .30.06, .270, .30/30 Winch, .318, .33 Winch, .275 Mag., .350 Mag., 400/350, .369 Purdey, .450/400, .470, .32 Win., 458 Win, .380 Rook, .220 Swift and .44 Win. bores.
- (b) An import Authorisation shall be issued at 5% of value of annual average sales turnover of ammunition (whether indigenous or imported) during preceding three licensing years subject to a minimum of Rs. 2000.
- (c) An application for grant of an Authorisation for items listed above may be made to RA in **ANF 2M** along with documents prescribed therein.

2.47 Duty Free Imports for specific Sectors:

(A) R&D Equipment for Pharmaceuticals and Bio- technology Sector

- (i) Duty free import of goods (as specified in list 28 of Customs notification No.21/2012 dated 17.3.2012, as amended from time to time) upto 25% of FOB value of exports during preceding licensing year, shall be allowed.
- (ii) The eligible unit may furnish an application given in Appendix-8A to RA concerned duly countersigned by Chartered Accountant.
- (iii) In respect of duty free import of R&D equipment, units not registered with jurisdictional Customs authority shall be allowed to give Installation Certificate issued by an independent Chartered Engineer.

(B) Agro-Chemicals Sector :

- (i) Duty free imports of goods as specified in list 28A of Customs notification No. 21/2012 dated 17.3.2012, upto 1% of FOB value of exports made during preceding licensing year, shall be allowed to agro chemicals sector unit having export turnover of Rs. 20 crore or above during preceding licensing year.
- (ii) The eligible unit shall apply in form given in Appendix-8B to RA concerned duly countersigned by Chartered Accountant.
- (iii) In respect of duty free import of R&D equipment, units not registered with jurisdictional Customs authority shall be allowed to give Installation Certificate issued by an independent Chartered Engineer.

2.48 Import under Govt. to Govt. Agreements

Import of goods under Government to Government agreements may be allowed without an Authorisation or CCP on production of necessary evidence to satisfaction of Customs authorities.

2.49 Transfer of Imported Goods

(a) Cases where prior permission is required:

Transfer of imported goods which are subject to Actual User condition and have become surplus to needs of Actual User, shall be made only with prior permission of RA concerned. Following information alongwith supporting documents shall be furnished with request for grant of permission for transfer, to RA concerned:

- (i) Reasons for transfer of imported material;
- (ii) Name, address, IEC number and industrial Authorisation registration, if any, of transferee;
- (iii) Description, quantity and value of goods imported and those sought to be transferred;

- (iv) Copies of import Authorisation and bills of entry relating to imports made;
- (v) Terms and conditions of transfer as agreed upon between buyer and seller.

(b) Cases where prior permission is not required

- (i) in case of sale or otherwise by importer of freely importable goods;
- (ii) for goods imported with Actual User condition, provided such good is freely importable without Actual User condition on date of transfer
- (iii) for goods with AU Condition after a period of two years from the date of import.
- (iv) for transfer of Imported Firearms (a) after 10 years of import or (b) on attaining the age of 60 years by such importer, subject to condition that transferee fulfils conditions as in Arms Act and Rules thereunder.
- (v) for transfer of weapon/s (firearm/s) imported by a Renowned Shooter (as defined in Policy Condition 3 of Chapter 93 of ITC (HS) 2012) for the purpose of his/her pursuing shooting as a sport to any upcoming shooter as certified either by the National Rifle Association of India (NRAI) or the Department of Sports, Ministry of Youth Affairs & Sports after two years from the date of import. The transferee can subsequently transfer/resell to any buyer as certified by the NRAI or Department of Sports for the sole purpose of pursuing shooting as a sport after one year from the date of its first sale. Such transfer/sale is subject to the provisions of the Arms Act, 1959 and other rules/regulations by state/local police. NRAI/Department of Sports will maintain the required records.

Import of Restricted Items:

2.50 Import of Restricted Items

An application for grant of an Authorisation for import or export of items mentioned as 'Restricted' in ITC (HS) may be made to RA, with a copy to DGFT Hqrs in ANF 2M along with documents prescribed therein. Original application along with Treasury Receipt (TR) / Demand Draft shall be submitted to RA concerned and self-attested copy of same shall be submitted to DGFT in duplicate along with proof of submission of application to concerned RA.

2.51 EXIM Facilitation Committee

- (a) Restricted item Authorisation may be granted by DGFT or any other RA authorised by him in this behalf. DGFT / RA may take assistance and advice of a Facilitation Committee while granting authorisation. The Assistance of technical authorities may also be taken by seeking their comments in writing. Facilitation Committee will consist of representatives of Technical Authorities and Departments / Ministries concerned.
- (b) Import authorisations for a restricted item, if so directed by the competent authority, shall be issued for import through one of the sea ports or air ports or ICDs or LCS, as per the option indicated, in writing, by the applicant. Authorisation holder shall register the import authorisation at the port specified in the Authorisation and thereafter all imports against said authorisation shall be made only through that port, unless the authorisation holder obtains permission from customs authority concerned to import through any other specified port.
- (c) EXIM Facilitation Committee (EFC) shall normally meet once every month. Where a case has been deferred in EFC for want of comments from the Technical Authorities and Departments / Ministries concerned but subsequently, NOC(s) has / have been received from the concerned agency(ies) with no divergence in views, authorisation shall be issued with the approval of Chairman, EFC and the case shall be brought before EFC in its subsequent meeting for approval on ex-post facto basis.

2.52 Import of Restricted items required by Hotels, Restaurants, Travel Agents, Tour Operators and other Specified Categories

Items mentioned as restricted for imports in ITC (HS) required by hotels, restaurants, travel agents and tour operators may be allowed against an Authorisation, based on recommendation of Director General, Tourism, Government of India.

- (a) Hotels, including tourist hotels, recognised by Director General of Tourism, Government of India or a State Government shall be entitled to import Authorisation upto a value of 25% of foreign exchange earned by them from foreign tourists during preceding licensing year, for import of essential goods related to hotel and tourism industry.
- (b) Travel agents, tour operators, restaurants, and tourist transport operators and other units for tourism, like adventure/ wildlife and convention units, recognized by Director General of Tourism, Government of India, shall be entitled to import authorisation up to a value of 10% of foreign exchange earned by them during preceding licensing year, for import of essential goods which are restricted for imports related to travel and tourism industry, including office and other equipment required for their own professional use.

- (c) Import entitlement under paragraphs **2.52 (a)** and **2.52 (b)** of any one licensing year can be carried forward, either in full or in part, and added to import entitlement of two succeeding licensing years.
- (d) Such imported goods may be transferred after 2 years with permission of DGFT. No permission for transfer will be required in case the imported goods are re-exported. However, re-export shall be subject to all conditionality, or requirement of licence, or permission, as may be required under Schedule II of ITC (HS).
- (e) An application for grant of an Authorisation under paragraphs **2.52 (a)** and **2.52 (b)** may be made in **ANF 2 M** to DGFT through Director of Tourism, Government of India who will forward application to RA concerned along with their recommendations.

2.53 Import of Restricted items for R&D by units of Government

All restricted items and items permitted to be imported by STEs, except live animals, required for R&D purpose may be imported without an Authorisation by Government recognized Research and Development units.

2.54 Import of Metallic Waste and Scrap

Import of any form of metallic waste, scrap will be subject to the condition that it will not contain hazardous, toxic waste, radioactive contaminated waste / scrap containing radioactive material, any type of arms, ammunition, mines, shells, live or used cartridge or any other explosive material in any form either used or otherwise.

- (a) Import of following types of metallic waste and scrap will be free subject to conditions detailed below:

Sl. No.	Exim Code	Item description
1.	720410 00	Waste and scrap of cast iron
2.	72042190	Other
3.	72042920	Of High speed steel
4.	72042990	Other
5.	72043000	Waste and scrap of tinned iron or Steel
6.	72044100	Turnings, shavings, chips, milling waste, saw dust, fillings, trimmings and stampings, whether or not in bundles.
7.	72044900	Other
8.	72045000	Re-melting scrap ingots
9.	74040012	Copper scrap
10.	74040022	Brass scrap
11.	75030010	Nickel scrap
12.	76020010	Aluminium scrap
13.	79020010	Zinc scrap
14.	80020010	Tin scrap
15.	81042010	Magnesium scrap

- (b) 'Freely' Importable metallic waste and scraps (shredded) as listed above shall be permitted through all ports of India subject to following conditions:
- (i) At the time of the clearance of goods, importer shall furnish to the Customs pre-shipment inspection certificate as per the format to Appendix 2H from any of the Inspection & Certification agencies given in Appendix-2G, to the effect that the consignment was checked for radiation level and scrap does not contain radiation level (gamma and neutron) in excess of natural background. The certificate shall give the value of background radiation level at that place as also the maximum radiation level on the scrap; and
- (ii) Importer shall also furnish copy of the contract with the exporter stipulating that the consignment does not contain any radioactive contaminated material in any form.

- (c) Import from Hodaideh, Yemen and Bandar Abbas, Iran will be in shredded form only.
- (d) Import of un-shredded compressed and loose form of metallic waste, scrap listed in paragraph 2.54(a) above in shall be subject to the following conditions:-
- (i) At the time of the clearance of goods, importer shall furnish to the Customs pre-shipment inspection certificate as per the format in Appendix 2H from any of the Inspection & Certification agencies given in Appendix-2G to the effect that the consignment does not contain any type of arms, ammunition, mines, shells, cartridges, or any other explosive material in any form either used or otherwise, and that the consignment was checked for radiation level and it does not contain radiation level (gamma and neutron) in excess of natural background. The certificate shall give the value of background radiation level at that place as also the maximum radiation level on the scrap.
 - (ii) The imported item (s) is actually a metallic waste/ scrap /seconds /defective as per the internationally accepted parameters for such a classification.
 - (iii) Copy of the contract between the importer and the exporter stipulating that the consignment does not contain any type of arms, ammunition, mines, shells, cartridges, radioactive contaminated, or any other explosive material in any form either used or otherwise.
 - (iv) Import of scrap would take place only through following designated ports and no exceptions would be allowed even in case of EOUs, SEZs:-
1. Chennai, 2. Cochin, 3. Ennore, 4. JNPT, 5. Kandla, 6. Mormugao, 7. Mumbai, 8. New Mangalore, 9. Paradip, 10. Tuticorin, 11. Vishakhapatnam, 12. Pipava 13. Mundra, 14. Kolkata.
 - (v) Only entry sea ports will be designated and notified for import of un- shredded Metallic Waste and Scrap subject to the following:
 - (i) Any sea port to be designated for import of un-shredded metallic scrap will be required to install Radiation Portal Monitors and Container Scanner with adequate security. The sea port having completed the above shall approach jurisdictional Customs for inspection and certification. Customs may give necessary clearance on receipt of certification from AERB. On getting clearance from Customs, DGFT will notify such a port as designated port for import of un-shredded scrap.
 - (ii) The existing designated sea ports namely Chennai, Cochin, Ennore, JNPT, Kandla, Mormugao, Mumbai, New Mangalore, Paradip, Tuticorin, Vishakhapatnam, Pipava, Mundra and Kolkata will be allowed to import un-shredded scrap till 31st March, 2018 by which time they are required to install and operationalize Radiation Portal Monitors and Container Scanner. Such sea ports which fail to meet the deadline will be derecognised for the purpose of import of un-shredded metallic scrap w.e.f 1.4.2018.
 - (iii) Further, any ICD can handle clearance of un-shredded metallic scrap provided the same passes through any of the designated sea ports as mentioned above or any new ports to be notified/designated from time to time, where Radiation Portal Monitors and Container Scanner are in operation and the consignment is subjected to risk based scanning/ monitoring as per the protocol laid down by Customs.
 - (iv) Notwithstanding the above, import consignments shall be subject to pre-inspection certificate from the country of origin. However, requirement of Pre-shipment Inspection Certification (PSIC) will be reviewed with the operationalisation of the above mechanism governing the clearance of imports of un- shredded metal scrap, based on assessment of risk associated with un-shredded metal scrap imports.

2.55 Recognition as Pre-shipment Inspection Agency (PSIA) and issuance of Pre- shipment Certificate (PSIC)

- (a) Applications for recognition in respect of PSIAs have to be made in proforma prescribed in **ANF 2L**. The scanned copy of application in **ANF 2L**, along with relevant annexures and documents should be sent by e-mail to DGFT (at psia-dgft@nic.in), in addition to sending the same by post.
- (b) For applicants based in India application fee will be Rs. 7500/- and for applicants based abroad the application fee will be US \$200. The fees may be amended from time to time by DGFT.
- (c) The applications will be considered by an Inter- Ministerial Committee.
- (d) The recognized PSIAs will be notified under **Appendix 2G** for a period of three years. At the end of 3 years PSIA has to make a fresh application for further recognition.
- (e) PSIA shall issue Pre-shipment Inspection Certificate (PSIC) in the format given in **Appendix 2H**. PSIC would also carry uniquely numbered hologram of the PSIA.

- (f) A PSIA can also carry out inspections in countries, where it does not have a full time equipped branch office but which falls within its area of operation, by deputing its Inspectors. However, for such inspections in other countries, the PSIA will be required to give prior intimation to DGFT by sending an email (at psia-travel-dgft@gov.in) and furnishing details of visit / inspection done by the Inspector in PSIC.
- (g) The applicants may submit their applications initially without bank guarantee, as required under S.No.9 of **ANF-2L**. Their applications would not be rejected only on the ground of non-submission of bank guarantee. Applicants would, however, be required to submit bank guarantee or an equivalent financial instrument, before they are notified as PSIA, by the competent authority, as per FTP/HBP 2015-20.

2.56 Responsibility and Liability of PSIA and Importer

- (a) In case of any mis-declaration in PSIC or mis-declaration in application form for recognition as PSIA, PSIA would be liable for penal action under Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992, as amended, in addition to suspension/ cancellation of recognition.
- (b) The importer and exporter would be jointly and severally responsible for ensuring that the material imported is in accordance with the declaration given in PSIC. In case of any mis-declaration, they shall be liable for penal action under Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992, as amended.
- (c) The scanned copy of the PSIC (in pdf format) shall have to be uploaded by the PSIA on DGFT website or emailed to DGFT (at psic-dgft@gov.in). The certificate shall be issued in prescribed form **Appendix 2H**.
- (d) The PSIA will also be required to take photographs or make video of the inspection carried out, duly capturing the following activities/details:
 - (i) Photograph(s) or video clipping of the place of inspection with PSIA inspector (mandatory) and representatives of exporter / importer, if available (optional); with time, date of the inspection (at least 1 photograph or video clipping);
 - (ii) Photograph(s) or video clipping of the testing instrument(s) used for inspection;
 - (iii) Photograph(s) or video clipping of the process of stuffing of containers showing the container number (at least 1 photograph or video clipping per container)
 - (iv) Photograph(s) or video clipping of the sealing process (at least 1 photograph or video clipping per container)
- (e) The photographs and/or video clippings [as per 2.56 (d) above] and PSIC shall be uploaded on DGFT website by PSIA, through digital signatures or sent to psicdgft@gov.in through registered e-mail of PSIA. Till such time the DGFT website link is operationalized, the PSIC and photographs/videos will be e-mailed to the DGFT (at psicdgft@gov.in).

2.57 Import of other kinds of metallic waste and scraps

Import of other kinds of metallic waste and scrap will be allowed in terms of conditions of ITC (HS).

2.58 Imports of seconds and defectives

Import policy for second and defective, rags, PET bottles /waste, and ships is given in ITC (HS).

2.59 Services of Inspection and Certification Agencies

Customs or any other Central or State Government authority may avail of services of Inspection and Certification Agencies in **Appendix 2I** of the Appendices and Aayat Niryat Forms, for certifying residual life as well as valuation / purchase price of capital goods.

Tariff Rate Quota Scheme:

2.60 Procedure for import under the Tariff Rate Quota Scheme

Attention is invited to Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), Notification No. 21/2002- Customs dated 01.03.2002 and Notification No. 33/2010- Customs dated 12.03.2010. As per these, import of four items viz., (1) Skimmed and whole milk powder, milk food for babies etc. (0402.10 or 0402.21) and White Butter, Butter oil, Anhydrous Milk Fat (0405) (2) Maize (corn): other (1005.90) (3) Crude sunflower seed or safflower oil or fractions thereof (1512.11) and (4) Refined rape, colza or mustard oil, other (1514.19 or 1514.99) is allowed in a financial year, up to quantities as well as such concessional rates of customs duty as indicated below:

Description	HS No.	In/out of quota rate (%) as per WTO	In/out of quota rate (%) As per Indian Tariff	Notification	TRQ (in MT)
Skimmed Milk powder/ whole milk powder	040210	15/60	15/60	12/12-Cus Sl. No. 7	10,000
	040221	15/60	15/60	12/12-Cus Sl. No. 7	
Maize (corn), other than seed quality	100590	15/60	0/50	12/12-Cus Sl. No. 37/38	5,00,000
Crude sunflower seed oil and safflower seed oil	151211	50/300	50/75	12/12-Cus Sl. No. 60/61	1,50,000
Rape, colza or mustard oil	151419	45/75	45/10	12/12-Cus Sl. No. 64/66	1,50,000
	151499	45/75	45/10	12/12-Cus Sl. No. 64/66	
Butter and other fats	040510	n.a.	0/30	12/12-Cus Sl. No. 9	15,000
	04059010		0/30	12/12-Cus Sl. No. 9	
	04059020		0/30	12/12-Cus Sl. No. 9	
Butter and other fats	040520	n.a.	0/40	12/12-Cus Sl. No. 9	15,000
	04059090		0/40	12/12-Cus Sl. No. 9	

2.61 Eligible entities for allocation of quota

- Milk Powder (Tariff Code No. 0402.10 or 0402.21) and White Butter, Butter oil, Anhydrous Milk Fat (0405): National Dairy Development Board (NDDB), State Trading Corporation (STC), National Cooperative Dairy Federation (NCDF), National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Ltd. (NAFED), Minerals and Metals Trading Corporation (MMTC), Projects & Equipment Corporation of India Limited (PEC) and Spices Trading Corporation Limited (STCL).
- Maize (corn)(Tariff Code No. 1005.90): National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Ltd.(NAFED), State Trading Corporation (STC), Minerals and Metals Trading Corporation (MMTC), Projects & Equipment Corporation of India Limited(PEC), Spices Trading Corporation Limited (STCL) and State Cooperative Marketing Federations
- Crude sunflower seed or safflower oil or fractions thereof (Tariff Code No. 1512.11) and Refined rape, colza, canola or mustard oil, other (Tariff Code No. 1514.19 or 1514.99): National Dairy Development Board (NDDB), State Trading Corporation (STC), National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Ltd.(NAFED),Spices Trading Corporation Limited (STCL) and Central Warehousing Corporation (CWC), State Cooperative Marketing Federation & State Cooperative Civil Supplies Corporation.

2.62 Conditions applicable on availing quotas

All eligible entities are eligible to avail quotas subject to the conditions as detailed below:

- All eligible entities desiring availment of quota as mentioned above, may make application to EFC in **ANF 2M** to DGFT, Udyog Bhavan, New Delhi – 110 011. Completed application forms along with prescribed documents must reach on or before 1st March of each financial year preceding to the year of quota
- Imports have to be completed before 31st March of financial year i.e. consignments must be cleared by customs authorities before this date.
- Since import of maize (corn) is through STEs, the allottees of quota i.e. designated agencies in paragraph 2.61 (b) above for this item shall also be granted an import Authorisation for allotted quantities as indicated at Sl. No. 21 (b) of Customs Notification No. 21/2002 dated 1.3.2002 in terms of paragraph 2.20 of FTP, 2015-2020.

- (iv) Application fee for these applications shall be paid according to procedure contained in **Appendix 2K of Appendices & Aayat Niryat Forms.**
- (v) EFC in DGFT will evaluate and allot quota among applicants by 31st March of each financial year preceeding to year of quota.

Exhibits and Samples:

2.63 Exhibits Required for National and International Exhibitions or Fairs and Demonstration

- (a) Import / export of exhibits, which are freely importable/exportable, including construction and decorative materials required for the temporary stands of foreign / Indian exhibitors at exhibitions, fair or similar show or display for a period of six months on re-export / re-import basis, shall be allowed without an Authorisation on submission of a bond/ security to Customs or ATA Carnet.
- (b) Extension beyond six months for re-export / re-import will be considered by Customs authorities on merits. Consumables such as paints, printed material, pamphlets, literature etc. pertaining to exhibits need not be re-exported/re-imported.

2.64 Sale of Exhibits

- (a) Restricted Items: Sale of exhibits of restricted items, mentioned in ITC (HS), imported for an international exhibition / fair may also be made, without an Authorisation within bond period allowed for re-export, on payment of applicable customs duties, subject to a ceiling limit of Rs.5 lakh (CIF) for such exhibits for each exhibitor.
- (b) Freely importable items: However, sale of exhibits of items which are freely importable shall be allowed within bond period allowed for re-export on payment of applicable customs duties.
- (c) If goods brought for exhibition are not re-exported or sold within bond period due to circumstances beyond control of importer, Customs Authorities may allow extension of bond period on merits.

2.65 Import of Samples

- (a) No Authorisation shall be required for Import of bonafide technical and trade samples of items restricted in ITC (HS) except vegetable seeds, bees and new drugs. Samples of tea not exceeding Rs.2000 (CIF) in one consignment shall be allowed without an Authorisation by any person connected with Tea industry.
- (b) Duty free import of samples upto Rs.3,00,000 for all exporters shall be allowed as per terms and conditions of Customs Notification.

2.66 Exports of Samples / Exhibits

- (a) Exports of bonafide trade and technical samples of freely exportable item shall be allowed without any limit.
- (b) An application for export of samples/exhibits, which are restricted for export, may be made to DGFT as per ANF-2Q.

Exports :

2.67 Export Policy

Policy relating to Exports is given in Chapter-2 of FTP. Further, Schedule 2, Appendix-1 of ITC (HS) specifies list of items, which may be exported without an Authorisation but subject to terms and conditions specified.

2.68 Gifts / Spares / Replacement Goods

For export of gifts, indigenous / imported warranty spares and replacement goods in excess of ceiling / period prescribed for exports of Gifts; export of Spares and export of replacement goods in FTP, an application may be made to DGFT in ANF 2Q.

2.69 Export of Items Reserved for MSME Sector

Units other than small scale units are permitted to expand or create new capacities in respect of items reserved for small scale sector, subject to condition that they obtain an Industrial licence under the Industries (Development and Regulation) Act, 1951, with export obligation as may be specified. Such licensee is required to furnish a LUT to RA and DGFT in this regard. DGFT / RA concerned shall monitor export obligation.

2.70 Export by post

In case of export by post, exporter shall submit following documents in lieu of documents prescribed for export by sea/air:

- (a) Bank Certificate of Export and Realisation as in e-BRC in Appendix2U

- (b) Relevant postal receipt
- (c) Invoice duly attested by Customs Authorities.

2.71 Direct negotiation of export documents

In cases where exporter directly negotiates document (not through authorised dealer) with permission of RBI, he is required to submit following documents for availing of benefits under export promotion schemes:

- (a) Permission from RBI allowing direct negotiation of documents (not required for status holders),
- (b) Copy of Foreign Inward Remittance Certificate (FIRC) as per Form 10-H of Income Tax department in lieu of BRC, and
- (c) Statement giving details of shipping bills / invoice against which FIRC was issued.

SCOMET:

2.72 Application for Grant of Export Authorisation/Certificate/ Permission for non-SCOMET Items

- (a) An application for grant of Export Authorisation in respect of restricted items [other than Special Chemicals, Organisms, Materials, Equipment and Technologies (SCOMET)] mentioned in Schedule 2 of ITC (HS) Classifications of Export and Import Items may be made in **ANF 2 N** to DGFT (Headquarters) along with documents prescribed therein. EFC shall consider applications on merits for issue of export Authorisation.
- (b) If the exporter has been notified in writing by DGFT or he knows or has reason to believe that an item not covered in the SCOMET list has a potential risk of use in or diversion to weapons of mass destruction (WMD) or in their missile system or military end use (including by terrorists and non-state actors), the export of such an item may be denied or permitted subject to the grant of a license, as per the procedure provided for SCOMET items in Paragraph 2.73.

Note: “Military use” shall mean incorporation into items listed in SCOMET Categories 5D or 6 or for the use, development, or production of military items listed in these categories.’

2.73 Application for SCOMET Authorisation

- (a) An application for grant of Export Authorisation in respect of SCOMET items mentioned in Appendix 3 to Schedule 2 of ITC (HS) Classifications of Export and Import Items may be made in **ANF 2 O** to DGFT (Hqrs) along with documents prescribed therein.
- (b) However, such applications are mandatorily to be filed through online system under the Icon E-COM on the website of DGFT. The Uniform Resource Locator [URL] for online application is <http://dgft.gov.in/CallModule.asp?scl =SCOMET>. While submitting the online application, all the required documents including End User Certificates (EUCs) are to be uploaded as PDF files. Manual submission of application is dispensed with except the original End User Certificate(s) in **Appendix 2 S** from all entities in the chain of supply viz. the foreign buyer, end user and intermediary/consignee (if they are different from the foreign buyer & end user), which is/are to be submitted in hard copy to SCOMET Section of DGFT (HQ), besides electronic submission.

(c) Maintenance of Records:

Every SCOMET authorisation holder shall maintain the following records in manual or electronic form for a period of 5 years from the date of export or import, as applicable:

- a) All documents submitted while making an application for SCOMET Authorization.
- b) Correspondence with buyer/consignee/end-user or DGFT or relevant Government agency;
- c) Relevant Contracts;
- d) Relevant Books of account;
- e) Relevant Financial records;
- f) Any communication from any government agency related to an application for authorization for any item on the SCOMET list or a commodity classification request;
- g) Shipping documents including shipping bill, bill of entry and bill of lading.

2.74 Inter Ministerial Working Group

An Inter-Ministerial Working Group (IMWG) in DGFT (Hqrs.) shall consider applications for export of SCOMET items as specified in Appendix-3 to Schedule 2 of ITC (HS) Classifications of Export and Import Items based on following guidelines:

- I. Applications for Authorisation to export items or technology on SCOMET List are considered on the basis of following general criteria:
 - (a) Credential of end-user, credibility of declaration of end-use of the item or technology, integrity of chain of transmission of item from supplier to end-user, and on potential of the item or technology, including timing of its export, to contribute to end-uses that are not in conformity with India's national security or foreign policy goals and objectives, goals and objectives of global non-proliferation, or India's obligations under International treaties/Agreements to which it is a State party.
 - (b) Assessed risk that exported items will fall into hands of terrorists, terrorist groups, and non-State actors;
 - (c) Export control measures instituted by the recipient State;
 - (d) Capabilities and objectives of programmes of the recipient State relating to weapons and their delivery;
 - (e) Assessment of end-use(s) of item(s);
 - (f) Applicability of provisions of relevant bilateral or multilateral Agreements and Arrangements, to which India is a party, or adherent, including but not limited to the guidelines and control lists of the Nuclear Suppliers Group, Missile Technology Control Regime, Australia Group and Wassenaar Arrangement (and its Sensitive List and Very Sensitive List) as updated from time to time.
- II. Application shall be accompanied by an end user certificate as per **Appendix 2S**, certifying that:
 - (a) The item will be used only for stated purpose and that such use will not be changed, nor items modified or replicated without consent of Government of India;
 - (b) Neither the items nor replicas nor derivatives thereof will be re-transferred without consent of Government of India;
 - (c) End-user shall facilitate such verifications as are required by Government of India.
- III. The end-user certificate will indicate the name of the item to be exported, the name of the importer, the specific end-use of the subject goods and details of Purchase Order/Contract.
- IV. Government of India may also require additional formal assurances, as deemed appropriate, including those on end-use and non-retransfer, from the State of the recipient.
- V. (a) Licensing authority for items in Category 0 and Note 2 of the 'Commodity Identification Note' in Appendix 3 to Schedule 2 of ITC (HS) is Department of Atomic Energy. Applicable guidelines are notified by the Department of Atomic Energy under Atomic Energy Act, 1962. For certain items in Category 0, formal assurances from the recipient State will include non-use in any nuclear explosive device. Authorisations for export of certain items in Category 0 will not be granted unless transfer is additionally under adequate physical protection and is covered by appropriate International Atomic Energy Agency (IAEA) safeguards, or any other mutually agreed controls on transferred items.
 - (b) Licensing authority for items in Category 6 in Appendix 3 to Schedule 2 of ITC (HS) is Department of Defence Production. Export of items in Category 6 is governed by the extant Standard Operating Procedure issued by the Department of Defence Production in the Ministry of Defence. Export of items covered in Note 3 of the 'Commodity Identification Note' in Appendix 3 to Schedule 2 of ITC (HS) is prohibited.
- VI. Additional end-use conditions may be stipulated in Authorisations for export of items or technology that bear possibility of diversion to or use in development or manufacture of, or use as, systems capable of delivery of weapons of mass destruction.
- VII. Authorisations for export of items in SCOMET List (other than those under Category 0, 1 and 2) solely for purposes of display or exhibition shall not require any end-use or end-user certification. However, no export Authorisation for display or exhibition shall be issued for 'Technology' in any category. IMWG would seek comments from technical agencies as deemed necessary.
- VIII. Authorization for export of items in Categories 0, 3 (other than 3D), 4, 5 and 7 of the SCOMET list to Iran would be subject to the relevant provisions contained in Annex B to the UN Security Council resolution 2231 (2015). The licensing authority, i.e. DGFT or Department of Atomic Energy, as the case may be, on completion of the

IMWG process or the applicable internal process, shall seek the concurrence of Disarmament and International Security Affairs (D&ISA) Division in the Ministry of External Affairs, as required.

- IX. The Inter Ministerial Working Group shall normally meet once every month. Where a case has been deferred in the IMWG and subsequently, NOC(s) has / have been received from all concerned agencies with no divergence in views, authorisation shall be issued with the approval of Chairman, IMWG and the case shall be brought before IMWG in its subsequent meeting for approval on ex-post facto basis. Case(s) where a decision could not be arrived at in IMWG shall be placed before Director General of Foreign Trade for appropriate decision on grant of authorization.

2.75 Applicability of WMD Act

Export of items not on SCOMET List may also be regulated under provisions of the Weapons of Mass Destruction and their Delivery Systems (Prohibition of Unlawful Activities) Act, 2005.

- Note 1: Export or attempt to export in violation of any of conditions of Authorisation shall invite civil and/or criminal prosecution.
- Note 2: Authorisations for export of items in SCOMET List for display or exhibition abroad are subject to a condition of re-import within a period not exceeding six months. Exporters are entitled to apply for an export authorisation for such items exhibited abroad. If exhibitor intends to offer that item for sale during exhibition abroad, such sale shall not take place without a valid Authorisation.
- Note 3: Export of items in Category 2 of SCOMET list may also be controlled by other applicable guidelines issued from time-to time.
- Note 4: Exporters are entitled to request that only such conditions need be imposed as are subject of government-to-government instruments of accord over export of items on SCOMET List.
- Note 5: 'Technology' (see also entry 'Technology' in glossary in Appendix-3 to Schedule 2 of ITC (HS) Classifications of Export and Import Items): Approval of export of an item on the SCOMET List also authorizes the export to same end-user of minimum 'technology' required for installation, operation, maintenance and repair of the item.

2.76 Supply of SCOMET Items from DTA to SEZ

No export authorisation is required for supply of SCOMET items from DTA to SEZ. However, all supplies of SCOMET items from DTA to SEZ will be reported to the Development Commissioner of the respective SEZ by the supplier in the prescribed proforma [Annexure 1 to Appendix-3 to Schedule 2 of ITC (HS) Classifications of Export and Import Items] within one week of the supplies getting effected. An annual report of such supplies from DTA to SEZ shall be sent to SCOMET Section, DGFT (Hqrs), Department of Commerce, Udyog Bhawan, Maulana Azad Road, New Delhi-110011, by the Development Commissioner (DC), SEZ in the prescribed proforma [Annexure 2 to Appendix-3 to Schedule 2 of ITC (HS) Classifications of Export and Import Items]. Report by the DC, SEZ is to be filed by 15th May of every financial year for the supplies effected during the preceding financial year. Export Authorisation is, however, required if the SCOMET items are to be physically exported outside the country from SEZ i.e. to another country (Refer Rule 26 of the SEZ Rules, 2006).

2.77 Outreach Programmes on SCOMET Export Control System

DGFT in association with Administrative Ministries/ Departments and Trade Associations will organize Industry Outreach Programme on regular basis for an effective awareness among the exporters/ importers dealing with trade, in particular, in SCOMET items.

2.78 Procedure/ Guidelines for filing / Evaluation of Applications for Entering into an Arrangement or Understanding for Site Visits, On-site Verification and Access to Records / Documentation

An application for entering into an arrangement or understanding involving site visit, on-site verification or access to records/documentation by a foreign government or a foreign third party either acting directly or through an Indian party as mentioned in Appendix 3 of Schedule 2 of ITC (HS) Classifications of Export and Import Items shall be made in **ANF 2 P** to DGFT (Hqrs.), New Delhi along with documents prescribed therein. These applications shall be considered by an Inter-Ministerial Working Group (IMWG) in DGFT (Hqrs.) based on following guidelines/general criteria:

- I. Following factors, among others, will be taken into account in the evaluation of applications for entering into an arrangement or understanding for site visits, on-site verification and access to records/ documentation:
- (a) Purpose for which arrangement / understanding is proposed under which site visit or on-site verification or access to records/documentation is to be undertaken.
 - (b) Credentials and details of the parties involved.
 - (c) Credentials of end-user, credibility of declarations of end-use of the items or technology, the integrity of chain of transmission of the item from the supplier to the end-user, and on the potential of the item

or technology, including the timing of its export, to contribute to end-uses that are not in conformity with India's national security or foreign policy goals and objectives, the objectives of global non-proliferation, or its obligations under treaties to which it is a State party.

- (d) The assessed risk that the arrangement / understanding could lead to dual-use items and technology falling into the hands of terrorists, terrorist groups and non-State actors.
- (e) In case site visit, on-site verification or access to records/ documentation is to be carried out by a foreign government or its representative(s), the following shall be taken into consideration :-
 - (i) Export control measures instituted by the foreign government;
 - (ii) Capabilities and objectives of programs of the foreign government relating to weapons and their delivery.
- (f) Applicability of relevant bilateral and multilateral agreements to which India is a party.
- (g) Assessment of any threat that such site visit, on-site verification or access to records/ documentation may pose to India's national security, and relations with any other country.
- (h) Assessment of possible links of the foreign parties with terrorist organizations and non-state actors within their own country or in any other country.

II. Permission for arrangement or understanding involving site visit, on-site verification or access to records / documentation will be subject to the following conditions:

- (a) Site visit, on-site verification or access to records /documentation will be confined to the purpose, sites and activity for which permission given/which have been mentioned in the authorisation.
- (b) Site visit, on-site verification or access to records/ documentation will be allowed only to individuals mentioned in the authorisation.
- (c) Site visit, on-site verification or access to records/ documentation shall be concluded during the period mentioned in the authorisation.
- (d) Exporter/Importer will keep a record of site visit, on site verification or access to records/documentation alongwith detail of individuals who visited the premises during this visit and produce the same as and when required to do so by the Government of India.
- (e) No exchange of goods, services and technologies and any documentation including drawings, specification sheets etc. will take place during the visit.
- (f) Exporter/importer may be required to give any additional assurance that the Government of India may require.
- (g) Any other condition that may be stipulated in the permission.

III. Provisions of Weapons of Mass Destruction Act, 2005 shall also apply to an arrangement or understanding that involves site visit, on-site verification or access to records/ documentation.

IV. Any violation of any condition of the license shall invite civil/ criminal prosecution as per law.

2.79 Issue of authorisation for repeat orders

Applications for grant of authorizations for repeat orders for export of SCOMET items shall be approved by Chairman IMWG and the case shall be brought before IMWG in its subsequent meeting for approval on ex-post facto basis. The approval will be subject to the fulfillment of the following criteria:

- (i) (a) the product along with the technical specification (b) the exporter (c) the foreign buyer (d) the consignee or the intermediaries, if any (e) the end user (f) the end use and (g) the country of destination; shall be same.
- (ii) The permitted quantity against repeat export authorisations shall not be more than 2 times of the quantity in original authorisation, subject to the annual manufacturing capacity of the end user in respect of the relevant product, as certified by the end user.
- (iii) Only the applications submitted within two years from the date of approval by IMWG of the original SCOMET authorisation will be eligible for repeat authorisation.
- (iv) There shall be a cap of two repeat authorisations against the original authorisation.
- (v) A declaration by the authorised signatory on the qualifying conditions as per (i) to (iv) above shall be submitted along with the application for consideration under the repeat order route.

2.79A Issue of export authorisation for "Stock and Sale" of SCOMET items

Stockist' refers to the entity abroad to whom the SCOMET items are originally exported by Indian principal/wholly owned subsidiary. The Stockist entity should be a subsidiary/principal company abroad of the Indian exporter. Applications for grant of authorization for export of SCOMET items for 'Stock & Sale' purpose shall be evaluated/considered by IMWG subject to the conditions prescribed as under:

a) Application for Authorization for Export of SCOMET items for 'Stock & Sale' purpose to the Stockist

- i. Export shall be permitted only from the principal company/the wholly owned subsidiary in India to their subsidiaries/principal company abroad on the basis of an End Use cum End User certificate (EUC) from the latter for 'stock & sale' purposes (as per Appendix 2S(iii)), when considered appropriate from the point of view of security and other critical considerations. The exhaustive list of countries to which exports would be done by the stockist needs to be indicated in the EUC for 'stock & sale' purposes. Documentary proof regarding relationship between exporter and stockist entity needs to be submitted at the time of application.
- ii. The Stock & Sale Authorization holder would submit a statement of exports made from India, inventory with the stockist and transfers made to final end-users as on December 31st of each calendar year by 31st January of the following year. A consolidated statement would be required to be submitted within a period of 3 months from the expiry of the Stock & Sale Authorization.
- iii. The items exported to the stockist entity under this authorization should be transferred to the final end-user within the validity period of the authorization. The authorization may be revalidated as per the procedure mentioned in Paragraph 2.80 of HBP.
- iv. No applications for Authorization for Export of SCOMET items for 'Stock & Sale' purpose would be considered for items falling in Category 0, 1C and 6 of the SCOMET list.
- v. No export Authorisation for 'Stock & Sale' purpose shall be issued for 'Technology' in any category.

(b) Application for permission for re-export/re-transfer from 'Stockist' to Ultimate end-user(s)

- (i) Applications for re-export/re-transfer of items from the stockist entity to the end-user to be submitted to DGFT(Hq) as per ANF 20(a) along with the following documents (hereinafter referred to as required documents):-
 - a) End-use/End-user certificate from each link in the supply chain as per Appendix- 2S (i)/2S(ii), as applicable
 - b) Purchase Order(s)/Invoice(s)
 - c) Technical specifications of the product to be transferred (only if there is any value addition in the product by the stockist)
- (ii) Re-transfer within the same country by the stockist:-
 - a) For any further transfer of these items by the stockist entity (to whom the items are originally exported by Indian principal/wholly owned subsidiary) to entity (ies), including end users, in the same country, the former shall obtain the required documents from each link in the supply chain and forward the same to the Indian applicant/licensee for the purpose of submission to DGFT(Hq) for seeking prior permission for such transfer. The IMWG may, however, relax this requirement of prior permission based on a Risk Assessment for such within same country sale/transfer.
 - b) In case of same country sale/transfer by the stockist entity, where IMWG has agreed to relax the requirement of prior permission, the required documents shall be submitted by the Indian applicant/licensee within 3 months of any such transfer. In such case, no link in the supply chain should be an entity outside the country and items should remain within the country.
 - c) Country would denote an independent sovereign entity which is a distinct national entity in political geography. Hence, transfers within an economic union or a customs union would not qualify as "same country transfers".
- (iii) Re-export outside the country by the stockist:- Application for re-export by the stockist entity to entity(ies) outside its country, shall be forwarded by the stockist entity to the Indian applicant/licensee, with the required documents from all links in chain of supply for the purpose of submission to DGFT(Hq) for seeking prior permission for such transfer.
- (iv) Applications for re-export/re-transfer of SCOMET items from the stockist entity to the end-user for repeat orders shall be considered by IMWG on automatic basis, subject to the condition that the product along with the technical specifications; the foreign buyer; the consignee or the intermediaries, if any; the end user; the end use and the country of destination, shall be the same as the earlier permission.

2.79B Issue of export authorisation for spare parts of SCOMET items under stock and sale

At the request of the applicant, export permission for spare parts covered under SCOMET may be considered by IMWG along with the application for the main item/ equipment. Accordingly, the applicant seeking permission for export of

spares may indicate the requirement of spares in the application for main equipment after judicious and reasonable assessment thereof, and provide the justification for the same.

2.80 Revalidation of SCOMET authorisation

Export license for SCOMET items may be revalidated by RA concerned as per para 2.20 (b) of HBP.

2.81 Export of SCOMET Category 6 items

Notwithstanding anything contained in Paragraphs 2.73 to 2.80, Export of SCOMET Category 6 items will be permitted against an authorisation issued by Department of Defence Production. The grant of authorisation will be governed by the Standard Operating Procedure (SOP) issued for the purpose by Department of Defence Production.

2.82 Timeline for comments/NOC

The members of IMWG will endeavour to furnish their written comments/views/No Objection to DGFT within 30 days from the date of forwarding of applications by DGFT (Hqrs.). If no comments/views/No Objection is received within the stipulated period. The cases will be placed before IMWG for taking a decision as deemed appropriate.

Export through State Trading Enterprises (STE):

2.83 Export of Items under (STE)

An application under ANF 2N for export of items mentioned in ITC (HS), 2012 under STE regime may be made to DGFT as per paragraph 2.20 of FTP.

Provisions for exporters/other provisions for doing trade and business:

2.84 Free of Cost Exports for status holders

Status holders shall be entitled to export freely exportable items on free of cost basis for export promotion subject to an annual limit of Rs.10 lakh or 2% of average annual export realisation during preceding three licensing years whichever is lower. For Pharma exports, the annual limit would be 2% of the annual export realisation during preceding three licensing years. In case of government supplies and supplies of vaccines and lifesaving drugs to health programmes of international agencies such as UN and WHO-PAHO, the annual limit shall be upto 8% of the average annual export realisation during preceding three licensing years. Such free of cost supplies shall not be entitled to Duty Drawback or any other export incentive under any export promotion scheme.

2.85 Admissibility of benefits on payment through insurance cover

(I) Payment through ECGC cover would count for benefits under FTP.

(II) Payment through General/ Private Insurance companies:

Amount of Insurance Cover for transit loss by General Insurance and Private Approved Insurance Companies in India would be treated as payment realized for exports under various export promotion schemes.

(a) An applicant realizing export proceeds through Insurance Agency will approach the concerned RA with the proof of payment issued by the concerned Insurance Agency. RA after satisfying itself of the bona fide of the claim, will obtain approval of Additional DGFT (EDI) and then will upload the value (in lieu of e BRC value) in EDI system of DGFT for processing of the case.

(b) If the proof of payment issued by the Insurance Agency mentions claim value both in foreign exchange and INR, RA will use the foreign exchange value for processing. If the claim value is mentioned only in equivalent INR, RA will convert this INR value in equivalent US\$ using the exchange rate (published by CBEC) applicable on the date of settlement of insurance claim”.

2.86 Irrevocable Letter of Credit

In case where applicant applies for duty credit scrip / discharge of EO against confirmed irrevocable letter of credit (or bill of exchange which is unconditionally Avalised / Co-Accepted / Guaranteed by a bank) and this is confirmed and certified by exporter's bank in relevant Bank Certificate of Export and Realization, payment of export proceeds shall be deemed to have been realized. For Status Holders, irrevocable letter of credit would suffice.

2.87 RBI write-off on export proceeds realization

Realization of export proceeds shall not be insisted under Foreign Trade Policy, if the Reserve Bank of India (RBI) or any “Authorised Bank” (authorised by RBI for this purpose) writes off the requirement of realization of export proceeds on merits and the exporter produces a certificate from the concerned Foreign Mission of India about the fact of non-recovery of export proceeds from the buyer. However, this would not be applicable in self – write off cases.

2.88 Conversion of E.P. copy of shipping bill from one Scheme to another

If Customs Authorities, after recording reasons in writing, permit conversion of an E.P. copy of any scheme-shipping bill on which benefit of that scheme has not been availed, exporter would be entitled to benefit under scheme in which shipment is subsequently converted.

2.89 Offsetting of Export Proceeds

Subject to specific approval of RBI, any payables, or equity investment made by an Authorisation holder under any export promotion scheme, can be used to offset receipts of his export proceeds. In such cases, offsetting would be equal to realisation of export proceeds and exporter would have to submit following additional documents:

- (a) **Appendix-2L** in lieu of Bank Realisation Certificate.
- (b) Specific permission of RBI.

Provisions related to Quality Certification:**2.90 Quality Certification**

It has been a constant endeavour to promote quality standards in export product / units manufacturing export product.

Agencies authorised to grant Quality Certification:

- (a) List of such agencies authorised to grant quality certification is given in **Appendix-2I**
- (b) For ISO 9000 (Series) and for ISO 14000 (Series), the Agencies accredited with National Accreditation Board for Certification Bodies (NABCB) under Quality Council of India shall be deemed to be authorised under this Policy. List of such accredited agencies is available on the web site www.qcin.org and also provided under **Appendix 2I**
- (c) The agencies for ISO (9000) Series & ISO 14000 Series have been accredited on further classification of:
 - (i) Quality Management System(QMS)-http://www.qcin.org/nabcb/accreditation/reg_bod_qms.php for Quality Management Systems
 - (ii) Environmental Management System(EMS) -http://www.qcin.org/nabcb/accreditation/reg_bod_ems.php for Environmental Management system .

These agencies are listed in **Appendix 2I** of the AANF.
- (d) Any agency desirous of enlistment in **Appendix 2I** may submit their application as per Annexure I to **Appendix 2I** to the DGFT.

2.90 A Track and Trace system for export of drug formulations

Procedure for Implementation of the Track and Trace system for export of drug formulations will be as under :

- i. The manufacturer or the exporter of drug formulations will print the barcode as per **GS1 Global Standard** at different packaging levels to facilitate tracking and tracing of their products. The details are as follows:

a) Primary Level:

Incorporation of two dimensional (2D) barcode encoding unique and **universal global product identification** code in the format of 14 digits Global Trade Item Number (GTIN) along with batch number, expiry date and a unique serial number of the primary pack. The bar code labeling at primary level is exempted till further notification; however, the above mentioned details are required to be printed in human readable form on **optional basis** till further notification.

b) Secondary level:

Incorporation of one or two dimensional (1D or 2D) barcode encoding unique and universal global product identification code in the format of 14 digits Global Trade Item Number (GTIN) along with batch number, expiry date and a unique serial number of the secondary pack. However, incase of monocartons manufacturer or exporter shall affix bar code on mono carton containing one primary pack on optional basis till further notification.

c) Tertiary Level:

Incorporation of one dimensional (1D) barcode encoding unique and universal global product identification code in the format of 14 digits Global Trade Item Number (GTIN) along with batch number, expiry date and a unique serial number of the tertiary pack i.e. Serial Shipping Container Code (SSCC).

ii. Parent-Child Relationship for SSI and Non-SSI Manufacturers:

The manufacturer or exporter shall maintain the data in the parent-child relationship for three levels of packaging i.e. Primary, Secondary and Tertiary packaging and their movement in its supply chain.

iii. Maintenance of data of Parent-Child relationship:

The data mentioned in (ii) above shall be uploaded on the central portal of the Government of India (<http://dava.gov.in>) by the manufacturer or exporter or its designated agency before release of the drug formulations for sale or distribution.

iv. The responsibility of the correctness, completeness and ensuring timely upload of data on the central portal shall be with the manufacturer or exporter.

v. In case, the Government of the importing country has mandated a specific requirement, the exporter has the option of adhering to the same and in such a case, it would not be necessary to comply with the stipulation under sub para (i) to (iv) above and if an exporter is seeking to avail such exemption from bar coding prescribed by the Government of India as above, the exporter is given the option to move an application to the Pharmaceutical Export Promotion Council of India (Pharmexcil) for this purpose, clearly specifying the nature of such an exemption in the interest of the exports from the country. Pharmexcil shall dispose of such applications on case to case basis with prior approval of Government. However, the tertiary level of packaging will have additional printing of barcode as per Para 2 (i) (c) in addition to importing country's requirement, if any.

vi. Export of drugs manufactured by non-SSI units and having manufacturing date prior to 31.03.2016 and export of the drugs manufactured by SSI units and having manufacturing date prior to 31.03.2017 are exempted from requirement of data uploading on Central Portal.

vii All drugs manufactured by non SSI units with manufacturing date on or after 01.04.2016 and all drug manufactured by SSI units with manufacturing date on or after 01.04.2017 can be exported only if both tertiary and secondary packaging carry barcoding as applicable and the relevant data as prescribed by DGFT is uploaded on the Central Portal.

Explanation:

(a) For the purpose of this rule,

(i) Drug formulation means a formulation manufactured with a license from Drug Control Authority under the provisions of Drugs & Cosmetics Act and Rules made there under and registered as "Drug" with the FDA of importing country.

(ii) Primary packaging means the package which is in direct physical contact with the active ingredient.

(iii) Secondary packaging means a carton containing one or more primary packs and includes a mono carton containing one primary pack.

(iv) Tertiary packaging means a shipper containing one or more secondary packs.

(b) All relevant guidelines regarding grant of specific exemption(s) if any, procedure of data requirement / maintenance / upload on central portal and clarifications issued under this notification etc. will be available on the central portal i.e. <http://dava.gov.in>

(c) It will be the responsibility of the drug manufactures/exporters as the case may be, to satisfy the customs authorities that the export consignment satisfies the conditions of the Notification

Export Promotion Council (EPC)/ Commodity Boards:**2.91 Registering Authorities**

(a) Registering Authority is a body notified by DGFT in this regard to register importers/ exporters as its members by issuing RCMC.

(b) The list of notified Registering Authorities is at **Appendix-2 T**.

(c) EPCs acting as the Registering Authorities for RCMC at present will continue to act as Registering Authorities and issue RCMC to their members till 31st March, 2016. EPCs wishing to continue as Registering Authority for their product group thereafter shall have to comply and fulfil the conditions as specified in Paragraph 2.92 below before 31st March, 2016.

2.92 Criteria for EPCs as Registering Authorities

In order to make the EPCs truly democratic and participative in nature and for better governance and transparency, the criteria for them to function as Registering Authority are being laid down as under:

- (a) **e-Voting:** Electronic Voting would be mandatory for election to the posts of Vice Chairman/Vice President and Executive Committee members with a view to ensuring wider participation.
- (b) **Tenure of Elected Heads:** The tenure of an elected head shall not be for more than two years. The election of Chairman/President of the EPC shall be via Vice Chairman/Vice President route. However, any member having held the post of Chairman/President and/or Vice Chairman/Vice President may come back as Vice Chairman/Vice President in the same council after a gap of not less than 4 years.
- (c) **Directions of the Central Government:** EPCs acting as the Registering Authorities shall abide by all directions of the Central Government in respect of promotion and development of international trade.

2.93 Registration- cum- Membership Certificate (RCMC)

- (a) An exporter may, on application given in **ANF 2C** register and become a member of EPC. On being admitted to membership, applicant shall be granted forthwith Registration-cum-Membership Certificate (RCMC) of EPC concerned, in format given in **Appendix 2R**. In case an exporter desires to get registration as a manufacturer exporter, he shall furnish evidence to that effect.
- (b) Prospective / potential exporters may also, on application, register and become an associate member of an EPC.

2.94 Applying for RCMC

- (a) While applying for RCMC, an exporter has to declare his main line of business in the application. The exporter is required to obtain RCMC from the Council which is concerned with the product of his main line of business.
- (b) In case an export product is not covered by any Export Promotion Council/Commodity Board etc., RCMC in respect thereof is to be obtained from FIEO. Further, in case of multi product exporters, not registered with any EPC, where main line of business is yet to be settled, the exporter has an option to obtain RCMC from Federation of Indian Exporters Organization (FIEO).
- (c) In respect of multi product exporters having their head office/ registered office in the North Eastern States, RCMC may be obtained from Shellac & Forest Products Export Promotion Council (except for the products looked after by APEDA, Spices Board and Tea Board).
- (d) In respect of exporters of handicrafts and handloom products from the State of Jammu & Kashmir, Director, Handicrafts, Government of Jammu & Kashmir is authorised to issue Registration Cum Membership Certificate (RCMC).

2.95 Validity Period of RCMC

RCMC shall be deemed to be valid from 1st April of licensing year in which it was issued and shall be valid for five years ending 31st March of the licensing year, unless otherwise specified.

2.96 Intimation Regarding Change in Constitution of Business of RCMC holder

- (a) In case of change in ownership, constitution, name or address of an exporter, it shall be obligatory on part of RCMC holder to intimate such change to registering authority within a period of one month from date of such change. Registering authority, however, may condone delays on merits.
- (b) Exporter shall furnish quarterly return /details of his exports of different commodities to concerned registering authority. However, status holders shall also send quarterly returns to FIEO in format specified by FIEO.

2.97 De- Registration

Registering authority may de-register an RCMC holder for a specified period for violation of conditions of registration. Before such de-registration, RCMC holder shall be given a show cause notice by registering authority, and an adequate and reasonable opportunity to make a representation against the proposed de-registration. Upon de-registration, concerned EPC shall intimate the same to all RAs.

2.98 Appeal Against De-registration

A person aggrieved by a decision of registering authority in respect of any matter connected with issue of RCMC may prefer an appeal to DGFT or an officer designated in this behalf within 45 days against said decision and decision of appellate authority shall be final.

2.99 Directives of DGFT

DGFT may direct any registering authority to register or deregister an exporter or otherwise issue such other directions to them consistent with and in order to implement provisions of FT (D&R) Act, Rules and Orders made there under, FTP or this Handbook.

Other General Provisions:**2.100 Identity Cards for Importers /Exporters**

- (a) To facilitate collection of Authorisation and other documents from DGFT Head Quarters and RA, identity cards (as in **Appendix 2W** valid for 3 years) may be issued to proprietor/ partners / directors and authorised employees (not more than three), of importers and exporters, upon application in **ANF 2B**
- (b) In addition, Identity Card may also be issued by the applicant firms on their letterhead to the concerned employees. These Identity Cards may be countersigned by the concerned RA. However, application for identity card in **ANF 2 B** will require to be made by the applicant and all other parameters would need to be met.
- (c) In case of limited companies, RA may approve allotment of more than three identity cards per company. In case of loss of an identity card, a duplicate card may be issued on the basis of a self-declaration. RA may issue multiple identity cards, after recording reasons in writing, in cases of Directors/Partners of companies.

2.101 Interview with authorised Officers

Officers may grant interview at their discretion to authorised representative of importer / exporter. Interviews /clarifications may also be sought through E-mails.

2.102 Authorised signatory

Any communication from the Exporter/Importer to DGFT's office including the RA's must have the name, signature, email id of the person duly authorised by the firm/company to send such communications.

Preferential Trade Agreements:**2.103 Free Trade Agreements (FTAs) / Preferential Trade Agreements (PTAs)**

- (a) India has always stood for a transparent, equitable, inclusive, predictable, non-discriminatory and rules based international trading system. In this context, India's trade agreements may be seen as a measured and calibrated exposure of the Indian economy to international competition. As of October, 2014; India has signed 10 FTAs and 6 limited Preferential Trade Agreements (PTAs). India is also negotiating around 18 other FTAs.
- (b) The list of the FTAs that have been signed by India are:
 - (i) India - Sri Lanka FTA
 - (ii) Agreement on South Asian Free Trade Agreement (SAFTA)
 - (iii) Revised Agreement of Cooperation between Government of India and Nepal to control unauthorised trade
 - (iv) India - Bhutan Agreement on Trade Commerce and Transit
 - (v) India - Thailand FTA - Early Harvest Scheme (EHS)
 - (vi) India - Singapore Comprehensive Economic Cooperation Agreement (CECA)
 - (vii) India – ASEAN CECA (Goods, Services and Investment)
 - (viii) India - South Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)
 - (ix) India - Japan CEPA
 - (x) India - Malaysia CECA
- (c) The list of Preferential Trade Agreements (PTAs) signed by India are:
 - (i) Asia Pacific Trade Agreement (APTA)
 - (ii) Global System of Trade Preferences (GSTP)
 - (iii) India - Afghanistan PTA
 - (iv) India - MERCOSUR PTA
 - (v) India - Chile PTA
 - (vi) SAARC Preferential Trading Arrangement (SAPTA)
- (d) The list of these agreements with the participating countries as well as their entry into force is given in **Appendix 2A**.

2.104 Unilateral Tariff Preferences

Under these schemes, both developed and developing countries grant unilateral tariff preferences to exports from developing countries including Least Developed Countries (LDCs). Some of these schemes are:

(A) Generalised System of Preferences (GSP):

- (a) GSP is a non-contractual instrument by which industrialized (developed) countries unilaterally and based on non-reciprocity extend tariff concessions to developing countries. Following countries extend tariff preferences under their GSP Scheme: (i) United States of America (ii) New Zealand (iii) Belarus (iv) European Union (v) Japan (vi) Russia (vii) Canada (viii) Norway (ix) Australia (only to LDCs) and (x) Switzerland
- (b) GSP schemes of these countries detail sectors / products and tariff lines under which benefits are available, including conditions and procedures governing benefits. These schemes are renewed and modified from time to time. Normally Customs of GSP offering countries require information in Form 'A' (prescribed for GSP Rules Of Origin) duly filled by exporters of beneficiary countries and certified by authorised agencies. List of agencies authorised to issue GSP CoO is given in **Appendix-2 C**.
- (c) The European Union (EU) has introduced a self-certification scheme for certifying the rules of origin under GSP from 1.1.2017 onwards. Under the Registered Exporter System (REX) being introduced from 1.1.2017, exporters with a REX number will be able to self-certify the Statement on Origin of their goods being exported to EU under the GSP Scheme. The registration on REX is without any fee or charges and this system would eventually phase out the current system of issuance of Certificates of Origin (Form-A) by the Competent Authorities listed in Appendix-2C. The details of the scheme are at Annex 1 to Appendix 2C.

(B) Duty Free Tariff Preference (DFTP) Scheme for LDCs:

- (a) The mandate for Duty Free Quota Free (DFQF) access to Least Developed Countries (LDCs) came from Paragraph 47 of the Hong Kong Ministerial Declaration of December 2005. India became the first developing country to extend this facility to LDCs through its Duty Free Tariff Preference (DFTP) Scheme for LDCs which came into effect in August, 2008 with tariff reductions spread over five years. The Scheme provided preferential market access on tariff lines that comprise 92.5% of global exports of all LDCs.
- (b) Subsequently in 2014, the Scheme was modified both with reference to increase in coverage as well as its simplification. This was in response to requests from several LDCs for additional product coverage on lines of their export interest and simplification of the Rules of Origin procedures. Under the new expanded DFTP Scheme, India is granting duty free access on 96.4% of the total tariff lines, thereby retaining only about 3.6% of lines in the Exclusion and Positive Lists. For details Department of Commerce's website: http://commerce.gov.in/trade/international_tpp_DFTP.pdf. and Customs' Notification No.8/2014 dated 1st April, 2014 may also be referred to in this regard.

2.105 Certificates of Origin (CoO)

- (a) Certificate of Origin (CoO) is an instrument to establish evidence on origin of goods imported into any country.
- (b) There are two categories of CoO viz.
 - (i) Preferential and
 - (ii) Non preferential

2.106 Rules of Origin (Preferential)

- (a) The rules of origin are the rules that determine the origin of a good for the purpose of exports to a trading partner. Under an FTA, PTA or a unilateral tariff concession, the tariff concessions are granted by an importing country only when these prescribed rules of origin are adhered to. Rules of origin also facilitate in computation of trade statistics and for determination and imposition of trade remedial measures.
- (b) Some of the key criteria used in the determination of the rules of origin are:
 - (i) Wholly obtained
 - (ii) Change in tariff classification
 - (iii) Value addition
 - (iv) Non minimal operations

- (c) For exports under India's FTAs, PTAs and GSP, specified agencies are authorised to issue the certificates of origin. They shall also provide services relating to issue of CoO, including details regarding rules of origin, list of items covered by an agreement, extent of tariff preference, verification and certification of eligibility. The list of these agencies authorised under the various FTAs/ PTAs is given in **Appendix 2B**
- (d) Export Inspection Council (EIC) is the agency authorised to print blank certificates. The website of the EIC (www.eicindia.gov.in) provides procedural details (including fee) for issuance of the certificate of origin.

2.107 TRQ under FTA/CECA

Government, from time to time, undertakes commitments for import under Tariff Rate Quota (TRQ) in various FTA/CECA. Accordingly, DGFT notifies the procedure for administration of TRQ from time to time. The Tariff Rate Quotas as existing is as under:

Descrip- tion	HS No.	In/out of quota rate (%) as per WTO	In/out of quota rate (%) As per Indian Tariff	Notification	TRQ
Vanaspati, bakery shortening and margarine from Sri Lanka	1516, 1517 or 1518 (other than 15161000, 15171010, 15179030 and 15180040 which are prohibited for import)	-	-	No.2/2007-Customs dated 5 th January 2007	*2,50,000 MT
Pepper from Sri Lanka	0904	-	-	No.2/2007-Customs dated 5 th January 2007	*2500 MT
Desiccated Coconut from Sri Lanka	08011100	-	-	No.2/2007-Customs dated 5 th January 2007	*500 MT
Articles of apparel and clothing accessories imported from Sri Lanka	61, 62	-	5%/10%	26/2000-Cus List 3	8 million pieces
Tea and preparapgraphptions thereof imported from Sri Lanka	2101	-	15%/30%	26/2000-Cus List 4	15 million kgs.
Vegetable fats (Vanaspati) from Nepal				22/2007-Cus 5 th June 2007	1 Lakh MT
Acrylic Yarn from Nepal				-do-	10,000 MT
Copper products from Nepal	Chapter 74 of ITC(HS) and 8544			-do-	10,000 MT
Zinc Oxide from Nepal				-do-	2500MT

* Imports will be permitted subject to the arrangements / Procedure as laid down in

Annexure-I of Appendix-2A.

2.108 Rules of Origin (Non-Preferential)

- (a) Rules of Origin (Non-Preferential) criteria are as under:
- (I) Goods are to be manufactured by the exporting entity as per the definition of “Manufacture” in Paragraph 9.31 of FTP; and
 - (II) If imported inputs (Duty Paid or Duty Free) have been used for the production of export product, the export product can be considered to be originating in India (Non Preferential) only if the imported inputs undergo the processing/ operations that exceed the following:
 - (i) simple operations consisting of removal of dust, sifting or screening, sorting, classifying, matching (including the making-up of sets of articles), washing, painting, cutting;
 - (ii) changes of packing and breaking up and assembly of consignments;
 - (iii) simple cutting, slicing and repacking or placing in bottles, flasks, bags, boxes, fixing on cards or boards, and all other simple packing operations;
 - (iv) operations to ensure the preservation of products in good condition during transport and storage (such as drying, freezing, keeping in brine, ventilation, spreading out, chilling, placing in salt, sulphur dioxide or other aqueous solutions, removal of damaged parts, and like operations);
 - (v) affixing of marks, labels or other like distinguishing signs on products or their packaging;
 - (vi) simple mixing of products ;
 - (vii) simple assembly of parts of products to constitute a complete product;
 - (viii) disassembly;
 - (ix) slaughter which means the mere killing of animals; and
 - (x) mere dilution with water or another substance that does not materially alter the characteristics of the products.
- (b) Government has also nominated certain agencies to issue Non-Preferential Certificate of Origin (CoO). These CoOs evidence origin of goods and do not bestow any right to preferential tariffs. List of notified agencies is provided in **Appendix-2 E**. In addition, agencies authorised to issue Preferential CoO are also authorised to issue Non-Preferential CoO.
- (c) All exporters who are required to submit CoO (Non Preferential) would have to apply to any of agencies enlisted in **Appendix-2 E** with following documents:
- (i) Details of quantum / origin of inputs / consumables used in export product.
 - (ii) Two copies of invoices.
 - (iii) Packing list in duplicate for concerned invoice.
 - (iv) Fee not exceeding Rs.100 per certificate as may be prescribed by concerned agency.
- (d) The agency would ensure that goods are of Indian origin as per criteria defined in (a) above before granting CoO (non preferential). Certificate would be issued as per format given in **Annexure-II** to **Appendix 2 E**. It should be ensured that no correction/re-type is made on certificate. Any agency desirous of enlistment in **Appendix-2 E** may submit their application as per **Annexure-I** to **Appendix 2 E** to DGFT.
- (e) **Non-preferential - Self Certification:** Manufacturer exporters who are also Status Holders shall be eligible to self-certify their goods as originating from India, if goods qualify the criteria, as laid down in (a) above, as per **Annexure -III** to **Appendix 2 E**.

2.109 Approved Exporter Scheme (AES) for self -certification

Details of the Scheme are provided in Appendix 2F of AANF.

Policy Interpretation and Relaxations:**2.110 Application to PIC**

Application for seeking interpretation of any policy provision shall be made in ANF-2F to Policy Interpretation Committee (in the Hqrs.) under Para 2.57(b) of FTP.

2.111 Application to PRC

- (a) Application to the Policy Relaxation Committee (PRC) under Para 2.58 FTP is to be made in ANF-2D with the prescribed fee and documents with a copy to the RA concerned for its comments. Similarly, under Para 2.59 of FTP, application for review of decision of any committee or a decision/order by any subordinate Authority in the Directorate General of Foreign Trade is required to be submitted in ANF-2E.
- (b) Director General of Foreign Trade shall be the Chairman of PRC with all Additional DGFTs, all Joint DGFTs in charge of Policy Divisions in Hqrs as members. The Joint DGFT (PRC) shall act as Member Secretary; and the Committee can Co-opt member/s with specific expertise/experience as and when required.

CHAPTER 3**EXPORTS FROM INDIA SCHEMES****3.01 Merchandise Exports From India Scheme (MEIS)**

- (a) Policy for Merchandise Exports from India Scheme (MEIS) is given in Chapter 3 of FTP.
- (b) An application for claiming rewards under MEIS on exports (other than Export of goods through courier or foreign post offices using e- Commerce), shall be filed online, using digital signature, on DGFT website at <http://dgft.gov.in> with RA concerned in ANF 3A. The relevant shipping bills and e BRC shall be linked with the on line application.
- (c) If application is filed for exports made through EDI ports, then the RAs shall not ask for any physical documents except under the provisions of para 3.01 (h) below and therefore hard copy of the following documents need not be submitted to RA: hard copy of applications to DGFT, EDI shipping bills, electronic Bank Realisation Certificate (e-BRC) and RCMC. The applicant shall submit the proof of landing in the manner prescribed under paragraph 3.03 of HBP.
- (d) In case application is filed for exports made through non EDI ports, then applicant need to submit export promotion copy of non EDI shipping bills. The applicant shall submit the proof of landing in the manner prescribed under paragraph 3.03 of HBP. The applicant shall upload scanned copies of any other prescribed documents for claiming scrip unless specified otherwise. However applicant need not submit hard copy of applications to DGFT, electronic Bank Realisation Certificate (e-BRC) and RCMC in this case also.
- (e) Applicant shall file separate application for each port of export in case of Non EDI Shipping bills. In case of EDI shipping bills, the applicant can file a single application containing shipping bills of different EDI ports. Accordingly shipments from different EDI ports will not require separate applications
- (f) Processing of Non EDI Shipping bills at RA: In cases the Non EDI shipping bills or the shipping bills not received through the Message Exchange from Customs, concerned RA shall verify the details entered by the exporter from the original shipping bills before grant of scrip.
- (g) No manual feeding allowed for EDI shipments: For EDI Shipping Bill, no manual feeding of Shipping bill details shall be allowed to the applicants in the online system. Rewards will be granted by RAs without the need for cross verifying EDI Shipping Bill details.
- (h) RA shall process the electronically acknowledged files and scrip shall be issued after due scrutiny of electronic documents. After scrutiny, if the officer has reasonable suspicion of wrong classification/ mis-declaration in any application, in such cases officer may, after approval of his senior officer/ Head of the Office, seek physical documents for scrutiny. On receipt of such documents, the officer must decide the claim within 7 working days. In cases, where the claim is rejected, a speaking order shall be issued.
- (i) The documents which are not required to be submitted in original, shall be retained by the applicant for a period of 3 years from the date of issuance of scrip or as prescribed under FTP para 3.19 (b).
- (j) Licensing Authority may call such documents in original at any time within 3 years. In case the applicant fails to submit the original documents on demand by Licensing Authority the applicant shall be liable to refund the rewards granted along with interest at the rate prescribed under Section 28 AA of Customs Act 1962, from the date of issuance of scrip.
- (k) Eligibility of product, corresponding ITC[HS] code, and markets (as given in Appendix 3B) for claiming rewards under MEIS shall be determined from Let Export Date as per Paragraph 9.12 of HBP.

3.02 Applications for Export of goods through courier or foreign post offices using e-Commerce

- (a) Application shall be filed online, using digital signature, in ANF 3D by exporter. The applicant shall submit the proof of landing in the manner prescribed under paragraph 3.03 of HBP.
- (b) Applicant shall file separate application for each port of export.
- (c) RA will manually examine the submitted documents before grant of scrip.

3.03 Proof of Landing

- (a) Wherever the reward under MEIS is available to all countries, proof of landing shall not be required to be submitted for claiming the reward
- (b) Uploading/submission of documents, as a proof of landing:

As a measure of ease of doing business, documents as a proof of landing of export consignment in notified market can be digitally uploaded in the following manner:-

- (i) Any exporter may upload the scanned copy of document as mentioned at paragraph 3.03 (c) (i) under his digital signature.
 - (ii) Status holders falling in the category of Three Star, Four Star or Five Star export house category may upload scanned copies of documents as mentioned at paragraph 3.03(c) (iv).
 - (iii) In all other cases the physical copy, in original, shall be filed by all categories of exporters.
- (c) Applicant shall be required to submit or upload, as the case may be, any one of the following documents as a proof of landing of export consignment in notified Market:
- (i) A self attested copy of import bill of entry filed by importer in specified market, or
 - (ii) Delivery order issued by port authorities, or
 - (iii) Arrival notice issued by goods carrier, or
 - (iv) Tracking report from the goods carrier (Shipping Line/Airline etc. or his accredited agent in India) duly certified by them, evidencing arrival of export cargo to destination Market, or
 - (v) For Land locked notified Market, Rail/Lorry receipts of transportation of goods from Port to Land locked notified Market,
 - (vi) Any other document that may satisfactorily prove to RA concerned that goods have landed in / reached the notified Market.
- (d) In case of (iv) and (vi) above, the accredited agent of the Goods Carrier must certify that he is the accredited agent of the concerned Goods Carrier on the date of issuance of the tracking report / document.
- (e) Further, in the case of issuance of any other document under (vi) above, the accredited agent must state that proof of landing of goods in relevant notified Market is given based on information available in the Goods Carrier's backup database and he has verified the same and issued this document accordingly.
- (f) In cases of exports using e commerce, exporter may submit express operator landing certificate/online web tracking print out indicating airway bill number as prescribed in enclosure (B) to ANF 3D.

3.04 Service Exports From India Scheme (SEIS)

- (a) Policy for Service Exports From India Scheme (SEIS) is given in Chapter 3 of FTP
- (b) An application for grant of duty credit scrip for eligible services rendered shall be filed online for a financial year on annual basis in ANF 3B using digital signature.
- (c) RA shall process the application received online after due scrutiny.

Common Procedural features applicable to MEIS and SEIS, unless specifically provided for:**3.05 Transitional Arrangement**

- (a) For the goods exported or services rendered upto the date of notification of current Foreign Trade Policy, which were otherwise eligible for issuance of scrip under erstwhile chapter 3 of the earlier Foreign Trade Policy(ies) and scrip is applied on or after the date of notification of current Foreign Trade Policy against such export of goods or services rendered, the application shall be made to Jurisdictional RA in the form with documents as prescribed in the HBP v I 2009-2014.
- (b) Deleted.

- (c) Applicants shall continue to file applications in respect of FPS/ MLFPS/FMS/VKGUY/SFIS/SHIS/IEIS and Agri Infrastructure Incentive Scheme Scrip in the application form and manner prescribed in the corresponding Hand Book of Procedures

3.06 Jurisdictional RA / RA Concerned

- (a) Applicant shall have option to choose Jurisdictional RA on the basis of Corporate Office/ Registered Office/Head Office / Branch Office address endorsed on IEC for submitting application/applications under MEIS and SEIS. This option need to be exercised at the beginning of financial year. Once an option is exercised, no change would be allowed for claims relating to that year. To illustrate, if an exporter has chosen RA Chennai for claiming rewards for exports made in 2015-16, then all claims for exports made in 2015-16, irrespective of the date of application shall be made to RA Chennai only.
- (b) Jurisdiction for MEIS

1	2	3
Sl No	Units	Jurisdictional RA
(i)	Importer Exporter Code (IEC) Holders having units in DTAs/ EHTPs/ BTPs/ STPs or more than one of these	Jurisdictional RA of DGFT as in Appendix 1A
(ii)	IEC Holders having units in SEZs/EOUs or both	Respective Development Commissioner of Special Economic Zones (SEZs) as in Appendix 1A
(iii)	IEC Holders having units both in (i) and (ii) above	Units located in category (i) and (ii) will apply to respective jurisdictions at Col -3

- (c) Jurisdiction for SEIS (Single Application on Annual Basis)

1	2	3
Sl No	Units	Jurisdictional RA
(i)	Importer Exporter Code (IEC) Holders having units only in DTAs	Jurisdictional RA of DGFT as in Appendix 1A
(ii)	IEC Holders having units only in SEZs	Respective Development Commissioner of Special Economic Zones (SEZs) as in Appendix 1A
(iii)	IEC Holders having units in Multiple SEZs	Single application for all units to the Development Commissioner of the SEZ where it has achieved highest Forex Earnings
(iv)	IEC Holders having units both in DTA and SEZs	Single Application for all different units to the Jurisdictional RA of DGFT as given in Appendix 1A

3.07 Applicability of Provisions contained in Chapter 2 and 9 of this HBP

Provisions contained in Chapter 2 and 9 of this HBP shall apply to MEIS and SEIS.

3.08 Port of Registration of Scrips

- (a) Port of Registration under MEIS would be as follows:
- (i) Duty Credit Scrip (including splits) under MEIS shall be issued with a single port of registration which shall be any one of the EDI ports from where export is made. In case of shipments from Non EDI ports, the Duty Credit Scrip (including splits) under MEIS shall be issued with a single port of registration which shall be the port of export.
- (ii) Duty credit scrip needs to be registered at the port of exports.

This is to be done prior to allowing usage of duty credit. Once registered at EDI port, scrip can be automatically used at any EDI port for import and at any manual port under Telegraphic Release Advise (TRA) procedure.

- (iii) In case port of registration is a manual port, TRA shall be required for imports at any other port.
- (iv) SEZs being non-EDI Ports, the scrip shall be registered at the SEZ port and in case the scrip holder intends to use the scrip for import from another port, the concerned DC shall issue Telegraphic Release Advice (TRA).
- (b) In case of scrip applied under Service Exports from India Scheme, the applicant can choose any port as port of registration and mention it in the application at the appropriate column. RA will issue the scrip with such port of registration. Such Duty credit scrip needs to be registered at the port of registration of duty credit. Once registered at EDI port, scrip can be automatically be used at any EDI port for import and at any manual port under Telegraphic Release Advise (TRA) procedure. In case port of registration is a manual port, TRA shall be required for imports at any other port.

3.09 Facility for Split Scrips

- (a) On request, split certificates of Duty Credit Scrip subject to a minimum of Rs. 5 Lakh each and multiples thereof may also be issued, at the time of application.
- (b) Once Duty Credit Scrip has been issued, request for splits can be permitted with same port of registration as appearing on the original Scrip. The above procedure shall be applicable only in respect of EDI enabled ports.
- (c) In case of export through non-EDI ports, the facility of splits shall not be allowed after issue of Scrip.

3.10 Procedure to upload documents by Chartered Accountant / Company Secretary / Cost Accountant

- (a) In order to move towards paperless processing of reward schemes, an electronic procedure is being developed to upload digitally signed documents by Chartered Accountant / Company Secretary / Cost Accountant. Such documents like annexure attached to ANF 3 B, ANF 3C and ANF 3D, which are at present signed by these signatories, can be facilitated by this procedure.
- (b) Till such time it is made mandatory to upload these annexure digitally, such annexure attached to ANF 3B, ANF3C, ANF3D would continue to be submitted in physical form to RA.
- (c) Exporter shall link digitally uploaded annexure with his online applications after creation of such facility.

3.11 Import from private / public Bonded warehouses

Entitlement can be used for import from private / public bonded warehouses subject to fulfilment of paragraph 2.36 of FTP and terms and conditions of DoR notification.

3.12 Re-export of defective / unfit goods

Goods imported which are found defective or unfit for use, may be re-exported, as per DoR guidelines. Where Duty Credit Scrip has been used for imports, Customs shall issue a certificate containing particulars of Scrip used, date of import of re-exported goods and amount debited while importing such goods. Based on this certificate, upon application, a fresh Scrip shall be issued by concerned RA to extent of 98% of debited amount, with same port of registration and valid for a period equivalent to balance period available on date of import of the defective / unfit goods.

3.13 Validity period and Revalidation

Duty Credit Scrip issued on or after 01.01.2016 under chapter 3 shall be valid for a period of 24 months from the date of issue and must be valid on the date on which actual debit of duty is made. Revalidation of Duty Credit Scrip shall not be permitted unless covered under paragraph 2.20(c) of HBP.

3.14 Procedure for Declaration of Intent on EDI and Non EDI shipping bills for claiming rewards under MEIS including export of goods through courier or foreign post offices using e-Commerce

- (a)
 - (i) EDI Shipping Bills: Marking/ ticking of “Y” (for Yes) in “Reward” column of shipping bills against each item, which is mandatory, would be sufficient to declare intent to claim rewards under the scheme. In case the exporter does not intend to claim the benefit of reward under Chapter 3 of FTP exporter shall tick “N” (for No). Such marking/ticking shall be required even for export shipments under any of the schemes of Chapter 4 (including drawback), Chapter 5 or Chapter 6 of FTP.

(ii) Non-EDI Shipping Bills: In the case of non-EDI Shipping Bills, Export shipments would need the following declaration on the Shipping Bills in order to be eligible for claiming rewards under MEIS: “We intend to claim rewards under Merchandise Exports From India Scheme (MEIS)”. Such declaration shall be required even for export shipments under any of the schemes of Chapter 4 (including drawback), Chapter 5 or Chapter 6 of FTP.

- (b) Whenever there is a decision during the financial year to include any new product/goods or new markets then to avail such rewards:
 - (i) For exports of such products/goods, to such markets, a grace period of one month from the date of notification/public notice will be allowed for making this declaration of intent.
 - (ii) After the grace period of one month, all exports (of such products/goods or to such markets) would have to include the declaration of intent on all categories of shipping bills.
 - (iii) For exports made prior to date of notification/public notice of products/markets, such a declaration would not be required since such exports would have already taken place.

3.15 Last date of filing of application for Duty Credit Scrips

- (a) Application for obtaining Duty Credit Scrip under MEIS shall be filed within a period of :
 - (i) Twelve months from the Let Export (LEO) date or
 - (ii) Three months from the date of :
 - (1) Uploading of EDI shipping bills onto the DGFT server by Customs.
 - (2) Printing/ release of shipping bills for Non EDI shipping bills.

whichever is later, in respect of shipments for which claim is being filed.

- (b) For SEIS, the last date for filing application shall be 12 months from the end of relevant financial year of claim period.

3.16 Application for Shipments from EDI Ports and Non-EDI Ports under MEIS

- (a) Shipments from EDI Ports and Non-EDI Ports cannot be clubbed in one application.
- (b) Port of registration for EDI enabled ports shall be any one of the ports from where export is made.
- (c) In case of exports through non-EDI port, the port of registration shall be the relevant non EDI port of exports. Accordingly separate application shall be filed for each non EDI port.
- (d) Multiple applications can be filed and supplementary cut shall not be applicable. However, an application can be filed with upto a maximum of 50 shipping bills.

3.17 Risk Management System

The policy relating to Risk Management System is given in Paragraph 3.19 of FTP. The Risk Management System shall be in operation as under:-

- (a) Computer System in DGFT HQ, on random basis and on the basis of guidelines issued by DGFT from time to time, will select 10% of cases for each RA which has issued scrips/ status holder certificates in the preceding month by 10th of every month.
- (b) The list of such selected cases will be sent to concerned RA by NIC by 15th of the month.
- (c) Concerned RA, will in turn, ask for the original/ physical documents by 30th of the month for examination in detail.
- (d) The applicant shall be under obligation to submit the document asked for in the next 15 days.
- (e) Concerned RA in turn will examine such documents in next 15 days. In cases, there is any deficiency the applicant shall rectify it in next one month from the date of communication by RA. In case of excess availment of rewards, the applicant shall refund the excess claim with interest as prescribed in paragraph 3.19 of FTP.
- (f) In case the applicant fails to submit the required original documents/ rectify the deficiencies / refund the excess claim as stipulated above or does not respond to any communication regarding the Risk Management System within 15 days of receipt of such communication, RA will initiate action as per FTDR Act and Rules.

3.18 Status Certificate

Policy for Status Holders is given in Chapter 3 of FTP.

3.19 Application for grant of Status Certificate

- (a) Status Certificates issued under FTP 2009-14 to an IEC holder shall remain valid till 30th September, 2015 or till the issuance of status certificate to such IEC holder under FTP 2015-20, whichever is earlier.
- (b) Applicants shall be required to file an application online for recognition of status under the Policy in ANF 3C. Scanned copy of relevant prescribed documents shall be uploaded by the applicant unless prescribed otherwise.
- (c) Online Application for status certificate shall be filed using digital signature with jurisdictional RA / Development Commissioner (DC) by Registered Office in the case of Company and by Head Office in the case of others as indicated in table below:

S.No.	Category	Issuing /renewing Authority for Status Certificate
1.	IEC holder having exports of DTA unit as well as exports of SEZ/EOU unit. EHTP/STP/BTP	Concerned Regional Authority as per jurisdiction indicated in Appendix 1A
2.	IEC holder having SEZ/EOU unit only	Concerned Development Commissioner as per jurisdiction indicated in Appendix 1A
3.	IEC holder having DTA unit only	Concerned Regional Authority as per jurisdiction indicated in Appendix 1A

3.20 Validity of status certificate

- (a) Status Certificates issued under this FTP shall be valid for a period of 5 years from the date on which application for recognition was filed.
- (b) Status Certificates valid beyond 31.3.2020 shall continue to remain in force, in case provisions of subsequent Foreign Trade Policy continue to recognize the status.

3.21 Maintenance of Accounts

Status Holders shall maintain true and proper accounts of its exports and imports based on which such recognition has been granted. Records shall be maintained for a period of two years from the date of grant of status certificate. These accounts shall be made available for inspection to RA concerned or any Authority nominated by DGFT.

3.22 Refusal /Suspension /Cancellation of Certificate

Status Certificate may be refused /suspended/ cancelled by RA concerned, if status holder or authorized representative acting on his behalf:

- (a) Fails to discharge export obligation imposed;
- (b) Tampers with Authorisations;
- (c) Misrepresents or has been a party to any corrupt or fraudulent practice in obtaining any Authorisation;
- (d) Commits a breach of FT (D& R) Act, or Rules, Orders made there under and FTP, The Customs Act 1962, The Central Excise Act 1944, FEMA Act 1999 and COFEPOSA Act 1974; or
- (e) Fails to furnish information required by this Directorate.

A reasonable opportunity shall be given to Status Holder before taking any action under this paragraph.

3.23 Appeal

An applicant, who is not satisfied with decision taken to suspend or cancel Status Certificate, may file an appeal to DGFT within 45 days. Decision of DGFT shall be final and binding thereon.

CHAPTER 4

DUTY EXEMPTION / REMISSION SCHEME

4.01 Policy

Policy relating to Duty Exemption / Remission Schemes is prescribed in Chapter 4 of Foreign Trade Policy.

4.02 General Provision

- (i) Application for grant of Advance Authorisation/Special Advance Authorization for export of Articles of Apparel and Clothing Accessories/Advance Authorisation for Annual Requirement / Duty Free Import Authorisation (DFIA) shall be filed online (digitally signed) by IEC holder to the concerned jurisdictional Regional Authority as per Appendix 1A. Applicant could be either Registered office or Head office or a branch office or a manufacturing unit of the IEC holder.
- (ii) Applicant shall upload documents as prescribed in ANF 4A, if any, at the time of online filing of application. No physical copy of application is required to be submitted to Regional Authority.
- (iii) In case an applicant is not able to upload any document as given in Appendix 4E electronically for fixation of adhoc norms /standardization of norms, then only such documents may be submitted in physical form to the concerned Norms Committee in DGFT headquarters.

4.03 Applicant details

Where applicant is a branch office or a manufacturing unit, name of branch office or manufacturing unit should appear in electronic RCMC and in IEC of the applicant.

4.04 Advance Authorisation

Applicant shall file application online in ANF 4A. Same form is applicable where Standard Input Output Norms (SION) have been notified or on the basis of ad hoc norms or on self declaration basis as per paragraph 4.07 of Hand Book of Procedures.

4.05 Advance Authorisation for items which are otherwise prohibited for export

- (i) Items covered under Chapter 7 and Chapter 15 of ITC (HS) Schedule 2, which are prohibited for export, may be allowed to be exported under the advance authorization scheme. Export shall be allowed subject to pre-import condition under notified SION/prior fixation of norms by Norms Committee in terms of paragraph 4.06 of Hand Book of Procedures. Import and Export would be permitted only through EDI enabled ports.
- (ii) The Export obligation period (EOP) of advance authorizations issued for such items shall be 90 days from the date of clearance of import consignment and no extension in EOP shall be allowed. Such import shall be subject to actual user condition and no transfer of imported raw material, for any purpose, including job work, shall be permitted. In case of non-fulfilment of EO/ non-achievement of stipulated value addition, a penalty equal to five times of the CIF value of the imported material, corresponding to the shortfall in EO, shall be imposed in addition to the applicable duty and interest. Provisions of Paragraph 4.49 of Handbook of Procedures shall not be applicable in this case.

4.06 Fixation of Norms

- (i) In case where norms have not been notified or where applicant wants to get the ad-hoc norms fixed before making an application for Advance Authorisation, application in ANF 4B, along with prescribed documents, shall be uploaded online to concerned Norms Committee (NC) in DGFT headquarters for

fixation of SION/Adhoc norm. Details of Norms Committees along with products groups dealt by each Norms Committee and respective email addresses for correspondence relating to norms fixation is as follows:

Norms Committees (NC) in DGFT headquarters	For fixation / revision / amendment of norms of Export Products under following ITC HS Chapters	Email addresses for communication with respective Norms Committee
NC-1	81 to 84, 86 to 93	nc1.dgft@nic.in
NC-2	72 to 76, 78 to 80, 85	nc2.dgft@nic.in
NC-3	29, 30	nc3.dgft@nic.in
NC-4	27, 28, 31 to 38, 44 to 49, 68 to 71	nc4.dgft@nic.in
NC-5	41 to 43, 50 to 67	nc5.dgft@nic.in
NC-6	1 to 26, 94 to 98	nc6.dgft@nic.in
NC-7	39, 40	nc7.dgft@nic.in

- (ii) An applicant shall indicate a valid email address for communication purpose and to ensure that this email address is active.
- (iii) The decisions of Norms Committees shall be available on the website of DGFT (<http://dgft.gov.in>) periodically and the applicants shall update themselves the status of norms fixation in respect of Authorisation obtained by them.
- (iv) Exporters /EPC shall provide data to the Norms Committee concerned for the fixation of SION/Adhoc Norms for an export product. Norms Committee shall endeavour to fix SION or adhoc norms on receipt of complete data. Any adhoc norm fixed under this para, on the basis of an application made by an exporter shall be valid for one authorisation for which such application is made and no repeat authorisations shall be issued. However, Norms Committee can specify extended validity period, not more than two years from the date of fixation of such adhoc norms, for grant of further authorisations under such norm.
- (v) Norms Committees shall also function as recommendatory authority for notification of SION and DGFT may notify such norms from time to time.
- (vi) It is mandatory for industry / manufacturers/ EPCs to provide production and consumption data etc. for the past three years, as may be required by DGFT for fixation of SION. Otherwise, applicants shall not be allowed to take benefit of Advance Authorisation scheme for taking repeat Advance Authorisations on self-declared basis. Norms Committee may also seek data from DoR (CBEC).
- (vii) Experts may be invited from Scientific and Technological institutions as members of Norms Committee for fixation of Norms.

4.07 Self Declared Authorisations where SION does not exist

- (i) Regional Authority may also issue Advance Authorisation where SION is not fixed, based on self declaration by applicant. Wastage so claimed shall be subject to wastage norms as decided by Norms Committee. The applicant shall submit an undertaking to abide by decision of Norms Committee. The provisions in this regard are given in paragraph 4.03 and 4.11 of FTP.

- (ii) In case of revision / rejection, applicant shall pay duty and interest as notified by DoR within thirty days from the date of hosting of Norms Committee decision on DGFT website.
- (iii) No Authorisation under this paragraph will be issued by Regional Authority for items listed in paragraph 4.11 of FTP.

4.08 Cases involving Acetic Anhydride, Ephedrine and Pseudo- ephedrine as inputs.

- (i) Where Acetic Anhydride, Ephedrine and Pseudo- ephedrine is required as an input for import, applications shall be filed with Regional Authority concerned. After filing application online, printed copy of such application shall also be simultaneously endorsed by applicant to (a) Drug Controller of India, Nirman Bhawan, New Delhi, (b) Narcotics Commissioner, Central Bureau of Narcotics, Gwalior (c) respective Zonal Director of Narcotics Control Bureau. The applicant should declare that they would maintain prescribed records / documents and also submit prescribed returns to the relevant authorities, within time as prescribed by law from time to time.
- (ii) Regional Authority shall endorse a copy of such Advance Authorisation to the above three agencies. Regional Authority shall also endorse a condition that before effecting imports, 'No Objection Certificate' shall be obtained from Drug Controller and Narcotics Commissioner of India.

4.09 Cases requiring Sanitary Import Permit.

- (i) Where import of meat and meat products of any kind including fresh, chilled and frozen meat, tissue or organs of poultry, pig, sheep, goat; egg & egg powder; milk & milk products; bovine, ovine and caprine embryos, ova or semen; and pet food products of animal origin has been sought as an input under Advance Authorisation, the Regional Authority, while issuing Advance Authorisation shall endorse a condition that before effecting imports of any of these inputs, Sanitary Import Permit shall be obtained from the Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries (DAHDF).
- (ii) Regional Authority shall also endorse a copy of authorisation to DAHDF, Krishi Bhawan, New Delhi.

4.10 Advance Authorisation for applicants with multiple units

- (i) Transfer of any duty free material imported or procured against Advance Authorisation from one unit of a company to another unit for manufacturing purpose shall be done with prior intimation to jurisdictional Customs Authority. Benefit of CENVAT shall not be claimed on such transferred input.
- (ii) Deleted
- (iii) Deleted
- (iv) Deleted
- (v) Imported duty free inputs can be taken from the port / domestic supplier's premises to the factory or the premises of the authorization / co-authorisation holder or the factory of the supporting manufacturer (whose name is endorsed in the authorization or allowed by the **Jurisdictional Customs** authority). However, such duty free material imported or procured against advance authorization can also be taken from the port directly to the project site of the project authority, subject to furnishing a bond to the customs authority at the port of import and other documents / declaration and other provisions as per Department of Revenue guidelines.

4.11 Advance Authorisation for Free of Cost and Paid Material

Authorisations granted in terms of paragraph 4.19 of FTP, a specific endorsement by Regional Authority shall be made on exchange control copy of Advance Authorisation disallowing remittances for material being supplied free of cost. All imported inputs excluding wastage shall be utilised in manufacturing of export product.

4.12 Entitlement

Maximum CIF value of one or more authorisations to be issued under paragraph 4.07 of Hand Book of Procedures shall be as under:

- (i) For Status Holders – upto 300% of FOB and / or FOR value of preceding year's exports and /or supplies.
- (ii) Other than Status Holders – upto 300% of FOB or Rs. 10 crore and / or FOR value of preceding year's exports and/or supplies, whichever is higher.
- (iii) Once adhoc norms are fixed by Norms Committee, value limits mentioned in sub paragraph (i) and (ii) above, would not be applicable to Advance Authorisations issued under paragraph 4.07 of Hand Book of Procedures. Value of such authorisations, subsequent to fixation of norms by Norms Committee, may be enhanced, if the Advance Authorisation was issued restricting the CIF value to maximum of value in sub-paragraph (i) & (ii) above.

- (iv) In such cases Authorisations shall be issued by Regional Authority concerned under "Adhoc Norms Fixed" category and application copies need not be forwarded to NC for fixation / ratification of norms. Where the application has already been forwarded before the ratification of Norms, the Regional Authority shall finalise the case as per the norms subsequently ratified by NC in a similar case of the party.
- (v) Authorisation holder in such cases shall be entitled for further authorisation (s) as per norms ratified by Norms Committee without need for subsequent ratification by Norms Committee. In such cases the applicant would file application under "Adhoc Norms Fixed" category to the Regional Authority concerned.
- (vi) Where Norms Committee has already ratified norms for same export and import products in respect of an authorization obtained under paragraph 4.07, such norms shall be valid for a period of two years reckoned from the date of ratification . The same applicant can avail repeat authorisations based on such adhoc norms. Regional Authority based on such adhoc norms. Another exporter, however, cannot be granted authorization by Regional Authority based on such adhoc norms.
- (vii) Wherever an applicant has applied for components on "net-to-net basis with accountability clause" and such cases fall under paragraph 6 of General Note for all Export Products, the same need not be referred to Norms Committee for fixation of norms. However, exporters shall indicate clearly details of such components imported on "net-to-net basis with accountability clause" in the export/supply documents namely Shipping Bills, Bill of Exports, Tax invoice for export/supplies prescribed under the GST rules evidencing that these imported inputs have been exported.

4.13 Authorisation in Excess of Entitlement

An applicant shall be entitled for authorisation in excess of entitlement of CIF mentioned in paragraph 4.12 above subject to furnishing of 100% Bank Guarantee to Customs authority to cover exemption from customs duties. Regional Authority shall make a specific endorsement to this effect on authorisation. This provision shall also apply to Status Holders.

4.14 Application and On-line Inter-Ministerial Consultations for fixation of norms / adhoc norms

- (i) Application filed online by the applicant shall be forwarded electronically to the concerned Technical / Administrative Ministry / Department /Scientific and Technological institutions or any other agency by the respective Norms Committee in the DGFT headquarters within three days.
- (ii) The concerned Technical / Administrative Ministry / Department / Scientific and Technological institutions or any other agency as the case may be, may communicate its views / comments / recommendations within 45 days electronically/online. In case no comments are received within 90 days, Norms Committee may take a view based on the facts available on record.

4.15 Undertaking

Applicant shall give an undertaking that he shall abide by norms fixed by Norms Committee and accordingly take following actions without any demur:

- (i) Pay customs duty saved, together with interest as notified by DoR, on excess inputs as per norms fixed by NC. However, in case Norms Committee allows lower norms for one, more, or all inputs authorisation holder will have option to undertake additional EO in proportion to excess inputs.
- (ii) In case application is rejected by Norms Committee, authorization holder shall pay duty saved amount along with interest on inputs, as applicable as notified by DoR. In cases of domestically procured inputs, the amount to be paid shall be based on exemptions/refund availed on customs duty/taxes/cess by the domestic supplier.
- (iii) Applicant shall deposit amount as per paragraph 4.49(a)(ii) of HBP in case the inputs were not freely importable. This amount is in addition to the amounts in sub-paragraph (i) above.

4.16 Time limit for fixation of norms by Norms Committees

- (i) Deleted.
- (ii) In case application for fixation of adhoc norms / SION is rejected on ground of non-furnishing of required documents/ information to Norms Committee or technical authority represented in Norms Committee, authorisation holder shall be liable to pay customs duty with interest as notified by DoR and amount as per paragraph 4.49(a)(ii). In case SION for the said product is notified, SION would be made applicable for deciding wastage norms and EO.
- (iii) In cases where entitlement of the applicant for grant of Advance Authorisation as per paragraph 4.12 was lower than the quantity of input applied by the applicant under Advance Authorisation and export obligation is completed pending fixation of norms by Norms Committee, entitlement for authorisation as given in paragraph

4.12 may be re-credited upon production of documentary evidence (copies of Shipping bill / bill of export/ Tax invoice for supply prescribed under GST rules) showing fulfilment of export obligation in respect of previous authorisations. However, bond waiver / redemption shall not be allowed pending fixation of norms in such cases.

4.17 Time limit for Representation

Applicant may file representation against the decision of the Norms Committee with regard to the fixation of norms within a period of 90 days from the date of hosting of decision on DGFT website. Representation beyond 90 days shall be subject to payment of composition fee of Rs.5000/-.

4.18 Provision for Pharmaceutical Products

Regional Authority may issue Advance Authorisation for pharmaceutical products manufactured through Non-Infringing (NI) process. A manufacturer exporter can avail the benefit of this provision whether the SION or the adhoc norms (under self declared basis in terms of paragraph 4.07 of the Hand Book of Procedures) for the said product is available or not. "Input combination permitted under NI process, as approved by the concerned agency of the regulated markets", shall be exporter specific and country specific and shall be available only when the exports are destined for the same country.

4.19 Application & Processing

- (i) An application for grant of an advance authorisation under paragraph 4.18 shall be filed online in ANF 4E to concerned Regional Authority along with the documents uploaded therein.
- (ii) Input combination permitted under NI process for manufacturing the product shall be certified by the Chartered Engineer (Chemical) after due verification of the details of each input and its quantity as given in Abbreviated New Drug Application (ANDA) / Drug Master File (DMF) of the applicant. The Chartered Engineer (Chemical) will certify the details as per Appendix 4L prescribed in Hand Book of Procedures. Regional Authority shall cross verify the requirement of inputs as per the details given in the application and with Chartered Engineer Certificate accompanying the application and issue the authorization. Regional Authority shall not forward such application to Norms Committee and the inputs and export product so allowed by Regional Authority, shall be treated as input combinations permitted under NI Process.

4.20 Redemption of Authorisation issued under paragraph 4.18 HBP

Provisions contained in paragraph 4.49 of Hand Book of Procedures, 2015-20, except sub-paragraph (f), shall be applicable. Regional Authority shall compare the details of Appendix 4-I, duly verified and certified by the jurisdictional Customs Authority, with that of the inputs made/allowed in the authorisation, before allowing redemption or Bond-waiver against individual advance authorization issued for pharmaceutical product(s) manufactured through NI process. As a result of the verification process, in case, it is found that the authorisation holder has consumed lesser quantity of inputs than imported, authorisation holder shall be liable to pay customs duty on unutilized imported material, along with interest thereon as notified by DoR, or effect additional export within the EO period to account for the export of the material remaining un utilized. However, for the Customs duty component, the authorisation holder has also the option to furnish valid duty credit scrip issued under Chapter 3 of FTP.

4.21 Maintenance of Proper Accounts for Authorisations issued under Para 4.18 of HBP

Every Advance Authorisation holder shall maintain a true and proper account of consumption and utilization of duty free imported / domestically procured inputs against each authorisation as prescribed in Appendix 4-I. This record in Appendix 4-I format, duly verified and certified by the jurisdictional Customs Authority, shall be submitted to the concerned Regional Authority at the time of filing application for redemption / bond waiver. Regional Authority shall compare the details of Appendix 4-I, with that of the inputs allowed in the authorisation, before allowing redemption or bond waiver against individual authorization. Such records shall be preserved for a period of at least three years from the date of redemption.

4.22 Standardisation of Adhoc Norms

- (a) For standardization of norms, an application in ANF 4B shall be filed online along with complete data. Such applications shall be made to concerned Norms Committee in DGFT headquarters.
- (b) Import of fuel may also be allowed with actual user condition under SION by Norms Committee subject to following:
 - (i) Facility of import of fuel shall be allowed only to manufacturer having captive power plant.
 - (ii) In cases where SION specifically allows fuel, same shall be permitted under Advance Authorisation. However, if fuel is not covered specifically under SION, it may be allowed as per general fuel Policy for products covered under SION or under paragraph 4.07 above.

- (iii) Applications for fixation of fuel entitlement for new sectors and modification of the existing entitlement as per General Note for Fuel in Hand Book of Procedures shall be filed online to the Norms Committee along with requisite data in ANF 4B.
- (iv) In case an applicant is not able to upload any prescribed document then such documents may be submitted in physical form to the concerned authority.

4.23 Modification of SION

An application for modification of existing SION shall be filed online in ANF 4B to the concerned Norms Committee in DGFT headquarters.

4.24 Amendment of Export item and inputs

- (i) An application for amendment of an export item or input or quantity of input under SION or under ad-hoc Norms shall be filed online in ANF 4B.
- (ii) Applicant would give justification for seeking amendment and Regional Authority would consider it with specific approval of Head of Office. In case of any major change in input or request for more wastage to that allowed under SION or ad-hoc norm, same should be referred to Norms Committee for ratification.

4.25 Revision of SION by NC

NC may identify SIONs which in its opinion are required to be reviewed. Exporters are required to submit revised data in ANF 4B for such revision. It is mandatory for industry / exporter(s) to provide production and consumption data etc. as may be required by DGFT / EPC for revision of SION. Otherwise, applicant shall not be allowed to take benefit of Advance Authorization scheme.

4.26 Description of an Advance Authorisation

An Advance Authorisation shall, inter-alia, specify:

- (a) Names and description of items including specifications, where applicable, to be imported and exported / supplied;
- (b) Quantity of each item to be imported or wherever quantity cannot be indicated, value of item shall be indicated. Wherever, quantity and value of individual inputs is a limiting factor in SION, same shall be applicable;
- (c) Aggregate CIF value of imports; and
- (d) FOB / FOR value and quantity of exports / supplies.

4.27 Exports/Supplies in anticipation or subsequent to issue of an Authorisation.

- (a) Exports/supplies made from the date of EDI generated file number for an Advance Authorisation, may be accepted towards discharge of EO. Shipping / Supply document(s) should be endorsed with File Number or Authorisation Number to establish co-relation of exports/supplies with Authorisation issued. Export/supply document(s) should also contain details of exempted materials/inputs consumed.
- (b) If application is approved, authorisation shall be issued based on input /output norms in force on the date of receipt of application by Regional Authority. If in the intervening period (i.e. from date of filing of application and date of issue of authorisation) the norms get changed, the authorization will be issued in proportion to provisional exports / supplies already made till any amendment in norms is notified. For remaining exports, Policy / Procedures in force on date of issue of authorisation shall be applicable.
- (c) The export of SCOMET items shall not be permitted against an Authorisation until and unless the requisite SCOMET Authorisation is obtained by the applicant.
- (d) Exports/supplies made in anticipation of authorisation shall not be eligible for inputs with pre-import condition.

4.28 Exporters Risk

Exports / supplies made in anticipation of grant of an Advance Authorisation shall be entirely on risk and responsibility of exporter.

4.29 Admissibility of drawback in case of rejection of application

Customs authorities in terms of DoR rules against shipping bills filed and processed under an Advance Authorisation, in case application for an Advance Authorisation is rejected or modified by Regional Authority, may permit drawback.

4.30 Advance Authorisation or DFIA for Intermediate Supplies

- (a) Application for grant of Advance Authorisation or DFIA for Intermediate supply may be made on the basis of a tie-up arrangement with an ultimate exporter (physical / deemed) holding an Advance Authorisation or DFIA. Regional Authority concerned shall consider such requests.

- (b) Advance Authorisation or DFIA for Intermediate supply shall be issued after making Authorisation of ultimate exporter invalid for direct import of item, to be supplied by intermediate manufacturer. In such case, a copy of the invalidation letter will be given to ultimate exporter holding Authorisation and copy thereof will be sent to intermediate supplier as well as Regional Authority of intermediate supplier. Intermediate Authorisation holder in such case has an option either to supply intermediate product to the holder of Advance Authorisation (i.e. ultimate exporter) or DFIA or to export (physical / deemed) directly. Intermediate supplier can also supply the product(s) directly to the port for export by the ultimate exporter (holder of Advance Authorisation or DFIA). In such cases, shipping bill shall be in the name of the ultimate exporter with the name of intermediate supplier endorsed on it.
- (c) Facility of Advance Authorisation shall be available even in cases where intermediate supplier has supplied or intend to supply material subsequent to fulfilment of EO by exporter holding Advance Authorisation / DFIA from where invalidation letter was issued.
- (d) The invalidation letter shall specify the following:
 - (i) Name, Address and GSTIN of supplier;
 - (ii) GSTIN & Address of recipient unit of Advance Authorisation/DFIA holder where inputs would be processed;
 - (iii) Name, description including specifications, where applicable, and quantity of items; and
 - (iv) Individual value of items to be procured.

4.31 Advance Release Order (ARO)

Application shall be filed online in ANF 4A to Regional Authority concerned for grant of ARO to procure inputs from indigenous sources / STEs.

4.32 Details to be given for issue of ARO

- (a) Application for ARO and ARO shall specify:
 - (i) Name, Address and GSTIN of supplier;
 - (ii) GSTIN & Address of recipient unit of Advance Authorisation/DFIA holder where inputs would be processed;
 - (iii) Name, description including specifications, where applicable, and quantity of items and
 - (iv) Individual value of items to be procured.
- (b) An ARO may be issued along with Advance Authorisation / DFIA or subsequently, and its validity shall be co-terminus with validity of Advance Authorisation / DFIA.
- (c) Deleted.

4.33 Deleted

4.34 Deleted

4.35 Facility of Supporting Manufacturer/ Jobber/co- licensee

- (a) Imported material may be used in any unit of holder of Advance Authorisation subject to condition of paragraph 4.10 of this Handbook or jobber / supporting manufacturer provided same is endorsed on authorisation by Regional Authority. If applicant desires to have name of any manufacturer or jobber added to authorisation, he may apply. Such endorsement shall be mandatory where prior import before export is a condition for availing Advance Authorisation scheme and authorisation holder desires to have material processed through any other manufacturer or jobber.
- (b) Upon such endorsement made by Regional Authority, authorisation holder and co-authorisation holder shall jointly and severally be liable for completion of EO. Any one of co-authorisation holders may import goods in his name or in joint names. BG/LUT shall also be furnished in their joint names.
- (c) If authorisation holder is registered under GST Act, he has an option of getting names of jobber endorsed by jurisdictional Customs authority as per GST Rules in lieu of Regional Authority's endorsement. In case manufacturer exporter holding authorisation is not registered / not required to be registered under GST Act, job work may be allowed after endorsement of supporting manufacturer's name in the authorisation from RA concerned. However, authorisation holder shall be solely responsible for imported items and fulfilment of EO.

4.36 Acceptance of BG/LUT

- (a) Regional Authority concerned will endorse on the reverse of Advance Authorisation at the time of issue of authorisation about acceptance of undertaking given by applicant in relevant ANF. Authorisation holder shall execute Bank Guarantee / Legal Undertaking, as the case may be, in terms of paragraph 2.29 of Hand Book of Procedures.
- (b) In case BG / LUT has been redeemed, Advance Authorization holder can get duty free inputs processed from any manufacturer under Actual User condition as per job work regulations prescribed in terms of provisions of GST Acts under intimation to the Customs authority. However, such restriction shall not be applicable in case of transferable DFIA holder.

4.37 Port of Registration

- (a) Advance Authorisation shall be issued for purpose of import and export through one of sea ports or airports or ICDs or LCS specified below. Authorisation holder shall register authorisation at the port specified in authorisation and thereafter all imports against said authorisation shall be made only through that port, unless the authorisation holder obtains permission from customs authority concerned to import through any other specified port. However, exports may be made through any of the specified ports.

Sea Ports:

Bedi (including Rozi-Jamnagar), Chennai, Dahej, Dharamtar, Ennore (Tamil Nadu), Haldia, Hazira (Surat), Jamnagar, Kakinada, Kandla, Kattupalli Sea Port (Tamil Nadu), Kochi, Kolkata, Krishnapatnam, Mangalore, Marmagoa, Muldwarka, Mumbai, Mundhra, Nagapattinam, Nhava Sheva, Okha, Paradeep, Pipavav, Porbander, Sikka, Surat (Magdalla), Tuticorin, Vadinar, Vishakhapatnam.

Air-ports:

Ahmedabad, Bangalore, Bhubaneshwar, Calicut Airport (Kerala), Chennai, Coimbatore Air Cargo Complex, Dabolim (Goa), Delhi, Hyderabad, Indore, Jaipur, Kochi, Kolkata, Lucknow (Amausi), Mumbai, Nagpur, Rajasansi (Amritsar), Srinagar, Trivandrum, Varanasi, Vishakhapatnam.

ICDs:

Agra, Ahmedabad, Anaparthi, Arakkonam (Tamil Nadu), Bangalore, Babarpur, Bhadohi, Bhatinda, Bhilwara, Bhiwadi, Bhusawal, Chettipalayam (Tamil Nadu), Chheharata (Amritsar), Coimbatore, Dadri, Delhi, Dighi (Pune), Dappar, Dera Bassi, Dhannad Rau (District Indore), Daulatabad, (Wanjarwadi and Maliwada), Durgapur (Export Promotion Industrial Park), Faridabad, Garhi Harsaru, Guntur, Guwahati (Amingaon), Hyderabad, Irugur Village (Tamil Nadu), Jaipur, Jalandhar, Jamshedpur, Jodhpur, Kalinganagar and Tumb Village (Taluka Umbergaon, District Valsad) Kanpur, Karur, Kheda (Pithampur, District Dhar), Kota, Kundli, Loni (District Ghaziabad), Ludhiana, Madurai, Mallanpur, Mandideep (District Raisen), Merripalem, Guntur District (AP), Miraj, Moradabad, Nagpur, Nasik, Pimpri (Pune), Pitampur (Indore), Patli (Gurgaon) Pondicherry, Raipur, Rewari, Rudrapur (Nainital), Salem, Singanalur, Surajpur, Surat, Talegoan (District Pune), Thudiyalur (Tamil Nadu), Tirupur, Todiarpet (TNPM), Tuticorin, Udaipur, Vadodara, Varanasi, Veerapandi (Tamil Nadu), Waluj (Aurangabad), Hosur (Tamil Nadu) and Nattakkam (Kottayam Taluk and District)

LCS:

Agartala, Amritsar Rail Cargo, Atari, Chengrabanda, Dawki, Ghojadanga, Hilly, Jogbani, Mahadipur, Nautanva (Sonauli), Nepalganj Road, Petrapole, Ranaghat, Raxaul, Singhabad, Sutarkhandi.

SEZ:

As notified by Central Government any SEZ can be a specified port for import and export.

- (b) Commissioner of Customs may permit imports and exports from any other seaport / airport / ICD or LCS.
- (c) For imports from Airport / Seaport / ICD / LCS other than port of registration, a TRA shall be issued by the customs authority at the port of registration to customs authority at port of import. However, this requirement of TRA shall not be required if the port of registration and port(s) of imports are EDI enabled and the authorisation holder has registered its authorization.

4.38 Facility of Clubbing of Authorisations

- (i) No clubbing of Authorisations issued on or before 31st March, 2009 shall be allowed.
- (ii) Request for clubbing shall be made in ANF - 4C to the concerned RA who has issued the Authorisations.
- (iii) Facility of clubbing of Advance Authorisations shall be available only for redemption / regularisation of such Authorisations and no further import or export shall be allowed.

- (iv) Facility of clubbing shall also be available for Advance Authorisations for Annual Requirement issued during Foreign Trade Policy period 2009-14 and 2015-20, wherever exports and imports have taken place as per Standard Input Output Norms (SION) notified.
- (v) Only Authorisations under which similar duty exemption has been availed shall only be allowed to be clubbed. Such Authorisations may pertain to different financial years.
- (vi) In case, exports are made outside EO period of any Authorisation, EO extension may be allowed before clubbing of such authorisation, as per Para 4.42 of Handbook of procedures on payment of composition fee.
- (vii) Only such Advance Authorisations shall be clubbed where exports under all Authorisations have been made within the initial/ extended EO period of the earliest issued Authorisation.
- (viii) Clubbing shall be permitted only when there is shortfall in fulfilment of export obligation occurred in first authorisation and excess exports are made in subsequent Authorisations. However, this condition may not be insisted when validity period (for import) of Authorisations runs concurrently and imports made in subsequent authorisation falls within validity period (for import) of first authorisation and such import made within validity period of first authorisation are on pro-rata, equal to or in excess to the extent of exports made in first authorisation. Subsequent Authorizations issued after expiry of validity of first Authorisation shall not be allowed to be clubbed.
- (ix) Clubbing of Authorisations issued with different EO periods shall also be allowed.
- (x) Accounting of exports made outside expiry of initial or extended EO period of earliest issued authorisation shall not be taken into consideration for EO fulfilment after clubbing of such Authorisations.
- (xi) Inputs which are common in all Authorisations shall only be clubbed and duty free inputs shall be accounted for as per SION/Ad-Hoc Norms fixed by NC. In other words all inputs covered in all Authorisations need not be same.
- (xii) Minimum value addition as prescribed in FTP and Procedures for the export product will be required to be maintained on clubbing. Upon clubbing, if shortfall in value or quantity is noticed, the same shall be regularized under the provisions of Para 4.49 of HBP 2015-20.
- (xiii) After clubbing, Authorisations shall for all purposes, be deemed to be one Authorisation. The value addition would be calculated on the basis of total CIF and total FOB arrived at after clubbing the Authorisations.
- (xiv) No clubbing shall be permitted in respect of Authorisations where misrepresentation / fraud have come to the notice of RA. Further, no clubbing of Authorisations, where EODC/redemption letter has already been issued or adjudication orders have already been passed by RA/Customs Authority, shall be permitted.
- (xv) Additional provisions for clubbing of Authorisations covered under Appendix-30A (issued under FTP 2009-14) / Appendix-4J (issued under FTP 2015-20) and Authorisations issued with EOP less than 18 months:
 - (a) Export obligation period of clubbed Authorisations shall be reckoned from the date of earliest import in any of the Authorisations proposed to be clubbed.
 - (b) Clubbing of such Authorisations shall be allowed provided all exports are completed within initial/extended Export Obligation period reckoned from date of earliest import in any of the Authorisations proposed to be clubbed.

4.39 Enhancement/ Reduction in the value of Advance Authorisation

- (a) In respect of an Advance Authorisation, Regional Authority concerned (as per their financial powers) may consider a request:
 - (i) for enhancement / reduction in CIF value of Advance Authorisation;
 - (ii) enhancement / reduction in CIF value, quantity of inputs, FOB value and quantity of exports of an Advance Authorization. However, VA after such enhancement does not fall below minimum VA stipulated (for the export product) in FTP and Hand Book of Procedures laid thereunder and there is no change in input-output norms and FTP under which Advance Authorisation was issued.
- (b) However, in case of Advance Authorisation (s) issued prior to 27.8.2009 under the FTP, 2004-09, the following conditions shall apply for any enhancement in the value of the authorisation:
 - (i) Wherever exports are on or subsequent to 27.8.09, enhancement in CIF / FOB values shall be subject to a minimum VA of 15% or the VA prescribed in Appendix 4D of current HBP, whichever is lower, for that component of exports.

- (ii) Wherever exports are prior to 27.8.09, enhancement in CIF / FOB values shall be subject to a minimum VA of 15% or the VA prescribed in Appendix 4D of current HBP, or the VA declared in the original Advance Authorisation application, whichever is lower.
- (c) Request for pro-rata enhancement in value and quantity may be made either before or after exports. In such cases where there is a change in SION prior to export of said product, pro-rata enhancement shall be given after calculating entitlement on revised SION.
- (d) Application for the enhancement in CIF or FOB value of Authorisation / reduction in the value of Authorisation / EOP Extension / Revalidation of Authorisation shall be filed online in ANF 4D to concerned Regional Authority.

4.40 Application fee for enhancement

Application fee payable for enhancement would be on the difference in CIF values of original and final Authorisation. However, no application fee would be charged if value of Authorisation is being reduced or applicant has already paid maximum fee of Rs 1,00,000 for Advance Authorisation / DFIA.

4.41 Validity period for import and Revalidation of Authorisation

- (a) Validity period for import of Advance Authorisation shall be 12 months from the date of issue of Authorisation.
- (b) Validity of Advance Authorisation for supplies under Chapter-7 of FTP shall be co-terminus with contracted duration of project execution or 12 months from the date of issue of Authorisation, whichever is later.
- (c) Regional Authority may consider a request of original Authorisation holder and grant one revalidation for six months from expiry date. Request(s) for revalidation of Authorisation shall be filed online in ANF 4D.
- (d) In case of revalidation of advance authorization issued prior to 27.8.2009 (FTP 2004-2009), it should be ensured that VA is maintained at 15% (and as per details mentioned in paragraph 4.09 of FTP) or as stipulated in the Advance Authorization, whichever is higher. However, for Advance Authorisations for products with VA as per Appendix 4D, the VA shall be as per the VA stated in Appendix 4D or as stated in Advance Authorisation, whichever is higher.

4.42 Export Obligation (EO) Period and its Extension

- (a) Period for fulfillment of export obligation under Advance Authorisation shall be 18 months from the date of issue of Authorisation. Period of EO fulfillment under an Advance Authorisation shall commence from date of issue of Authorisation, unless otherwise specified.
- (b) In cases of supplies to projects in India under Chapter-7 of FTP or projects abroad, the Export Obligation period shall be co-terminus with contracted duration of the project execution or 18 months whichever is more.
- (c) Export Obligation for items falling in categories of defence, military store, aerospace and nuclear energy shall be 24 months from the date of issue of authorization or co-terminus with contracted duration of the export order whichever is more.
- (d) Extension in export obligation period for Authorisations issued under Appendix-4J (issued under FTP 2015-20) shall be allowed for a period not more than the half of the stipulated export obligation period. In such cases, composition fee shall be levied @ 0.5% per month of unfulfilled FOB value, in case exports effected are more than 50% within initial Export Obligation period and @ 1% per month where less than 50% exports have been effected within initial export obligation period.
- (e) Regional Authority may consider a request of Advance Authorisation holder for one extension of EO period upto six months from the date of expiry of EO period subject to payment of composition fee of 0.5% of the shortfall in EO. Authorisation holder will have to submit a self declaration to RA stating that unutilised imported/domestically procured inputs are available with the applicant.
- (f) Request for further extension of six months after first extension as in (b) above can be considered by Regional Authority, provided Authorisation holder has fulfilled minimum 50% export obligation in quantity as well as in value, on pro-rata basis. This will be subject to payment of composition fee @ 0.5% per month on unfulfilled FOB value of export obligation. No further extension shall be allowed by Regional Authority. This provision shall also be applicable to Advance Authorisations issued during FTP 2009-2014. However, only two extensions of six months each as mentioned above can be allowed subject to payment of composition fee and under no circumstance Regional Authority shall allow any extension beyond 12 months from date of expiry of EO period. At the time of filing application for second EO extension, the Authorisation holder will have to submit a self declaration to RA stating that unutilised imported/domestically procured inputs are available with the applicant.
- (g) Deleted.

- (h) Whenever a ban / restriction is imposed on export of any product, export obligation period in respect of Advance Authorisation already issued prior to imposition of ban, would stand automatically extended for a period equivalent to the duration of ban, without any composition fee.

4.43 Provisional clearance of export consignment

Customs may allow provisional clearance of export consignment as and when Authorisation holder produces documentary evidence of having applied for Export Obligation extension to concerned Regional Authority.

4.43A Re-export of goods imported under Advance Authorisation Scheme

Goods imported against Advance Authorisation Scheme, which are found defective or unfit for use, may be re-exported, as per Department of Revenue guidelines. The authorisation holder has to inform the RA who has issued the authorisation before re-export of such defective goods.

4.44 Monitoring of Export Obligation

- (a) Regional Authority, with whom undertaking is executed by Advance Authorisation holder, shall maintain a proper record in a master register indicating starting and closing dates of obligation period and other particulars to monitor EO. In addition, this information may be generated from Computer System and maintained in a book form.
- (b) Within two months from the date of expiry of EO period, Authorisation holder shall file application online by linking details of shipping bills against the authorization.
- (c) In case of online filing of EODC application, Exporters shall link all exports on line on DGFT system by linking file number / authorisation number with the relevant shipping bill numbers / bill of exports / invoices in case of deemed exports/Tax invoices for supplies prescribed under GST rules on quarterly basis.
- (d) In case of non EDI shipping bills and supplies under Chapter-7 of FTP, exporter shall file relevant details manually on the website of the DGFT within two months from the date of expiry of EO period. Copies of shipping bills shall be submitted to Regional Authority concerned for verification within two months from date of expiry of export obligation period. In case an applicant is not able to upload any prescribed document then such documents may be submitted in physical form to the concerned authority.
- (e) e-BRC shall be linked with these shipping bills within six months from the date of expiry of export obligation/realisation or as per the time period prescribed for realization of foreign exchange by RBI. Regional Authority shall not take action for non linking / submission of e-BRC before expiry of said period, provided other documents substantiating fulfilment of EO have been furnished by the exporter
- (f) In case Authorisation holder fails to complete EO or fails to submit relevant information / documents, Regional Authority shall enforce condition of Authorisation and Undertaking and also initiate penal action as per law including refusal of further authorization to the defaulting exporter.

4.45 Advance Authorisation for Annual Requirement

- (a) Exporters eligible for such Authorisations shall file online application in ANF 4A to Regional Authority concerned. All provisions applicable to Advance Authorisation given above would apply except the following:
 - (i) Authorisation holder shall have flexibility to export any product falling under export product group using duty exempted material.
 - (ii) Within eligible entitlement, an exporter may apply for one or more than one authorisation in a licensing year, subject to the condition that against one Port of registration, not more than five authorisations can be issued for same product group. One time enhancement / reduction of the authorisation shall be available.
 - (iii) On completion of EO against one or more authorisations, all issued in same licensing year, entitlement of an exporter for that licensing year shall be deemed to be revived by an amount equivalent to EO completed against authorisation (s).
 - (iv) In respect of export product for which SION does not exist, no Advance Authorisation for Annual Requirement shall be available. Further, where SION is fixed but input is listed in Appendix 4J, no exports shall be made under Advance Authorisation.
- (b) At the time of clearance of the import consignment against the authorisation, exporter shall mention technical characteristics, quality and specifications which shall be endorsed in the Bill of Entry / invoice, duly attested by the Customs authority, in respect of following inputs:

“Alloy steel including stainless steel, copper alloy, synthetic rubber, bearings, solvents, perfumes/ essential oils/aromatic chemicals, surfactants, relevant fabrics and marble.”

4.45 A Special Advance Authorisation for export of Articles of Apparel and Clothing Accessories covered under Chapter 61 and 62 of ITC(HS) Classification of Export and Import.

- (i) Policy relating to Special Advance Authorisation for export of Articles of Apparel and Clothing Accessories covered under Chapter 61 and 62 of ITC(HS) Classification of Export and Import is prescribed in Para 4.04A of Foreign Trade Policy.
- (ii) Provisions of Para 4.05, 4.06, 4.10, 4.11, 4.12(v)&(vi), 4.21, 4.24, 4.25, 4.26, 4.29, 4.35, 4.36, 4.37, 4.39, 4.40, 4.41, 4.42, 4.43, 4.43A, 4.44, 4.46, 4.47(b), 4.49, 4.50, 4.51, 4.52 of Hand Book of Procedures shall be applicable to this scheme in so far as they are not inconsistent with this scheme.

4.46 Fulfilment of Export Obligation

Authorisation holder shall file online application in ANF 4F to Regional Authority concerned and upload prescribed documents in support of fulfilment of EO.

4.47 Redemption / No Bond Certificate

- (a) Bond Waiver: In case Authorisation holder exports first (before effecting imports) by using imported inputs / indigenously procured inputs, in that case the Authorisation holder can seek waiver of Bond condition by submitting evidence of export made and payment realised to that extent. If exports made are less than the export obligation stipulated in the Authorisation, request for waiver of bond condition, on pro-rata basis, can also be considered.
 - (i) For such a request, an applicant has to file online application attaching Shipping Bills and e-BRC. Scanned copy of other documents as prescribed in the ANF 4F shall also be uploaded. In case of deemed exports or export from non-EDI ports, the documents evidencing proof of export/supply shall be submitted at the counter of Regional Authority concerned giving reference of online application in physical form except e-BRC.
 - (ii) Deleted.
 - (iii) In case EO has been fulfilled, Regional Authority shall issue Bond Waiver Certificate (BWC) and forward a copy to the Customs authority at the port of registration of Authorisation enclosing details of shipping bill number(s), date(s), FOB value in Indian Rupees as per shipping bill(s) and description of export products in respect of shipment taken into account for allowing waiver of Bond condition. Such bond waiver shall not preclude the Customs Authority from taking bond in terms of the Customs notification.
 - (iv) While allowing waiver of Bond for such exports, Regional Authority may revalidate the Authorisation in continuation for further six months for replenishment of inputs consumed in the production of exported product, from the date of endorsement provided applicant has made a specific request in ANF 4D and paid requisite fee for revalidation. It will be further subject to condition that the applicant had not obtained revalidation earlier in terms of Para 4.41(a) of HBP 2015-20. Maximum period of validity of the Authorisation including revalidation allowed under this para shall not exceed 24 months from the date of issue of Authorisation.
 - (v) Copy of the Bond Waiver Certificate will also be endorsed by the Regional Authority to the Customs at the Port of Registration by post till system of transmitting these through EDI mode under message exchange is introduced between DGFT and CBEC.
- (b) **Export Obligation Discharge Certificate (EODC):**
 - (i) On completion of exports and imports, the Authorisation holder shall submit online application in ANF-4F as in (a) (i) above. In such cases, if EO has been fulfilled, the Regional Authority may issue EODC / Redemption Certificate to Authorisation holder and forward a copy to the Customs authority at the port of registration of Authorisation indicating the same details of proof of fulfilment of EO as stated in paragraph (a) above evidencing fulfilment of Export Obligation.
 - (ii) Copy of EODC will also be endorsed by Regional Authority to Customs at the Port of Registration by post till system of transmitting these through EDI under message exchange between DGFT and CBEC is introduced.
- (c) Ordinarily, redemption of BG / LUT shall not preclude customs authority from conducting random checks and from taking action against Authorisation holder for any misrepresentation, mis-declaration and default detected subsequently as per the Customs Act.
- (d) Authenticity of such Certificate shall be verified by referring to DGFT website (dgft.gov.in) or from the websites of Zonal offices of DGFT. Zonal offices of DGFT shall publish details of such EODC certificates issued by them and by all RAs coming under their jurisdiction on their official websites every month.

- (e) Regional Authority shall take action against Authorisation holder in case of non-submission of Appendix 4H & 4-I duly filled in, as stipulated in paragraph 4.51 below or for any misrepresentation, mis-declaration and default detected subsequently in details declared and furnished in Appendix 4H & 4-I. An endorsement to this effect shall be made by Regional Authority in the redemption certificate.

4.48 Transitional Arrangement for Authorisations issued upto 26.08.2009

- (a) Advance Licences including Advance Licence for Annual Requirement issued up to 26.08.2009 shall be governed by provisions contained in Chapter-7 of HBP v1(RE-2001), Chapter 4 of HBP v1 (2002-2007) as Notified on 31.3.2002, Chapter 4 of HBP v1 (2004-2009) as notified on 31.8.2004, and Chapter 4 of HBP v1 (2009-14) as notified on 27.08.2009 respectively as amended from time to time, excepting provisions relating to clubbing and extension in E.O. period which shall be governed by provisions of paragraphs 4.38 and 4.42 (e) respectively and any other provision, as notified by DGFT.
- (b) Wherever Customs duty is to be paid on unutilised material, same shall be paid along with interest thereon as notified by DoR.

4.49 Regularisation of Bona fide Default

Cases of bona fide default in fulfilment of EO may be regularised by Regional Authority as under:

- (a) If EO is fulfilled in terms of value, but there is a shortfall in terms of quantity, the Authorisation holder shall, for regularisation, pay:
- (i) To customs authorities, customs duty on unutilized value of imported / indigenously procured material along with interest as notified by DoR. Exporter will have the option to pay customs duty through valid duty credit scrips issued under FTP. However, interest / penalty shall be required to be paid in cash.
 - (ii) An amount equivalent to 3% of the CIF value of unutilised imported material, if the item of import is restricted, into "Head Account: 1453, Foreign Trade and Export Promotion and Minor Head102". Provisions of this sub paragraph will not be applicable if unutilized material was freely importable on date of import/domestic procurement.
- (b) If the EO is fulfilled in quantity but there is shortfall in value, no penalty shall be imposed if Authorisation holder has achieved minimum VA prescribed. However, if VA falls below the minimum VA prescribed, Authorisation holder shall be required to deposit an amount equal to 1% of shortfall in FOB value in Indian Rupee through TR in authorised branch of Central Bank of India as above or through EFT mode or through credit card.
- (c) Value wise shortfall shall be calculated with reference to actual quantity of exports and FOB value of realisation with reference to pro-rata quantity of imports and CIF value. For example, if export performance is only 50% quantity wise but import has been for complete CIF value permitted, then VA would be calculated on a pro-rata basis, i.e. with reference to 50% of CIF value of imports. This would, accordingly, imply that where Authorisation holder is unable to export, no penalty on value wise shortfall shall be imposed.
- (d) If EO is not fulfilled both in terms of quantity and value, the Authorisation holder shall, for the regularisation, pay as per a), b) and c) above.
- (e) In case an exporter is unable to complete EO undertaken in full and he has not made any import under Authorisation, Authorisation holder will also have an option to get the Authorisation cancelled and apply for drawback after obtaining permission from Customs authorities for conversion of shipping bills to Drawback Shipping Bills.
- (f) Regional Authority shall compare relevant portion of Appendix 4H duly verified and certified by Chartered Accountant / Cost Accountants with that of norms allowed in Authorisation(s) and actual quantity imported against Authorisation(s) in the beginning of licensing year for all such Authorisations redeemed in preceding licensing year. In this verification process, in case it is found that Authorisation holder has consumed lesser quantity of inputs than imported, Authorisation holder shall be liable to pay customs duty on unutilized value of imported material, along with interest thereon as notified, or affect additional export within the EO period.
- (g) Regularization of Bona fide default in the cases where Authorisation was issued for import of drugs from unregistered sources with pre import condition.

Import of drugs from unregistered sources issued with pre import condition shall be regularised in the following manner:

- (i) The Authorisation holder shall submit documents showing consumption of full imported quantity as per norms. In case, there is shortfall in fulfilment of EO and unutilised imported quantity remains with

the authorisation holder, the Authorisation holder shall either submit a certificate from the jurisdictional Central Excise / Customs Authority certifying destruction of the unutilised imported quantity in their presence or proof of re-export of the same to the same supplier in-terms of para 4.43A of HBP 2015-2020.

- (ii) Exports made under free shipping bills/under same authorisation after expiry of EO period using unutilised quantity of drugs shall also be accepted in-lieu of submission of destruction certificate as stated in para (i) above, provided the exact description and technical characteristics of the drug exported matches with that of export item described in the Advance Authorisation. However, the Authorisation holder shall pay customs duty with applicable interest to the Customs Authority on unutilized quantity imported under Advance Authorisation. The exports made outside EO period shall only be considered for waiver of destruction certificate and not for waiver of liability of applicable duties and interest.

4.50 Payment of Customs Duty and Interest in case of bonafide default in EO

- (a) Customs duty with interest as notified by DoR to be recovered from Authorisation holder on account of regularisation or enforcement of BG / LUT, shall be deposited by Authorisation holder in relevant Head of Account of Customs Revenue i.e., "Major Head 0037 - Customs and minor head 001-Import Duties" in prescribed T.R. Challan within 30 days of demand raised by Regional / Customs Authority and documentary evidence shall be produced to this effect to Regional Authority / Customs Authority immediately. Exporter can also make suo motu payment of customs duty and interest based on self/own calculation as per procedure laid down by DoR.
- (b) Mode of payment: Following modes of payment are available:
 - (i) Payment in cash through TR Challan to Customs Authority.
 - (ii) Payment of customs duty through debit of valid duty credit scrips issued under Chapter 3 (excluding SHIS, SFIS and AIIS scrips) in terms of FTP (2009-14) or Chapter 3 of this FTP or post-export EPCG duty remission scheme scrip, in respect of goods which are permitted under the respective reward/duty remission scrip.
- (c) Exporter shall obtain an endorsement from Customs authorities on the TR Challan 006 or on the back of the duty credit scrip(s) against which payment of customs duties have been accepted/debited and produce the same to RA along with duty calculation sheet at the time of regularization of their case.
- (d) Regional Authority shall verify the quantity of excess import before redeeming the case. RA may direct licence holders to pay balance amount of customs duty after informing the reasons of the difference in the liability worked out by Authorisation holder and the calculations by Regional Authority. In such case, the balance amount of duty and interest, if any shall be paid by Authorisation holder within 30 days, for regularization of the matter.
- (e) The interest shall be paid in cash through TR Challan 006 at the rate applicable on the date of payment of delayed duty amount to the Customs Authority.
- (f) On receipt of said documentary evidence from Authorisation holder, Regional Authority shall redeem the case, shall endorse details of duty paid on the EODC/Redemption Letter and inform details of recovery/deposits made to the Customs Authority at the port of registration or the Commissioner of Customs having jurisdiction over the factory of the Authorisation holder, as the case may be.
- (g) Payment of duty, interest and any dues for regularisation shall, however, be without prejudice to any other action that may be taken by Customs Authorities at any stage under Customs Act, 1962.

4.51 Maintenance of Proper Accounts

Every Advance Authorisation holder shall maintain a true and proper account of consumption and utilisation of duty free imported / domestically procured goods against each authorisation as prescribed in Appendix 4H or 4I, as applicable. These records are required to be sent to the concerned Regional Authority at the beginning of each licensing year for all those authorisations, which have been redeemed in previous licensing year. However, these records in said format are required to be submitted for authorisations issued on or after 13-05-2005. Such records should be preserved for a period of at least three years from date of redemption.

4.52 Consideration of cases against lost EP copy of the Shipping Bills and / or Bank Realisation Certificate

- (a) In case where Original EP copy of Shipping Bill / original BRC has been lost, request for EODC, No BG / LUT condition under Advance Authorisation / DFIA scheme or endorsement of transferability under DFIA scheme can be considered subject to submission of following documents in lieu of those original documents:
 - (i) A duplicate / Customs Certified / Self-attested copy of the shipping Bill in lieu of the original; Duplicate / Bank certified copy of BRC in lieu of original;

- (ii) An application fee equivalent to 1% of duty saved amount. However, no fee shall be charged when such document is lost by Government agencies and a documentary proof to this effect is submitted;
 - (iii) Self declaration by exporter about loss of document and an undertaking to surrender it immediately to concerned Regional Authority, if found subsequently;
 - (iv) An indemnity bond by exporter to the effect that he would indemnify Government for financial loss, if any, on account of duty free import entitlement availed / allowed against lost Shipping Bills / BRC.
- (b) Customs Authority, before allowing redemption of BG / LUT or clearance after endorsement of “No BG / LUT condition” or endorsement of transferability, shall verify the genuineness of such shipping bill (s) and ensure that no double benefit against such shipping bill has been availed. This specific condition shall be endorsed by Regional Authority concerned on the EODC.

DUTY FREE IMPORT AUTHORISATION SCHEME (DFIA)

4.53 Policy

Policy relating to the Duty Free Import Authorisation (DFIA) Scheme is prescribed in Chapter 4 of FTP.

4.54 Application

- (a) Application in ANF 4G along with documents therein, shall be filed online to concerned Regional Authority.
- (b) Provisions of paragraphs 4.26, 4.27, 4.28, 4.48, 4.49(e) & 4.49 (f) and 4.52 of this Handbook of Procedures shall also be applicable for DFIA Scheme.
- (c) After completion of exports and realization of proceeds, request for issuance of transferable Duty Free Import Authorisation may be made to concerned Regional Authority within a period of twelve months from the date of export or six months (or additional time allowed by RBI for realization) from the date of realization of export proceeds, whichever is later.
- (d) Applicant shall be allowed to file application beyond 24 months from the date of generation of file number as per paragraph 9.02 of Hand Book of Procedures.

4.55 Facility for Split DFIA

Split Authorisations of DFIA subject to a minimum of CIF value of Rs. 10 lakh each and multiples thereof may also be issued, on request at the time of seeking transferability. A fee of Rs. 1000/- each shall be paid for each split authorization. Split-up DFIA's shall be permitted with the same port of registration as appearing on the original DFIA.

4.56 Re-export of goods imported under DFIA Scheme

- (i) Goods imported against transferable DFIA, which are found defective or unfit for use, may be re-exported, as per Department of Revenue guidelines. In such cases, if the goods were not put to use after import, a certificate shall be generated by concerned Commissioner of Customs to the extent of 95% of CIF value debited against DFIA containing amount and description of exported goods and the details of original DFIA.
- (ii) Based on the certificate, a fresh DFIA shall be issued by Regional Authority concerned. Fresh DFIA, so issued, shall have same port of registration and shall be valid for a period equivalent to balance period available on date of import of such defective/unfit goods.

4.57 Maintenance of proper accounts of import and its utilisation

Original DFIA holder shall maintain a true and proper account of consumption and utilisation of duty free imported / domestically procured goods against each authorisation as prescribed in Appendix 4H. These records are required to be sent to Regional Authority concerned along with request for bond waiver / redemption / discharge of export obligation / transferability. Such records should be preserved for a period of at least three years from date of redemption.

GEMS AND JEWELLERY SECTOR

4.58 General Provision

Policy relating to Gem Replenishment Authorisation and scheme for gold/ silver/platinum jewellery is given in FTP. Application in respect of export promotion scheme for gems & jewellery sector including those of Nominated Agency Certificate shall be made to concerned Regional Authority as per Appendix 4A.

4.59 Application for Replenishment Authorisation

- (a) Application for REP Authorisation shall be filed online in ANF 4 H and upload the documents prescribed therein to concerned Regional Authority as per Appendix 4A.
- (b) Application shall be filed within six months following the month during which the export proceeds are realised. For export proceeds realised during a month, consolidated application for entire month shall be filed.
- (c) In case E.P Copy of Shipping Bill and Customs attested invoice is submitted to nominated agencies, exporter shall furnish a self certified photo copy of same along with a certificate from nominated agencies certifying carat / value of studdings in case of studded jewellery.
- (d) In cases where payment is received in advance and exports take place subsequently, application for REP Authorisation shall be filed within six months following the month during which exports are made.
- (e) It is clarified that the month in which the export has been made in case of advance payment and the month in which export proceeds have been realised in part or full after making of exports, shall be excluded while calculating period of six months for filing of application for REP Authorisation.

4.60 Wastage Norms

Maximum wastage or manufacturing loss on gold/silver/ platinum jewellery and articles thereof is as follows:

SI No	Items of export	Percentage of wastage by weight with reference to Gold/ Platinum / Silver content in export item	
		Gold / platinum	Silver
a)	Plain jewellery, articles, and ornaments like Mangalsutra containing gold and black beads /imitation stones, cubic zirconia diamonds, precious, semi-precious stones.	2.5 %	3.2 %
b)	Studded jewellery and articles thereof	5.0 %	5.0 %
c)	Mountings and findings manufactured (by non-mechanised process) indigenously	2.5 %	3.2 %
d)	Any jewellery/ articles manufactured by a fully mechanised process and unstudded.	0.9 %	0.9 %
e)	Mountings, whether imported or indigenously procured/ manufactured, used in studded jewellery	1.8 %	1.8 %
f)	Gold / silver / platinum medallions and coins (excluding coins of nature of legal tender)	0.2%	0.2%
g)	Findings and mountings manufactured by mechanized process	0.9%	0.9%

4.61 Value Addition

Under scheme for export of jewellery, value addition shall be calculated as per paragraph 4.38 of FTP. Minimum value addition shall be:

SI No	Items of export	Minimum Value Addition
-------	-----------------	------------------------

a)	Plain gold / platinum / silver jewellery and Articles and ornaments like Mangalsutra containing gold and black beads / imitation stones, except in studded form of jewellery.	3.5%
b)	All types of Studded gold / platinum / silver Jewellery and articles thereof.	6.0% (for those studded with coloured Gem stones) and 7.0% (for those studded with diamonds).
c)	Any jewellery/articles manufactured by fully mechanized process	2%
d)	Gold / silver / platinum medallions & coins (excluding coins of nature of legal tender)	1.5%
e)	Gold / silver /platinum findings/mountings manufactured by mechanized process	2.5%

4.62 Entitlement

Entitlement of quantity of gold / silver /platinum against the export of articles made out of these metals shall be quantity of gold / silver / platinum in item of export plus admissible wastage / manufacturing loss. In the case of Studded Jewellery, the calculation of the quantum of precious metal shall be done excluding the weight of studding.

4.63 Loss of Gem and Jewellery in transit

Consignments of gem and jewellery items exported out of country and lost in transit after exports, where foreign exchange against such exports has been realised or insurance claims settled, will also be eligible for REP Authorisation.

4.64 Gem & Jewellery Replenishment Authorisations

- (a) Gem REP Authorisations shall be valid for import of precious stones, semi-precious and synthetic stones and pearls used in export of Gems and Jewellery products. In addition, Authorisation shall also be valid for import of empty jewellery boxes up to 5% of value of Authorisation within its overall CIF value. Gem REP Authorisations issued against export of studded gold / silver / platinum jewellery articles, shall also be valid for import of cut and polished precious / semi- precious stones other than emerald up to 10% of CIF value of Authorisation within its overall CIF value.
- (b) Gem REP Authorisation will be as per the replenishment rate prescribed in Appendix 4F and the scale of replenishment on the remaining FOB value in the case of studded jewellery shall be as given in Appendix-4G.

4.65 Agency Commission

Exporter availing scheme of gold / silver / platinum jewellery are allowed to pay agency commission subject to the guidelines laid down by RBI. VA shall be calculated after deducting agency commission.

4.66 Endorsement on shipping Bill and Invoice.

During export of jewellery, shipping bill and invoice presented to customs authorities shall contain description of item, its purity, weight of gold/ silver/ platinum content, wastage claimed thereon, total weight of gold/ silver/ platinum content plus wastage claimed and its equivalent quantity in terms of 0.995/0.999 fineness for gold / silver and in terms of 0.9999 fineness for platinum and its value, FOB value of exports and value addition achieved. If purity of gold/silver/platinum used is same in respect of all or some of items made out from each of these metals for export, exporter may give total weight of gold/silver/platinum and other details of such similar items which are of same purity. In case of studded items, shipping bill shall also contain description, weight and value of precious / semi-precious stones / diamonds / pearls used in manufacture and weight / value of any other precious metal used for alloying gold/silver.

4.67 Conditions of Exports

Exports shall be allowed by customs authorities provided endorsement made on shipping bill and invoice are correct and value addition achieved is not below minimum prescribed in FTP.

4.68 Proof of Exports

- (a) Exporter has to furnish the proof of exports, wherever required for export of gold / silver / platinum jewellery and articles thereof, by furnishing following documents:
- (i) E.P copy of the shipping bill;

- (ii) Customs attested Tax invoice for export/supplies as prescribed under GST rules;
- (iii) Bank certificate/e-BRC of realisation in Appendix 2U.
- (b) In case of personal carriage of jewellery by foreign buyer, following documents should be submitted by the exporter/seller as proof of exports for claiming export entitlements:
 - (i) Copy of shipping bill filed by Indian Seller;
 - (ii) copy of Currency Declaration Form filed by Foreign Buyer with Customs at the time of his arrival; and
 - (iii) Foreign Exchange Encashment Certificate from Bank.
- (c) In addition to this, Personal Carriage on Documents Against Acceptance (DA)/ Cash On Delivery (COD) basis is also allowed. Exporter will have to furnish following documents as proof of exports for claiming export entitlements:
 - (i) Copy of Shipping Bill filed by Indian Seller; and
 - (ii) Bank Certificate / e-BRC of Export and Realisation.
- (d) Instructions issued by Customs Department in this regard should be followed mutatis mutandis.

4.69 Conversion of Purity/Fineness

For conversion of quantity of gold/ silver/platinum in terms of equivalent quantity in terms of fineness, following formula shall be used:

- (i) Where items of gold has been exported in terms of carats, quantity of gold shall be multiplied by number of carat of gold exported, divided by 24 and thereafter again divided by 0.995/0.999/0.900 to arrive at equivalent quantity of gold in terms of fineness of 0.995/0.999/0.900 respectively; and
- (ii) Wherever purity of item of export is expressed in terms of fineness, the quantity of gold/silver/platinum shall be multiplied by fineness of gold/silver/platinum exported and thereafter divided by 0.995 / 0.999 / 0.900 to arrive at equivalent quantity of gold/ silver/platinum in terms of 0.995 / 0.999 / 0.900 fineness respectively.

4.70 Release of Gold/Silver/ Platinum by Nominated Agencies

Gold / silver / platinum shall be released to exporter of jewellery by nominated agencies/RBI authorised banks in multiples of 10 gms or in Ten Tola Bars in respect of gold. However, silver shall be released to exporters in multiples of 1 Kg only. Any balance of gold/ silver/ platinum shall be available to exporter along with his future entitlement. Gold/ silver shall be released by the nominated agencies in terms of 0.995 fineness or more and platinum in terms of 0.900 fineness or more.

4.71 Terms of payment

Export of gold / silver / platinum jewellery and articles thereof shall be against irrevocable letter of credit, payment of cash on delivery basis, Documents Against Acceptance (DA) basis or advance payment in foreign exchange or replenishment of gold/silver/platinum content in exported jewellery / articles.

4.72 Port of Export

Exports under schemes of gold /silver/platinum jewellery and articles thereof shall be allowed by airfreight and Foreign Post Office through the Customs House at Mumbai, Kolkata, Chennai, Delhi, Jaipur, Bangaluru, Kochi, Coimbatore, Ahmedabad, Dabolin Airport, Goa, Hyderabad and Surat (Surat Hira Bourse). Export by courier shall also be allowed through Custom Houses at Mumbai, Kolkata, Chennai, Kochi, Coimbatore, Delhi, Jaipur, Bangaluru, Ahmedabad and Hyderabad upto FOB value of Rs.20 lakh per consignment.

4.73 Export by Post

Policy for export of gems and jewellery parcel by post is in paragraph 4.48 of FTP. At the time of exports, exporter shall submit following documents:

- (i) Shipping bills or Tax invoice for export/supplies as prescribed under GST rules presented at foreign Post Office;
- (ii) Certificate from nominated agencies indicating price at which gold/ silver/platinum was booked or given on outright sale basis or loan basis;
- (iii) Three copies of Tax invoices for export/supplies as prescribed under GST rules.

4.74 Export of Cut & Polished Diamonds for Certification/ Grading & Re- import

Following are authorized laboratories for certification / grading of diamonds of 0.25 carat and above :

- (1) International Gemological Institute (IG) – Hong Kong.

- (2) American Gem Society Laboratories (AGS Laboratories), 8917 West Sahara Avenue, Las Vegas, Nevada 89117;
- (3) Central Gem Laboratory, Miyagi Building, 5-15-14 Ueno Taito-Ku, Tokyo, Japan;
- (4) Diamond Trading Company, Maidenhead, UK;
- (5) European Gemological Laboratory (EGL), USA;
- (6) Gemological Institute of America (GIA), USA;
- (7) Hoge Road Voor Diamond, Antwerp, (HRD);
- (8) International Diamond Laboratories DMCC, Dubai.
- (9) The Robert Mouawad Campus, International Gemological Institute (IGI) USA;
- (10) World Diamond Centre of Diamonds High Council, Antwerp, Belgium.
- (11) GIA Hong Kong Laboratory Ltd., Hong Kong;
- (12) Gemological Research (Thailand) Co. Ltd., Bangkok;
- (13) GIA Education and Laboratory (Pvt) Ltd., Johannesburg;
- (14) GIA Education and Laboratory, Gaborone (Botswana);
- (15) Forevermark NV, Antwerp, Belgium;
- (16) International Gemological Institute (IG) – Antwerp, Belgium;

4.75 Import of Diamonds for Certification/Grading & re-export

- (a) This facility has been stated in Paragraph 4.42 of FTP. At the time of imports of diamonds, the bill of entry shall have the detailed description, including the dimensions / specifications of the diamonds. At the time of re-export after grading/certification, the Bill of Entry details should be endorsed in the shipping bill, so far as the dimensions and other specifications/ details of the diamonds are concerned, so as to establish a clear correlation between the imported diamonds and the diamonds being re-exported. In addition, a separate self certificate shall be attached by GIA (or any other approved agency) along with the shipping bill at the time of shipment, for matching of the imports to that of the exports as per the documents and GIA (or any other approved agency) certificate.
- (b) GIA (or any other agency approved in this regard) shall obtain GR waiver as per the procedure laid down by RBI, in all such cases.
- (c) Re-export of the imported diamonds shall be completed within a maximum time period of 3 months from the date of import(s). At the time of import, the agency shall give an undertaking to the customs to this effect. GIA (or any other agency approved in this regard) shall furnish a quarterly report to the customs authority at the port of import by 25th of the month, succeeding the end of the quarterly period, to ensure that the exports are effected within the stipulated time period.

4.76 Enlistment /Authorisation of Laboratories for Certification/ Grading of Diamonds of 0.25 carat and above

Applications for enlistment of laboratories should be submitted to Gems and Jewellery Promotion Council (GJEPC) for scrutiny of the application for fulfilment of the norms prescribed. GJEPC will forward the application after verification of bona fides with their clear recommendation for in principle approval of DGFT. After in principle approval of DGFT is granted, GJEPC will conduct inspection of the facility to verify the availability of equipments, technical manpower as well as other infrastructure required for the Laboratory, to function as Authorised Laboratory for certification/ grading of diamonds of 0.25 carat and above. Based on the Inspection Report and recommendations of the GJEPC, the concerned laboratory would be considered for inclusion in paragraph 4.42 or 4.43 of FTP as the case may be.

4.77 Export Against Supply By Foreign Buyer

- (a) Before clearance of each consignment of import supplied by foreign buyer, Nominated Agency / Status Holder having Nominated Agency Certificate/Eligible Exporter shall execute a bond with Customs, undertaking to export within stipulated period in contract, gold/silver/platinum jewellery or articles equivalent to entire import quantity of gold/silver/platinum, mountings and findings etc excluding admissible wastage.
- (b) In case of direct supply of gold/silver/platinum, alloys, findings and mountings of gold/silver/platinum and plain semi-finished gold/silver/platinum jewellery to status holder/ exporter, Status Holder/exporter shall furnish a Bank Guarantee/LUT, as per Customs Rules and regulations to Customs equivalent to Basic Customs Duty leviable on imported gold/ silver/ platinum, alloys, findings and mountings of gold/ silver/

platinum and plain semi-finished gold/ silver/ platinum jewellery etc. Integrated Goods and Services tax and Compensation Cess leviable under Section 3(7) AND 3(9) of Customs Tariff Act shall be payable separately on imports.

- (c) BG /LUT, executed with Customs shall be valid for one year. In case of direct supply to Status Holder/exporter, exports shall be completed within 90 days. In case of non-fulfillment of EO / non- achievement of stipulated value addition, Customs Authority shall proceed to recover custom duty alongwith interest as notified by DoR which may include enforcement of BG/LUT. Besides, importer will be liable to penal action under Customs Act.

4.78 Export Procedure / Payment of Customs Duty

- (a) Nominated Agency / Status Holder having Nominated Agency Certificate / exporter shall be liable to pay customs duty leviable on that quantity which is proved to have not been exported.
- (b) Goods shall be cleared through Customs by Nominated Agency/ Status Holder having Nominated Agency Certificate / exporter. Even where export order is received by an Associate, goods shall be cleared through Customs by nominated agency only and not by Associate. Associate shall, in such cases, authorise Nominated Agency to act as its agent to file Bill of Entry and shipping bill.
- (c) At the time of export, shipping bill presented to Customs shall also contain the following:
 - (i) Name and address of associate/ Status Holder having Nominated Agency Certificate /exporter;
 - (ii) An endorsement by Nominated Agency / Status Holder having Nominated Agency Certificate that export is made against an order received by concerned associate, its date of registration with nominated agency. In case of exports by Status Holder having Nominated Agency Certificate /exporter, a self declaration shall be provided to this effect;
 - (iii) Name of Customs House through which gold/ silver/ platinum/plain semi-finished gold/ silver/ platinum jewellery was imported and corresponding Bill of Entry No. and date and date of import.
- (d) Each shipping bill shall be valid for exports only through Customs House located at the place where office of Nominated Agency/ Status Holder having Nominated Agency Certificate / exporter concerned is situated. It shall be valid for shipment for a period of seven days including the date on which endorsement was made by nominated agency in case of exports through nominated agency. If exports cannot be made within this period, exporter shall file a fresh shipping bill.
- (e) At the time of export, exporter shall submit following documents:
 - (i) Shipping bill with two extra copies where exports are made from a Customs House other than Customs House through which corresponding import of gold/ silver/ platinum/plain semi-finished gold/silver/ platinum jewellery was effected. In other cases, shipping bill with an extra copy;
 - (ii) Three copies of tax invoices for export/supplies as prescribed under GST rules ;
 - (iii) Certificate from nominated agency indicating quantity and value of items supplied by foreign buyer.
- (f) Customs authorities shall return two copies of shipping bill and connected invoice duly attested. One copy shall be sent to person who presented documents and the other copy shall be sent by Customs to office of nominated agency/Status holder/ exporter.
- (g) In case of exports through nominated agency, exporter shall submit proof of exports to nominated agency within 15 days of exports, who shall, after verifying documents, release admissible quantity of the gold/ silver/ platinum etc. to exporter.
- (h) Exporter may also obtain, in advance, gold/ silver/ platinum etc. supplied by foreign buyer by furnishing a BG /LUT for an amount equal to international price of such items plus customs duty payable thereon. Integrated Goods and Services tax and Compensation Cess leviable under Section 3(7) AND 3(9) of Customs Tariff Act shall be payable separately on imports. BG /LUT shall be redeemed only when the exporter has furnished proof of exports to nominated agency and accounted for the use of items supplied in advance in export product.
- (i) For redemption of bond/ BG/LUT executed with Customs, Nominated Agency/ Status Holder having Nominated Agency Certificate/exporter shall furnish a statement indicating items, its quantity and value supplied by foreign buyer, corresponding Bill of Entry number and date, number of each of shipping bills against which corresponding exports was made.

4.79 Maintenance of Accounts

Nominated Agency/Status Holder having Nominated Agency Certificate shall maintain complete account, consignment-wise, of the gold, silver, platinum, mountings, findings/ plain semi-finished gold/silver/ platinum jewellery etc. imported

for execution of each export order, exports effected and quantity of gold, silver, platinum mountings, findings etc. released against such exports. Such accounts shall be maintained for a minimum period of three years from date of exports.

4.80 Export Through Exhibitions / Export Promotion Tours / Export of Branded Jewellery

- (A) Nominated Agencies shall produce to Customs Authorities letter in original or its certified copy, containing Government's approval for holding exhibition/export of branded jewellery. Any other person shall produce to the Asst. Commissioner, customs letter in original or its certified copy containing GJEPC's approval for holding exhibitions/ export promotion tour/export of branded jewellery.
- (B) In case of re-import, such items, on arrival, shall be verified along with export documents before clearance.
- (C) Exports under this scheme shall be subject to following conditions for following modes of export:
 - (i) Export of Gems and Jewellery for holding/participating in overseas exhibition.
 - (a) Items not sold abroad shall be re- imported within 60 days of close of exhibition. However in case exporter is participating in more than one exhibition within 45 days of close of first exhibition, then 60 days shall be counted from date of close of last exhibition. In case of exhibition in USA, the time period shall be 90 days instead of 60 days mentioned above. In case of personal carriage of gems and jewellery for holding / participating in overseas exhibitions, value of such gems and jewellery shall not exceed US \$ 5 million. Gold/ silver/ platinum content on items sold in such exhibitions may be imported as replenishment.
 - (b) Exporter shall take replenishment from nominated agency within 120 days from the close of the exhibition gold /silver / platinum for replenishment content against items sold abroad in exhibition.
- (D) Personal Carriage of gems & jewellery or export through airfreight/post parcel route for Export Promotion Tours/photo shoots/fashion shows overseas. Personal carriage/export through airfreight/post parcel route of gold/silver/ platinum jewellery, cut and polished diamonds, precious, semi-precious stones, beads and articles as samples upto US \$ 1 Million for export promotion tours/photo shoots/fashion shows and temporary display/sale abroad is also permitted with approval of Gem & Jewellery EPC subject to the condition that promoter would bring back jewellery / goods or repatriate sale proceeds within 45 days from date of departure through normal banking channel. In case of personal carriage for export promotion tours, exporter shall declare personal carriage of such samples to Customs while leaving country and obtain necessary endorsement on Export Certificate issued by Jewellery Appraiser of Customs. In such cases exporter shall book with nominated agency, within 120 days after export promotion tour or expiry of stipulated period of 45 days, whichever is earlier, gold/silver/ platinum for replenishment content against items sold abroad.
- (E) **Export of branded jewellery.**
 - (i) Export of branded jewellery is also permitted with approval of Gem & Jewellery EPC for display/sale in permitted shops set up abroad or in showroom of their distributors/ agents. Items not sold abroad within 365 days shall be re-imported. Exporter shall book with nominated agency within 120 days after the end of stipulated period of 365 days, gold/silver/platinum for replenishment content against items sold abroad.
 - (ii) Following documents shall be submitted for claiming such replenishment:
 - (a) Customs attested invoice;
 - (b) Copy of the approval letter issued by Government/GJEPC;
 - (c) Certificate from Nominated Agency / GJEPC as in **Appendix 4-O.**

In case of exhibitions organised by nominated agencies, gold/silver/ platinum shall be imported as replenishment by nominated agencies within 60 days from close of exhibition.

- (F) Nominated Agencies shall maintain a complete account of exports made, goods sold abroad, goods re-imported, and metals purchased abroad and imported into India. Such account shall be maintained for a minimum period of three years from date of close of exhibition.

4.81 Export against supply by Nominated Agencies

Exporter may obtain gold/silver/ platinum on following basis:

- (i) Replenishment basis after completion of exports;
- (ii) Outright purchase basis in advance;
- (iii) Loan basis.

4.82 Replenishment Basis

- (a) Exporter may apply to Nominated Agency / Status Holder having Nominated Agency Certificate for booking of precious metal gold/silver/platinum. Quantity of precious metal booked with nominated agency shall be equivalent to precious metal content in the export product and admissible wastage.
- (b) Applicant shall at the time of booking deposit an earnest money for a minimum amount of 20% of notional price of precious metal, which shall be adjusted at actual sale.
- (c) Exporter may also export jewellery on a notional rate based on certificate provided by Bank. Exporter must fix price within credit terms allowed to buyer and realise proceeds within the due date of the credit terms or 180 days, whichever is earlier. Exporter exporting on a notional basis under Replenishment Scheme must book the same quantity of gold with Nominated Agency on same rate that he may have booked with buyer. Nominated agencies shall purchase precious metal on behalf of exporter at the rate so fixed and thereafter issue a purchase certificate bearing a serial number to exporter indicating quantity of gold/ silver/platinum and CIF value, in dollars including the Rupee equivalent. Price shall be actual price at which gold/silver/platinum is purchased by nominated agencies plus permitted service charges levied by nominated agencies shall be included with the price of gold/ silver/ platinum for value addition. Duplicate and triplicate copies of exporter's application together with copies of purchase certificate for exporter shall be sent by nominated agencies to concerned Custom House as well as to the negotiating bank who will confirm realization at which gold has been purchased. Exporter exporting under notional rate will get replenishment only after proceeds are realised.
- (d) Exports shall be effected within a period of 120 days from date of booking and drawal of precious metal shall be completed within a period of 150 days from date of booking or within 30 days from date of export whichever is later.

4.83 Outright Purchase Basis in Advance

- (a) Exporter may obtain required quantity of precious metal in advance on outright purchase basis subject to furnishing of BG / LUT to nominated agencies for an amount as may be prescribed by nominated agency. On failure to effect exports within period prescribed, the nominated agencies shall enforce BG / LUT, as the case may be.
- (b) Exports shall be effected within a maximum period of 90 days from date of outright purchase of precious metal.

4.84 Loan Basis

- (a) Exporter may obtain required quantity of precious metal on loan basis subject to furnishing of BG / LUT, for customs duty to nominated agencies for an amount as may be prescribed by nominated agencies. Integrated Goods and Services tax and Compensation Cess leviable under Section 3(7) AND 3(9) of Customs Tariff Act shall be payable separately on imports. On failure to effect exports within the period prescribed, the nominated agencies shall enforce the BG / LUT.
- (b) Exporter has to pay interest as notified by IDoR on gold taken on loan basis at the rate as may be specified.
- (c) Export has to be completed within a maximum period of 90 days from date of release of gold on loan basis. No extension for fulfilment of EO shall be allowed.
- (d)
 - (i) Exporter shall be permitted to export jewellery on the basis of a notional rate certificate to be issued by nominated agency / GJEPC. This rate will be based on prevailing Gold/US\$ rate and the US\$/INR rate in notional rate certificate. Certificate issued by nominated agency/GJEPC should not be older than 7 working days of date of shipment.
 - (ii) VA will have to be achieved on rate as may be got fixed with buyer and Nominated Agency.
 - (iii) Exporter shall have flexibility to fix the price and repay Gold Loan within 180 days from date of export. This price shall be communicated to nominated agencies who will issue a certificate showing final confirmation of the rate to the bank negotiating documents, to ensure export proceeds are realized at this rate.
- (e) Nominated agencies may accept payment in dollars towards cost of import of precious metal from EEFC account of exporter.

4.85 Exports against Advance Authorisation

- (a) Procedure applicable to Advance Authorisations under Chapter 4 of Hand Book of Procedures shall generally apply to this scheme except norms for value addition, EO period and regularization of default. Value addition for Gems and Jewellery items shall be as per paragraph 4.61 of this Handbook of Procedures.

- (b) EO will be required to be fulfilled within 120 days from date of import of each consignment against Authorisation. However EO period shall be 180 days from date of import of findings, mountings made of gold, platinum and silver and export of jewellery. No further extension in EO period will be allowed. Advance Authorisation holder may also import gold as replenishment after completion of exports.
- (c) Advance Authorisation holder may obtain gold /silver / platinum from nominated agencies in lieu of direct imports. In such a case, EO will be required to be fulfilled within 90 days from date of supply of Gold/Silver/Platinum by nominated agency and the nominated agency shall also make, both exchange control copy and customs purpose copy of Authorisation invalid for direct imports.

4.86 Regularisation of Bona fide Default

Cases of bona fide default in fulfilment of EO by an exporter who has obtained precious metals from nominated agencies may be regularised provided exporter has paid customs duty along with interest thereon as notified by DoR. Exporter will have the option to pay customs duty through valid duty credit scrips issued under FTP. The interest / penalty shall be required to be paid in cash. In case of Advance Authorisation, the provisions as given in paragraph 4.49 above shall apply. This shall be without prejudice to any action that may be taken against exporter under FT(D&R) Act, Order or Rules Issued hereunder as amended from time to time.

4.87 Replenishment Authorisation for Import of Consumables etc.

Application for import of consumables etc., as given in paragraph 4.36 of FTP shall be filed online to the concerned Regional Authority in ANF 4H.

4.88 Personal Carriage of Gems & Jewellery Export Parcels

- (a) Personal Carriage of gems & jewellery parcels by Foreign Bound Passengers from all EOU/SEZ units and all firms in DTA through Airports in Delhi, Mumbai, Kolkata, Chennai, Kochi, Coimbatore, Bangalore, Hyderabad, Jaipur is permitted. Procedure for Personal Carriage of exports shall be as prescribed by Customs. Export proceeds shall, however, be realised through normal banking channel.
- (b) For claiming Replenishment in case of Personal Carriage of Exports by Foreign Bound passenger, documents shall be same as mentioned under paragraph 4.82(c) above. Authorised Courier Companies are also permitted to operate on the above lines.

4.89 Personal Carriage of Gems & Jewellery Import Parcels

Personal carriage of gems & jewellery import parcels by an Indian importer/ Foreign National may be permitted into all EOUs/SEZ units and all firms in DTA through airports in Delhi, Mumbai, Kolkata, Chennai, Bangalore, Hyderabad Jaipur. Procedure will be same as for import of goods by air-freight except that parcels shall be brought to Customs by Importer / Foreign National for examination and release. Clearance of imports under this scheme shall be as per normal customs clearance procedure.

4.90 Duty free import of samples

Duty free import of gems and jewellery samples upto Rs 3 lakh or 0.25% of the average of last three years export turnover of gems and jewellery items, whichever is lower, shall be allowed in a financial year as per Customs notification.

4.91 Re-import of rejected jewellery

An exporter of plain/ studded precious metal jewellery shall be allowed to re-import duty free jewellery rejected and returned by buyer up to 2% of FOB value of exports in preceding licencing year (based on CA certified copy of export of preceding year) with refund of any duty exemption/refund/replenishment benefit availed on inputs used as per customs rules and regulations.

4.92 Diamond & Jewellery Dollar Accounts

Policy for Diamond and Jewellery Dollar Accounts is given in paragraph 4.50 of FTP. Detailed procedure for its operation will be notified separately.

4.93 Export and import of Diamond, Gemstone & Jewellery on consignment basis

- (a) Policy for export and import of diamond, gemstone and jewellery on consignment basis is given in paragraph 4.53 of FTP.
- (b) Detailed procedure in this regard shall be governed as per the relevant Customs Rules & Regulations. Re-import of these items (either in complete or partial lot) exported on consignment basis shall be subject to condition that exporter follows prescribed provisions of relevant customs notification to establish that goods are the same which were exported.

4.94 Guidelines/ Monitoring for import of precious metal by the Nominated Agencies

The guidelines on import of precious metal by the nominated agencies and monitoring are as under:

- (a) Deleted.
- (b) Following guidelines for monitoring the import of precious metal and its distribution and / or own use by the Nominated Agencies will be followed, (other than the Banks nominated by RBI for this purpose):
 - (i) Every Nominated Agency is required to maintain records of imports of precious metal (both quantity and value) and its distribution for the purpose of exports of value added product as well as for the purpose of domestic consumption as per the format given in Appendix 4-M of Hand Book of Procedures. Nominated Agencies will also have to follow the guidelines/ rules/procedures /directions as prescribed by RBI and DGFT. Failure to comply will render Nominated Agency Certificate liable to be cancelled in addition to action under FT (DR) Act 1992, as amended, after affording opportunity of personal hearing.
 - (ii) Monitoring by Gems & Jewellery Export Promotion Council:
Monitoring in respect of Nominated Agencies MMTC Ltd, Handicraft and Handlooms Exports Corporation Ltd, The State Trading Corporation Ltd, PEC Ltd, STCL Ltd, MSTC Ltd, Diamond India Limited will be by Gems & Jewellery Export Promotion Council (G&J EPC). Nominated Agencies shall file half yearly return as per format given in Appendix 4-M of Hand Book of Procedures, to the Gems & Jewellery Export Promotion Council (GJEPC), Mumbai within 15 days of every completed half year. In turn, G&J EPC shall compile the half yearly return and the figures submitted by the Nominated Agency and check the performance of the Nominated Agency. Thereafter, GJEPC shall forward the compiled half yearly returns along with its observation on performance of Nominated Agency to DGFT headquarters within one month of every completed half year. In case of delay in filing or non-submission of half yearly return within 15 days of every completed half year, GJEPC shall seek comments of defaulting Nominated Agencies. GJEPC will also forward the particulars of defaulting Nominated Agency to DGFT headquarters for taking appropriate action against defaulting Nominated Agency.
 - (iii) Monitoring by Regional Authorities of DGFT:
Regional Authority which has issued Nominated Agency Certificate shall monitor performance of such Certificate holders based on the half yearly returns to be filed by such agencies to the concerned Regional Authority. The Nominated Agency shall file half yearly return to Regional Authority in the month of October (for the period April to September) / April (for the period October to March) as per the format given in Appendix 4-M of Hand Book of Procedures. Regional Authority shall consolidate and verify these returns. Regional Authority will also inform DGFT which agency has not filed the return and to also take appropriate action within 30 days for suspension / cancellation of the Nominated Agency Certificate.
- (d) DGFT headquarters can also review the performance of Nominated Agencies, whenever necessary.
- (e)

CHAPTER 5**EXPORT PROMOTION CAPITAL GOODS (EPCG) SCHEME****5.01 Policy**

Policy relating to EPCG Scheme is given in Chapter 5 of FTP.

5.02 Application Form

An application for grant of an authorisation may be made by Registered Office or Head Office or a Branch Office or Manufacturing Unit of an eligible exporter to RA concerned in ANF 5A along with documents prescribed therein.

5.03 Nexus Certification

- (a) RA concerned shall, on the basis of nexus certificate from an Independent Chartered Engineer (CEC) submitted by the applicant in Appendix 5A, issue EPCG authorisation. Reasonable wastage, if any, anticipated at the time of installation of capital goods will also be certified by the Chartered Engineer in the nexus certificate and the same would be mentioned in the condition sheet of the EPCG authorisation at the time of issue. For issuance of such certificate, the Chartered Engineer shall act only in the domain of his/her competence.
- (b) RA shall thereafter forward a copy of the EPCG authorisation to the concerned Jurisdictional Customs Authority. The wastage so permitted at the time of issuance of authorisation would be allowed to be sold as scrap/waste on payment of applicable duty.

- (c) An application for amendment in the list of import item(s) including addition(s)/deletion(s), if any, may be filed with RA concerned provided the authorisation is valid for import. The applicant would give justification for seeking such amendment(s) along with fresh nexus certificate from an independent Chartered Engineer.
- (d) An application for amendment in the list of export item(s) including addition(s)/deletion(s) if any, may be filed with RA concerned provided the Export Obligation period of the authorisation is valid and the CG has nexus with export product. The applicant would give justification for seeking such amendment(s) along with fresh nexus certificate from an independent Chartered Engineer.

5.04 Certificate of Installation of Capital Goods

- (a) Authorization holder shall produce, within six months from date of completion of import, to the concerned RA, a certificate from the jurisdictional Customs authority or an independent Chartered Engineer, at the option of the authorisation holder, confirming installation of capital goods at factory/premises of authorization holder or his supporting manufacturer(s). The RA may allow one time extension of the said period for producing the certificate by a maximum period of 12 months with a composition fee of Rs. 5000/-. Where the authorisation holder opts for independent Chartered Engineer's certificate, he shall send a copy of the certificate to the jurisdictional Customs Authority for intimation/record. The authorization holder shall be permitted to shift capital goods during this period to other units mentioned in the IEC and RCMC of the authorization holder subject to production of fresh installation certificate.
- (b) In the case of import of spares, the installation certificate shall be submitted by the Authorization holder within a period of three years from the date of import.

5.05 Port of Registration

EPCG Authorisation shall be issued with a single port of registration as per paragraph 4.37 of HBP, for imports. However, exports can be made from any port specified in paragraph 4.37 of HBP.

5.06 Import of spares, tools, refractories and catalysts

- (a) Applications for procurement of capital goods covered under sub-paragraphs (a) (iii) and (iv) of paragraph 5.01 of FTP shall contain a list of plant/machinery installed in factory/premises of the applicant for which such capital goods are required, duly certified by Chartered Engineer or Jurisdictional Customs Authorities."
- (b) In case of import of spares, EPCG authorisation shall not specify list of spares but shall indicate:
 - (i) Name of plant /machinery for which spares are required.
 - (ii) Value of duty saved allowed under the authorisation.
 - (iii) Description of product to be exported and value of export obligation.
- (c) Authorisation holder shall maintain a register of stock & consumption of capital goods covered under sub-paragraphs (a) (iii) and (iv) of paragraph 5.01 of FTP imported under the scheme and at the time of final redemption of export obligation, authorization holder shall submit certificate from independent Chartered Engineer confirming their use in the installed capital goods on the basis of such register.

5.07 Conversion of EOU/ Relocated SEZ Units to DTA Unit under EPCG Scheme

- (a) An EOU/ a relocated SEZ unit, while converting to a DTA Unit, may apply for an EPCG authorisation along with documents prescribed. 'No Objection Certificate' should be produced from the concerned Development Commissioner.
- (b) The export obligation period for a unit which converts from EOU / SEZ Scheme to EPCG Scheme would be the same as is available to a direct EPCG Authorisation Holder as per Paragraph 5.01 of Foreign Trade Policy (FTP).
- (c) If a standalone EOU / SEZ unit wishes to de-bond from EOU to EPCG Scheme, there shall be no requirement for maintenance of average export obligation and the unit shall be required to maintain only specific export obligation equivalent to six times of the proportionate duty saved amount of the depreciated value of capital goods for which the Authorisation has been obtained.
- (d) In case one unit of a firm / company opts to de-bond from EOU to EPCG Scheme, while other unit(s) are DTA units, then the average export obligation in respect of the authorisations issued to the firm / company (other than de-bonding unit) shall remain unchanged and the average EO, after de-bonding of the unit, shall be fixed by excluding the exports made by the de-bonded unit from the total exports of the firm / company, which runs concurrently for all the units of the firm / company. In such a case, specific EO equivalent to six times of the proportionate duty saved amount on the depreciated value of the Capital Goods would be imposed on the de-bonding unit shifting to the EPCG Scheme.

5.08 Sourcing of Capital Goods Manufactured Indigenously

- (a) EPCG authorisation holder intending to source capital goods manufactured indigenously shall make a request to the RA for invalidation of EPCG authorisation for direct import / issuance of Advance Release Order (ARO) for availing deemed export benefits as given in paragraph 7.03 of FTP read with paragraph 7.02(c) of HBP.
- (b) This request can be made either along with application or during the validity period of EPCG Authorisation.
- (c) Applicant shall give the name and address of the manufacturer(s) of capital goods.
- (d) RA concerned will issue the invalidation letter / ARO, in quadruplicate.

5.09 Issuance of Advance authorisation for import of inputs

Indigenous manufacturer intending to supply capital goods to EPCG authorisation holder may apply to RA for issuance of Advance authorisation for import of inputs including components required for manufacture of capital goods to be supplied to EPCG authorisation holder.

5.10 Conditions for fulfilment of Export Obligation

In addition to conditions in paragraph 5.04 of FTP, the following conditions shall also be applicable for fulfilment of export obligation:

- (a) Name of the supporting manufacturer as well as the exporter shall be indicated on export documents.
- (b) EPCG authorisation holder may export either directly or through third party(ies).
- (c) In case the Authorization Holder wants to export through a third party, export documents viz., shipping bills / Bill of exports etc. shall indicate name of both authorization holder and supporting manufacturer, if any, along with EPCG authorization number. BRC, GR declaration, export order and invoice should be in the name of third party exporter. The goods exported through third party should be manufactured by the EPCG Authorisation Holder or the supporting manufacturer where the capital goods imported under the authorisation have been installed. Proceeds realised through normal banking channel from third party exporter's account to the authorisation holder's account on account of such exports only shall be counted towards fulfilment of export obligation.
- (d) The EPCG authorization holder shall submit the following additional documents for discharge of EO through third party (ies):
 - (i) A copy of agreement entered into between the authorization holder and the ultimate exporter undertaking to export the goods manufactured by the authorization holder/supporting manufacturer for fulfilment of the export obligation against the EPCG authorization in question.
 - (ii) Proof of having despatched the goods from authorization Holder's factory premises to the ultimate exporter/port of export viz. (a) ARE 1 certificate issued by Central Excise / Tax invoice for export prescribed under the GST rules with due authentication by the Customs verifying the exports along with the shipping bill number, date and EPCG authorization number or (b) Invoice duly incorporating the relevant EPCG authorization number & date at the time of dispatch in case the unit is not registered with Central Excise / GST.
 - (iii) Lorry Receipt (LR) /Logistical evidence for transportation of goods from the premises of the authorization holder to the third party/port of export.
 - (iv) An undertaking from the 3rd party on a stamp paper, declaring that the products exported for fulfillment of EO by them on behalf of the license holder as per details given in the statement of exports, were manufactured by the license holder.
 - (v) Financial evidence for having received proceeds through normal banking channel from third party exporter's account to the authorization holder's account on account of such exports towards such third party supplies.
 - (vi) Disclaimer certificate from third party that they shall not use such proceeds towards EO fulfillment of any EPCG authorization (s) obtained by them.

5.11 Realization of Export proceeds

Export proceeds shall be realized in freely convertible currency except for deemed exports supplies under Chapter 7. Exports to SEZ units /Supplies to developers/ co-developers irrespective of currency of realization, would also be counted for discharge of Export Obligation. Realization in case of supplies to SEZ units shall be from foreign currency account of the SEZ unit.

5.12 Calculation of Average Export Obligation

While calculating Average Export Obligation, exports counted/being counted for fulfilling specific EO against EPCG Authorisations within valid EO Period (whether original or extended) that have been made in the preceding 3 years will not be taken into account.

5.13 Exemption from maintenance of average export obligation

- (a) In case of export of goods relating to the following the EPCG authorisation holder shall not be required to maintain average export obligation:
- (i) Handicrafts,
 - (ii) Handlooms,
 - (iii) Cottage & Tiny sector,
 - (iv) Agriculture,
 - (v) Aqua-culture (including Fisheries), Pisciculture,
 - (vi) Animal husbandry,
 - (vii) Floriculture & Horticulture,
 - (viii) Poultry,
 - (ix) Viticulture,
 - (x) Sericulture,
 - (xi) Carpets,
 - (xii) Coir, and
 - (xiii) Jute
- (b) However, this exemption from maintenance of average export obligation shall not be allowed for import of fishing trawlers, boats, ships and other similar items.
- (c) Goods, excepting tools imported under EPCG scheme by sectors specified in sub-paragraph (a) above, shall not be allowed to be transferred for a period of five years from date of imports even in cases where export obligation has been fulfilled.

5.14 Block-wise Fulfilment of EO

- (a) The Authorisation holder under the EPCG scheme shall, while maintaining the average export obligation, fulfill the specific export obligation over the prescribed block period in the following proportions:

Period from the date of issue of Authorisation	Minimum export obligation to be fulfilled
Block of 1st to 4th year	50%
Block of 5th and 6th year	Balance EO

- (b) The Authorisation holder would intimate the Regional Authority on the fulfilment of the export obligation, as well as average exports, within three months of completion of the block, by secured electronic filing using digital signatures.
- (c) Where EO of the first block is not fulfilled in terms of the above proportions, except in cases where the EO prescribed for first block is extended by the Regional Authority subject to payment of composition fee of 2% on duty saved amount proportionate to unfulfilled portion of EO pertaining to the block, the Authorization holder shall, within 3 months from the expiry of the block, pay duties of customs (along with applicable interest as notified by DOR) proportionate to duty saved amount on total unfulfilled EO of the first block.
- (d) (i) Authorisations issued from 1st April, 2002 upto 31st August, 2004 shall be governed by provisions of paragraph 5.8 of HBP Vol. 1 (RE-02) as amended from time to time.
- (ii) Authorisations issued from 1st September, 2004 upto 17th April, 2013 shall be governed by provisions of paragraph 5.8 of HBP Vol. 1 (RE-12) as amended till 17.04.2013.
- (iii) Authorisations issued from 18th April, 2013 till issue of Notification of FTP 2015-20 shall be governed by provisions of paragraph 5.8 of HBP Vol. 1 as amended vide PN No. 1 dated 18.04.2013.
- (iv) Authorisations issued from 1st April, 2015 till 4th December 2017 shall be governed by provisions of paragraph 5.14 of HBP as amended vide PN No. 1 dated 01.04.2015.

5.15 Monitoring of Export Obligation

Authorisation holder shall submit to RA concerned by 30th April of every year, report on fulfilment of export obligation by secured electronic filing using digital signatures/ or hard copy thereof.

5.16 Automatic Reduction/ Enhancement upto 10% Duty saved amount and pro rata Reduction/ Enhancement in export obligation

If authorization issued has been utilized for import of goods: –

- (a) in excess of duty saved amount indicated on the authorization by not more than 10%, the authorization shall be deemed to have been enhanced by that proportion. Customs shall automatically allow clearance of such goods without endorsement by RA concerned. The authorization holder shall furnish additional fee to cover excess imports effected, in terms of duty saved amount, to RA concerned, within one month of excess imports taking place. Export obligation shall automatically stand enhanced proportionately.
- (b) in excess of duty saved amount indicated on the authorization by more than 10%, the RA concerned, as per its delegated powers, may allow enhancement in duty saved amount of the EPCG authorization. The Authorisation holder shall furnish additional BG/LUT to the Customs Authority.
- (c) less than the duty saved amount indicated on the authorization, the export obligation shall stand reduced on pro-rata basis with reference to actual utilization of the authorization.

5.17 Extension in Export Obligation Period

- (a) Extension in Export Obligation Period of EPCG authorization issued prior to Notification of FTP 2015-20 RE 2017 shall be governed by relevant provisions of HBP applicable on the date of issue of authorisation.
- (b) Extension in Export Obligation Period of EPCG authorization issued prior to Notification of FTP 2015-20 shall be governed by relevant provisions of HBP Vol 1 applicable on the date of issue of authorization.
- (c) In case of zero duty EPCG Authorizations, two extensions of one year each in export obligation period may be considered by RA concerned, on payment of composition fee equal to 5% and 10% respectively of proportionate duty saved amount on unfulfilled export obligation for the first/second year of extension or an enhancement in export obligation imposed to the extent of 10% /20% respectively of the total export obligation imposed under the authorization for first/second year of extension, as the case may be, at the choice of the exporter. Minimum composition fee will be Rs.10,000.
- (d) Request for extension in EO Period shall be made to RA within 90 days from the date of expiry of original EO Period. However, RA may consider the request for extension received upto 180 days with additional composition fee of Rs.5,000.

5.18 Provision for Units under BIFR/Rehabilitation

- (a) Deleted
- (b) Deleted

5.19 Relief in Average Export Obligation

- (a) To provide relief to exporters of those sectors where total exports in that sector/product group has declined by more than 5% as compared to the previous year, average export obligation for the year may be reduced proportionate to reduction in exports of that particular sector/product group during the relevant year as against the preceding year. However, in case export decline is continuous over consecutive years, the base year for calculation of eligibility and calculation of reduction in average export obligation will be taken as the year after which the exports have shown continuous decline.
- (b) The sectors /product groups for which this relaxation is to be allowed shall be conveyed by the DGFT to all the RAs within seven months of the end of the previous financial year, and the RAs shall re-fix the annual average EO for previous year accordingly for exporters in that sector / product group.

5.20 Automatic EO extension in the event of ban on export product

Whenever a ban/restriction is imposed on export of any product, export obligation period in respect of EPCG authorisations already issued prior to imposition of ban on such export products would stand automatically extended for a period equivalent to duration of such ban, without any composition fee. Authorisation holder would not be required to maintain average E.O. as well for the ban period.

5.21 Deleted**5.22 Redemption**

- (a) Authorisation holder shall apply for redemption in ANF 5B with documents prescribed therein as a proof of EO fulfilment.

- (b) On being satisfied, RA concerned shall issue a certificate of discharge of export obligation to the EPCG authorisation holder and forward a copy to Customs Authorities with whom BG/LUT has been executed. A statement giving details of the documents submitted by the authorisation holder towards evidence of EO fulfilment shall also be enclosed with the certificate.
- (c) RA shall process such applications ordinarily within 30 days. Shortcomings, if any, shall be pointed out in one go. All correspondence, thereafter, shall relate to these deficiencies only. Fresh correspondence, if necessary, shall be within 15 days. Once documents are complete, EO will be discharged within 30 days of receipt of complete documents /information.
- (d) Applications that remain outstanding beyond a period of 60 days after receipt of complete documents shall be reported to the EPCG Division at DGFT headquarters alongwith reasons thereof.

5.23 Regularization of Bonafide Default and Exit from EPCG Scheme

- (a) In case, EPCG authorisation holder fails to fulfil prescribed export obligation, he shall pay Customs Duty along with applicable interest as prescribed by Customs Authority. Such facility can also be availed by EPCG authorisation holder to exit at his option. The authorisation holder will have the option to furnish valid duty credit scrips, issued under Chapter 3 or Chapter 5 of FTP, for payment of the Customs duty component.
- (b) Authorisation holder can also pay duty and interest suo-motu on the basis of self /own calculation as per the procedure specified in paragraph 4.50 of HBP.

5.24 Maintenance of Records

Every EPCG authorisation holder shall maintain, for a period of 2 years from date of redemption, a true and proper account of exports/ supplies made and services rendered towards fulfilment of export obligation.

5.25 Re-Export / Repair/Replacement of Capital Goods Imported under EPCG Scheme

- (a) Capital Goods imported under EPCG scheme, which are found defective or unfit for use, may be re-exported to foreign supplier within three years from the date of clearance by Customs of such goods, with permission of RA / Customs Authority. Consequently, EO would be re-fixed.
- (b) Capital Goods imported and found defective or otherwise unfit for use may be exported, within two years from the date of clearance by Customs of such goods, with permission of RA / Customs Authority and Capital Goods in replacement thereof be imported under EPCG scheme. In such cases, while allowing export, the Customs shall credit the duty benefit availed which can be debited again at the time of import of such replaced Capital Goods.
- (c) Capital Goods imported under EPCG scheme, may be re-exported for repairs abroad within three years from the date of clearance by Customs of such goods, with permission of RA / Customs Authority. The duty component on the expenditure incurred on the repairs as well as the insurance and the freight, both ways shall be taken into account for re-fixation of the EO.

5.26 Penal Action

In case of failure to fulfil export obligation or any other condition of authorisation, authorisation holder shall be liable for action under FT (D&R) Act, 1992, as amended, Orders and Rules made thereunder, provisions of FTP/HBP, Customs Act, 1962, as amended from time to time or any other law in force.

5.27 Clubbing of EPCG authorisations

- (a) Clubbing of two or more EPCG authorisations issued to the same authorisation holder would be permitted.
- (b) An application for clubbing can be made to RA concerned in ANF 5C. Clubbing shall only be permitted in case export products endorsed on the authorisations are same /similar and if authorisations are issued by the same RA.
- (c) Total export obligation would be re-fixed taking into account total of duty saved amount of the clubbed authorisations.
- (d) On Clubbing, authorisations for all purpose shall be deemed to be a single EPCG authorisation. Export obligation period for clubbed authorisations shall be reckoned from first authorisation issue-date.
- (e) Average export obligation for clubbed authorisations would be highest of average export obligations endorsed on individual authorisations so clubbed.
- (f) Clubbing would be permitted during valid EOP including extended period, if any. However, clubbing in case of all authorisations where EO period is over may be allowed for regularisation purposes provided they have been issued under same policy period.

- (g) In case of clubbing of EPCG authorizations where EO can be fulfilled by export of alternate product(s)/service(s), the proportion of alternate product(s)/service(s) for EO fulfilment / regularization will be restricted to the lowest of the percentage of alternate product(s) / service(s) allowed in the clubbed authorizations.
- (h) EPCG authorisations issued prior to 1.4.2007 shall be governed by provisions contained in Chapter 5 of HBP Vol.1 (RE-2006). The EPCG Authorisations issued between 01.04.2007 and 17.04.2013 shall be governed by provisions contained in Chapter 5 of HBP Vol.1 (RE-2012, as amended). The EPCG Authorisations issued from 18.04.2013 till the issue of Notification of HBP 2015-20 shall be governed by provisions contained in Public Notice No.1 dated 18.4.2013. The EPCG Authorisations issued between Notification of HBP 2015-20 till the Notification of HBP 2015-20 (RE 2017) shall be governed by provisions contained in HBP 2015-20.

5.28 Post Export EPCG Duty Credit Scrip(s)

- (a) Exporters can exercise this option by filing an application in ANF5A with the RA concerned by selecting the option for this Scheme.
- (b) All applicable duties shall be paid in cash by the exporter at the time of import of Capital Goods.
- (c) RA shall issue an Authorisation specifying
- (i) “Not for imports” on the body of the Authorisation;
 - (ii) Average EO, if any;
 - (iii) Specific EO @ 85% of the applicable specific EO, computed as if the imports were to take the benefit of duty exemption; and
 - (iv) EOP, which shall commence from the Authorisation issue date.
- (d) Exporter can file request in ANF 5 B, for issuance of Duty Credit Scrip(s) in proportion to the EO completed within the specified EOP. Only for first such request, proof of actual duty payments on Capital Goods, nexus and installation certificate(s) of Capital Goods shall be submitted alongwith proof of fulfilment of EO alongwith proof of maintenance of Average EO. Subsequently, only proof of fulfilment of specific EO (alongwith proof of maintenance of Average EO) additionally completed vis-à-vis specific EO fixed {as in c(iii) above} may be submitted, unless there have been any changes in documents / proofs submitted earlier.
- (e) RA shall issue freely transferable duty credit scrip(s) equivalent to proportionate EO fulfilled.
- (f) The computation of freely transferable Duty Credit Scrip(s) will be based on basic Customs duty amount paid.
- (g) Deleted
- (h) All provisions of the existing EPCG Scheme shall apply insofar as they are not inconsistent with this scheme.
- (i) The CG imported under paragraph 5.12 of FTP shall not be disposed of till the date of last export for offsetting EO against such CG.
- (j) In case of re-export of CG found defective or unfit for use as per the provisions of paragraph 5.25 of HBP if the exporter claims drawback on such re-export there would be no remission of duty under paragraph 5.12 of FTP.

5.29 Green Technology Products

The Export Products covered under Paragraph 5.10 of FTP which provides for reduced export obligation of 75% for green technology products are:

- (i) Equipment for Solar Energy decentralized and grid connected products,
- (ii) Bio-Mass Gassifier,
- (iii) Bio-Mass/Waste Boiler,
- (iv) Vapour Absorption Chillers,
- (v) Waste Heat Boiler,
- (vi) Waste Heat Recovery Units,
- (vii) Unfired Heat Recovery Steam Generators,
- (viii) Wind Turbine,
- (ix) Solar Collector and Parts thereof,
- (x) Water Treatment Plants,
- (xi) Wind Mill, Wind Mill Turbine / Engine,
- (xii) Other Generating Sets - Wind powered,
- (xiii) Electrically Operated Vehicles – Motor Cars,
- (xiv) Electrically Operated Vehicles - Lorries and Trucks,
- (xv) Electrically Operated Vehicles – Motor Cycles/Mopeds, and
- (xvi) Solar Cells.

CHAPTER 6

EXPORT ORIENTED UNITS (EOUs), ELECTRONICS HARDWARE TECHNOLOGY PARKS (EHTPs), SOFTWARE TECHNOLOGY PARKS (STPs) SCHEME AND BIO-TECHNOLOGY PARKS (BTPs).

6.00 Scheme

Policy relating to EOUs, EHTPs, STPs and BTPs Schemes is given in Chapter 6 of Foreign Trade Policy (FTP).

6.01 Application / Approval / Renewal of approval

- (a) For setting up an EOU, three copies of application as in ANF 6 A of Appendices & ANFs may be submitted to DC.
- (b)
 - (i) Applications for setting up units under EOU scheme shall be approved or rejected by Units Approval Committee within 15 days, as per criteria indicated in Appendix 6 A of Appendices & ANFs and sector specific conditions relating to approval as in Appendix 6 B of Appendices & ANFs. In other cases, approval may be granted by DC after clearance by BOA.
 - (ii) On approval, a Letter of Permission (LoP) / Letter of Intent (LoI) shall be issued by DC / designated officer to EOU/ EHTP / STP / BTP unit. LoP / LoI shall have an initial validity of 2 years to enable the Unit to construct the plant & install the machinery and by this time the unit should have commenced production. In case the unit is not able to commence production in initial validity of 2 years, an extension of one year may be given by the DC for valid reasons to be recorded in writing. Subsequent extension of one year may be given by the Unit Approval Committee subject to condition that two thirds of activities including construction, relating to the setting up of the Unit are complete and Chartered Engineer's certificate to this effect is submitted by the Unit. Further extension, if necessary, will be granted by the Board of Approval. Once unit commences production, LoP / LoI issued shall be valid for a period of 5 years for its activities. This period may be extended further by DC for a period of 5 years at a time.
- (c) Proposals for setting up EOU requiring industrial licence may be granted approval by DC after clearance of proposal by BOA (as per Appendix 6 C of Appendices & ANFs) and Department of Industrial Policy and Promotion within 45 days on merits.
- (d) STP / EHTP complexes can be set up by Central Government, State Government, Public or Private Sector Undertakings or any combination thereof, duly approved by Inter-Ministerial Standing Committee (IMSC) in Ministry of Communication and Information Technology (Department of Electronics & Information Technology - DeitY). Application for setting up EHTP / STP unit shall be in format prescribed by DeitY and shall be submitted to officer designated by DeitY.
- (e) BTP can be set up by Central Government, State Government, Public or Private Sector Undertakings or any combination thereof. Application for setting up of BTP shall be submitted to Department of Bio-Technology (DoBT) and such applications which meet guidelines prescribed by DoBT will be approved and recommended to DGFT for notification. Application for setting up of BTP unit shall be submitted to officer designated by DoBT.
- (f) LoP / LoI shall specify item(s) of manufacture / service activity, annual capacity, projected annual export for first five years in dollar terms, Net Foreign Exchange (NFE) earnings, limitations, if any, regarding sale of finished goods, by-products and rejects in DTA and such other matter as may be necessary and also impose such conditions as may be required.
- (g) LoP / LoI issued to EOU / EHTP / STP / BTP units by concerned authority would be construed as an authorization for all purposes. Standard format for LoP for EOU is given in Appendix 6 D of Appendices & ANFs.
- (h) EOUs shall have separate earmarked premises for separate LoP. Similarly, EOUs may be approved on leased premises provided lease has been obtained from Government Department / Undertaking / Agency. However, in case lease is obtained from private parties, it shall have a validity period of five years from date of LUT and DC shall satisfy himself of genuine nature of lease.
- (i) On completion of approval period as provided for in Paragraph 6.05 of FTP, it shall be open to unit to continue under scheme or opt out of scheme. Where unit opts to continue, DC will extend approval period. If no intimation in this regard is received from unit within a period of six months of expiry of approval period, DC will take action, suo motu, to cancel approval under EOU scheme and take further action in this regard. Where units give their option to continue after expiry of six months as stipulated above, DC will grant extension after obtaining approval of BOA.

6.02 Legal Undertaking (LUT)

- (a) Approved EOU / EHTP / STP / BTP unit shall execute an LUT with DC / Designated Officer concerned as in Appendix 6 E of Appendices & ANFs.
- (b) All EOU / EHTP / STP / BTP units should have permanent e-mail address. No LUT for new units shall be executed unless unit has its permanent e-mail address and digital signature on said e-mail ID. In event of an EOU not having permanent e-mail address and digital signature, further imports and DTA sale shall not be permitted by DC.

6.03 Export of Goods and Services

- (a) Software units may undertake exports using data communication links or in form of physical exports (which may be through courier service also), including export of professional services.
- (b) EOUs shall be permitted to export jewellery on basis of a notional rate certificate issued by nominated agency. This rate will be based on prevailing Gold / US\$ rate and US\$ / INR rate in notional rate certificate. Certificate issued by nominated agency should not be older than 7 working days of date of shipment.
- (c) Exporter shall have flexibility to fix price and repay gold loan within 180 days from date of export. Price shall be communicated to nominated agencies who will issue a certificate showing final confirmation of rate to bank negotiating document, to ensure export proceeds are realized at this rate.
- (d) Gems & Jewellery EOUs may re-export imported goods and export domestically procured goods, including goods generated out of partial processing / manufacture. Besides, supply of unsuitable / broken cut and polished diamonds, precious and semi-precious stones upto 5% of value of imported or indigenously procured goods to DTA against valid Gems & Jewellery REP as applicable on payment of appropriate duty is also permitted.

6.04 Import / Domestic Procurement of Goods

Goods permitted to be imported / procured from DTA shall include:

- (a) Raw materials, components, consumables, intermediates, spares and packing materials .
- (b) Capital goods, whether new or second-hand, including inter-alia following and their spares:
 - (1) DG sets, captive power plants, transformers and accessories for all above.
 - (2) Pollution control equipment.
 - (3) Quality assurance equipment.
 - (4) Material handling equipment, like fork lifts and overhead cranes, mobile cranes, crawler cranes, hoists and stackers.
 - (5) Un-interrupted Power Supply System (UPS), Special racks for storage, storage systems, modular furniture, computer furniture, anti- static carpet, teleconference equipment, Servo Control System, Air-conditioners / Air conditioning system, panel for electricals and special data transmission cable.
 - (6) Security Systems
 - (7) Tools, jigs, fixtures, gauges, moulds, dyes, instruments and accessories.
- (c) Raw materials for making capital goods for use within unit.
- (d) Others including:
 - (1) Prototypes and technical samples for existing product(s) and product diversification development or evaluation.
 - (2) Drawings, blue prints, charts, microfilms and technical data.
 - (3) Office equipment, including PABX, Fax machines, projection system, Computers, Laptop and Server.
- (e) Spares and consumables for above items.
- (f) Any other items not mentioned above with approval of BOA.

6.05 Repair / Remaking of Jewellery

EOUs may import plain / studded gold / platinum or silver jewellery for export after repairs / remaking.

6.06 Conditions of Import

Import of goods by EOU / EHTP / STP / BTP units shall be subject to following conditions:

- (a) Goods shall be imported into EOU / EHTP / STP / BTP premises. However, agriculture and allied sectors and granite sector units in EOU may supply / transfer capital goods and inputs in farm / fields / quarries with prior intimation to jurisdictional Customs authorities, provided ownership of goods rests with EOUs. Granite sector would also be allowed to take spares upto 5% of value of Capital Goods to quarry site.
- (b) Procedure as prescribed under Customs/Central Excise rules for EOUs and units in EHTP / STP / BTP will be followed, and appropriate bond executed with Customs/Central Excise Authorities.
- (c) (i) The period of utilisation of goods, including capital goods, shall be co-terminus with the validity of LoP.
(ii) However, imported tea shall be utilized within a period of 6 months from date of import. Similarly, export obligation against import of items {covered by Chapter 9 of ITC(HS)} and coconut oil shall be fulfilled within a period of 90 days from the date on which first import consignment is cleared by Customs Authorities.
(iii) Further, in case of import of spices for VA purpose like crushing / grinding / sterilization or for manufacture of oils and oleoresins of pepper, cardamom and chillies (and not for simple cleaning, grading, re-packing etc.), EO shall be fulfilled within 120 days from the date of importation of first consignment. In case of import of spices (other than pepper, cardamom and chillies) for manufacture of spice oils and oleoresins, EO shall be fulfilled within 12 months.
- (d) Goods already imported / shipped / arrived before issue of LoP / LoI are also eligible for clearance as provided under para 6.01 (d) (ii) of FTP 2015-20 under EOU / EHTP / STP / BTP scheme without payment of duty and/or taxes as applicable, provided, the said duties and/or taxes has not been paid and goods have not been cleared from Customs.
- (e) Consumption of inputs by the EOU / EHTP / STP / BTP unit shall be based on the Standard Input Output Norms (SION) provided that:
 - (i) where no SION have been notified, generation of waste, scrap and remnants upto 2% of input quantity shall be allowed;
 - (ii) where additional items other than those given in SION are required as inputs or where generation of waste, scrap and remnants is beyond 2% of input quantity, use of such inputs shall be allowed by the jurisdictional DC within a period of three months from the date of and based on self declared norms, with the unit undertaking to adjust self-declared / ad hoc norms in accordance with norms as finally fixed by Norms Committee in DGFT;
 - (iii) in case of any difficulty in fixation of SION as above, BOA in consultation with Norms Committee in DGFT, will decide on a case to case basis.

6.07 Taking out of Fax Machines / Laptop / Computers outside approved premises

- (a) EOU / EHTP / STP / BTP units may install one fax machine at a place of its choice, outside premises of unit, subject to intimation of its location to concerned Customs authorities.
- (b) EOU / EHTP / STP / BTP units may, temporarily take out of premises of unit, duty and/or tax free laptop / computers and video projection systems for working upon by authorized employees.
- (c) EOU / EHTP / STP / BTP units may install personal computers not exceeding two in number, imported / procured duty and/or tax free in their registered / administrative office subject to DoR guidelines.
- (d) For IT and IT enabled services, persons authorized by software units may access facility installed in EOU / EHTP / STP / BTP unit through communication links.

6.08 Facility of working from a place outside the unit

Person(s) / employee(s) authorized by a unit of (i) IT related EOU or (ii) STP or (iii) EHTP or (iv) BTP may work from a place outside the said unit, subject to the following conditions:

- (i) There must be an Authorisation from the unit specifying the duration of such authorization.
- (ii) Responsibility for carrying out the work and supervision, if any, be that of the unit, which will be liable for any misuse.
- (iii) Export of the resultant products / services would take place only from the premises of the unit.

6.09 Leasing of Capital Goods

Value of imported capital goods financed through leasing companies or obtained free of cost and / or on loan / lease basis, shall also be taken into account for purpose of calculation of NFE as defined in FTP.

6.10 Net Foreign Exchange (NFE) Earnings

- (a) EOU / EHTP / STP / BTP unit shall be a positive net foreign exchange earner. NFE earnings shall be calculated cumulatively in the block period as per Paragraph 6.04 of FTP, according to the formula given below. Items of manufacture for export specified in LoP / LoI alone shall be taken into account for calculation of NFE.

$$\text{Positive NFE} = A - B > 0$$

Where

‘NFE’ is Net Foreign Exchange;

‘A’ is FOB value of exports by EOU / EHTP / STP / BTP unit;

‘B’ is sum total of CIF value of all imported inputs and CIF value of all imported capital goods, and value of all payments made in foreign exchange by way of commission, royalty, fees, dividends, interest on external borrowings / high sea sales during first five year period or any other charges. It will also include payment made in Indian Rupees on high sea sales.

“Inputs” mean raw materials, intermediates, components, consumables, parts and packing materials.

- (b) If any goods are obtained from another EOU / EHTP / STP / BTP / SEZ unit, or procured from an international exhibition held in India, or bonded warehouses or precious metals procured from nominated agencies, value of such goods shall be included under ‘B’.
- (c) If any capital goods are imported duty and/or tax free or leased from a leasing company, received free of cost and / or on loan basis or transfer, CIF value of capital goods shall be included pro-rata, under ‘B’ for period it remains with units.
- (d) For annual calculation of NFE, value of imported capital goods and lump sum payment of foreign technical know-how fee shall be amortized as under:

1st – 10th year : 10%.

Provided that above amortization rates would be applicable only if an undertaking is given by a unit that it will not exit to DTA in the first 10 years. For existing units, proportionate Customs and excise duty must be paid where NFE is less than depreciation already claimed, before exit.

6.11 Maintenance of Accounts

- (a) EOU / EHTP / STP / BTP unit shall maintain proper account, and shall file digitally signed quarterly and annual report as prescribed in Annexure to Appendix 6 E of Appendices & ANFs to DC / Designated Officer in DeitY / DoBT and Customs and Central Excise authorities.
- (b) Unit shall be able to account for entire quantity of each category of homogenous goods imported / procured duty and/or tax free, by way of exports, sales / supplies in DTA or transfer to other SEZ / EOU / EHTP / STP / BTP units and balance in stock. However, at no point of time, units shall be required to correlate every import consignment with its exports, transfer to other SEZ / EOU / EHTP / STP / BTP units, sales in DTA and balance in stock. Any matter for clarification as to whether goods are homogenous or not shall be decided by Units Approval Committee.

6.12 Monitoring of NFE

Performance of EOUs shall be monitored by Units Approval Committee as per guidelines given in Appendix 6 F of Appendices & ANFs. Performance of EHTP / STP / BTP shall be monitored by DeitY / DoBT jointly with jurisdictional Customs authority.

6.13 Conversion of Scrap / Dust / sweeping of Gold / Silver / Platinum into Standard Bars

Scrap / dust / sweeping of gold / silver / platinum may be sent to Government of India Mint / private mint from EOU / EHTP / STP units and returned to them in standard bars in accordance with procedure prescribed by Customs authorities, or may be permitted to be sold in DTA on payment of applicable GST and compensation cess alongwith reversal of duties of Customs leviable under First Schedule of the Customs Tariff Act, 1975 availed as exemption on inputs, on basis of gold / silver / platinum content, as may be notified by Customs authorities.

6.14 DTA Supplies

Notwithstanding provision of DTA sales in Paragraph 6.08 of FTP, such DTA sales shall not affect application, to any goods, of any other prohibition or regulation affecting import thereof in force at the time, when such goods are imported. This also does not confer any immunity, exemption or relaxation at any time from any commitment or compliance with any requirements to which importer may be subject to under other laws or regulations.

6.15 Supplies to other EOU / EHTP / STP / SEZ / BTP Units

Supplies to other EOU / EHTP / STP / BTP / SEZ units shall be counted towards NFE provided that such goods are permissible for procurement by these units.

6.16 Transfer of Power from one Unit to another

Transfer of power from Captive Power plants (DG Sets) from one unit of EOU / EHTP / STP / BTP unit to another is permitted as prescribed in sector specific condition in Appendix 6 B of Appendices & ANFs.

6.17 Supply of Precious / Semiprecious / Synthetic Stones from DTA

Supplier of precious and semi-precious stones, synthetic stones and processed pearls from DTA to EOUs shall be eligible for grant of Replenishment Authorisation at rates and for items mentioned in HBP. Procedure for submission of application for grant of Replenishment Authorisation as contained in relevant Chapter of HBP Vol. I shall be applicable. However, application shall be made to DC concerned. Such supplies to EOUs are not eligible for any of deemed export benefits under chapter 7 of the FTP 2015-20.

6.18 Application for grant of entitlements

Application for grant of all entitlements may be made to DC concerned.

6.19 Export through Other Exporters

An EOU / EHTP / STP / BTP unit may export goods manufactured / software developed by it through other exporter, or any other EOU / EHTP / STP / BTP / SEZ unit subject to condition that:

- (a) Goods shall be produced in EOU / EHTP / STP / BTP unit concerned.
- (b) Level of NFE or any other conditions relating to imports and exports as prescribed shall continue to be discharged by EOU / EHTP / STP / BTP unit concerned.
- (c) Export orders so procured shall be executed within parameters of EOU / EHTP / STP / BTP schemes and goods shall be directly transferred from unit to port of shipment.
- (d) Fulfilment of NFE by EOU / EHTP / STP / BTP units in regard to such exports shall be reckoned on basis of price at which goods are supplied by EOUs to other exporter or other EOU / EHTP / STP / BTP / SEZ unit.
- (e) All export entitlements, including recognition as Status Holder would accrue to exporter in whose name foreign exchange earnings are realized. However, such export shall be counted towards fulfilment of obligation under EOU / EHTP / STP / BTP scheme only.

6.20 Others Entitlements

- (a) FOB value of export of an EOU / EHTP / STP / BTP unit can be clubbed with FOB value of exports of its parent company in DTA or vice versa for the purpose of according Export House and Trading House status.
- (b) Sectoral norms as notified by Government shall apply to FDI in service activities.
- (c) STP Units / EHTP Units / Software EOUs may also use all duty and/or tax free equipment / goods for training purpose (including commercial training), subject to condition that no duty free equipment / goods shall be installed outside premises of the unit for this purpose.
- (d) Export of iron ore shall be subject to decision of Government. Requirements of other conditions of exports like minimum export price / export in consumer pack etc. as per ITC (HS) shall apply in case raw materials are sourced from DTA and exported without further processing / manufacturing by EOU. Export of textile items shall be covered by bilateral agreements. Wood based units shall comply with direction of Supreme Court contained in its order dated 12.12.1996 in Writ (civil) No 202 of 1995- T.N.Godavarman Thirumulpad v/s Union of India and others with WP (Civil) No 171 of 1996 in regard to use of timber / other wood.

6.21 Sub – Contracting

- (a) Sub - contracting by EOU gems and jewellery units through other EOUs, or SEZ Units, or units in DTA shall be subject to following conditions:-
 - (i) Goods, finished or semi finished, including studded jewellery, taken out for sub - contracting shall be brought back to unit within 90 days.
 - (ii) No cut and polished diamonds, precious and semiprecious stones (except precious, semi- precious and synthetic stones having zero duty) shall be allowed to be taken out for sub - contracting.

- (iii) Receive plain gold / silver / platinum jewellery from DTA / EOU / SEZ units in exchange of equivalent quantity of gold / silver / platinum, as the case may be, contained in said jewellery.
- (iv) EOUs shall be eligible for wastage as applicable as per Paragraph 4.60 of HBP for sub - contracting and against exchange.
- (v) DTA unit undertaking job work or supplying jewellery against exchange of gold / silver / platinum shall not be entitled to deemed export benefits under Chapter 7 of FTP.
- (b) Facility of getting job work done from DTA unit will be available subject to condition that goods are brought back to premises of unit on completion of job work.
- (c) Export of finished goods from job worker's premises may be permitted, provided such premises are registered with Central Excise/GST authorities. Where job worker is SEZ / EOU / EHTP / STP / BTP unit, export may be effected either from job worker's premises or from premises of unit. Export of such products from job worker's premises shall not be allowed through third parties as provided in FTP.
- (d) EOUs may be permitted to remove moulds, jigs, tools, fixtures, tackles, instruments, hangers and patterns and drawings to premises of sub - contractors, subject to condition that these shall be brought back to premises of units on completion of job work within a stipulated period. Raw materials may or may not be sent along with these goods.
- (e) In case of sub - contracting of production process abroad, goods may be exported from sub - contractor premises subject to conditions that at the time of clearance of goods, the EOU / EHTP / BTP / STP unit shall declare (i) the transaction value of the finished goods to be cleared from the sub - contractor's premises abroad; (ii) job work charges to be paid to the sub - contractor abroad; and (iii) value of intermediate goods; supported with documents like (a) sale price contract / or invoice for the finished goods, (b) job work contract and (c) the basis of arriving at the value of intermediate goods. The EOU / EHTP / BTP / STP unit shall also ensure full repatriation of foreign exchange declared as the transaction value of the finished goods cleared from the sub - contractor's premises abroad.

6.22 Contract Farming

EOUs engaged in production / processing of agriculture / horticulture / aquaculture products may, on basis of annual permission from Customs authorities, take out inputs and equipments (specified in Appendix 6 I of Appendices & ANFs) to DTA farm subject to following conditions:

- (a) Supply of inputs by EOUs to contract farm(s) shall be subject to input-output norms approved by DGFT / BOA.
- (b) There shall be contract farming agreement between EOU and DTA farmer(s).
- (c) Unit has been in existence for at least two years and engaged in export of agriculture / horticulture / aquaculture products; otherwise it shall furnish bank guarantee equivalent to duty and/or taxes foregone on capital goods / inputs proposed to be taken out, to Deputy / Assistant Commissioner of Customs, till unit completes two years.

6.23 Export through Exhibitions / Export Promotion Tour

EOU / EHTP / STP / BTP units may export goods for holding / participating in exhibitions abroad, with permission of DC, subject to following conditions:

- (a) Unit shall produce to Customs authorities letter in original, or its certified copy containing approval of DC. For gems and jewellery items, a self certified photograph of products shall also be submitted.
- (b) In case of re - import, such items, on arrival shall be verified along with export documents before clearance
- (c) Items not sold abroad shall be re - imported within 60 days of close of exhibition. However, in case exporter is participating in more than one exhibition within 45 days of close of first exhibition, then 60 days shall be counted from date of close of last exhibition. In case of exhibition in USA, the time period shall be 90 days instead of 60 days mentioned above.
- (d) In case of personal carriage of goods and for holding / participating in overseas exhibitions, value of such gems and jewellery shall not exceed US \$ 5 million.

6.24 Personal Carriage of Gems and Jewellery for Export Promotion Tours

Personal carriage of gold / silver / platinum jewellery, cut and polished diamonds, precious, semi-precious stones, beads and articles as samples upto US \$ 1 million for export promotion tours, and temporary display / sale abroad by EOUs, is also permitted with approval of DC subject to following conditions:

- (a) EOU shall bring back goods or repatriate sale proceeds within 45 days from date of departure through normal banking channel.

- (b) Unit shall declare personal carriage of such samples to Customs while leaving country and obtain necessary endorsement.

6.25 Export through Show-rooms abroad / Duty free shops

Export of goods is also permitted for display / sale in permitted shops set up abroad or in showrooms of their distributors / agents. Items not sold abroad within 180 days shall be re-imported within 45 days.

6.26 Sale through Showrooms / Retail outlets at International Airports

EOUs may set up showrooms / retail outlets at International Airports for sale of goods in accordance with procedure laid down by Customs authorities. Items remaining unsold after a period of 60 days shall be exported or returned to respective EOUs.

6.27 Personal Carriage of Import / Export Parcels including through Foreign Bound Passengers

- (a) For Personal carriage of jewellery by foreign bound passenger, following documents shall be submitted by EOUs as proof of exports:
- (i) Copy of shipping bill filed by EOUs;
 - (ii) A copy of Currency Declaration Form filed by Foreign buyer with Customs at time of his arrival; and
 - (iii) Foreign Exchange Realisation / Encashment Certificate from Bank.
- (b) In addition to this, Personal Carriage by foreign bound passenger on Document Against Acceptance (DA) / Cash On Delivery (COD) basis is also allowed. EOUs will have to furnish following documents as proof of exports:-
- (i) Copy of Shipping Bill;
 - (ii) Bank Certificate of Export and Realisation.
- (c) Procedure for personal carriage of import parcels will be same as for import of goods by airfreight except that parcels shall be brought to Customs by EOUs / foreign national for examination and release. Instructions issued by Customs authorities in this regard should be followed mutatis mutandis.
- (d) Personal carriage of parts by foreign bound passengers shall be allowed in case same are required for repairs of exported goods at customer site. Following documents should be submitted as proof of exports:
- (i) Permission letter from Customs for exports.
 - (ii) Invoice with value (for payment or free of charge).

6.28 Replacement / Repair of Imported / Indigenous Goods

- (a) Units may send capital goods abroad for repair with permission of Customs authorities. Any foreign exchange payment for this purpose will also be allowed. However, no permission will be required for sending capital goods for repair within country.
- (b) EOU / EHTP / STP / BTP units may, on basis of records maintained by them and prior intimation to Customs authorities:
- (i) Transfer goods to DTA / abroad for repair / replacement, testing or calibration and return.
 - (ii) Transfer goods for quality testing / R&D purpose to any recognised laboratory / institution upto Rs.5 lakh per annum without payment of duty and/or taxes as applicable in such cases on giving suitable undertaking to Customs for return of goods. However, if goods have been consumed / destroyed in process of testing etc. a certificate from laboratory / institution to this effect be furnished to Customs.

6.29 Samples

- (a) EOU / EHTP / STP / BTP units may on basis of records maintained by them, and on prior intimation to Customs authority, supply or sell samples in DTA for display / market promotion on payment of excise duty, if applicable, and/or payment of GST and compensation cess alongwith reversal of duties of Customs leviable under First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975, if availed on inputs.
- (b) Remove samples without payment of duty and/or taxes on furnishing a suitable undertaking to Customs authorities for bringing back samples within a stipulated period.
- (c) An EOU may export free samples, without any limit, including samples made in wax moulds, silver mould and rubber moulds through all permissible mode of export including through courier agencies / post.

For statutory requirement of Stability & Retention sample with manufacturer, an EOU / EHTP / BTP / STP unit may re- import with or without payment of duties/taxes as provided at para 6.01(d)(ii) of FTP those samples, which were exported by it, under intimation to Custom Authorities, and FOB value of such samples shall not be counted for NFE purpose and other export benefits, if any.

- (d) An EOU, on basis of records maintained by them and on prior intimation to Customs authorities, may send samples to other EOUs for display on returnable basis within a period of 30 days.

6.30 Donation of Computer and Computer Peripherals

EOU / EHTP / STP / BTP unit may be allowed by Customs authorities concerned to donate imported / indigenously procured (bought or taken on loan) computer and computer peripherals, including printer, plotter, scanner, monitor, keyboard and storage units without payment of duty other than applicable taxes under GST Law, two years after their import / procurement and use by units, to a school run by Central Government, or Government of a State or, a Union Territory or, a local body; an Educational Institution run on non-commercial basis by any organization; a Registered Charitable Hospital; a Public Library; a Public Funded Research and Development Establishment; a Community Information Center run by Central Government or, Government of a State or, a Union Territory or local body; an Adult Education Center run by Central Government or, Government of a State or, a Union Territory or a local body; or an organization of Central Government or, a Government of a State or, a Union Territory as per Customs / Central Excise notification.

6.31 Distinct Identity

If an industrial enterprise is operating both as a domestic unit as well as an EOU / EHTP / STP / BTP unit, it shall have two distinct identities with separate accounts, including separate bank accounts. It is, however, not necessary for it to be a separate legal entity, but it should be possible to distinguish imports and exports or supplies effected by EOU / EHTP / STP / BTP units from those made by other units of enterprise.

6.32 Unit Approval Committee for EOUs

- (a) Composition of Unit Approval Committee shall be as under:

Development Commissioner	: Chairperson
Jurisdictional Commissioner of	: Member
Central Excise & Customs or nominee	
Joint DGFT or nominee	: Member
Joint / Deputy Development	: Member
Commissioner of the Zone	

Any other nominee of any Department / Agency as special invitee

- (b) Powers and functions of Unit Approval Committee of EOUs shall be as under:

- (i) To consider applications for setting up EOUs. Items of manufacture requiring industrial licence under Industrial (Development & Regulation) Act, 1951 shall be considered by BOA.
- (ii) to consider and permit conversion of units in SEZ to EOU;
- (iii) to monitor performance of units;
- (iv) to supervise and monitor permission, clearances, licences granted to units and take appropriate action in accordance with law;
- (v) to call for information required to monitor performance of unit under permission, clearances, licenses granted to it;
- (vi) to perform any other function delegated by Central Government or its agencies;
- (vii) to perform any other function as may be delegated by State Governments or its agencies; and
- (viii) to grant all approvals and clearances for establishment and operation of EOUs

6.33 Approval of EHTP / STP / BTP Units

In case of units under EHTP / STP scheme, necessary approval / permission shall be granted by officer designated by DeitY / Director (STPI). Designated officer shall also exercise powers of adjudication under Section 13 read with Section 11 of FT (D&R) Act, 1992, as amended, in respect of STP / EHTP as mentioned in Gazette Notification No. S.O. 106 (E) dated 30-1-2006. Similarly in case of units under BTP, necessary approval / permission

shall be granted by officer designated by DoBT. However, designated officers shall adopt criteria for automatic approval of new units as laid down in Appendix 6 A of Appendices & ANFs.

6.34 Administration of EOUs / Powers of DC / Designated Officer

DC / Designated Officer shall have following powers in respect to units. Jurisdiction of DC is given in Appendix 6 J of Appendices & ANFs.

- (1) Conversion of sick / closed DTA unit into EOU;
- (2) Conversion of EOU to STP / EHTP / BTP and vice-versa as per prescribed procedure;
- (3) To allow increase in value of capital goods in terms of Indian Rupees, on account of foreign exchange rate fluctuations;
- (4) To permit capacity enhancement without any limit in case of de-licensed industries only;
- (5) Permit broad-banding for similar goods and activities mentioned in LoP or to provide for backward or forward linkages to existing line of manufacture;
- (6) Authorize change in name of company or implementing agency and change from a company to another provided new implementing agency / company undertakes to take over assets and liabilities of existing unit;
- (7) Permit change of location from place mentioned in LoP to another and / or include additional location provided that no change in other terms and conditions of approval is envisaged and that new location is within territorial jurisdiction of DC / Designated Officer;
- (8) Extend validity period of LoP beyond initial validity period of LoP (except in case where there is a restriction on initial period of approval, like setting up of oil refinery projects) as per Paragraph 6.05 (a) of FTP;
- (9) Cancel LoP wherever warranted;
- (10) Permit merger of two or more units into one unit provided units fall within jurisdiction of same DC / Designated Officer subject to condition that activities are covered under provision of broad banding;
- (11) Exercise powers of adjudication under Section 13 read with Section 11 of FT (D&R) Act, in respect of EOUs as mentioned in Gazette Notification No. SO. 194(E) dated 6.3.2000;
- (12) Do valuation of exports declared on SOFTEX form by EOUs as per RBI A.D. (M.A Series) Circular AP (DIR series Circular No.9 dated 25.10.2001);
- (13) Issue eligibility certificates for grant of employment visa to low level foreign technicians to be engaged by EOUs as per Ministry of Home Affairs letter No. 25022 / 7 / 99- F.1 dated 20.9.1999;

(14) Registration - cum - Membership Certificate

Function as a Registering authority for EOU / EHTP / STP / BTP unit. A separate Registration – cum – Membership Certificate shall not be required in their cases as provided for in Paragraph 2.44 of FTP except in case of spices. In case of spices, it would be mandatory for units to get themselves registered with Spices Board also;

(15) Importer Exporter Code No.

Allot Importer - Exporter Code number for EOUs, if same has already not been allotted to entity;

(16) Green Card

Issue of Green Card automatically after execution of LUT;

- (17) Grant / renewal of Status Certificate in respect of EOUs provided it does not involve clubbing of FOB value of exports of its parent company in DTA;

- (18) Publicity of EOU / EHTP / STP / BTP Scheme under their jurisdiction.

6.35 Change of Location / Inclusion of Additional Location with BOA Approval

BOA may consider change of location of EOU / EHTP / STP / BTP unit from place mentioned in LoP to another and / or to include additional location outside territorial jurisdiction of original DC / Designated Officer, subject to such conditions as BOA may decide.

6.36 Clearance of Capital Goods in DTA

Clearance of capital goods, including second hand, in DTA shall be allowed as per para 6.15(b) of FTP and import policy in force on date of such clearance.

6.37 Depreciation Norms

Depreciation up to 100% is permissible for Computers and Computer peripherals in 5 years and 10 years in case of other items.

(a) Depreciation Norms for Computers and Computer Peripherals:

Depreciation for computers and computer peripherals shall be as follows.

10% for every quarter in first year;

8% for every quarter in second year;

5% for every quarter in third year;

1% for every quarter in fourth and fifth year.

(b) Depreciation Norms for Other Capital Goods:

For capital goods, other than above, depreciation rate would be as follows:

4% for every quarter in first year;

3% for every quarter in second and third year;

2.5% for every quarter in fourth and fifth year;

2% for every quarter thereafter.

6.38 Conversion

- (a) Existing DTA units, may also apply for conversion into an EOU /EHTP / STP / BTP unit, but no concession in duties and taxes would be available under scheme for plant, machinery and equipment already installed. For this purpose, DTA unit may apply to DC / Designated Officer concerned in same manner as applicable to new units. In case there is an outstanding export commitment under EPCG scheme / Advance Authorization Scheme, it will follow the procedure laid down in Appendix 6 M of Appendices & ANFs.
- (b) Existing EHTP / STP / BTP units may also apply for conversion / merger to EOU unit and vice-versa. In such cases, units will continue to avail permissible exemption in duties and taxes as applicable under relevant scheme. EHTP / STP / BTP units desiring conversion as an EOU may apply to DC concerned through Officer designated by DeitY / DoBT in same manner as applicable to new units. Likewise, EOU desiring conversion into EHTP / STP / BTP may apply to officer designated by DeitY / DoBT through DC concerned.
- (c) An EOU may be shifted to SEZ with approval of DC provided EOU has achieved pro-rata obligation under EOU scheme.

6.39 Revival of Sick Units

Subject to a unit being declared sick by appropriate authority, proposals for revival of unit or its take over may be considered by BOA. Guidelines on revival of sick units are given in Appendix 6 L of Appendices & ANFs.

6.40 Fast Track Clearance Procedure**(a) Eligibility:**

EOUs having a status holder certificate under FTP shall be eligible for Fast Track Clearance Procedure.

(b) Examination of Import Cargo:

Status holder units shall be exempted from examination of import cargo at port of import. However, jurisdictional Commissioner of Customs may examine consignments at unit's place on random basis.

(c) Deleted**(d) Installation of Fax Machine / Computers:**

Eligible EOUs may install one fax machine and two computers in their administrative / registered office outside premises of the unit under prior intimation to jurisdictional Asstt. / Deputy Commissioner of Customs .

(e) Procurement of DG sets:

Procurement of DG set of capacity commensurate with actual requirement of unit shall be permitted under intimation to DC and jurisdictional Customs authority.

(f) Temporary removal of Capital Goods:

Eligible EOU may remove their capital goods or parts thereof for repairs under prior intimation to jurisdictional Asstt. / Deputy Commissioner of Customs or Central Excise.

(g) Personal carriage of samples:

Personal carriage of samples of Gems & Jewellery by status holder EOUs are allowed subject to limit fixed in Paragraph 6.24 without a need for prior permission from DC / Customs.

(h) Activities which do not require permission:

In respect of following activities of a status holder, permission will not be required from DC or jurisdictional Central Excise/Customs authority:

DTA sale of finished products in terms of Paragraph 6.08(a) of FTP; Participation in exhibition and Personal carriage of Gems & Jewellery for export promotion tours subject to fulfilment of conditions of Paragraph 6.24 of HBP. However, prior intimation thereof needs to be given.

6.41 Time Bound Disposal of Applications

DC shall dispose of applications expeditiously. Following time schedule shall normally be followed to dispose of applications provided application is complete in all respects and is accompanied with prescribed documents.

S. No.	Category of Application	Time limit for disposal (days)
1	Issue of LoP / LoI	15
2	Conversion of LoP / LoI	15
3	Acceptance of LUT	3
4	Renewal of LUT	3
5	Permission for broad banding / Diversification	3
6	Permission for change in locations	7
7	Permission for Advance DTA sale	2
8	Permission for merger of units	7
9	Permission for enhancement of production capacity	3
10	Cancellation of LoP	3
11	Permission for debonding / exit	7
12	Permission for DTA sale	2
13	Eligibility certificate for employment visa for lower level technicians	2
14	Issue of Green Card	2
15	Renewal of Green Card	Same day
16	Permission to lease CG	1
17	Permission for disposal of scrap / waste	2
18	Permission for change in name	2
19	Inter Unit Transfer	2
20	Wastage Norms, ad-hoc	2
21	Permission for re-import	Same day
22	Permission for re-export	Same day
23	Permission for replacement / repair of goods	Same day

24	Allotment of I.E. Code	1
25	Authorization of softex form	1
26	Reimbursement of CST claims	7
27	Issue of GSP Certificate	Same day
28	Permission for conversion of EOU to STPI, EPCG	5
29	Permission of final exit of EOU	5
30	Permission of extension of EOU	2
31	Permission to allow increase in value of CG	2
32	Permission for export through exhibition / tour	2
33	Reimbursement of Duty Drawback / TED	7

CHAPTER 7

DEEMED EXPORTS

7.00 Policy

Policy relating to Deemed Exports is given in Chapter-7 of FTP 2015-20.

7.01 Procedure for claiming Benefits

- (a) Supplier / Recipient of goods shall submit application for claiming deemed export benefits, in ANF-7A, along with the documents prescribed therein, to the concerned RA.
- (b) In case of supply of goods to an EOU, claim shall be filed with the concern Development Commissioner. A DTA Unit shall claim benefits from the concerned RA.

7.02 Criteria for claiming Benefits

- (a)
 - (i) In respect of supply of intermediate goods to Advance Authorisation / DFIA holder, against Invalidation Letter, issued in terms of Paragraph 4.13 of HBP, application to obtain Advance Authorisation for import of duty free inputs, as provided under chapter 4 of FTP 2015-20, shall be made as per procedures given in Chapter 4 of HBP. For supplies against invalidation letter, TED refund shall be given in accordance with para 7.03(c) of FTP 2015-20, provided, there is no exemption.
 - (ii) In respect of supply of goods to Advance Authorisation / DFIA, against ARO, procedure given in Chapter 4 of the HBP shall be followed. TED refund for supplies against ARO shall be allowed in accordance with para 7.03(c) of FTP 2015-20, provided, there is no exemption. Duty Drawback shall be allowed on basic custom duty paid on inputs used in such supplies.
- (b) In respect of supply of goods to EOU / EHTP / STP / BTP, Advance Authorisation / DFIA can be obtained as per procedure given in the Chapter 4 of HBP for exemption from payment of Terminal Excise Duty, procedure as per Excise Circular number 851/9/2007-CX dated 3.5.2007 read with circular No. 10/2009-Cus dated 25.2.2009, shall be followed for removal of goods against CT-3. TED refund shall be given for supply of goods to EOU / EHTP / STP / BTP in accordance with para 7.03(c) of FTP 2015-20, provided, there is no exemption. In case Advance Authorisation, as provided in chapter 4 of FTP 2015-20, is not obtained for import of duty free inputs against such supply, drawback claim for basic custom duty paid on inputs, used in the resultant product, shall be filed with the DC concerned. A DTA Unit shall claim benefits from the concerned RA.
- (c) In respect of supply of goods to an EPCG Authorisation holder, against Invalidation Letter, application for Advance Authorisation / DFIA shall be made as per procedures given in Chapter 4 of HBP. If Advance Authorisation / DFIA is not obtained for duty free inputs, Duty drawback shall be allowed on basic custom duty paid on inputs used in the resultant product.
- (d) In respect of supply of goods to other categories as listed in the Paragraph 7.02 (e), (f), (g) & (h) of FTP, Advance Authorisation / DFIA for import of duty free inputs as provided under chapter 4 of FTP 2015-20 may

be obtained against Project Authority Certificate as per Appendix- 7C. However, if Advance Authorisation / DFIA is not obtained against such supplies for duty free inputs as provided in chapter 4 of FTP 2015-20, claim for duty drawback for basic custom duty may be filed as per ANF-7A. TED refund for projects mentioned in para 7.08(iii)(a) of FTP 2015-20 in respect of eligible items of supply covered under schedule IV of Central Excise Act, 1944, shall be available provided there is no exemption.

7.03 Eligibility criteria for claiming TED / Drawback

- (a) Application can be filed either by supplier or by recipient of goods, having IEC Number.
- (b) Application can be made by Registered office / Head office / Branch office or Manufacturing unit.
- (c) In case supplier files claim for TED refund, it shall obtain a certificate for non-availment of CENVAT credit from the recipient of goods as per Annexure - I to ANF-7A and submit the same. In case recipient of goods is an applicant, then the applicant itself shall submit such certificate.
- (d) Deleted
- (e) In case recipient unit files claim for TED / Duty Drawback, disclaimer certificate as prescribed in the Annexure-III to ANF- 7A shall be obtained from supplier and shall be submitted along with the application. In case supplier of the goods is an applicant then the disclaimer certificate from the recipient of the goods shall be submitted.
- (f) Claim can be filed only after payment is received in full, to the extent of supplies made.
- (g) Claim can be filed against payment received through normal banking channel, as per e-BRC. In other words, supply documents have to be negotiated through bank only. In respect of supplies covered under Paragraph 7.02 (e) to (h) of the FTP 2015-20, payment certificate issued by Project Authority, in APPENDIX-7D, has also to be submitted.
- (h) Sub-contractor can also file claim provided its name is endorsed in the Project Authority Certificate / Contract before supply of such goods.

7.04 Procedure for claiming TED refund on Fuel

For supply of High Speed Diesel (HSD) from Depots of domestic oil Public Sector Undertakings under Paragraph 7.02(b) of FTP 2015-20, terminal excise duty shall be refunded on the basis of duty paid certificate issued by concerned domestic oil Public Sector Undertaking in the format given in Annexure-IV to ANF-7A. Duty refund will be allowed for quantity of HSD procured by EOU / EHTP / STP / BTP unit for its production activities, as certified by concerned DC / Bond authorities.

7.05 Frequency of application and time period for claiming TED /Drawback

- (a) In respect of supplies covered in Paragraphs 7.02 (a) to (d) of FTP 2015-20, application for TED refund / drawback (whichever applicable) may be filed within 12 months from the date of realisation of 100% payment against such supplies. In cases where payment is received in advance and supply is made subsequently, in such cases application can be filed within 12 months from the last date of such supplies. Claim can be filed 'Invalidation Letter / ARO wise' against individual Authorisation within the time limit as specified above.
- (b) In respect of supplies covered in Paragraphs 7.02 (e) to (h) of FTP 2015-20, claim may be filed either on the basis of proof of supplies effected or payment received. Claims should be filed within a period of twelve months from date of receipt of supplies by project authority or from date of receipt of the payment by supplier as per the option of applicant, either against a particular project or all the projects. Claims may also be filed where part payments have been received. Deemed export benefits may be allowed after 100% supplies have been made. However, benefit will be limited to the extent of payment received.

7.06 Fixation of Brand Rate

An application in ANF- 7A, along with documents prescribed in **ANF-7A & Appendix-7E**, may be made to RA or DC concerned, as the case may be, for fixation of brand rate. Application for fixation of Brand rate may be made for the following:

- (a) Deleted
- (b) Where basic customs duty paid is claimed as brand rate of duty drawback, in terms of Paragraph 7.06 of FTP 2015-20.

7.07 Time barred / supplementary claim

In case claim is filed after prescribed time period, provision of late cut, under Paragraph 9.02 of HBP and provision of supplementary claim under Paragraph 9.03 of HBP shall be applicable.

7.08 Exemption from payment of TED

For claiming exemption from payment of terminal excise duty, wherever applicable, procedure prescribed by Central Excise Authority shall be followed.

7.09 Applicability of other Rules

Subject to procedure laid down in HBP, Customs and Central Excise Duties and Service Tax Drawback Rules, 1995 or Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 2017, as the case may be, shall apply mutatis mutandis to deemed exports scheme.

7.10 Payment of interest

- (a) RA shall make payment within 30 days from the date of issuance of Approval Letter. In case payment is not made within the time period as given above, then RA shall add interest component, along with principal amount, in accordance with Paragraph 7.09 of the FTP 2015-20. No separate application for claiming interest is required to be made. A single mandate shall be issued to the bank for principal amount and interest.
- (b) If interest is not added by RA/DC, a separate application, as per ANF-7B may be filed, within 30 days from the date of receipt of principal amount. No interest shall be paid thereafter. RA shall maintain separate account for disbursement of principal amount and interest for accounting purpose.
- (c) RA shall submit a monthly report regarding disbursement of deemed exports claims, in the proforma as given in Appendix-7F. Wherever interest is paid, RA shall inform the reason for payment of interest. Report shall be sent at the email ID ddgdbk@nic.in.

7.11 Internal Audit Mechanism

The zonal offices of Additional DGFT shall constitute Audit team in their offices as per Paragraph 7.10 of FTP 2015-20 and shall carry out post Audit.

CHAPTER 8**QUALITY COMPLAINTS AND TRADE DISPUTES****8.01 Committee on Quality Complaint & Trade Dispute (CQCTD)**

For effective dealing of quality complaints and trade disputes, a Committee on Quality Complaint & Trade Dispute (CQCTD) is constituted in the 22 offices of the DGFT. Name of the office, where CQCTD has been constituted and jurisdiction of CQCTD is given in the table below:

Sl. No	Location of CQCTD	Designation of Chairperson	Jurisdiction of the CQCTD
<u>Northern Zone</u>			
1	Zonal Addl. DGFT, CLA, New Delhi	Addl. DGFT	Zonal DGFT, New Delhi; RA, Moradabad and RA, Dehradun
2	Jt. DGFT, Chandigarh	Jt. DGFT	RA, Chandigarh; RA, Jammu and RA, Srinagar
3	Jt. DGFT, Panipat	Jt. DGFT	RA, Panipat
4	Jt. DGFT, Jaipur	Jt. DGFT	RA, Jaipur
5	Jt. DGFT, Kanpur	Jt. DGFT	RA, Kanpur
6	Jt. DGFT, Ludhiana	Jt. DGFT	RA, Ludhiana and RA, Amritsar
7	Jt. DGFT, Varanasi	Jt. DGFT	RA, Varanasi
<u>Western Zone</u>			
8	Zonal Addl. DGFT, Mumbai	Addl. DGFT	Zonal DGFT, Mumbai; RA, Nagpur and RA, Panjim
9	Jt. DGFT, Pune	Jt. DGFT	RA, Pune
10	Jt. DGFT, Vadodara	Jt. DGFT	RA, Vadodara and RA, Gandhidham, Kutch
11	Jt. DGFT, Ahmedabad	Jt. DGFT	RA, Ahmedabad
12	Jt. DGFT, Surat	Jt. DGFT	RA, Surat

13	Jt. DGFT, Bhopal	Jt. DGFT	RA, Bhopal and Indore extn.office
<u>Eastern Zone</u>			
14	Zonal Addl. DGFT, Kolkata	Addl. DGFT	Zonal DGFT, Kolkata; RA, Patna; RA, Guwahati; RA, Shillong and RA, Raipur, Chhattisgarh
15	Jt. DGFT, Cuttack	Jt. DGFT	RA, Cuttack
<u>Southern Zone</u>			
16	Zonal Addl. DGFT, Chennai	Addl. DGFT	Zonal DGFT, Chennai and RA Puducherry
17	Jt. DGFT, Bangalore	Jt. DGFT	RA, Bangalore
18	Jt. DGFT, Hyderabad	Jt. DGFT	RA, Hyderabad
19	Jt. DGFT, Madurai	Jt. DGFT	RA, Madurai
20	Jt. DGFT, Coimbatore	Jt. DGFT	RA, Coimbatore
21	Jt. DGFT, Vishakhapatnam	Jt. DGFT	RA, Vishakhapatnam
22	Jt. DGFT Cochin	Dy. DGFT	RA, Cochin and RA, Thiruvananthapuram

8.02 Composition of the CQCTD

The CQCTD may comprise of the following members:

1. Additional DGFT/Joint DGFT/ (H.O.O): Chairperson
2. Representative of Bureau of India Standard (BIS): Member
3. Representative of Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority: Member
4. Representative of the Branch Manager of the concerned Bank: Member
5. Representative of Federation of Indian Exporter Organisation / and OR Export Promotion Council: Member
6. Representative of Export Inspection Agency: Member
7. Nominee of Director of Industries of State Government: Member
8. Nominee of Development Commissioner of MSME: Member
9. Officer as nominated by Chairperson: Member Secretary
10. Any other agency, as co-opted by Chairperson: Member.

8.03 Format for Lodging Complaint

An application for investigation of quality complaints and/or other trade disputes may be filed to the concerned RA, as indicated in paragraph 8.01 above, in the format given in ANF8 of Appendices & Aayaat Nirayat Forms. Complaint has to be duly supported by self-attested photocopies of relevant documents. Complainant can also file its complaint online on DGFT's website <www.dgft.gov.in>.

8.04 Mechanism for resolving Quality Complaint and Trade Dispute

- (a) The CQCTD, on receipt of a complaint, from importer abroad, against Indian exporter would call for comments from the firm against whom the complaint has been made. After giving reasonable opportunity of hearing to both sides, CQCTD may arrive at a conclusion to resolve the matter and CQCTD /RA will take action as considered appropriate.
- (b) RA would forward a copy of the complaint received from Indian importer, against foreign exporter to the concerned Foreign Trade (FT) Division in the Department of Commerce (DoC). FT Division in DoC will take up the complaint with the concerned Embassy/High Commission/ Consulate General in India and with concerned Indian Embassy/ High Commission abroad for effective resolution of the complaint.

8.05 Role of the Nodal Officer

- (a) The Nodal officer in DGFT, on receipt of complaints from importers abroad, would forward it to the Jurisdictional RA for examination and appropriate action.

- (b) The Nodal officer would forward copy of the complaint received from Indian importer, against foreign exporter to the concerned Foreign Trade (FT) Division in the Department of Commerce (DoC). FT Division in DoC will take up the complaint with the concerned Embassy/High Commission/ Consulate- General in India and with concerned Indian Embassy/ High Commission abroad for effective resolution of the complaint.
- (c) Regional Authorities of DGFT will send a consolidated quarterly report in respect of cases received/ referred to it, with details of action taken to the Nodal Officer.

CHAPTER 9

MISCELLANEOUS MATTERS

9.01 Denomination of Import Authorisation/Licence/ Certificate/ Permissions

- (a) CIF value of Authorisation / FOB value of export obligation shall be indicated both in Rupees and in freely convertible currency(s) at the exchange rate(s) prevailing on Authorisation issue date.
- (b) Remittance of foreign exchange and discharge of export obligation against Authorisation shall be regulated in freely convertible currency.
- (c) No enhancement in Rupee value shall be necessary if remittance of foreign exchange is covered by CIF value of Authorisation shown in freely convertible currency.
- (d) However, on Advance Authorisation(s), issued for exports to ACU countries, export obligation shall be denominated and discharged in ACU dollars.
- (e) Export obligation in Advance Authorisation for intermediate supply and for deemed export, where supplies are to be made within the country, shall be denominated and discharged in Indian rupees.

9.02 Late Cut

Wherever any application for any fiscal/financial benefits under FTP complete in all respects is received after expiry of last date for submission of such application, the application may be considered after imposing a late cut in the following manner:

i.	Application received after the expiry of last date but within six months from the last date	2%
ii.	Application received after six months from the prescribed date of submission but not later than one year from the prescribed date	5%
iii.	Application received after 12 months from the prescribed date of submission but not later than 2 years from the prescribed date	10%

9.03 Supplementary Claims

Wherever any application for supplementary claim is received, within specified time limits, such application may also be considered after imposing a cut @2% on the entitlement.

9.04 Furnishing of Information

Every importer/ exporter shall furnish such information within the stipulated time as may be called for by DGFT or any officer duly authorised. Failure to furnish the requisite information within the stipulated time shall warrant Penal action as laid down in the FTP or as per the FT(D&R) Rules,1993.

9.05 Clarifications on Policy/Procedure

A request seeking clarifications on any provision of FTP or HBP, importability or exportability of items under ITC(HS), made to DGFT in the form in ANF2F. Clarification may also be sought on E-mail.

9.06 Consumption Register

Importer shall maintain a register as in Appendix-4H (for 3 years period) of items imported under an Authorisation and separately for items imported with actual user condition and its consumption. In respect of particular schemes such register shall be maintained for specified period.

9.07 Export Facilitation

In order to resolve exporters' problems in a co-ordinated manner, field offices of DGFT shall act as Export Facilitation Centres and nodal agencies.

9.08 Standing Grievance Committee

For speedy redressal of genuine grievances of trade and industry pertaining to FTP and Procedure, Grievance Committees have been constituted chaired by (i) DGFT at Headquarters and (ii) head(s) of RA(s) in regional offices Headquarters and (ii) head(s) of RA(s) in regional offices. Grievance Committee will include representatives of Federation of Indian Export Organisations (FIEO), Export Promotion Councils/ Commodity Boards, Development Authorities, and Government Departments/ technical authorities as their members.

9.09 Counter Assistance

- (a) While the endeavour of DGFT is to make filling/submission of all applications online, till the time the facility for online application is not available, applications will continue to be received at the counter.
- (b) For speedy disposal of applications, "Counter Assistance" will function in all offices of DGFT. An FTDO shall be in charge of counter in each office. On presentation of application at the counter, applicant would be advised whether his application is complete or there is any deficiency that needs to be rectified.
- (c) Counter Assistance may also be availed of for amendments of minor nature/enquiries. Applications, in such cases, will be received in regional offices at counter against a proper receipt. Authorisation / licence /list /enquiry shall be returned after carrying out necessary amendments/ giving necessary reply as far as possible on the same day, across the Counter.

9.10 Time Bound Disposal of Applications

RA shall dispose of applications expeditiously. Following time schedule shall normally be followed to dispose of applications provided it is complete in all respects and is accompanied by prescribed documents.

S. No.	Category of Application	Time Limit For Disposal (in working days)
i	IEC Number	2
ii	Advance Authorisation where Input-Output norms are notified or under paragraph 4.07 of HBP, Advance Authorisation for Annual Requirement and DFIA.	3
iii	Fixation of input output norms	120
iv	Issuance of EPCG Authorisations	3
v	All Authorisations under Gem & Jewellery scheme	3
vi	Revalidation of Authorisation and extension of export obligation period by R.A	3
vii	Acceptance of BG/LUT	3
viii	Redemption/EODC of Advance Authorisation/ DFIA	15
ix	Redemption of EPCG Authorisations and release of BG /LUT.	30
x	Issuance/renewal of status certificate	3
xi	Amendment of any category of Authorisation	3

xii	Miscellaneous	10
xiii	Refund of DBK/ TED under deemed export	30
xiv	Fixation of Brand Rate for duty drawback	30
xv	Schemes of Chapter 3	3

In all the above cases, the number day is counted from the date of submission of complete application. Cases of undue delay in disposal of applications may be brought to notice of head of regional offices by way of a written representation, which shall be promptly enquired into and responded to.

9.11 Date of shipment/Dispatch in respect of Imports

Date of shipment/dispatch for imports will be reckoned as under:-

S.No.	Mode of Transportation	Date of Shipment / Dispatch
(i)	By Sea	The date affixed on the Bill of Lading
(ii)	By Air	Date of relevant Airway Bill provided this represents date on which goods left last airport in the country from which the import is effected.
(iii)	From land-Locked Countries	Date of dispatch of goods by rail, road or other recognised mode of transport to consignee in India through consignment basis.
(iv)	By Post Parcel	Date stamp of office of dispatch on the packet or dispatch note
(v)	By Registered Courier Service	Date affixed on Courier Receipt / Waybill
(vi)	Multimodal Transport	Date of handing over goods to first carrier in a combined transport Bill of Lading

9.12 Date of Shipment/ Dispatch in respect of Exports

(A) Date of shipment/dispatch for exports will be reckoned as under:

Sl. No.	Mode of Transportation	Date of Shipment / Dispatch
(i)	By Sea	(a) For bulk cargo, date of Bill of Lading or date of mate receipt, whichever is later? (b) For containerised cargo, date of "Onboard Bill of Lading", or "Received for Shipment Bill of Lading", where the L/C provides for such Bill of Lading. For exports by containers from Inland Container Depot (ICD), date of Bill of Lading issued by shipping agents at the time of loading of export goods in ICD after customs clearance. (c) For Lash barges, date of Bill of Lading evidencing loading of export goods on board.
(ii)	By Air	Date mentioned by appropriate Officer of Customs on Shipping Bill, evidencing loading or handing over of goods to air cargo complex, which are not international airports, or by way of rotation of flight number and date.
(iii)	By Post Parcel	Date stamped on postal receipt
(iv)	By Rail	Date of RR (Railway Receipt)
(v)	By Registered Courier Service	Date affixed on Courier Receipt/ Waybill.

(vi)	By Road	Date on which goods crossed Indian border as certified by Land Customs Authorities.
------	---------	---

- (B) However, wherever Procedural / Policy provisions have been modified to disadvantage of exporters, the same shall not be applicable to consignments already handed over to Customs for examination and subsequent exports up to Public Notice / Notification date.
- (C) Similarly, in cases where goods are handed over to the customs authorities before expiry of export obligation period but actual Exports take place after expiry of the export obligation period, such exports shall be considered within export obligation period and taken towards fulfilment of export obligation.
- (D) However, for benefit under FTP, Let Export Order (LEO) date shall be the date of reckoning of export.

9.13 General Power of Review

DGFT may, on his own or otherwise, call for records of any case pending with or decided by an officer subordinate to him or an officer of any EPC/FIEO including a Group/ Committee of officers nominated, appointed or authorised by him and pass such orders as he may deem fit.

GLOSSARY (ACRONYMS)

Acronym	Explanation
AA	Advance Authorisation
AANF	Appendices and Aayaat Niryaat Form
ACU	Asian Clearing Union
AEZ	Agri Export Zone
ANF	Aayat Niryaat Form
ARE-1	Application for Removal of Excisable Goods for Export (By Air/Sea/Post/Land)
ARE-3	Application for Removal of Excisable Goods from a factory or a warehouse to another warehouse
ACP	Accredited Clients Programme
AEO	Authorised Economic Operator
AES	Approved Exporter's Scheme
APEDA	Agricultural & Processed Food Products Export Development Authority
ARO	Advance Release Order
ASEAN	Association of South- East Asian Nations
ASIDE	Assistance to States for Infrastructure Development of Exports
AU	Actual User
BCD	Basic Customs Duty
BG	Bank Guarantee
BIFR	Board of Industrial and Financial Reconstruction
BOA	Board of Approval
BOT	Board of Trade
BRC	Bank Realisation Certificate
BTP	Biotechnology Park
BIS	Bureau of Indian Standards
CBEC	Central Board of Excise and Customs

CCP	Customs Clearance Permit
CEA	Central Excise Authority
CEC	Chartered Engineer Certificate
CED	Central Excise Duty
CENVAT	Central Value Added Tax
CETF	Common Effluent Treatment Facility
CFCs	Common Facility Centres
CG	Capital Goods
CGST	Central Goods and Services Tax
CIF	Cost, Insurance & Freight
CIN	Corporate Identification Number
CIS	Commonwealth of Independent States
CKD	Completely Knocked Down
CoD	Cash on Delivery
CoO	Certificate of Origin
CQCTD	Committee on Quality Complaints and Trade Disputes
CRES	Certificate of Registration as Exporter of Spices
CST	Central Sales Tax
CIN	Company Identification Number
CRES	Certification of Registration as Exporter of Spices
CEPA	Comprehensive Economic Partnership Agreement
CBEC	Central Board of Excise and Customs
CSP	Common Service Provider
CECA	Comprehensive Economic Cooperation Agreement
CVD	Countervailing Duty
DA	Document against Acceptance
DBK	Drawback
DC	Development Commissioner
DDA	Diamond Dollar Accounts
DEA	Department of Economic Affairs
DEL	Denied Entity List
DES	Duty Exemption Schemes
DFIA	Duty Free Import Authorisation
DGCI&S	Director General, Commercial Intelligence & Statistics.
DIN	Director Identification Number
DPIN	Designated Partner Identification Number
DGFT	Director General of Foreign Trade
DIPP	Department of Industrial Policy & Promotion

DoBT	Department of Bio-Technology
DoC	Department of Commerce
DeitY	Department of Electronics and Information Technology
DoR	Department of Revenue
DoT	Department of Telecommunications
DRS	Duty Remission Schemes
DTA	Domestic Tariff Area
e-BRC	Electronic Bank Realisation Certificate
e-IEC	Electronic Importer-Exporter Code
ECA	Enforcement- cum-Adjudication
EDI	Electronic Data Interchange
ECGC	Export Credit Guarantee Corporation
EEFC	Exchange Earners' Foreign Currency
EFC	Exim Facilitation Committee
EFT	Electronic Fund Transfer
EGM	Export General Manifest
EHTP	Electronic Hardware Technology Park
EIC	Export Inspection Council
EO	Export Obligation
EODC	Export Obligation Discharge Certificate
EOP	Export Obligation Period
EOU	Export Oriented Unit
EPC	Export Promotion Council
EPCG	Export Promotion Capital Goods
EPO	Engineering Process Outsourcing
EXIM	Export Import
FDI	Foreign Direct Investment
FE	Foreign Exchange
FEMA	Foreign Exchange Management Act
FIEO	Federation of Indian Export Organisation
FIRC	Foreign Exchange Inward Remittance Certificate
FOB	Free On Board
FOR	Freight on Road and Rails
FT (D&R)Act	Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 (22 of 1992)
FTDO	Foreign Trade Development Officer
FTP	Foreign Trade Policy
FT(R) Rules	Foreign Trade (Regulation) Rules
FTWZ	Free Trade and Warehousing Zone

FTA	Free Trade Agreement
G&J EPC	Gems & Jewellery Export Promotion Council
GOI	Government of India
GATS	General Agreement on Trade in Services
GR	Guarantee of Realisation
GST	Goods and Services Tax
HACCP	Hazard Analysis and Critical Control Process
HBP	Handbook of Procedures
HHEC	Handicraft & Handlooms Exports Corporation
ICB	International Competitive Bidding
ICD	Inland Container Depot
ICM	Indian Commercial Mission
IEC	Importer Exporter Code
IGST	Integrated Goods and Services Tax
ISO	International Organisation for Standardisation
IAEA	International Atomic Energy Agency
INFCIRC	International Atomic Energy Agency Information Circular
IEM	Industrial Entrepreneurial Memorandum
IMSC	Inter-Ministerial Standing Committee
IL	Industrial Licensing
ISO	International Standards Organisation
ITC (HS)	Indian Trade Classification (Harmonised System) for Export & Import Items
KVIC	Khadi and Village Industries Commission
LC	Letter of Credit
LCS	Land Customs Station
LLPIN	Limited Liability Partnership Number
LPG	Liquefied Petroleum Gas
LoC	Line of Credit
LoI	Letter of Intent
LoP	Letter of Permit
LUT	Legal Undertaking
MAI	Market Access Initiative
MDA	Market Development Assistance
MEA	Ministry of External Affairs
MEIS	Merchandise Exports from India Scheme
MRA	Mutual Recognition Agreements
MoD	Ministry of Defence
MoF	Ministry of Finance

MSME	Ministry of Micro Small and Medium Enterprises
MSMED	Micro Small and Medium Enterprises Development
MSTC	Metal Scrap Trade Corporation
NBFC	Non- Banking Financial Company
NC	Norms Committee
NFE	Net Foreign Exchange
NI	Non-Infringing
NCB	National Competitive Bidding
NOC	No Objection Certificate
PDS	Public Distribution System
PEC	Project and Equipment Corporation of India Ltd.
PIC	Policy Interpretation Committee
PRC	Policy Relaxation Committee
PAN	Permanent Account Number
PH	Personal Hearing
PTA	Preferential Trade Agreement
PSU	Public Sector Undertaking
R&D	Research and Development
RA	Regional Authority
RBI	Reserve Bank of India
RCMC	Registration-cum-Membership Certificate
REP	Replenishment
RPA	Rupee Payment Area
S/B	Shipping Bill
SAD	Special Additional Duty
SCOMET	Special Chemicals, Organisms, Materials, Equipment and Technology
SEI CMM	Software Engineers Institute's Capability Maturity Model
SEZ	Special Economic Zone
SEIS	Service Exports from India Scheme
SGST	State Goods and Services Tax
SIA	Secretariat for Industrial Assistance
SIIC	State Industrial Infrastructure Corporation
SION	Standard Input Output Norms
SKD	Semi- Knocked Down
SLEPC	State Level Export Promotion Committee
STC	State Trading Corporation
STCL	Spices Trading Corporation Limited
STE	State Trading Enterprise

STH	Star Trading House
STPI	Software Technology Park of India
STR	State Trading Regime
SUVs	Sports Utility Vehicles
TED	Terminal Excise Duty
TEE	Towns of Export Excellence
TH	Trading House
TPO	Trade Promotion Organization
TRA	Telegraphic Release Advice
TRQ	Tariff Rate Quota
TUFS	Technology Upgradation Fund Scheme
UAC	Units Approval Committee
UN	United Nations
VA	Value Addition
WCO	World Customs Organisation
WHOGMP	World Health Organisation Good Manufacturing Practices